

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



अप्रैल 2025

खंड 79 अंक 4

संपादक समिति
मनीष कपूर
अजीत आर जोशी
रेखा मिश्र
प्रज्ञा दास
सुनिल कुमार
स्नेहल हेरवाडकर
पंकज कुमार
वी. धन्या
श्वेता कुमारी
अनिर्बन सान्याल
सुजाता कुंडू

संपादक
जी. वी. नथनएल

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित की जाती है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित आलेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2025

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः उत्पादन की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन की सदस्यता के लिए कृपया 'हाल के प्रकाशन' खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को
<https://bulletin.rbi.org.in> पर देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

मौद्रिक नीति वक्तव्य (अप्रैल 7-9) 2025

गवर्नर का वक्तव्य: अप्रैल 9, 2025	1
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प 7 से 9 अप्रैल 2025	7
विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य	9
मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अप्रैल 2025	11

भाषण

24वें फिमडा-पीडीएआई वार्षिक सम्मेलन में मुख्य भाषण श्री संजय मल्होत्रा	115
01 अप्रैल 2025 को आरबीआई@90 स्मरणोत्सव समारोह में स्वागत भाषण श्री संजय मल्होत्रा	121
वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के निजी क्षेत्र सहयोग मंच पर संबोधन श्री संजय मल्होत्रा	123
साझा दृष्टिकोण, साझी जिम्मेदारी – एनबीएफसी को मजबूत बनाना श्री स्वामीनाथन जे	127

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति	131
स्थायी जमा सुविधा के तीन वर्ष: कुछ विचार	181
जलवायु नीति अनिश्चितता और ऊर्जा वस्तु मूल्यों की बदलती गतिशीलता	195
भारत में ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास: अंतर को पाटना	205

वर्तमान सांख्यिकी	245
-------------------	-----

हाल के प्रकाशन	299
----------------	-----

**मौद्रिक नीति वक्तव्य,
(अप्रैल 7-9) 2025-26**

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य*

संजय मल्होत्रा

यह एमपीसी की 54वीं बैठक और वित्तीय वर्ष 2025-26 में आयोजित पहली बैठक थी। वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए वर्ष की शुरुआत चिंताजनक रही है। व्यापार के व्यवधानों से संबंधित कतिपय चिंताएँ सच हो रही हैं, जिससे वैश्विक समुदाय बेचैन है। इन वैश्विक घटनाक्रमों के प्रति सतर्क रहते हुए, हमने रिजर्व बैंक में, 1 अप्रैल 1935 को अपनी स्थापना के बाद से इस प्रतिष्ठित संस्था के 90 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाते हुए वर्ष की शुरुआत की। पिछले नौ दशकों में रिजर्व बैंक की यात्रा देश के विकास और प्रगति के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ी रही है। मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के संरक्षक के रूप में, रिजर्व बैंक पिछले कुछ वर्षों में एक पूर्ण-सेवा केंद्रीय बैंक के रूप में विकसित हुआ है, जिसके विभिन्न कार्य बाज़ार अर्थव्यवस्था को सुविधाजनक बनाते हैं।

इस चुनौतीपूर्ण वैश्विक माहौल¹ में नीतिगत रेपो दर पर विचार-विमर्श और निर्णय लेने के लिए मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 7, 8 और 9 अप्रैल को संपन्न हुई। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। हाल ही में व्यापार शुल्क संबंधी उपायों ने अनिश्चितताओं को बढ़ा दिया है जो सभी क्षेत्रों में आर्थिक संभावना पर छा गया जिससे वैश्विक संवृद्धि और मुद्रास्फीति के लिए नई चुनौतियाँ उत्पन्न हो गई हैं। इस उथल-पुथल के बीच, अमेरिकी डॉलर में काफी गिरावट आई है; बॉण्ड प्रतिफल में काफी कमी आई है; इक्विटी बाजार में गिरावट हो रहा है; और कच्चे तेल की कीमतें तीन वर्ष से भी अधिक समय के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। इन परिस्थितियों में, केंद्रीय बैंक सावधानीपूर्वक कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि विभिन्न अधिकार-क्षेत्रों में नीतिगत भिन्नता के संकेत मिल रहे हैं, जो उनकी अपनी घरेलू प्राथमिकताओं को दर्शाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था ने मूल्य स्थिरता और सतत संवृद्धि के लक्ष्यों की दिशा में लगातार प्रगति की है। मुद्रास्फीति के स्तर

पर, खाद्य मुद्रास्फीति में अपेक्षा से अधिक गिरावट ने हमें राहत और आत्मविश्वास दिया है, लेकिन हम वैश्विक अनिश्चितताओं और मौसम की गड़बड़ी से संभावित जोखिमों के प्रति सतर्क हैं। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में कमजोर प्रदर्शन के बाद संवृद्धि में सुधार हो रहा है, हालांकि यह अभी भी हमारी अपेक्षा से कम है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का निर्णय

उभरती हुई समष्टि-आर्थिक और वित्तीय स्थितियों तथा संभावना के विस्तृत मूल्यांकन के बाद, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक घटाकर 6.00 प्रतिशत करने के लिए वोट किया; परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.75 प्रतिशत पर तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.25 प्रतिशत पर समायोजित हो जाएंगी।

अब मैं लिए गए इन निर्णयों के औचित्य को संक्षेप में बताऊंगा। एमपीसी ने कहा कि मुद्रास्फीति वर्तमान में लक्ष्य से नीचे है, जिसे खाद्य मुद्रास्फीति में तेज गिरावट का समर्थन मिला है। इसके अलावा, मुद्रास्फीति की संभावना में भी निर्णायक सुधार हुआ है। अनुमानों के अनुसार, अब 12 महीने के हराइज़न पर 4 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ हेडलाइन मुद्रास्फीति के टिकाऊ संरेखण का विश्वास अधिक है। दूसरी ओर, चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण से बाधित, 2024-25 की पहली छमाही में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद संवृद्धि अभी भी सुधार की राह पर है। ऐसी चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक स्थितियों में, सौम्य मुद्रास्फीति की संभावना और मध्यम संवृद्धि की मांग है कि एमपीसी संवृद्धि का समर्थन करना जारी रखे। तदनुसार, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक कम करके 6.0 प्रतिशत करने के लिए वोट किया। इसके अलावा, इसने रुख को तटस्थ से बदलकर निभावकारी करने का भी निर्णय लिया। इसने यह भी कहा कि तेजी से विकसित हो रही स्थिति के लिए आर्थिक संभावना की निरंतर निगरानी और आकलन की आवश्यकता है।

मैं मौद्रिक नीति के रुख पर थोड़ा विस्तार से बात करना चाहूंगा। अंतर-देशीय नजरिए से, मौद्रिक नीति के रुख को आम तौर पर निभावकारी, तटस्थ या सख्त रुख के रूप में परिभाषित

* गवर्नर का वक्तव्य- 09 अप्रैल 2025

¹ ऑर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को-ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) की आर्थिक संभावना अंतरिम रिपोर्ट, मार्च 2025 के अनुसार, वैश्विक जीडीपी संवृद्धि 2024 में 3.2 प्रतिशत से घटकर 2025 में 3.1 प्रतिशत और 2026 में 3.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें दिसंबर 2024 की पिछली रिलीज की तुलना में क्रमशः 20 बीपीएस और 30 बीपीएस की गिरावट है।

किया जाता है। जहां निभावकारी रुख में मौद्रिक नीति आसान होती है, जो सौम्य ब्याज दरों के माध्यम से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए तैयार होती है; सख्त रुख का तात्पर्य संकुचनकारी मौद्रिक नीति से है जिसके तहत व्यय को नियंत्रित करने और आर्थिक गतिविधि को रोकने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जाती है, जिसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना होता है। तटस्थ रुख आमतौर पर अर्थव्यवस्था की उस स्थिति से जुड़ा होता है जिसमें न तो आर्थिक गतिविधि को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता होती है और न ही मांग में कटौती करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है, बल्कि इसमें उभरती आर्थिक स्थितियों के आधार पर किसी भी दिशा में आगे बढ़ने की सुविधा प्रदान की जाती है।

हमारे संदर्भ में, मौद्रिक नीति का रुख भविष्य में नीतिगत दरों की इच्छित दिशा का संकेत देता है। तदनुसार, नीति दर के संबंध में, जो एमपीसी का अधिदेश है, आज 'तटस्थ' रुख से 'निभावकारी' रुख में परिवर्तन का अर्थ है कि आगे चलकर, कोई भी आघात न होने की स्थिति में, एमपीसी केवल दो विकल्पों पर विचार कर रही है – यथास्थिति या दर में कटौती। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि रुख को सीधे चलनिधि की स्थिति से न जोड़ा जाए। जबकि मौद्रिक नीति के लिए चलनिधि प्रबंधन महत्वपूर्ण है, जिसमें नीतिगत दर से संबंधित निर्णय शामिल हैं, यह मौद्रिक नीति संचरण सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का परिचालनात्मक साधन है। हालांकि, नीतिगत दरों में बदलाव करने संबंधी मौद्रिक नीति निर्णयों का चलनिधि प्रबंधन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह नीति परिवर्तनों को पूरा करने के लिए परिचालनात्मक साधन है। संक्षेप में, हमारा रुख चलनिधि प्रबंधन पर बिना किसी भी प्रत्यक्ष मार्गदर्शन के, नीतिगत दर मार्गदर्शन प्रदान करता है। मैं थोड़ी देर बाद चलनिधि प्रबंधन के लिए हमारे दृष्टिकोण पर चर्चा करूंगा।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति का आकलन

वैश्विक व्यापार और नीतिगत अनिश्चितताओं का संवृद्धि और मुद्रास्फीति पर प्रभाव

इससे पहले कि मैं संवृद्धि और मुद्रास्फीति के बारे में अपना आकलन साझा करूँ, हाल ही में वैश्विक व्यापार और उससे जुड़ी नीतिगत अनिश्चितताओं के प्रभावों पर कुछ शब्द कहना उचित होगा। पहले मैं संवृद्धि के लिए संभावित प्रभावों पर प्रकाश डालूँगा। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अनिश्चितता अपने

आप में कारोबारों और परिवारों के निवेश और व्यय संबंधी निर्णयों को प्रभावित करके संवृद्धि को धीमा कर देती है। दूसरा, व्यापार संबंधी बाधाओं के कारण वैश्विक संवृद्धि पर पड़ने वाला असर घरेलू संवृद्धि को बाधित करेगा। तीसरा, उच्च टैरिफ का निवल निर्यात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालाँकि, कई ज्ञात अज्ञात बातें हैं – कुछ ऐसे विषय जैसे सापेक्ष टैरिफ का प्रभाव, हमारे निर्यात और आयात मांग की लोच; और सरकार द्वारा अपनाए गए नीतिगत उपाय जिनमें यूएसए के साथ प्रस्तावित विदेशी व्यापार समझौता शामिल हैं। ये प्रतिकूल प्रभाव की मात्रा का आकलन करना मुश्किल बनाते हैं।

दूसरी ओर, मुद्रास्फीति के जोखिम दोतरफा हैं। ऊर्ध्वगामी पक्ष यह है कि अनिश्चितताओं के कारण मुद्रा पर दबाव और आयातित मुद्रास्फीति की संभावना हो सकती है। अधोगामी पक्ष यह है कि वैश्विक संवृद्धि में मंदी के कारण कमोडिटी और कच्चे तेल की कीमतों में और नरमी आ सकती है, जिससे मुद्रास्फीति पर अधोगामी दबाव बढ़ सकता है। कुल मिलाकर, जबकि वैश्विक व्यापार और नीतिगत अनिश्चितताएं संवृद्धि में बाधा उत्पन्न करेगी, घरेलू मुद्रास्फीति पर इसका प्रभाव बहुत अधिक चिंता का विषय नहीं है, लेकिन हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है।

संवृद्धि

2024-25 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में पिछले वर्ष में देखी गई 9.2 प्रतिशत की वृद्धि दर से ऊपर 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।² 2025-26 में, जलाशय के बेहतर स्तरों और फसल उत्पादन में मजबूती के कारण कृषि क्षेत्र की संभावनाएं उज्ज्वल बनी हुई हैं।³ विनिर्माण गतिविधि में सुधार⁴ के संकेत दिख

² राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमान (एसआई) के अनुसार, 2024-25 में जीडीपी वृद्धि 2023-24 में 9.2 प्रतिशत की तुलना में 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) और सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) में क्रमशः 7.6 प्रतिशत और 6.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। सरकारी उपभोग व्यय (जीएफसीई) में पिछले वर्ष की तुलना में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बुनियादी कीमतों (वर्ष-दर-वर्ष) पर योजित सकल मूल्य (जीवीए) में 6.4 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है। कृषि और संबद्ध गतिविधियों में 2024-25 में 4.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जबकि औद्योगिक संवृद्धि 4.3 प्रतिशत तक कम हो गया, जबकि सेवाओं में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

³ अप्रैल 2025 तक 155 प्रमुख जलाशयों में अखिल भारतीय जल भंडारण कुल क्षमता का 40 प्रतिशत है, जबकि एक वर्ष पहले यह 35 प्रतिशत था और दशकीय औसत 34 प्रतिशत है। (2024-25 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान (एसआई) के अनुसार, कुल खाद्यान्न उत्पादन में वर्ष-दर-वर्ष 4.8 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

⁴ विनिर्माण जीवीए में दूसरी तिमाही में 2.1 प्रतिशत की कमजोर वृद्धि के बाद तीसरी तिमाही के दौरान 3.5 प्रतिशत की रिकवरी के कारण उद्योग क्षेत्र में 2024-25 की तीसरी तिमाही में 3.5 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई, जबकि 2024-25 की दूसरी तिमाही में यह वृद्धि 2.0 प्रतिशत थी।

रहे हैं, साथ ही व्यावसायिक प्रत्याशा मजबूत बनी हुई है⁵, जबकि सेवा क्षेत्र की गतिविधि आघात-सहनीय बनी हुई है।⁶

मांग पक्ष पर, कृषि क्षेत्र की उज्ज्वल संभावनाएं ग्रामीण मांग के लिए शुभ संकेत हैं जो स्वस्थ बनी हुई है, जबकि शहरी खपत धीरे-धीरे विवेकाधीन खर्च में वृद्धि के साथ बढ़ रही है।⁷ निवेश गतिविधि में तेजी आई है⁸ और निरंतर उच्च क्षमता उपयोग,⁹ बुनियादी ढांचे संबंधी व्यय पर सरकार के निरंतर जोर,¹⁰ बैंकों और कॉरपोरेट्स की स्वस्थ तुलन-पत्र, साथ ही वित्तीय स्थितियों में आसानी के कारण इसमें और सुधार होने की उम्मीद है। वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण वाणिज्यिक वस्तु निर्यात पर असर पड़ेगा, जबकि सेवाओं के निर्यात में लचीलापन रहने की उम्मीद है।¹¹ वैश्विक व्यापार के व्यवधानों से उत्पन्न प्रतिकूल परिस्थितियाँ अधोगामी जोखिम उत्पन्न करती रहेंगी।

इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि अब 6.5 प्रतिशत अनुमानित है, जोकि पहली तिमाही में 6.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालाँकि जोखिम इन आधारभूत अनुमानों के आसपास समान रूप से संतुलित हैं, लेकिन वैश्विक अस्थिरता में हाल ही में हुई वृद्धि के मद्देनजर अनिश्चितताएँ अभी भी अधिक हैं।

⁵ मार्च 2025 में पीएमआई विनिर्माण भावी उत्पादन सूचकांक 64.4 पर रखा गया था। अप्रैल 2023 से भावी उत्पादन सूचकांक 60.0 से ऊपर रहा है।

⁶ 2024-25 की चौथी तिमाही में ई-वे बिल में 19.4 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई। मार्च 2025 के दौरान सकल जीएसटी राजस्व में 9.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और टोल संग्रह में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फरवरी 2025 में तैयार स्टील की खपत में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और सीमेंट उत्पादन में 10.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, फरवरी 2025 में पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में 5.4 प्रतिशत की कमी आई। मार्च 2025 के लिए पीएमआई सेवाएं फरवरी 2025 के 59.0 से घटकर 58.5 हो गईं।

⁷ जनवरी 2025 में आईआईपी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई। फरवरी 2025 में घरेलू हवाई यात्री यातायात में 12.1 प्रतिशत और मार्च में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

⁸ निवेश के संकेतक अच्छी वृद्धि दर्ज कर रहे हैं। जनवरी 2025 में पूंजीगत वस्तुओं के आईआईपी में 7.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान पूंजीगत वस्तुओं के आयात में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान तैयार इस्पात की खपत और सीमेंट उत्पादन में क्रमशः 10.9 प्रतिशत और 12.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

⁹ आदेश बही, माल सूची और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) के अनुसार, 2024-25 की तीसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में मौसमी रूप से समायोजित क्षमता उपयोग 75.3 प्रतिशत रहा जो दीर्घकालिक औसत से काफी अधिक था।

¹⁰ केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार, केंद्र सरकार के प्रभावी पूंजीगत व्यय (पूंजीगत व्यय के लिए राज्य सरकारों को अनुदान सहायता सहित) में 17.4 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

¹¹ मजबूत सॉफ्टवेयर और व्यापार निर्यात के बल पर जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान सेवा निर्यात में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान वर्ष के लिए संवृद्धि के अनुमान को फरवरी नीति में हमारे पहले के 6.7 प्रतिशत के आकलन की तुलना में 20 आधार अंक कम कर दिया गया है। यह अधोगामी संशोधन अनिवार्य रूप से वैश्विक व्यापार और नीतिगत अनिश्चितताओं के प्रभाव को दर्शाता है, जिसे मैंने पहले भी उजागर किया था।

मुद्रास्फीति

खाद्य मुद्रास्फीति में तीव्र करेक्शन के बाद जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति में कमी आई।¹² खाद्य मुद्रास्फीति संबंधी संभावना निर्णायक रूप से सकारात्मक हो गया है। रबी फसलों से संबंधित अनिश्चितताएँ काफी हद तक कम हो गई हैं और दूसरे अग्रिम अनुमान पिछले वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन और प्रमुख दालों के अधिक उत्पादन की ओर इशारा करते हैं।¹³ खरीफ की अच्छी उत्पादन के कारण, यह अनुमान है कि इससे खाद्य मुद्रास्फीति में स्थायी नरमी आएगी। हमारे नवीनतम सर्वेक्षण में तीन महीने और एक वर्ष के लिए मुद्रास्फीति की उम्मीदों में तीव्र गिरावट से भी आगे चलकर मुद्रास्फीति अनुमानों को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।¹⁴ इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट मुद्रास्फीति की संभावना के लिए शुभ संकेत है। हालाँकि, वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं और प्रतिकूल मौसम संबंधी आपूर्ति व्यवधानों की पुनरावृत्ति की चिंताएँ, मुद्रास्फीति के प्रक्षेपवक्र के लिए जोखिम उत्पन्न करती हैं।

¹² जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति में संचयी 1.6 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई, जो दिसंबर 2024 में 5.2 प्रतिशत से फरवरी 2025 में 3.6 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई। इस वर्ष सब्जियों की कीमतों में मजबूत मौसमी करेक्शन से उत्साहित होकर, खाद्य मुद्रास्फीति फरवरी में 21 महीने के निचले स्तर 3.8 प्रतिशत पर आ गई, जो जनवरी 2025 में 5.7 प्रतिशत थी। ईंधन समूह में अपस्फीति, वर्ष-दर-वर्ष, दिसंबर 2024 में (-) 1.3 प्रतिशत, जनवरी 2025 में (-) 1.5 प्रतिशत और फरवरी 2025 में (-) 1.3 प्रतिशत थी। हालाँकि, दिसंबर 2024-जनवरी 2025 के दौरान वर्ष-दर-वर्ष 3.6 प्रतिशत पर स्थिर रहने के बाद खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई फरवरी 2025 में 4.1 प्रतिशत हो गई।

¹³ मार्च 2025 में जारी वर्ष 2024-25 के लिए कृषि उत्पादन (खरीफ और रबी) के दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार, 2024-25 के लिए गेहूं का उत्पादन रिकॉर्ड 115.4 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो 2023-24 के अंतिम अनुमानों से 1.9 प्रतिशत अधिक है। 2024-25 में दालों (खरीफ और रबी) का उत्पादन 2023-24 के अंतिम अनुमानों से 3.8 प्रतिशत अधिक होने का अनुमान है। चना और मसूर जैसी प्रमुख रबी सीजन की दालों के उत्पादन में क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 1.5 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है।

¹⁴ सर्वेक्षण के हालिया दौर में, वर्तमान औसत मुद्रास्फीति के बारे में परिवारों की धारणा में 50 आधार अंकों (बीपीएस) की गिरावट आई और यह 7.8 प्रतिशत पर पहुंच गई। अगले तीन महीनों और एक वर्ष के लिए परिवारों की मुद्रास्फीति की अपेक्षाएँ भी 40 बीपीएस और 50 बीपीएस तक कम होकर क्रमशः 8.9 प्रतिशत और 9.7 प्रतिशत पर पहुंच गईं।

इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए और सामान्य मानसून को मानते हुए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पहली तिमाही में 3.6 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 3.9 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 3.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.4 प्रतिशत रहेगी। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

बाह्य क्षेत्र

जनवरी-फरवरी 2025 में भारत का सेवा निर्यात आघात-सह बनी रही, जिसका श्रेय सॉफ्टवेयर, व्यापार और परिवहन सेवाओं को जाता है।¹⁵ आगे चलकर, निवल सेवाओं और विप्रेषण प्राप्ति के बड़े अधिशेष में रहने की उम्मीद है, जो आंशिक रूप से व्यापार घाटे की भरपाई करेगा। 2024-25 और 2025-26 के लिए सीएडी के टिकाऊ स्तर के भीतर रहने की उम्मीद है।

वित्तपोषण पक्ष पर, सकल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 2024-25 में 24 अप्रैल से 25 जनवरी की अवधि के दौरान मजबूत रहा, जो भारत के मजबूत समष्टि आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों को दर्शाता है। हालांकि, इस अवधि के दौरान अधिक प्रत्यावर्तन और बाह्य एफडीआई के कारण शुद्ध एफडीआई में तेजी से कमी आई।¹⁶ वर्ष 2024-25 के दौरान भारत में शुद्ध एफपीआई अंतर्वाह 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसे ऋण अंतर्वाह से समर्थन मिला, जबकि इक्विटी खंड में शुद्ध बहिर्वाह दर्ज किया गया। दूसरी ओर, बाह्य वाणिज्यिक उधार और अनिवासी जमा में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक शुद्ध अंतर्वाह देखा गया।¹⁷

4 अप्रैल 2025 तक भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि 676.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी, जो लगभग 11 महीने का आयात कवर प्रदान करता है।¹⁸ कुल मिलाकर, भारत का बाह्य

¹⁵ जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान भारत का सेवा निर्यात वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 11.8 प्रतिशत बढ़ा।

¹⁶ अप्रैल-जनवरी 2024-25 में सकल एफडीआई अंतर्वाह 15.3 प्रतिशत बढ़कर 69.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि के दौरान 60.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-जनवरी 2024-25 में शुद्ध एफडीआई अंतर्वाह एक वर्ष पहले के 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया।

¹⁷ अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान भारत में बाह्य वाणिज्यिक उधार के तहत शुद्ध अंतर्वाह बढ़कर 15.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि एक वर्ष पहले यह 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। अप्रैल-जनवरी 2024-25 में अनिवासी जमाओं में 14.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का शुद्ध अंतर्वाह दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था। जनवरी 2025 और फरवरी 2025 के दौरान शुद्ध एफपीआई बहिर्वाह क्रमशः 6.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 4.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। हालांकि, मार्च 2025 में शुद्ध एफपीआई अंतर्वाह 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा।

क्षेत्र आघात- सह बना हुआ है क्योंकि प्रमुख संकेतक मजबूत बने हुए हैं।¹⁹

चलनिधि और वित्तीय बाजार की स्थितियाँ

जनवरी 2025 में प्रणालीगत चलनिधि घाटे में थी तथा चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत शुद्ध निवेश 23 जनवरी 2025 को 3.1 लाख करोड़ रुपये के शिखर पर पहुंच गया। हालांकि, लगभग 6.9 लाख करोड़ रुपये²⁰ की चलनिधि बढ़ाने वाले कई उपायों के परिणामस्वरूप, फरवरी-मार्च 2025 के दौरान प्रणालीगत चलनिधि घाटा कम हो गया और 29 मार्च 2025 को अधिशेष में बदल गया। मार्च के उत्तरार्ध में सरकारी व्यय में तेजी आने के साथ ही प्रणालीगत चलनिधि में और सुधार हुआ तथा 7 अप्रैल 2025 तक यह 1.5 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष पर पहुंच गई।

इन घटनाक्रमों को दर्शाते हुए, भारत औसत मांग दर (डबल्यूएसीआर) नरम हो गई और पिछली नीति बैठक के बाद से रेपो दर के आसपास बनी रही।²¹ 91-दिवसीय खजाना बिल दर की तुलना में 3-माह के सीपी और 3-माह के सीडी दरों का प्रसार भी मार्च के दूसरे पखवाड़े से कम हुआ है, जो चलनिधि की स्थिति में सुधार का संकेत देता है।²²

रिजर्व बैंक पर्याप्त प्रणाली चलनिधि प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम उभरती हुई चलनिधि और वित्तीय बाजार स्थितियों पर नज़र रखना जारी रखेंगे और पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय रूप से उचित उपाय करेंगे।

¹⁸ चार तिमाहियों (क्यू4: 2023-24 से क्यू3: 2024-25) के दौरान वास्तविक व्यापारिक आयात (बीओपी आधार पर) के आधार पर।

¹⁹ भारत का बाह्य ऋण और जीडीपी अनुपात दिसंबर 2024 के अंत में 19.1 प्रतिशत (मार्च 2024 के अंत में 18.5 प्रतिशत) रहा, जबकि शुद्ध अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) मार्च 2024 के अंत में जीडीपी के (-) 10.1 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2024 के अंत में जीडीपी के (-) 9.8 प्रतिशत हो गई।

²⁰ रिजर्व बैंक ने 8 ओएमओ खरीद नीलामियाँ आयोजित कीं, जिनसे ₹2.85 लाख करोड़ की चलनिधि लगाई गई। 3 टर्म वीआरआर नीलामियों से ₹1.83 लाख करोड़ की चलनिधि लगाई गई। 3 यूएसडी/ आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप नीलामियों ने अब तक ₹2.18 लाख करोड़ की चलनिधि लगाई गई। ₹40,000 करोड़ की राशि के लिए 2 ओएमओ खरीद नीलामियाँ अप्रैल 2025 के अंत में निर्धारित की गई हैं।

²¹ नीतिगत रेपो दर पर डबल्यूएसीआर का औसत स्प्रेड दिसंबर-जनवरी के दौरान 13 बीपीएस की तुलना में फरवरी-मार्च 2025 के दौरान 6 बीपीएस था।

²² मार्च 2025 के मध्य से सीडी और सीपी स्प्रेड का औसत क्रमशः 88 बीपीएस और 113 बीपीएस रहा, जबकि मार्च के पहले पखवाड़े में यह क्रमशः 143 बीपीएस और 112 बीपीएस था।

वित्तीय स्थिरता

बैंकिंग क्षेत्र की वित्तीय सुदृढ़ता मानदंड मजबूत बने हुए हैं।²³ बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि बफर विनियामक सीमा से काफी ऊपर है।²⁴ लाभप्रदता संकेतक भी स्वस्थ हैं जो प्रणाली की मजबूत परिचालन दक्षता को दर्शाते हैं।²⁵ इसी तरह, एनबीएफसी के प्रणाली -स्तरीय मानदंड भी मजबूत हैं।²⁶

अतिरिक्त उपाय

अब मैं बैंकिंग विनियमन, फिनटेक और भुगतान प्रणालियों से संबंधित छह अतिरिक्त उपायों की घोषणा करूंगा।

सबसे पहले, बाजार आधारित तंत्र के माध्यम से दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण को सक्षम करने का प्रस्ताव है। यह वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्चना एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (SARFAESI) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत मौजूदा एआरसी मार्ग के अतिरिक्त है।

दूसरा, सह-उधार पर मौजूदा दिशा-निर्देश वर्तमान में केवल बैंकों और एनबीएफसी के बीच की व्यवस्थाओं पर लागू हैं। इसके अलावा, वे प्राथमिकता क्षेत्र को उधार तक ही सीमित हैं। ऐसी उधार व्यवस्थाओं की विशाल क्षमता का दोहन करने के लिए, इन्हें सभी विनियमित संस्थाओं और सभी ऋणों - प्राथमिकता क्षेत्र या अन्य तक विस्तारित करने का प्रस्ताव है।

तीसरा, स्वर्ण आभूषणों और गहनों के संपार्श्विक पर ऋण, जिसे सामान्यतः स्वर्ण ऋण के रूप में जाना जाता है, विनियमित संस्थाओं द्वारा उपभोग और आय- अर्जन दोनों उद्देश्यों के लिए दिया जाता है। विभिन्न प्रकार की विनियमित संस्थाओं के लिए दिशानिर्देशों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, जहां तक संभव

हो, उनकी विभिन्न जोखिम- वहन क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए, हम ऐसे ऋणों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों और आचरण संबंधी पहलुओं पर व्यापक विनियम जारी करेंगे।

चौथा, विनियमित संस्थाओं में गैर-निधि आधारित सुविधाओं को नियंत्रित करने वाले विनियमों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए, हम व्यापक दिशा-निर्देश जारी करने का प्रस्ताव करते हैं। विनियमित संस्थाओं द्वारा आंशिक ऋण वृद्धि (पीसीई) से संबंधित निर्देशों को भी संशोधित करने का प्रस्ताव है। इससे बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए निधीयन स्रोतों के व्यापक होने की आशा है।

इन चार दिशा-निर्देशों और विनियमों का मसौदा आज सार्वजनिक परामर्श के लिए प्रकाशित किया जा रहा है। हम प्राप्त प्रतिक्रिया के आधार पर इन दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप देंगे।

अन्य दो घोषणाएं एनपीसीआई को बैंकों और अन्य हितधारकों के परामर्श से यूपीआई में व्यक्ति से व्यापारी के बीच लेनदेन की सीमा तय करने में सक्षम बनाने; और विनियामक सैंडबॉक्स की थीम- तटस्थ और 'ऑन-टैप' बनाने से संबंधित हैं। इन दोनों उपायों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक निदेश अलग से जारी किए जाएंगे।

समापन टिप्पणी

वैश्विक अर्थव्यवस्था असाधारण अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है। शोरगुल और अनिश्चितता भरे माहौल से संकेत निकालने में कठिनाई, नीति निर्माण के लिए चुनौतियां खड़ी करती है। फिर भी, मौद्रिक नीति यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कि अर्थव्यवस्था स्थिर बनी रहे।

हमारे संदर्भ में, जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, घरेलू संवृद्धि -मुद्रास्फीति प्रक्षेप पथ मांग करता है कि मौद्रिक नीति संवृद्धि सहायक हो, जबकि मुद्रास्फीति के मोर्चे पर सतर्क रहा जाए। हम एक गैर-मुद्रास्फीतिकारी संवृद्धि का लक्ष्य बना रहे हैं जो बेहतर मांग और आपूर्ति प्रतिक्रिया तथा सतत समष्टि आर्थिक संतुलन की नींव पर निर्मित है। पहले की तरह, हम अपनी प्रतिक्रिया में चुस्त और निर्णायक बने रहेंगे तथा ऐसी नीतियां लागू करेंगे जो स्पष्ट, सुसंगत, विश्वसनीय और अर्थव्यवस्था के सर्वोत्तम हित में हों।

धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।

²³ दिसंबर 2024 में प्रणाली-स्तरीय जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) 16.43 प्रतिशत था, जो विनियामक न्यूनतम स्तर से काफी ऊपर था। दिसंबर 2024 में सकल गैर-निष्पादित आस्ति (जीएनपीए) अनुपात 2.42 प्रतिशत पर दिसंबर 2023 की तुलना में 54 बीपीएस बेहतर हुआ। दिसंबर 2024 में विशेष उल्लेख खाता (एसएमए) -2 अनुपात 0.90 प्रतिशत था।

²⁴ दिसंबर 2024 तक चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) 130 प्रतिशत था।

²⁵ दिसंबर 2024 तक, प्रणाली स्तरीय आस्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए), इक्विटी पर प्रतिलाभ (आरओई) और शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) क्रमशः 1.37 प्रतिशत, 14.14 प्रतिशत और 3.49 प्रतिशत थे।

²⁶ दिसंबर 2024 में एनबीएफसी का कुल सीआरएआर 26.22 प्रतिशत और टियर I सीआरएआर 24.13 प्रतिशत था। जीएनपीए अनुपात दिसंबर 2023 में 2.70 प्रतिशत से बढ़कर दिसंबर 2024 में 2.53 प्रतिशत हो गया। आरओए दिसंबर 2023 में 3.11 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2024 में 2.86 प्रतिशत हो गया।

**मौद्रिक नीति वक्तव्य,
(अप्रैल 7-9) 2025-26**

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) का संकल्प
7 से 9 अप्रैल 2025

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2025-26 मौद्रिक नीति समिति का संकल्प 7 से 9 अप्रैल 2025*

मौद्रिक नीति निर्णय

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 54वीं बैठक 7 से 9 अप्रैल 2025 तक श्री संजय मल्होत्रा, गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। एमपीसी के सदस्य डॉ. नागेश कुमार, श्री सौगत भट्टाचार्य, प्रो. राम सिंह, डॉ. राजीव रंजन और श्री एम. राजेश्वर राव बैठक में शामिल हुए।

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक स्थिति के आकलन के पश्चात, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक घटाकर 6.00 प्रतिशत करने के लिए वोट किया। परिणामस्वरूप, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 5.75 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.25 प्रतिशत पर समायोजित हो जाएगी। यह निर्णय संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति के लिए +/- 2 प्रतिशत के दायरे में 4 प्रतिशत के मध्यम अवधि लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप है।

संवृद्धि और मुद्रास्फीति संभावना

वैश्विक आर्थिक संभावना तेजी से बदल रही है। हाल ही में व्यापार शुल्क संबंधी उपायों ने अनिश्चितताओं को बढ़ा दिया है जो सभी क्षेत्रों में आर्थिक संभावना पर छा गया जिससे वैश्विक संवृद्धि और मुद्रास्फीति के लिए नई चुनौतियां उत्पन्न हो गई हैं। वित्तीय बाजारों ने डॉलर सूचकांक में तेज गिरावट और इक्विटी में बिकवाली के साथ बॉण्ड प्रतिफल और कच्चे तेल की कीमतों में उल्लेखनीय नरमी के माध्यम से प्रतिक्रिया दी है।

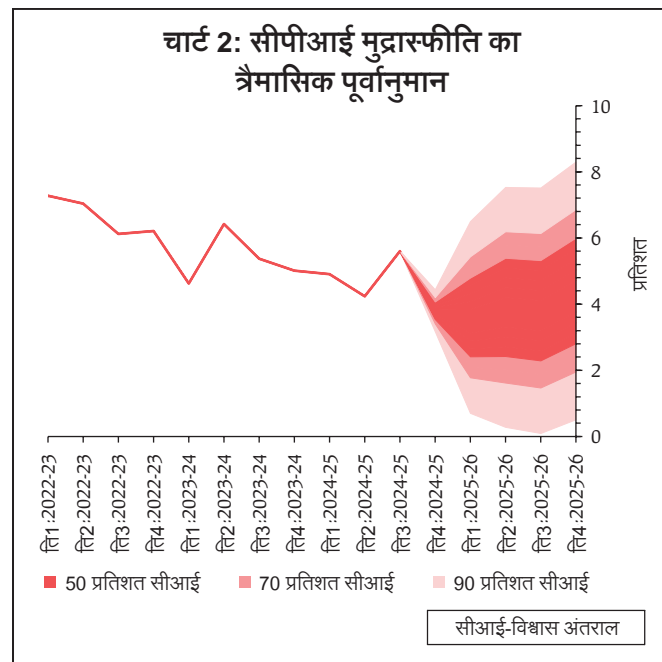
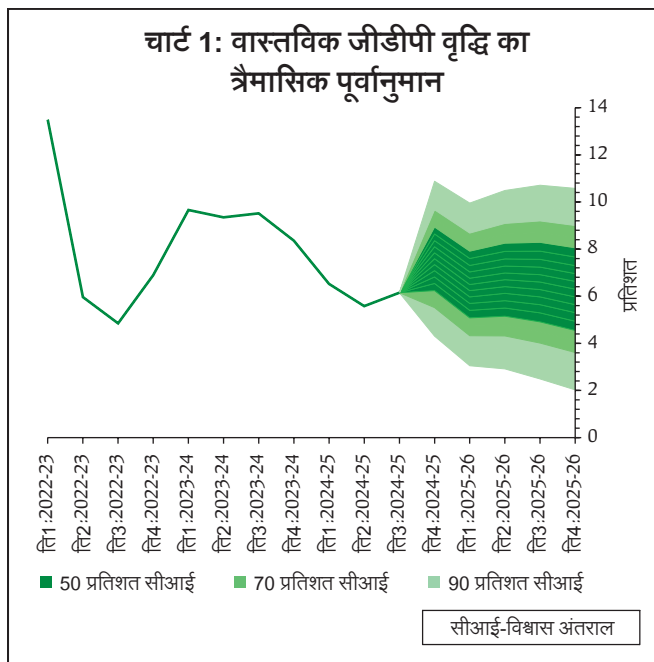
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) ने 2024-25 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) संवृद्धि का

अनुमान 6.5 प्रतिशत लगाया है, जो 2023-24 में 9.2 प्रतिशत के अलावा है। आगे चलकर, ग्रामीण क्षेत्रों से धारणीय मांग, शहरी खपत में प्रत्याशित बहाली, बढ़े हुए सरकारी पूंजीगत व्यय द्वारा समर्थित स्थिर पूंजी निर्माण के अपेक्षित सुधार, उच्चतर क्षमता उपयोग तथा कॉर्पोरेट्स और बैंकों के मजबूत तुलन पत्र से संवृद्धि को समर्थन मिलने की आशा है। मौजूदा समय में अनिश्चित प्रतीत होने वाले वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के कारण व्यापारिक निर्यात पर अधोगामी दबाव पड़ेगा, जबकि सेवा निर्यात में आघात-सहनीयता जारी रहने की आशा है। आपूर्ति पक्ष पर, जबकि कृषि की संभावनाएं उज्ज्वल दिखाई दे रही हैं, औद्योगिक गतिविधि में सुधार जारी है, और सेवा क्षेत्र के आघात सह रहने की आशा है। वैश्विक व्यापार व्यवधानों से होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियाँ अधोगामी जोखिम उत्पन्न कर रही हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी संवृद्धि अब 6.5 प्रतिशत अनुमानित है, जो पहली तिमाही में 6.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.3 प्रतिशत रहेगी। (चार्ट 1)। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति में कुल 1.6 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई, जो दिसंबर 2024 में 5.2 प्रतिशत से घटकर फरवरी 2025 में 3.6 प्रतिशत के निचले स्तर पर आ गई। इस वर्ष सब्जियों की कीमतों में मजबूत मौसमी सुधार के कारण, फरवरी में खाद्य मुद्रास्फीति 21 महीने के निचले स्तर 3.8 प्रतिशत पर आ गई। ईंधन समूह में अपस्फीति बनी रही। दिसंबर 2024 - जनवरी 2025 में स्थिर रहने के बाद मूल मुद्रास्फीति फरवरी 2025 में 4.1 प्रतिशत तक बढ़ गई, जो मुख्य रूप से स्वर्ण की कीमतों में तेज उछाल से प्रेरित थी।

खाद्य मुद्रास्फीति की संभावना निर्णायक रूप से सकारात्मक हो गई है। सब्जियों की कीमतों में पर्याप्त और व्यापक मौसमी सुधार हुआ है। रबी फसलों पर अनिश्चितताएं काफी कम हो गई हैं तथा दूसरे अग्रिम अनुमानों में पिछले वर्ष की तुलना में रिकॉर्ड गेहूं उत्पादन और प्रमुख दालों के अधिक उत्पादन की ओर इशारा किया गया है। खरीफ की मजबूत आवक के साथ, इससे खाद्य

* 9 अप्रैल 2025 को जारी किया जाएगा।



मुद्रास्फीति में टिकाऊ नरमी रहने की आशा है। तीन महीने और एक वर्ष आगे की अवधि के लिए मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं में तेज गिरावट से आगे चलकर मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को सुस्थिर करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट मुद्रास्फीति की संभावना के लिए शुभ संकेत है। वैश्विक बाजार की अनिश्चितताओं और प्रतिकूल मौसम संबंधी आपूर्ति व्यवधानों की पुनरावृत्ति की चिंताएं, मुद्रास्फीति प्रक्षेपवक्र के लिए ऊर्ध्वगामी जोखिम उत्पन्न करती हैं। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए और सामान्य मानसून की परिकल्पना करते हुए, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो पहली तिमाही में 3.6 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 3.9 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 3.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.4 प्रतिशत रहेगी। जोखिम समान रूप से संतुलित हैं।

मौद्रिक नीति निर्णयों का औचित्य

एमपीसी ने कहा कि मुद्रास्फीति वर्तमान में खाद्य मुद्रास्फीति में तेज गिरावट के समर्थन से लक्ष्य से नीचे है। इसके अलावा, मुद्रास्फीति की संभावना में निर्णायक सुधार हुआ है। अनुमानों के अनुसार, अब 12 महीने के क्षितिज पर 4 प्रतिशत के लक्ष्य

के साथ हेडलाइन मुद्रास्फीति के टिकाऊ संरेखण का अधिक विश्वास है। दूसरी ओर, चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण से बाधित, 2024-25 की पहली छमाही में निराशाजनक निष्पादन के बाद संवृद्धि अभी भी बहाली की राह पर है। यद्यपि जोखिम, संवृद्धि के आधारभूत अनुमानों के आसपास समान रूप से संतुलित हैं, वैश्विक अस्थिरता में हाल की तेजी के कारण अनिश्चितताएं उच्च स्तर पर बनी हुई हैं। ऐसी चुनौतीपूर्ण वैश्विक आर्थिक स्थितियों में, सौम्य मुद्रास्फीति और मध्यम संवृद्धि संभावना की मांग है कि एमपीसी संवृद्धि का समर्थन प्रदान करना जारी रखे। तदनुसार, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंक घटाकर 6.00 प्रतिशत करने के लिए वोट किया। इसके अलावा, एमपीसी ने अपने रुख को तटस्थ से बदलकर निभावकारी करने का भी निर्णय लिया। तथापि, एमपीसी ने कहा कि तेजी से उभरती परिस्थितियों के लिए आर्थिक संभावना की निरंतर निगरानी और आकलन की आवश्यकता है।

एमपीसी की इस बैठक का कार्यवृत्त 23 अप्रैल 2025 को प्रकाशित किया जाएगा।

एमपीसी की अगली बैठक 4 से 6 जून 2025 के दौरान निर्धारित है।

**मौद्रिक नीति वक्तव्य,
(अप्रैल 7-9) 2025-26**

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (I) विनियमन; (II) भुगतान प्रणाली; और (III) फिनटेक से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है।

I. विनियमन

1. दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण का ढांचा

विवेकपूर्ण ढंग से संरचित प्रतिभूतिकरण लेनदेन दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए एक सक्षमकर्ता हो सकता है क्योंकि इससे जोखिम वितरण में सुधार होने और ऋणदाताओं के लिए ऐसे एक्सपोज़रों से बाहर निकलने का मार्ग प्रदान करने की आशा है। इस उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2023 में दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण ढांचे पर एक चर्चा पत्र जारी किया था, ताकि ढांचे के विभिन्न पहलुओं पर बाजार सहभागियों से टिप्पणियां मांगी जा सकें। चर्चा पत्र पर हितधारकों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण के लिए ढांचे का मसौदा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया जा रहा है। इस ढांचे का उद्देश्य सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत वर्तमान एआरसी मार्ग के अलावा, बाजार-आधारित तंत्र के माध्यम से दबावग्रस्त आस्तियों के प्रतिभूतिकरण को सक्षम करना है।

2. सह-उधार व्यवस्था (सीएलए) का ढांचा

सह-उधार पर मौजूदा दिशा-निर्देश केवल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार के लिए बैंकों और एनबीएफसी के बीच व्यवस्थाओं पर लागू होते हैं। इस तरह की उधार पद्धतियों के विकास और एक व्यापक क्षेत्र की ऋण आवश्यकताओं को स्थायी तरीके से पूरा करने में इस तरह की उधार व्यवस्था की क्षमता को देखते हुए, सह-उधार के दायरे का विस्तार करने और आरई के बीच सभी प्रकार की सह-उधार व्यवस्थाओं के लिए एक सामान्य विनियामक ढांचा जारी करने का निर्णय लिया गया है। दिशानिर्देशों का मसौदा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया जा रहा है।

3. स्वर्ण आभूषणों के बदले उधार देने संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा

स्वर्ण आभूषणों और गहनों के संपार्श्विक के बदले ऋण, विनियमित संस्थाओं (आरई) द्वारा उपभोग और आय-अर्जन

दोनों उद्देश्यों के लिए दिए जाते हैं। ऐसे ऋणों के लिए समय-समय पर विवेकपूर्ण और आचरण संबंधी विनियमन जारी किए गए हैं और वे विभिन्न श्रेणियों के आरई के लिए अलग-अलग हैं। आरई की जोखिम लेने की क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए सभी आरई के लिए ऐसे विनियमनों को सुसंगत बनाने और साथ ही देखी गई कतिपय चिंताओं को दूर करने के उद्देश्य से, ऐसे ऋणों के लिए विवेकपूर्ण मानदंडों और आचरण संबंधी पहलुओं पर व्यापक विनियमन जारी करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में दिशानिर्देशों का मसौदा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया जा रहा है।

4. गैर-निधि आधारित सुविधाओं की समीक्षा

गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सुविधाएं जैसे गारंटी, साख्रपत्र, सह-स्वीकृति आदि, प्रभावी ऋण मध्यस्थता को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, साथ ही व्यापार लेनदेन सहित निर्बाध कारोबारी लेनदेन को सक्षम बनाती हैं। अब सभी विनियमित संस्थाओं में इन सुविधाओं को शामिल करने वाले दिशानिर्देशों को सुसंगत बनाने और समेकित करने का निर्णय लिया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों में आरई द्वारा आंशिक ऋण वृद्धि जारी करने संबंधी अनुदेशों की समीक्षा शामिल है, जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण के लिए निधीयन स्रोतों को व्यापक बनाना है। इस संबंध में दिशानिर्देशों का मसौदा सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया जा रहा है।

II. भुगतान प्रणाली

5. यूपीआई में लेनदेन की सीमा बढ़ाना

वर्तमान में, यूपीआई के लिए लेनदेन राशि, जिसमें व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) दोनों भुगतान शामिल हैं, की सीमा ₹1 लाख है, पी2एम भुगतान के विशिष्ट उपयोग मामलों को छोड़कर, जिनकी सीमा अधिक है, कुछ के लिए ₹2 लाख और अन्य के लिए ₹5 लाख है।

पारितंत्र को नए उपयोग मामलों के लिए कुशलतापूर्वक प्रतिक्रिया देने में सक्षम बनाने के लिए, यह प्रस्तावित है कि एनपीसीआई, बैंकों और यूपीआई पारितंत्र के अन्य हितधारकों के परामर्श से, उपयोगकर्ता की बदलती जरूरतों के आधार पर ऐसी सीमाओं की घोषणा और संशोधन कर सकता है। उच्चतर सीमाओं से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए उचित सुरक्षा उपाय किए जाएंगे। बैंकों को एनपीसीआई द्वारा घोषित सीमाओं

के भीतर अपनी आंतरिक सीमाएँ तय करने का विवेकाधिकार जारी रहेगा।

यूपीआई पर पी2पी लेनदेन की सीमा पहले की तरह ₹1 लाख ही रहेगी। एनपीसीआई को तदनुसार सूचित किया जाएगा।

III. फिनटेक

6. विषय तटस्थ विनियामक सैंडबॉक्स के अंतर्गत 'ऑन-टैप' आवेदन सुविधा

रिज़र्व बैंक 2019 से विनियामक सैंडबॉक्स (आरएस) ढांचे का संचालन कर रहा है, और अब तक चार विशिष्ट विषयगत कोहोर्ट की घोषणा की गई है और उन्हें पूरा किया गया है। बंद कोहोर्ट के विषय के लिए 'ऑन टैप' आवेदन सुविधा की घोषणा

अक्तूबर 2021 में की गई थी। आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्दिष्ट समय-सीमा के साथ पांचवें 'विषय तटस्थ' कोहोर्ट की भी अक्तूबर 2023 में घोषणा की गई थी, जो मई 2025 में बंद हो जाएगी। इस कोहोर्ट के अंतर्गत, रिज़र्व बैंक के विनियामक दायरे में किसी भी नवोन्मेषी उत्पाद या समाधान, यदि वह योग्य पाया जाता है, का परीक्षण किया जा सकता है। प्राप्त अनुभव और हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, अब विनियामक सैंडबॉक्स को 'विषय तटस्थ' और 'ऑन टैप' बनाने का प्रस्ताव है।

इस पहल से निरंतर नवाचार को बढ़ावा मिलने और तेजी से विकसित हो रहे फिनटेक/विनियामक परिदृश्य के साथ तालमेल बनाए रखने की आशा है। इस संबंध में अतिरिक्त विवरण अलग से सूचित किए जाएंगे।

मौद्रिक नीति वक्तव्य (अप्रैल 7-9) 2025-26

मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अप्रैल 2025

I. समष्टि-आर्थिक परिदृश्य

घरेलू आर्थिक परिदृश्य मजबूत समष्टि-आर्थिक आधार एवं बेहतर उपभोग मांग की बदौलत सुदृढ़ बना हुआ है। खाद्य मुद्रास्फीति का परिदृश्य अनुकूल होने की वजह से मुद्रास्फीति लक्ष्य के अनुरूप होने की उम्मीद है। व्यापार में अत्यधिक तनाव, अस्थिर वित्तीय बाजार, भू-राजनीतिक संघर्ष, और जलवायु परिवर्तन का परिदृश्य पर भारी प्रभाव पड़ता है। मौद्रिक नीति का उद्देश्य है कि वह अनुकूल समष्टि-आर्थिक परिस्थितियां उपलब्ध कराए जो मूल्य स्थिरता एवं सतत आर्थिक विकास को सुदृढ़ करे।

I.1 अक्तूबर 2024 एमपीआर से अब तक के प्रमुख घटनाक्रम

अक्तूबर 2024 में मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) जारी होने के बाद से, वैश्विक आर्थिक गतिविधि 2024 में सुदृढ़ बनी हुई है, हालांकि ऐतिहासिक औसत से नीचे, जिसमें उच्च आवृत्ति संकेतक 2025 में विकास की गति में मंदी का संकेत देते हैं। कई तरह के शुल्क लगाए जाने के कारण व्यापार संबंधी तनाव के बढ़ने से विकास के परिदृश्य को अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। भले ही हेडलाइन मुद्रास्फीति कम हो रही है, लेकिन अवस्फीति की सुस्त और असमान गति के कारण कई अर्थव्यवस्थाओं में लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। कोर मुद्रास्फीति (अर्थात्, खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) कम होने की वजह से हेडलाइन मुद्रास्फीति का गिरना अच्छा संकेत है, हालांकि लगातार उच्च सेवा मुद्रास्फीति का परिदृश्य पर भारी प्रभाव पड़ता है। देशों में मौद्रिक नीतिगत तौर-तरीकों में भिन्नता जारी है। एक साथ अत्यधिक सख्त चरण की तुलना में अब दर में कटौती को लेकर हिचकिचाहट और संरक्षित सिलसिला प्रगति पर है।

मौद्रिक नीति संबंधी बदलती उम्मीदों और टैरिफ युद्ध की आशंकाओं के कारण वित्तीय बाजार कशमकश में रहे हैं। भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं, व्यापार संबंधी तनाव के बढ़ने एवं पोर्टफोलियो निवेशकों के पीछे हटने के परिणामस्वरूप इक्विटी जनवरी 2025 की ऊंचाइयों से नीचे उतर गई। व्यापार युद्ध की आशंका के कारण मार्च के बाद से बिक्री और तेज हो गई है। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल 2024

की चौथी तिमाही में बढ़ गया, लेकिन तत्पश्चात मंदी की चिंताओं के कारण वृद्धि कम हो गई है। सोने की कीमतों में मजबूती जारी रही और 2025 के प्रत्येक महीने में मार्च तक नई ऊंचाइयों को प्राप्त किया। यूएस फेडरल रिजर्व द्वारा दर में ढील की विलंबित प्रत्याशाओं और नए यूएस प्रशासन की प्रत्याशित नीतियों के कारण यूएस डॉलर सूचकांक चौथी तिमाही में मजबूत हुआ, लेकिन कमजोर वृद्धि संबंधी प्रत्याशाओं और बढ़ी हुई व्यापार नीति अनिश्चितता के बीच जनवरी 2025 के मध्य से गिरने लगा है। वैश्विक कमोडिटी की कीमतें 2024 की चौथी तिमाही में थोड़ी कम हुईं, लेकिन 2025 की पहली तिमाही में तेजी से बढ़ीं, जो मुख्य रूप से धातुओं और कृषि कीमतों की वजह से थी। ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें दिसंबर 2024 के अंत से जनवरी 2025 के मध्य तक तेजी से बढ़ीं, जो रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंधों, टैरिफ लगाने के खतरों और ठंडे मौसम की स्थिति को दर्शाती हैं। तब से भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम में कमी और पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन प्लस (ओपेक+) से आपूर्ति में सुधार के बाद उसमें गिरावट आई है। अनिश्चित वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के कारण शुल्क लगाने के बाद ऊर्जा और धातु की कीमतों में गिरावट आई है।

घरेलू अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी दूसरे अग्रिम अनुमान (एसआई) के अनुसार 2024-25 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि निजी अंतिम उपभोग व्यय में मजबूत वृद्धि की बदौलत 6.5 प्रतिशत वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) रहने का अनुमान लगाया गया है। आपूर्ति पक्ष की बात करें तो, वास्तविक जीवीए (योजित सकल मूल्य) में वर्ष-दर-वर्ष 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें कृषि और सेवा क्षेत्रों की प्रमुख भूमिका थी। 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि को 6.2 प्रतिशत पर रखा गया था, जिसमें मजबूत निजी और सरकारी उपभोग व्यय की अहम भूमिका थी।

हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति, जो 2024-25 की पहली छमाही में औसतन 4.6 प्रतिशत थी, अक्तूबर 2024 में बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई, लेकिन तब से वह कम होने लगी है और फरवरी 2025 में मुद्रास्फीति का आंकड़ा 3.6 प्रतिशत पर सात महीने के निचले स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें सब्जी की कीमतों में मुद्रास्फीति तेजी से घटने की मुख्य भूमिका

है। कोर मुद्रास्फीति, जो 2024-25 की पहली छमाही में औसतन 3.3 प्रतिशत थी, हालांकि, 2024-25 की दूसरी छमाही (फरवरी तक) में औसतन 3.8 प्रतिशत तक बढ़ गई। इसके विपरीत, खाद्य मुद्रास्फीति जो अक्तूबर-दिसंबर 2024 के दौरान औसतन 8.5 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बनी रही, फरवरी 2025 में घटकर 3.8 प्रतिशत हो गई। तथापि, ईंधन मुद्रास्फीति में अपस्फीति कम हुई।

फरवरी 2023 से नीतिगत रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर बनाए रखने के बाद, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 2024-25 की दूसरी छमाही में मौद्रिक सहजता शुरू की है। समिति ने अक्तूबर 2024 में रुख को समायोजन वापस लेने से बदलकर तटस्थ किया और फरवरी 2025 की बैठक में नीतिगत रेपो दर में 25 आधार अंकों (बीपीएस) की कटौती करते हुए 6.25 प्रतिशत कर दिया। दिसंबर 2024 में, रिजर्व बैंक ने बैंकों द्वारा रखे जाने वाले आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में 50 बीपीएस तक की कटौती की।

मौद्रिक नीति समिति की बैठकें : अक्तूबर 2024 - मार्च 2025

अक्तूबर 2024 में जब एमपीसी की बैठक हुई, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था ने सुदृढ़ता दर्शाया, हालांकि तीव्र भू-राजनीतिक संघर्ष, भू-आर्थिक दरार, वित्तीय बाजार में अस्थिरता और उच्च सरकारी कर्ज की वजह से गिरावट का जोखिम जारी रहा। मुद्रास्फीति कम हो रही थी लेकिन भिन्न-भिन्न देशों में वृद्धि-मुद्रास्फीति की गतिशीलता में बढ़ते विचलन के परिणामस्वरूप मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाएं अलग-अलग थीं। घरेलू स्तर पर, वास्तविक जीडीपी ने 2024-25 की पहली तिमाही में 6.7 प्रतिशत, व-द-व, की वृद्धि दर्ज की, जिसमें निजी खपत और निवेश की मुख्य भूमिका थी। औसत से अधिक वर्षा, खरीफ की बेहतर बुवाई और जलाशय के अच्छे-खासे स्तर की बदौलत कृषि के लिए परिदृश्य सकारात्मक रहा। विनिर्माण गतिविधियों ने घरेलू मांग में सुधार, कम इनपुट लागत और एक सहायक नीतिगत परिवेश की बदौलत जोर पकड़ा, जबकि सेवा क्षेत्र की वृद्धि मजबूत रही। मजबूत बैंक ऋण वृद्धि, उच्च क्षमता उपयोग, बैंकों के मजबूत बैलेंस शीट और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च पर सरकार के जोर की बदौलत निवेश गतिविधियों में तेजी रहने की उम्मीद है। 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.2 प्रतिशत अनुमानित थी। हेडलाइन मुद्रास्फीति जून में 5.1 प्रतिशत से तेजी से गिरकर जुलाई और

अगस्त में क्रमशः 3.6 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत हो गई। ईंधन में अपस्फीति और गहरी हो गई लेकिन कोर मुद्रास्फीति बढ़ गई। निकट अवधि में क्षणिक वृद्धि के बाद, हेडलाइन मुद्रास्फीति कम होने की उम्मीद थी। अप्रत्याशित मौसम संबंधी घटनाओं और भू-राजनीतिक संघर्षों के बदत्तर होने के कारण प्रमुख अपसाइड जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति के अनुमान को 4.5 प्रतिशत पर बनाए रखा गया। एमपीसी ने, 5-1 के बहुमत से, नीतिगत रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया, जिसमें उभरते मुद्रास्फीति परिदृश्य के प्रति सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अच्छी तरह से संतुलित वृद्धि-मुद्रास्फीति गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए, एमपीसी ने, वृद्धि का समर्थन करते हुए, मुद्रास्फीति को टिकाऊ आधार पर लक्ष्य के अनुरूप करने पर स्पष्ट रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए सर्वसम्मति से रुख को समायोजन वापस लेने से बदलकर तटस्थ करने का निर्णय लिया ताकि मुद्रास्फीति और वृद्धि के परिदृश्य की निगरानी और आकलन करने के लिए लचीलापन प्रदान किया जा सके और उभरती स्थिति के अनुसार कदम उठाया जा सके।

दिसंबर 2024 की बैठक के समय, वैश्विक अर्थव्यवस्था स्थिर थी और मुद्रास्फीति कम हो रही थी। हालांकि, भू-राजनीतिक जोखिम और नीतिगत अनिश्चितता-विशेष रूप से व्यापार नीतियों के परिणामस्वरूप वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई। घरेलू मोर्चे पर, 2024-25 की दूसरी तिमाही में 5.4 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि अपेक्षा से बहुत कम थी क्योंकि निजी उपभोग और निवेश के विस्तार में कमी आई थी, हालांकि तिमाही के दौरान सरकारी खर्च में सुधार हुआ। वास्तविक जीवीए वृद्धि औद्योगिक गतिविधि की वृद्धि में मंदी से प्रभावित हुई, जो विनिर्माण कंपनियों के कमजोर प्रदर्शन, खनन गतिविधि में संकुचन और बिजली की मांग में कमी दर्शाती है। 2024-25 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.6 प्रतिशत अनुमानित थी। हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति अक्तूबर में ऊपरी सहन सीमा को पार कर 6.2 प्रतिशत पर पहुंच गई जिसकी मुख्य वजह खाद्य कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि थी। अक्तूबर में कोर मुद्रास्फीति में भी वृद्धि दर्ज की गई। 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति के अनुमान में संशोधन करते हुए उसे बढ़ाकर 4.8 प्रतिशत कर दिया गया। एमपीसी ने दीर्घकालिक उच्च आर्थिक विकास के लिए मूल्य स्थिरता को आधार के रूप में बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया और वह अर्थव्यवस्था के समग्र हित में वृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन को बहाल

करने के लिए प्रतिबद्ध रहा। इसने 4-2 के बहुमत से नीतिगत रेपो दर को 6.5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया और तटस्थ रुख जारी रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया।

फरवरी 2025 की बैठक से पहले, वैश्विक आर्थिक परिदृश्य चुनौतीपूर्ण बना रहा, जिसमें वैश्विक विकास ऐतिहासिक औसत से नीचे रहा, हालांकि उच्च आवृत्ति संकेतकों ने विश्व व्यापार में विस्तार के साथ-साथ सुदृढ़ता का संकेत दिया। अवस्फीति की गति सेवा मूल्य मुद्रास्फीति से प्रभावित हुई। डॉलर के मजबूत होने से उभरते बाजारों की मुद्राओं पर दबाव पड़ा और वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव आया। घरेलू मोर्चे पर, एनएसओ के प्रथम अग्रिम अनुमान (एफएई) के अनुसार 2024-25 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ना अनुमानित था, जो निजी उपभोग में सुधार पर आधारित था। आने वाले समय में, बेहतर रबी संभावनाएं और औद्योगिक गतिविधि में सुधार 2025-26 में विकास का समर्थन करने की उम्मीद है। 2025-26 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.7 प्रतिशत अनुमानित थी। हेडलाइन मुद्रास्फीति अक्तूबर के उच्च स्तर से नवंबर और दिसंबर में क्रमिक रूप से कम हुई जिसमें खाद्य मुद्रास्फीति में कमी की अहम भूमिका थी, और इसमें सब्जियों की कीमतों में गिरावट से सहायता मिली। कोर मुद्रास्फीति कम रही और ईंधन अपस्फीति जारी रही। खरीफ के अच्छे उत्पादन, सब्जियों की कीमत कम होने और रबी फसल की अनुकूल संभावनाओं की वजह से आने वाले समय में मुद्रास्फीति संबंधी दबाव कम होने की उम्मीद है, जबकि वैश्विक वित्तीय बाजारों में जारी अनिश्चितता, ऊर्जा की कीमतों में अस्थिरता और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से जोखिम और बढ़ने का पता चलता है। 2024-25 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति के अनुमान को 4.8 प्रतिशत पर बनाए रखा गया था। साथ ही, यह मानते हुए कि अगले साल मानसून सामान्य रहेगा, 2025-26 के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत अनुमानित है। एमपीसी ने पाया कि मुद्रास्फीति गिरने की राह पर है जो प्रमुख रूप से खाद्य मूल्यों के अनुकूल परिदृश्य एवं पूर्व में किए गए मौद्रिक नीतिगत उपायों के प्रभाव की बदौलत है तथा 2025-26 में और कम होने की उम्मीद है, एवं इस प्रकार धीरे-धीरे लक्ष्य के अनुरूप होगा। लिहाजा, उभरती वृद्धि-मुद्रास्फीति गतिशीलता विकास के लिए आसरा बनी। तदनुसार, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 25 बीपीएस से घटाकर 6.25 प्रतिशत करने के लिए मतदान किया। एमपीसी ने तटस्थ रुख

सारणी I.1 मौद्रिक नीति समिति की बैठकें और नीति दर मतदान पद्धति

देश	नीतिगत बैठकें : अक्तूबर 2024 – मार्च 2025			
	कुल बैठकें	पूर्ण सहमति वाली बैठकें	बगैर पूर्ण सहमति की बैठकें	नीतिगत दर में बदलाव (आधार अंक)
ब्राजील	4	4	0	350
चिली	4	4	0	-50
कोलंबिया	4	0	4	-75
चेक गणराज्य	4	2	2	-50
हंगरी*	6	3	2	0
भारत	3	1	2	-25
जापान	4	2	2	25
दक्षिण अफ्रीका	3	1	2	-50
स्वीडन	4	4	0	-100
थाईलैंड	3	1	2	-50
यूके	4	0	4	-50
यूएस	4	3	1	-50

टिप्पणी: *: कुल बैठकों की संख्या छह है। हालांकि, पिछली बैठक (25 मार्च 2025) का कार्यवृत्त अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है।

स्रोत: केंद्रीय बैंक की वेबसाइटें।

जारी रखने का भी निर्णय लिया ताकि उभरते समष्टि-आर्थिक परिवेश के मद्देनजर लचीलापन बनाए रखा जा सके।

एमपीसी के मतदान का स्वरूप प्रत्येक सदस्यों के आकलन, प्रत्याशाओं और नीतिगत प्राथमिकताओं में विविधता को दर्शाता है - एक ऐसी विशेषता जो अन्य केंद्रीय बैंकों के मतदान स्वरूप में भी नज़र आती है (सारणी I.1)। जहां अधिकांश आई और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) ने नीति में ढील दी, वहीं अवस्फीति की धीमी गति को लेकर चिंताओं और उस पर भी भू-राजनीतिक मोर्चे एवं व्यापार में दरार पड़ने संबंधी घटनाक्रमों के मद्देनजर नीतिगत अनिश्चितताओं के बीच दर में कटौती का सिलसिला कम होने का पता चला। जापान और ब्राजील जैसे कुछ अपवाद थे जिन्होंने मुद्रास्फीति को अपने संबंधित लक्ष्यों के आसपास रखने के लिए मौद्रिक सख्ती को जारी रखा।

समष्टि-आर्थिक परिदृश्य

अध्याय II और III में 2024-25 की दूसरी छमाही (अक्तूबर 2024 – मार्च 2025) के दौरान मुद्रास्फीति और आर्थिक गतिविधि से संबंधित समष्टि-आर्थिक घटनाक्रमों का विश्लेषण किया गया है। आधारभूत धारणाओं के संदर्भ में, कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों ने अक्तूबर-दिसंबर 2024 के दौरान गिरावट का पैटर्न प्रदर्शित किया, जो वैश्विक तेल की मांग में अपेक्षाकृत मामूली वृद्धि के साथ-साथ गैर-ओपेक देशों से मजबूत आपूर्ति

सारणी 1.2 : अनुमान हेतु आधारभूत धारणाएं

संकेतक	एमपीआर अक्तूबर 2024	एमपीआर अप्रैल 2025
कच्चा तेल (भारतीय बास्केट)	छ2:2024-25 के दौरान प्रति बैरल यूएस\$ 80	2025-26 के दौरान प्रति बैरल यूएस\$ 70
विनिमय दर	छ2:2024-25 के दौरान ₹83.50/यूएस\$	2025-26 के दौरान ₹86/यूएस\$
मानसून	2025-26 के लिए सामान्य	2025-26 के लिए सामान्य
वैश्विक वृद्धि	2024 में 3.2 प्रतिशत 2025 में 3.3 प्रतिशत	2025 में 3.1 प्रतिशत 2026 में 3.0 प्रतिशत
राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	बीई 2024-25 के भीतर बना रहेगा केंद्र : 4.9 संयुक्त : 7.3	बीई 2025-26 के भीतर बना रहेगा केंद्र : 4.4 संयुक्त : 7.1
पूर्वानुमान अवधि के दौरान घरेलू समष्टि-आर्थिक / संरचनात्मक नीतियां	कोई बड़ा परिवर्तन नहीं	कोई बड़ा परिवर्तन नहीं

टिप्पणियां : 1. भारतीय कच्चे तेल का बास्केट एक व्युत्पन्न मूल्यमान को दर्शाता है जिसमें खट्टा ग्रेड (ओमान और दुबई औसत) और मीठा ग्रेड (ब्रेंट) कच्चा तेल शामिल हैं।
2. यहां माना गया विनिमय दर पथ आधारभूत अनुमानों को उत्पन्न करने के उद्देश्य से है और विनिमय दर के स्तर पर किसी 'राय' को इंगित नहीं करता है। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्रा बाजार में अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित करने के उद्देश्य से निर्देशित होता है और न कि विनिमय दर के आसपास किसी विशिष्ट स्तर और/या दायरे के द्वारा।
3. बीई : बजट अनुमान।
4. संयुक्त राजकोषीय घाटे से तात्पर्य केन्द्र और राज्यों की सम्मिलित राजकोषीय घाटे से है।

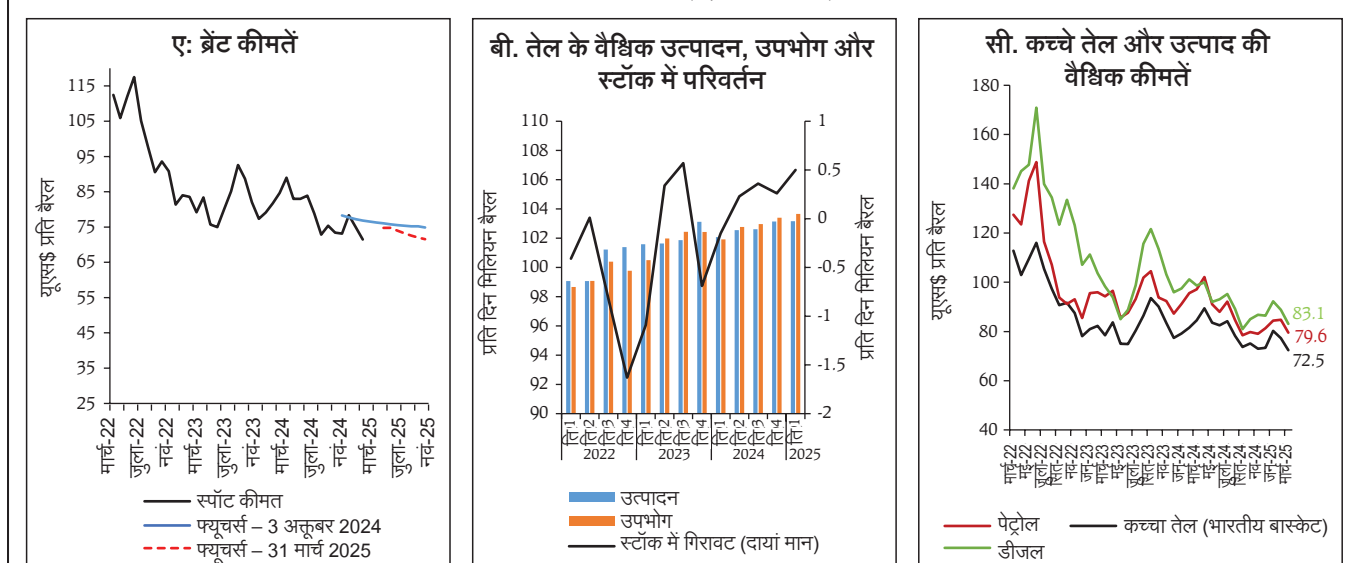
स्रोत : आरबीआई अनुमान; बजट दस्तावेज; अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ); एवं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी)।

के कारण लगभग 74 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के आसपास घट-बढ़ रही थी। रूस पर प्रतिबंधों के प्रभाव पर चिंता और ईरान

पर बढ़ते प्रतिबंधों की अटकलों के साथ-साथ संभावित आपूर्ति व्यवधानों की आशंकाओं के परिणामस्वरूप जनवरी की शुरुआत में कीमत बढ़कर लगभग 84 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई। तब से, कीमतें फरवरी में धीरे-धीरे घटीं और हाल ही में मार्च 2025 में गिरकर अपने निम्नतम स्तर पर पहुंचीं, जो मुख्य रूप से ओपेक द्वारा उत्पादन को बढ़ाने की घोषणा के साथ-साथ भू-राजनीतिक जोखिम प्रीमियम कम होने और पर्याप्त इन्वेंट्री की वजह से थी। भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से परिदृश्य को काफी अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है (चार्ट 1.1ए और 1.1बी)। वैश्विक पेट्रोलियम उत्पाद की कीमतों और कच्चे तेल की कीमतों के बीच अंतर कम हो गया (चार्ट 1.1सी)। इन कारकों के मद्देनजर, कच्चे तेल की कीमत (भारतीय बास्केट) के लिए आधारभूत धारणा 2025-26 के दौरान घटकर 70 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गई है (सारणी 1.2)।

दूसरा, भारतीय रुपये (₹) की सांकेतिक विनिमय दर में 2024-25 की दूसरी छमाही में अब तक ₹83.8-87.6 प्रति अमेरिकी डॉलर के दायरे में दो-तरफा उतार-चढ़ाव देखा गया, जिसमें 2025 में मार्च की शुरुआत तक मूल्यहास पूर्वाग्रह था। अक्तूबर 2024 की शुरुआत से अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के परिणामस्वरूप रुपये सहित ईएमई की मुद्राओं का मूल्यहास हुआ और वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई। हालांकि, जनवरी

चार्ट 1.1: कच्चे तेल की कीमतें



स्रोत : ब्लूमबर्ग; यूएस एनर्जी इन्फार्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (ईआईए); और पेट्रोलियम प्लानिंग एंड अनैलिसिस सेल।

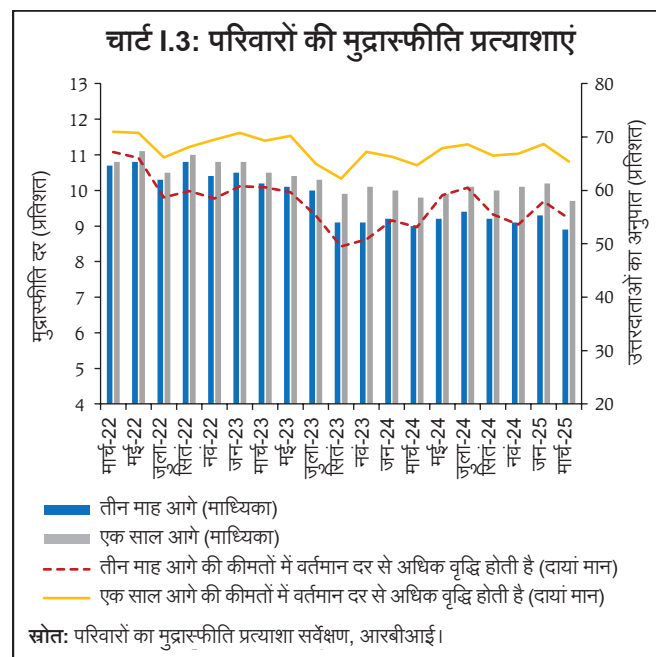
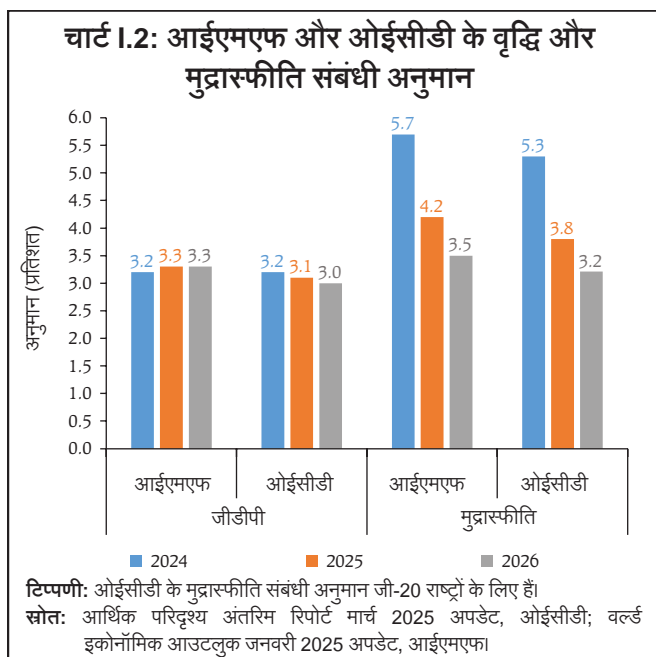
के मध्य से, डॉलर गिरने लगा क्योंकि उच्च आवृत्ति संकेतक सुस्त वृद्धि और उच्च नीतिगत अनिश्चितता का संकेत दे रहे थे। तदनुसार, ईएमई मुद्राओं में सुधार हुआ है, हालांकि पूरी तरह से नहीं। अमेरिकी डॉलर में घट-बढ़, वैश्विक पूंजी प्रवाह में उतार-चढ़ाव और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के आसपास की अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए, विनिमय दर के लिए आधारभूत धारणा को अक्टूबर 2024 एमपीआर में ₹83.50 के मुकाबले संशोधित कर ₹86 प्रति अमेरिकी डॉलर कर दिया गया।

तीसरा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) द्वारा मार्च 2025 में जारी अपनी आर्थिक आउटलुक अंतरिम रिपोर्ट में वैश्विक विकास 2025 में 3.1 प्रतिशत और 2026 में 3.0 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा जनवरी 2025 के अपडेट में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार वैश्विक अवस्फीति जारी है, मुद्रास्फीति 2025 में घटकर 4.2 प्रतिशत और 2026 में 3.5 प्रतिशत होने की उम्मीद है (चार्ट 1.2)। वैश्विक व्यापार विकास (वस्तुओं और सेवाओं को मिलाकर) 2026 में 3.3 प्रतिशत तक पहुंचने से पहले 2024 में 3.4 प्रतिशत से घटकर 2025 में 3.2 प्रतिशत होने का

अनुमान है। तथापि, अमेरिकी प्रशासन के हालिया पारस्परिक टैरिफ घोषणाओं और संबद्ध नीतिगत अनिश्चितताओं ने वैश्विक वृद्धि और मुद्रास्फीति के समक्ष बाधाएं उत्पन्न की हैं।

1.2 मुद्रास्फीति परिदृश्य

2024-25 की दूसरी छमाही में अब तक (फरवरी तक), हेडलाइन मुद्रास्फीति अक्टूबर 2024 में कुछ समय के लिए ऊपरी सहनशीलता दायरे के पार चली गई, लेकिन तब से खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट की वजह से उसमें कमी आई है। रिजर्व बैंक के मार्च 2025 दौर के परिवारों के सर्वेक्षण¹ में, शहरी परिवारों की तीन महीने और एक साल आगे की मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाएं जनवरी 2025 दौर की तुलना में 40 बीपीएस और 50 बीपीएस घटकर क्रमशः 8.9 प्रतिशत और 9.7 प्रतिशत हो गईं। पिछले दौर की तुलना में दोनों अवधि के लिए सामान्य मूल्य स्तर में वर्तमान दर से अधिक की वृद्धि की उम्मीद करने वाले उत्तरदाताओं के अनुपात में गिरावट आई है (चार्ट 1.3)। इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना ठीक है कि विभिन्न आर्थिक एजेंट भिन्न-भिन्न कारकों के आधार पर अपनी मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाएं बनाते हैं (बॉक्स 1.1)।



¹ रिजर्व बैंक का मुद्रास्फीति प्रत्याशा संबंधी परिवारों का सर्वेक्षण मार्च 2021 से 19 शहरों (पिछले दौर में 18 शहरों) में किया जा रहा है और मार्च 2025 दौर के परिणाम 6,091 परिवारों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।

बॉक्स 1.1: विषम एजेंटों की मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को क्या प्रभावित करता है ?

मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं को सहारा देना मौद्रिक नीति निरूपण में, विशेष रूप से मुद्रास्फीति-लक्षित रूपरेखा में सर्वोपरि है। अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि ब्याज दरों में सकारात्मक बदलाव के कारण मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं में गिरावट आती है (गोसाल्वेस एवं अन्य, 2025)। हालांकि, विभिन्न एजेंटों की मौद्रिक प्रतिक्रियाएं अलग-अलग होती हैं, अर्थात्, भिन्न-भिन्न श्रेणी के उत्तरदाता मौद्रिक नीति में बदलाव के प्रति अलग-अलग प्रतिक्रिया देते हैं। रेपो दर में वृद्धि का वित्तीय और व्यावसायिक क्षेत्र के एजेंटों की मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं पर गंभीर, लेकिन ट्रेड यूनियनों पर विपरीत प्रभाव पाया गया है (म्लांगेनी और बुथेलेजी, 2023)।

भारतीय संदर्भ में इस स्थिति की जांच करने के लिए, एक वेक्टर त्रुटि सुधार मॉडल (वीईसीएम) का उपयोग प्रमुख संकेतकों और विभिन्न आर्थिक एजेंटों जैसे वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारियों, दैनिक कामगारों और स्व-नियोजित श्रमिकों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के बीच संबंधों का पता लगाने के लिए किया जाता है, जिसके लिए निम्नानुसार जनवरी 2017 से जनवरी 2025 तक द्विमासिक मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के आंकड़ों का उपयोग किया जाता है :

$$\Delta x_t = \Gamma * x_{t-1} + \epsilon_t, \text{ where } \Gamma = \alpha * \beta^c$$

जहां x_t एंडोजेनस वेरीअबलज का वेक्टर है, α समायोजन गुणांक है और β^c कोइटीग्रेटिंग वेक्टर है (जो वेरीअबलज के बीच दीर्घकालिक संबंध को परिभाषित करता है) और ϵ_t त्रुटि टर्म है।

मॉडल की परिभाषा इस प्रकार है :

$$\Delta Y_{t+1} = \alpha * (Y_t + \beta_1 * wacr_{t-1} + \beta_2 * inflation_{t-1} + \beta_3 * govt_share_{t-1} + \beta_4 * ln_crude_oil_t + c) + \epsilon_t$$

जहां Y_t वित्तीय क्षेत्र कर्मचारियों, दैनिक कामगारों, और स्व-नियोजित की एक वर्ष आगे की मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाएं हैं, $wacr$ मौद्रिक नीति को दर्शाती भारित औसत मांग दर है; $inflation$ सीपीआई मुद्रास्फीति है; $govt_share$ जीडीपी में सरकारी व्यय का हिस्सा है और ln_crude_oil वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों के नैचुरल लॉगरिदम को दर्शाता है जो ब्रेंट, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (डब्ल्यूटीआई) स्पॉट और दुबई फतेह का औसत है। यूनिट रूट टेस्ट से पता चलता है कि सभी वेरीअबल्स ऑर्डर 1 के एकीकृत हैं। उपयुक्त लैंग लेन्ड मानदंडों का उपयोग करते हुए, जोहानसन कोइटीग्रेटिंग टेस्ट वेरीअबल्स के बीच एक सह-संबंध पाता है।

परिणाम बताते हैं कि मौद्रिक नीति में बदलाव का विभिन्न समूहों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर विभेदक प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाएं वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारियों और स्व-नियोजित के लिए लंबे समय में नीतिगत ब्याज दर में बदलाव के साथ नकारात्मक रूप से जुड़ी हुई पाई गई हैं। इसके अलावा, वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारियों

सारणी 1: वीईसी मॉडल के दीर्घकालिक अनुमान

वेरीअबल	वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारी	दैनिक कामगार	स्व-नियोजित
डब्ल्यूएसीआर(-1)	-0.297* (0.113)	-0.260 (0.136)	-0.407* (0.121)
इन्फ्लेशन(-1)	0.443** (0.095)	0.529*** (0.115)	0.526*** (0.102)
जीओवीटी_शेयर(-1)	0.053 (0.056)	-0.229** (0.067)	-0.059 (0.060)
इन_क्रूड_ऑइल	1.248 (0.509)	4.127*** (0.617)	3.901*** (0.546)
कान्स्टन्ट	2.451 (1.987)	-5.017 (2.409)	-5.977 (2.131)
एरर करेक्शन, α	-0.904** (0.132)	-0.278* (0.094)	-0.417* (0.125)
आर-स्क्वार्ड	0.503	0.158	0.193
जोहानसन कोइटीग्रेटिंग टेस्ट फॉर नं. ऑफ सी.ई.	2	2	2
ऑब्जर्वेशन्स	49	49	49

कोष्ठकों में मानक त्रुटियां।

* $p < 0.10$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$

सी.ई. कोइटीग्रेटिंग इक्वेशन्स को दर्शाता है।

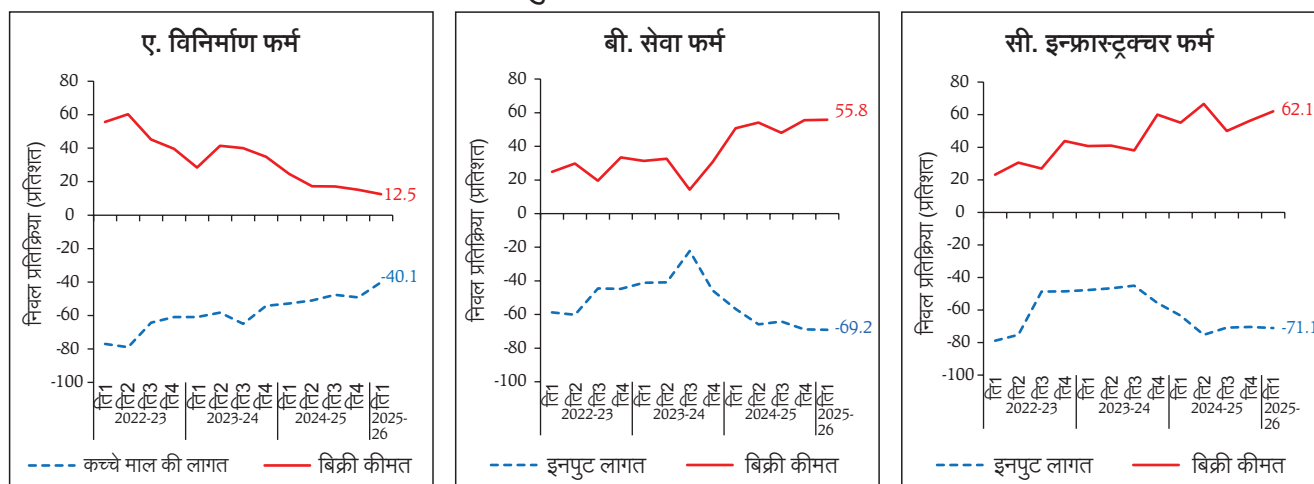
स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

में अन्य समूहों की तुलना में उच्च समायोजन कारक पाया गया है, जो दीर्घकालिक स्थिर स्थिति से वास्तविक मुद्रास्फीति में किसी भी विचलन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया का संकेत देता है। पूर्व की मुद्रास्फीति सभी समूहों के लिए मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के गठन में सकारात्मक प्रभाव डालती है जो दृढ़ता दर्शाती है। इसके विपरीत, कच्चे तेल की कीमतें केवल स्व-नियोजित और दैनिक कामगारों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को प्रभावित करती हैं (सारणी 1)। कुल मिलाकर, निष्कर्ष बताते हैं कि विभिन्न आर्थिक एजेंटों की मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं का गठन क्रॉस-कंट्री अनुभव की पुष्टि करने वाले विविध कारकों द्वारा नियंत्रित होता है।

संदर्भ :

- गोसाल्वेस, एम., रोड्रिग्स, एम., और जेंटा, एफ (2025)। “मॉनिटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेडेशनस : हाई-फ्रीक्वेन्सी एविडेन्स फ्रम ब्राजील”, आईएमएफ वर्किंग पेपर WP/25/48.
- म्लांगेनी, टी., और बुथेलेजी, ई. एम (2023)। “मॉनिटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेडेशनस : इम्पैक्ट एंड कॉजल एनैलिसिस ऑफ हीटरोजेनस इकोनॉमिक एजेन्ट्स एक्सपेक्टेडेशन इन साउथ अफ्रीका”, जर्नल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक्स, 27: 1.

चार्ट 1.4: कच्चे माल/इनपुट की लागत और बिक्री कीमत संबंधी प्रत्याशाएं



टिप्पणी : निवल प्रतिक्रिया आशावाद रिपोर्ट करने वाले और निराशावाद रिपोर्ट करने वाले उत्तरदाताओं के योग के बीच का अंतर है। निवल प्रतिक्रिया का रेंज -100 से 100 है। उत्तरदाता फर्मों के नजरिए से निवल प्रतिक्रिया के धनात्मक / ऋणात्मक मान को आशावादी / निराशावादी माना जाता है। इसलिए, बिक्री कीमतों के उच्च धनात्मक मान उत्पादन कीमतों में वृद्धि का संकेत देते हैं जबकि कच्चे माल की लागत/ इनपुट लागत के लिए कम मान उच्च इनपुट कीमत दबाव और इसके विपरीत का संकेत देते हैं।

स्रोत : औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण एवं सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर परिदृश्य सर्वेक्षण, आरबीआई।

रिजर्व बैंक के औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण के जनवरी-मार्च 2025 दौर में शामिल विनिर्माण फर्मों को पिछली तिमाही की तुलना में 2025-26 की पहली तिमाही में कच्चे माल की लागत से दबाव कम होने और बिक्री मूल्य में वृद्धि घटने की उम्मीद है (चार्ट 1.4ए)।² सेवा क्षेत्र की कंपनियां और इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्म दोनों 2025-26 की पहली तिमाही में उच्च इनपुट लागत दबाव और उच्च आउटपुट कीमत की उम्मीद करते हैं (चार्ट 1.4बी और 1.4सी)।³ मार्च 2025 के क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) सर्वेक्षण में, विनिर्माण फर्मों की इनपुट कीमतों में पिछले महीने की तुलना में वृद्धि हुई और सेवा फर्मों के मामले में गिरावट आई जबकि दोनों के लिए आउटपुट कीमतों में गिरावट आई।

मार्च 2025 में रिजर्व बैंक द्वारा सर्वेक्षण किए गए पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं ने सीपीआई मुद्रास्फीति 2024-25 की तीसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत से घटकर चौथी तिमाही में 3.9 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया। वे उम्मीद करते हैं कि यह 2025-26 की चौथी तिमाही में 4.5 प्रतिशत तक बढ़ने से पहले 2025-26 की तीसरी तिमाही तक लगभग 3.9-4.0 प्रतिशत रहेगी (चार्ट 1.5ए और सारणी 1.3)।⁴ कोर मुद्रास्फीति (अर्थात्, खाद्य और पेय पदार्थ, पान, तंबाकू एवं नशीले पदार्थ, और ईंधन तथा बिजली

को छोड़कर सीपीआई) 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान 4.0 प्रतिशत रहने की उम्मीद है, उसके बाद, यह 2025-26 की तीसरी तिमाही तक लगभग 4.2-4.3 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है।

पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं की दीर्घकालिक मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं - जो उनके 5 और 10 साल आगे की प्रत्याशाओं से मापी जाती हैं - वर्तमान दौर में क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 4.3 प्रतिशत पर हैं (चार्ट 1.5बी)।

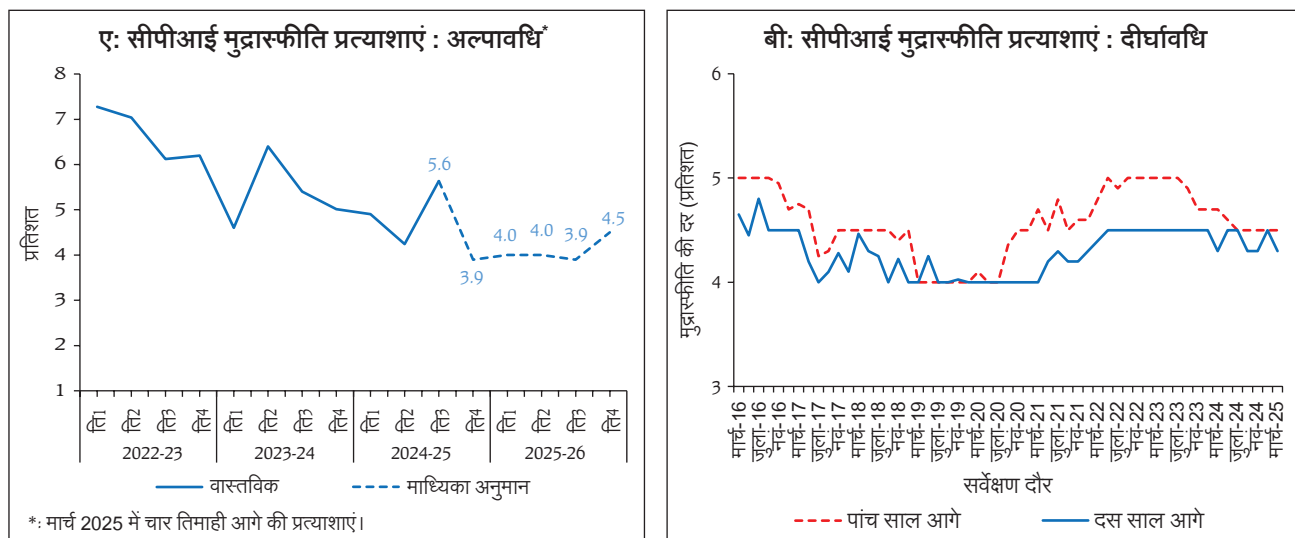
भविष्य में, मुद्रास्फीति का परिदृश्य कई कारकों, वैश्विक और घरेलू दोनों द्वारा निश्चित होगा। जोरदार खरीफ फसल आवक की बंदौलत खाद्य मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रह सकती है, जो आशाजनक रबी फसल के साथ मिलकर मुद्रास्फीति के परिदृश्य के लिए अच्छा है। कृषि संबंधी केंद्रीय बजट प्रस्ताव और राजकोषीय समेकन के प्रति प्रतिबद्धता से मुद्रास्फीति परिदृश्य और सुदृढ़ हुआ है। हालांकि, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता, ऊर्जा की कीमतों में अस्थिरता, प्रतिकूल मौसम की घटनाएं, बढ़ती वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला दबाव और निरंतर भू-राजनीतिक संघर्ष प्रमुख जोखिम बने हुए हैं।

² औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण के जनवरी-मार्च 2025 दौर के परिणाम 1,310 कंपनियों की प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।

³ सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर परिदृश्य सर्वेक्षण के जनवरी-मार्च 2025 दौर के सर्वेक्षण में शामिल 725 सेवा कंपनियों और 154 इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्मों पर आधारित।

⁴ रिजर्व बैंक के पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं के सर्वेक्षण के मार्च 2025 दौर में 45 पैनालिस्टों ने भाग लिया।

चार्ट 1.5: पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं की मुद्रास्फीति प्रत्याशाएं



स्रोत: पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता सर्वेक्षण, आरबीआई; और राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

प्रारंभिक स्थितियों, भविष्योन्मुखी सर्वेक्षणों के संकेतों एवं समय-शृंखला और संरचनात्मक मॉडल⁵ के अनुमानों को ध्यान

सारणी 1.3: अनुमान – रिजर्व बैंक और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ता

	(प्रतिशत)		
	2024-25	2025-26	2026-27
रिजर्व बैंक का आधारभूत अनुमान			
मुद्रास्फीति	4.7*	4.0	4.3
वास्तविक जीडीपी वृद्धि	6.5@	6.5	6.7
पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का औसत अनुमान			
मुद्रास्फीति, ति4 (व-द-व)	3.9	4.5	-
वास्तविक जीडीपी वृद्धि	6.4	6.5	6.6
सकल घरेलू बचत (जीएनडीआई का प्रतिशत)	30.2	30.4	30.3
सकल पूंजी निर्माण (जीडीपी का प्रतिशत)	31.0	30.7	31.1
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की ऋण वृद्धि	11.5	12.3	13.5
संयुक्त सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	7.8	7.4	7.1
केंद्र सरकार सकल राजकोषीय घाटा (जीडीपी का प्रतिशत)	4.8	4.4	4.3
रेपो दर (समाप्त-अवधि)	6.25	5.75	-
91-दिनों के ट्रेजरी बिलों पर प्रतिफल (समाप्त-अवधि)	6.5	6.0	6.4
10-साल की केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिफल (समाप्त-अवधि)	6.6	6.4	6.5
समग्र भुगतान शेष (बिलियन यूएस\$)	4.1	17.0	24.1
पण्य निर्यात वृद्धि	-0.2	3.5	5.0
पण्य आयात वृद्धि	4.6	4.5	5.5
चालू खाता शेष (जीडीपी का प्रतिशत)	-0.8	-1.0	-1.0

टिप्पणी: जीएनडीआई: सकल राष्ट्रीय प्रयोज्य आय।

@: एनएसओ द्वितीय अग्रिम अनुमान।

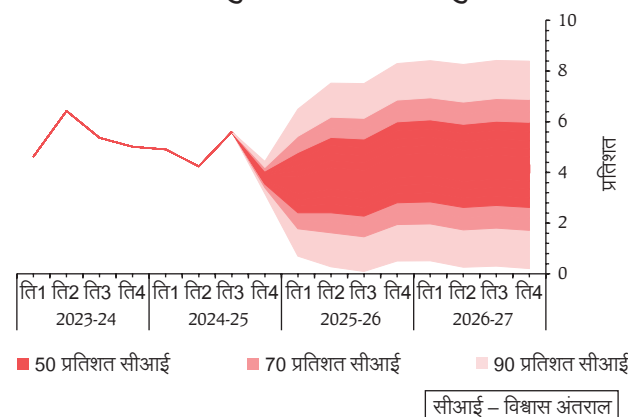
*: 2024-25 (फरवरी तक) में औसत सीपीआई मुद्रास्फीति

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान; और पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण (मार्च 2025)।

में रखते हुए, सीपीआई मुद्रास्फीति 2025-26 में औसतन 4.0 प्रतिशत – पहली तिमाही में 3.6 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 3.9 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 3.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जिसमें जोखिम समान रूप से संतुलित हैं (चार्ट 1.6 और सारणी 1.3)। वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति के लिए 50 प्रतिशत और 70 प्रतिशत विश्वास अंतराल क्रमशः 2.8-6.0 प्रतिशत और 1.9-6.9 प्रतिशत हैं। वर्ष 2026-27 के लिए, यह मानते हुए कि मानसून सामान्य रहेगा और आगे कोई बाह्य या नीतिगत आघात नहीं लगेगा, संरचनात्मक मॉडल अनुमानों से संकेत मिलता है कि मुद्रास्फीति औसतन 4.3 प्रतिशत - पहली तिमाही में 4.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 4.3 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 4.4 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 4.3 प्रतिशत रहेगी। वर्ष 2026-27 की चौथी तिमाही में हेडलाइन मुद्रास्फीति के लिए 50 प्रतिशत और 70 प्रतिशत विश्वास अंतराल क्रमशः 2.6-6.0 प्रतिशत और 1.7-6.9 प्रतिशत हैं।

आधारभूत पूर्वानुमान कई अपसाइड और डाउनसाइड जोखिमों के अधीन हैं। अपसाइड जोखिम निरंतर भू-राजनीतिक संघर्ष और परिणामी आपूर्ति व्यवधान; ऊर्जा की कीमतों में अस्थिरता; और प्रतिकूल मौसम की घटनाओं से उत्पन्न होता

⁵ जोइस जॉन, दीपक कुमार, आशिष थॉमस जॉर्ज, प्रतीक मित्रा, मनीष कपूर और माइकल देवब्रत पात्र (2023), "अ रीकैलिब्रेटेड क्वार्टरली प्रोजेक्शन मॉडल (क्यूपीएम 2.0) फार इंडिया", भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, फरवरी खंड LXXVII(2), पीपी.59-77.

चार्ट I.6: सीपीआई मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान (व-द-व)


टिप्पणी: फैन चार्ट आधारभूत अनुमान पथ के आसपास अनिश्चितता को दर्शाता है। आधारभूत अनुमान सारणी I.2 में निर्धारित धारणाओं पर आधारित हैं। गहरा लाल छायांकित क्षेत्र 50 प्रतिशत विश्वास अंतराल को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि 50 प्रतिशत संभावना है कि वास्तविक परिणाम गहरे लाल छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाई गई सीमा के भीतर होगा। इसी तरह, 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत विश्वास अंतराल के लिए, क्रमशः 70 प्रतिशत और 90 प्रतिशत संभावना है कि वास्तविक परिणाम संबंधित छायांकित क्षेत्रों द्वारा दर्शाई गई सीमा में होंगे।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

है। डाउनसाइड जोखिम भू-राजनीतिक संघर्षों के जल्द समाधान; राजकोषीय समेकन एवं ऋण पथ का पालन; वैश्विक मांग में कमी की स्थिति में वैश्विक कच्चे तेल एवं कमोडिटी की कीमतें और कम होने; तथा आपूर्ति की स्थिति में सुधार से उत्पन्न हो सकता है।

I.3 वृद्धि परिदृश्य

उपभोग में सुधार और सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ाने से घरेलू आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई हैं। निजी खपत में वृद्धि, कृषि गतिविधियों में तेजी, सेवा क्षेत्र की सतत सुदृढ़ता, उच्च क्षमता उपयोग, बैंकों और कंपनियों की मजबूत बैलेंस शीट और पूंजीगत व्यय पर सरकार का निरंतर जोर विकास के परिदृश्य के लिए अच्छा है। बढ़ते संरक्षणवादी उपायों की वजह से वैश्विक व्यापार के बारे में अनिश्चितता, लगातार भू-राजनीतिक तनाव, बढ़ती आपूर्ति श्रृंखला दबाव और अस्थिर वैश्विक वित्तीय स्थिति, हालांकि, परिदृश्य को अनिश्चित बनाती है।

भविष्योन्मुखी सर्वेक्षणों के प्रमुख संदेशों की बात करें तो, उपभोक्ता विश्वास (वर्तमान स्थिति सूचकांक) निराशावादी के संदर्भ में पिछले दौर की तुलना में मार्च 2025 में बेहतर हुआ, जो सभी सर्वेक्षण मापदंडों⁶ में मनोभाव में सुधार से प्रेरित था। आने वाले वर्ष के लिए उपभोक्ताओं का आशावाद, जिसे भावी प्रत्याशा

चार्ट I.7: उपभोक्ता विश्वास


सूचकांक द्वारा मापा जाता है, और मजबूत हुआ तथा आशावादी क्षेत्र में अपनी सुदृढ़ता बनाए रखा (चार्ट I.7)।

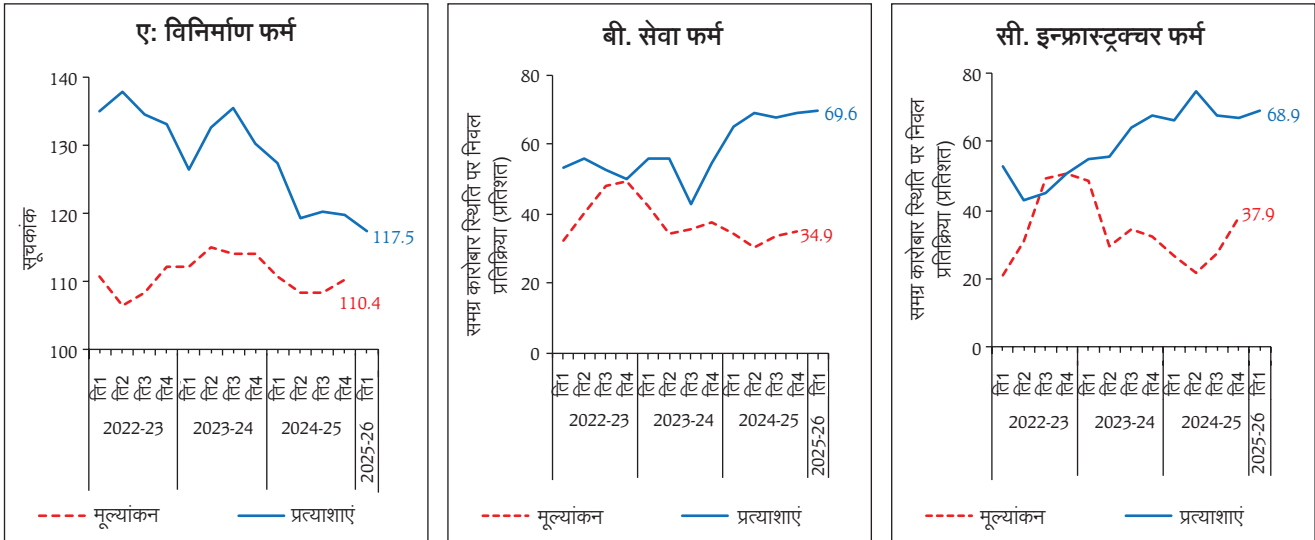
रिजर्व बैंक के औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण के परिणामों से पता चलता है कि 2025-26 की पहली तिमाही के लिए विनिर्माण क्षेत्र में कारोबार संबंधी आशावाद मामूली रूप से कम हुआ, जो आंशिक रूप से मौसमी है (चार्ट I.8ए)। दूसरी ओर, सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनियों, 2025-26 की पहली तिमाही में समग्र कारोबार स्थिति के बारे में आशावादी बनी रहीं (चार्ट I.8बी और I.8सी)।

अन्य एजेंसियों द्वारा हाल में किए गए सर्वेक्षणों से पिछले दौर के सापेक्ष कारोबार प्रत्याशाओं के बारे में भिन्न-भिन्न धारणाओं का पता चलता है (सारणी I.4)। मार्च 2025 के पीएमआई सर्वेक्षण में, विनिर्माण फर्म आने वाले वर्ष के बारे में सकारात्मक बने रहे, हालांकि सेवा फर्मों के मनोभाव में कमी आई।

रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के मार्च 2025 दौर में शामिल पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं ने 2024-25 की अंतिम तिमाही के दौरान वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.0 प्रतिशत रहने की उम्मीद की। वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही से चौथी तिमाही के दौरान विकास दर 6.5-6.7 प्रतिशत रहने की उम्मीद है (चार्ट I.9 और सारणी I.3)।

⁶ रिजर्व बैंक का उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण मार्च 2021 से 19 शहरों (पिछले दौर में 13 शहरों) में किया जा रहा है और मार्च 2025 दौर के परिणाम 6,021 उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।

चार्ट 1.8: कारोबार मूल्यांकन और प्रत्याशाएं



स्रोत : औद्योगिक परिवृश्य सर्वेक्षण एवं सेवा और इन्फ्रास्ट्रक्चर परिवृश्य सर्वेक्षण, आरबीआई ।

वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2024-25 की तीसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत थी जो दूसरी तिमाही के 5.6 प्रतिशत की तुलना में अधिक थी। आधारभूत धारणाओं, सर्वेक्षण के संकेतकों और मॉडल पूर्वानुमानों को ध्यान में रखते हुए, वास्तविक जीडीपी वृद्धि 2025-26 में 6.5 प्रतिशत – पहली तिमाही में 6.5 प्रतिशत; दूसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत; और तीसरी तिमाही में 6.6 प्रतिशत तथा

चौथी तिमाही में 6.3 प्रतिशत होने की उम्मीद है - इस आधारभूत पथ के आसपास जोखिम समान रूप से संतुलित हैं (चार्ट 1.10 और सारणी 1.3)। वर्ष 2026-27 के लिए, यह मानते हुए कि मानसून सामान्य रहेगा और कोई बाह्य या नीतिगत आघात नहीं लगेगा, संरचनात्मक मॉडल अनुमान संकेत देते हैं कि वास्तविक जीडीपी वृद्धि 6.7 प्रतिशत रहेगी, जो पहली तिमाही में 6.5 प्रतिशत, दूसरी तिमाही में 6.4 प्रतिशत, तीसरी तिमाही में 6.8 प्रतिशत और चौथी तिमाही में 6.8 प्रतिशत रहेगी।

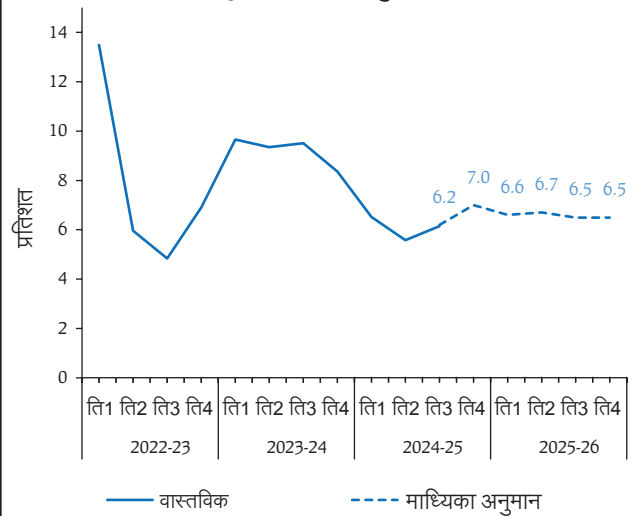
सारणी 1.4: कारोबार प्रत्याशा सर्वेक्षण

मद	एनसीआईआर कारोबार विश्वास सूचकांक (जनवरी 2025)	फिक्की समग्र कारोबार विश्वास सूचकांक (नवंबर 2024)	डन और ब्रैडस्ट्रीट संयुक्त कारोबार आशावाद सूचकांक (अप्रैल 2025)	सीआईआई कारोबार विश्वास सूचकांक (मार्च 2025)
सूचकांक का वर्तमान स्तर	138.4	62.5	120.2	63.7
पिछले सर्वेक्षण के अनुसार सूचकांक	134.3	67.3	114.4	66.2
% परिवर्तन (ति-द-ति) आनुक्रमिक	3.0	-7.1	5.1	-3.8
% परिवर्तन (व-द-व)	8.5	-6.6	11.2	-6.8

टिप्पणियाँ : 1. एनसीआईआर : राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद।
2. फिक्की : भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ।
3. सीआईआई : भारतीय उद्योग महापरिसंघ।
4. डन और ब्रैडस्ट्रीट संयुक्त कारोबार आशावाद सूचकांक ति1:2025-26 के लिए है, सीआईआई कारोबार विश्वास सूचकांक ति4:2024-25 के लिए है, फिक्की समग्र कारोबार विश्वास सूचकांक ति2:2024-25 के लिए है, और एनसीआईआर कारोबार विश्वास सूचकांक ति3:2024-25 के लिए है।

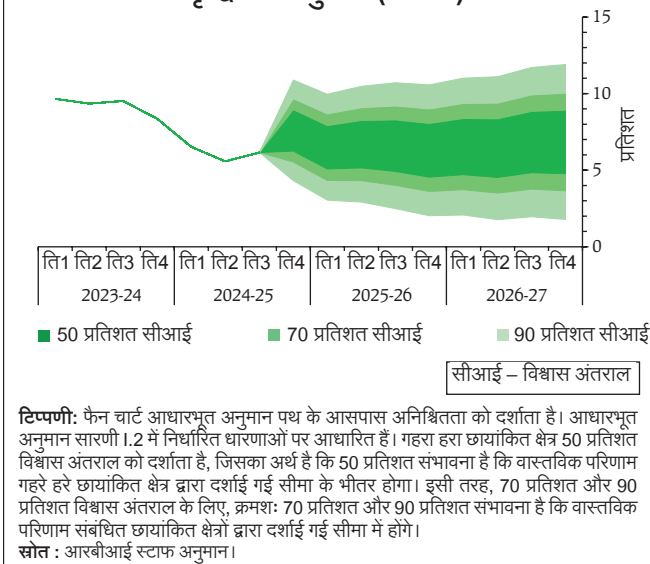
स्रोत : एनसीआईआर, फिक्की, सीआईआई एवं भारतीय डन और ब्रैडस्ट्रीट सूचना सेवा प्रा. लि.

चार्ट 1.9: पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का वास्तविक जीडीपी वृद्धि संबंधी अनुमान



स्रोत : पेशेवर पूर्वानुमानकर्ताओं का सर्वेक्षण, आरबीआई और राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय।

चार्ट 1.10: वास्तविक जीडीपी में वृद्धि का अनुमान (व-द-व)



इस आधारभूत विकास पथ के लिए अपसाइड और डाउनसाइड जोखिम हैं। कॉर्पोरेट निवेश चक्र में बहाली; कारोबार संबंधी मनोभाव में सुधार; वैश्विक अवस्फीति में तेजी; वैश्विक व्यापार संबंधी मुद्दों का त्वरित समाधान; वैश्विक कमोडिटी की कीमत लगातार घटने; और भू-राजनीतिक संघर्षों के जल्द समाधान से अपसाइड जोखिम पैदा होते हैं। इसके विपरीत, उच्च टैरिफ सहित संरक्षणवादी नीतियों के कारण व्यापार में बढ़ते दरार; भू-राजनीतिक तनाव का और बढ़ना; अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अस्थिरता; अक्सर मौसम संबंधी गड़बड़ी; और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं से आधारभूत विकास पथ के लिए डाउनसाइड जोखिम पैदा होते हैं।

1.4 जोखिम संतुलन

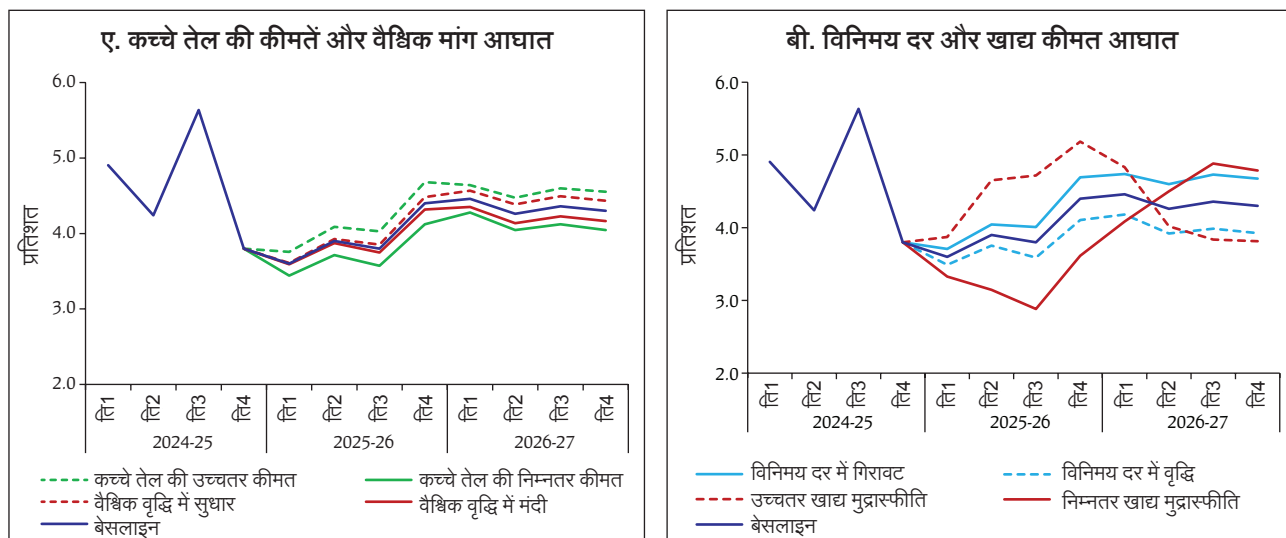
वृद्धि और मुद्रास्फीति के आधारभूत अनुमान प्रमुख घरेलू और वैश्विक समष्टि-आर्थिक वेरीअबल्स के संभावित पथ से संबंधित कुछ एक धारणाओं पर आधारित हैं जो सारणी 1.2 में दिए गए हैं। तथापि, ये आधारभूत धारणाएं प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाई गई संरक्षणवादी व्यापार नीतियों की वजह से पारस्परिक एवं जवाबी टैरिफ, दीर्घकालिक भू-राजनीतिक संघर्षों, वैश्विक वित्तीय और कमोडिटी बाजारों में अस्थिरता तथा

प्रतिकूल जलवायु घटनाओं की संभावना से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितताओं के अधीन हैं। इस पृष्ठभूमि में, यह खंड मुद्रास्फीति और वृद्धि के आधारभूत अनुमान के आसपास जोखिम संतुलन का आकलन करने के लिए समान वैकल्पिक परिदृश्य तलाशता है।

(i) वैश्विक वृद्धि संबंधी अनिश्चितताएं

वैश्विक आर्थिक गतिविधि 2024 की दूसरी छमाही में स्थिर रही, हालांकि कुछ एशियाई और यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में पाई गई सुस्त वृद्धि से प्रभावित हुई क्योंकि विनिर्माण और व्यापार निर्यात में कमजोरी ने संयुक्त राज्य अमेरिका में वृद्धि की मजबूत गति को बराबर कर दिया। हालांकि, आने वाले समय में, वैश्विक वृद्धि बहुत अनिश्चितताओं से ग्रस्त है। प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार तनाव और भू-राजनीतिक संघर्षों से वैश्विक वित्तीय बाजारों में अनिश्चितता, वैश्विक व्यापार में मंदी और आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान पैदा होने की संभावनाएं हैं। इसके अतिरिक्त, पारस्परिक टैरिफ सहित संरक्षणवादी व्यापार नीतियां वैश्विक व्यापार में और दरार पैदा करेंगी एवं वृद्धि की संभावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगी जिससे कारोबार की इनपुट लागत बढ़ने की संभावना है। प्रमुख केंद्रीय बैंक भी अवस्फीति के अंतिम मील को प्राप्त करने में मौद्रिक नीतिगत कार्रवाइयों की गति और दिशा में भिन्नता ला सकते हैं, जिससे वैश्विक वित्तीय बाजारों में उच्च अस्थिरता पैदा हो सकती है नतीजतन ईएमई पर स्पिलओवर प्रभाव पड़ सकता है। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य राजकोषीय स्थिरता संबंधी चिंताओं, अत्यधिक खराब मौसम की घटनाओं और तकनीकी व्यवधानों की विपरीत परिस्थितियों के अधीन है। यदि इनमें से कुछ परिदृश्य प्रकट होते हैं, और यदि वैश्विक वृद्धि बेसलाइन में अनुमानित से 100 बीपीएस कम हो जाती है, तो घरेलू वृद्धि और मुद्रास्फीति बेसलाइन अनुमानों की तुलना में क्रमशः लगभग 30 बीपीएस और 15 बीपीएस कम हो सकती है। तथापि, यदि प्रमुख आर्थिक शक्तियों के बीच व्यापार संबंधी मुद्दों के त्वरित समाधान की वजह से वैश्विक व्यापार में तेजी से सुधार होता है और आगे चलकर सौम्य मुद्रास्फीति परिदृश्य के मद्देनजर मौद्रिक नीति में समान रूप से उदारता बरती जाती है

चार्ट I.11: आधारभूत मुद्रास्फीति पथ पर जोखिम परिदृश्यों का प्रभाव



स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

तो वैश्विक वृद्धि संभावनाएं बेहतर हो सकती हैं। यदि वैश्विक वृद्धि बेसलाइन के सापेक्ष 50 बीपीएस अधिक है, तो घरेलू वृद्धि और मुद्रास्फीति क्रमशः लगभग 15 बीपीएस और 7 बीपीएस अधिक हो सकती है (चार्ट I.11ए और I.12ए)।

(ii) कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें

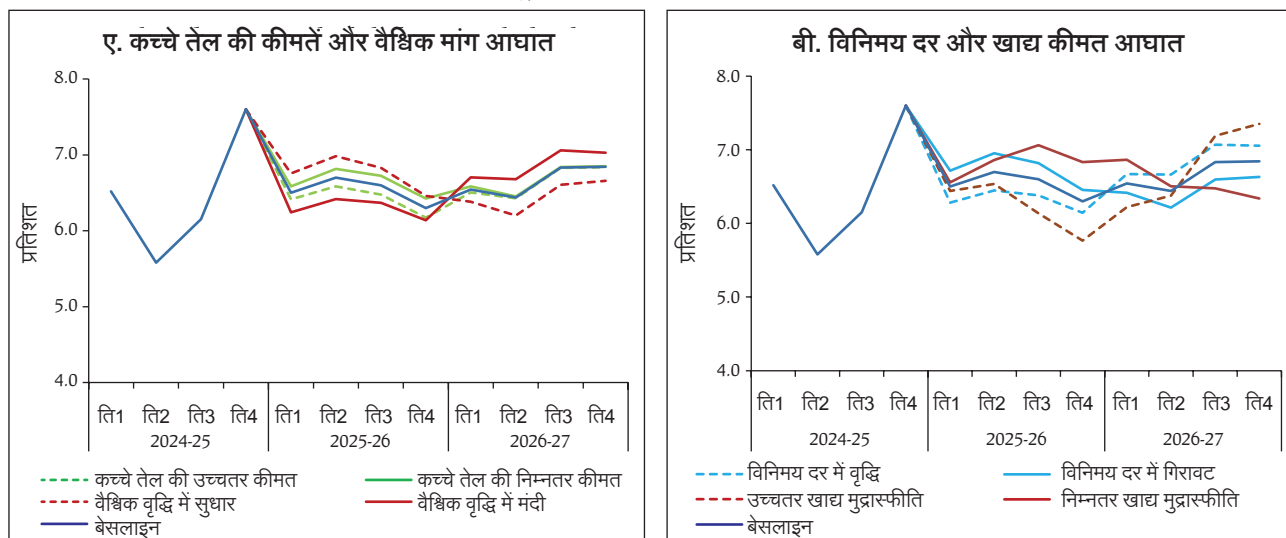
वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों ने गिरावट का रुझान दर्शाया, जिसमें ब्रेंट क्रूड अक्टूबर 2024 की शुरुआत में 82 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के उच्च स्तर से गिरकर मार्च 2025 में औसतन 73 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गया है। इसके विपरीत, कमजोर वैश्विक मांग की स्थिति, ओपेक+ और गैर-ओपेक देशों से निरंतर आपूर्ति में वृद्धि और भू-राजनीतिक संघर्षों के सुव्यवस्थित समाधान के प्रभाव से कच्चे तेल की कीमत कम होने की संभावना है। इस परिदृश्य में, यदि कच्चे तेल की कीमतें बेसलाइन के सापेक्ष 10 प्रतिशत तक गिरती हैं, तो मुद्रास्फीति लगभग 30 बीपीएस तक कम हो सकती है, जिससे भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि में 15 बीपीएस की बढ़त हो सकती है। वैश्विक मांग में सुधार और भू-राजनीतिक तनाव जारी रहने के कारण तेल आपूर्ति में अंकुश से कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे परिदृश्य

में, जब कच्चे तेल की कीमतें बेसलाइन अनुमान से 10 प्रतिशत अधिक होती हैं और घरेलू उत्पाद की कीमतों पर इसका पूरा पास-थ्रू होने की स्थिति में, घरेलू मुद्रास्फीति 30 बीपीएस तक बढ़ सकती है और वृद्धि लगभग 15 बीपीएस तक कम हो सकती है (चार्ट I.11ए और I.12ए)।

(iii) विनिमय दर

अक्टूबर 2024-मार्च 2025 के दौरान अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये में गिरावट आई, जो मुख्य रूप से वैश्विक व्यापार में व्यवधानों, अमेरिकी डॉलर की मजबूती और 'सुरक्षा के लिए उड़ान' के मद्देनजर पूंजी बहिर्वाह के कारण अनिश्चितताओं को दर्शाती है। आगे बढ़ते हुए, वित्तीय बाजार ने वर्तमान में जो सोच रखा था उसकी अपेक्षा अमेरिकी फेडरल रिजर्व की प्रतिबंधात्मक मौद्रिक नीति से ईएमई आस्तियों का आकर्षण और कम हो सकता है। बढ़ते व्यापार संबंधी संरक्षणवाद, मुद्रा युद्ध के खतरे और कच्चे तेल की उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतें भी कुछ ऐसे कारक हैं जिससे भारतीय रुपये पर नीचे गिरने का दबाव पैदा हो सकता है। इस परिदृश्य में, यदि बेसलाइन के सापेक्ष भारतीय रुपये में 5 प्रतिशत मूल्यहास होता है, तो मुद्रास्फीति लगभग 35

चार्ट I.12: आधारभूत वृद्धि पथ पर जोखिम परिदृश्यों का प्रभाव



बीपीएस तक बढ़ सकती है, जबकि जीडीपी वृद्धि को अल्पावधि में व्यापार चैनल के माध्यम से लगभग 25 बीपीएस तक लाभ हो सकता है। दूसरी ओर, भारतीय अर्थव्यवस्था निरंतर सुदृढ़ता दर्शाती है जिसमें मुद्रास्फीति संबंधी परिदृश्य स्थिर है और वैश्विक मांग स्थितियों के पुनरुत्थान में योगदान करने की उम्मीद है। इन घटनाक्रमों के साथ-साथ व्यापार संरक्षणवाद के तीव्र समाधान और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं द्वारा मौद्रिक नीति में उम्मीद से जल्द ढील देने से भारतीय रुपए में मजबूती आएगी। इस परिदृश्य में, यदि बेसलाइन के सापेक्ष भारतीय रुपये में 5 प्रतिशत मूल्यवृद्धि होती है, तो मुद्रास्फीति और जीडीपी वृद्धि क्रमशः लगभग 35 बीपीएस और 25 बीपीएस तक कम हो सकती है (चार्ट I.11बी और I.12बी)।

(iv) खाद्य मुद्रास्फीति

अक्तूबर 2024 में अपनी ऊंचाइयों को छूने के बाद खाद्य मुद्रास्फीति में 2024-25 की दूसरी छमाही में कमी पाई गई, जिसमें सब्जियों की कीमतों में तेजी से गिरावट, अनाज और दाल में कम मुद्रास्फीति और मसालों में अपस्फीति की प्रमुख भूमिका थी। आने वाले समय में, खरीफ फसल के मजबूत उत्पादन और

रबी की बंपर आवक की वजह से खाद्य कीमतें तेजी से कम हो सकती हैं। ऐसे परिदृश्य में, हेडलाइन मुद्रास्फीति बेसलाइन के सापेक्ष लगभग 50 बीपीएस तक कम हो सकती है। दूसरी ओर, खराब होने वाली खाद्य वस्तुओं की कीमतों में अचानक उलटफेर और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों के कारण कृषि उपज में कमी से खाद्य कीमतों में वृद्धि का दबाव उत्पन्न हो सकता है। इन कारकों के कारण बेसलाइन की तुलना में हेडलाइन मुद्रास्फीति 50 बीपीएस तक बढ़ सकती है (चार्ट I.11बी और I.12बी)।

I.5 निष्कर्ष

घरेलू आर्थिक गतिविधि सुधार की राह पर है और उपभोग मांग की बदौलत सुदृढ़ बने रहने की उम्मीद है। यह स्वीकार करने की आवश्यकता है कि भारत की विशेषता उसकी उच्च विकास क्षमता और मजबूत समष्टि-आर्थिक आधार है। उपभोग और पूंजीगत व्यय पर सरकार का जोर, सुदृढ़ सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के मजबूत परिदृश्य और मजबूत कॉर्पोरेट और बैंक बैलेंस शीट से आने वाले समय में वृद्धि की गति को बल मिलता है। केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित उपाय घरेलू उपभोग में सुधार के लिए अच्छे हैं। इसके अलावा, व्यय की गुणवत्ता से समझौता किए बिना

राजकोषीय समेकन और ऋण मार्ग का पालन करने से सॉवरेन रेटिंग में सुधार करने, पूंजी अंतर्वाह को आकर्षित करने, वित्तीय स्थितियों को सहज बनाने और समग्र मनोभाव एवं परिदृश्य में सुधार करने में मदद मिलेगी। सुसंगठित राजकोषीय और मौद्रिक नीति साथ मिलकर निस्संदेह बेहतर वृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन के संदर्भ में अच्छे परिणाम दे सकती है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा

हाल ही में की गई टैरिफ घोषणाओं ने नीतिगत अनिश्चितता को बढ़ा दिया है जिससे वैश्विक वृद्धि और मुद्रास्फीति के लिए नई बाधाएं उत्पन्न हो गई हैं। हालांकि भारत इन घटनाक्रमों से अछूता नहीं रह सकता है, लेकिन अवस्फीति के मोर्चे पर हुई प्रगति मौद्रिक नीति को वृद्धि-मुद्रास्फीति परिणाम को संतुलित करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गुंजाइश प्रदान करती है।

II. मूल्य और लागत

वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान मुख्य मुद्रास्फीति में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है, जो खाद्य कीमतों में उतार-चढ़ाव के कारण हुआ है। जैसे-जैसे आघातों का असर कम हुआ, एक तेज सुधार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2025 तक मुख्य मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत की लक्ष्य दर से नीचे आ गई। दूसरी छमाही में मुख्य मुद्रास्फीति का दबाव कम रहा, हालांकि फरवरी में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। औद्योगिक और कृषि इनपुट लागत में कमी आई। कृषि मजदूरी के कारण नाममात्र ग्रामीण मजदूरी वृद्धि उच्च बनी रही, जबकि संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की लागत वृद्धि में कमी आई।

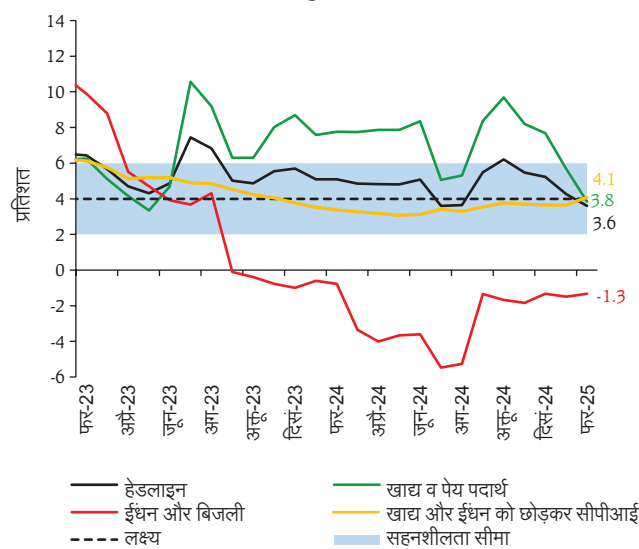
अगस्त 2024 से हेडलाइन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति¹ में गति अतिव्यापी खाद्य मूल्य आघातों के कारण उत्पन्न काफी अस्थिरता देखी गई, जिसके कारण अक्तूबर 2024 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 6 प्रतिशत की अधिकतम सहनीय सीमा से ऊपर हो गया। आघातों का प्रभाव कम होते ही इसमें, तेज सुधार हुआ, जिसके परिणामस्वरूप फरवरी 2025 तक हेडलाइन मुद्रास्फीति 4 प्रतिशत की लक्षित दर से नीचे आ गई।

अक्तूबर 2024 तक हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति अगस्त के 3.7 प्रतिशत से बढ़कर 6.2 प्रतिशत हो गई, यह सब्जियों, तेल और वसा की कीमतों में बढ़ोतरी होने के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में उछाल की वजह से हुआ था। आगामी महीनों में, सब्जियों की कीमतों में सुधार के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आई, जनवरी 2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति क्रमिक रूप से कम होकर 4.3 प्रतिशत और फरवरी में 3.6 प्रतिशत हो गई। खाद्य मुद्रास्फीति में अस्थिरता को दर्शाते हुए, खाद्य और पेय पदार्थ समूह (सीपीआई बास्केट में लगभग 46 प्रतिशत भार के साथ) का हेडलाइन मुद्रास्फीति में योगदान अक्तूबर 2024 में 74 प्रतिशत से गिर कर फरवरी 2025 में 50 प्रतिशत हो गया। ईंधन समूह में अपस्फीति बनी रही, हालांकि अपस्फीति की दर अगस्त 2024 में (-) 5.3 प्रतिशत से कम होकर फरवरी 2025 में (-) 1.3 प्रतिशत हो गई। कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई)

मुद्रास्फीति² स्थिर रही, जो फरवरी 2025 में 4.1 प्रतिशत तक मजबूत होने से पहले, सितंबर 2024 से जनवरी 2025 के दौरान 3.5 प्रतिशत से 3.8 प्रतिशत की सीमा में रही (चार्ट II.1)।

आरबीआई अधिनियम, 1934 (2016 में संशोधित), आरबीआई को अनुमानों से वास्तविक मुद्रास्फीति परिणामों के विचलन, यदि कोई हो, को निर्धारित करने और इसके अंतर्निहित कारणों की व्याख्या करने का निर्देश देता है। अक्तूबर 2024 के एमपीआर ने 2024-25 की तीसरी तिमाही में 4.8 प्रतिशत और 2024-25 की चौथी तिमाही में 4.2 प्रतिशत मुद्रास्फीति अनुमानित की थी (चार्ट II.2)। वास्तविक मुद्रास्फीति परिणामों का विचलन अनुमानों से द्वि-दिशात्मक था – जिसमें मुद्रास्फीति 2024-25 की तीसरी तिमाही में अनुमानों से अधिक और चौथी तिमाही में अनुमानों से कम थी। तीसरी तिमाही में अनुमानों से 80 आधार अंकों की कमी मुख्य रूप से मौसम व्यवधान के कारण टमाटर की कीमतों में अप्रत्याशित क्षणिक तेजी और आयात की उच्च लागत के कारण घरेलू खाद्य तेल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी के कारण हुई। इसके बाद, जनवरी और फरवरी 2025 के दौरान सब्जियों की कीमतों में अनुमानित शीतकालीन मौसम मूल्य सुधार की तुलना में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई, जिससे अब तक (फरवरी तक) चौथी तिमाही में 3.9 प्रतिशत पर वास्तविक

चार्ट II.1: सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)

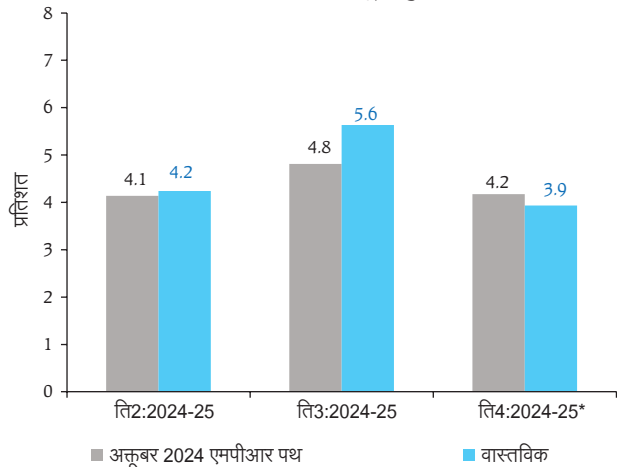


स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ): और आरबीआई स्टॉफ अनुमान।

¹ हेडलाइन मुद्रास्फीति को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा बनाए गए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) में वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) परिवर्तन के आधार पर मापा जाता है।

² कोर सीपीआई, अर्थात खाद्य एवं ईंधन को छोड़कर सीपीआई, मुख्य सीपीआई से 'खाद्य एवं पेय पदार्थ' तथा 'ईंधन एवं बिजली' समूहों को हटाते हुए तैयार किया जाता है।

चार्ट II.2: सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) : वास्तविक बनाम पूर्वानुमान



*: 2024-2025 की संपूर्ण चौथी तिमाही के लिए पूर्वानुमानों की तुलना में जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान वास्तविक औसत मुद्रास्फीति।

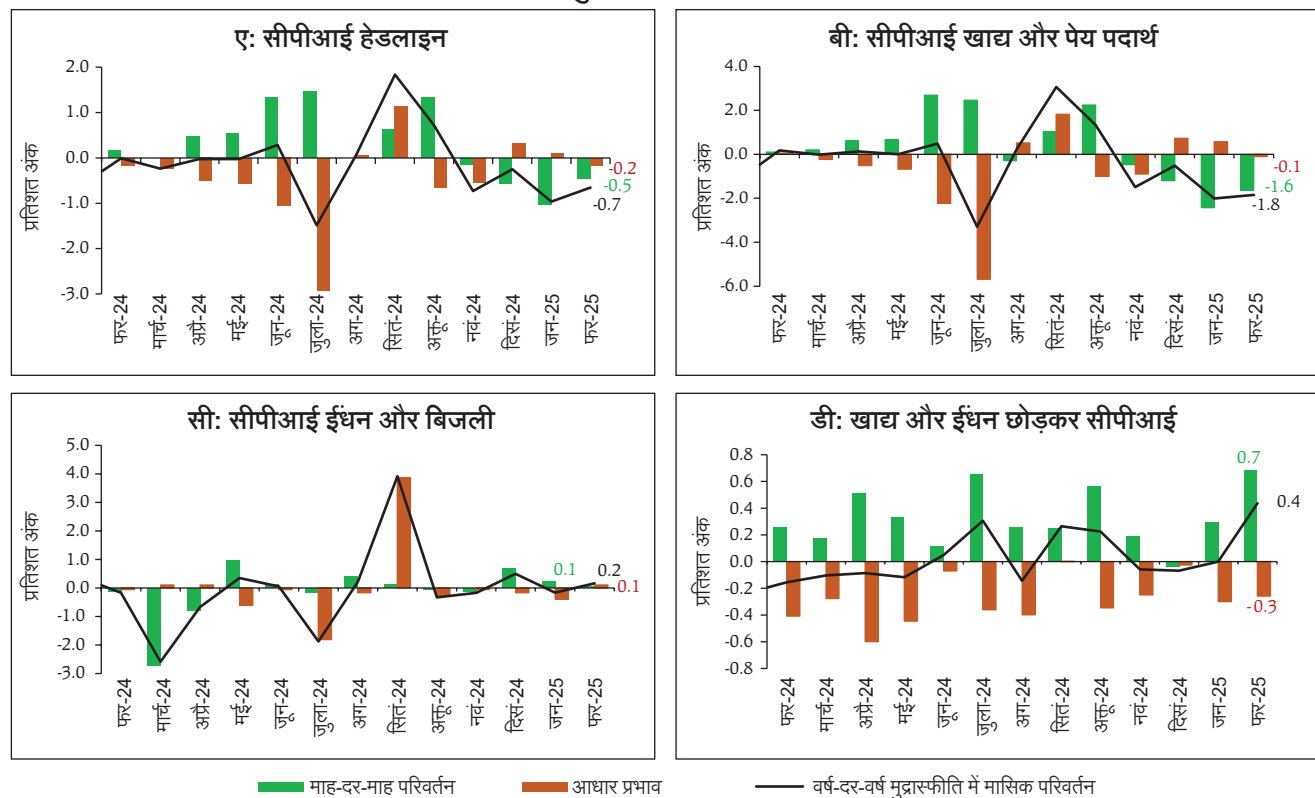
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

हेडलाइन मुद्रास्फीति अक्तूबर एमपीआर में निर्धारित अनुमानों की तुलना में 25 बीपीएस कम हो गई।

II.1 उपभोक्ता मूल्य

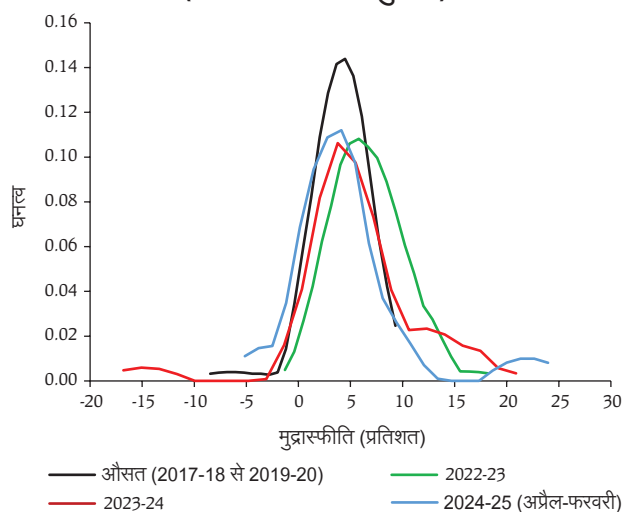
अगस्त में 3.7 प्रतिशत से सितंबर में 5.5 प्रतिशत तक हेडलाइन मुद्रास्फीति में 1.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि मूल्य गति³ में तेजी के साथ-साथ तीव्र प्रतिकूल आधार प्रभावों से हुई। अक्तूबर में हेडलाइन सीपीआई गति में तेजी आई, ऐसा मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में तेज वृद्धि के कारण हुआ जिसमें - अक्तूबर तक हेडलाइन मुद्रास्फीति 6.2 प्रतिशत तक बढ़ गई, जो महत्वपूर्ण अनुकूल आधार प्रभावों के बावजूद ऊपरी सहनशीलता सीमा को पार कर गया। इसके बाद, खाद्य मूल्य गति में तेज सुधार के कारण, हेडलाइन गति ने नवंबर 2024-फरवरी 2025 के दौरान लगातार गिरावट दर्ज करना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप इस अवधि के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति में 2.6 प्रतिशत अंकों की कमी आई और फरवरी में यह 3.6 प्रतिशत के निचले स्तर पर पहुंच गई। यह गिरावट फरवरी में कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) गति में तेज उछाल के बावजूद थी (चार्ट II.3)।

चार्ट II.3: सीपीआई मुद्रास्फीति – गति तथा आधार प्रभाव

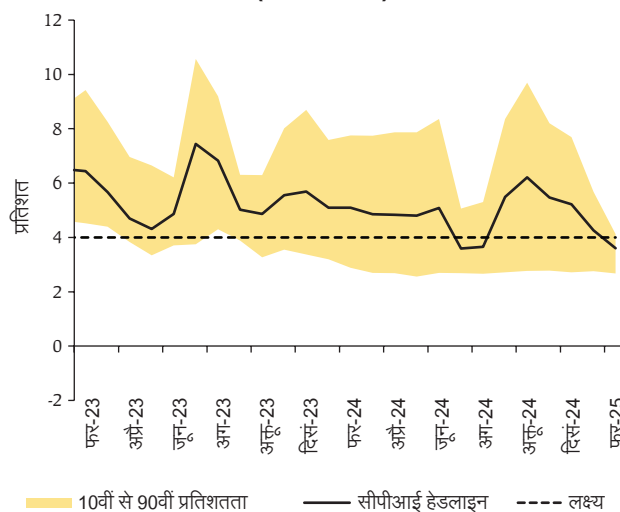


स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

³ किसी भी दो महीनों के बीच सीपीआई वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) मुद्रास्फीति में परिवर्तन मूल्य सूचकांक (गति) में वर्तमान माह-दर-माह (एम-ओ-एम) परिवर्तन और 12 महीने पहले से मूल्य सूचकांक में एम-ओ-एम परिवर्तन (आधार प्रभाव) के बीच का अंतर है। अधिक जानकारी के लिए, एमपीआर, सितंबर 2014 महीने का बॉक्स 1.1 देखें।

**चार्ट II.4: औसत सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)
(केरनेल घनत्व अनुमान)**

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

**चार्ट II.5: सीपीआई उप समूह/समूह मुद्रास्फीति सीमा
(वर्ष-दर-वर्ष)**

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

2024-25 में सीपीआई मुद्रास्फीति का वितरण अब तक (अप्रैल 2024-फरवरी 2025) 2023-24 की तुलना में उच्च सकारात्मक झुका हुआ और अपेक्षाकृत उच्च मानक विचलन को दर्शाता है, जो सतत हेडलाइन मुद्रास्फीति को उत्पन्न करने में निरंतर क्षेत्रीय आपूर्ति पक्ष के आघातों के बड़े प्रभाव को दर्शाता है (चार्ट II.4)। सितंबर-अक्तूबर के दौरान मुद्रास्फीति में तेजी सीपीआई उप-समूहों में मुद्रास्फीति विचलन के बढ़ने से भी चिह्नित की गई थी, जो कुछ उप-समूहों में मुद्रास्फीति में तेज वृद्धि

को दर्शाती है। दिसंबर से इन उप-समूहों में मुद्रास्फीति के दबाव में कमी के बाद, विभिन्न मात्राओं में मुद्रास्फीति विचलन में भी कमी आई (चार्ट II.5)। स्थानिक मुद्रास्फीति गतिशीलता के विश्लेषण से पता चलता है कि आपूर्ति आघातों के कारण मुद्रास्फीति और सापेक्ष मूल्यों में तेज उतार-चढ़ाव के बावजूद, लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) अवधि के दौरान राज्यों में मुद्रास्फीति राष्ट्रीय औसत के अनुरूप हो गई है (बॉक्स II.1)

बॉक्स II.1: भारत में स्थानिक मुद्रास्फीति अभिसरण

कई अतिव्यापी आघातों के कारण 2020 के बाद से इस अवधि को लगातार मुद्रास्फीति दबाव का माना जा रहा है। इसने इस बात पर भी चिंता बढ़ाई है कि समय के साथ इसकी स्थानिक अस्थिरता और अभिसरण के संदर्भ में क्या इनसे भारत में स्थानिक मुद्रास्फीति की गतिशीलता में मौलिक परिवर्तन आया है। जिसका मौद्रिक नीति और 4 प्रतिशत सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्य की विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ेगा।

इस पृष्ठभूमि में, 2016 में लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) के कार्यान्वयन के बाद से समग्र सीपीआई मुद्रास्फीति के स्थानिक

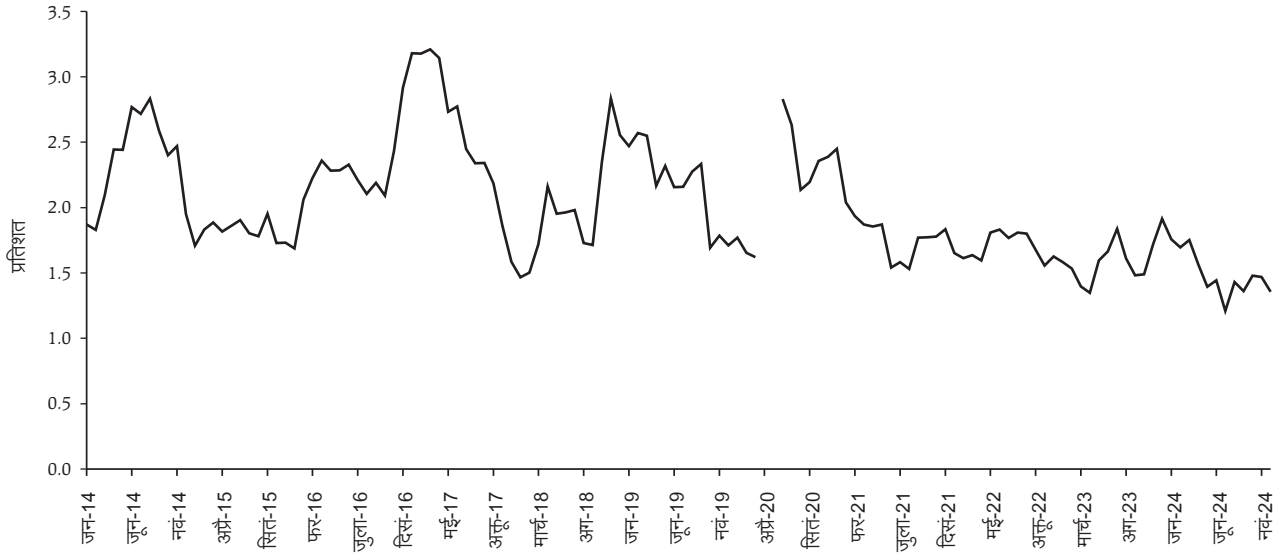
अभिसरण गुणों की जांच की गई है, जिसमें कोविड-पश्चात अवधि पर ध्यान केंद्रित किया गया है। विश्लेषण के लिए अक्तूबर 2016 से दिसंबर 2024⁴ तक 35 भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुद्रास्फीति के माप के रूप में सीपीआई संयुक्त सूचकांक में मासिक वर्ष-दर-वर्ष (वाई-ओ-वाई) परिवर्तनों का उपयोग किया गया है। यह देखा गया है कि राज्यों में हेडलाइन मुद्रास्फीति प्रसार समय के साथ कम हुआ है (चार्ट II.1.1)।

स्थानिक अभिसरण गुणों की आगे जांच (ए) पैनल यूनिट रूट परीक्षणों जैसे कि लेविन-लिन-चू (एलएलसी) और इम-पेसरन-

(जारी)

⁴ अप्रैल से जून 2020 के आंकड़ों को कोविड-19 लॉकडाउन के कारण छूटे अवलोकनों को ध्यान में रखते हुए पिछले सीपीआई मूल्यों का उपयोग करके भरा गया था।

चार्ट II.1.1: राज्यों में सीपीआई-संयुक्त (वर्ष-दर-वर्ष) मुद्रास्फीति प्रसार की प्रवृत्ति



टिप्पणी: अप्रैल और मई 2020 के लिए लगाए गए सीपीआई प्रिंट को सीपीआई श्रृंखला में एक विराम माना गया है।

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

शिन (आईपीएस) द्वारा स्थिरता के लिए की गई, और (बी) बीटा (β) अभिसरण विश्लेषण यह पता लगाने के लिए किया गया कि क्या राष्ट्रीय मुद्रास्फीति स्तर के साथ उच्च प्रारंभिक अंतर वाले राज्यों ने समय के साथ मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट का अनुभव किया, अर्थात् एक सामान्य स्थिर स्थिति में अभिसरण। तदनुसार, निम्नलिखित विनिर्देश के साथ एक पैनल प्रतिगमन ढांचे का उपयोग किया जाता है (1)।

$$\Delta\pi\text{diff}_{it} = \alpha + \beta\pi\text{diff}_{it-1} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

जहाँ $\Delta\pi\text{diff}_{it}$ उसी अवधि में राष्ट्रीय स्तर के संबंध में अवधि t में राज्य i के मुद्रास्फीति अंतर की दर में परिवर्तन है, πdiff_{it-1} एक-अवधि विलंबित मुद्रास्फीति अंतर है, β अभिसरण की गति को मापने वाला गुणांक है, और α और ε क्रमशः स्थिर और त्रुटि शब्द हैं।

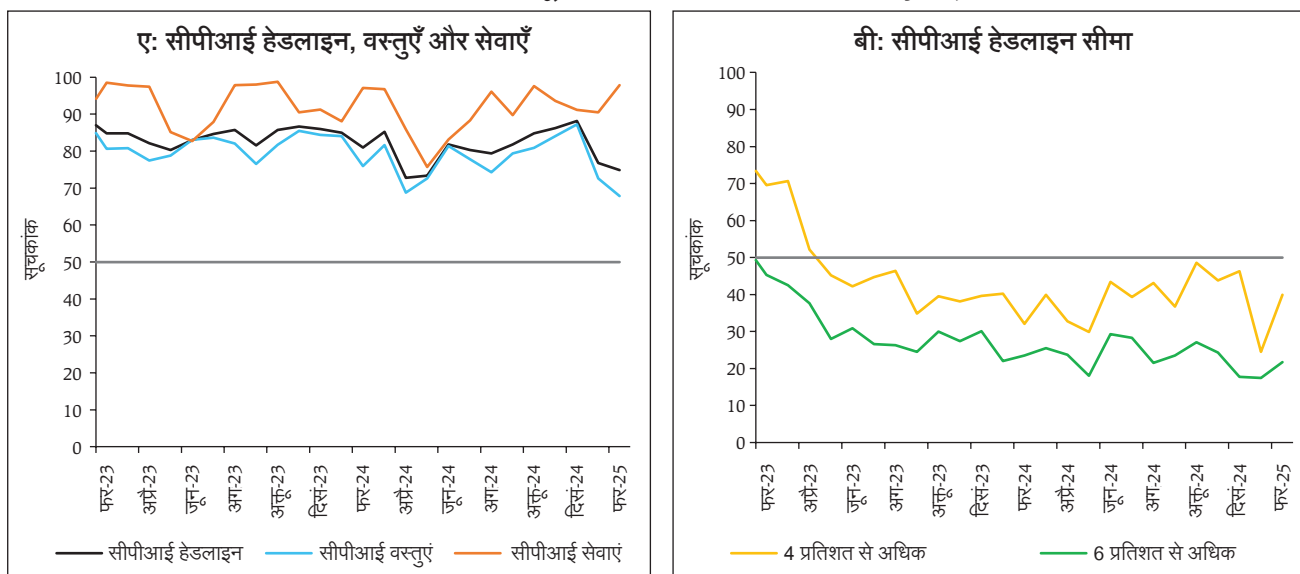
इसके अलावा, समय के दौरान मुद्रास्फीति⁵ के क्रॉस-सेक्शनल प्रसार (मानक विचलन) की गतिविधियों के परीक्षण के लिए सिम्मा (σ)-अभिसरण; और (d) लॉग- t और अभिसरण क्लब परीक्षण, यह जांचने के लिए कि क्या सभी इकाइयाँ एक ही संतुलन में परिवर्तित होती हैं या क्या वे क्लस्टर या 'क्लब' में विभाजित हैं, अर्थात्, कई संतुलन की उपस्थिति की भी जांच की जाती है।⁶

दोनों पैनल यूनिट रूट परीक्षणों के परिणाम 'पैनल में यूनिट रूट होते हैं' की शून्य परिकल्पना को खारिज करते हैं, जो स्थिरता को दर्शाता है, यानी समस्त राज्यों में मुद्रास्फीति प्रसार को दर्शाता है। इसी तरह, पूल किए गए साधारण न्यूनतम वर्ग (ओएलएस) प्रतिगमन ढांचे का उपयोग करके β -प्रसार परीक्षण के परिणाम एफआईटी और कोविड-पश्चात अवधि दोनों के लिए नकारात्मक और सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण बीटा गुणांक दिखाते हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पर स्थानिक मुद्रास्फीति प्रसार की मौजूदगी की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा, σ -प्रसार परीक्षण, जिसमें समय की प्रवृत्ति पर राज्यों में मुद्रास्फीति के मानक विचलन को वापस लेना शामिल है, एक नकारात्मक और महत्वपूर्ण गुणांक देता है, जो समय के साथ मुद्रास्फीति प्रसार में कमी को दर्शाता है, जिसमें कोविड-पश्चात अवधि भी शामिल है। फिलिप्स और सुल (पीएस) लॉग-टी परीक्षण भी एफआईटी अवधि के लिए प्रसार का संकेत देता है, जिसमें क्लब प्रसार परीक्षण सभी 35 राज्यों (सारणी II.1.1) वाले एकल क्लब की उपस्थिति की पुष्टि करता है। ये निष्कर्ष 2020 के बाद से कई प्रतिकूल आपूर्ति पक्ष आघातों के प्रभाव के बावजूद कम प्रसार के साथ राष्ट्रीय औसत की ओर राज्यों में मुद्रास्फीति के चल रहे प्रसार को इंगित करते हैं, जिससे एफआईटी के दौरान आर्थिक एकीकरण और मुद्रास्फीति अपेक्षाओं के स्थिर होने का संकेत मिलता है।

(जारी)

⁵ मुद्रास्फीति माप का मानक विचलन $\sigma_t = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\pi_{it} - \bar{\pi}_t)^2}$ के रूप में निर्मित किया गया है, जहाँ π_{it} अवधि t में राज्य i की मुद्रास्फीति दर है और $\bar{\pi}_t$ राष्ट्रीय स्तर की मुख्य मुद्रास्फीति है।

⁶ यादृच्छिक प्रभावों के लिए ब्रेश और पैगन लैंग्रेज गुणक (एलएम) परीक्षण शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है कि राज्यों में पैनल-स्तरीय प्रभाव का विचरण शून्य ($\pi = 0.116$) है, जो दर्शाता है कि एक पूल ओएलएस प्रतिगमन अधिक उपयुक्त है। सुदृढ़ और क्लस्टर मानक त्रुटियों का उपयोग संभावित विषमता और क्रमिक स्वतः सहसंबंध (ऑटोकोरिलेशन) के लिए किया जाता है।

चार्ट II.6: सीपीआई प्रसार सूचकांक (माह-दर-माह मौसमी रूप से समायोजित)


स्रोत: एनएसओ, और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

तिमाही में देखे गए आपूर्ति पक्ष के आघातों के प्रतिलोमित होने से आई (चार्ट II.7ए)।

वस्तु मुद्रास्फीति (समग्र सीपीआई में 76.6 प्रतिशत के भार के साथ) ने सितंबर 2024 और जनवरी 2025 के बीच औसतन हेडलाइन मुद्रास्फीति के 85 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया और सेवाओं (23.4 प्रतिशत के भार के साथ) ने शेष 15 प्रतिशत का योगदान दिया। हालाँकि, फरवरी 2025 में, सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति में बड़ी गिरावट के बाद समग्र मुद्रास्फीति में वस्तुओं का योगदान तेजी से गिरकर लगभग 76 प्रतिशत हो गया, जबकि सेवाओं का योगदान बढ़ गया (चार्ट II.7बी)।

2024-25 की तीसरी तिमाही में नाशवान वस्तुओं (7-दिन की वापसी¹⁰ के साथ गैर-टिकाऊ) का योगदान - जिसमें सब्जियाँ, मसाले, फल, और अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, मांस और मछली, और तैयार भोजन शामिल हैं - बढ़ गया, जिसने जनवरी-फरवरी 2025 में कमी आने से पहले हेडलाइन मुद्रास्फीति में स्थिरता लाने में योगदान दिया। दूसरी ओर, अर्ध-नाशवान वस्तुओं (30-दिन की वापसी के साथ गैर-टिकाऊ सामान) का समग्र मुद्रास्फीति

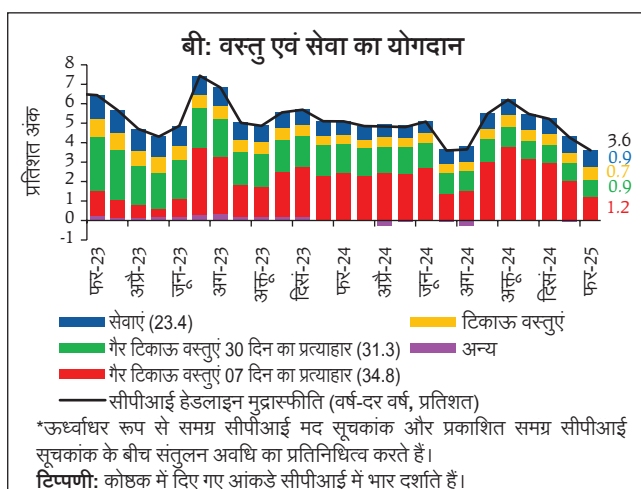
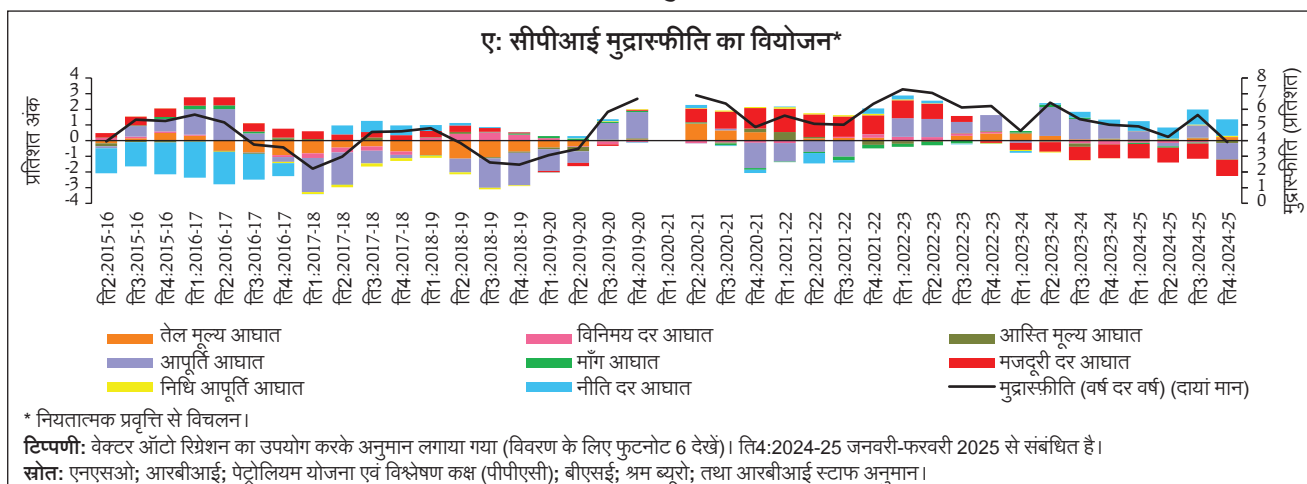
में योगदान तीसरी तिमाही में घट गया। ऐसा मुख्य रूप से दालों और चीनी में मुद्रास्फीति में कमी के कारण हुआ, जबकि व्यक्तिगत देखभाल की वस्तुओं में स्थिरता बनी रही। यह जनवरी-फरवरी 2025 में फिर से मजबूत होने लगी। टिकाऊ वस्तुओं (365-दिन की वापसी वाली वस्तुएँ) का समग्र मुद्रास्फीति में योगदान भी सितंबर-दिसंबर 2024 के दौरान कमोबेश स्थिर रहने के बाद जनवरी-फरवरी में मामूली रूप से बढ़ा, जो कि सितंबर-दिसंबर 2024 की अवधि के दौरान स्थिर बना रहा था। यह सोने और चाँदी की कीमतों में बढ़ी हुई अधिक मुद्रास्फीति को दर्शाता है।

हेडलाइन मुद्रास्फीति में आयातित घटकों¹¹ के योगदान में अक्तूबर से क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई और फरवरी 2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति में इसका योगदान लगभग 21 प्रतिशत रहा (0.8 प्रतिशत का योगदान जो 3.6 प्रतिशत की मुख्य मुद्रास्फीति दर की ओर इंगित करता है), जो मुख्य रूप से सोने और चाँदी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि और रुपये के मूल्यहास से प्रेरित है (चार्ट II.7सी)।

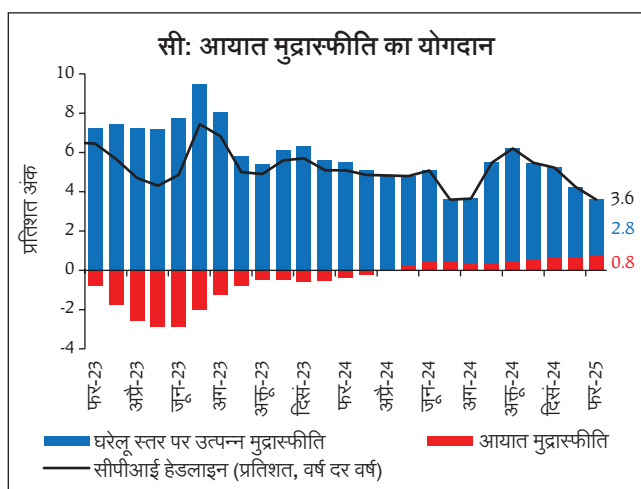
¹⁰ सीपीआई भार आरेख राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा किए गए 2011-12 उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण पर आधारित संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (एमएमआरपी) डेटा का उपयोग करते हैं। एमएमआरपी के तहत, खाद्य तेल, अंडे, मछली, मांस, सब्जियाँ, फल, मसाले, पेय पदार्थ, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों जैसी अक्सर खरीदी जाने वाली वस्तुओं के लिए पिछले सात दिनों के दौरान किए गए व्यय पर डेटा एकत्र किया जाता है; पिछले 365 दिनों के दौरान कपड़े, बिस्तर, जूते, शिक्षा, चिकित्सा (संस्थागत), टिकाऊ वस्तुओं जैसी वस्तुओं पर किया गया व्यय; और पिछले 30 दिनों में अन्य सभी खाद्य, ईंधन और प्रकाश, विविध वस्तुओं और सेवाओं सहित गैर-संस्थागत चिकित्सा सेवाओं, किराए और करों पर किया गया व्यय इसमें शामिल है।

¹¹ वैश्विक वस्तुएँ जो घरेलू कीमतों को बढ़ाती हैं उनमें पेट्रोलियम उत्पाद; कोयला; इलेक्ट्रॉनिक सामान; सोना; चाँदी; रासायनिक उत्पाद; धातु उत्पाद; वस्त्र; अनाज; दूध उत्पाद और वनस्पति तेल शामिल हैं - इनका कुल मिलाकर सीपीआई बास्केट में हिस्सा 36.4 प्रतिशत होता है।

चार्ट II.7: सीपीआई मुद्रास्फीति के चालक



स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।



सीपीआई खाद्य समूह

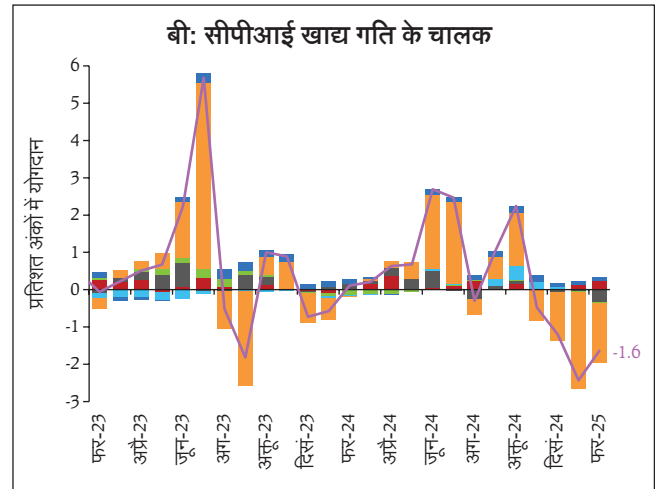
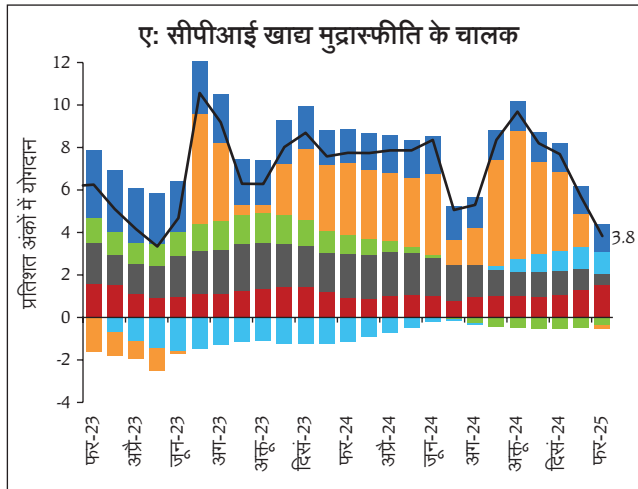
खाद्य और पेय पदार्थ (सीपीआई बास्केट में 45.9 प्रतिशत का भार) समूह ने अब तक 2024-25 की दूसरी छमाही में उच्च अस्थिरता प्रदर्शित की है। सितंबर में मूल्य दबाव उत्पन्न हुए, जो अक्टूबर में और बढ़ गए। नवंबर के बाद से नई फसल की आवक और मौसमी सर्दी के कम होने से सब्जियों की कीमतों में तेजी से सुधार हुआ, साथ ही दालों की कीमतों पर दबाव कम हुआ। इससे फरवरी 2025 तक खाद्य मुद्रास्फीति में पर्याप्त कमी आई और यह 3.8 प्रतिशत पर आ गई (चार्ट II.8)।

2024-25 में अब तक (फरवरी तक) खाद्य कीमतों में वृद्धि पिछले साल और ऐतिहासिक स्तरों की तुलना में काफी कम रही

है। हालांकि, इस साल खाद्य कीमतों में वृद्धि के कारक पिछले साल की तुलना में बदल गए हैं। जबकि तेल और वसा, फल, तैयार भोजन और गैर-मादक पेय पदार्थों में पिछले साल की तुलना में अधिक मूल्य वृद्धि दर्ज की गई, दालों, अनाज, चीनी और अंडों में पिछले साल की तुलना में काफी कम वृद्धि दर्ज की गई। पिछले साल के विपरीत, मसालों और सब्जियों की कीमतों में औसतन काफी गिरावट दर्ज की गई। हालांकि सब्जियों में साल के दौरान बड़ी मूल्य अस्थिरता गिरावट देखी गई। मांस और मछली, और दूध में भी अल्प मूल्य वृद्धि देखी गई (चार्ट II.9)।

अनाज की मुद्रास्फीति (सीपीआई में 9.7 प्रतिशत और खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह में 21.1 प्रतिशत का भार) उच्च स्तर पर रही,

चार्ट II.8 सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति



■ अनाज और उत्पाद (21.1) ■ प्रोटीन आधारित भोजन* (28.4) ■ सब्जियाँ (13.2) ■ अन्य** (24.1)
■ तेल और वसा (7.8) ■ मसाले (5.5) — सीपीआई खाद्य एवं पेय पदार्थ (प्रतिशत, वर्ष दर वर्ष) — सीपीआई खाद्य एवं पेय पदार्थ (प्रतिशत, माह-दर-माह)

*: इसमें मांस और मछली, अंडा, दूध और दालें शामिल हैं।

** इसमें फल, चीनी, अल्कोहल-रहित पेय और तैयार भोजन शामिल हैं।

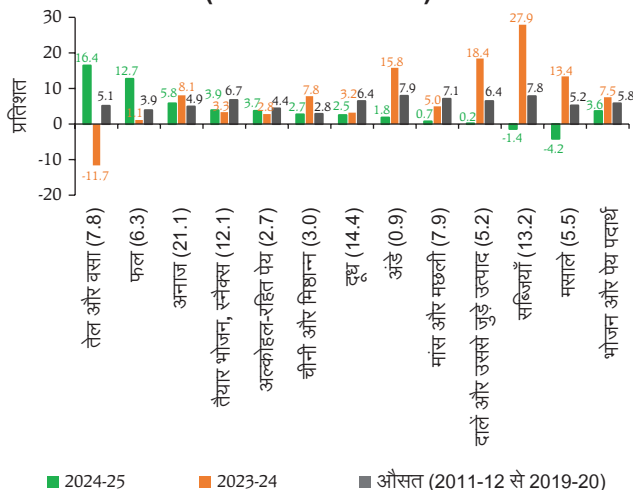
टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सीपीआई में खाद्य और पेय पदार्थों का भार दर्शाते हैं।

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

हालांकि यह अक्टूबर 2024 में 6.9 प्रतिशत से घटकर फरवरी 2025 में 6.1 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.10)। यह कमी मुख्य रूप से चावल से आई, क्योंकि आपूर्ति की स्थिति में सुधार हुआ, जैसा कि उच्च उत्पादन (2023-24 की तुलना में दूसरे अग्रिम अनुमान (ईई) 2024-25 के अनुसार 6.7 प्रतिशत) और पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मंडी आवक में परिलक्षित होता है, सितंबर के

दौरान निर्यात प्रतिबंधों में ढील के बावजूद अक्टूबर 2024 में चावल के पर्याप्त बफर स्टॉक (16 मार्च 2025 तक मानक से 8.7 गुना), राज्यों को चावल की सीधी बिक्री और निरंतर खुदरा बिक्री ने आपूर्ति की स्थिति को आसान बनाने और मूल्य दबाव को नियंत्रित करने में सहायता की है। दूसरी ओर, गेहूं की मुद्रास्फीति सितंबर 2024 में 6.7 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2025 में 9.2

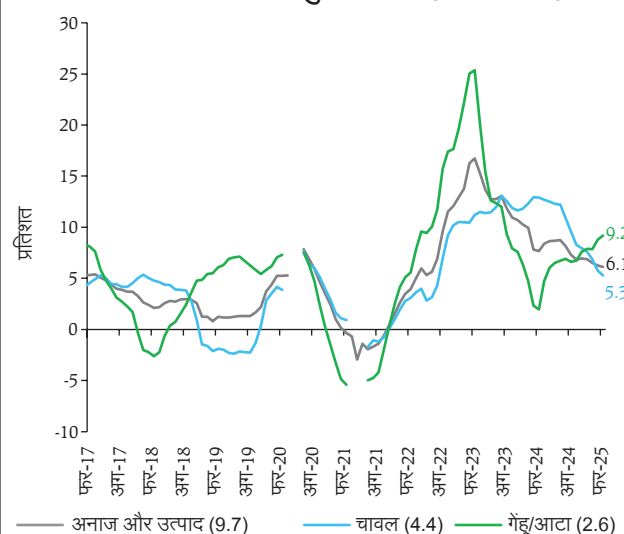
चार्ट II.9: वित्तीय वर्ष मूल्य वृद्धि (फरवरी से मार्च तक)



टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सीपीआई में खाद्य और पेय पदार्थों का भार दर्शाते हैं।

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.10: अनाज मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)



टिप्पणी: कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सीपीआई में भार दर्शाते हैं।

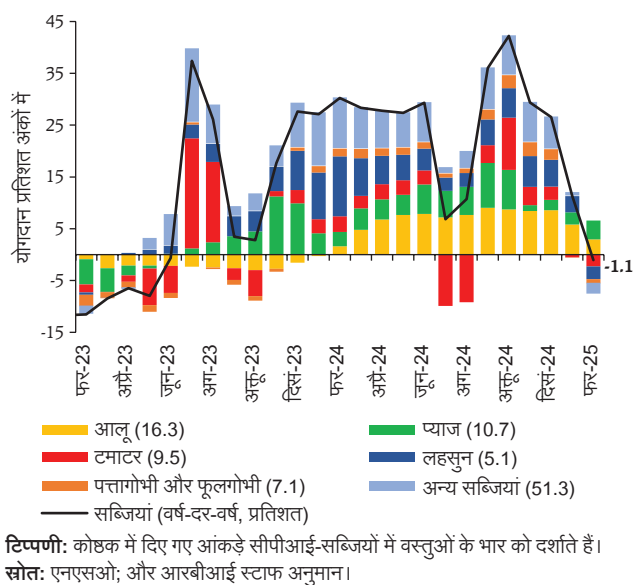
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

प्रतिशत हो गई, जो कि कम मंडी आवक और कम बफर स्टॉक (16 मार्च 2025 तक मानक से 0.9 गुना) में परिलक्षित आपूर्ति की स्थिति के कारण है। मूल्य दबाव को नियंत्रित करने के लिए, सरकार द्वारा आपूर्ति प्रबंधन उपायों को लागू किया गया, जिसमें खुला बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत ई-नीलामी के माध्यम से मार्च 2025 तक एक निश्चित आरक्षित मूल्य पर 2.5 मिलियन टन गेहूं की बिक्री, दिसंबर 2024 में मौजूदा स्टॉक सीमा में कमी और फरवरी 2025 में आगे संशोधन और गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रखना शामिल है। कृषि उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमानों से रबी गेहूं उत्पादन में सुधार (2023-24 की तुलना में 1.9 प्रतिशत वृद्धि) हुआ है।

कई और एक साथ आने वाले मौसम संबंधी आघातों के कारण सब्जियों (सीपीआई में 6.0 प्रतिशत और खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह में 13.2 प्रतिशत का भार) की मुद्रास्फीति अक्टूबर 2024 में 42.2 प्रतिशत के शिखर पर पहुंच गई, जिससे अस्थिर और उच्च मुद्रास्फीति का एक और वर्ष चिह्नित हुआ। इसके बाद, नवंबर 2024-फरवरी 2025 के दौरान मजबूत उत्पादन और ताजा बाजार आवक के परिणामस्वरूप एक असामान्य रूप से तेज शीतकालीन कीमतों में कमी के कारण सब्जियों की मुद्रास्फीति फरवरी 2025 तक तेजी से घटकर (-) 1.1 प्रतिशत हो गई (चार्ट II.11)।

प्रमुख सब्जियों में वर्ष 2023-24 में आलू की कीमतों में कम उत्पादन [वर्ष 2022-23 में (-) 5.0 प्रतिशत] के कारण सितंबर-दिसंबर 2024 के दौरान औसतन लगभग 66.2 प्रतिशत की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) हुई। हालांकि, पिछले वर्ष कम उत्पादन के कारण कीमतों में हुई तीव्र वृद्धि को बाद में 2024-25 के लिए उत्पादन में वृद्धि (2023-24 की तुलना में प्रथम अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार 4.4 प्रतिशत) और बाजार में अधिक आवक से जनवरी-फरवरी 2025 में कम कर लिया गया। प्याज की कीमतों में वृद्धि, सितम्बर 2024 में 66.1 प्रतिशत से फरवरी 2025 में 30.4 प्रतिशत तक वर्ष-दर-वर्ष आधार पर तेजी से कम हो गई, ऐसा निर्यात प्रतिबंधों पर ढील के बावजूद अधिक उत्पादन (2023-24 की तुलना में प्रथम अग्रिम अनुमान 2024-

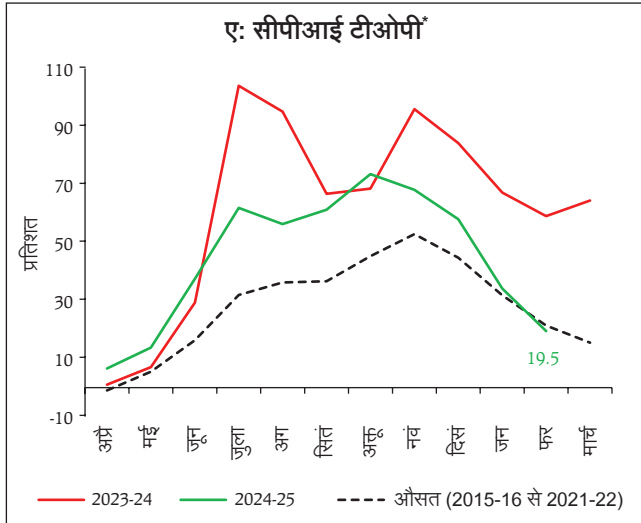
चार्ट II.11 : सब्जी मुद्रास्फीति के चालक (वर्ष-दर-वर्ष)



25 के अनुसार 18.9 प्रतिशत) और खरीफ की विलंबित आवक में वृद्धि के कारण हुआ। कीमत दबाव को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने सितंबर 2024 में प्रमुख उपभोग केंद्रों में 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर खुले बाजार में बिक्री के माध्यम से अपने बफर स्टॉक से प्याज जारी किया। इसके अलावा, अधिशेष से घाटे वाले राज्यों में तेजी से वितरण के लिए अक्टूबर 2024 में एक विशेष ट्रेन, कांदा एक्सप्रेस शुरू की गई। टमाटर की कीमतों में, बेमौसम वर्षा के कारण दक्षिणी राज्यों में कम मंडी आवक के कारण अगस्त 2024 में (-) 47.9 प्रतिशत की अपस्फीति से अक्टूबर 2024 में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 161 प्रतिशत की तीव्र वृद्धि के बाद, फरवरी 2025 में बाजार में आपूर्ति में सुधार के साथ (-) 28.5 प्रतिशत की अपस्फीति दर्ज करते हुए तेजी से कम हुई।

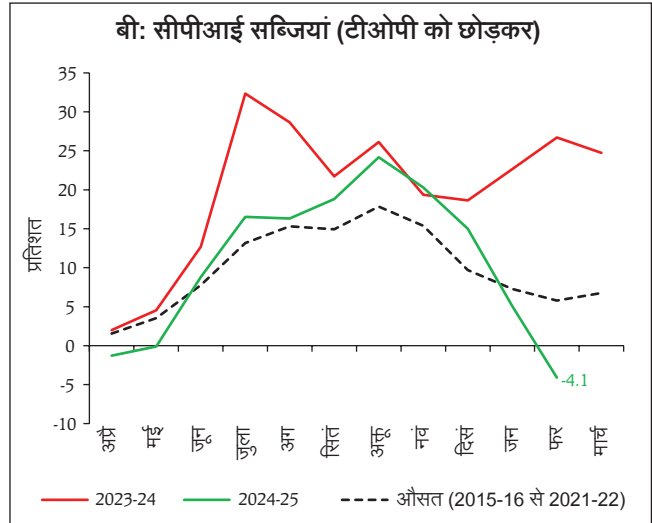
टीओपी (टमाटर, प्याज और आलू) को छोड़कर सब्जियों में, लहसुन में लगातार उच्च मुद्रास्फीति का अनुभव हुआ, जो कि 2023-24 में मामूली उत्पादन वृद्धि (2021-22 की तुलना में 2022-23 में (-) 8.1 प्रतिशत की गिरावट के बाद 2022-23 में 2.3 प्रतिशत की वृद्धि) के कारण सितंबर-दिसंबर 2024 के दौरान औसतन लगभग 75 प्रतिशत रही। इसके बाद, गैर-टीओपी सब्जियों में मुद्रास्फीति का दबाव फरवरी 2025 तक कम हो गया, जिसका कारण बेहतर उत्पादन (2023-24 की तुलना

चार्ट II.12: सीपीआई सब्जियों में कीमत वृद्धि



*: टीओपी का अर्थ है टमाटर, प्याज और आलू।

स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

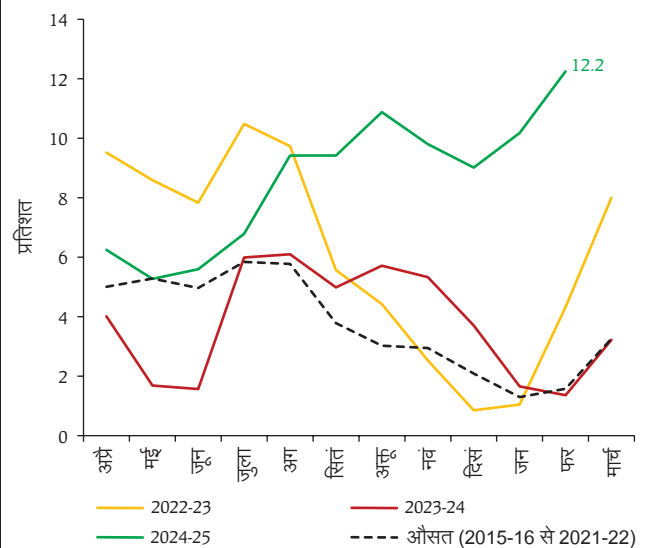


में पहले एई 2024-25 के अनुसार 3.2 प्रतिशत की वृद्धि) के कारण लहसुन की कीमतों में तेज गिरावट थी। नतीजतन, दिसंबर 2024 तक टीओपी और गैर- टीओपी दोनों श्रेणियों में कीमत वृद्धि ऐतिहासिक स्वरूप से अधिक रही। इसके बाद, सब्जियों की कीमतों में व्यापक आधार पर तीव्र सुधार के परिणामस्वरूप टीओपी और गैर- टीओपी श्रेणियों में कीमत वृद्धि में उल्लेखनीय गिरावट आई (चार्ट II.12)।

मौसम के अंत में आयात में गिरावट को दर्शाता है। सितंबर-दिसंबर 2024 के दौरान नरमी के बाद, फरवरी 2025 में केले की महंगाई दर में तेजी से वृद्धि हुई, जो काफी हद तक प्रतिकूल आधार प्रभाव को दर्शाती है। हालांकि, उच्च खरीफ उत्पादन (2023-24 की तुलना में दूसरे अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार 20.4 प्रतिशत) के कारण अगस्त 2024 से मूंगफली की कीमतें अपस्फीति में रहीं।

फलों में मुद्रास्फीति (सीपीआई में 2.9 प्रतिशत और खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह में 6.3 प्रतिशत का भार) अगस्त 2024 से उच्च स्तर पर बनी हुई है। फरवरी 2025 में, यह बढ़कर 14.8 प्रतिशत हो गई, जो अक्टूबर 2014 के बाद से उच्चतम प्रिंट है, जो कीमत दबावों में वृद्धि के कारण है, जो प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण और बढ़ी है। इस वर्ष फलों में कीमत वृद्धि पिछले वर्ष और इसके ऐतिहासिक रुझान की तुलना में काफी अधिक रही है (चार्ट II.13)। कीमतों पर दबाव मुख्य रूप से नारियल की वजह से था, क्योंकि केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों में कम उत्पादन के कारण आपूर्ति की स्थिति खराब थी, साथ ही त्योहारों के दौरान भी मांग अधिक थी। दिसंबर 2024 से सेब की कीमतों में भी तेजी आई है, जो भारत में सेब विपणन

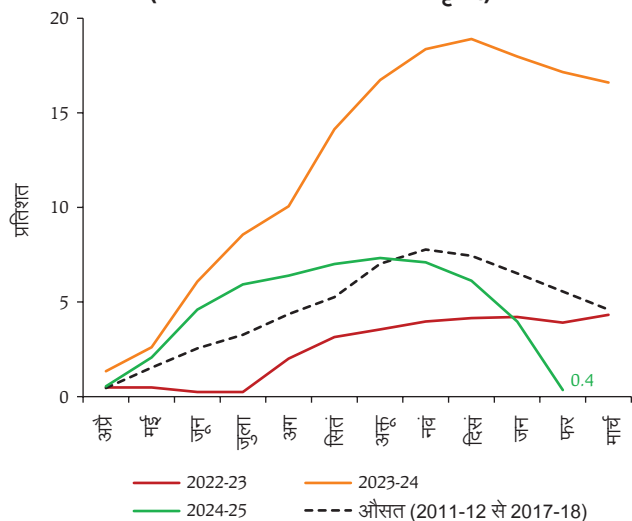
चार्ट II.13: सीपीआई फलों में कीमत वृद्धि



स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

पौधे-आधारित प्रोटीन का प्राथमिक स्रोत दालें (सीपीआई में 2.4 प्रतिशत और खाद्य और पेय पदार्थ समूह में 5.2 प्रतिशत का भार), जिसने अप्रैल-अगस्त 2024 के दौरान दोहरे अंकों की मुद्रास्फीति दर्ज की, उसके बाद उच्च उत्पादन (2023-24 की तुलना में दूसरे अग्रिम अनुमान 2024-25 के अनुसार तुअर के लिए 2.8 प्रतिशत और मूंग के लिए 28 प्रतिशत) और मजबूत आयात के कारण निरंतर कम होते हुए फरवरी 2025 में (-) 0.3 प्रतिशत हो गई। हालांकि, रबी उत्पादन में सुधार के बावजूद चने की मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी रही [2022-23 के मुकाबले 2023-24 में (-) 10.0 प्रतिशत के बाद 2023-24 के मुकाबले दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार 2024-25 में 4.5 प्रतिशत]। कुल मिलाकर, दालों में कीमत वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में अप्रैल 2024-फरवरी 2025 के दौरान कम रही, जो भारत दाल ब्रांड नाम के तहत सब्सिडी वाले चना, मूंग और मसूर दालों की खुदरा बिक्री और 31 मई, 2025 तक चरणों में पीली मटर और 31 मार्च, 2026 तक तुअर के मुफ्त आयात के विस्तार के माध्यम से आपूर्ति की स्थिति को आसान बनाने की दिशा में सरकारी हस्तक्षेप को दर्शाती है (चार्ट II.14)। इसी प्रकार, सितंबर 2024-मार्च 2025 के दौरान स्टॉक-टू-यूज़ अनुपात 6.3 रहा, जबकि 2023-24 में इसी अवधि में यह 5.9 था, जो दालों की आपूर्ति की स्थिति में सुधार का संकेत था (चार्ट II.15)।

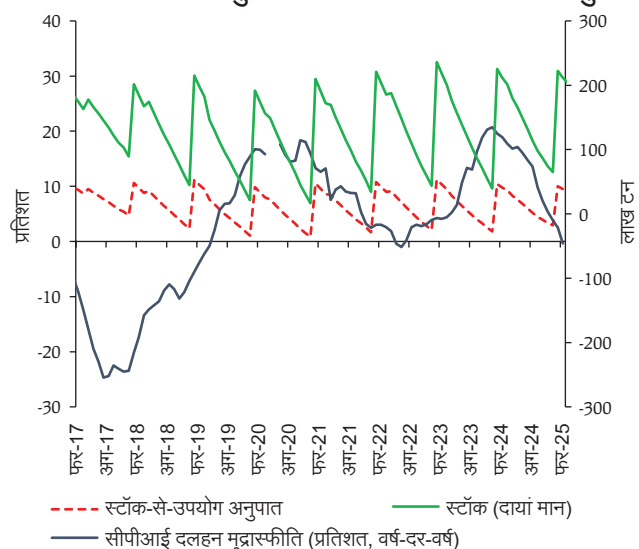
चार्ट II.14: सीपीआई दलहन और उत्पाद (संचयी वित्तीय वर्ष कीमत वृद्धि)



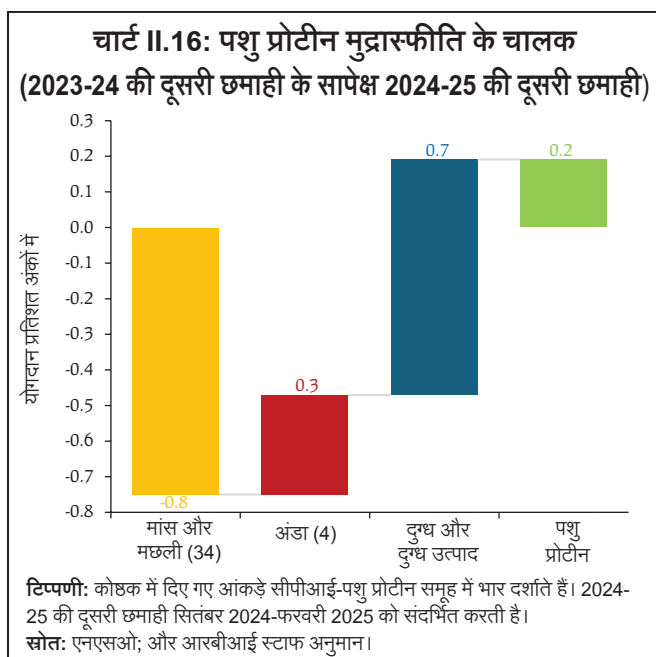
स्रोत: एनएसओ; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान पशु-आधारित प्रोटीन वस्तुओं की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई, जिसका कारण दूध और उत्पाद तथा अंडे रहे। हालांकि, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, मांस और मछली (सीपीआई में 3.6 प्रतिशत और सीपीआई खाद्य और पेय पदार्थ समूह में 7.9 प्रतिशत का भार) में कीमत मुद्रास्फीति दिसंबर 2024-जनवरी 2025 के दौरान क्रमिक रूप से औसतन 5.3 प्रतिशत तक बढ़ गई, जो कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के कारण चिकन की मांग में कमी के कारण फरवरी 2025 में 2.1 प्रतिशत तक कम हो गई। अंडों (सीपीआई में 0.4 प्रतिशत और सीपीआई खाद्य और पेय पदार्थ समूह में 0.9 प्रतिशत का भार) की कीमतों में तेजी और अस्थिर उतार-चढ़ाव देखने को मिला, जो तेज सर्दियों की मांग और चारा लागत में वृद्धि के कारण दिसंबर में 6.9 प्रतिशत तक बढ़ जाने के पूर्व अप्रैल-सितंबर 2024 के दौरान औसतन 6.5 प्रतिशत से नवंबर 2024 में 4.8 प्रतिशत हो गया। जनवरी-फरवरी 2025 में हल्की सर्दी और बर्ड फ्लू की चिंताओं के कारण मांग में कमी और अनुकूल आधार प्रभाव से कीमतों में तेज गिरावट के कारण अंडे की मुद्रास्फीति कम हो गई। दूध और उत्पादों (सीपीआई में 6.6 प्रतिशत और खाद्य और पेय पदार्थ समूह के भीतर 14.4 प्रतिशत का भार) में मुद्रास्फीति इनपुट लागत के कारण सितंबर 2024-फरवरी 2025 के दौरान लगभग 2.9 प्रतिशत पर कम रही (चार्ट II.16)।

चार्ट II.15: दालों की मुद्रास्फीति और स्टॉक-उपयोग अनुपात

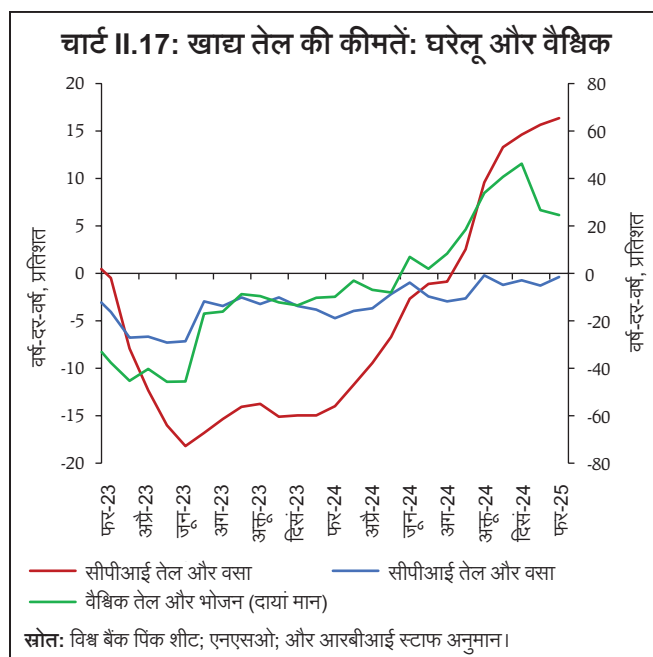


स्रोत: एमओएसपीआई; डीजीसीआई एंड एस, सीपीआई; कृषि मंत्रालय; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।



लगातार 19 महीनों तक अपस्फीति दर्ज करने के बाद, तेल और वसा (सीपीआई में 3.6 प्रतिशत और खाद्य और पेय पदार्थ समूह में 7.8 प्रतिशत का भार), कीमत मुद्रास्फीति सितंबर 2024 में 2.5 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2025 तक 16.4 प्रतिशत हो गई। सितंबर 2024 में कच्चे और परिशोधित खाद्य तेलों पर मूल सीमा शुल्क में 20 प्रतिशत अंकों की बढ़ोतरी के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय खाद्य तेल की कीमतों में तेजी के कारण खाद्य तेल की कीमतों में तेज उछाल आया। हालांकि, महीने-दर-महीने आधार पर, नवंबर 2024 से कीमतों में वृद्धि की दर में नरमी आई है, जो तिलहन के उच्च घरेलू उत्पादन (2023-24 के मुकाबले दूसरे ईई 2024-25 के अनुसार 8.4 प्रतिशत) और वैश्विक खाद्य तेल की कीमतों में कमी के कारण बेहतर आपूर्ति स्थितियों को दर्शाता है (चार्ट II.17)। तेल और वसा उप-समूह में, घी और मक्खन की कीमतों में मुद्रास्फीति मोटे तौर पर कम रही, जो दूध की कीमतों में कम मुद्रास्फीति का संकेत है।

चीनी और कन्फेक्शनरी (सीपीआई में 1.4 प्रतिशत और खाद्य एवं पेय पदार्थ समूह में 3.0 प्रतिशत का भार) की मुद्रास्फीति 2024-25 में अब तक अधिक स्टॉक और गन्ना पेराई मौसम के दौरान ताजा आवक के कारण कम हुई है। हालांकि,



कम अनुमानित खरीफ उत्पादन [2023-24 की तुलना में दूसरे ईई 2024-25 के अनुसार (-) 4.0 प्रतिशत] और निर्यात प्रतिबंधों को आंशिक रूप से हटाने के साथ-साथ अगस्त 2024 में इथेनॉल उत्पादन के लिए चीनी के व्यपवर्तन पर प्रतिबंध हटाने से चीनी की कीमतों में वृद्धि का जोखिम है।

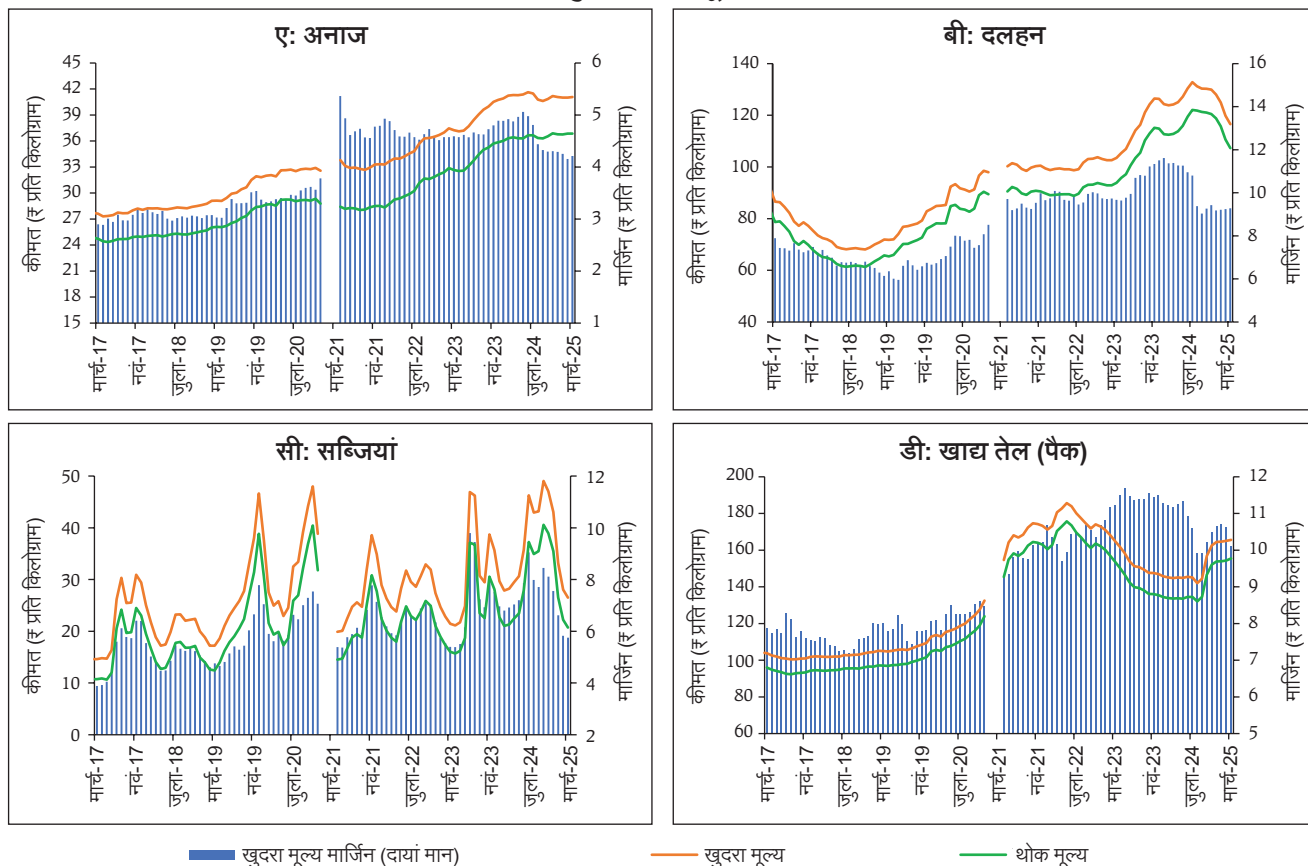
अन्य खाद्य पदार्थों में, मसालों में अपस्फीति फरवरी 2025 में (-) 5.8 प्रतिशत तक कम होने से पहले जुलाई 2024 में (-) 1.4 प्रतिशत से बढ़कर नवंबर और दिसंबर 2024 के दौरान औसतन (-) 7.4 प्रतिशत हो गई थी, जो मुख्य रूप से जीरा और सूखी मिर्च द्वारा संचालित है। तैयार भोजन की कीमतों में मुद्रास्फीति में अब तक दूसरी छमाही में क्रमिक वृद्धि देखी गई है, हालांकि यह अभी भी कम बनी हुई है।

खुदरा मार्जिन

अनाज के मामले में खुदरा और थोक कीमतों¹² के बीच अंतर के रूप में परिभाषित पूर्ण खुदरा कीमत मार्जिन में फरवरी-मार्च 2025 में 4.2 रुपए प्रति किलोग्राम तक की मामूली गिरावट जो कि दिसंबर 2020 से सबसे कम है, देखी जाने के पूर्व अक्टूबर 2024-जनवरी 2025 के दौरान स्थिर रहीं। अक्टूबर-नवंबर 2024 के दौरान दालों की खुदरा कीमत मार्जिन में वृद्धि हुई,

¹² मद-स्तरीय खुदरा और थोक कीमतों को मद-स्तरीय सीपीआई भार का उपयोग करके संबंधित उपसमूहों में एकत्रित किया जाता है। डीओसीए द्वारा जनवरी-मार्च 2021 के आंकड़ों को कीमत संग्रहण तंत्र और मद के प्रकारों में बदलाव के कारण बाहर रखा गया है।

चार्ट II.18: खुदरा, थोक मूल्य और मार्जिन



स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

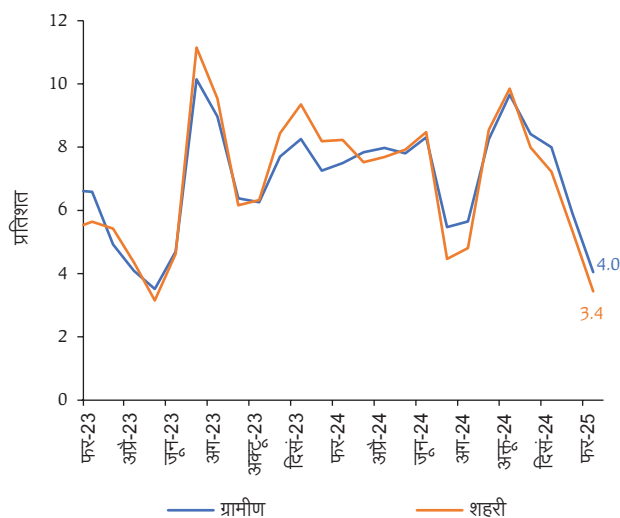
लेकिन उसके बाद मार्च 2025 में मामूली बढ़ोतरी होकर 9.3 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाने से पूर्व फरवरी 2025 तक लगभग 9.2 रुपये प्रति किलोग्राम के आसपास रही। सभी खाद्य तेलों – सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों और परिशोधित तेलों के मार्जिन में वृद्धि के कारण अक्टूबर 2024-फरवरी 2025 के दौरान खाद्य तेलों के खुदरा कीमत मार्जिन में धीरे-धीरे बढ़ोतरी देखी गई। इसके बाद, मार्च 2025 में खुदरा मार्जिन घटकर ₹10.1 प्रति किलोग्राम रह गया, साथ ही खाद्य तेलों की खुदरा और थोक कीमतों में भी कमी आई। टीओपी सब्जियों के मामले में, खुदरा कीमत मार्जिन में अक्टूबर 2024 से क्रमिक गिरावट दर्ज की गई और मार्च 2025 में यह ₹5.7 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया, जो मुख्य रूप से टमाटर और आलू के कारण हुआ (चार्ट II.18)।

खाद्य मुद्रास्फीति का क्षेत्रीय और स्थानिक वितरण

ग्रामीण खाद्य मुद्रास्फीति की तुलना में शहरी खाद्य मुद्रास्फीति के अधिक कम होने के साथ ही नवंबर 2024 से

ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति दबाव कम हो गया है (चार्ट II.19)।

चार्ट II.19: सीपीआई खाद्य मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) : शहरी और ग्रामीण



स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी II.1: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में खाद्य मुद्रास्फीति का वितरण : राज्यों की संख्या[#]

खाद्य मुद्रास्फीति कार्यक्षेत्र	2023-24 (अप्रै-फर)	2024-25 (अप्रै-फर)
2 प्रतिशत से कम	1	1
2 से 4 प्रतिशत के बीच	4	0
4 से 6 प्रतिशत के बीच	11	12
6 प्रतिशत के बीच	20	23

[#]दमन और दीव का दादरा और नगर हवेली के एकीकरण तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) बनने को शामिल करते हुए।

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

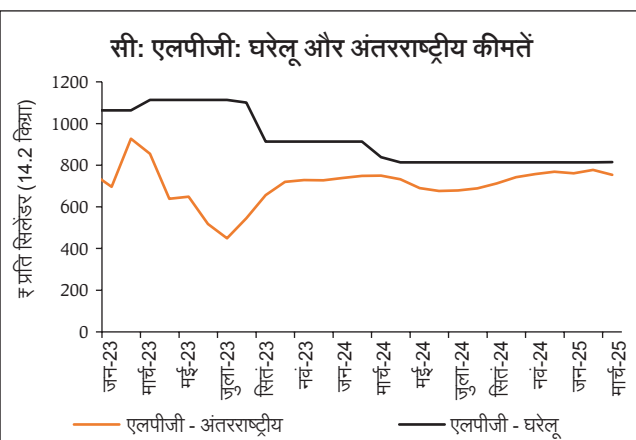
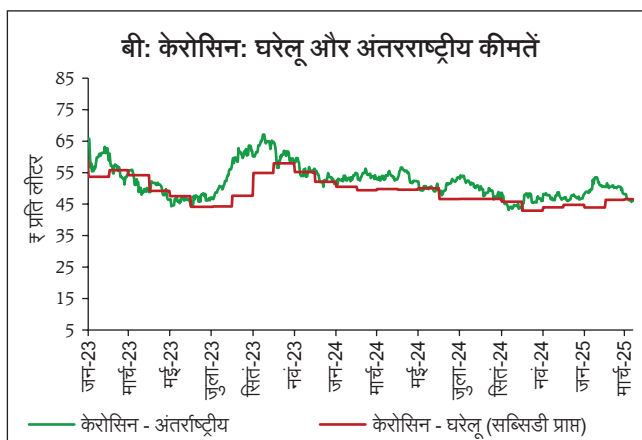
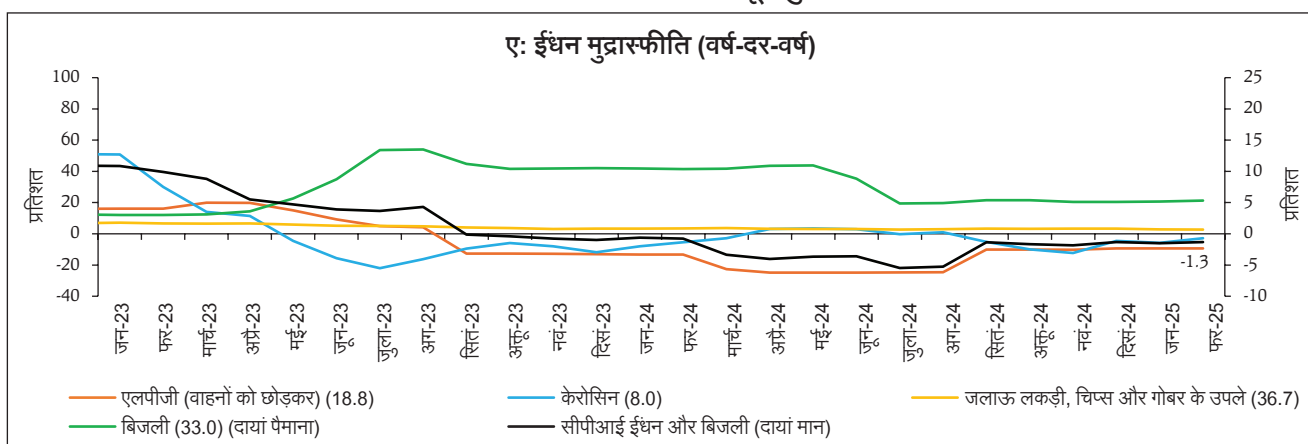
अप्रैल 2024-फरवरी 2025 के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति का दबाव स्थानिक रूप से मजबूत हुआ है क्योंकि औसतन 6.0 प्रतिशत से अधिक खाद्य मुद्रास्फीति का अनुभव करने वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, एक वर्ष पहले की इसी

अवधि में, 20 की तुलना में बढ़कर 23 हो गई है। हालांकि, क्रमिक रूप से, राज्यों में खाद्य मुद्रास्फीति के दबाव में काफी नरमी आई है क्योंकि 6.0 प्रतिशत से अधिक खाद्य मुद्रास्फीति का अनुभव करने वाले राज्यों की संख्या में उल्लेखनीय कमी (नवंबर 2024 में ऐसे राज्यों की संख्या 32 थी जो कि घटकर फरवरी 2025 में 05 राज्य हो गई) देखी गई (सारणी II.1)।

सीपीआई ईंधन समूह

2024-25 की दूसरी छमाही में सीपीआई ईंधन अब तक अपस्फीति में रहा, हालांकि उक्त अपस्फीति अगस्त 2024 में (-) 5.3 प्रतिशत से सितंबर 2024-फरवरी 2025 के दौरान औसतन (-) 1.5 प्रतिशत तक तेजी से कम हुई। प्रतिकूल आधार प्रभावों के कारण एलपीजी में नरम अपस्फीति, और दिसंबर में कीमतों में

चार्ट II.20: सीपीआई ईंधन समूह मुद्रास्फीति



टिप्पणियाँ: (1) एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमत सऊदी ब्यूटेन और प्रोपेन की हाजिर कीमतों के मिश्रण पर आधारित है, जिसमें ये दोनों क्रमशः 60:40 के अनुपात में होती हैं। ये अंतरराष्ट्रीय उत्पाद कीमतें सांकेतिक आयात कीमतें हैं। अधिक विवरण www.ppac.org.in पर उपलब्ध हैं।
(2) केरोसिन की सांकेतिक अंतरराष्ट्रीय कीमत सिंगापुर जेट केरो हाजिर कीमत है।
(3) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, एलपीजी और केरोसिन की घरेलू कीमतें क्रमशः चार और तीन महानगरों की औसत कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं।
(4) कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सीपीआई-ईंधन समूह में मदों के भार को दर्शाते हैं।

स्रोत: एनएसओ; ब्लूमबर्ग; आईओसीएल; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

तेज उछाल के कारण केरोसिन में, साथ ही वर्ष-दर-वर्ष आधार पर जलाऊ लकड़ी और चिप्स की कीमतों में तेजी के कारण, दूसरी छमाही में सीपीआई ईंधन में अपस्फीति कम हुई। घरेलू केरोसिन की कीमतों में उतार-चढ़ाव काफी हद तक अंतरराष्ट्रीय मूल्य में हुए उतार-चढ़ावों को दर्शाता है, जबकि एलपीजी के मामले में, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेजी के बावजूद दूसरी छमाही में घरेलू कीमतें अपरिवर्तित बनी हुई हैं, जिसने इसकी निरंतर अपस्फीति में योगदान दिया। बिजली की कीमतें, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर, फरवरी 2025 में 5.3 प्रतिशत तक घटने से पहले अगस्त में 4.9 प्रतिशत से सितंबर-अक्टूबर में 5.4 प्रतिशत तक एक सीमित दायरे में बढ़ीं (चार्ट II.20)।

कोर सीपीआई (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई)

कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) अगस्त 2024 में 3.3 प्रतिशत के निचले स्तर से बढ़कर अक्टूबर में 3.8 प्रतिशत हो गई और नवंबर 2024-जनवरी 2025 के दौरान 3.6-3.7 प्रतिशत के आसपास स्थिर रही। मुख्य रूप से सोने की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण, फरवरी 2025 में कोर मुद्रास्फीति बढ़कर 4.1 प्रतिशत हो गई जो कि 15 महीनों में सबसे अधिक थी। अंतर्निहित मुद्रास्फीति के अपवर्जन-आधारित उपाय, जो खाद्य और ईंधन के अलावा पेट्रोल और डीजल, सोना और चांदी जैसी अस्थिर वस्तुओं को हटाते हैं, भी फरवरी में कम परिमाण की उल्लेखनीय वृद्धि देखने से पहले जनवरी तक मंदित रहे (सारणी II.2)।

सितंबर 2024-फरवरी 2025 के दौरान एक्सक्लूजन-आधारित सीपीआई प्रारंभिक सीमा प्रसार सूचकांक कोर सीपीआई बास्केट में मंद मूल्य दबावों की निरंतरता की ओर इंगित करते हैं। खाद्य, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी को छोड़कर 4 प्रतिशत (एसएएआर) से अधिक की मूल्य वृद्धि के लिए सीपीआई डीआई पूरी दूसरी छमाही में संकुचन क्षेत्र में रहा, जो कि यह दर्शाता है कि अधिकांश वस्तुओं ने 4 प्रतिशत से कम के एसएएआर पर मूल्य वृद्धि प्रदर्शित की। 6 प्रतिशत (एसएएआर) से अधिक की मूल्य वृद्धि के लिए डीआई भी सितंबर 2024-फरवरी 2025 के दौरान गहन संकुचन क्षेत्र में रहा, जो कि यह दर्शाता है कि सीपीआई कोर में अधिकांश वस्तुओं ने इस अवधि के दौरान 6 प्रतिशत एसएएआर सीमा से नीचे मूल्य वृद्धि प्रदर्शित की (चार्ट II.21)। हालांकि प्रारंभिक सीमा डीआई अभी भी संकुचन क्षेत्र में होने के बावजूद उसमें फरवरी माह में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।

सारणी II.2: मुद्रास्फीति के एक्सक्लूजन-आधारित माप (वर्ष-दर-वर्ष)

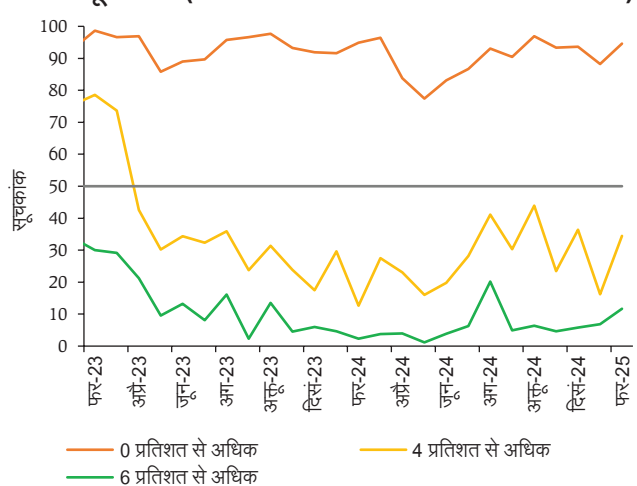
माह	खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई (47.3)	खाद्य, ईंधन, पेट्रोल और डीजल को छोड़कर सीपीआई (45.0)	खाद्य, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, स्वर्ण और चांदी को छोड़कर सीपीआई (43.8)
जन-24	3.5	3.7	3.4
फर-24	3.4	3.5	3.3
मार्च-24	3.3	3.4	3.2
अप्रैल-24	3.2	3.4	3.0
मई-24	3.1	3.3	2.8
जून-24	3.1	3.3	2.8
जुलाई-24	3.4	3.6	3.1
अगस्त-24	3.3	3.5	3.0
सित-24	3.5	3.8	3.2
अक्तू-24	3.8	4.0	3.3
नव-24	3.7	3.9	3.3
दिसं-24	3.6	3.9	3.3
जन-25	3.6	3.9	3.2
फर-25	4.1	4.3	3.4

टिप्पणियां: (1) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े सीपीआई में भार को दर्शाते हैं।
(2) हेडलाइन सीपीआई से अवशिष्ट के रूप में व्युत्पन्न।

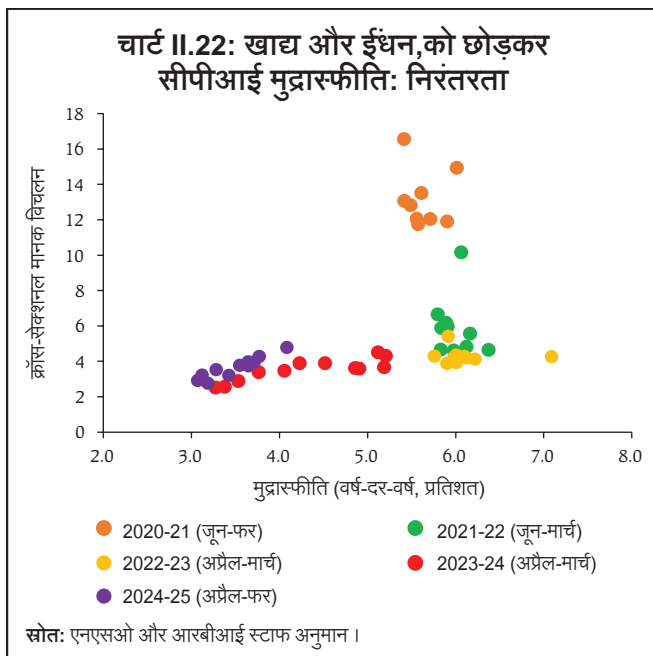
स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान कोर मुद्रास्फीति ने पिछले वर्ष की तुलना में उच्च मुद्रास्फीति परिवर्तनशीलता के कुछ संकेत प्रदर्शित किए, लेकिन मुद्रास्फीति का स्तर और इसकी परिवर्तनशीलता अन्य कोविड-पश्चात वर्षों की तुलना में बहुत कम थी (चार्ट II.22)। 2024-25 में अब तक कोर मुद्रास्फीति दबाव औसतन कम था और यह व्यापक था, जिसमें कोर वस्तु

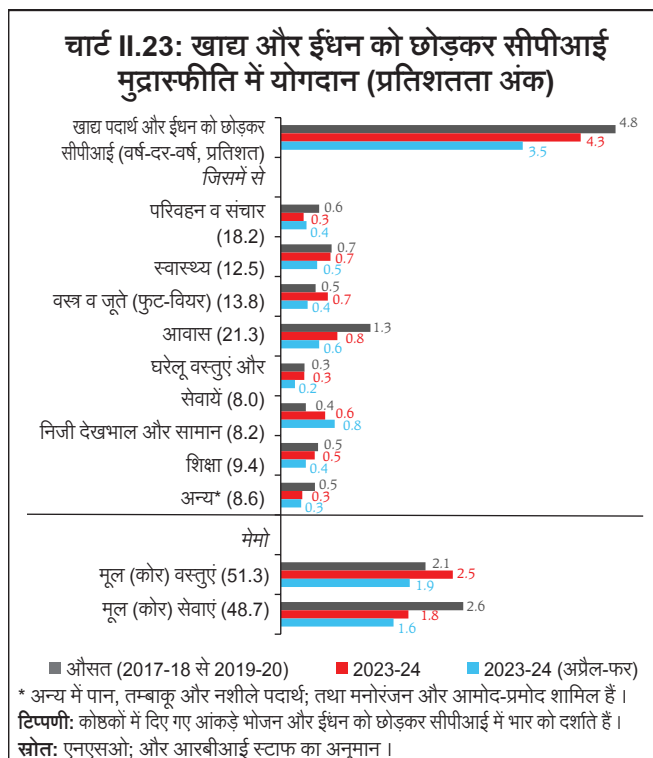
चार्ट II.21: खाद्य और ईंधन, पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति: थ्रेसहोल्ड द्वारा प्रसार सूचकांक (माह-दर-माह मौसमी रूप से समायोजित)



स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

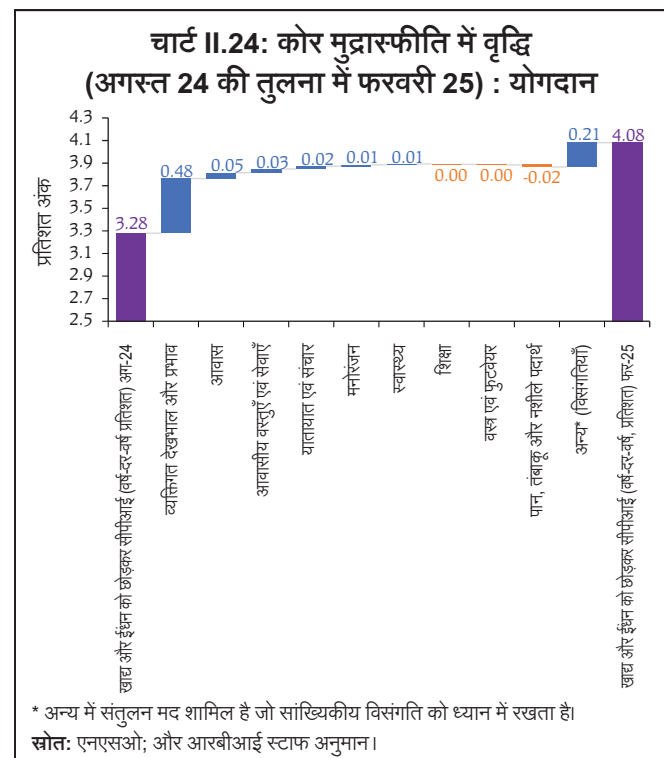


और सेवाएं दोनों श्रेणियां शामिल थी। सभी उप-समूहों/समूहों (परिवहन और संचार, और व्यक्तिगत देखभाल और सामान को छोड़कर) के योगदान ने पिछले वर्षों और कोविड-पूर्व पैटर्न की तुलना में मुद्रास्फीति की कम दर दर्ज की (चार्ट II.23)।



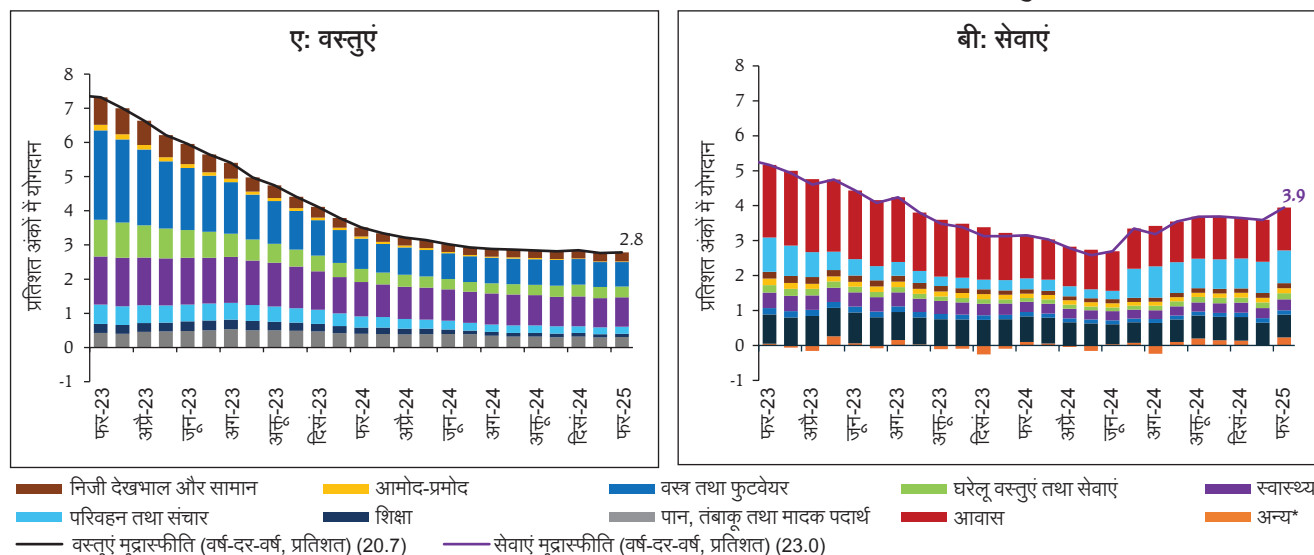
अगस्त 2024 और फरवरी 2025 के बीच कोर मुद्रास्फीति में उछाल का मुख्य कारण व्यक्तिगत देखभाल और सामान उप-समूह था, जो सोने और चांदी की कीमतों में उछाल को दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से, वृद्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा सांख्यिकीय विसंगति¹³ के लिए जिम्मेदार संतुलन मद से भी उपजा है। सोने और चांदी की कीमतों में उछाल और सांख्यिकीय विसंगतियों के लिए समायोजित, कोर मुद्रास्फीति में वृद्धि कम रही है, जिसमें आवास, घरेलू सामान और सेवाएं, परिवहन और संचार, मनोरंजन और स्वास्थ्य के मामूली योगदान को, जो कुछ हद तक शिक्षा, पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों और कपड़ों और फुटवेयर के समग्र कोर मुद्रास्फीति में योगदान में गिरावट द्वारा प्रतिसंतुलित कर दिया है। (चार्ट II.24)।

खाद्य, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी की मुद्रास्फीति को छोड़कर सीपीआई को उसके माल (मुख्य सीपीआई में 20.7 प्रतिशत का भार) और सेवाएं (23.0 प्रतिशत का भार) घटकों में विघटित करके प्राप्त वस्तु मुद्रास्फीति, अब तक दूसरी छमाही में (फरवरी 2025 तक) मोटे तौर पर स्थिर रही, हालांकि अगस्त-



¹³ सीपीआई कोर में विचलन के कारण सीपीआई खाद्य और सीपीआई ईंधन के सीपीआई हेडलाइन नेट से बकाया के रूप में गणना की जाती है और सीपीआई कोर उप-समूह सूचकांकों के एकत्रीकरण से प्राप्त होती है। इस पर आगे की चर्चा के लिए देखें: दास और जॉर्ज (2023), 'द अग्रीगेशन मेथड मैटर्स', आरबीआई बुलेटिन, मार्च।

चार्ट II.25: खाद्य पदार्थ, ईंधन, पेट्रोल, डीजल, स्वर्ण और चांदी को छोड़कर सीपीआई मुद्रास्फीति में योगदान



* सभी मर्च (आइटम) में लंबवत समेकित सीपीआई मंद (आइटम) सूची और प्रकाशित उप-समूह/समूह/समग्र सीपीआई सूचकांक में अंतर का समाधान करने के लिए संतुलन मद को दर्शाते हैं।

टिप्पणी: कोष्ठक में दिये गए आंकड़े सीपीआई में भार को दर्शाते हैं।

स्रोत: एनएसओ तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सितंबर 2024 में मामूली कमी दिखाते हुए 2.9 प्रतिशत से अक्टूबर 2024 में 2.8 प्रतिशत हो गई, जहां यह फरवरी 2025 तक उस स्तर पर स्थिर रही। घरेलू और व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव वस्तुओं को छोड़कर, सभी उप-समूहों में मुद्रास्फीति नरम हुई (चार्ट II.25ए)। कोर सेवाओं की मुद्रास्फीति अगस्त 2024 में 3.4 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2025 में 3.7 प्रतिशत हो गई। उक्त वृद्धि का महत्वपूर्ण कारण सांख्यिकीय समायोजन प्रभाव¹⁴ था। इसका सार यह है कि मुख्य सेवाओं की मुद्रास्फीति में वृद्धि मुख्य रूप से आवास (मकान किराया, आवासीय भवन और भूमि, जल शुल्क), स्वास्थ्य, सामान और परिवहन तथा संचार सेवाओं के कारण हुई (चार्ट II.25बी)।

दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति के सूक्ष्म समंजित माध्य¹⁵ उपाय मंद रहे। हालांकि उक्त उपायों में महीनों के दौरान भिन्नताएँ थीं तथापि मुद्रास्फीति के सभी सूक्ष्म समंजितमाध्य उपायों में अक्टूबर 2024 से फरवरी 2025 तक धीरे-धीरे कमी हुई (सारणी II.3)।

मुद्रास्फीति के अन्य माप

कृषि श्रमिकों (सीपीआई-एएल) और ग्रामीण श्रमिकों (सीपीआई -आरएल) के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति में सितंबर 2024 से क्रमिक रूप से कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा,

सारणी II.3: मुद्रास्फीति के कम करके सुव्यवस्थित किए गए माध्य माप (वर्ष-दर-वर्ष)

माह	5% कम करके सुव्यवस्थित	10% कम करके सुव्यवस्थित	25% कम करके सुव्यवस्थित	भारित माप
जन-24	4.7	4.5	3.9	3.7
फर-24	4.6	4.4	3.7	3.6
मार्च-24	4.7	4.4	3.6	3.3
अप्रै-24	4.6	4.2	3.5	3.0
मई-24	4.5	4.2	3.4	2.9
जून-24	4.3	3.9	3.4	2.9
जुला-24	3.8	3.7	3.3	3.0
अग-24	3.9	3.7	3.3	3.0
सितं-24	4.4	3.9	3.5	3.0
अक्टू-24	4.6	4.1	3.5	3.0
नव-24	4.6	4.1	3.5	3.2
दिसं-24	4.5	4.1	3.5	3.1
जन-25	4.1	3.7	3.4	2.9
फर-25	3.7	3.5	3.2	2.9

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

¹⁴ अधिक जानकारी के लिए फुटनोट 12 देखें।

¹⁵ जबकि अपवर्जन-आधारित उपायों में प्रत्येक अवधि में अस्थिर वस्तुओं (उदाहरण के लिए, खाद्य और ईंधन) का एक निश्चित समूह हटा दिया जाता है, सूक्ष्म उपायों में मुद्रास्फीति वितरण के अंतिम छोर पर स्थित वस्तुओं को छोड़ दिया जाता है - प्रत्येक माह कीमतों में निर्दिष्ट सीमा से अधिक परिवर्तन प्रदर्शित करने वाली वस्तुओं को छोड़ दिया जाता है तथा माह दर माह अलग-अलग वस्तुएं हटाई जाती हैं।

सीपीआई-एल (और आरएल) के बीच सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति के संबंध में अंतर पिछले वर्ष की तुलना में कम हुआ है, क्योंकि सीपीआई-एल और आरएल दोनों में खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी आई है। दूसरी ओर, औद्योगिक श्रमिकों (सीपीआई-आई डब्ल्यू) के लिए सीपीआई मुद्रास्फीति उसी अवधि के दौरान हेडलाइन सीपीआई से कम थी, जिसका मुख्य कारण हेडलाइन सीपीआई की तुलना में खाद्य मुद्रास्फीति में कमी और सीपीआई-आई डब्ल्यू में ईंधन में अधिक अपस्फीति थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पीआई) मुद्रास्फीति, साल-दर-साल, अक्टूबर 2024 में 2.8 प्रतिशत तक बढ़ गई, जिसमें खाद्य मुद्रास्फीति एक दशक से अधिक समय में 12.1 प्रतिशत के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर को छू गई। इसके बाद, खाद्य मुद्रास्फीति में कमी के बाद, नवंबर में डब्ल्यू पीआई मुद्रास्फीति नरम होकर 2.2 प्रतिशत हो गई। दिसंबर में 2.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करने के बाद, डब्ल्यू पीआई मुद्रास्फीति में नरमी आई है और जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान यह 2.3 से 2.4 प्रतिशत की संकरी सीमा के भीतर रही, क्योंकि खाद्य मुद्रास्फीति में नरमी गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति में वृद्धि और ईंधन समूह में अपस्फीति के संकुचन से ऑफसेट हो गई थी। समग्र डब्ल्यू पीआई में 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान वृद्धि दर्ज करने के साथ, सकल मूल्य वर्धित

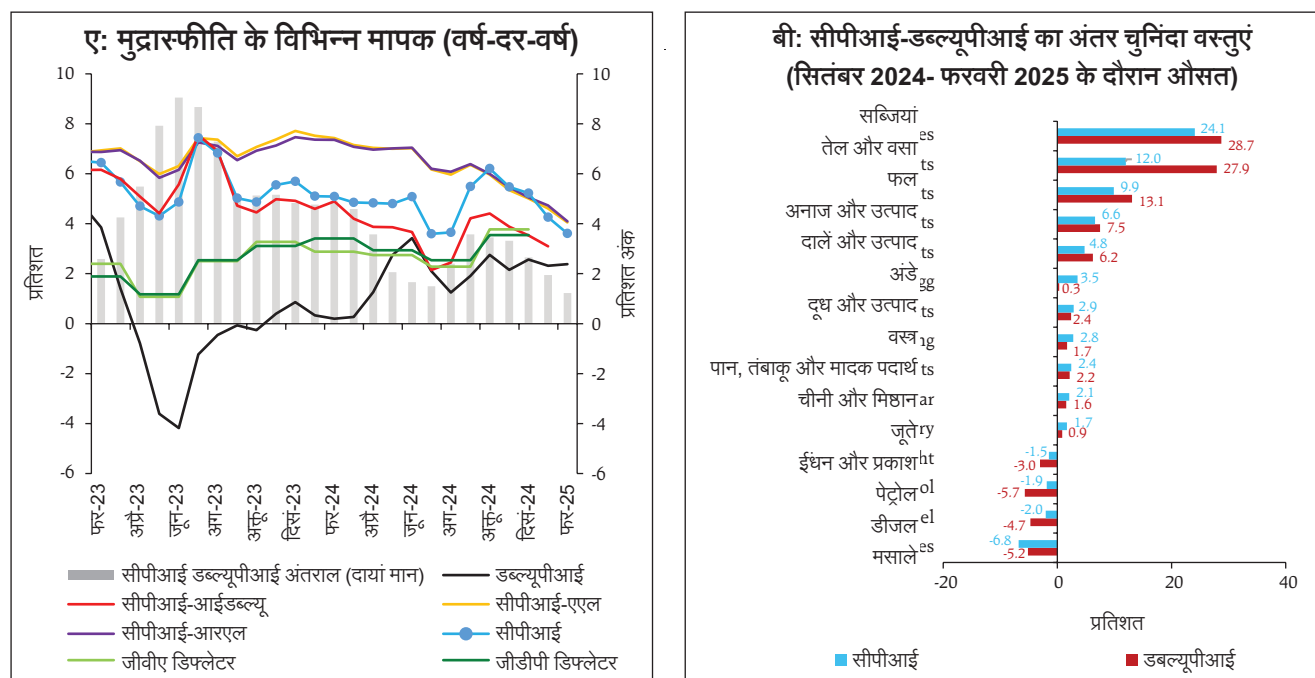
(जीवीए) और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिए डिफ्लेटर द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। जीडीपी डिफ्लेटर दूसरी तिमाही में 2.5 प्रतिशत से बढ़कर तीसरी तिमाही में 3.5 प्रतिशत हो गया और जीवीए डिफ्लेटर दूसरी तिमाही में 2.3 प्रतिशत से बढ़कर तीसरी तिमाही में 3.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट II.26ए)।

सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में समान उप-समूहों/वस्तुओं ने भी विविध मुद्रास्फीति उतार-चढ़ावों का प्रदर्शन किया। जबकि अनाज, दालें, फल, तेल और वसा, और सब्जियां जैसे खाद्य उप-समूहों में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति संबंधित सीपीआई समूहों/उपसमूहों से ऊपर रही, वहीं चीनी, दूध और अंडे की कीमतें डब्ल्यूपीआई की तुलना में सीपीआई में अधिक थी। इसी तरह कपड़ों, और पान, तंबाकू और मादक पदार्थों में मुद्रास्फीति डब्ल्यूपीआई की तुलना में सीपीआई माप में अधिक थी। दूसरी ओर, ईंधन और प्रकाश ने सीपीआई में सकारात्मक वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, जबकि यह डब्ल्यूपीआई में अपस्फीति में रहा। इसी तरह, पेट्रोल और डीजल में अपस्फीति डब्ल्यूपीआई की तुलना में सीपीआई में कम थी (चार्ट II.26बी)।

II.3 लागत

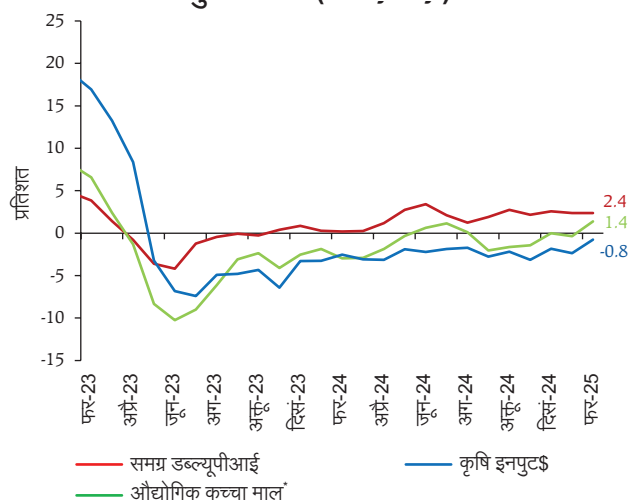
औद्योगिक कच्चे माल और कृषि इनपुट में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति द्वारा मापी गई लागतें, सितंबर 2024 से बड़े पैमाने

चार्ट II.26: मुद्रास्फीति के वैकल्पिक मापक



स्रोत: एनएसओ; श्रम ब्यूरो; आर्थिक सलाहकार का कार्यालय मंत्रालय; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट 11.27: कृषि तथा गैर-कृषि कार्य इनपुट लागत मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)



*: डब्ल्यूपीआई से प्राथमिक गैर-खाद्य वस्तुएं, खनिज, कोयला, विमानन टरबाइन ईंधन, उच्च गति डीजल, नेफ्था, बिटुमेन, फर्नेस तेल, चिकनाई तेल, पेट्रोलियम कोक, बिजली, सूती धागे और कागज व लुगदी शामिल हैं।

\$: डब्ल्यूपीआई से उच्च गति डीजल, चारा, बिजली, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि एवं वानिकी मशीनरी शामिल हैं।

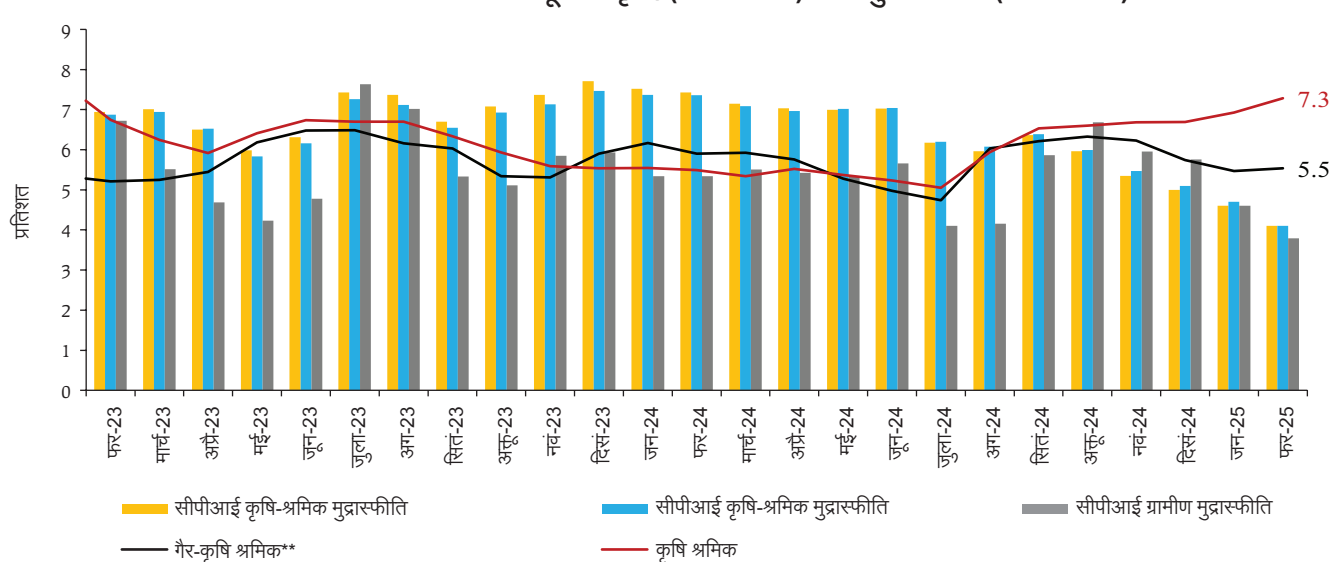
स्रोत : आर्थिक सलाहकार का कार्यालय; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

पर अपस्फीति में रहीं, जो अंतरराष्ट्रीय कमोडिटी कीमतों में कमी द्वारा संचालित थी और मुख्य रूप से बिजली, चारा, विमानन टरबाइन ईंधन (एटीएफ), हाई स्पीड डीजल (एचएसडी), और

कीटनाशकों के कारण थी (चार्ट 11.27)। अन्य योगदान देने वाले कारक गैर-खाद्य वस्तुएँ थीं - विशेष रूप से कच्चा कपास और तिलहन - जिनकी कीमतें इस अवधि के दौरान अधिकतर अपस्फीति में थीं। खनिज तेल भी अपस्फीति में रहे, जो मुख्य रूप से एचएसडी, एटीएफ, केरोसिन और पेट्रोल द्वारा संचालित थे। हालाँकि, फरवरी 2025 में, औद्योगिक इनपुट लागत में वृद्धि हुई और कृषि इनपुट लागत में अपस्फीति औद्योगिक क्षेत्र में फर्नेस ऑयल, नेफ्था और कागज और लुगदी उत्पादों की कीमतों में वृद्धि और कृषि क्षेत्र में चारा और मशीनरी की उच्च लागत के साथ कम हुई। दूसरी ओर, खनिज मुद्रास्फीति, 2024-25 की दूसरी छमाही में सकारात्मक रही, जिसका मुख्य कारण लौह अयस्क रहा, क्योंकि चीन की उच्च मांग और कम आपूर्ति के कारण वैश्विक लौह अयस्क की कीमतों में वृद्धि हुई।

अक्टूबर 2024-फरवरी 2025 के दौरान नाममात्र ग्रामीण मजदूरी वृद्धि औसतन 6.3 प्रतिशत रही। जबकि इस अवधि के दौरान कृषि क्षेत्र की मजदूरी में क्रमिक वृद्धि देखी गई, गैर-कृषि क्षेत्र की मजदूरी वृद्धि में मंदी देखी गई (चार्ट 11.28)। कृषि मजदूरी वृद्धि मुख्य रूप से बागवानी श्रमिकों, अंतर्देशीय मछुआरों, कटाई करने वाले श्रमिकों और जुताई और बुवाई

चार्ट 11.28: ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) और मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष)

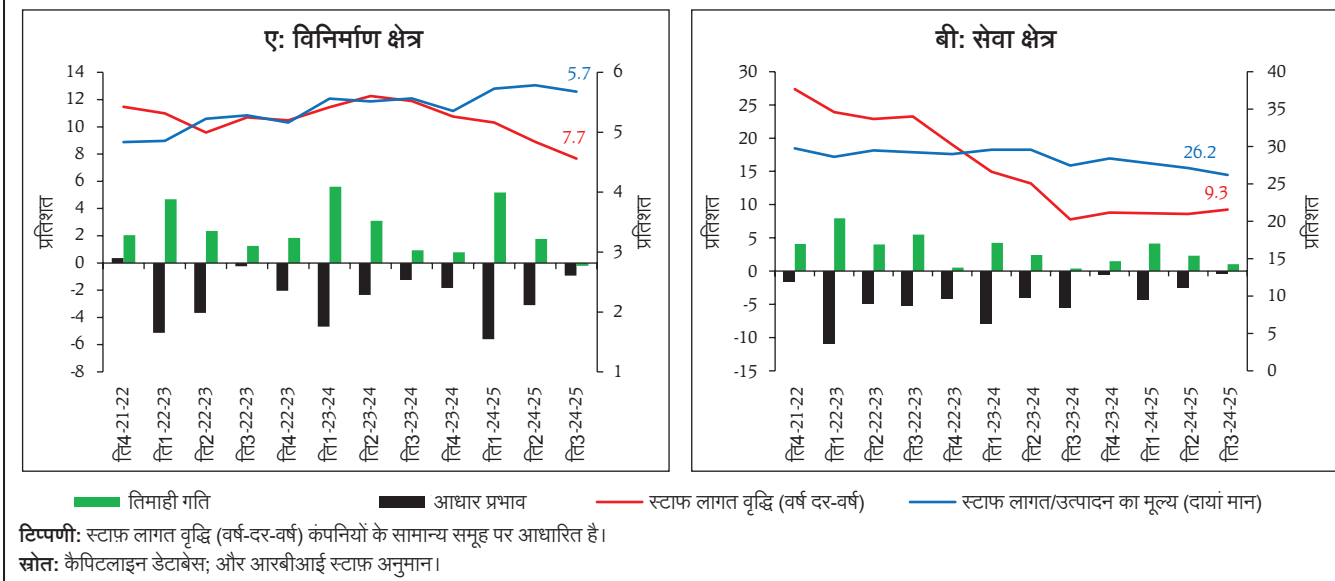


*: जुताई, बुवाई, कटाई, तुड़ाई, बागवानी मजदूर, मछुआरे, मछुआरे तटीय, लकड़हारे और लकड़ी काटनेवाले, पशुपालन, पैकेजिंग, सामान्य कृषि मजदूर, पौध संरक्षण मजदूर शामिल हैं।

** : बढ़ई, लोहार, राज मिस्त्री, बुनकर, बीड़ी बनानेवाले, बांस-बेंत टोकरी बुनकर, हस्तशिल्प कामगार, नलसाज (प्लंबर), इलेक्ट्रीशियन, निर्माण मजदूर, एलएमवी और ट्रैक्टर चालक, झाड़-पोछ/सफाई कर्मचारी और अन्य गैर-कृषि मजदूर शामिल हैं।

स्रोत : एनएसओ; श्रम ब्यूरो; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट II.29: विनिर्माण और सेवाओं में स्टाफ लागत



करने वाले श्रमिकों द्वारा संचालित थी; जबकि ग्रामीण क्षेत्र में गैर-कृषि मजदूरी प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और एलएमवी और ट्रैक्टर चालकों के कारण थी।

संगठित क्षेत्र में, पिछली तिमाही की तुलना में 2024-25 की तीसरी तिमाही में विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों दोनों के लिए स्टाफ लागत वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) धीमी हो गई, जो अनुकूल आधार प्रभावों के कारण स्टाफ लागत की गति में गिरावट से प्रेरित थी (चार्ट II.29)।

लागत स्थितियों के आकलन और दृष्टिकोण पर, रिज़र्व बैंक के उद्यम सर्वेक्षणों¹⁶ में शामिल विनिर्माण फर्मों ने संकेत दिया है कि 2025-26 की पहली तिमाही में इनपुट लागत दबाव कम हो सकता है, लेकिन वेतन व्यय से दबाव बढ़ सकते हैं। विनिर्माण फर्मों को भी कम इनपुट लागत के साथ-साथ पहली तिमाही में बिक्री मूल्यों की वृद्धि में कमी आने का अनुमान है, जबकि सेवा फर्मों के लिए 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान इनपुट और मजदूरी लागत दबाव के साथ-साथ बिक्री की कीमतें बढ़ने की संभावना है। दूसरी ओर, बुनियादी संरचनागत फर्मों

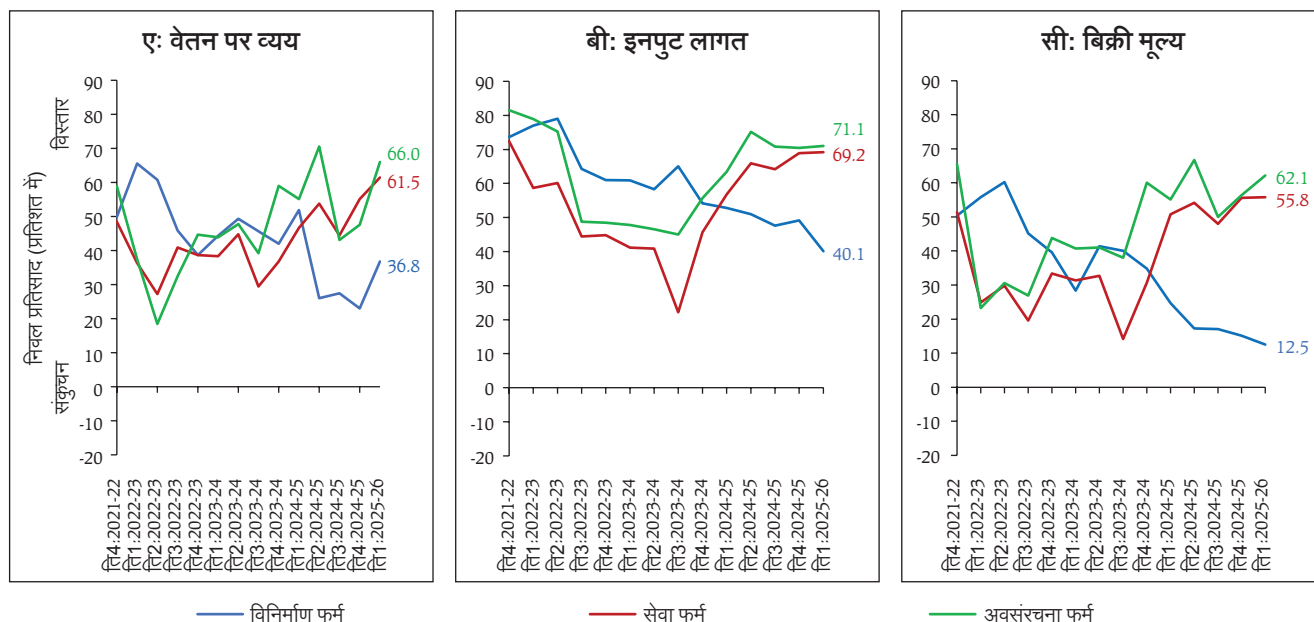
को 2025-26 की पहली तिमाही में बिक्री मूल्यों में उच्च वृद्धि के साथ-साथ इनपुट लागत और मजदूरी लागत दबाव और भी बढ़ने की अपेक्षा है (चार्ट II.30)।

एक वर्ष आगे के व्यापारिक मुद्रास्फीति पूर्वानुमान¹⁷ में, नवंबर में 4.18 प्रतिशत से दिसंबर 2024 में 4.79 प्रतिशत तक बढ़ने के बाद, जनवरी 2025 में 4.24 प्रतिशत तक तेज़ी से कम हुए और फरवरी 2025 में और कम होकर 4.06 प्रतिशत हो गए। सर्वेक्षण में शामिल व्यवसायों ने लागत दबाव में मामूली कमी की अपेक्षा की, हालांकि, बिक्री के मंद आंकड़ों के परिणामस्वरूप पिछले दौर की तुलना में लाभ मार्जिन के लिए उम्मीदें कम रहीं।

क्रय प्रबंधकों के सूचकांक (पीएमआई) के लिए अपना मत देने वाली विनिर्माण फर्मों ने लगातार तीन महीनों की मंदी के बाद मार्च-25 में इनपुट कीमतों में बढ़ोतरी की सूचना दी। दिसंबर 2024 से मार्च 2025 के दौरान, विनिर्माण क्षेत्र में आउटपुट कीमतों की वृद्धि दर में मंदी देखी गई, हालांकि इनका इनपुट लागत की तुलना में तेज़ गति से बढ़ना जारी रहा। दूसरी ओर, पीएमआई सेवा क्षेत्र ने मार्च 2025 में अपेक्षाकृत स्थिर इनपुट कीमतों की सूचना देना जारी रखा।

¹⁶ औद्योगिक आउटलुक सर्वेक्षण; और सेवा और बुनियादी ढांचा आउटलुक सर्वेक्षण।

¹⁷ भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद के मासिक व्यवसाय मुद्रास्फीति अपेक्षा सर्वेक्षण (बीआईईएस) पर आधारित है। सर्वेक्षण मुख्य रूप से विनिर्माण क्षेत्र से व्यवसाय के प्रमुखों के एक पैनल से अल्प और मध्यम अवधि में उनकी मुद्रास्फीति अपेक्षाओं के बारे में पूछता है।

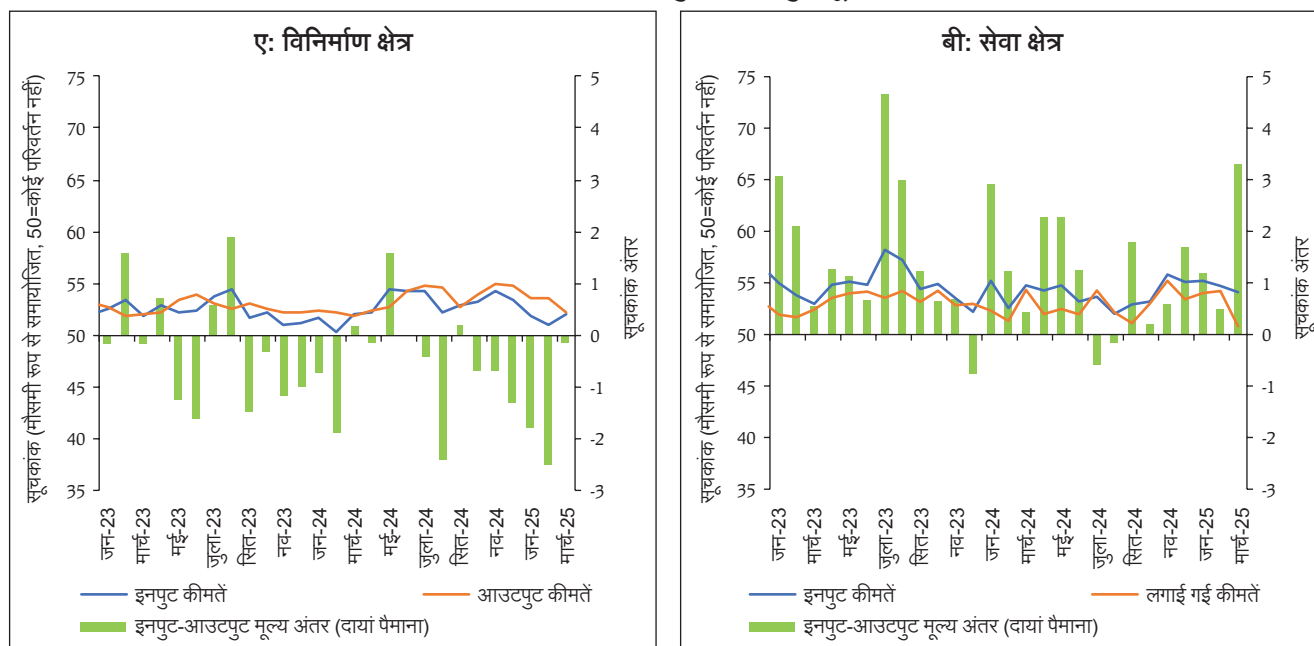
चार्ट II.30: लागत और मूल्य स्थितियों संबंधी प्रत्याशाएं


टिप्पणी: 'निवल प्रतिसाद' मूल्यों में वृद्धि बताने वाले और कमी बताने वाले उत्तरदाताओं के प्रतिशत के बीच का अंतर है।

स्रोत: रिजर्व बैंक का औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण; सेवा और आधारभूत संरचना परिदृश्य का सर्वेक्षण; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

विनिर्माण क्षेत्र के लिए इनपुट-आउटपुट मूल्य अंतर अक्टूबर 2024 से आउटपुट मूल्य वृद्धि के अपरिवर्तित बने रहने के बावजूद कोई दबा हुआ पास-थ्रू नहीं दर्शाता है, जबकि सेवा क्षेत्र

द्वारा लगाए गए मूल्यों में वृद्धि सितंबर 2024 से इनपुट कीमतों की तुलना में कम रही (चार्ट II.31)।

चार्ट II.31: पीएमआई इनपुट-आउटपुट मूल्य अंतर


स्रोत: एसएंडपी ग्लोबल; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

II.4 निष्कर्ष

वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में खाद्य मूल्य आघातों के कारण हेडलाइन मुद्रास्फीति ने उल्लेखनीय अस्थिरता प्रदर्शित की। आपूर्ति पक्ष के आघातों की पुनरावृत्ति के बावजूद, पूर्व-निवारक मौद्रिक नीति कार्रवाइयों ने अंतर्निहित मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों पर उनके दूसरे दौर के प्रभावों को सीमित करने और अवस्फीति प्रक्रिया को बनाए रखने में मदद की है। इस संदर्भ में, आपूर्ति पक्ष के उपायों ने सामान्य मुद्रास्फीति प्रवृत्तियों पर क्षेत्रवार मूल्य आघातों के प्रभाव को कम करने में भी भूमिका निभाई है। खाद्य मुद्रास्फीति में तेज गिरावट के कारण अब तक वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति में महत्वपूर्ण नरमी के, मजबूत कृषि उत्पादन के कारण बने रहने की संभावना है। आगे यदि प्रतिकूल मौसम की घटनाओं और भू-राजनीतिक

तथा बाह्य क्षेत्र की अनिश्चितताओं के नकारात्मक प्रभाव न हों तो यह स्थिति हेडलाइन मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ टिकाऊ रूप से संरेखित करने तथा मुद्रास्फीति की अपेक्षाओं को प्रभावी रूप से स्थिर करने में सहायक हो सकती है, जिससे मौद्रिक नीति की विश्वसनीयता बढ़ेगी। अमेरिका द्वारा व्यापार शुल्क में की गई वृद्धि का घरेलू मुद्रास्फीति पर प्रभाव फिलहाल अनिश्चित है। शुल्क घोषणाओं के बाद, हालांकि कमोडिटी की कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव देखा गया है जहां ऊर्जा और धातु की कीमतें घट गईं, वहीं स्वर्ण की कीमतों में काफी अस्थिरता देखी गई। वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के इर्द-गिर्द व्याप्त भारी अनिश्चितताओं के बीच, मुद्रास्फीति-विरोधी मोर्चे पर हुई उल्लेखनीय प्रगति ने मौद्रिक नीति को विकास-मुद्रास्फीति संतुलन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में अधिक गुंजाइश प्रदान की है।

III. मांग और उत्पादन

घरेलू आर्थिक गतिविधि 2024-25 की दूसरी तिमाही से 2024-25 की दूसरी छमाही में बहाल हुई, जिसका मुख्य कारण उपभोग मांग रही। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संभावनाएं बेहतर रहने, सेवाओं में सतत उछाल, मांग उत्पन्न करने के लिए सरकार के प्रयासों, और बैंकों तथा कॉर्पोरेटों के तुलन-पत्र बढ़िया होने से परिदृश्य उज्ज्वल हुआ है। दूसरी ओर, अमेरिका द्वारा हाल ही में टैरिफ घोषणाओं से भारत की शुद्ध बाहरी मांग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। व्यापार नीति की बढ़ती अनिश्चितताएं, भू-आर्थिक विखंडन, भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता और मौसम की गड़बड़ी घरेलू विकास परिदृश्य के लिए डाउनसाइड जोखिम पैदा करती है।

घरेलू आर्थिक गतिविधियों ने दूसरी तिमाही में सुस्ती के बाद 2024-25 की दूसरी छमाही में गति पकड़ी। निजी खपत मजबूत रही, जो मजबूत ग्रामीण मांग और शहरी मांग में सुधार से प्रेरित थी, और सरकार के अंतिम उपभोग व्यय में दूसरी छमाही में तेजी आई। पिछले वर्षों की ऊंचाइयों की तुलना में निवेश गतिविधियों में कमी आई है। निवल बाह्य मांग में उछाल बना रहा जिसे सुदृढ़ सेवाओं के निर्यात से बल मिला। आपूर्ति पक्ष पर, जबकि कृषि ने एक मजबूत वृद्धि दर्ज की और सेवाओं में सुदृढ़ता

बनी रही, विनिर्माण गतिविधि में मंदी के कारण औद्योगिक वृद्धि कम थी।

III.1 समग्र मांग

वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पिछली तिमाही में 5.6 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 की तीसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष)¹ हो जाने के कारण समग्र मांग परिस्थितियों में सुधार हुआ (सारणी III.1 एवं चार्ट III.1ए)। सकल घरेलू उत्पाद में बढ़ोतरी – तिमाही-दर-तिमाही मौसम के अनुसार समायोजित वार्षिक संवृद्धि दर (एसएएआर) – में भी पिछली तिमाही की तुलना में सुधार हुआ (चार्ट III.1बी)।

जीडीपी अनुमान बनाम वास्तविक परिणाम

अक्तूबर 2024 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट (एमपीआर) में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दूसरी तिमाही के लिए 7.0 प्रतिशत और 2024-25 की तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही दोनों के लिए 7.4 प्रतिशत का अनुमान लगाया गया था। दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में वास्तविक वृद्धि बहुत कम हो गई (चार्ट III.2), जो मुख्य रूप से सरकारी पूंजीगत व्यय के कम होने से निवेश में कमी आने की वजह से थी। चौथी तिमाही के लिए डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 30 मई 2025 को जारी किए जाने वाले हैं।

सारणी III.1: वास्तविक जीडीपी वृद्धि

(वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत)

मद	2023-24	2024-25	भारत योगदान*		2023-24				2024-25			
	(एफआरई)	(एसएई)	2023-24	2024-25	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4#
अंतिम निजी उपभोग व्यय	5.6	7.6	3.2	4.3	7.4	3.0	5.7	6.2	7.7	5.9	6.9	9.9
अंतिम सरकारी उपभोग व्यय	8.1	3.8	0.8	0.4	5.3	20.1	2.3	6.6	-0.5	3.8	8.3	4.2
सकल स्थायी पूंजी निर्माण	8.8	6.1	3.0	2.1	8.4	11.7	9.3	6.0	6.7	5.8	5.7	6.4
निर्यात	2.2	7.1	0.5	1.5	-7.0	4.6	3.0	7.7	8.1	2.5	10.4	7.6
आयात	13.8	-1.1	3.3	-0.3	18.0	14.3	11.3	11.4	-0.7	-2.5	-1.1	-0.1
बाजार मूल्य पर जीडीपी	9.2	6.5	9.2	6.5	9.7	9.3	9.5	8.4	6.5	5.6	6.2	7.6

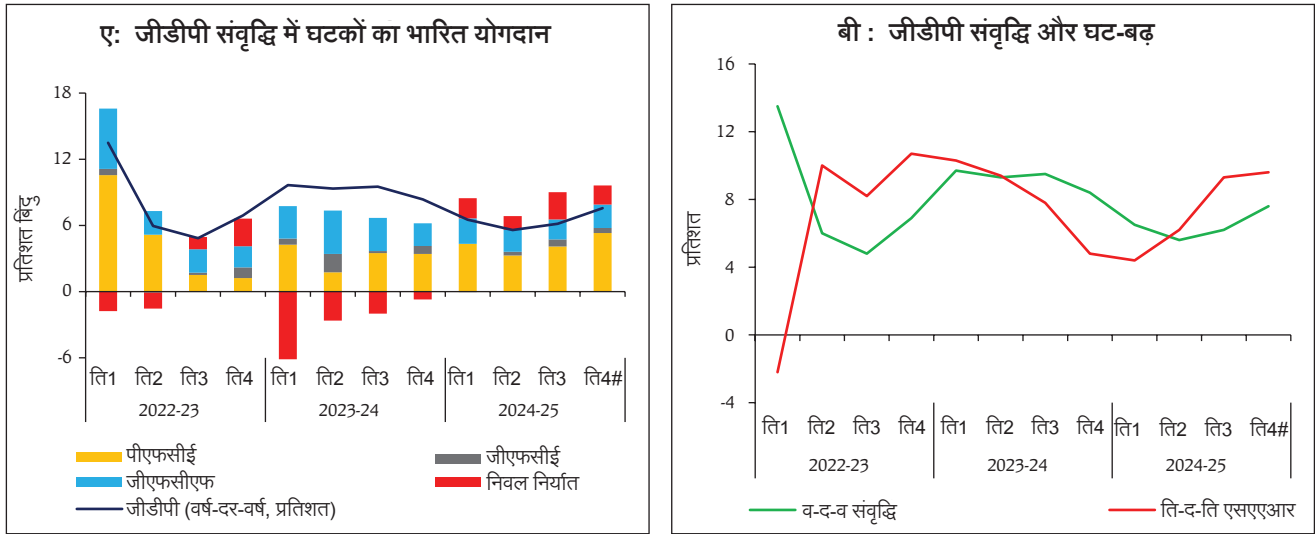
टिप्पणियां * : संवृद्धि का घटक-वार योग जीडीपी संवृद्धि से मेल नहीं खाता क्योंकि भंडार, बहुमूल्य वस्तुओं और अनियमितताओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

एफआरई : प्रथम संशोधित अनुमान; एसएई : द्वितीय अग्रिम अनुमान। # : अंतर्निहित

स्रोत : एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

¹ इस अध्याय में संवृद्धि संबंधी सभी विमर्श, जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, वर्ष-दर-वर्ष आधार पर हैं।

चार्ट III.1: जीडीपी संवृद्धि और इसके घटक



टिप्पणियाँ: # अंतर्निहित; एसएएआर - मौसम के अनुसार समायोजित वार्षिकीकृत दरा
 स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमाना

III.1.1 निजी अंतिम उपभोग व्यय

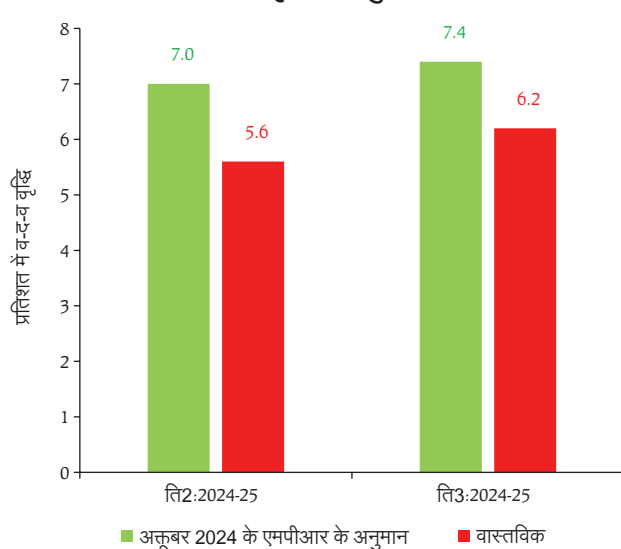
निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई), जो समग्र मांग का मुख्य अवयव है, में बहाली हुई और 2024-25 की तीसरी तिमाही में इसमें 6.9 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज की गई, जिसका समग्र घरेलू उत्पाद की संवृद्धि में 4.1 प्रतिशत बिंदु का योगदान रहा। शहरी उपभाग के उच्च आवृत्ति संसूचकों (एचएफआई) के अंतर्गत घरेलू हवाई यात्री करों में तीसरी तिमाही में 11.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह वृद्धि जनवरी-फरवरी 2025 में भी बनी रही। यात्री वाहन

की बिक्री में दूसरी तिमाही में कमी आने के बाद दूसरी छमाही में अब तक (अक्टूबर-फरवरी) धनात्मक वृद्धि हुई है। उपभोक्ता टिकाऊ उत्पादन में तीसरी तिमाही में 9.1 प्रतिशत और जनवरी में 7.2 प्रतिशत की दर से अच्छी बढ़ोतरी हुई, जो अपने विवेक से व्यय करने में हुई सतत वृद्धि का सूचक है। हाउसहोल्ड को दिए जाने वाले बैंक ऋण में गैर-प्रतिभूतिकृत वैयक्तिक ऋणों तथा क्रेडिट कार्डों के बकाया में कमी आने के बाद भी द्विअंकीय वृद्धि हुई। तीसरी तिमाही तथा जनवरी-फरवरी 2025 में तेजी से बिकने वाली उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमसीजी) की बिक्री की मात्रा की वृद्धि में उनके ग्रामीण समकक्षों के पिछड़े रहने के बाद भी सुधार दिखाई दिया (सारणी III.2)।

फसल उत्पादन अच्छे होने और जलाशय के स्तर में सुधार होने से मिली सहायता के साथ ग्रामीण मांग में बढ़ोतरी हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में एफएमसीजी की बिक्री की मात्रा, जो तीसरी तिमाही और जन-फर 2025 में काफी अच्छी थी, शहरी क्षेत्रों से आगे जारी रही। ट्रैक्टर की बिक्री पहली छमाही में मंद रहने के बाद 2024-25 की दूसरी छमाही में अब तक (अक्टूबर-फरवरी) उत्साही वृद्धि देखी गई है। उर्वरक की बिक्री में वृद्धि दूसरी तिमाही में गिरावट के बाद तीसरी तिमाही और जनवरी में मंद धनात्मक हो गई। हालांकि, मोटरसाइकिल की बिक्री में 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान अब तक गिरावट देखी गई है (सारणी III.2)।

भारत में निजी उपभोग और जीडीपी में एक मजबूत सह संचरण दिखाई देता है और यह किसी भी प्रकार के आघातों से विचलन के प्रति तेजी से समायोजित हो जाता है। हालांकि,

चार्ट III.2: जीडीपी संवृद्धि - अनुमान बनाम वास्तविक



स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमाना

सारणी III.2: उपभोग संकेतक

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

संकेतक	2023-24				2024-25				
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	जन	फर
शहरी मांग									
घरेलू हवाई यात्री शुल्क	19.1	23.0	9.1	5.2	5.6	7.2	11.4	14.1	12.1
यात्री वाहन की बिक्री*	9.6	5.8	8.7	10.8	3.4	-1.3	5.0	3.5	3.3
आईआईपी उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएँ	-2.7	1.1	5.3	11.2	10.7	6.6	9.1	7.2	
वैयक्तिक ऋण	21.3	18.2	17.6	17.6	16.6	16.4	14.9	14.2	14.0
वाहन ऋण	23.0	21.2	19.7	17.6	14.9	13.3	8.8	9.7	9.6
क्रेडिट कार्ड की बकाया राशि	37.6	31.4	32.6	25.6	23.3	18.0	15.6	13.0	11.2
ग्रामीण मांग									
ट्रेक्टर की बिक्री	-1.9	-5.8	-4.9	-22.9	0.5	0.7	13.5	11.4	35.9
मोटरसाइकिल की बिक्री	13.8	-2.9	22.1	27.0	16.8	10.2	-1.9	-3.1	-12.9
आईआईपी उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुएँ	6.8	7.0	2.5	0.7	-0.2	-2.2	-1.8	-0.2	
उर्वरक की बिक्री	-2.8	4.2	0.2	-7.4	5.5	-6.1	2.8	8.2	
एफएमसीजी बिक्री की मात्रा									
ग्रामीण	3.1	5.4	4.9	7.2	4.9	5.8	9.2	10.5	10.5*
शहरी	9.6	10.2	6.9	5.3	1.3	1.9	4.2	4.8	3.5*
अखिल-भारतीय	6.7	8.2	6.0	6.1	2.8	3.6	6.3	7.2	6.4*

टिप्पणी : * : फरवरी में लीप वर्ष के प्रभाव को समायोजित किया गया है। # : टाटा मोटर्स के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

स्रोत : नागरी विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए), भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माणकर्ता सोसायटी (एसआईएम); एनएसओ; आरबीआई ।

टैक्टर एवं मेकनाइजेशन संघ (टीएमए); तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय; नीलसनआईक्यू की खुदरा लेखापरीक्षा सेवा; आरबीआई स्टाफ अनुमान।

अभिसरण की गति में कोविड के बाद कोविड के पूर्व की तुलना में कमी आई है (बॉक्स III.1)।

जैसा कि शहरी आवधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के अंतर्गत श्रम शक्ति सहभागिता दर (एलएफपीआर) और

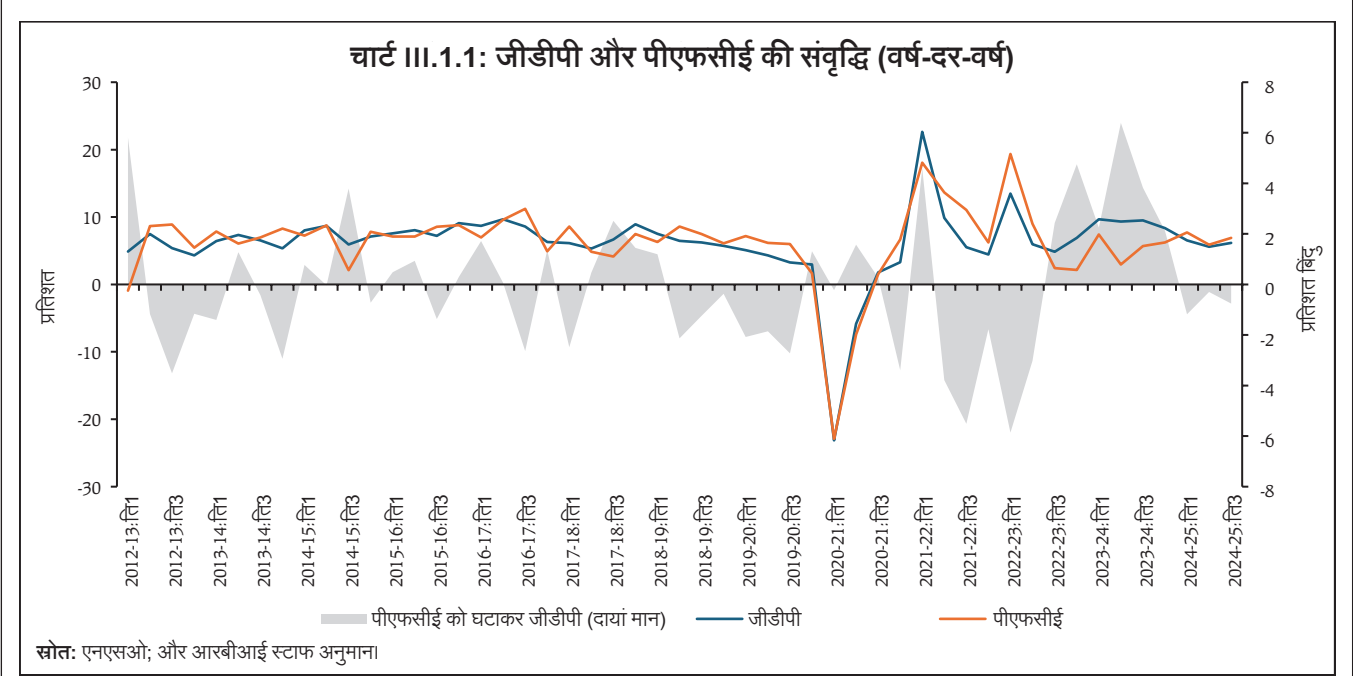
बॉक्स III.1 : उपभोग की पहली को सुलझाना : दीर्घावधि संबंध और आघात के पश्चात जीडीपी से अभिसरण

सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि को दिशा प्रदान करने में निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) का सुस्थापित महत्व है क्योंकि यह समग्र मांग का प्राथमिक कारक है, जो उत्पादन को सीधे तौर पर प्रभावित करता है (कीन्स, 1936)। भारत में भी अंतिम निजी उपभोग व्यय का वर्षों से समग्र मांग में सबसे बड़ा योगदान रहा है। भारत के संदर्भ में पीएफसीई और जीडीपी के बीच के संबंध की पड़ताल करने के लिए 1996-97 की पहली तिमाही से 2024-25 की तीसरी तिमाही तक के त्रैमासिक आंकड़ों का उपयोग करते हुए सह-समाकलन तकनीक का प्रयोग किया गया है।

इसके परिणामों से पीएफसीई और जीडीपी के बीच दृढ़ दीर्घावधि संबंध की पुष्टि होती है। अल्पावधि परिणाम यह इंगित करते हैं कि दीर्घावधि साम्य से विचलन में सुधार प्राथमिक रूप से निजी

उपभोग के समायोजन के माध्यम से होता है। इसका तात्पर्य यह है कि आर्थिक आघात के पश्चात साम्य को पुनर्स्थापित करने के लिए अंतिम निजी उपभोग व्यय की प्रतिक्रिया अधिक तीव्र गति से होती है। इसके साथ ही, कोविड से पहले की अवधि और पूर्ण प्रतिदर्श अवधि (कोविड और कोविड के बाद की अवधि को शामिल करते हुए) के परिणामों की तुलना से यह ज्ञात होता है कि पूर्ण प्रतिदर्श अवधि के लिए निजी उपभोग में समायोजन की गति कोविड पूर्व की अवधि की तुलना में धीमा थी। संभवतः ऐसा बड़ी हुई अनिश्चितता पर धीमी हो रही प्रतिक्रिया के कारण हुआ। तथापि, ये तथ्य भारत के आर्थिक पथ को आकार देने और बाहरी आघातों के प्रति इसकी आघातसहनीयता में अंतिम निजी उपभोग व्यय की महत्वपूर्ण भूमिका को मजबूती प्रदान करते हैं।

(जारी)



सारणी III.1.1: जीडीपी और पीएफसीई : सह-समाकलन और त्रुटि सुधार के अनुमान

कोविड से पहले (1998 ति1 – 2019 ति4)		
लॉन्ग-रन ईक्वेशन		
एलएन (जीडीपी)	0.96***	
	(-53.53)	
शॉर्ट-रन ईक्वेशन		
त्रुटि सुधार टर्म	डी(एलएनपीएफसीई)	डी(एलएनजीडीपी)
	-0.28***	-0.13
	(-2.92)	(-1.9)
समायोजित आर-स्क्वायर्ड	0.45	0.07
पूर्ण सैम्पल (1998 ति1 – 2024 ति3)		
लॉन्ग-रन ईक्वेशन		
एलएन (जीडीपी)	0.98***	
	(-48.77)	
शॉर्ट-रन ईक्वेशन		
त्रुटि सुधार टर्म	डी(एलएनपीएफसीई)	डी(एलएनजीडीपी)
	-0.19***	-0.06
	(-3.06)	(-1.37)
समायोजित आर-स्क्वायर्ड	0.77	0.83

टिप्पणियां: (1) जीडीपी और पीएफसीई श्रृंखलाएं मौसम के अनुसार समायोजित हैं; (2) वैश्विक महामारी से उत्पन्न अल्पावधि महत्वपूर्ण व्यवधानों को शामिल करने के लिए कोविड-19 डमीज का प्रयोग किया गया है, जिसमें 2020 की प्रारंभिक तिमाहियों के दौरान ऋणात्मक प्रभाव देखे गए, उसके बाद की अवधि में आंशिक बहाली देखी गई। (3) ट्रेस परीक्षण और मैक्स-आइजनवेल्यु परीक्षण महत्व के 5 प्रतिशत के स्तर पर सह-समाकलन संबंध को इंगित करते हैं; (4) कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े टी-स्टेटिक्स हैं; (5) *** 1 प्रतिशत के स्तर पर महत्व को दर्शाते हैं।

स्रोत: एनएसओ और आरबीआई स्टाफ के अनुमान।

संदर्भ :

1. इन्गल, आर एफ एवं ग्रेंगर, सी डब्लू जे (1987) सह-समाकलन और त्रुटि संशोधन : प्रतिनिधित्व, आकलन और परीक्षण – इकोनोमेट्रिका, 55(2), 252-276.
2. जोहान्सेन, एस (1988)। सहसमाकलन वेक्टर का सांख्यिकीय विश्लेषण। आर्थिक गतिशीलता और नियंत्रण पत्रिका, 12(2-3), 231-254.
3. कीन्स, जे एम (1937)। रोजगार का सामान्य सिद्धांत। अर्थशास्त्र की तिमाही पत्रिका, 15(2), 209-223.

सारणी III.3: भारत में रोजगार की स्थिति

(प्रतिशत)

संकेतक	2023-24				2024-25		
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3
श्रम शक्ति प्रतिभागिता दर	48.8	49.3	49.9	50.2	50.1	50.4	50.4
श्रमिक जनसंख्या अनुपात	45.5	46	46.6	46.9	46.8	47.2	47.2
बेरोजगारी की दर	6.6	6.6	6.5	6.7	6.6	6.4	6.4
ईपीएफओ के दस्तावेजों में हुई निवल पेयरोल बढ़ोतरी (वर्ष-दर-वर्ष)	-9.2	-0.6	12.5	22.7	7.8	-3.4	4.2

स्रोत: एनएसओ; और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ)।

रोजगार दर (ईआर) से पता चलता है, 2024-25 की तीसरी तिमाही में रोजगार परिस्थितियां अच्छी बनी रही हैं। शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी की दर तीसरी तिमाही में 6.4 प्रतिशत बनी रही, जो (पीएलएफएस) श्रृंखला में सबसे कम रही है। औपचारिक रोजगार में बेहतरी होने का प्रमाण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के पेरोल आंकड़ों से मिलता है। तीसरी तिमाही में पेयरोल में 4.2 प्रतिशत की निवल बढ़ोतरी हुई, जबकि पिछली तिमाही में इसमें कमी हुई थी (सारणी III.3)।

III.1.2 सकल स्थायी पूंजी निर्माण

सकल स्थायी पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) विस्तार तीसरी तिमाही: 2024-25 में 5.7 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 9.3 प्रतिशत की तुलना में कम था। चौथी तिमाही में, सहारा प्रदान करने वाले मुख्य संसूचकों के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं के आयात में जनवरी-फरवरी 2025 में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक सामानों, विद्युत और गैर-विद्युत मशीनों, लोहा और इस्पात, तथा मशीनी औजार अग्रणी रहे। जनवरी 2025 में पूंजीगत वस्तुओं के घरेलू उत्पादन में सुधार

हुआ। निर्माण गतिविधि के संयोग संकेतकों में, इस्पात की खपत और सीमेंट उत्पादन दोनों जनवरी-फरवरी 2025 में दोहरे अंकों की वृद्धि पर लौट आए। हालांकि, मार्च 2025 में इस्पात की खपत में मामूली संकुचन हुआ (सारणी III.4)।

विनिर्माण क्षेत्र² में क्षमता उपयोग (सीयू) 2024-25 की तीसरी तिमाही में बढ़कर 75.4 प्रतिशत हो गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 74.7 प्रतिशत था। मौसम के अनुसार 75.3 प्रतिशत रहा समायोजित क्षमता उपयोग 73.8 प्रतिशत³ के दीर्घावधिक औसत से काफी बेहतर रहा (चार्ट III.3)। निजी निवेश को बढ़ाने में क्षमता उपयोग का मजबूत होना महत्वपूर्ण निर्धारक के रूप में कार्य करता है (बॉक्स II.2)। पिछली कुछ तिमाहियों में क्षमता उपयोग के दीर्घावधि रुझान से अधिक के स्तर पर रहने के कारण बढ़ी हुई राजनीतिक अनिश्चितता निजी पूंजीगत व्यय की बहाली को कम करने वाली शक्ति के रूप में कार्य कर सकती है।

सूचीबद्ध निजी विनिर्माण कंपनियों के ब्याज व्याप्ति अनुपात (आईसीआर)⁴ 2024-25 की तीसरी तिमाही में पर्याप्त रहे, जो कर्ज चुकाने की बेहतर क्षमता को इंगित करता है और वित्तीय

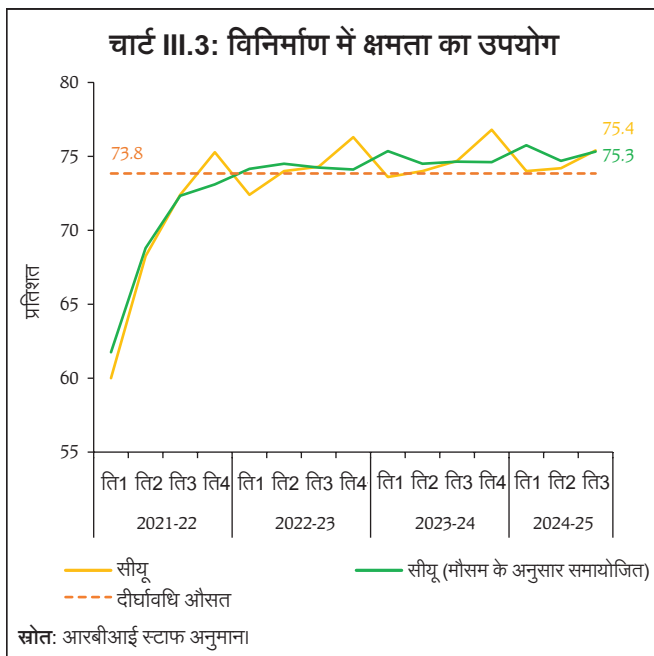
सारणी III.4: निवेश मांग के संकेतक

(वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत)

संकेतक	2023-24				2024-25					
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	जन	फर	मार्च
पूंजीगत वस्तुओं का आयात	9.2	9.6	5.6	8.9	10.0	11.7	6.0	15.5	-0.5	
आईआईपी : पूंजीगत वस्तुएं	5.1	8.8	7.5	4.1	3.0	4.9	7.3	7.8		
तैयार इस्पात का उपभोग	12.1	17.7	14.7	10.4	15.0	12.0	7.8	10.9	10.9	-0.5
सीमेंट का उत्पादन	12.7	10.3	5.1	7.6	0.4	3.2	6.7	14.5	10.5	

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआई एंड एस); संयुक्त प्लॉट समिति; तथा आर्थिक सलाहकार का कार्यालय।

² भारतीय रिजर्व बैंक की आदेश बही, माल-सूची और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) पर आधारित।³ दीर्घावधि औसत 2008-09 की पहली तिमाही से 2024-25 की तीसरी तिमाही से संबंधित हैं, जिसमें 2020-21 की पहली तिमाही को शामिल नहीं किया गया है।⁴ ब्याज व्याप्ति अनुपात ब्याज पर होने वाले व्यय की तुलना में ब्याज और कर के पूर्व आय का अनुपात होता है और यह कंपनियों के कर्ज पर ब्याज के भुगतान करने की उसकी क्षमता की माप करता है। व्यवहार्य आईसीआर की न्यूनतम माप 1 होती है।



परिस्थितियों के सुगम होने के साथ में यह क्षमता विस्तार के लिए शुभ संकेत है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, गैर-आईटी कंपनियों के ब्याज व्याप्ति अनुपात में तीसरी तिमाही के दौरान सुधार हुआ जबकि आईटी कंपनियों का ब्याज व्याप्ति अनुपात कम होने के बाद भी उच्च स्तर पर बना रहा (सारणी III.5)।

2023-24 में निवेश दर⁵ 31.4 प्रतिशत थी जो पिछले वर्ष के स्तर (32.6 प्रतिशत) से कम हुई। दूसरी तरफ, 2023-24 में घरेलू बचत दर निरंतर सकल घरेलू उत्पाद के 30.7 प्रतिशत के स्तर पर बनी रही, जो बाह्य वित्तपोषण पर निर्भरता में कमी को इंगित करता है (चार्ट III.4)। निवल हाउसहोल्ड वित्तीय बचत मामूली वृद्धि के साथ सकल घरेलू उत्पाद के 5.2 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई जो पिछले वर्ष 5.0 प्रतिशत थी, जो मुख्य रूप से हाउसहोल्डों की वित्तीय आस्तियों में वृद्धि होने की वजह से थी (सारणी III.6)।

बॉक्स III.2 : क्षमता उपयोग के नजरिए से निवेश की गतिशीलता

सार्वजनिक क्षेत्र ने सकल स्थायी निवेश के महामारी के बाद की बहाली में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जबकि निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र पिछड़ रहा है, जो अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता के विस्तार में महत्वपूर्ण है (आईएमएफ, 2025)। क्षमता उपयोग (सीयू) स्तर यह समझने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है कि क्या क्या निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले नए निवेशों से घरेलू मांग की स्थितियों में सुधार की शुरुआत हो सकती है। हाल की अवधि में विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग इसके दीर्घकालिक औसत से अधिक रहा है। आमतौर पर यह समझा जाता है कि सकारात्मक आर्थिक परिदृश्य के साथ मिलकर क्षमता उपयोग का उच्च स्तर नई क्षमता परिवर्धन को प्रोत्साहित करता है। हालांकि, उत्पादकता में सुधार से क्षमता उपयोग का स्तर कम हो सकता है। इस प्रकार, क्षमता उपयोग के न्यूनतम स्तर की जांच करना महत्वपूर्ण है; विशेष रूप से, वर्तमान समय में जब स्वस्थ बैलेंस शीट और वित्तीय स्थितियों में ढील के साथ निजी पूंजीगत व्यय चक्र में बदलाव के लिए वातावरण अनुकूल प्रतीत होता है। क्षमता उपयोग और निजी निवेश के बीच गतिशील संबंध को अनुभवजन्य रूप से पता लगाया

जाता है ताकि क्षमता उपयोग के न्यूनतम स्तर का पता लगाया जा सके जो निवेश को ट्रिगर करता है।

संरचनात्मक वेक्टर ऑटो-रिग्रेशन (एसवीएआर) मॉडल का आकलन पांच चरों⁶ अर्थात कारोबार प्रत्याशा, सीयू, सकल स्थायी निवेश, मुद्रास्फीति (जीएफसीएफ डिफ्लेटर) और रेपो दर का उपयोग करके 2008-09 की दूसरी तिमाही से 2024-25 की तीसरी तिमाही की अवधि के लिए किया जाता है। चूंकि यह माना जाता है कि अनिश्चितता के कारण वर्तमान और भावी निवेश में कमी होती है, इसे बहिर्जात चर⁷ के रूप में शामिल किया गया है। अनुभवजन्य परिणामों से यह पता चलता है कि निजी निवेश में हुई लगभग 50.0 प्रतिशत वृद्धि की व्याख्या क्षमता उपयोग के द्वारा हो जाती है, जो निजी निवेश के निर्धारक के रूप में इसकी प्रभावी भूमिका को दर्शाता है (चार्ट III.2.1)। यह पाया गया है कि आर्थिक नीति की अनिश्चितता से नए निवेश कम होने का प्रभाव पड़ता है। सीयू के न्यूनतम स्तर, आने वाले समय में निजी कॉर्पोरेट निवेश को ट्रिगर कर सकता है, का अनुमान चर के एक ही सेट के साथ

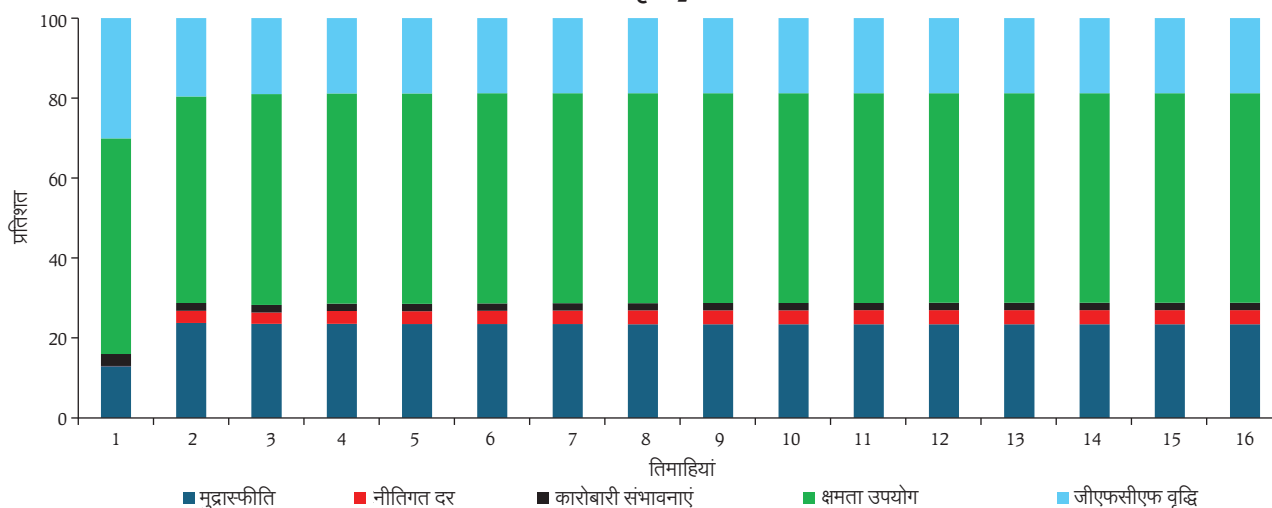
(जारी)

⁵ वर्तमान मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल पूंजी निर्माण का अनुपात।

⁶ कारोबारी संभावना सूचकांक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले तिमाही औद्योगिक परिदृश्य सर्वेक्षण (आईओएस) के अनुसार है; क्षमता उपयोग (सीयू) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाले तिमाही आदेश बही, माल-सूची और क्षमता उपयोग सर्वेक्षण (ओबीआईसीयूएस) के अनुसार है; निजी कॉर्पोरेट क्षेत्र द्वारा तिमाही सकल स्थायी पूंजी निर्माण की गणना अर्थमितीय पद्धति का प्रयोग करके वार्षिक अनुमान से की गई है।

⁷ अनिश्चितता की माप बैकर, ब्लूम और डैविस द्वारा प्रकाशित भारत से संबंधित आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक द्वारा की गई है।

चार्ट III.2.1: जीएफसीएफ वृद्धि के परिवर्तनों का विश्लेषण



स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

लगाया जाता है लेकिन थ्रेसहोल्ड वीएआर मॉडल (बाल्के, 2000) के वैकल्पिक विनिर्देश का उपयोग किया जाता है। परिणामों से सीयू

के न्यूनतम स्तर का 72.4 से 74.4 प्रतिशत के अंतर्गत होने का पता चलता है।

संदर्भ :

1. आईएमएफ (2025), 'इंडिया 2024 आर्टिकल IV कन्सल्टेशन', अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष कंट्री रिपोर्ट नं. 25/54.
2. एन बाल्के (2000), 'ऋण और आर्थिक गतिविधि : ऋण के दौर और आघातों का अरैखिक नमूने' द रिव्यू ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, खंड 82(2), 334-349.

III.1.3 सरकारी उपभोग

वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि के साथ तीव्र सुधार दर्ज किया गया, जबकि पहली छमाही में यह वृद्धि केवल 1.6 प्रतिशत थी, जिसका मुख्य कारण आम चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता का होना था। उल्लेखनीय है कि, ब्याज भुगतान और प्रमुख सब्सिडी को छोड़कर वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में केंद्र सरकार के राजस्व व्यय में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि

हुई, और पूंजीगत व्यय में 20.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट III.5)। हालांकि, वर्ष 2024-25 के लिए जीएफसीई वृद्धि पिछले वर्ष के 8.1 प्रतिशत की तुलना में घटकर 3.8 प्रतिशत हो गई।

सारणी III.5: ब्याज व्याप्ति अनुपात

(अनुपात)

क्षेत्र	2023-24				2024-25		
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3
विनिर्माण	6.8	7.5	7.4	7.5	7.9	7.9	7.6
सेवाएं (गैर-आईटी)	1.6	1.4	1.8	1.7	1.8	1.7	2.1
आईटी	44.5	43.2	41.2	44.1	42.9	45.6	40.9

टिप्पणी: 2024-25 की तीसरी तिमाही के आंकड़े सूचीबद्ध 2,924 गैर-सरकारी और गैर-वित्तीय कंपनियों के परिणामों पर आधारित हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

चार्ट III.4: बचत-निवेश अंतराल



स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी III.6: घरेलू बचत

(जीडीपी का प्रतिशत)

क्षेत्र	2011-12 से 2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
हाउसहोल्ड की बचत									
भौतिक (1)	13.3	10.7	11.6	12.4	11.4	11.0	12.8	13.7	13.0
सकल वित्तीय आस्तियां (2)	10.6	10.5	12.0	12.0	11.6	15.4	11.1	10.9	11.4
सकल वित्तीय देयताएँ (3)	3.1	3.0	4.4	4.1	3.9	3.7	3.8	5.9	6.2
निवल वित्तीय बचत (4=2-3)	7.5	7.4	7.6	7.9	7.7	11.7	7.3	5.0	5.2
कुल हाउसहोल्ड बचत (5=1+4)	20.8	18.1	19.3	20.3	19.1	22.7	20.1	18.6	18.1
निजी कॉर्पोरेट बचत (6)	10.8	10.8	11.5	11.2	10.5	10.2	10.5	11.2	11.0
सार्वजनिक बचत (7)	1.2	1.2	1.7	1.6	0.9	0.2	-4.1	-0.1	1.1
सकल घरेलू बचत (5+6+7)	32.8	32.8	31.3	32.1	31.7	29.6	29.1	31.2	30.7

टिप्पणी: भौतिक बचत में भौतिक आस्तियों में बचत और सोना तथा चाँदी के गहनों के रूप में बचत शामिल हैं।

स्रोत: एनएसओ।

वर्ष 2024-25 (आरई) के दौरान केंद्र सरकार के राजस्व व्यय (ब्याज भुगतान और प्रमुख सब्सिडी को छोड़कर) में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पूंजीगत व्यय में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण का अनुसरण करते हुए, केंद्र सरकार का सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) वर्ष 2024-25 (आरई) में सकल घरेलू उत्पाद का 4.7 प्रतिशत था, जो इसके बजट अनुमान से 20 आधार अंक कम था, और पिछले वर्ष की तुलना में 75 आधार अंक कम था। वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र के जीएफडी को सकल घरेलू उत्पाद का 4.4 प्रतिशत रखा गया है, जो 2025-26 तक जीएफडी-जीडीपी अनुपात को 4.5 प्रतिशत से कम करने के मध्यम अवधि के लक्ष्य के अनुरूप है। वर्ष 2025-26 (बीई) में केंद्र सरकार के राजकोषीय सुदृढ़ीकरण की योजना

मुख्य रूप से राजस्व व्यय में तर्कसंगत रूप से बनाई गई है, जबकि पूंजीगत व्यय पर जोर दिया गया है, जिसे जीडीपी के 3.1 प्रतिशत पर बजट में रखा गया है। सकल कर राजस्व वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान में 11.6 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025-26 (बीई) में जीडीपी के 12.0 प्रतिशत पर पहुंचने का अनुमान है (सारणी III.7)। पूंजीगत व्यय अनुपात की तुलना में राजस्व व्यय

सारणी III.7: केंद्र सरकार का वित्त

(जीडीपी का प्रतिशत)

संकेतक	2022-23	2023-24	2024-25 (आरई)	2025-26 (बीई)
1. सकल कर राजस्व	11.4	11.5	11.6	12.0
2. राजस्व प्राप्ति	8.9	9.1	9.3	9.6
ए. कर राजस्व (निवल)	7.8	7.7	7.7	7.9
बी. गैर-कर राजस्व	1.1	1.3	1.6	1.6
3. गैर-कर्ज पूंजी प्राप्ति	0.3	0.2	0.2	0.2
4. राजस्व व्यय	12.8	11.6	11.2	11.0
ए. ब्याज भुगतान	3.5	3.5	3.4	3.6
बी. प्रमुख सब्सिडी	2.0	1.4	1.2	1.1
5. ब्याज भुगतान और सब्सिडी को छोड़कर राजस्व व्यय	7.4	6.7	6.6	6.4
6. पूंजीगत व्यय	2.8	3.2	3.1	3.1
7. पूंजीगत परिव्यय	2.3	2.6	2.6	2.5
8. प्रभावी पूंजीगत व्यय	3.9	4.2	4.0	4.3
9. कुल व्यय	15.6	14.8	14.2	14.2
10. सकल राजकोषीय घाटा	6.5	5.5	4.7	4.4
11. राजस्व घाटा	4.0	2.5	1.8	1.5
12. प्राथमिक घाटा	3.0	2.0	1.3	0.8

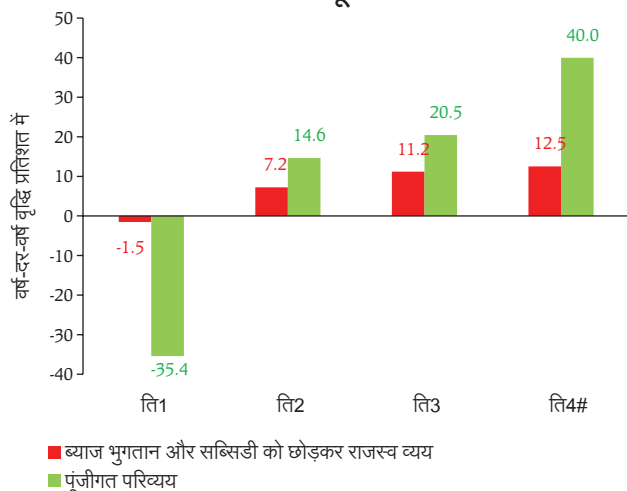
टिप्पणी: आरई: संशोधित अनुमान; बीई: बजट अनुमान।

प्रभावी पूंजीगत व्यय में पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए राज्यों को सहायता अनुदान शामिल है।

जीडीपी में संशोधन के कारण आंकड़े केंद्रीय बजट में प्रकाशित आंकड़ों से भिन्न हो सकते हैं।

स्रोत: केंद्रीय बजट 2025-26 और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

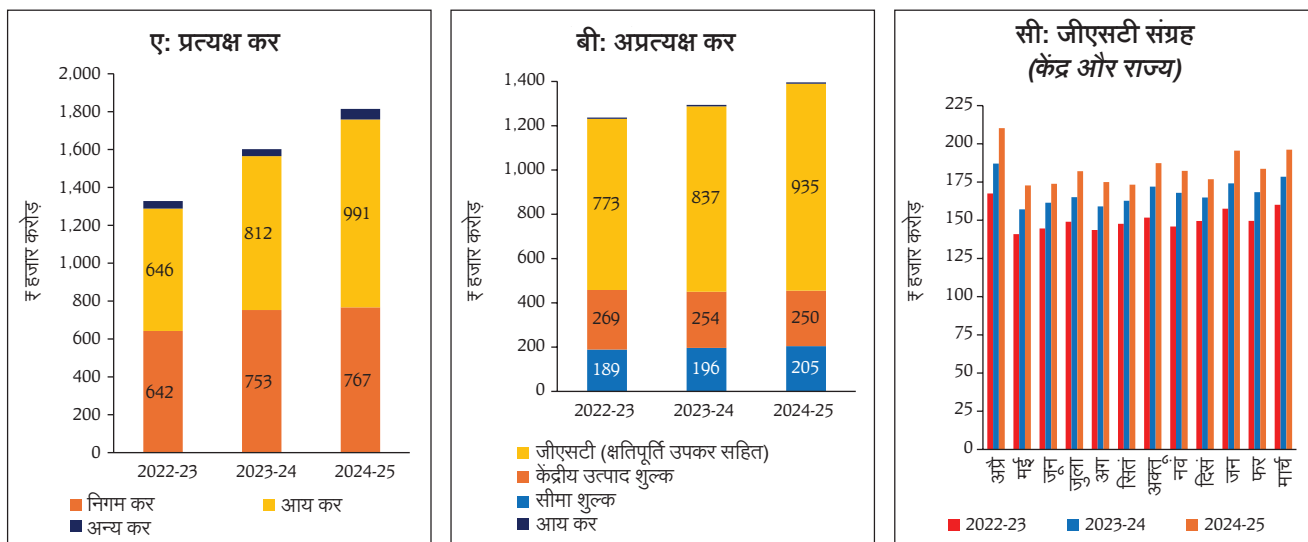
चार्ट III.5: वर्ष 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार का राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय



टिप्पणी: #: निहित

स्रोत: लेखा महानियंत्रक (सीजीए); और केंद्रीय बजट 2025-26

चार्ट III.6: केंद्र सरकार कर संग्रह: अप्रैल-फरवरी



स्रोत: सीजीए; पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी); और जीएसटी पोर्टल

(आरईसीओ), जो व्यय की गुणवत्ता का एक प्रमुख संकेतक है, वर्ष 2025-26 (बीई) में 4.4 रहा, जो पिछले दो वर्षों के समान है और तीन दशकों में सबसे कम है।

अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान, ब्याज और प्रमुख सब्सिडी भुगतान को छोड़कर केंद्र सरकार के राजस्व व्यय में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पूंजीगत व्यय में 0.8 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई। केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिसका कारण प्रत्यक्ष कर संग्रह में उछाल रहा। प्रत्यक्ष करों में 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि आयकर में 22.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वर्ष-दर-वर्ष 7.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें माल और सेवा कर (जीएसटी) और सीमा शुल्क में क्रमशः 11.6 और 4.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2024-25 के दौरान मासिक औसत जीएसटी संग्रह (केंद्र और राज्य) ₹1.84 लाख करोड़ था, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 9.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है (चार्ट III.6)।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कुल सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) वर्ष 2024-25 (बीई) के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 3.2 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था (सारणी III.8)। राज्यों ने कर और गैर-कर दोनों घटकों से प्रेरित 2024-25 (बीई) की राजस्व प्राप्ति में वृद्धि का अनुमान लगाया

है। विशेष रूप से, राज्यों ने 2024-25 में 22.4 प्रतिशत की बजटीय वृद्धि के साथ पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर अपना जोर जारी रखा है।

अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान राज्यों का जीएफडी उनके बजट अनुमान का 61.3 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष में दर्ज किए गए स्तर से अधिक है (चार्ट III.7.ए)। अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान भले ही गैर-कर राजस्व में वृद्धि धीमी रही किंतु राज्यों के लिए कुल राजस्व प्राप्ति में उछाल बना रहा, जो मुख्य रूप से कर राजस्व में मजबूत वृद्धि की वजह से थी। व्यय पक्ष पर नजर डालें तो पूंजीगत व्यय अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान मामूली रूप से 0.6 प्रतिशत कम हुआ, जबकि इस अवधि के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि तेजी से हुई (चार्ट III.7.बी)।

सारणी III.8: राज्य सरकार का वित्त - मुख्य राजकोषीय संकेतक

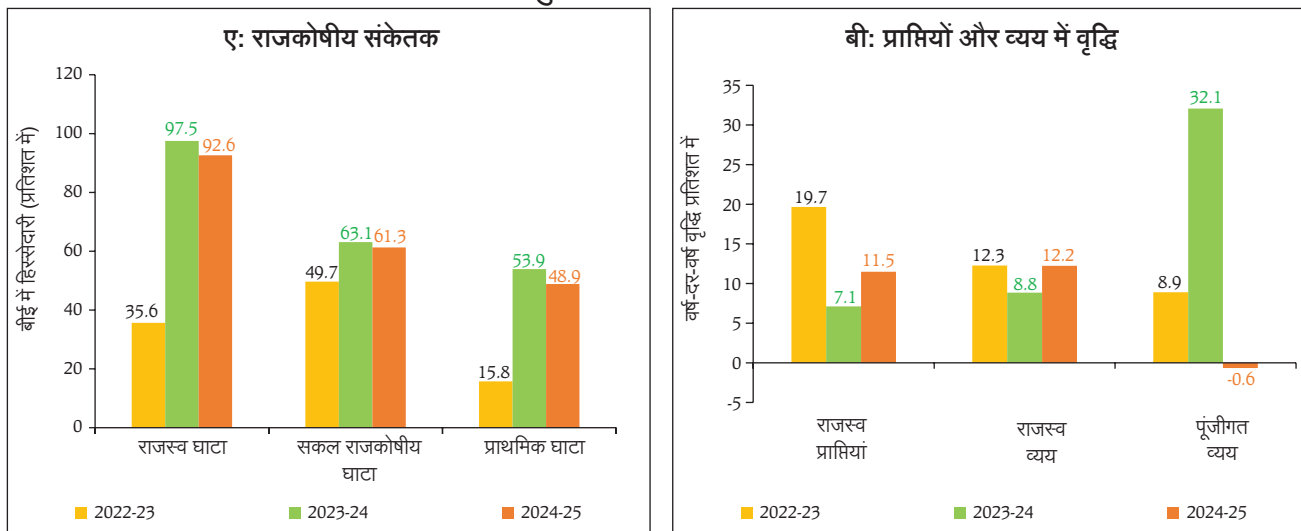
	(जीडीपी का प्रतिशत)		
मदें	2022-23 (ए)	2023-24 (पीए)	2024-25 (बीई)
राजस्व घाटा	0.2	0.2	0.2
सकल राजकोषीय घाटा	2.7	2.9	3.2
प्राथमिक घाटा	1.0	1.4	1.5

टिप्पणी: आंकड़े 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं

ए: वास्तविक; पीए: अंतिम लेखा; बीई: बजट अनुमान

स्रोत: राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के बजट दस्तावेज और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी)।

चार्ट III.7: राज्यों के प्रमुख राजकोषीय संकेतक: अप्रैल-जनवरी



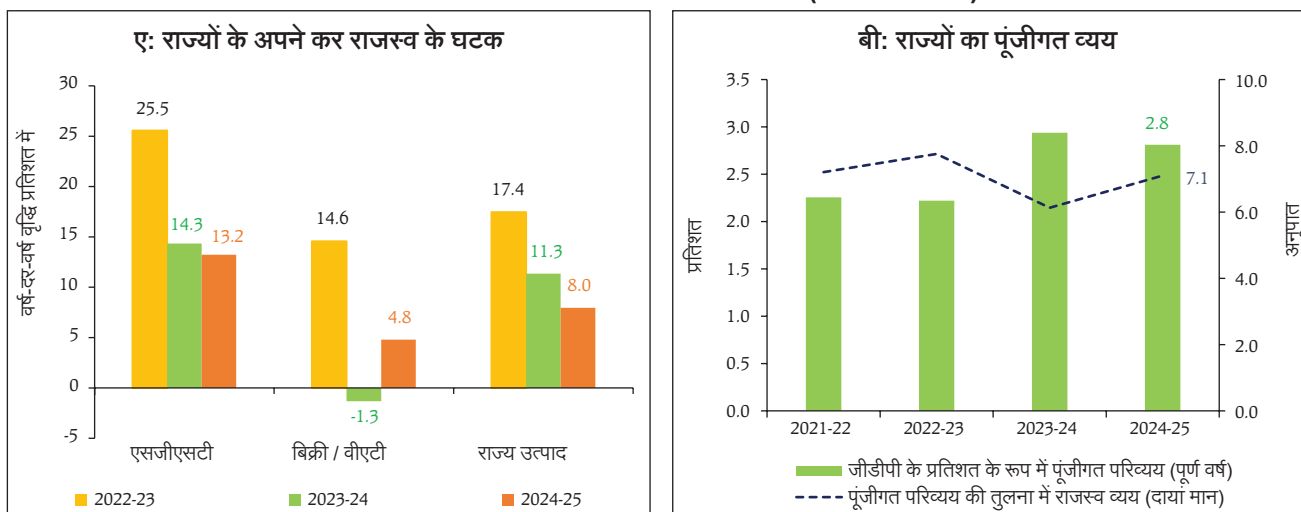
टिप्पणी: आंकड़े 21 राज्यों से संबंधित हैं

स्रोत: राज्य सरकारों के बजट दस्तावेज़; और सीएजी

राजस्व व्यय में वृद्धि के साथ-साथ पूंजीगत व्यय में कमी ने राज्य व्यय की गुणवत्ता को कम कर दिया है (चार्ट III.8)। राज्यों के पूंजीगत व्यय को पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना का सहारा प्राप्त है। इस पहल के तहत, केंद्र ने 31 जनवरी 2025 तक कुल ₹1,22,180

करोड़ के ऋण स्वीकृत किए हैं, जिनमें से लगभग ₹1,10,792 करोड़ संवितरित किए जा चुके हैं।⁸ निवेश और संवृद्धि को बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए केंद्रीय बजट में इस योजना को वर्ष 2025-26 के लिए विस्तारित कर दिया गया है।

चार्ट III.8: राज्यों का राजस्व और व्यय: (अप्रैल-जनवरी)



टिप्पणी: पूंजीगत परिसंचय की तुलना में राजस्व व्यय (आरईसीओ) अनुपात के आंकड़े 23 राज्यों से संबंधित हैं। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत परिसंचय के आंकड़े सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित हैं और वर्ष 2024-25 के आंकड़े बजट अनुमान हैं।

स्रोत: सीएजी; और आरबीआई।

⁸ लोकसभा अतारंकित प्रश्न संख्या 1080, https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU1080_mHyVcX.pdf?source=pqals पर उपलब्ध है।

सारणी III.9: सरकारी बाज़ार उधारियां

(₹ करोड़)

	2022-23			2023-24			2024-25		
	केंद्र	राज्य	कुल	केंद्र	राज्य	कुल	केंद्र	राज्य	कुल
निवल उधारियां	11.08,261	5.18,830	16.27,091	11.80,456	7.17,140	18.97,596	10.39,275	7.53,345	17.92,620
सकल उधारियां	14.21,000	7.58,392	21.79,392	15.43,000	10.07,058	25.50,058	14.00,697	10.73,310	24.74,007

स्रोत: भारत सरकार; तथा आरबीआई स्टाफ अनुमान।

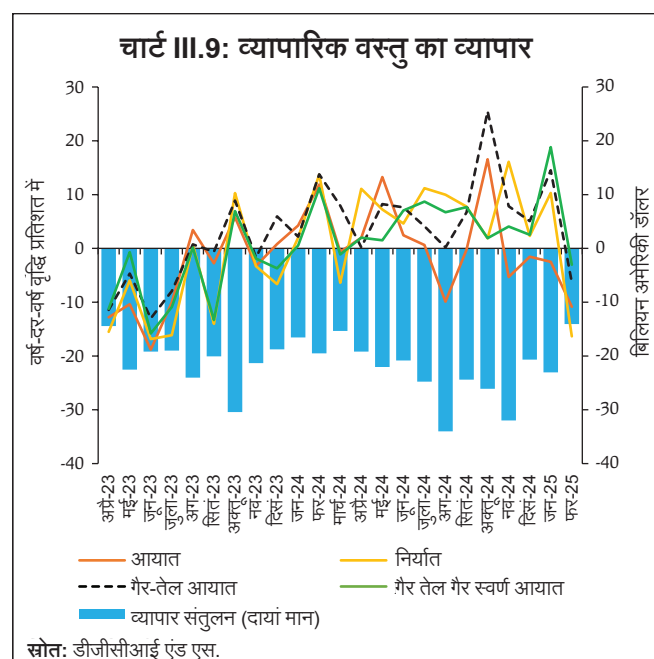
वर्ष 2024-25 में, केंद्र की सकल बाजार उधारी ₹14.01 लाख करोड़ थी, जो बजट अनुमानों से थोड़ी कम थी। सक्रिय ऋण समेकन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने केंद्र सरकार की ओर से आठ स्विच नीलामी आयोजित की, जिनकी कुल राशि ₹1.47 लाख करोड़ थी। इन नीलामियों में अल्प-परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों को दीर्घ परिपक्वता वाली प्रतिभूतियों से प्रतिस्थापित करना शामिल था। वर्ष 2024-25 के दौरान निर्माणों पर भारित औसत प्रतिफल घटकर 7.0 प्रतिशत हो गया, जो वर्ष 2023-24 में 7.2 प्रतिशत था। दूसरी ओर, उधारियों की भारित औसत परिपक्वता पिछले वर्ष के 18.1 वर्षों से बढ़कर 20.7 वर्ष हो गई। दूसरी तरफ, राज्यों ने वर्ष 2024-25 में ₹10.73 लाख करोड़ की बाजार उधारी जुटायी, जो वित्तीय वर्ष के लिए संस्वीकृत कुल राशि ₹11.72 लाख करोड़ से कम है (सारणी III.9)। प्राप्तियों और भुगतानों के बीच अस्थायी विसंगतियों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) की सीमा पिछले वर्ष की तुलना में अपरिवर्तित रही, जो कि पहली छमाही के लिए ₹1.5 लाख करोड़ और वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के लिए ₹50,000 करोड़ है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए (डब्ल्यूएमए) सीमा को पहले के ₹47,010 करोड़ से बढ़ाकर ₹60,118 करोड़ कर दिया गया, जो 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है⁹। वर्ष 2025-26 (बीई) के लिए केंद्र के सकल बाजार उधार और निवल उधार क्रमशः ₹14.82 लाख करोड़ और ₹11.54 लाख करोड़ रखे गए हैं।

III.1.4 बाह्य मांग

अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान, व्यापारिक निर्यात में 0.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई, जबकि व्यापारिक आयात में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही (अक्तूबर-फरवरी) में, भारत के व्यापारिक निर्यात में 1.2 प्रतिशत की कमी आई, जबकि आयात में 2.4 प्रतिशत

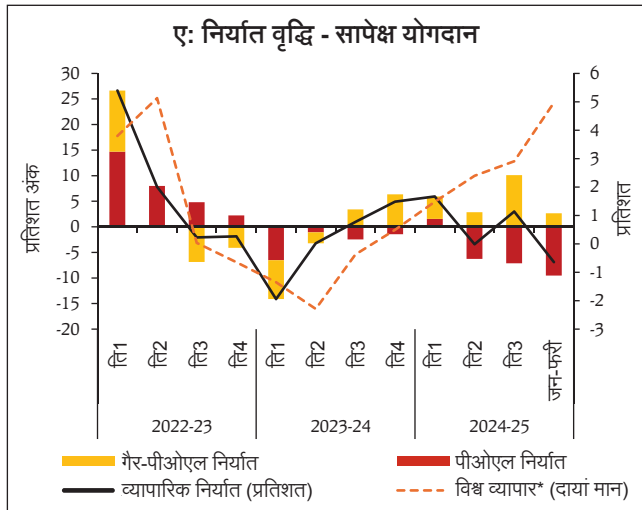
की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, व्यापारिक व्यापार घाटा 2024-25 की दूसरी छमाही (अक्तूबर-फरवरी) के दौरान बढ़कर 115.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में 106.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर था (चार्ट III.9)। दूसरी छमाही के दौरान व्यापारिक निर्यात में संकुचन मुख्य रूप से पेट्रोलियम, तेल और लूब्रिकेंट्स (पीओएल), रत्न और आभूषण, लौह अयस्क, कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन, तथा खली (ऑइल मिल्स) के कारण हुआ, जबकि इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान, चावल, सभी वस्त्रों में से रेडीमेड परिधान (आरएमजी), और दवाओं तथा फार्मास्यूटिकल्स ने सकारात्मक योगदान दिया (चार्ट III.10)।

वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही (अक्तूबर-फरवरी) के दौरान व्यापारिक आयात में वृद्धि मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना, मशीनरी (इलेक्ट्रिकल और गैर-इलेक्ट्रिकल दोनों), वनस्पति तेल और रासायनिक सामग्री और उत्पादों के आयात

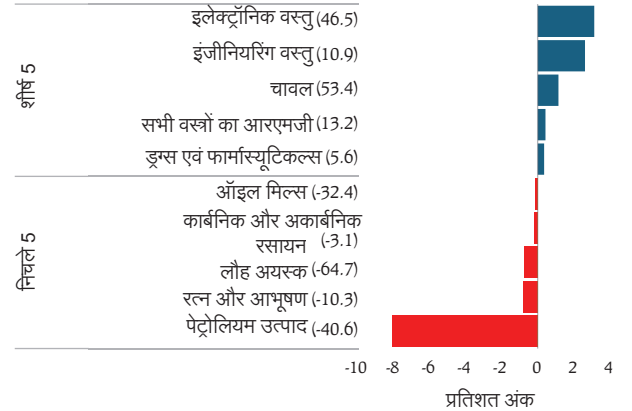


⁹ आरबीआई द्वारा गठित समूह द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, जिसमें चुनिंदा राज्य वित्त सचिव शामिल हैं।

चार्ट III.10: व्यापारिक निर्यात



बी: वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही (अक्टूबर-फरवरी) में निर्यात के प्रमुख चालक - सापेक्ष योगदान



टिप्पणी: चार्ट बी में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े इस अवधि के दौरान कमोडिटी के निर्यात में वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत परिवर्तन हैं।

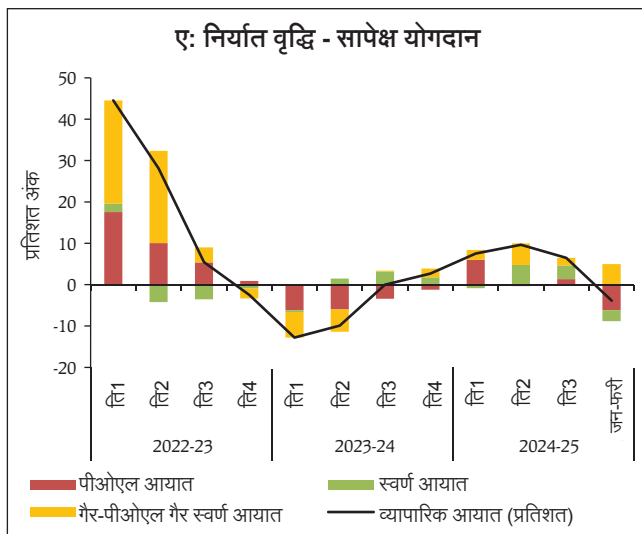
*: विश्व व्यापार के आंकड़े जनवरी 2025 तक उपलब्ध हैं।

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस; सीपीबी नीदरलैंड; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

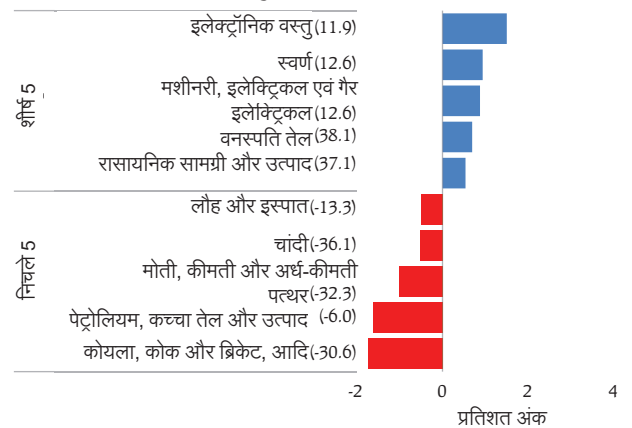
की वजह से थी (चार्ट III.11)। दूसरी ओर, कोयला, कोक और ब्रिकेट, पेट्रोलियम, कच्चे तेल और उत्पाद, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर, चांदी, और लौह एवं इस्पात के आयात ने समग्र आयात वृद्धि में नकारात्मक योगदान दिया। दूसरी छमाही के दौरान गैर-तेल निर्यात में 8.7 प्रतिशत की मजबूत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जबकि गैर-तेल गैर-सोना आयात 4.7 प्रतिशत बढ़कर इस अवधि के दौरान 199.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा।

वर्ष 2024-25 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान सेवाओं के निर्यात में 13.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि में दर्ज 5.5 प्रतिशत की वृद्धि से उल्लेखनीय वृद्धि है, जो भारतीय सेवाओं की मजबूत वैश्विक मांग को दर्शाता है। वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही (अक्टूबर-फरवरी) में, सेवाओं के निर्यात में पिछले वर्ष की मामूली 6.0 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट III.12)। दूसरी छमाही में वृद्धि मुख्य रूप से

चार्ट III.11: व्यापारिक आयात

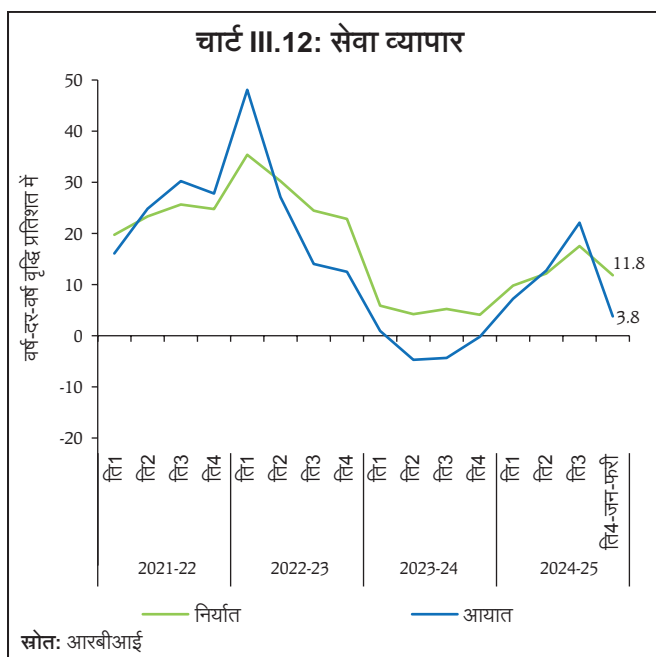


बी: वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही (अक्टूबर-फरवरी) में आयात के प्रमुख चालक - सापेक्ष योगदान



टिप्पणी: चार्ट बी में कोष्ठक में दिए गए आंकड़े इस अवधि के दौरान कमोडिटी के आयात में वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत परिवर्तन हैं।

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।



सॉफ्टवेयर, व्यवसाय और परिवहन सेवाओं में मजबूत प्रदर्शन की वजह से थी। दुनिया के अग्रणी सेवा-निर्यातक देशों में, भारत ने वर्ष 2024-25 (दिसंबर 2024 तक) में शीर्ष पांच देशों में अपना स्थान बनाए रखा। संकुचन के बाद सेवा आयात में उछाल आया, तथा वर्ष 2024-25 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान 12.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि घरेलू मांग में तेजी के कारण दूसरी छमाही (अक्तूबर-फरवरी) में 14.6 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

भुगतान संतुलन (बीओपी) के आधार पर, भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही के 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.1 प्रतिशत) से मामूली रूप से बढ़कर वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.1 प्रतिशत) हो गया, लेकिन 2024-25 की दूसरी तिमाही के 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.8 प्रतिशत) से कम हो गया।

वित्तीय खातों में, भारत में निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह अप्रैल-जनवरी 2024-25 में पिछले वर्ष की समान अवधि के 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य कारण प्रत्यावर्तन में उछाल और जावक एफडीआई में वृद्धि है (सारणी III.10)। हालांकि, कुल एफडीआई प्रवाह वर्ष 2024-25 (जनवरी तक) में 69.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर मजबूत रहा, जो

सारणी III.10: निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और पोर्टफोलियो निवेश

(बिलियन अमेरिकी डॉलर)

	2023-24				2024-25			
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
निवल एफडीआई	4.7	-0.8	4.0	2.3	6.6	-2.3	-2.8	0.9#
निवल एफपीआई*	16.1	5.3	11.7	11.6	0.9	19.8	-11.4	-6.8

टिप्पणीयां: #: वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के लिए निवल एफडीआई जनवरी 2025 तक है;

*: 2024-25 की तीसरी तिमाही तक के निवल एफपीआई डेटा आरबीआई के भुगतान संतुलन (बीओपी) सांख्यिकी पर आधारित हैं, जबकि 2024-25 की चौथी तिमाही के डेटा एनएसडीएल द्वारा प्रकाशित दैनिक डेटा से लिए गए हैं।

स्रोत: नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल); और आरबीआई।

पिछले वर्ष की तुलना में 15.3 प्रतिशत बढ़ा, जो पिछले वर्ष की समान अवधि के 2.6 प्रतिशत की कमी की तुलना में उल्लेखनीय उछाल है। एफडीआई प्रवाह के प्रमुख स्रोतों में सिंगापुर, मॉरीशस, यूएसए, यूएई, नीदरलैंड और जापान शामिल हैं, जिनकी कुल एफडीआई में हिस्सेदारी 80.0 प्रतिशत है। अधिकांश एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह विनिर्माण, वित्तीय सेवाओं, बिजली उत्पादन, वितरण और संचरण, संचार सेवाओं, खुदरा और थोक व्यापार तथा कंप्यूटर सेवाओं में था, जिन्हें कुल मिलाकर एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह का 77.0 प्रतिशत प्राप्त हुआ।

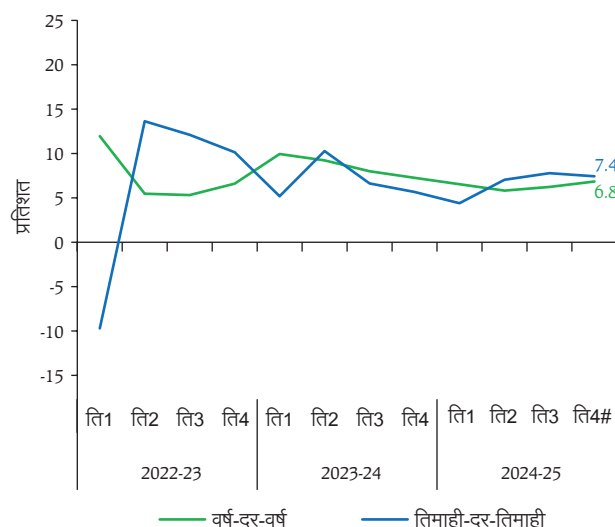
भारत में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) में वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में 18.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल बहिर्वाह दर्ज किया गया, क्योंकि पोर्टफोलियो निवेशक मुख्य रूप से बढ़ी हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के कारण इक्विटी में निवल विक्रेता बन गए। हालांकि, कर्ज खंड (डेट सेगमेंट) में एफपीआई प्रवाह वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में कम हुआ, लेकिन वे पूरे वर्ष के लिए सकारात्मक रहे, जो जे.पी. मॉर्गन के बेंचमार्क उभरते बाजार सूचकांक और अन्य सूचकांकों में भारतीय सरकारी बॉण्ड के समावेश को दर्शाता है। कुल मिलाकर, एफपीआई में वर्ष 2024-25 में 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 44.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवल अंतर्वाह से काफी कम है। अनिश्चित वैश्विक आर्थिक परिदृश्य, बढ़ते अमेरिकी बॉण्ड प्रतिफल और कॉर्पोरेट आय में नरमी ने एफपीआई की धारणा को कमजोर कर दिया है। मार्च 2025 में एफपीआई प्रवाह फिर से बढ़ा है और 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल अंतर्वाह दर्ज किया गया है।

बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) प्रवाह में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान 15.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, जो एक वर्ष पहले 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। सभी तीनों खातों, अर्थात्, एफसीएनआर(बी), एनआरई और एनआरओ में जमाराशियों में मजबूत वृद्धि के कारण अप्रैल-जनवरी 2024-25 में अनिवासी जमाराशियों में निवल वृद्धि पिछले वर्ष के 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 14.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। 28 मार्च 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 665.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो भुगतान संतुलन के आधार पर 11.0 महीने के वार्षिक व्यापारिक आयात के बराबर है और दिसंबर 2024 तक बकाया विदेशी कर्ज का 92.7 प्रतिशत है।

III.2 सकल आपूर्ति

मूल कीमतों पर वास्तविक सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) द्वारा मापित सकल आपूर्ति में वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 6.2 प्रतिशत (2023-24 की तीसरी तिमाही में 8.0 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो पिछली तिमाही (2024-25 की दूसरी तिमाही में 5.8 प्रतिशत की वृद्धि) से काफी सुधार दर्शाती है। तीसरी तिमाही में इस सुधार में कृषि और संबद्ध क्षेत्र की गतिविधि में मजबूत वृद्धि और सेवा गतिविधि में लचीलेपन द्वारा सहायता मिली (सारणी III.11 और चार्ट III.13)।

चार्ट III.13: जीवीए वृद्धि और गति



टिप्पणी: #: निहित; और एसएएआर – मौसमी रूप से समायोजित वार्षिकीकृत दरा
 स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

III.2.1 कृषि

कृषि और संबद्ध गतिविधियों में वास्तविक जीवीए ने अच्छे खरीफ उत्पादन के दम पर 2024-25 की तीसरी तिमाही में 5.6 प्रतिशत की सात तिमाही की उच्च वृद्धि दर्ज की (एक वर्ष पहले 1.5 प्रतिशत)।

27 मार्च 2025 तक, भारत भर के प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण का स्तर पूर्ण क्षमता का 42 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष की

सारणी III.11: वास्तविक जीवीए वृद्धि

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

क्षेत्र	2023-24	2024-25	भारत योगदान		2023-24				2024-25			
	(एफआरई)	(एसएई)	2023-24	2024-25	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4#
कृषि, वानिकी और फिशिंग	2.7	4.6	0.4	0.7	5.7	3.7	1.5	0.9	1.7	4.1	5.6	6.2
उद्योग	11.0	4.3	2.4	0.9	6.6	15.3	12.6	9.9	7.7	2.0	3.5	4.3
खनन और उत्खनन	3.2	2.8	0.1	0.1	4.1	4.1	4.7	0.8	6.8	-0.3	1.4	2.4
विनिर्माण	12.3	4.3	2.1	0.8	7.3	17.0	14.0	11.3	7.5	2.1	3.5	4.3
बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगिताएं	8.6	6.0	0.2	0.1	4.1	11.7	10.1	8.8	10.2	3.0	5.1	6.0
सेवाएँ	9.2	7.5	5.8	4.7	12.1	8.3	8.5	8.0	7.2	7.4	7.3	8.0
निर्माण	10.4	8.6	0.9	0.8	9.2	14.6	10.0	8.7	10.1	8.7	7.0	8.9
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	7.5	6.4	1.4	1.2	11.0	5.4	8.0	6.2	5.4	6.1	6.7	7.0
वित्तीय, अचल संपत्ति और व्यावसायिक सेवाएं	10.3	7.2	2.4	1.7	15.0	8.3	8.4	9.0	6.6	7.2	7.2	8.0
लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं	8.8	8.8	1.1	1.1	9.3	8.9	8.4	8.7	9.0	8.8	8.8	8.7
मूल कीमतों पर जीवीए	8.6	6.4	8.6	6.4	9.9	9.2	8.0	7.3	6.5	5.8	6.2	6.8

टिप्पणियां: एफआरई : प्रथम संशोधित अनुमान; एसएई : द्वितीय अग्रिम अनुमान; #: निहिता

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी III.12: 2024-25 में कृषि उत्पादन

(लाख टन)

फसल	2023-24 अंतिम अनुमान	2024-25		2024-25 में परिवर्तन (प्रतिशत) 2023-24 की तुलना में
		लक्ष्य	एसएई	
1. खाद्यान्न	3157.7	3259.2	3309.2	4.8
खरीफ़	1557.7	1613.7	1663.9	6.8
रबी	1600.1	1645.5	1645.3	2.8
क. चावल	1278.6	1260.5	1364.4	6.7
ख. गेहूँ	1132.9	1150.0	1154.3	1.9
ग. दलहन	221.7	276.5	230.2	3.8
2. तिलहन	384.4	434.0	416.7	8.4
3. गन्ना	4531.6	4700.0	4350.8	-4.0
4. कपास #	325.2	350.0	294.3	-9.5
5. पटसन और मेस्टा##	96.9	105.0	86.2	-11.0

टिप्पणियाँ: सारणी केवल खरीफ और रबी मौसम को कवर करता है।

#: प्रत्येक 170 किग्रा की लाख गांठ, ##: प्रत्येक 180 किग्रा की लाख गांठ।

एसएई: दूसरे अग्रिम अनुमान।

स्रोत: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय; भारत सरकार।

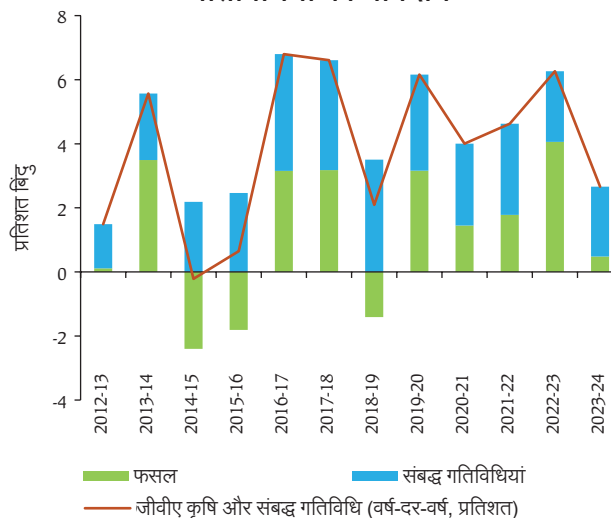
तुलना में 16.5 प्रतिशत और दशकीय औसत से 14.6 प्रतिशत अधिक है। विशेष रूप से, उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों को छोड़कर सभी क्षेत्रों में भंडारण का स्तर दशकीय औसत से अधिक हो गया।

वर्ष 2024-25 के लिए दूसरे अग्रिम अनुमान (एसएई) में खाद्यान्न उत्पादन 3309.2 लाख टन रखा गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है (सारणी III.12)। प्रमुख फसलों में खरीफ और रबी दोनों फसलों में चावल उत्पादन में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि गेहूँ के उत्पादन में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दालों के उत्पादन में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान है। वाणिज्यिक फसलों में तिलहन उत्पादन में 8.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि कपास और गन्ने के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई।

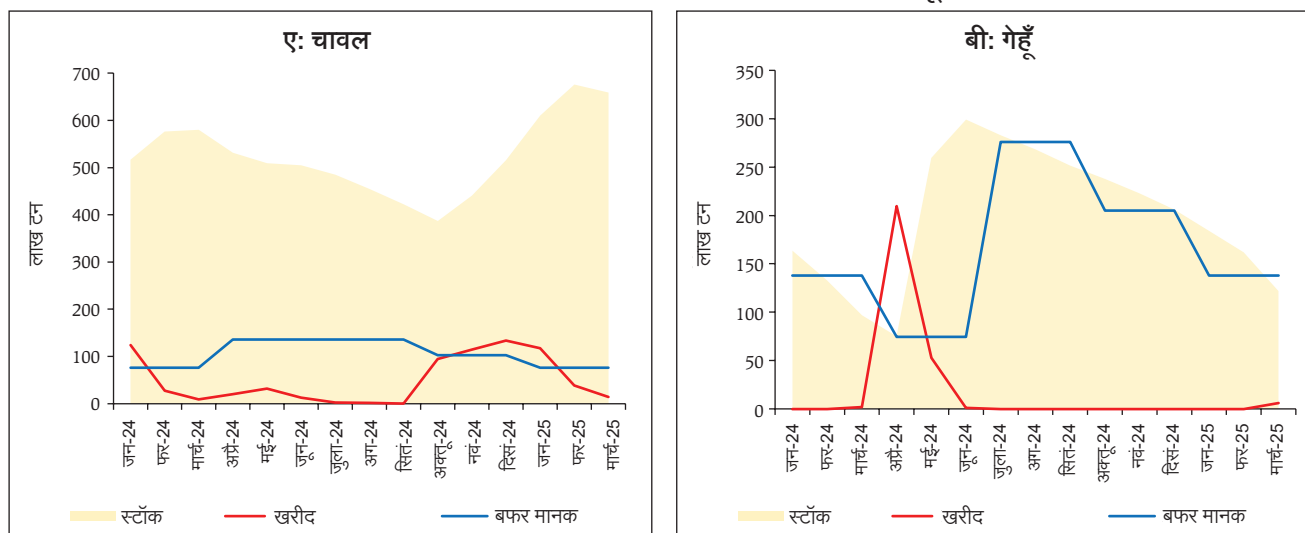
वर्ष 2024-25 में बागवानी फसलों का उत्पादन पहले अग्रिम अनुमानों (एसएई) के अनुसार 3620.9 लाख टन तक पहुँच गया, जो वर्ष 2023-24 के अंतिम अनुमानों से 2.1 प्रतिशत अधिक था। उत्पादन में वृद्धि को मुख्य रूप से प्याज और आलू के उच्च उत्पादन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

पशुधन, वानिकी और मछली पकड़ने जैसी संबद्ध गतिविधियों ने 2023-24 में कृषि जीवीए वृद्धि में लगभग 82.0 प्रतिशत का योगदान दिया (चार्ट III.14)। कृषि और संबद्ध गतिविधियों का वास्तविक जीवीए 2023-24 (एफआरई) में 2.7 प्रतिशत बढ़ा, ऐसा मुख्य रूप से पशुधन में 5.4 प्रतिशत की वृद्धि

चार्ट III.14: फसल और संबद्ध गतिविधियाँ का योगदान



स्रोत: एनएसओ, और आरबीआई स्टाफ अनुमान

चार्ट III.15: स्टॉक और खरीद – चावल और गेहूँ


टिप्पणी: स्टॉक डेटा 16 मार्च 2025 के हैं।

स्रोत: भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई); और केन्द्रीय खाद्यान्न क्रय पोर्टल (सीएफपीपी)।

और मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में 5.9 प्रतिशत की वृद्धि से हुआ है। वर्ष 2023-24 में, कुल मांस उत्पादन में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि दूध उत्पादन में 3.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

31 मार्च 2025 तक, वर्ष 2024-25 के खरीफ़ विपणन सीजन के लिए चावल की खरीद 511.5 लाख टन तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.9 प्रतिशत अधिक है। 16 मार्च 2025 तक चावल का स्टॉक 659.3 लाख टन था, जो बफर आवश्यकता का 8.7 गुना था, जबकि 121.7 लाख टन गेहूँ का स्टॉक बफर मानदंडों से थोड़ा कम था (चार्ट III.15)।

ट्रैक्टर, उर्वरक बिक्री और कृषि निर्यात जैसे उच्च आवृत्ति संकेतकों ने वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उछाल दर्शाया, जबकि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत रोजगार की मांग और कृषि ऋण वृद्धि में नरमी देखी गई (सारणी III.13)। बेहतर जलाशय स्तरों के साथ मिलकर उच्च खरीफ और रबी उत्पादन ग्रामीण आर्थिक गतिविधि के लिए सहायक हैं। बागवानी उत्पादन के लिए एफआई भी पिछले वर्ष की तुलना में सकारात्मक रुझान दर्शाता है।

सारणी III.13: ग्रामीण अर्थव्यवस्था - उच्च आवृत्ति संकेतक

मद	यूनिट	पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर)			दूसरी छमाही (अक्टूबर-मार्च)		
		2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
ट्रैक्टर की बिक्री*	संख्या (लाख में)	4.9	4.7	4.7	3.8	3.3	3.9
टू-व्हीलर सेल्स*	संख्या (लाख में)	84.0	87.4	101.6	61.7	77.5	77.9
उर्वरक की बिक्री#	लाख टन	335.4	338.5	335.5	248.8	243.8	253.6
रोजगार की मांग (मनरेगा)	करोड़ परिवार	13.9	15.1	12.6	12.0	11.5	12.0
कृषि और संबद्ध क्षेत्र का निर्यात#	बिलियन अमेरिकी डॉलर	26.4	23.3	23.4	16.4	15.4	18.2
कृषि ऋण वृद्धि*	वर्ष-दर-वर्ष	13.4	16.7	16.4	14.9	20.	11.4
चावल स्टॉक से बफर मानदंड**	अनुपात	2.8	3.1	3.8	5.8	7.6	8.7
गेहूँ स्टॉक से बफर मानदंड**	अनुपात	1.1	1.2	1.2	0.7	0.6	0.9

टिप्पणियाँ: *: फरवरी तक; #: जनवरी तक; **: 16 मार्च 2025 तक।

स्रोत: टीएमए; सियाम; एमओसी एंड एफ; ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी); सीएमआईई; आरबीआई; और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई)।

III.2.2 उद्योग

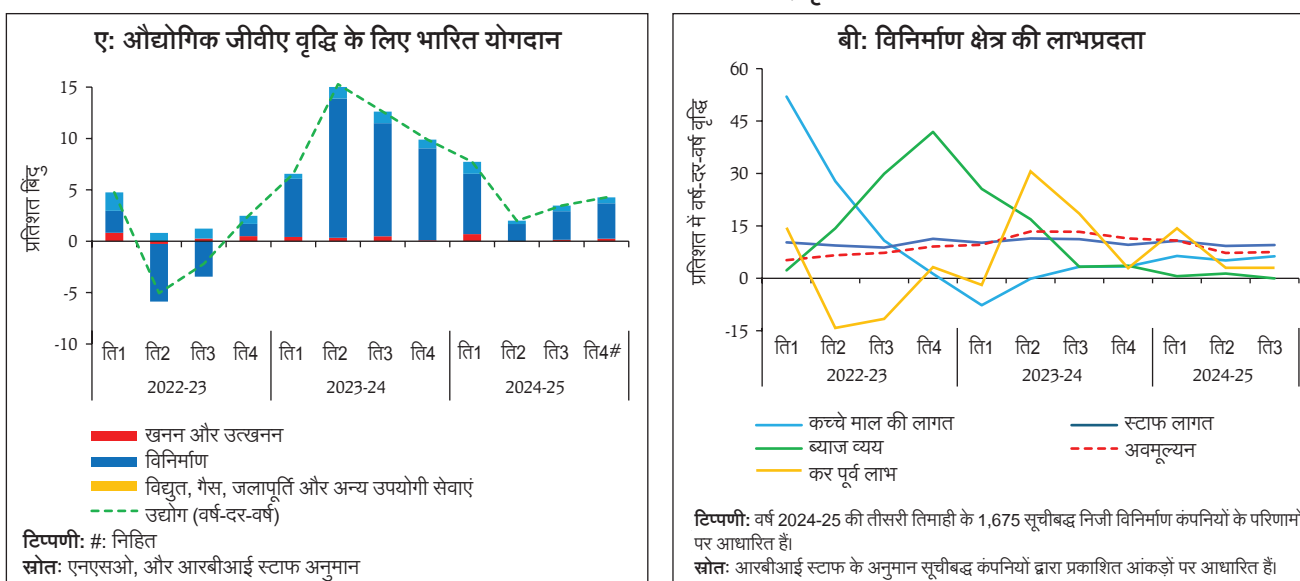
एसएई के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि 2024-25 में घटकर 4.3 प्रतिशत हो गई, जो पिछले वर्ष में 11.0 प्रतिशत थी, जिसका मुख्य कारण विनिर्माण में तेज मंदी के साथ-साथ खनन गतिविधि में मंदी थी। हालांकि, औद्योगिक क्षेत्र ने मामूली रूप से जोर पकड़ा और 2024-25 की तीसरी तिमाही में 3.5 प्रतिशत तक विस्तार किया, जबकि दूसरी तिमाही में 2.0 प्रतिशत था, जो विनिर्माण गतिविधि में सुधार से समर्थित था। विनिर्माण क्षेत्र में बिक्री वृद्धि और परिचालन लाभ में धीरे-धीरे सुधार देखा गया। खनन और उत्खनन गतिविधियों में तीसरी तिमाही में कोयला उत्पादन में मंदी और कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में संकुचन देखा गया। विद्युत, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवाओं का जीवीए तीसरी तिमाही के दौरान 5.1 प्रतिशत बढ़ा, जो अपेक्षाकृत गर्म सर्दियों के साथ-साथ औद्योगिक गतिविधि में मंदी के कारण था (चार्ट III.16)।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान 4.1 प्रतिशत और जनवरी में 5.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट III.17 और सारणी III.14)। खनन और उत्खनन क्षेत्र में तीसरी तिमाही में 1.8 प्रतिशत और जनवरी

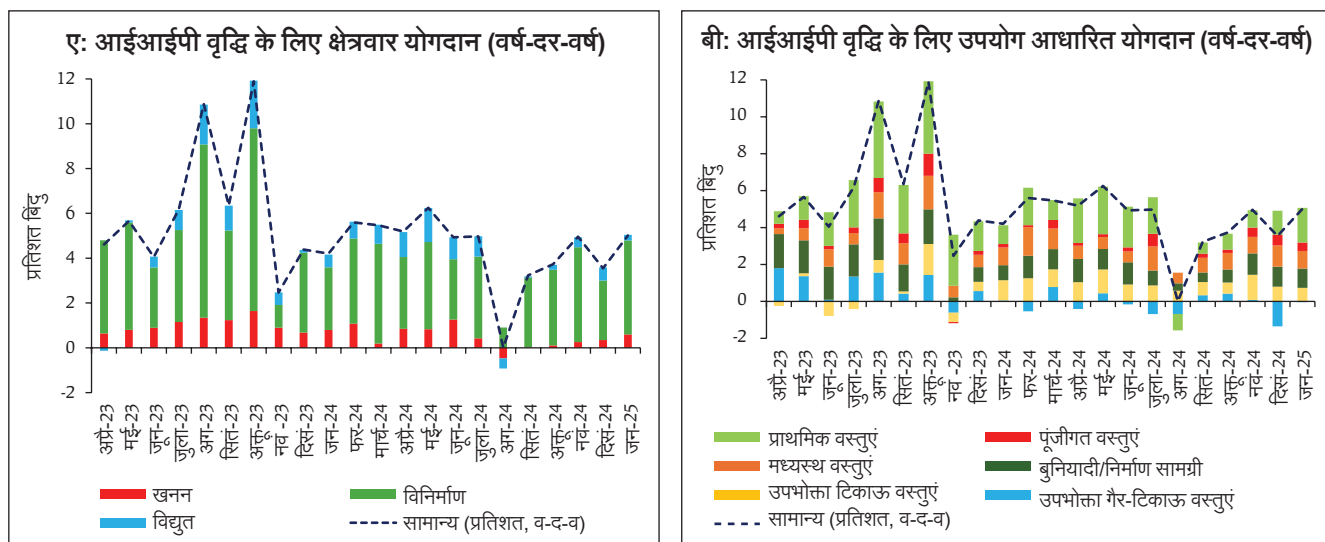
में 4.4 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई। विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर तीसरी तिमाही में 4.4 प्रतिशत रही जो पिछले वित्त वर्ष में 5.4 प्रतिशत थी। जबकि बुनियादी धातुओं, विद्युत उपकरणों, कोक और परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों, गढ़े धातु उत्पादों, और मशीनरी और उपकरणों के उत्पादन ने तीसरी तिमाही में वृद्धि हुई, लेकिन खाद्य उत्पादों, फार्मास्यूटिकल्स, मुद्रण और चमड़े के उत्पादों के निर्माण ने वृद्धि को थोड़ा धीमा किया। उपयोग आधारित वर्गीकरण के संदर्भ में प्राथमिक, पूंजी, मध्यवर्ती, बुनियादी ढांचा और टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में तीसरी तिमाही और जनवरी के दौरान वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, इस अवधि के दौरान उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं में संकुचन देखा गया।

बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाओं में दूसरी छमाही में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में बिजली उत्पादन में 4.0 प्रतिशत (एक साल पहले 9.2 प्रतिशत) की मामूली वृद्धि हुई, कम कठोर सर्दियों के कारण कम मांग के बीच थर्मल पावर उत्पादन मंद रहा। नवीकरणीय ऊर्जा, जिसकी कुल उत्पादन में 12.7 प्रतिशत की हिस्सेदारी है, तीसरी तिमाही में 17.2 प्रतिशत की तेजी से बढ़ी। चौथी तिमाही (फरवरी तक) में बिजली उत्पादन में 3.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

चार्ट III.16: औद्योगिक जीवीए वृद्धि



चार्ट III.17: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)



स्रोत: एनएसओ, और आरबीआई स्टाफ अनुमाना

क्षेत्र-वार, बिजली की मांग ने विचलन प्रदर्शित किया – जबकि उत्तरी क्षेत्र ने मजबूत मांग बनाए रखी, अन्य क्षेत्रों में मांग में कमी दर्ज की गई, दक्षिणी क्षेत्र में तीसरी तिमाही में संकुचन देखा गया।

चौथी तिमाही में, बिजली की मांग में वृद्धि 3.5 प्रतिशत तक बढ़ गई, जिसमें पश्चिमी क्षेत्र वृद्धि में आगे है, इसके बाद पूर्वी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्र हैं (सारणी III.15)।

सारणी III.14: औद्योगिक क्षेत्र में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

(प्रतिशत)

संकेतक	2024-25					
	ति1	ति2	ति3	जन	फर	मार्च
1 पीएमआई : विनिर्माण (>50 पिछले महीने की तुलना में वृद्धि दर्शाता है)	58.2	57.4	56.8	57.7	56.3	58.1
2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)	5.5	2.7	4.1	5.0		
3 आईआईपी: विनिर्माण	4.3	3.3	4.4	5.5		
4 आईआईपी: प्राथमिक वस्तुएं	1.1	1.6	3.0	5.5		
5 आईआईपी: पूंजीगत वस्तुएं	3.0	4.9	7.3	7.8		
6 आईआईपी: बुनियादी ढांचा और निर्माण सामान	8.1	3.9	6.7	7.0		
7 आईआईपी: कंज्यूमर ड्यूरेबल्स	10.7	6.6	9.1	7.2		
8 आईआईपी: कंज्यूमर नॉन-ड्यूरेबल्स	-0.2	-2.2	-1.8	-0.2		
9 आठ मुख्य उद्योग (ईसीआई)	6.3	2.4	4.8	5.1	2.9	
10 ईसीआई: स्टील	8.4	4.3	7.8	4.7	5.6	
11 ईसीआई: सीमेंट	0.4	3.2	6.6	14.6	10.5	
12 बिजली की मांग	10.2	-0.7	2.6	1.3	2.4	6.6
ऑटोमोबाइल का उत्पादन						
13 यात्री वाहन	5.8	-0.7	-8.9	3.7	4.5	
14 दुपहिया वाहन	19.6	12.5	8.0	10.3	1.6	
15 तीन पहिया वाहन	9.4	6.3	-2.1	16.2	6.5	
16 ट्रैक्टर	1.0	3.2	12.1	23.7	-7.8	

स्रोत: सीएमआईई, सीईआईसी, एनएसओ, सियाम और आरबीआई स्टाफ अनुमाना

सारणी III.15: बिजली उत्पादन और खपत

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

संकेतक	2023-24				2024-25					
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	जन	फर	मार्च
बिजली उत्पादन										
थर्मल	2.1	14.7	14.3	10.1	12.1	-1.3	0.0	-2.9	1.0	3.1
न्यूक्लियर	-6.4	16.7	10.0	-2.2	28.3	18.4	11.4	15.1	18.6	16.8
हाइड्रो	-10.0	-13.4	-30.7	-20.2	1.0	6.2	28.3	16.3	17.6	24.2
नवीकरणीय	8.1	21.9	7.0	5.6	7.0	7.3	17.2	31.9	12.2	
बिजली की खपत										
उत्तरी क्षेत्र	-8.9	8.4	6.0	8.3	22.0	3.1	9.5	-2.9	2.4	6.0
पश्चिमी क्षेत्र	3.5	20.8	7.7	7.1	5.5	-6.7	0.4	3.3	3.0	9.5
दक्षिणी क्षेत्र	10.7	16.3	18.2	9.3	3.3	0.8	-2.3	3.1	2.1	3.9
पूर्वी क्षेत्र	4.9	6.6	9.2	7.9	9.8	0.6	3.9	2.7	1.7	6.6
अखिल भारतीय	1.5	13.4	9.9	8.1	10.2	-0.7	2.6	1.3	2.4	6.6

स्रोत: केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए); और पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीओएसओसीओ)।

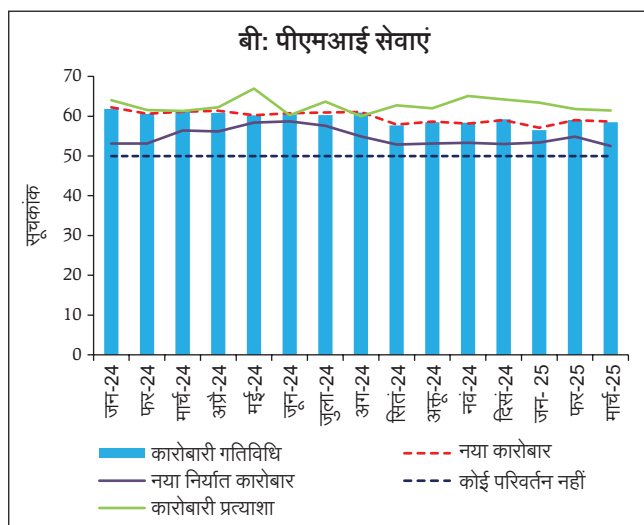
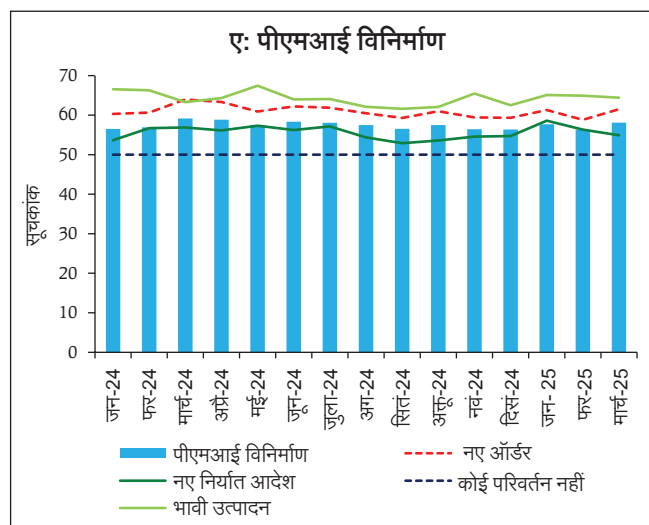
विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में विस्तार हुआ और यह तीसरी तिमाही में 56.8 रहा, जो नए निर्यात आदेशों और रोजगार में तेजी के साथ चौथी तिमाही में बढ़कर 57.4 हो गया। विनिर्माण के लिए व्यावसायिक अपेक्षाएं आशावादी बनी रहीं, जैसा कि भविष्य के उत्पादन मूल्यांकन (चार्ट III.18ए) द्वारा इंगित किया गया है।

III.2.3 सेवाएं

सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार बना हुआ है, जिनका योगदान 2024-25 में जीवीए वृद्धि में लगभग

75 प्रतिशत है। भारत के सेवा क्षेत्र में एक उल्लेखनीय परिवर्तन देखा गया है जो उच्च-कौशल और उच्च-मूल्य सेवाओं की बढ़ती हिस्सेदारी से पता चलता है। सेवा क्षेत्र ने व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण; वित्तीय, अचल संपत्ति और पेशेवर सेवाओं; और लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाओं में प्रोत्साहन के साथ 2024-25 की तीसरी तिमाही में अपनी गति बनाए रखी; (चार्ट III.19ए)। एसआई के अनुसार, सेवा क्षेत्र 2024-25 में 7.5 प्रतिशत की मजबूती से बढ़ा, जो एक साल पहले 9.2 प्रतिशत की वृद्धि के शीर्ष पर था। तैयार इस्पात की उपभोग वस्तुओं और

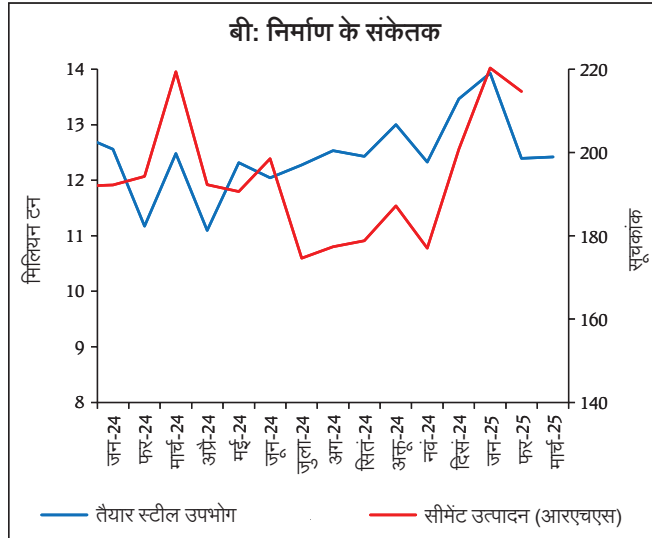
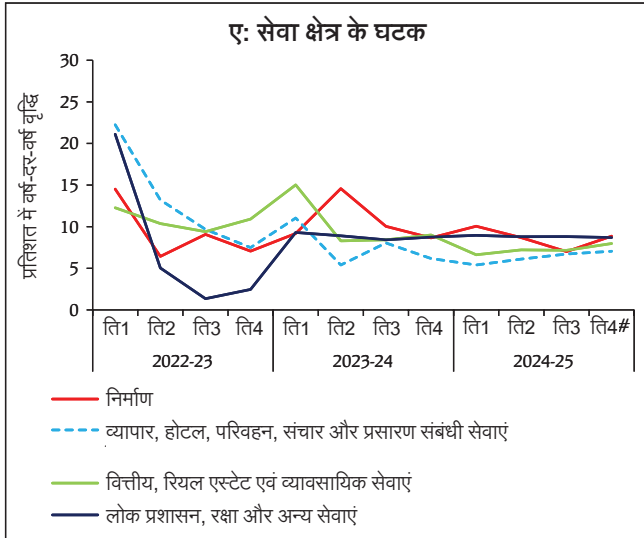
चार्ट III.18: पीएमआई विनिर्माण और सेवाएं



टिप्पणी: पीएमआई > 50: विस्तार, पीएमआई < 50: संकुचन।

स्रोत: एचएसबीसी, एस एंड पी ग्लोबल।

चार्ट III.19: सेवा क्षेत्र



टिप्पणी: #: निहिता

स्रोत: एनएसओ; आर्थिक सलाहकार का कार्यालय; और संयुक्त संयंत्र समिति

सीमेंट उत्पादन जो निर्माण गतिविधि के अनुमानित संकेतक हैं, में तीसरी तिमाही से सुधार देखा गया और जनवरी-फरवरी 2025 के दौरान दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई। हालांकि, इस्पात का उपभोग मार्च में मामूली रूप से घटा (चार्ट III.19बी)।

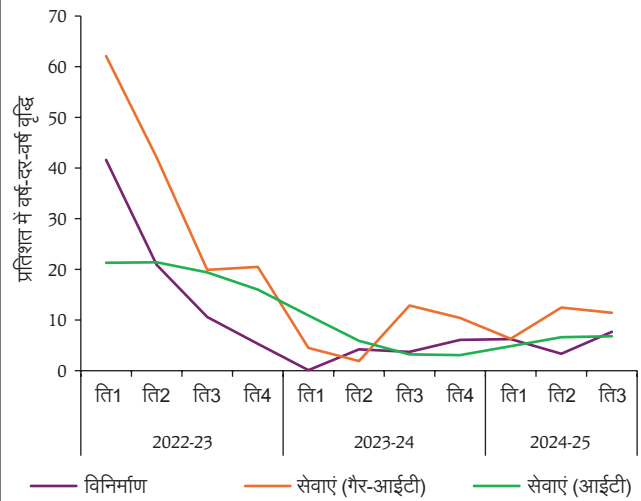
व्यापार, होटल, परिवहन और संचार ने वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 6.7 प्रतिशत (दूसरी तिमाही में 6.1 प्रतिशत) की वृद्धि दर्ज की। चौथी तिमाही में जीएसटी संग्रह में सुधार हुआ है, जो स्वस्थ घरेलू व्यापारिक गतिविधि का संकेत है। घरेलू हवाई यात्री यातायात ने जनवरी-फरवरी 2025 में मजबूत वृद्धि को बनाए रखा, जो पर्यटन और व्यवसाय से संबंधित यात्राओं में स्थिर वृद्धि को दर्शाता है। परिवहन सेवाओं के संकेतकों ने मिश्रित तस्वीर प्रदर्शित की - टोल संग्रह चौथी तिमाही में मजबूत रहा और कमजोर तीसरी तिमाही के बाद चौथी तिमाही में पोर्ट कार्गो में काफी सुधार हुआ, जबकि यात्री वाहन बिक्री ने इस अवधि के दौरान मंद वृद्धि दर्ज की।

वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाओं में 2024-25 की तीसरी तिमाही में 7.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह सेवा क्षेत्र जीवीए वृद्धि (33.1 प्रतिशत) के साथ-साथ समग्र जीवीए वृद्धि (23.9 प्रतिशत) में एक प्रमुख योगदानकर्ता था। मार्च 2025 में बैंक क्रेडिट और डिपॉजिट में क्रमशः 12.1 प्रतिशत और 10.5

प्रतिशत का विस्तार हुआ। गैर-जीवन क्षेत्रों में बीमा प्रीमियम दूसरी छमाही में (अक्तूबर-फरवरी) में अच्छी दर से बढ़ा, जबकि जीवन बीमा प्रीमियम में संकुचन देखा गया (सारणी III.16)।

गैर-आईटी सेवाओं की नॉमिनल बिक्री पार्याप्त रही और इसमें तीसरी तिमाही में दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद तीसरी तिमाही में आईटी क्षेत्र का कार्य-निष्पादन भी बढ़ा (चार्ट III.20)।

चार्ट III.20: सांकेतिक बिक्री वृद्धि



टिप्पणी: वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए परिणाम 2,924 सूचीबद्ध गैर-सरकारी गैर-वित्तीय कंपनियों पर आधारित हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ अनुमान।

सारणी III.16: सेवा क्षेत्र में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि

(प्रतिशत)

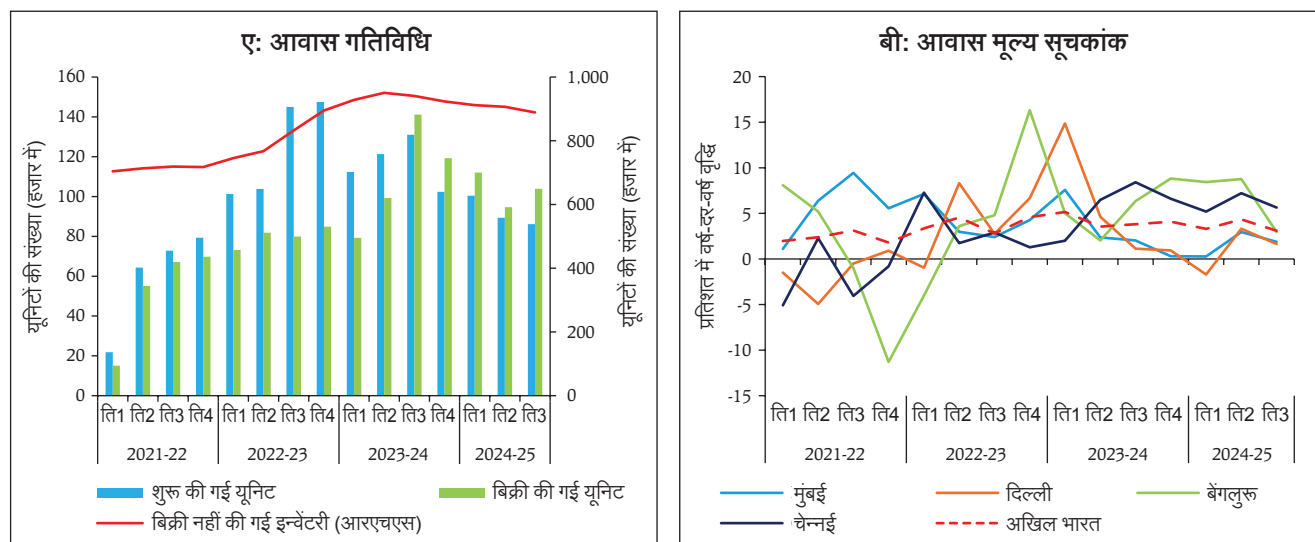
	संकेतक	2024-25					
		ति1	ति2	ति3	जन	फर	मार्च
1	पीएमआई: सेवाएं (>50 पिछले महीने की तुलना में वृद्धि दर्शाता है)	60.5	59.6	58.7	56.5	59.0	58.5
	निर्माण						
2	स्टील की खपत	15.0	12.0	7.8	10.9	10.9	-0.5
3	सीमेंट उत्पादन	0.4	3.2	6.6	14.6	10.5	
	व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं						
4	वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री	3.5	-11.0	1.2			
5	घरेलू हवाई यात्री यातायात	5.6	7.2	11.4	14.1	12.1	
6	घरेलू एयर कार्गो	7.1	7.6	4.6	6.9	-2.5	
7	अंतर्राष्ट्रीय एयर कार्गो	18.4	21.9	15.0	7.1	-6.3	
8	पोर्ट कार्गो	3.9	6.2	-1.7	6.2	7.4	13.3
9	टोल संग्रह: मात्रा	5.6	7.6	9.9	14.8	18.7	11.9
10	पेट्रोलियम की खपत	3.9	1.0	5.4	3.0	-5.2	-3.1
11	जीएसटी ई-वे बिल	16.0	16.8	16.9	23.1	14.7	20.2
12	जीएसटी राजस्व	10.2	8.9	8.3	12.3	9.1	9.9
	वित्तीय, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं						
13	बकाया ऋण	13.9	14.4	12.4	12.5	12.0	12.1
14	बैंक जमा	10.6	12.0	10.2	10.6	10.6	10.5
15	जीवन बीमा प्रीमियम	22.9	16.5	-6.6	-8.1	-11.6	
16	गैर-जीवन बीमा प्रीमियम	13.3	1.9	10.8	6.6	-2.8	

स्रोत: सीआईआईसी; एचएसबीसी; आईआरडीई; एमओएसपीआई; एनएसओ; एस एंड पी ग्लोबल; सियाम; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में रियल एस्टेट गतिविधि ने कम नए लॉन्च के साथ मिश्रित संकेत प्रस्तुत किए, जो भविष्य की मांग के बारे में अनिश्चितता को दर्शाते हैं, जबकि बिक्री की गति में कुछ वृद्धि दर्ज की गई। जैसे-जैसे बिक्री लॉन्च से आगे बढ़ी, न

बेची गई इन्वेंट्री में मामूली गिरावट दर्ज की गई (चार्ट III.21ए)। अखिल भारतीय आवास की कीमतों में वृद्धि तीसरी तिमाही में कम हो गई, इसकी गति सभी प्रमुख शहरों में कम हो गई (चार्ट III.21बी)। लोक प्रशासन, रक्षा और अन्य सेवाएं (पीएडीओ)

चार्ट III.21: आवास क्षेत्र - लॉन्च, बिक्री और कीमतें



स्रोत: प्रॉपर्टाइगर और आरबीआई

तीसरी तिमाही में 8.8 प्रतिशत की दर से बढ़ी, जो मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन जैसी अन्य सेवाओं की वजह से थी। ब्याज भुगतान और सब्सिडी को छोड़कर केंद्र का राजस्व व्यय जनवरी-फरवरी 2025 में 3.0 प्रतिशत तक संकुचित होने से पहले तीसरी तिमाही के दौरान 11.2 प्रतिशत तक बढ़ा।

सेवा पीएमआई तीसरी तिमाही में 58.7 और चौथी तिमाही में 58.0 रही, हालांकि यह 2024-25 की पहली छमाही में 60.1 से कम हो गया है, जिसे विदेशों से रोजगार और नई व्यावसायिक गतिविधि द्वारा सहायता मिली (चार्ट III.18बी और सारणी III.8)। समग्र पीएमआई सूचकांक 2024-25 की पहली छमाही में 60.4 के उच्च स्तर से घटकर तीसरी तिमाही में 58.9 और चौथी तिमाही में 58.6 हो गया, लेकिन आसानी से 50-अंक से ऊपर रहा जो निरंतर वृद्धि का संकेत देता है। भारत के लिए पीएमआई विनिर्माण और पीएमआई सेवाओं के अंक क्रमशः जुलाई 2022 और अप्रैल 2023 के बाद से विश्व स्तर पर सबसे अधिक बने हुए हैं।

III.3 निष्कर्ष

वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में क्षणिक मंदी देखने के बाद, मजबूत निजी खपत और सरकार के पूंजीगत व्यय में सुधार के कारण तीसरी में आर्थिक गतिविधि में सुधार हुआ। इसके अलावा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उछाल, सुदृढ़ सेवा क्षेत्र, कर प्रोत्साहन के माध्यम से घरेलू मांग को बढ़ाने के लिए सरकार के प्रयास, वित्तीय संस्थाओं और कॉर्पोरेट की मजबूत बैलेंस शीट के साथ-साथ वित्तपोषण की स्थिति में ढील से विकास को गति मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर, निरंतर भू-राजनीतिक अनिश्चितताएं, वैश्विक व्यापार व्यवधान, वैश्विक वित्तीय बाजारों में उच्च अस्थिरता के बीच मौसम संबंधी गड़बड़ी, परिदृश्य के लिए डाउनसाइड जोखिम पैदा करते हैं। जबकि अमेरीका द्वारा पारस्परिक टैरिफ भारत की निवल बाह्य मांग पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा, भारत की समकक्ष अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के सापेक्ष टैरिफ लाभ का प्रभाव कम हो सकता है।

IV. चलनिधि स्थितियां और वित्तीय बाजार

वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान अस्थिर वैश्विक बाजारों के विपरीत घरेलू वित्तीय बाजार अपेक्षाकृत स्थिर और लचीले बने रहे। मुद्रा बाजार की दरें नीतिगत रुख और चलनिधि की स्थितियों में बदलाव के साथ तालमेल बिठाते हुए विकसित हुईं, जबकि घरेलू गविविधियां और वैश्विक संकेतों के फलस्वरूप बॉण्ड प्रतिफल में कमी आई। उधार और जमा दरों में संचरण मजबूत बना हुआ है। वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में बैंक ऋण वृद्धि में नरमी आई। रिजर्व बैंक ने व्यवस्थित बाजार स्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए चलनिधि बढ़ाने के कई उपाय किए।

परिचय

वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान, वैश्विक वित्तीय बाजार उच्च व्यापार और नीति अनिश्चितताओं तथा निरंतर भू-राजनीतिक तनावों के बीच अस्थिर बने रहे। उन्नत अर्थव्यवस्था के केंद्रीय बैंक अस्थिरता में उछाल और धुंधले समष्टि आर्थिक दृष्टिकोण के मद्देनजर मौद्रिक नीति के लिए सावधानीपूर्वक सुविचारित रुख अपना रहे हैं। सभी देशों में वैश्विक बॉण्ड प्रतिफल, विशेष रूप से लंबी अवधि वाले, बदलते आर्थिक परिदृश्य और मौद्रिक नीति प्रक्षेप पथ के विपरीत बढ़ रही अपेक्षाओं के अनुरूप रहा। अत्यधिक अस्थिरता और क्षेत्रीय स्तर पर उतार-चढ़ाव के बीच, वैश्विक इक्विटी बाजारों में वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में तेज गिरावट आई। अस्थिर पूंजी प्रवाह और विनिमय दरें तथा घरेलू वित्तीय स्थितियों पर उनके प्रभाव से उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) में जटिल नीतिगत चुनौतियाँ पैदा हुईं (ब्योरे के लिए अध्याय V देखें)।

IV.1 चलनिधि की स्थितियां और मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के अनुसार आरबीआई से यह अपेक्षित है कि वह मौद्रिक नीति के कार्यान्वयन से संबंधित परिचालन प्रक्रिया और समय-समय पर उसमें होने वाले परिवर्तनों, यदि कोई हो, को सार्वजनिक डोमेन में रखे।¹

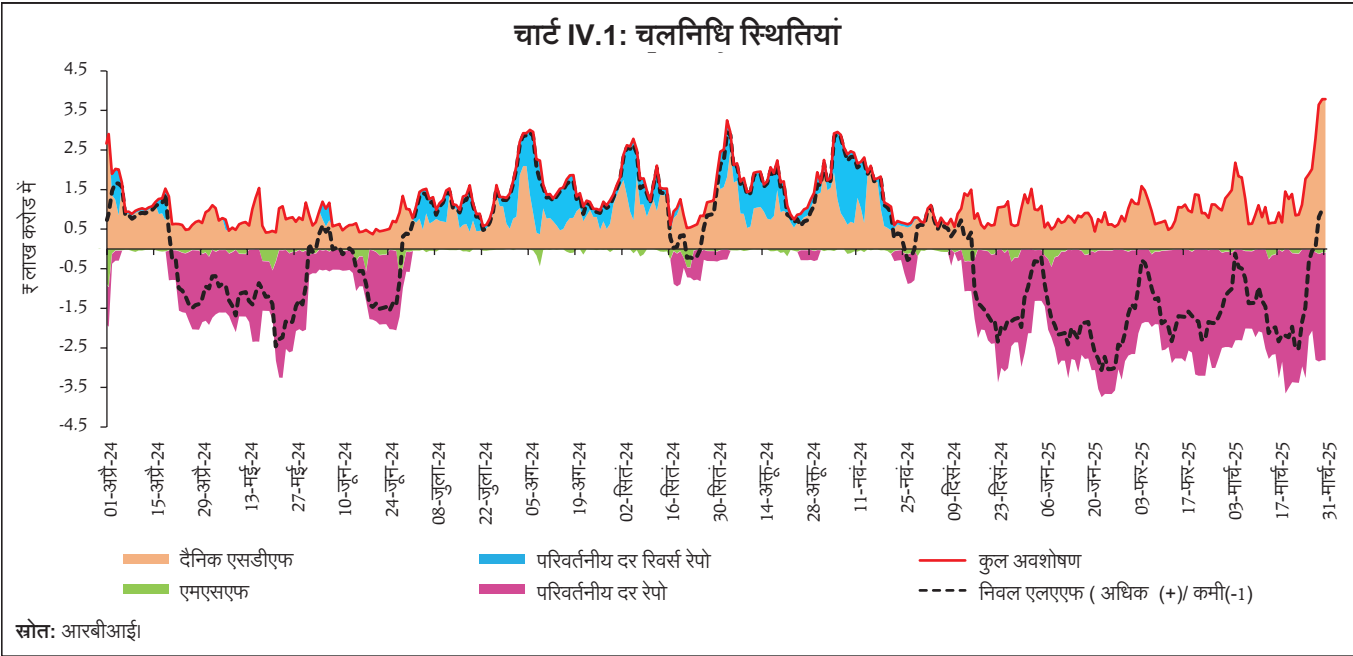
वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान, मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अक्टूबर 2024 में समायोजन वापस लेते हुए तटस्थ रुख को अपनाया ताकि वृद्धि को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति क्रमिक रूप से 4 प्रतिशत के लक्ष्य के अनुरूप रहे। चलनिधि की स्थिति को आसान बनाने के लिए, बैंकों के आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) को दिसंबर 2024 में 50 आधार अंक कम करते हुए उसे निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएन) के 4.0 प्रतिशत तक कर दिया गया, जिससे बैंकिंग प्रणाली में ₹1.16 लाख करोड़ की प्राथमिक चलनिधि जारी करते हुए सीआरआर को महामारी से पहले के स्तर पर बहाल किया जा सका। अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि की उपलब्धता के बारे में बाजारों को आश्वस्त करने और विश्वास पैदा करने के लिए, रिजर्व बैंक ने 2024-25 की चौथी तिमाही में चलनिधि बढ़ाने के कई उपाय किए। इसने सभी कार्य दिवसों पर दैनिक परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामी शुरू की, जो अगले कार्य दिवस में 16 जनवरी 2025 से वापस लेते हुए प्रभावी हुआ। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने टर्म रेपो नीलामी, खुले बाजार खरीद परिचालन और यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप के माध्यम से टिकाऊ चलनिधि समाविष्ट की। रिजर्व बैंक ने 2 अप्रैल, 2025 से स्थायी चलनिधि सुविधा (एसएलएफ) के तहत एकल प्राथमिक व्यापारियों (एसपीडी) के लिए उपलब्ध कुल सीमा को ₹10,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹15,000 करोड़ कर दिया और अप्रैल 2025 के लिए खुले बाजार खरीद परिचालन के मासिक कैलेंडर की घोषणा की। साथ ही, एमपीसी ने फरवरी 2025 में नीति रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया।

चलनिधि के चालक और प्रबंधन

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत निवल शेष राशि द्वारा गणना की गई प्रणालीगत चलनिधि वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में अधिशेष की स्थिति से 2024-25 की दूसरी छमाही में घाटे में चली गई (चार्ट IV.1)।

निवल आधार पर, एलएएफ के तहत दूसरी छमाही में औसत दैनिक अंतःक्षेपण ₹0.36 लाख करोड़ था, जबकि पहली छमाही में औसत दैनिक निवल अवशोषण ₹0.39 लाख करोड़ था।

¹ संशोधित चलनिधि प्रबंधन ढांचे की घोषणा 6 फरवरी, 2020 को विकासात्मक और नियामक नीतियों पर वक्तव्य में की गई और 14 फरवरी, 2020 को इसे लागू किया गया। ढांचे की मुख्य विशेषताएं अप्रैल 2024 की मौद्रिक नीति रिपोर्ट में दी गई हैं।



दूसरी छमाही के दौरान भारत सरकार के नकदी शेष में परिवर्तन, प्रचलन में मुद्रा (सीआईसी) में विस्तार और अस्थिर पूंजी प्रवाह चलनिधि के प्रमुख चालक बनकर उभरे। मुद्रा की मांग में वृद्धि और रिज़र्व बैंक के विदेशी मुद्रा बाजार परिचालन के कारण बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि में क्षरण को भारत सरकार के नकदी शेष में कमी, सीआरआर में कमी और दूसरी छमाही के दौरान रिज़र्व

बैंक की चलनिधि बढ़ाने के उपायों द्वारा आंशिक रूप से ऑफसेट किया गया (सारणी IV.1)।

दूसरी छमाही में, अक्टूबर-नवंबर के दौरान (नवंबर के अंत में एक छोटी अवधि को छोड़कर) उच्च सरकारी खर्च के कारण प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष में थी, हालांकि अक्टूबर में त्योहार संबंधी मांग और नवंबर में महत्वपूर्ण पूंजी बहिर्वाह

सारणी IV.1: चलनिधि – प्रमुख चालक और प्रबंधन

(राशि ₹ करोड़ में)

चालक	2023-24		2024-25			
	एच1	एच2	एच1	ति3	ति4*	एच2*
(i) सीआईसी [निकासी (-) / प्रतिफल (+)]	89,356	-2,26,366	33,556	-78,963	-1,59,204	-2,38,167
(ii) निवल विदेशी मुद्रा खरीद (+) / बिक्री (-)	1,44,667	1,94,861	70,402	-3,27,601	-2,52,034 ^	-5,79,635 ^
(iii) भारत सरकार के नकद शेष [बिल्ड-अप (-) / ड्रॉडाउन (+)]	-4,17,850	1,42,694	-1,50,494	1,06,873	78,358	1,85,231
(iv) अतिरिक्त रिज़र्व [बिल्ड-अप (-) / ड्रॉडाउन (+)]	34,925	-46,886	36,768	41,534	-39,962	1,572
प्रबंधन						
(i) निवल ओएमओ खरीद (+)/बिक्री (-)	-8,480	-10,025	-24,040	0	2,83,386	2,83,386
(ii) अपेक्षित रिज़र्व [एनडीटीएल और सीआरआर दोनों में परिवर्तन सहित]	-1,35,220	7,503	-55,613	39,349	37,101	76,450
(iii) दीर्घकालिक फॉरेक्स स्वैप खरीद/बिक्री (+) / बिक्री/ खरीद (-)	-	-	-	-	2,18,000 ^	2,18,000 ^
(iv) आवधिक रेपो नीलामी	-	-	-	-	1,82,964	1,82,964
मेमो आइटम						
अंतिम अवधि के अनुसार निवल अवशोषण (+)/इंजेक्शन (-)	-97,015	-52,918	84,651	-1,82,788	-172	-172

टिप्पणीयां: 1 (+) / (-) चिह्न बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि में वृद्धि/कमी को दर्शाता है। 2 डेटा संबंधित अवधि के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है। 3 निवल विदेशी मुद्रा खरीद या बिक्री में रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा स्वैप का पहला चरण शामिल नहीं है।

*: ति4 और एच2: 2024-25 के लिए डेटा 28 मार्च, 2025 तक है। ^: अनुमानित मूल्य।

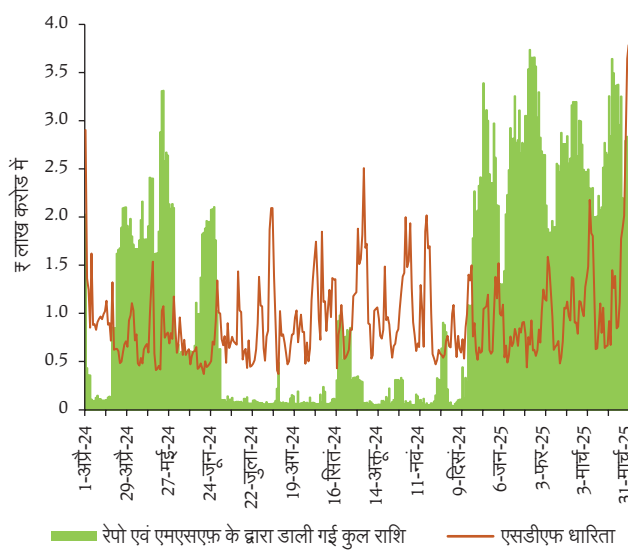
स्रोत: आरबीआई

के कारण सीआईसी में वृद्धि हुई थी। अग्रिम कर भुगतान, पूंजी बहिर्वाह और मुद्रा अवमूल्यन के संयुक्त प्रभाव के कारण दिसंबर की दूसरी छमाही के दौरान प्रणालीगत चलनिधि घाटे में बदल गई। सीआरआर में कमी, भारत सरकार के नकदी शेष में आहरण के कारण हुई कमी और अतिरिक्त भंडार सीआईसी में वृद्धि के कारण बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि की निकासी और रिजर्व बैंक के विदेशी मुद्रा बाजार परिचालन के कारण दब गया। नतीजतन, एलएएफ (एमएसएफ सहित) के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण पिछली तिमाही में ₹1.3 लाख करोड़ की तुलना में 2024-25 की तीसरी तिमाही में घटकर ₹0.80 लाख करोड़ हो गया। इसके विपरीत सीआईसी में मौसमी वृद्धि और लगातार पूंजी बहिर्वाह के कारण चौथी तिमाही के अधिकांश हिस्सों में चलनिधि स्थितियां घाटे में बनी रहीं। चौथी तिमाही में एलएएफ के अंतर्गत औसत निवल अंतःक्षेपण ₹1.6 लाख करोड़ रहा जो चलनिधि की सख्य स्थिति को दर्शाता है। चलनिधि की स्थिति का प्रबंधन करने के लिए, रिजर्व बैंक ने 16 जनवरी, 2025 से सभी कार्य दिवसों के लिए उभरती चलनिधि की स्थितियों के साथ तालमेल बिठाते हुए अधिसूचित राशि के साथ दैनिक वीआरआर की नीलामी शुरू की। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने सिस्टम में टिकाऊ चलनिधि डालने के लिए खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) खरीद, यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप और दीर्घकालिक वीआरआर जैसे कई उपाय किए। नतीजतन, 3 महीने से अधिक के अंतराल के बाद मार्च के अंत तक प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष में बदल गई।

दूसरी छमाही में बैंकों द्वारा प्रतिदिन औसतन ₹0.06 लाख करोड़ की सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) पहली छमाही की तुलना में ₹0.08 लाख करोड़ से कम थी। दूसरी छमाही के दौरान एलएएफ के तहत औसत कुल अवशोषण ₹1.26 लाख करोड़ में से, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत औसत प्लेसमेंट लगभग 82.6 प्रतिशत (₹1.04 लाख करोड़) था, जबकि शेष राशि परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) नीलामी के माध्यम से अवशोषित की गई थी। एसडीएफ के तहत पर्याप्त फंड प्लेसमेंट के साथ-साथ चलनिधि घाटे की स्थिति का एक साथ होना बैंकिंग प्रणाली के भीतर चलनिधि के विषम वितरण के साथ-साथ बैंकों की ओर से बढ़ी हुई चलनिधि वरीयता को दर्शाता है (चार्ट IV.2)।

रिजर्व बैंक अपने चलनिधि प्रबंधन में चुस्त और लचीला बना रहा और बदलती चलनिधि गतिशीलता के मद्देनजर एलएएफ के

चार्ट IV.2: बैंकों की चलनिधि मांग और एसडीएफ धारिता/ होल्डिंग

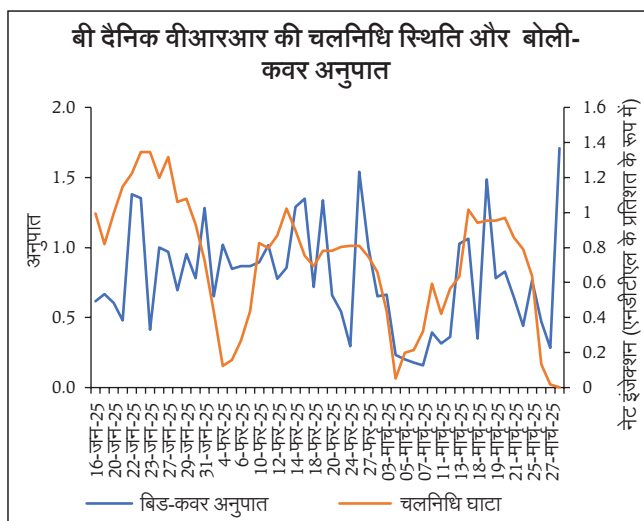
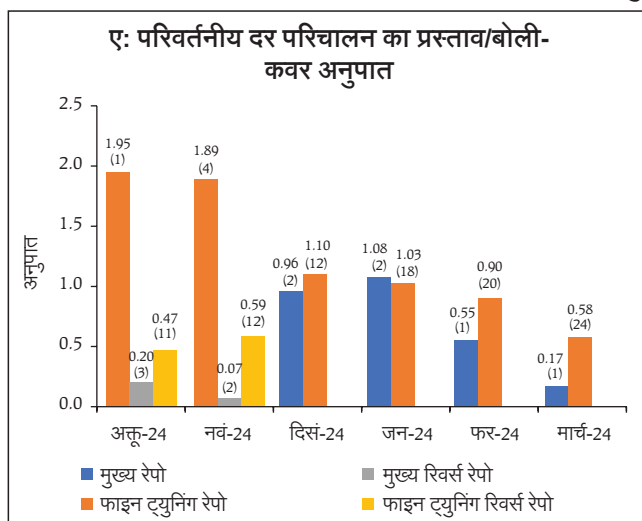


स्रोत: आरबीआई

तहत दो-तरफा परिचालनों को संचालित किया। तीसरी तिमाही के दौरान प्रणालीगत चलनिधि अधिशेष में रहने के साथ, पाँच मुख्य और 23 फाइन ट्यूनिंग वीआरआरआर नीलामियाँ (1-4 दिन की परिपक्वता) आयोजित की गईं, जिससे अक्टूबर-नवंबर 2024² में बैंकिंग सिस्टम से संचयी रूप से लगभग ₹11.7 लाख करोड़ की राशि प्राप्त हुई। बैंक रिजर्व बैंक के पास चलनिधि रखने के प्रति अनिच्छुक दिखाई दिए, जैसा कि मुख्य और साथ ही फाइन-ट्यूनिंग वीआरआरआर परिचालनों के लिए उनके कम बोली-प्रस्ताव अनुपात में परिलक्षित होता है (चार्ट IV.3ए)। दिसंबर के मध्य से फरवरी के दौरान चलनिधि की माँग ऊँची बनी रही, जैसा कि रेपो नीलामियों के लिए उच्च बोली-कवर अनुपात में परिलक्षित होता है। दिसंबर के उत्तरार्ध से चलनिधि की कमी होने के कारण, दो मुख्य और 12 फाइन-ट्यूनिंग वीआरआर नीलामियाँ आयोजित की गईं, जिनसे संचयी रूप से प्रणाली में 9.4 लाख करोड़ रुपये डाले गए। दैनिक वीआरआर के बोली-कवर अनुपात में परिलक्षित चलनिधि की माँग मार्च में कम हुई क्योंकि कई चलनिधि बढ़ाने वाले उपायों के मद्देनजर चलनिधि की स्थिति में नरमी देखी गई (चार्ट IV.3बी)। कुल मिलाकर, रिजर्व बैंक ने 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान चलनिधि की कमी को कम करने के लिए चार मुख्य और 62 फाइन-ट्यूनिंग

² जीएसटी से संबंधित भुगतानों के कारण चलनिधि की कमी को कम करने के लिए 22-28 नवंबर के दौरान चार फाइन-ट्यूनिंग वीआरआर नीलामियाँ आयोजित की गईं।

चार्ट IV.3: बोली-प्रस्ताव(ऑफर)/ कवर अनुपात और बैंकों की चलनिधि के प्रति प्राथमिकता



नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े परिचालनों की संख्या को दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई

वीआरआर नीलामियाँ आयोजित कीं, जिससे बैंकिंग प्रणाली में कुल मिलाकर ₹48.7 लाख करोड़ डाले गए।

टिकाऊ चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, रिजर्व बैंक ने 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान सीआरआर

में कटौती, ओपन मार्केट खरीद, मीयादी वीआरआर नीलामी और यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप के संयोजन के माध्यम से लगभग ₹8.0 लाख करोड़ की चलनिधि डाली (सारणी IV.2)। ओएमओ और एफएक्स स्वैप के लिए उच्च बोली-कवर अनुपात

सारणी IV.2: एच2:2024-25 के दौरान टिकाऊ चलनिधि उपाय

(राशि ₹ करोड़ में)

उपाय	नीलामी तिथि	विवरण	बिड कवर अनुपात	अंतर्वेशित चलनिधि
सीआरआर में कटौती	6 दिसंबर, 2024 को घोषित	14 दिसंबर और 28 दिसंबर से शुरू होने वाले पखवाड़े से 25 बीपीएस की दो बराबर किस्तों में सीआरआर में 50 बीपीएस की कटौती		1,16,000*
ओएमओ खरीद	Q4:2024-25	एनडीएस-ओएम के माध्यम से		38.825
ओएमओ खरीद नीलामी	जनवरी 30, 2025	अधिसूचित राशि: 20,000	6.03	20,020
	फरवरी 13, 2025	अधिसूचित राशि: 40,000	4.53	40,000
	फरवरी 20, 2025	अधिसूचित राशि: 40,000	4.69	40,000
	मार्च 12, 2025	अधिसूचित राशि: 50,000	2.51	50,000
	मार्च 18, 2025	अधिसूचित राशि: 50,000	2.02	50,000
	मार्च 25, 2025	अधिसूचित राशि: 50,000	1.35	44,541
आवधिक रेपो नीलामी	फरवरी 07, 2025	56-दिवसीय वीआरआर नीलामी अधिसूचित राशि: 50,000	2.17	50,010
	फरवरी 14, 2025	49-दिवसीय वीआरआर नीलामी अधिसूचित राशि: 75,000	1.33	75,003
	फरवरी 21, 2025	45-दिवसीय वीआरआर नीलामी अधिसूचित राशि: 75,000	0.77	57,951
यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी	जनवरी 31, 2025 (4 फरवरी 2025 को निपटान)	अवधि: 6 माह अधिसूचित राशि: यूएसडी 5 बिलियन	5.12	44,000* (यूएसडी 5.10 बिलियन)
	फरवरी 28, 2025 (4 मार्च 2025 को निपटान)	अवधि: 3 वर्ष अधिसूचित राशि: यूएसडी 10 बिलियन	1.62	88,000* (यूएसडी 10.06 बिलियन)
	मार्च 24, 2025 (26 मार्च 2025 को निपटान)	अवधि: 3 वर्ष अधिसूचित राशि: यूएसडी 10 बिलियन	2.23	86,000* (यूएसडी 10.04 बिलियन)
कुल				8,00,350*

टिप्पणी: * अनुमानित मूल्य दर्शाता है।

स्रोत: आरबीआई।

ने टिकाऊ चलनिधि की उच्च मांग का संकेत दिया। इसे और भावी वित्तीय वर्ष के अंत में चलनिधि में कमी को ध्यान में रखते हुए, रिजर्व बैंक ने मार्च के दौरान छत्तीस महीनों की अवधि के लिए ₹1,50,000 करोड़ की अतिरिक्त ओएमओ खरीद नीलामी और यूएसडी/आईएनआर खरीद/बिक्री स्वैप नीलामी के माध्यम से और अधिक टिकाऊ चलनिधि सहायता प्रदान की।

28 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, आरक्षित मुद्रा (आरएम) में एक साल पहले के 6.7 प्रतिशत की तुलना में 3.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। आरएम में कम वृद्धि दिसंबर 2024 में आरक्षित नकदी निधि अनुपात (सीआरआर) में कमी के कारण आरबीआई के पास बैंकों की जमाराशियों में गिरावट को दर्शाती है। सीआरआर परिवर्तन के लिए समायोजित किए गए, आरएम में वृद्धि 5.8 प्रतिशत (एक साल पहले 6.7 प्रतिशत) रही। 21 मार्च, 2025 तक, मुद्रा आपूर्ति (एम3) में वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) एक वर्ष पहले के 11.2 प्रतिशत से घटकर 9.6 प्रतिशत हो गई।

21 मार्च, 2025 तक मुद्रा गुणक एक वर्ष पहले के 5.4 से बढ़कर 5.7 हो गया, जो सीआरआर कटौती और कम मुद्रा-जमा अनुपात दोनों के दोहरे प्रभाव को दर्शाता है।

IV.2 घरेलू वित्तीय बाजार

वैश्विक गतिविधियों के विपरीत, घरेलू वित्तीय बाजार अपेक्षाकृत स्थिर और लचीले बने रहे। मुद्रा बाजार की दरें नीतिगत रुख और चलनिधि की स्थिति में बदलाव के साथ तालमेल बिठाकर विकसित हुईं। घरेलू गतिविधियां और वैश्विक संकेतों के प्रतिसाद स्वरूप दीर्घकालिक सरकारी बॉण्ड के प्रतिफल में गिरावट हुई। कॉरपोरेट बॉण्ड प्रतिफल में आम तौर पर नरमी आई, जबकि 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान स्प्रेड में वृद्धि हुई, जो जी-सेक प्रतिफल में अधिक नरमी को दर्शाता है। एक साथ बढ़ती अनिश्चितताओं और चलनिधि कठिनाइयों ने बाजार के सभी खंडों में स्प्रेड को बढ़ा दिया (बॉक्स IV.1)। भू-

बॉक्स IV.1: प्रतिफल और स्प्रेड को कौन प्रेरित करता है - चलनिधि या अनिश्चितता?

हाल के समय में, वैश्विक वित्तीय बाजार व्यापार और नीति अनिश्चितताओं, लंबे समय से चल रहे भू-राजनीतिक तनावों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के केंद्रीय बैंकों की मौद्रिक नीति प्रक्षेप पथ के बारे में बदलती अपेक्षाओं के बीच अस्थिर बने हुए हैं। इन वैश्विक प्रभाव-विस्तारों का उभरते बाजार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) में घरेलू वित्तीय स्थितियों पर एक निराशाजनक प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। उच्च अनिश्चितताओं के चलते घरेलू चलनिधि स्थितियों पर इस तरह के हस्तक्षेपों का प्रभाव बाजार खंडों में प्रतिफल और प्रसार पर पड़ता है, जो नीतिगत दृष्टिकोण से गहन जांच के योग्य है।

संबंधित साहित्य से पता चलता है कि मुद्रा और बॉण्ड बाजारों में स्प्रेड मौजूदा चलनिधि स्थितियों के अलावा अनिश्चितता से प्रेरित होते हैं। अनिश्चितता चलनिधि स्थितियों में अस्थिरता से उत्पन्न हो सकती है, जिसका अपना स्वतंत्र प्रभाव स्प्रेड पर पड़ सकता है जिसके कारण एहतियाती रूप से बचत के प्रति मांग बढ़ जाती है (एमिसानो और ट्रिस्टानी, 2019)। इसके अतिरिक्त, आर्थिक और नीतिगत अनिश्चितता भी ऋण आपूर्ति को सख्त करने और उधारकर्ताओं के डिफॉल्ट प्रीमियम को बढ़ाने के कारण प्रसार को

बढ़ा सकती है (अशरफ और यिनजी, 2019)। तदनुसार, जनवरी 2012 से जनवरी 2025 की अवधि के लिए मुद्रा और बॉण्ड बाजारों के मासिक आंकड़ों के आधार पर स्प्रेड पर चलनिधि की स्थिति और अनिश्चितता के प्रभाव की जांच की जाती है, जिसमें निम्नलिखित रिग्रेशन विनिर्देश का उपयोग किया जाता है:

$$S_t = \beta_0 + \beta_1 * Liq_Cond_t + \beta_2 * Liq_Uncert_t + \beta_3 * Liq_Cond_t * Liq_Uncert_t + \beta_4 * Eco_Pol_Uncert_t + \rho * S_{t-1} + \varepsilon_t$$

जहां S_t मुद्रा और बॉण्ड बाजार खंडों³ में स्प्रेड को दर्शाता है; Liq_Cond_t चलनिधि की स्थिति है, जिसे एनडीटीएल के अनुपात के रूप में निवल चलनिधि समायोजन सुविधा द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें कम मूल्य अपेक्षाकृत सख्त चलनिधि की स्थिति को दर्शाता है; Liq_Uncert_t उच्च चलनिधि अनिश्चितता⁴ के महीनों के लिए एक संकेतक वेरिएबल है; और Eco_Pol_Uncert वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता⁵ को दर्शाता है। इसके अलावा, उच्च अनिश्चितता की अवधि के दौरान स्प्रेड पर चलनिधि की स्थिति के विषम प्रभाव को दर्ज करने के लिए चलनिधि की स्थिति और चलनिधि अनिश्चितता की एक अंतःक्रिया अवधि विशेष रूप से शामिल की गई है (चार्ट IV.1.1)। स्प्रेड में निरंतरता को दर्ज करने के लिए विलंबित आश्रित वेरिएबल को शामिल किया गया है।

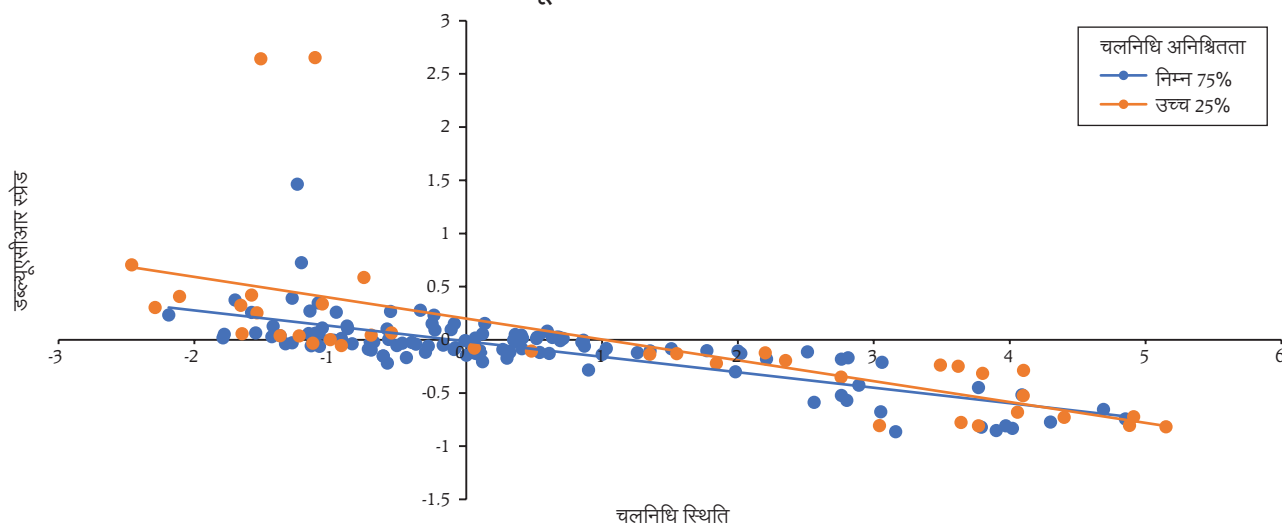
(Cont.)

³ भारत औसत कॉल दर (डब्ल्यूएसीआर) और भारत औसत मुद्रा बाजार दर (डब्ल्यू एएमएमआर) स्प्रेड की गणना नीति रेपो दर पर की जाती है, जबकि सीपी और बॉण्ड बाजार स्प्रेड की गणना संबंधित परिपक्वताओं की जोखिम-मुक्त दरों पर की जाती है।

⁴ चलनिधि अनिश्चितता को सशर्त अस्थिरता द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका अनुमान चलनिधि स्थितियों के दैनिक डेटा पर निर्धारित किए गए जीएआरसीएच (1,1) मॉडल का उपयोग करके लगाया जाता है। उच्चतर अनिश्चितता वाले महीनों (सशर्त अस्थिरता के शीर्ष दशमलव में) को 1 का मान दिया जाता है, और बाकी को 0 दिया जाता है।

⁵ लॉगरिथमिक में क्रय शक्ति समानता (पीपीपी)-समायोजित वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता सूचकांक (बेकर और अन्य., 2016) के रिग्रेशन रूप का उपयोग किया जाता है।

चार्ट IV.1.1: डब्ल्यू एसीआर स्प्रेड और चलनिधि स्थितियां



स्रोत: आरबीआई

अनुमानों से यह संकेत मिलता है कि चलनिधि की स्थिति में नरमी से सभी खंडों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण तरीके से स्प्रेड कम हो जाता है, जो बॉण्ड बाजारों की तुलना में मुद्रा में अधिक होता है (तालिका IV.1.1)। चलनिधि की अनिश्चितता में वृद्धि ओवरनाइट मुद्रा बाजार में उच्च स्प्रेड से जुड़ी हैं, लेकिन वाणिज्यिक पत्र (सीपी) और बॉण्ड बाजारों में स्प्रेड से इसका प्रभाव नगण्य हो गया है। इसका कारण सीपी और बॉण्ड मार्केट में स्प्रेड हो सकता है, जो निवल क्रेडिट जोखिम प्रीमियम को दर्शाता है, जबकि चलनिधि अनिश्चितता प्रीमियम जोखिम-मुक्त दरों में दर्ज होता है। उल्लेखनीय रूप से, चलनिधि की स्थिति और चलनिधि अनिश्चितता की परस्पर क्रिया अवधि मुद्रा बाजार

स्प्रेड के लिए सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण होती है, जिसका अर्थ उच्च अनिश्चितता की अवधि के दौरान चलनिधि की स्थिति का तीव्र प्रभाव है। नीतिगत दृष्टिकोण से, परिणाम बताते हैं कि पर्याप्त चलनिधि प्रदान करने से स्प्रेड पर अधिक स्पष्ट प्रभाव पड़ता है, खासकर अनिश्चित समय के दौरान। इसके अलावा, वैश्विक आर्थिक नीति अनिश्चितता का काफी प्रभाव सीपी और कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजारों में पर पड़ता है। कुल मिलाकर, परिणाम यह बताते हैं कि चलनिधि और अनिश्चितता वित्तीय बाजारों में स्प्रेड को प्रेरित करती हैं और उनके एक साथ होने से बड़ा प्रभाव पड़ता है, लेकिन उनका सापेक्ष महत्व बाजार खंडों और वित्तीय चक्रों में भिन्न होता है।

सारणी IV.1.1: मुद्रा और बॉण्ड बाजार में स्प्रेड के चालक

रिग्रेसर्स	आश्रित वेरिएबल						
	डब्ल्यू एसीआर स्प्रेड	डब्ल्यूएएमएमआर स्प्रेड	सीपी स्प्रेड	एए 3-वर्ष स्प्रेड	एए 3-वर्ष स्प्रेड	एए 5-वर्ष स्प्रेड	एए 5-वर्ष स्प्रेड
चलनिधि स्थिति	-0.033***	-0.031**	-0.046***	-0.024***	-0.026***	-0.021***	-0.020***
चलनिधि अनिश्चितता	0.192***	0.194***	0.039	0.054	0.022	-0.006	-0.026
चलनिधि की स्थिति*चलनिधि अनिश्चितता	-0.056**	-0.089***	0.043	0.013	0.021	0.009	0.012
वैश्विक ईपीयू स्थिर	-0.014	-0.029	0.154**	0.103**	0.040	0.096***	0.050**
पिछड़ा आश्रित वेरिएबल	0.749***	0.751***	-0.554	-0.230	-0.057	-0.289**	-0.176
टिप्पणियों की संख्या	156	156	0.707***	0.774***	0.815***	0.840***	0.890***
समायोजित आरस्क्वायर	0.782	0.768	0.615	0.712	0.785	0.800	0.882

नोट: '***', '**' और '*' क्रमशः 1 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 10 प्रतिशत स्तर पर सांख्यिकीय महत्व दर्शाते हैं।

संदर्भ:

एमिसानो, जी, और ट्रिस्टानी, ओ (2019)। अनसर्टीनिटी शॉक्स, मॉनिटरी पोलिसी एंड लांग टर्म इंटेरेस्ट रेट्स। ईसीबी वर्किंग पेपर नंबर 2279।

अशरफ, बीएन, और यिनजी, एस (2019)। इकोनामिक पोलिसी अनसर्टीनिटी एंड बैंक लोन प्राइसिंग। जर्नल ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, वॉल्यूम 44।

बेकर, एसआर, ब्लूम, एन, डेविस, एसजे (2016)। मेज़रिंग इकोनामिक पोलिसी अनसर्टीनिटी। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स, 131, 1593-1636।

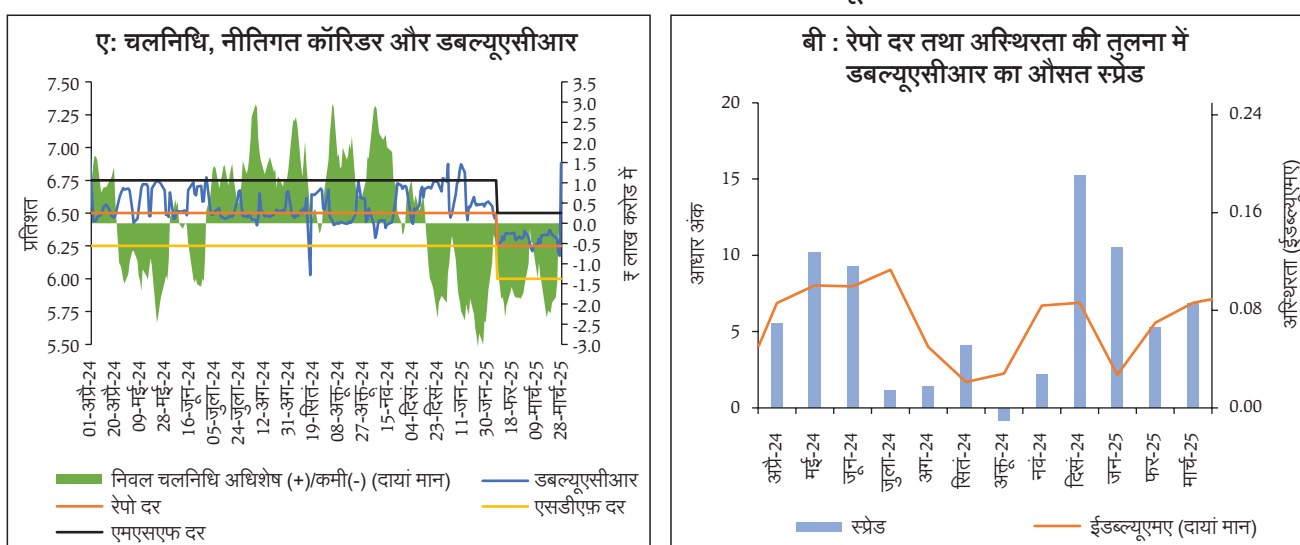
राजनीतिक, व्यापार और नीतिगत अनिश्चितताओं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के बहिर्वाह के बीच 2024-25 की दूसरी छमाही में इक्विटी बाजारों में लगातार गिरावट देखी गई। फरवरी तक आईएनआर ने अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मूल्यहास की तरफ झुका रहा, लेकिन मार्च में इसके कुछ नुकसान की भरपाई हुई और वह सबसे कम अस्थिर प्रमुख ईएमई मुद्राओं में से एक रहा। क्रेडिट मार्केट में, कुछ नरमी के बावजूद, बैंक ऋण में वृद्धि 2024-25 की दूसरी छमाही में जमा विस्तार से आगे निकल गई।

IV.2.1 मुद्रा बाजार

मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य अर्थात् भारित औसत मांग दर (डब्ल्यूएसीआर), नीतिगत रेपो दर और उभरती चलनिधि स्थितियों के साथ तालमेल में आगे बढ़ा। 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान, डब्ल्यूएसीआर बढ़कर नीतिगत कॉरिडोर के भीतर बना रहा और अक्तूबर-नवंबर के दौरान नीतिगत रेपो दर के करीब बना रहा तथा दिसंबर के उत्तरार्ध और जनवरी की शुरुआत में एलएफ कॉरिडोर (एमएसएफ दर) उच्चतम सीमा के करीब रहा, तथा कभी-कभी कॉरिडोर उच्चतम सीमा (एमएसएफ दर) के बाहर चला गया। इसका आंशिक रूप से श्रेय मांग मुद्रा बाजार में कम ऋण देने की मात्रा को दिया जाता है क्योंकि बैंक

इस तिमाही में गैर-संपार्श्विक बाजार में उधार देने के लिए तैयार नहीं थे, इसके बजाय उन्होंने एसडीएफ के तहत धन जमा करना पसंद किया। जनवरी की शुरुआत में, डब्ल्यूएसीआर नीतिगत रेपो दर के करीब वापस आ गया क्योंकि दूसरे सप्ताह में फिर से कड़े होने से पहले चलनिधि की स्थिति आसान हो गई। जनवरी के मध्य से दैनिक वीआरआर की शुरुआत, फरवरी में नीतिगत रेपो दर में कटौती और आरबीआई के चलनिधि बढ़ाने के उपायों के साथ डब्ल्यूएसीआर में नरमी आई। सामान्यतः डब्ल्यूएसीआर में उतार-चढ़ाव मुख्य रूप से क्षणिक चलनिधि की स्थिति को दर्शाते हैं, जो उच्च सरकारी खर्च की वजह से महीने की शुरुआत में नरम और कर बहिर्वाह के कारण तीसरे सप्ताह के दौरान सख्त (चार्ट IV.4.ए) रहती है। अंतिम स्थिति (शॉर्ट-एंड) पर चलनिधि की कठोरता में कमी को दर्शाते हुए, नीतिगत रेपो दर पर डब्ल्यूएसीआर का औसत स्प्रेड मार्च 2025 में घटकर 7 आधार अंक (बीपीएस) हो गया, जो दिसंबर 2024 में 15 बीपीएस के उच्च स्तर पर था (चार्ट IV.4.बी)। डब्ल्यूएसीआर की अस्थिरता, जैसा कि एक्सपोनेंशियल वेटेड मूविंग एवरेज (ईडब्ल्यूएमए)⁶ द्वारा मापा जाता है, हालांकि, मार्च 2025 तक ऊंचा बना रहा। संपार्श्विक खंड अर्थात् त्रिपक्षीय रेपो (टीआरईपीएस) और बाजार रेपो में ओवरनाइट दरें मोटे तौर पर डब्ल्यूएसीआर के साथ संरेखित रहीं।

चार्ट IV.4: नीतिगत कॉरिडोर और डब्ल्यूएसीआर



स्रोत: रिजर्व बैंक (आरबीआई) और आरबीआई स्टाफ गणना।

⁶ ईडब्ल्यूएमए सरल विचरण पर एक सुधार है क्योंकि यह हाल के अवलोकनों को अधिक भार प्रदान करता है। ईडब्ल्यूएमए हाल के अवलोकनों को सौंपे गए उच्च भार के साथ पिछली अस्थिरता के भारित औसत के रूप में अस्थिरता व्यक्त करता है।

सारणी IV.3 : एक-दिवसीय मुद्रा बाजार की औसत मात्रा एवं हिस्सा

(₹ लाख करोड़)

	2023-24		2024-25			
	पहली छमाही	दूसरी छमाही	पहली छमाही	तिसरी तिमाही	चौथी तिमाही	दूसरी छमाही
कॉल/नोटिस	0.10(2)	0.10(2)	0.10(2)	0.10(2)	0.13(2)	0.11(2)
त्रिपक्षीय रेपो	2.87(64)	3.14(68)	3.30(68)	3.74(72)	3.51(69)	3.62(70)
बाजार रेपो	1.51(34)	1.37(30)	1.48(30)	1.37(26)	1.48(29)	1.42(28)
कुल	4.47(100)	4.62(100)	4.88(100)	5.20(100)	5.11(100)	5.16(100)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एक-दिवसीय मुद्रा बाजार के प्रत्येक खंड का हिस्सा दर्शाते हैं। आंकड़ों को राउन्ड ऑफ किए जाने के कारण उनका जोड़ कुल जोड़ के बराबर नहीं हो सकता है।

स्रोत : सीसीआईएल; आरबीआई

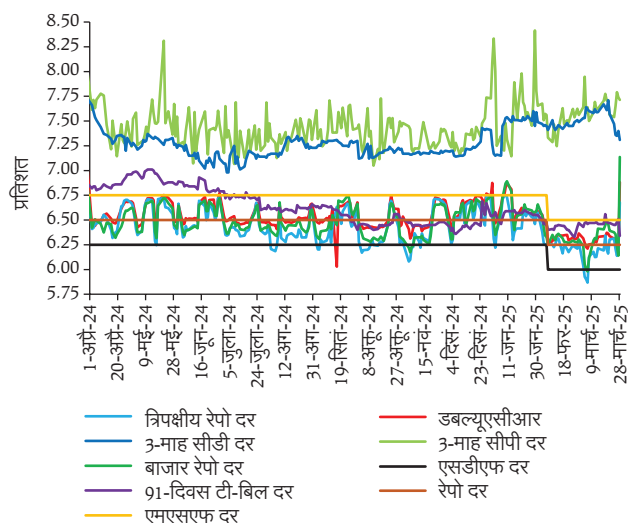
मुद्रा बाजार की गतिविधियों में संपार्श्विक (त्रिपक्षीय और बाजार रेपो) खंडों का दबदबा बना रहा, जिसमें रातोंरात मुद्रा बाजार की मात्रा में उनकी हिस्सेदारी ज्यादातर 98 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रही। (सारणी IV.3)।

म्यूचुअल फंड (एमएफ) त्रिपक्षीय रेपो (टीआरईपीएस) बाजार में प्रमुख ऋणदाता बने रहे, जिनकी हिस्सेदारी 2024-25 की पहली छमाही में 65 प्रतिशत से बढ़कर दूसरी छमाही में 67 प्रतिशत हो गई। बाजार रेपो खंड में, म्यूचुअल फंड (एमएफ) की उधार देने की हिस्सेदारी 2024-25 की पहली छमाही में 41 प्रतिशत से बढ़कर दूसरी छमाही में 46 प्रतिशत हो गई, विदेशी बैंकों की हिस्सेदारी 34 प्रतिशत से घटकर 31 प्रतिशत हो गई। उधार पक्ष पर, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) टीआरईपीएस में प्रमुख खिलाड़ी बने रहे, हालांकि उनका हिस्सा 2024-25 की पहली छमाही के 47 प्रतिशत से घटकर दूसरी छमाही में 40 प्रतिशत हो गया। हालांकि बाजार रेपो में उनकी हिस्सेदारी इसी अवधि में 4 प्रतिशत से बढ़कर 6 प्रतिशत हो गई।

मुद्रा बाजार के दीर्घावधि खंडों में, वाणिज्यिक पत्र (सीपी) तथा जमा प्रमाण पत्र (सीडी) पर दरें बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि की तंगी के कारण 2024-25 की पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही के दौरान बढ़ी (चार्ट IV.5)। इसके विपरीत टी-बिल दर इसी अवधि में कम हो गए। नीतिगत रेपो दर की तुलना में सीडी और सीपी का औसत स्प्रेड 2024-25 की पहली छमाही में क्रमशः 74 बीपीएस और 92 बीपीएस से बढ़कर दूसरी छमाही में क्रमशः 91 बीपीएस और 105 बीपीएस हो गया। जबकि नीतिगत रेपो दर पर टी-बिलों का औसत स्प्रेड उसी अवधि के दौरान 25 आधार अंक से कम होकर 4 बीपीएस हो गया।

सीडी के नए निर्गम दूसरी छमाही में बढ़कर ₹ 6.6 लाख करोड़ रुपये हो गए, जो 2024-25 की पहली छमाही में ₹5.4

चार्ट IV.5 : मुद्रा बाजार दरें और नीतिगत कॉरिडोर



स्रोत : फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लि. (एफबीआईएल) और आरबीआई

लाख करोड़ थे। फलस्वरूप 21 मार्च 2025 को समाप्त पखवाड़े के लिए सीडी जारी करने की कुल बकाया राशि ₹5.3 लाख करोड़ रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई, क्योंकि बैंकों ने जमा वृद्धि के बीच सीडी के माध्यम से धन जुटाने पर भरोसा करना जारी रखा। दूसरी छमाही के भीतर, छोटी अवधि (91-दिनों तक) में सीडी जारी करने में गिरावट आई, कुल निर्गमों में उनकी हिस्सेदारी अक्टूबर 2024 में 68 प्रतिशत से घटकर मार्च 2025 में 58 प्रतिशत हो गई। इसके साथ ही, लंबी अवधि की सीडी (181-365 दिन) की हिस्सेदारी अक्टूबर 2024 में 30 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2025 में 40 प्रतिशत हो गई (सारणी IV.4)।

दूसरी छमाही के दौरान सीपी के नए निर्गमों के माध्यम से संसाधन जुटाना बढ़कर ₹8.2 लाख करोड़ रुपये (मार्च 2025

सारणी IV.4 सीडी निर्गमों का अवधि वार ब्यौरा

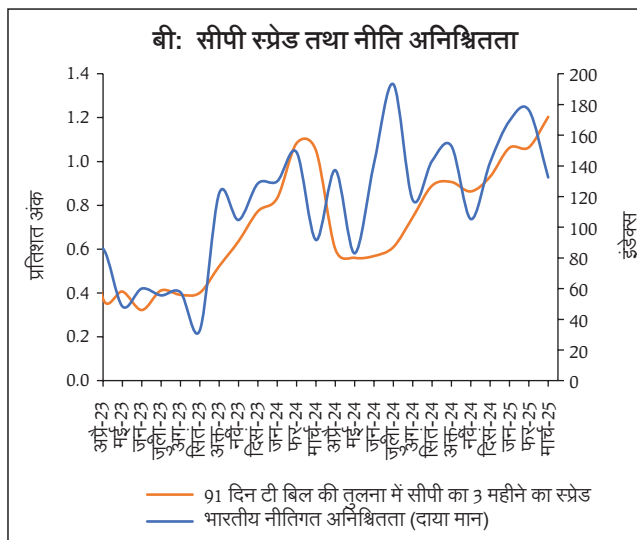
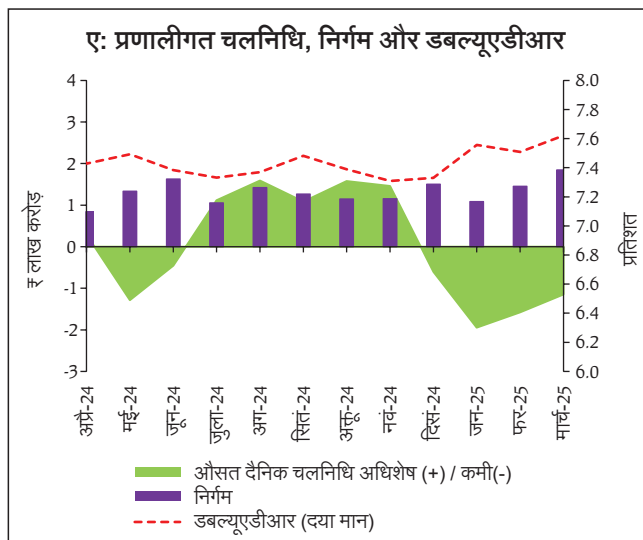
(₹ लाख करोड़)

	2023-24		2024-25			
	पहली छमाही	दूसरी छमाही	पहली छमाही	तिसरी तिमाही	चौथी तिमाही	दूसरी छमाही
90 दिन तक	2.37(76)	3.76(68)	3.93(73)	1.75(61)	1.99(54)	3.74(57)
92-180 दिन	0.18(6)	0.18(3)	0.20(4)	0.09(3)	0.08(2)	0.17(3)
181-365 दिन	0.58(19)	1.59(29)	1.22(23)	1.02(36)	1.63(44)	2.64(40)
कुल	3.13(100)	5.52(100)	5.35(100)	2.86(100)	3.70(100)	6.56(100)

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े एक-दिवसीय मुद्रा बाजार के प्रत्येक खंड का हिस्सा दर्शाते हैं। आंकड़ों को राउन्ड ऑफ किए जाने के कारण उनका जोड़ कुल जोड़ के बराबर नहीं हो सकता है।

स्रोत : सीसीआईएल और आरबीआई स्टाफ अनुमान

चार्ट IV.6 : वाणिज्यिक पत्र के प्राथमिक निर्गम



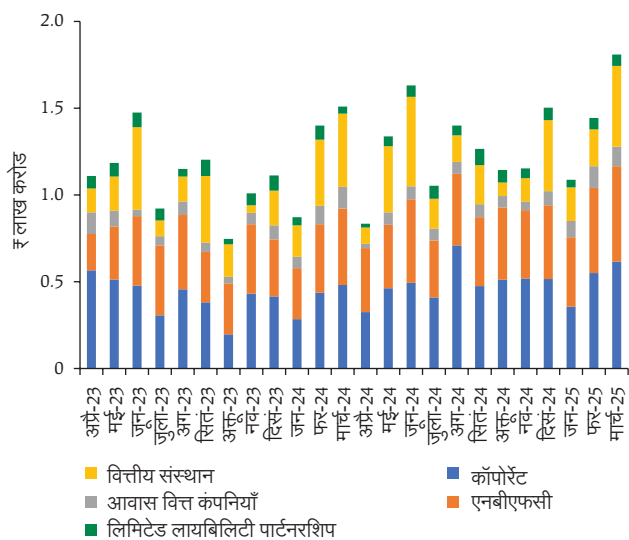
स्रोत : आरबीआई; सीसीआईएल-एफ-टीआरएसी; www.policyuncertainty.com और आरबीआई स्टाफ अनुमान

तक) हो गया, जो 2024-25 की पहली छमाही में ₹7.6 लाख करोड़ रुपये था (चार्ट IV.6ए)। सीपी की भारित औसत छूट दर आम तौर पर 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान बढ़ जाती है, जो मार्च 2025 के उत्तरार्द्ध में मुख्य रूप से चलनिधि घाटे के कारण कम हो जाती है। फरवरी 2025 की नीति दर में कटौती से पहले टी-बिलों के स्प्रेड की तुलना में सीपी दर के स्प्रेड में वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण सख्त चलनिधि स्थितियों के बीच नीतिगत अनिश्चितता थी (चार्ट IV.6.बी)।

नए निर्गमों में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की औसत हिस्सेदारी 2024-25 की दूसरी छमाही में 2024-25 की पहली छमाही के 32 प्रतिशत से बढ़कर 33 प्रतिशत हो गई। वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में सीपी बाजार में, कॉर्पोरेट कुल निर्गम में 38 प्रतिशत की औसत हिस्सेदारी के साथ प्रमुख खिलाड़ी थे (चार्ट IV.7)।

परिपक्वता बकेट वार, नए सीपी जारी करने का सबसे बड़ा हिस्सा 91-180 दिनों के खंड में था (सारणी IV.5)। ब्याज दर नरमी चक्र की शुरुआत के मद्देनजर पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में दीर्घावधि सीपी के उच्च निर्गम की वजह से निवेशकों में इनकी बहुत मांग है।

चार्ट IV.7 : वाणिज्यिक पत्र जारी करनेवालों का प्रोफाइल



स्रोत : आरबीआई; सीसीआईएल-एफ-टीआरएसी और आरबीआई स्टाफ अनुमान

सारणी IV.5 : सीपी निर्गमों की परिपक्वता प्रोफाइल

(₹ लाख करोड़)

अवधि	2023-24 की पहली छमाही	2023-24 की दूसरी छमाही	2024-25 की पहली छमाही	2024-25 की दूसरी छमाही
7-30 दिन	0.45(6)	0.48(7)	0.63(8)	0.51(6)
31-90 दिन	3.18(45)	2.32(35)	2.35(31)	2.33(28)
91-180 दिन	2.75(39)	3.11(47)	3.94(52)	4.24(52)
181-365 दिन	0.70(10)	0.77(12)	0.64(8)	1.11(14)
कुल	7.09(100)	6.67(100)	7.55(100)	8.19(100)
बकाया (समाप्ति-अवधि के अनुसार)	4.12	3.89	3.98	4.43

टिप्पणी: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रत्येक परिपक्वता प्रोफाइल का हिस्सा दर्शाते हैं। पूर्णांकन के कारण आंकड़े कुल में नहीं जुड़ सकते हैं।

स्रोत : सीसीआईएल-एफ-टीआरएसी; और आरबीआई

IV.2.2 सरकारी प्रतिभूतियां (जी-सेक) बाजार

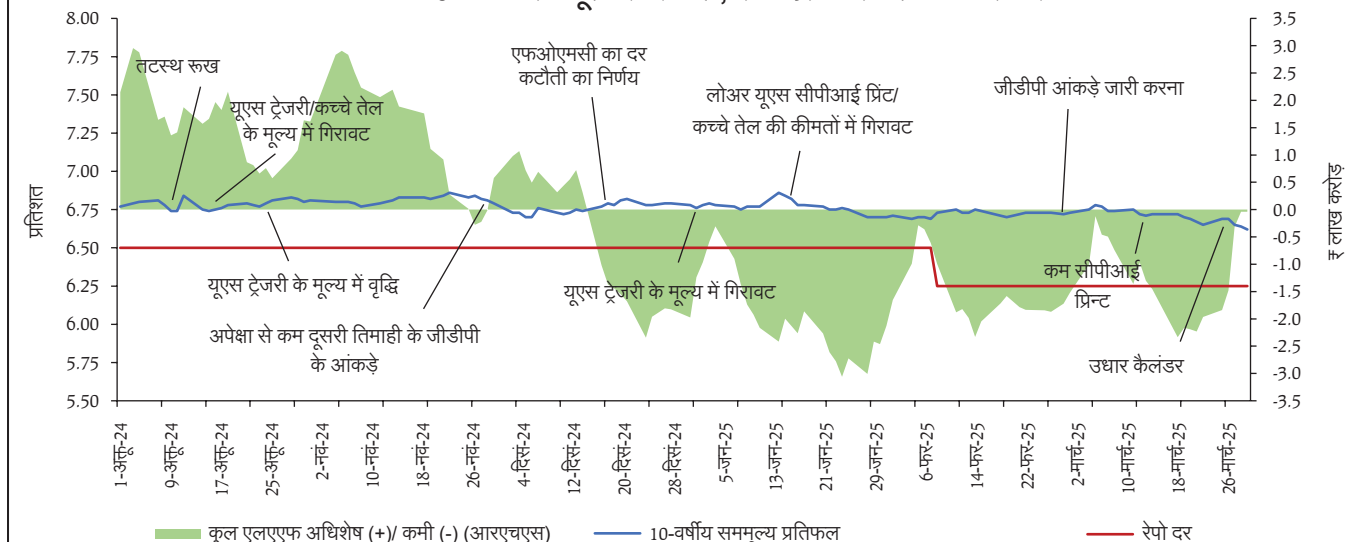
10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों का प्रतिफल 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान 6.62 से 6.86 प्रतिशत के बीच रहा। दूसरी छमाही की शुरुआत में प्रतिफल में मजबूती आई, जिसका कारण अमेरिकी प्रतिफल में उतार-चढ़ाव और कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि थी। हालांकि, उभरते बाजार सरकारी बॉण्ड सूचकांक (ईएमजीबीआई) में भारतीय सरकारी बॉण्डों को शामिल किए जाने पर सकारात्मक भावनाओं के बीच प्रतिफल में नरमी आई। नवंबर के दौरान, मुख्य रूप से 2024-25 की दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि अनुमानों में तेज गिरावट और मौद्रिक नीति चक्र में जल्द ही ढील दिए जाने की प्रत्याशा के कारण प्रतिफल में नरमी आई।

दिसंबर में प्रतिफल में गिरावट जारी रही, लेकिन अपरिवर्तित रेपो दर और दिसंबर नीति में तटस्थ रुख जारी रहने से यह कम हो गई। इसके बाद फेडरल ओपन मार्केट्स कमेटी (एफओएमसी) द्वारा दरों में कटौती की धीमी गति के संकेत के बाद प्रतिफल में वृद्धि हुई और उसके बाद यह स्थिर रहा। जनवरी की शुरुआत में, अमेरिकी प्रतिफल और बायबैक घोषणाओं के अनुरूप प्रतिफल में कुछ नरमी देखी गई। जनवरी के उत्तरार्ध में प्रतिफल में कमी आई, क्योंकि अमेरिका में सीपीआई मुद्रास्फीति के आंकड़े अपेक्षा से कम रहे, कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई और उभरते

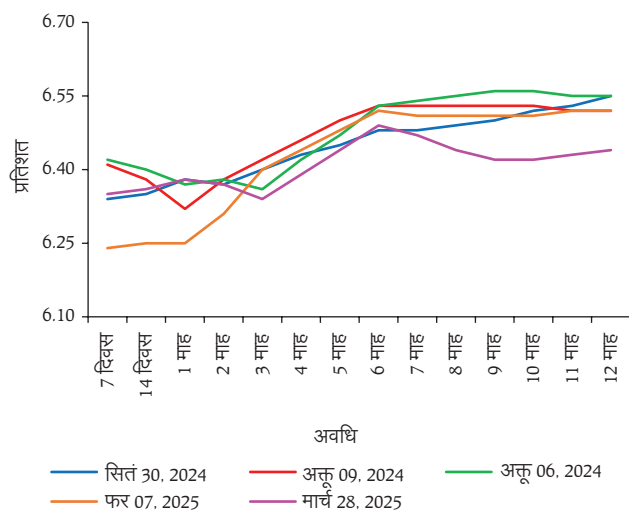
बाजार स्थानीय मुद्रा सूचकांक (ईएमएलसीआई) में भारतीय सरकारी बॉण्ड को शामिल किया गया। फरवरी के दौरान प्रतिफल सीमित दायरे में रहा और फरवरी के अंत में स्थिर रहा, ऐसा तीसरी तिमाही के जीडीपी डेटा जारी होने और अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में गिरावट के कारण हुआ। मार्च के दौरान, उम्मीद से कम सीपीआई आंकड़ा, आरबीआई द्वारा एक और खुला बाजार परिचालन की प्रत्याशा, अप्रैल-सितंबर में केंद्र सरकार का प्रत्याशा से कम का उधार कैलेंडर और दरों में एक और कटौती की प्रत्याशा के मद्देनजर प्रतिफल में नरमी आई (चार्ट IV.8)।

वैश्विक वित्तीय बाजारों में बढ़ती अस्थिरता के बीच अक्तूबर के दौरान टी-बिल पर प्रतिफल में तेजी आई। नवंबर के दौरान अल्पावधि के लिए उनमें नरमी आई लेकिन निर्धावधि के लिए उनमें वृद्धि हो गयी। सख्त चलनिधि की स्थिति और दरों में कटौती की उम्मीदों में कमी के कारण दिसंबर में सख्त पूर्वाग्रह जारी रहा। जनवरी के दौरान, टी-बिल दरें परिपक्वता काल में नरम हो गईं, घरेलू प्रतिफल में गिरावट पर नज़र रखी, और नीति में ढील की उम्मीदों से उत्साहित हुई। ट्रेजरी बिल की नीलामी रद्द होने के बीच प्रतिफल सख्त होने के साथ फरवरी में छोटी अवधि के लिए नरम पूर्वाग्रह जारी रहा। मार्च के दौरान, वैश्विक और घरेलू विकास पर नज़र रखते हुए टी-बिल दरों में नरमी आई (चार्ट IV.9)।

चार्ट IV.8 : 10-वर्षीय सममूल्य प्रतिफल, रेपो दर और चलनिधि स्थितियाँ



चार्ट IV.9 : एफबीआईएल – टी-बिल बेंचमार्क
(परिपक्वता प्रतिफल)



स्रोत: एफबीआईएल

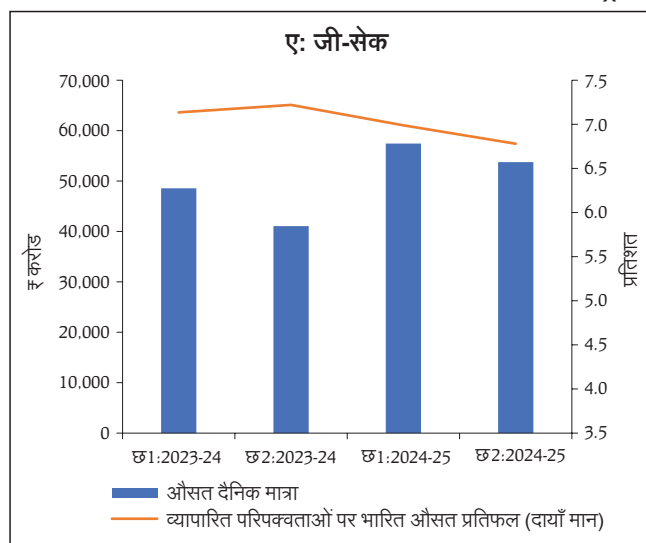
जी-सेक और टी-बिलों में औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम पहली छमाही (चार्ट IV.10) के सापेक्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में नरम हुआ। जी-सेक और टी-बिलों के लिए ट्रेडेड मेच्योरिटी पर भारित औसत प्रतिफल (डब्ल्यूएवाई) 2024-25 की पहली

छमाही तुलना में दूसरी छमाही में क्रमशः 21 बीपीएस और 26 बीपीएस कम हो गईं।

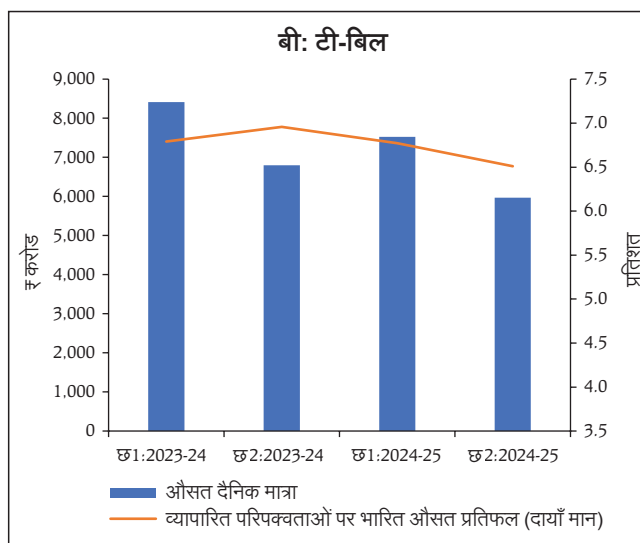
प्रतिफल वक्र की समग्र गतिशीलता को इसके गुप्त कारकों जैसे, स्तर, ढलान और वक्रता⁷ द्वारा कैप्चर किया जाता है। दीर्घावधि में अवधि संरचना में प्रतिफल नरम हो गई है जैसा कि 2024-25 की दूसरी छमाही (चार्ट IV.11ए) के दौरान प्रतिफल वक्र के नीचे की ओर बदलाव में परिलक्षित होता है, प्रतिफल का औसत स्तर 8 बीपीएस कम हो जाता है जबकि प्रतिफल वक्र का ढलान 10 बीपीएस (चार्ट IV.11बी) बढ़ जाता है। दूसरी ओर, वक्रता में 20 बीपीएस की गिरावट आई, जो अल्प और दीर्घ अवधि की तुलना में मिड-सेगमेंट में नरम पूर्वाग्रह को दर्शाती है। भारतीय संदर्भ में, प्रतिफल वक्र के स्तर और वक्रता में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) के विपरीत, बाजार विभाजन के कारण ढलान की तुलना में भविष्य के व्यापक आर्थिक परिणामों पर अधिक जानकारी सामग्री पाई जाती है (पात्रा एवं अन्य, 2022)⁸।

ऋण समेकन की सुविधा के लिए, रिजर्व बैंक ने 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान भारत सरकार की ओर से ₹31,424 करोड़ की दो स्विच नीलामी आयोजित की। जी-सेक के बकाया

चार्ट IV.10 : ट्रेडिंग मात्रा और प्रतिफल



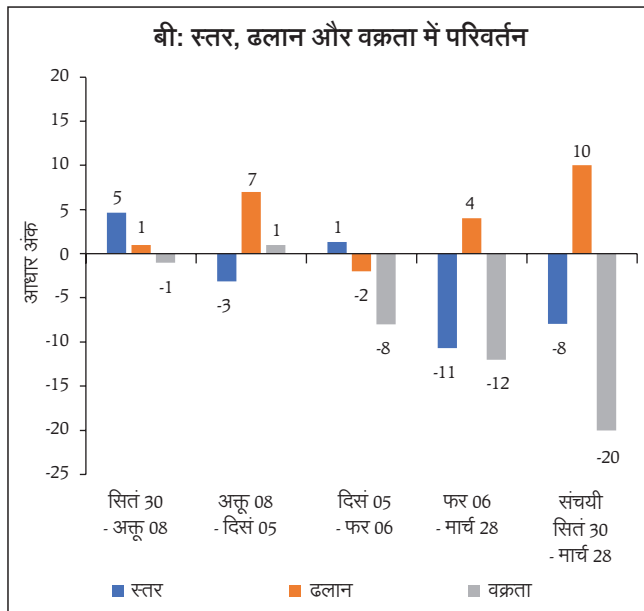
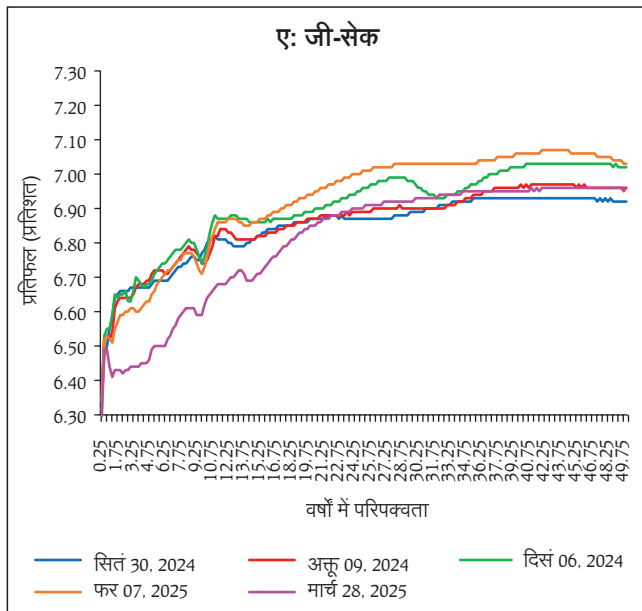
स्रोत : सीसीआईएल और आरबीआई स्टॉफ अनुमान



⁷ स्तर एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित 30 साल तक की सभी अवधि के बराबर प्रतिफल का औसत है और ढलान (टर्म स्प्रेड) 3 महीने और 30 साल की परिपक्वता के प्रतिफल में अंतर है। वक्रता की गणना 15 साल की प्रतिफल से 30 साल और 3 महीने की प्रतिफल के योग से दोगुनी के रूप में की जाती है।

⁸ पात्रा, एमडी, जॉयस, जे., कुशवाहा, केएम, और आई. भट्टाचार्य (2022), "अर्थव्यवस्था के बारे में हमें बताने वाला यील्ड कर्व क्या है?", भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन, जून।

चार्ट IV.11: जी-सेक प्रतिफल वक्र



स्रोत : एफबीआईएल; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

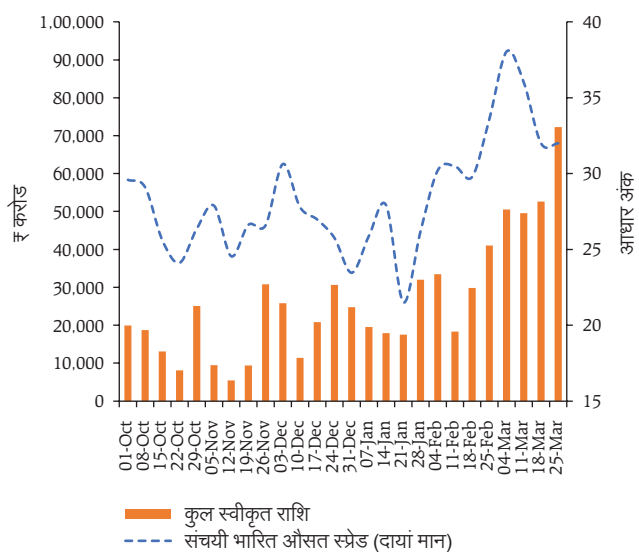
स्टॉक की भारित औसत परिपक्वता (डब्ल्यूएएम) मार्च, 2025 के अंत तक बढ़कर 13.29 वर्ष हो गई, जो सितंबर 2024 के अंत में 12.96 वर्ष थी, भारित औसत कूपन (डब्ल्यूएसी) इसी अवधि (7.28 प्रतिशत के मुकाबले 7.25 प्रतिशत) से कम था।

2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान, विशेष रूप से सरकार की बेहतर नकदी स्थिति की पृष्ठभूमि में, ₹ 1.25 लाख करोड़ रुपये की कुल राशि के लिए, पांच बायबैक नीलामियों की घोषणा की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत सरकार के कुछ ऋणों को चुकाना था⁹। हालांकि, नीलामियों के प्रति बाजार की प्रतिक्रिया धीमी रही, जिसमें रिजर्व बैंक को ₹1.25 लाख करोड़ रुपये की अधिसूचित राशि के मुकाबले केवल ₹0.88 लाख करोड़ रुपये के प्रस्ताव प्राप्त हुए।

2024-25 की दूसरी छमाही में तुलनीय परिपक्वताओं वाले भारत सरकार के जी-सेक प्रतिफल तथा राज्य सरकार की प्रतिभूतियों (एसजीएस) पर अधिकतम प्रतिफलों के भारित औसत स्प्रेड का अंतर 30 बीपीएस था (चार्ट IV.12) जबकि पहली छमाही में यह 31 बीपीएस था। 10-वर्ष की अवधि

(नए निर्गम) वाली प्रतिभूतियों का औसत अंतर-राज्य स्प्रेड पहली छमाही के 2 बीपीएस की तुलना में दूसरी छमाही में 4 बीपीएस था।

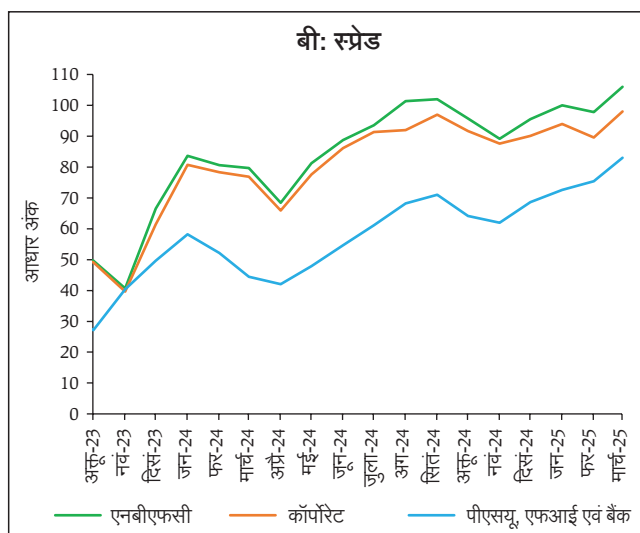
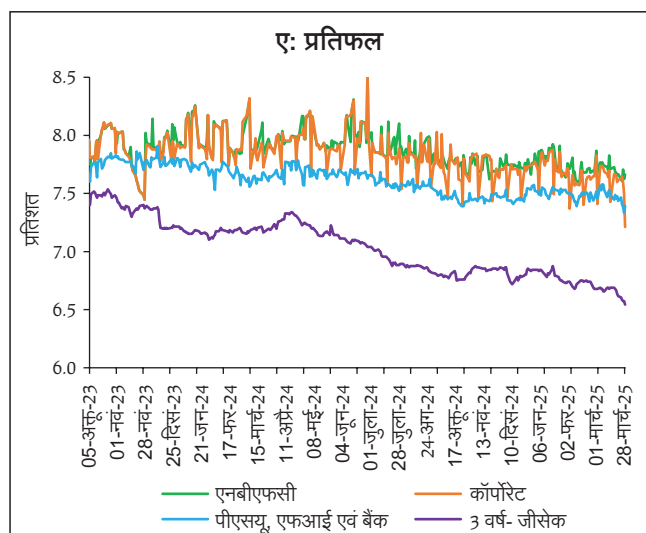
चार्ट IV.12: एसजीएस- जुटाई गई राशि और स्प्रेड



स्रोत: आरबीआई।

⁹ यद्यपि बायबैक का चलनिधि पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन उन्हें चलनिधि प्रबंधन परिचालन के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए; इसके बजाय, वे एक सक्रिय ऋण समेकन रणनीति का हिस्सा हैं।

चार्ट IV.13: एए-रेटेड 3-वर्षीय कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल और स्प्रेड



नोट: जी-सेक पर पर मासिक औसत स्प्रेड को दर्शाता है।

स्रोत: भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा)।

IV.2.3 कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केट

2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल सामान्यतः कम हुआ जबकि स्प्रेड बढ़ गया। निर्गमकर्ता-वार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू), वित्तीय संस्थाओं (एफआई) और बैंकों द्वारा जारी एए-रेटेड 3-वर्षीय बॉण्ड पर औसत प्रतिफल 5 बीपीएस की कमी के साथ 7.48 प्रतिशत तक हो गया, जबकि गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और कॉर्पोरेट्स द्वारा जारी किए बॉण्ड पर प्रतिफल में क्रमशः मार्च 2025 में सितंबर 2024 की तुलना में 14 बीपीएस की कमी के साथ 7.70 प्रतिशत और 18 बीपीएस की कमी के साथ 7.62 प्रतिशत तक की गिरावट आई (चार्ट IV.13ए)। इसके बावजूद, 2024-25 की दूसरी छमाही में जोखिम प्रीमियम (3-वर्षीय एए

कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल का 3-वर्षीय जी-सेक प्रतिफल की तुलना में स्प्रेड) पीएसयू, एफआई और बैंकों के लिए 71 बीपीएस से बढ़कर 83 बीपीएस, एनबीएफसी के लिए 102 बीपीएस से बढ़कर 106 और कॉर्पोरेट्स के लिए 97 बीपीएस से बढ़कर 98 बीपीएस हो गया (चार्ट IV.13बी)।

2024-25 की तीसरी तिमाही में कॉर्पोरेट प्रदर्शन में नरमी और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नरम आर्थिक विकास परिदृश्य के बीच सभी अवधियों तथा रेटिंग स्पेक्ट्रम में जोखिम प्रीमियम में वृद्धि देखी गई (सारणी IV.6)। इसी तरह, 2024-25 की पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में भारतीय स्टेट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के लिए विदेशों में होने वाले औसत 3-वर्षीय क्रेडिट डिफॉल्ट स्वेप (सीडीएस) स्प्रेड में क्रमशः 2 बीपीएस और 4 बीपीएस की वृद्धि हुई।

सारणी IV.6: वित्तीय बाजार- दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (बीपीएस) (तदनरूपी जोखिम-मुक्त दर पर)		
	मार्च 2024	सितंबर 2024	मार्च 2025	मार्च 2024	सितंबर 2024	मार्च 2025
1	2	3	4	5	6	7
कॉर्पोरेट बॉण्ड						
(i) एए (1-वर्ष)	7.97	7.92	7.76	77	117	115
(ii) एए (3-वर्ष)	7.95	7.80	7.62	77	97	98
(iii) एए (5-वर्ष)	7.74	7.70	7.60	54	86	89
(iv) एए (3-वर्ष)	8.55	8.55	8.43	137	172	178
(v) बीबीबी-माइनस (3-वर्ष)	12.19	12.14	12.09	500	531	544

नोट: प्रतिफलों और स्प्रेड को मासिक औसतों के रूप में परिकलित किया गया है।

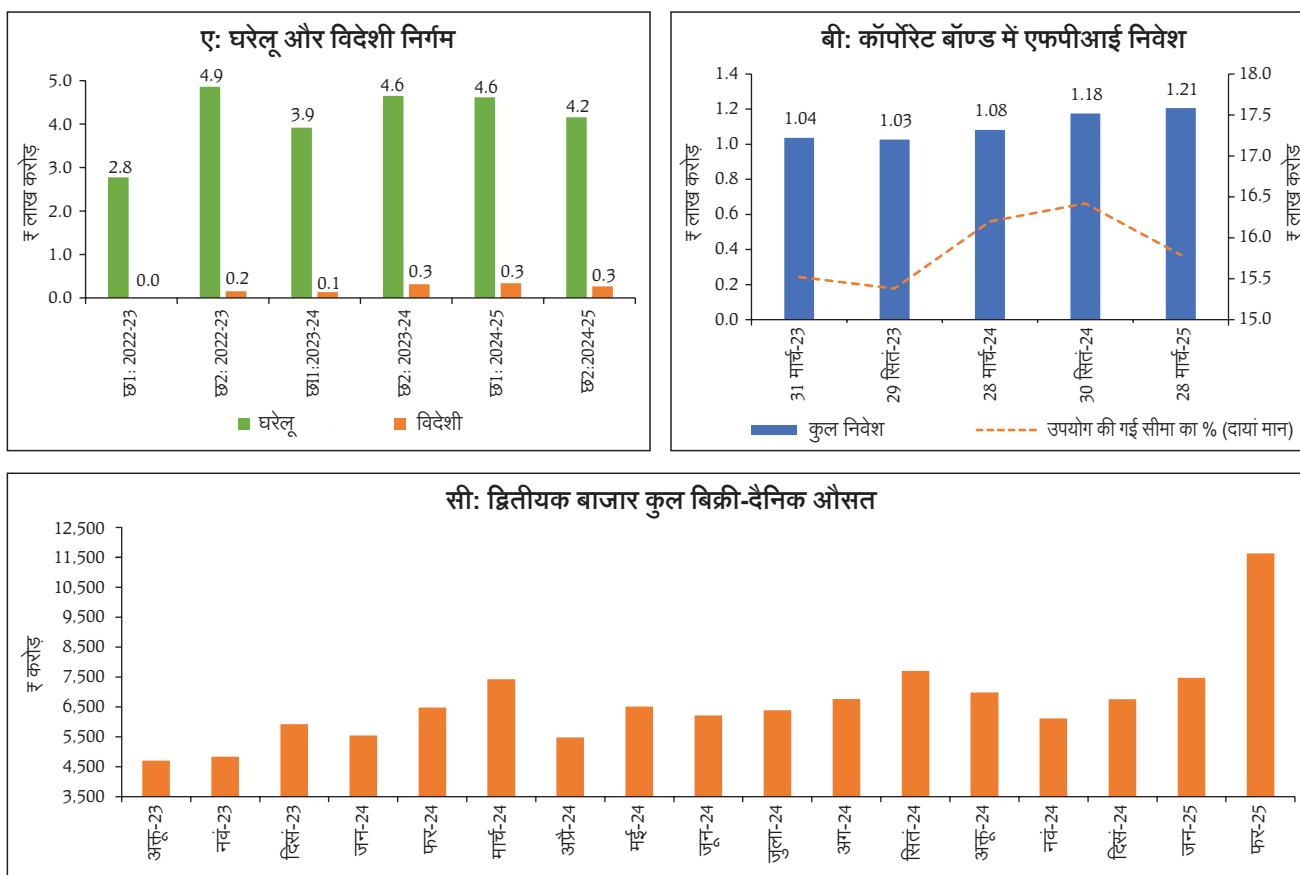
स्रोत: फिम्डा।

घरेलू बाजारों में सूचीबद्ध कॉर्पोरेट बॉण्ड का प्राथमिक निर्गम दूसरी छमाही (फरवरी 2025 तक) के दौरान ₹4.2 लाख करोड़ रहा, जबकि 2024-25 की पहली छमाही के दौरान यह ₹4.6 लाख करोड़ था¹⁰ (चार्ट IV.14ए)। वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने और घरेलू कॉर्पोरेट बॉण्डों के प्रतिफल में गिरावट के बीच दूसरी छमाही के दौरान ₹26,494 करोड़ का विदेशी निर्गम 2024-25 की पहली छमाही के दौरान ₹33,952 करोड़ के निर्गम की तुलना में कम था। कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार में संसाधनों का लगभग पूरा संग्रहण (99.3 प्रतिशत) निजी तौर पर शेयर आबंटन मार्ग (फरवरी 2025 तक) के माध्यम से हुआ। मार्च 2025 के अंत में कॉर्पोरेट बॉण्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा बकाया निवेश ₹1.21 लाख करोड़ रहा जबकि यह सितंबर 2024 के अंत में ₹1.18 लाख करोड़ था जिससे अनुमोदित सीमाओं का उपयोग 16.4 प्रतिशत से घटकर 15.8 प्रतिशत हो

गया (चार्ट IV.14बी)। हालांकि, द्वितीयक बाजार की गतिविधि में तेजी आई है, जिसमें 2024-25 की दूसरी छमाही (फरवरी 2025 तक) के दौरान दैनिक औसत कारोबार की राशि ₹7,715 करोड़ रही जो 2024-25 की पहली छमाही के दौरान ₹6,533 करोड़ थी (चार्ट IV.14सी)।

कॉर्पोरेट बॉण्ड के लिए द्वितीयक बाजार में चलनिधि की कमी की समस्या दूर करने के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) ने चलनिधि विंडो सुविधा शुरू करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसके द्वारा बॉण्ड जारीकर्ता निवेशकों को स्वैच्छिक पुट ऑप्शन देने की अनुमति दी गई, जो विशिष्ट अंतराल पर बॉण्ड को परिपक्वता से पहले जारीकर्ता को वापस बेचने का अधिकार होता है। इसके अलावा, विनियामक ने भारत में जारी किए गए कॉर्पोरेट बॉण्ड पर जानकारी का एक एकल

चार्ट IV.14: कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार गतिविधि



नोट: * घरेलू निर्गमों का डेटा फरवरी 2025 तक है जबकि विदेशी निर्गमों का डेटा मार्च 2025 तक है; दैनिक औसत की गणना मासिक टर्नओवर को ट्रेडिंग दिनों की संख्या से विभाजित करके की जाती है।

स्रोत: सेबी, एनएसडीएल और प्राइम डेटाबेस।

¹⁰ वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में जारी किए गए ऋण आम तौर पर दूसरी छमाही की तुलना में कम होते हैं क्योंकि कॉर्पोरेट्स की उधार योजनाएं धीरे-धीरे बनाई जाती हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार के उधार आम तौर पर शुरुआत में ही काफी अधिक होते हैं, जो कॉर्पोरेट्स को दूसरी छमाही में संसाधन जुटाने के लिए अधिक समय प्रदान करता है।

प्रामाणिक स्रोत बनाने के उद्देश्य से कॉरपोरेट बॉण्ड के लिए एक केंद्रीकृत डेटाबेस की स्थापना की भी घोषणा की।

IV.2.4 इक्विटी बाजार

वैश्विक टैरिफ युद्धों और भू-राजनीतिक तनावों के बीच अनिश्चितता के चलते जोखिम से दूर रहने की भावना बढ़ी और एफपीआई के बहिर्वाह के कारण 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान भारतीय इक्विटी बाजार में लगातार गिरावट देखी गई। भू-राजनीतिक तनावों के बीच एफपीआई की बिकवाली और 2024-25 की दूसरी तिमाही में उम्मीद से कम कॉर्पोरेट आय के कारण बेंचमार्क बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) सेंसेक्स में अक्टूबर में गिरावट आई। अनुकूल वैश्विक संकेतों के कारण नवंबर के अंत और दिसंबर की शुरुआत में बाजारों में नुकसान की कुछ भरपाई हुई। इसके बाद, 2025 के लिए यूएस फेड की मौद्रिक नीति के दृष्टिकोण में बदलाव के कारण वैश्विक बिकवाली के बीच बाजारों को प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।

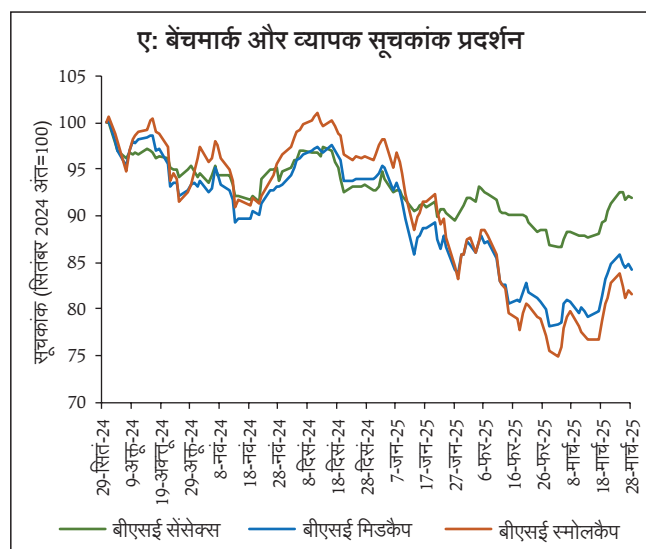
2024-25 के लिए जीडीपी अनुमानों के आधार पर उम्मीद से कम घरेलू विकास दृष्टिकोण के कारण बाजारों में जोखिम से दूर रहने की भावना से नकारात्मक भावना के साथ 2025 की शुरुआत हुई। इसके अलावा, अमेरिकी नीति परिवर्तनों, लगातार एफपीआई की बिकवाली और 2024-25 की तीसरी तिमाही के लिए मिश्रित घरेलू कॉर्पोरेट आय के बारे में अनिश्चितताओं के कारण भी निवेशकों में उत्साह की भावना कम हुई। हालांकि, अनुकूल वैश्विक संकेतों और एफपीआई प्रवाह में तेजी के बीच

मार्च के दूसरे पखवाड़े में बाजार में सुधार दिखा। कुल मिलाकर, बीएसई सेंसेक्स 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान 8.2 प्रतिशत की गिरावट के साथ मार्च 2025 के अंत में 77,415 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार सूचकांकों ने बेंचमार्क से कम प्रदर्शन किया, जिसमें बीएसई मिडकैप और बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक में क्रमशः 15.8 प्रतिशत और 18.4 प्रतिशत की गिरावट आई (चार्ट IV.15ए)। भारत का अस्थिरता सूचकांक (वीआईएक्स), जो निफ्टी 50 की अल्पकालिक अपेक्षित अस्थिरता की एक माप है, 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान औसतन 14.5 रहा, जबकि 2024-25 की पहली छमाही में यह 14.9 था। सभी बीएसई क्षेत्रवार सूचकांकों में दूसरी छमाही के दौरान हानि हुई (चार्ट IV.15बी)।

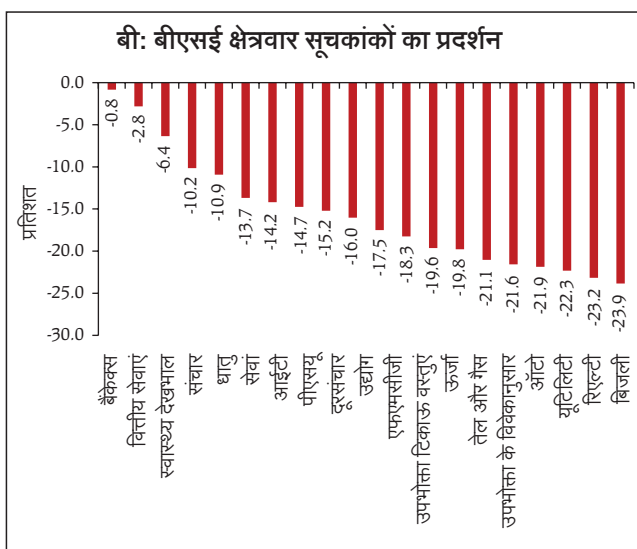
20 नवंबर 2024 से इक्विटी डेरिवेटिव्स ढांचे को मजबूत करने के लिए सेबी के विशिष्ट उपायों के कार्यान्वयन के अनुसार, औसत दैनिक नोशनल इक्विटी डेरिवेटिव्स वॉल्यूम में पहली छमाही की तुलना में दूसरी छमाही में गिरावट का रुझान दिखा (चार्ट IV.16)।

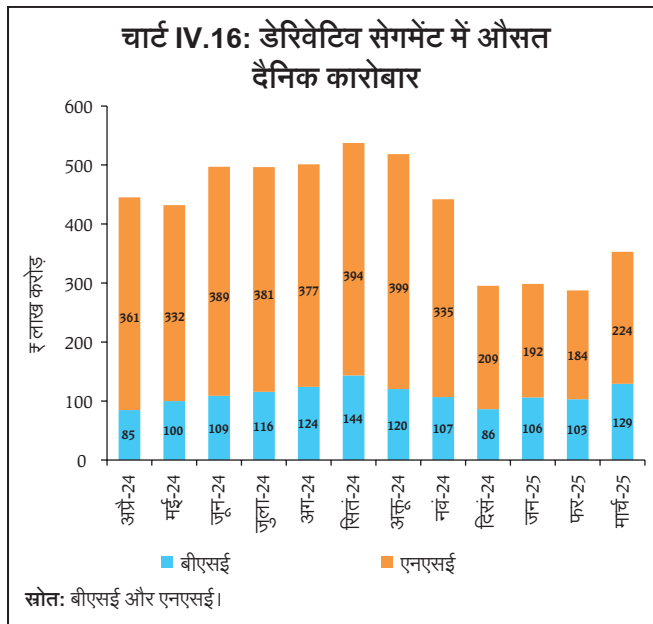
2024-25 की दूसरी छमाही में घरेलू इक्विटी बाजारों में निवल एफपीआई प्रवाह ऋणात्मक हो गया। इसके विपरीत, घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) से प्रवाह मजबूत बना रहा। कुल मिलाकर, एफपीआई ₹2.2 लाख करोड़ के निवल विक्रेता थे, जबकि डीआईआई ₹3.6 लाख करोड़ के निवल खरीदार थे (चार्ट IV.17ए)। सापेक्ष आधार पर, यानी, जब एफपीआई बहिर्वाह को कुल बाजार पूंजीकरण के संबंध में मापा जाता है, तो अक्तूबर

चार्ट IV.15: शेयर बाजार का प्रदर्शन



स्रोत: ब्लूमबर्ग।





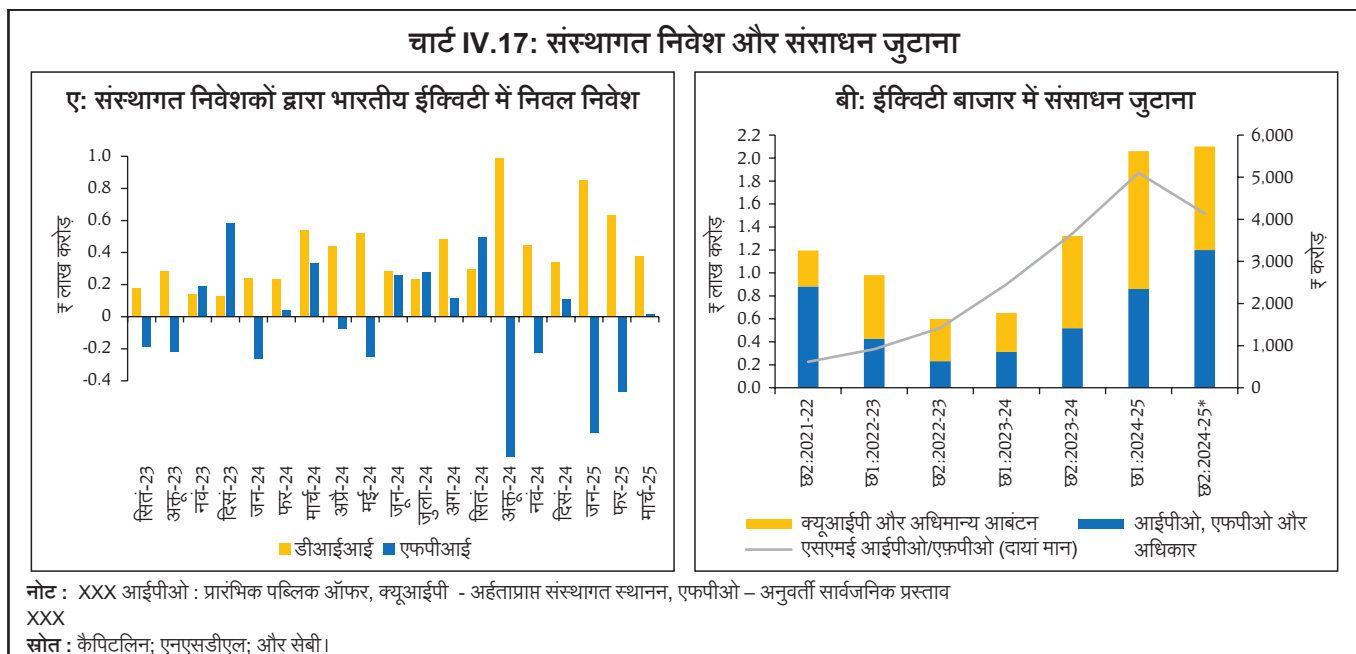
2021 से जुलाई 2022 के दौरान देखी गई 1 प्रतिशत की बिक्री की तुलना में अब तक बहिर्वाह बाजार पूंजीकरण के 0.5 प्रतिशत के मामूली स्तर पर बना हुआ है।

इक्विटी बाजारों में प्राथमिक बाजार संसाधन जुटाना 2024-25 की पहली छमाही में ₹2.09 लाख करोड़ की तुलना में 2024-25 की दूसरी छमाही (फरवरी 2025 तक) के दौरान ₹2.07 लाख करोड़ पर बना रहा (चार्ट IV.17बी)। दिसंबर तक मजबूत रहने के बाद, जोखिम भावना कम होने के कारण जनवरी और फरवरी में निर्गमों में काफी गिरावट आई। कुल प्राथमिक

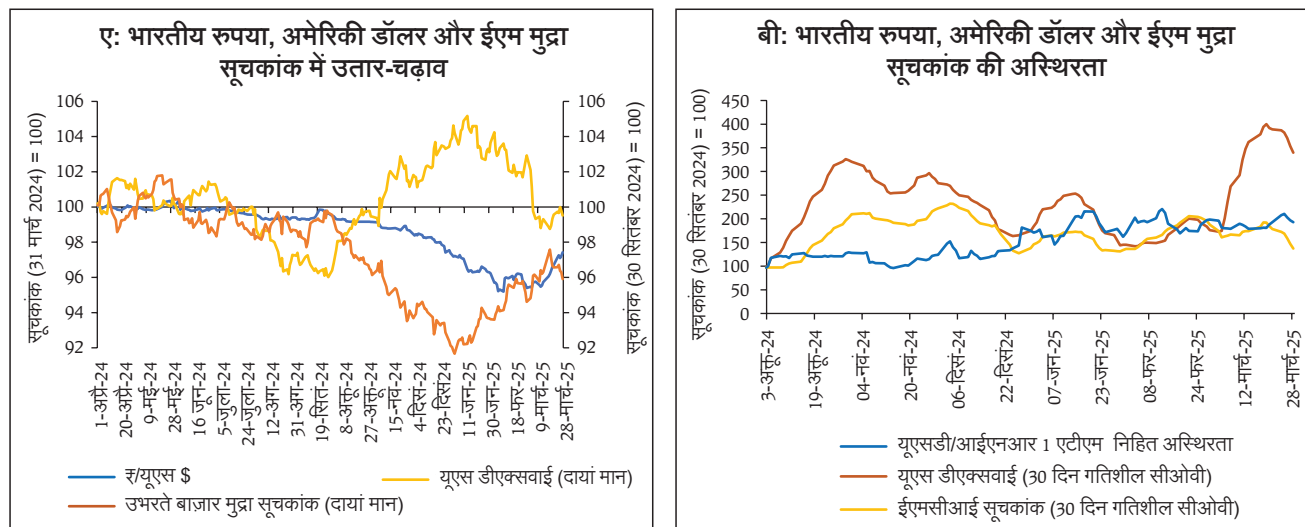
बाजार संग्रहण में से, सार्वजनिक निर्गमों के माध्यम से एसएमई कंपनियों द्वारा जुटाई गई राशि 2024-25 की पहली छमाही में ₹5,253 करोड़ की तुलना में दूसरी छमाही (फरवरी 2025 तक) के दौरान कुल ₹4,178 करोड़ थी।

IV.2.5 विदेशी मुद्रा बाजार

2024-25 के उत्तरार्ध के दौरान मुख्य रूप से बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और व्यापार नीतियों के संबंध में अनिश्चितताओं के कारण वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता में वृद्धि महसूस की गई। अमेरिकी डॉलर में तेज उतार-चढ़ाव हुआ, जो मजबूत अमेरिकी आर्थिक विकास की उम्मीदों के कारण जनवरी 2025 के मध्य में दो साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, बाद में इसमें गिरावट आई, जो आसन्न व्यापार युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिकी आर्थिक विस्तार की स्थिरता पर बढ़ती चिंताओं को दर्शाता है। उभरते बाजार की मुद्राओं को शुरुआत में अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने के कारण मूल्यहास दबाव का सामना करना पड़ा, लेकिन डॉलर के कमजोर होने के साथ ही इसमें सुधार हुआ। इस अवधि के दौरान, भारतीय रुपये को मुख्य रूप से अमेरिकी डॉलर में तेजी के कारण गिरावट के दबाव का सामना करना पड़ा। इसके अलावा, लगातार विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) बहिर्वाह, वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता में वृद्धि, और बढ़ते व्यापार घाटे के कारण भारतीय रुपये पर गिरावट का दबाव पड़ा। हालांकि, एफपीआई के अंतर्वाह और बेहतर जोखिम भावनाओं के कारण भारतीय रुपये में मार्च 2025 में सुधार दिखा (चार्ट IV.18ए)। भारतीय रुपये में भी विशेष रूप से 2024-25 की चौथी तिमाही



चार्ट IV.18: विनिमय दर और अस्थिरता



के दौरान बढ़ी हुई अस्थिरता दिखी जो वैश्विक विदेशी मुद्रा बाजार में उतार-चढ़ाव को प्रतिबिंबित करता है (चार्ट IV.18बी)। भारतीय रुपये के लिए 1-महीने का एट-द-मनी (एटीएम) विकल्प-निहित अस्थिरता 2024-25 की पहली छमाही में 2.2 प्रतिशत से बढ़कर 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान 3.0 प्रतिशत हो गया।

2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान विदेशी मुद्रा बाजार में अस्थिरता के पीछे कई वैश्विक घटना कारक रहीं, जिसमें अमेरिका में चुनाव, टैरिफ घोषणाएँ और यूएस फेड बैठकों से प्राप्त संकेत शामिल हैं (सारणी IV.7)।

फॉरवर्ड प्रीमिया में भी बहुत अधिक उतार-चढ़ाव दिखा और 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान सभी परिपक्वताएँ में ऊंचाई पर बनी हुई हैं, जो चलनिधि की सख्त स्थिति अत्यधिक

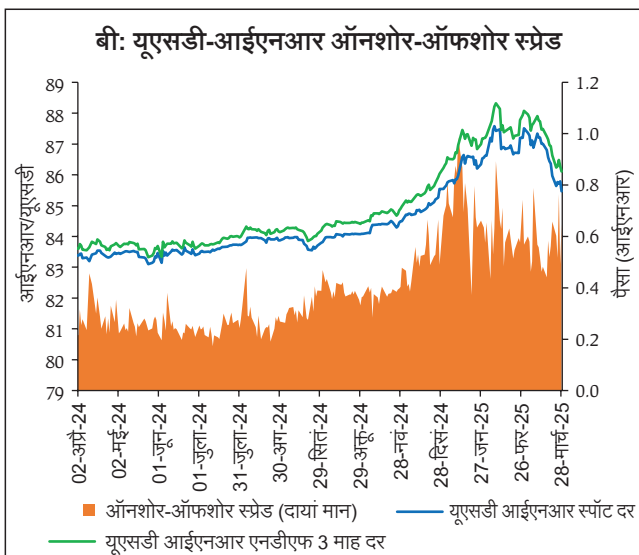
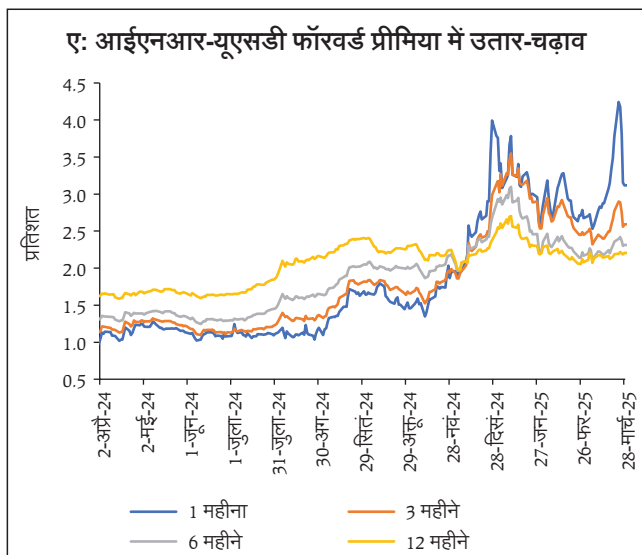
वैश्विक अनिश्चितताओं को दर्शाती है (चार्ट IV.19ए)। नवंबर 2024 के बाद से इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसमें 1 महीने का अग्रिम प्रीमियम लंबी अवधि के प्रीमियम से ऊपर बढ़ गया, जिसके परिणामस्वरूप अग्रिम प्रीमियम वक्र पलट गया, जिससे बढ़ती वैश्विक जोखिम-विरोधी भावना के कारण निकट अवधि में अनिश्चितता और अस्थिरता में वृद्धि का संकेत मिला। जबकि फॉरवर्ड प्रीमियम ऊंचाई पर बना रहा, मार्च के अंत में बढ़ने से पहले सिस्टम में टिकाऊ चलनिधि डालने के लिए रिजर्व बैंक के खरीद-बिक्री स्वैप संचालन के कारण 2025 की शुरुआत से इसमें गिरावट शुरू हो गई। भारतीय रुपए के लिए ऑनशोर-ऑफशोर स्प्रेड में इसी तरह का पैटर्न दिखा, जिससे 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान वैश्विक जोखिम से बचने की पृष्ठभूमि में चौथी तिमाही में कम होने से पहले बढ़ गया (चार्ट IV.19बी)।

सारणी IV.7: 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान वैश्विक और घरेलू विनिमय दर बाजार में महत्व के प्रकरण

	(मूल्यवृद्धि या/मूल्यहासः%)			अस्थिरता माप (%)	
	₹/यूएस\$	यूएस डीएक्सवाई	ईएमसीआई सूचकांक	आईएनआर 1 एटीएम अस्थिरता	3 माह फॉरवर्ड प्रीमियम
6 नवंबर 2024 (अमेरिकी चुनाव परिणाम)	-0.1	1.6	-0.5	2.1	1.7
25 नवंबर 2024 (मेक्सिको, कनाडा और चीन पर अमेरिकी टैरिफ की घोषणा)	0.3	-0.7	0.4	2.2	1.8
2 दिसंबर 2024 (ब्रिक्स पर अमेरिकी टैरिफ की घोषणा)	-0.2	0.7	-0.5	2.8	1.9
18 दिसंबर, 2024 (यूएस एफएमओसी बैठक)	-0.01	1.0	-1.0	2.3	2.4
3 फरवरी 2025 (टैरिफ पर कार्यकारी आदेश)	-0.5	0.6	-0.03	3.9	2.9
4 फरवरी 2025 (एक महीने के लिए टैरिफ रोका गया)	-0.01	-0.9	0.3	3.7	2.7
3 मार्च 2025 (रोका गया टैरिफ लगाया गया)	0.1	-0.8	0.2	3.8	2.5
19 मार्च 2025 (यूएस एफएमओसी बैठक)	0.2	0.2	-0.5	3.5	2.6

स्रोत : एफबीआईएल; रिफिनिटिव ईकोन; ब्लूमबर्ग और आरबीआई स्टाफ गणना।

चार्ट IV.19: भारतीय रुपये के अस्थिरता माप



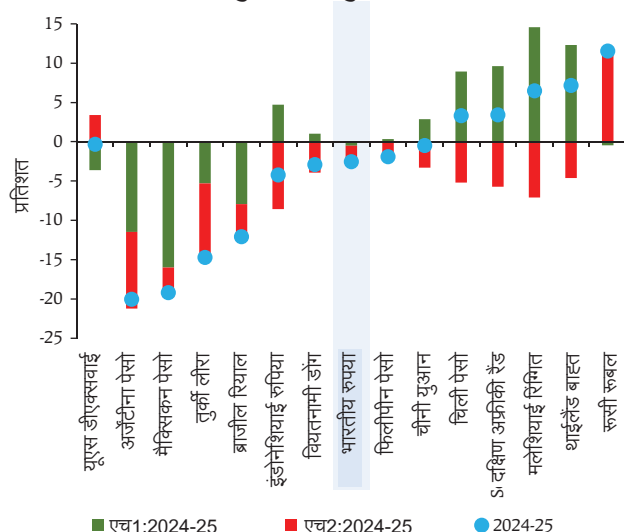
स्रोत : ब्लूमबर्ग।

2024-25 की दूसरी छमाही में अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने और वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने के कारण अधिकांश प्रमुख ईएम मुद्राओं में गिरावट आई (चार्ट IV.20)। मार्च 2024 के अंत और मार्च 2025 के अंत के बीच, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में 2.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसमें सबसे बड़ी गिरावट 2024-25 की दूसरी छमाही में हुई। इसके बावजूद, 2024-25 के दौरान रुपये में गिरावट कुछ समकक्ष ईएमई की तुलना में अपेक्षाकृत मामूली रही।

मार्च 2024 के अंत और मार्च, 2025 के अंत के बीच, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया (आईएनआर) में 2.6 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसमें वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में अधिक मूल्यहास हुआ। इसके बावजूद, वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय रुपए का मूल्यहास कुछ समकक्ष ईएमई की तुलना में सापेक्ष रूप से कम था।

वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में अधिकांश ईएम मुद्राओं में भी अस्थिरता बढ़ गई (सारणी IV.8)। हालांकि, बढ़ती वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद, भारतीय रुपया ईएम मुद्राओं में सबसे

चार्ट IV.20 : प्रमुख ईएम मुद्राओं में गतिविधियां



नोट: यह उतार-चढ़ाव पूर्ववर्ती अवधि में बिंदु से बिंदु परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
स्रोत: एफबीआईएल; और रेफिनिटिव एकोन।

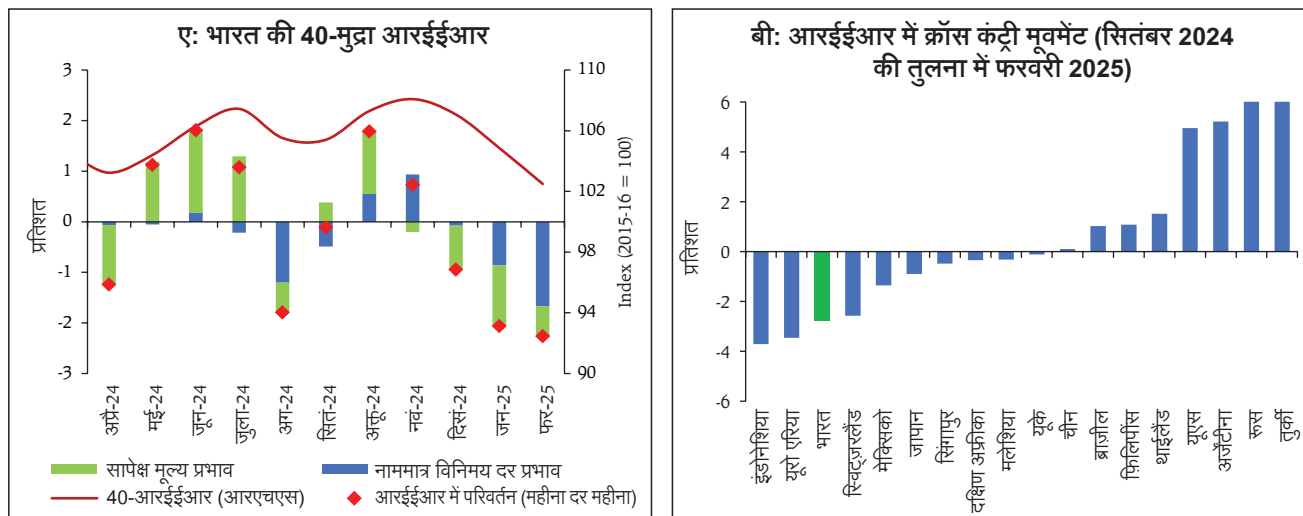
सारणी IV.8: प्रमुख ईएम मुद्राओं की माह-वार अस्थिरता*

	अक्तू-24	नव-24	दिस-24	जन-25	फर-25	मार्च-25	एच1: 2024-25	एच2: 2024-25
यूएस डीएक्सवाई	0.9	1.1	0.8	0.7	0.7	0.8	1.7	2.0
भारतीय रुपया	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.7	0.3	1.4
अर्जेंटीना पेसो	0.6	0.5	0.6	0.7	0.3	0.3	3.5	3.1
ब्राजील रियाल	1.9	1.4	1.4	1.8	0.9	1.2	3.8	3.2
चीनी युआन	0.6	0.5	0.2	0.5	0.3	0.2	1.0	1.1
चिली पेसो	1.6	1.6	0.9	1.1	1.3	1.1	2.2	2.8
इंडोनेशियाई रुपिया	0.9	0.9	0.9	0.5	0.5	0.6	2.3	2.0
मलेशियाई रिंगित	1.4	2.0	0.6	1.1	0.4	0.3	4.2	1.6
मेक्सिकन पेसो	1.5	1.4	0.9	0.8	0.5	1.1	6.1	1.7
फिलीपीन पेसो	1.2	0.5	0.7	0.4	0.3	0.3	1.8	1.1
रूसी रूबल	0.7	1.9	3.3	4.4	5.0	3.0	2.8	7.4
दक्षिण अफ्रीकी रैंड	0.6	1.6	2.1	1.0	0.6	0.7	2.5	2.4
थाईलैंड बाहत	0.9	1.7	0.6	1.1	0.6	0.4	3.8	1.3
तुर्की लीरा	0.2	0.3	0.6	0.5	0.6	1.8	2.1	2.9
वियतनामी डॉंग	1.1	0.4	0.1	0.6	0.5	0.2	1.2	0.8

नोट: *: भिन्नता के गुणांक द्वारा मापा गया।

स्रोत: आरबीआई

चार्ट IV.21: वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईआईआर) में रुझान



स्रोत: आरबीआई

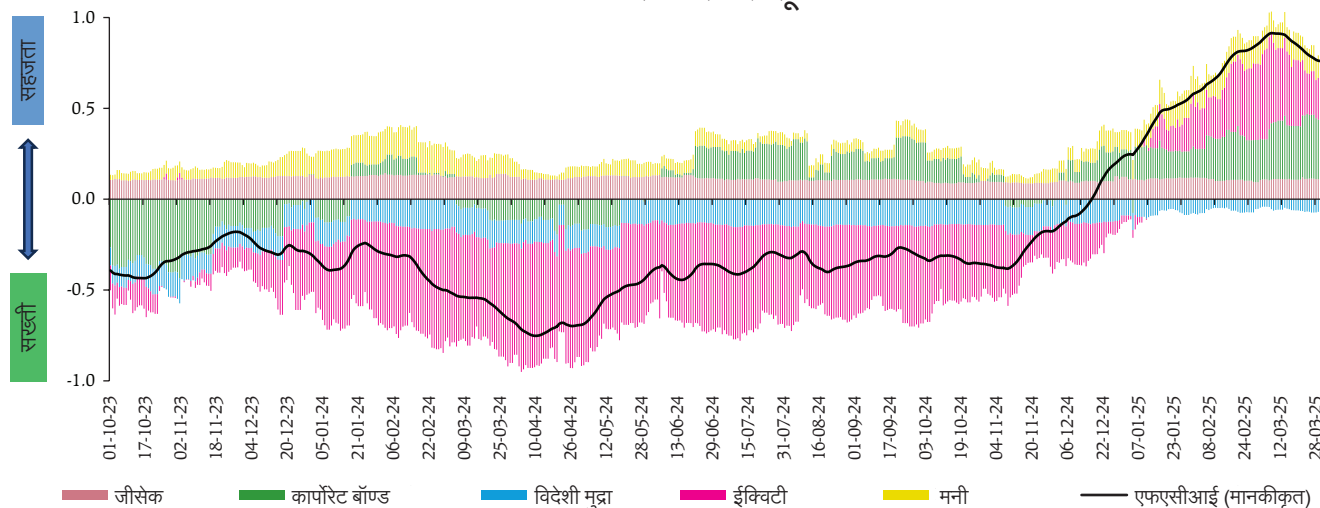
कम अस्थिर मुद्रा था जो उथल-पुथल के समय में उसकी सुदृढ़ता को दर्शाता है।

40- मुद्रा वाली वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईआईआर) के अनुसार भारतीय रुपए ने भी वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान तनाव का अनुभव किया, जिसके कारण उसकी कीमत में सितंबर 2024 (औसत) और 28 मार्च, 2025 के बीच 1.9 प्रतिशत मूल्यहास हुआ। हाल के महीनों में 40-मुद्रा वाली आरईआईआर में हुए मूल्यहास से भी प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के सापेक्ष भारत की मुद्रास्फीति के अंतर में कमी प्रदर्शित होती है

(चार्ट IV.21.ए)। विभिन्न देशों के परिप्रेक्ष्य से, भारतीय रुपए की 40-मुद्रा आरईआईआर में हुआ मूल्यहास कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की आरईआईआर के सापेक्ष कम रहा (चार्ट IV.21.बी)।

1 अप्रैल, 2016 से 24 मार्च, 2025 की अवधि के लिए दैनिक आवृत्ति पर बीस भारतीय वित्तीय बाजार संकेतकों¹¹ के आधार पर निर्मित वित्तीय स्थिति सूचकांक (एफसीआई) तथा गतिशील कारक मॉडल (डीएफएम) दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए, नवंबर 2024 की शुरुआत से बाजार के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक सख्ती का संकेत देता है (चार्ट IV.22)। मुद्रा, इक्विटी और विदेशी

चार्ट : IV.22 : वित्तीय स्थिति सूचकांक



स्रोत: आरबीआई।

¹¹ चुने गए संकेतक पांच बाजार खंडों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात् (i) मुद्रा बाजार; (ii) सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार; (iii) कारपोरेट बॉण्ड बाजार; (iv) विदेशी मुद्रा बाजार; और (v) इक्विटी बाजार।

मुद्रा बाजारों में अपेक्षाकृत अनुकूल स्थितियों के कारण मार्च के दौरान वित्तीय स्थितियों में सुधार हुआ।

IV.2.6 क्रेडिट बाज़ार

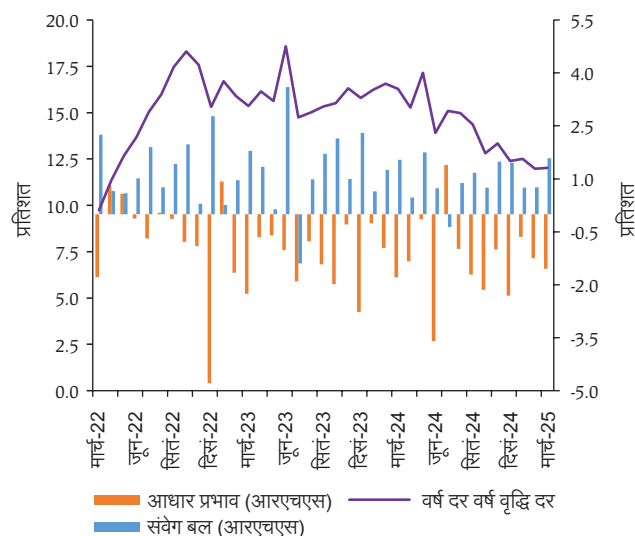
बैंक क्रेडिट ¹²

वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) में नरमी देखी गई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को छोड़कर सभी बैंक समूहों में यह नरमी देखी गई (चार्ट IV.23.ए)। वर्ष 2024-25 में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा दिए गए वृद्धिशील ऋण के प्रमुख चालक बने रहे, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) के हिस्से में गिरावट आई (चार्ट IV.23.बी)।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) का गैर-खाद्य बैंक ऋण 21 मार्च, 2025 को 12.0 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की धीमी गति से बढ़ा, जबकि एक वर्ष पहले यह 16.3 प्रतिशत था (चार्ट IV.24)।

उद्योग के लिए क्षेत्रवार¹³ बैंक ऋण वृद्धि 7.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) पर मजबूत स्थिति में बनी रही, जबकि फरवरी 2025 में कृषि ऋण वृद्धि 11.4 प्रतिशत के दोहरे अंक में बनी रही, लेकिन फरवरी 2024 में 20.0 प्रतिशत के स्तर से यह कमतर हो गई।

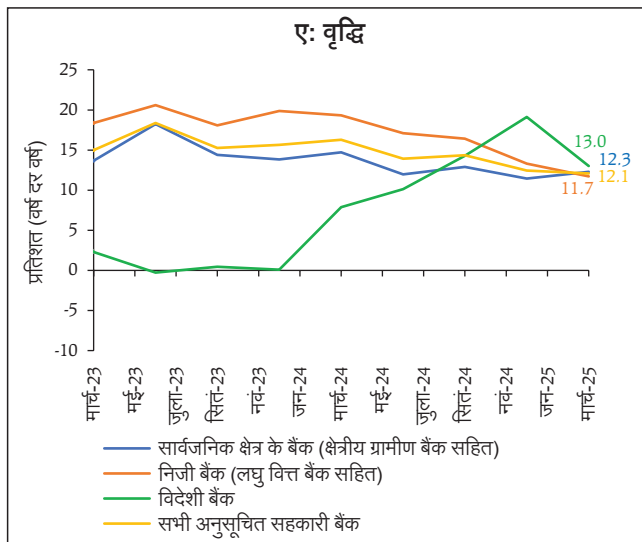
चार्ट IV.24 : अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की खाद्येतर ऋण वृद्धि



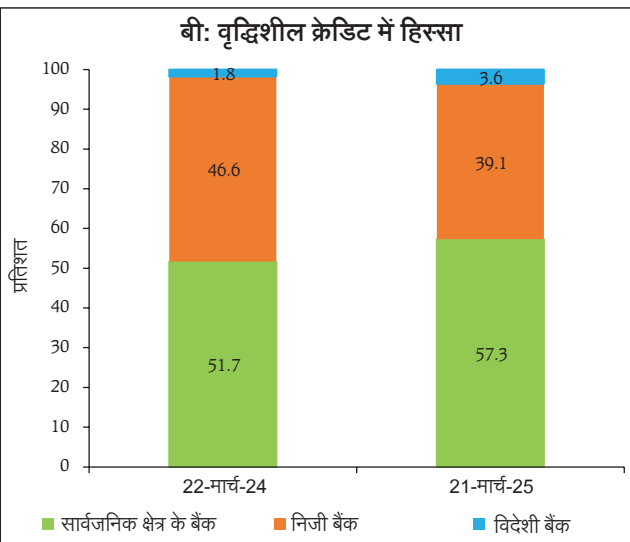
स्रोत : आरबीआई।

कुछ नरमी के बावजूद, सेवा क्षेत्र और वैयक्तिक ऋण खंडों में ऋण की वृद्धि फरवरी 2025 में क्रमशः 13.0 प्रतिशत और 14.0 प्रतिशत रही, जो कि 2024-25 की दूसरी छमाही¹⁴ के दौरान गैर-खाद्य ऋण वृद्धि के प्रमुख चालक बने रहें (चार्ट IV.25)।

चार्ट IV.23 : बैंक समूहों में ऋण प्रवाह



स्रोत: आरबीआई।

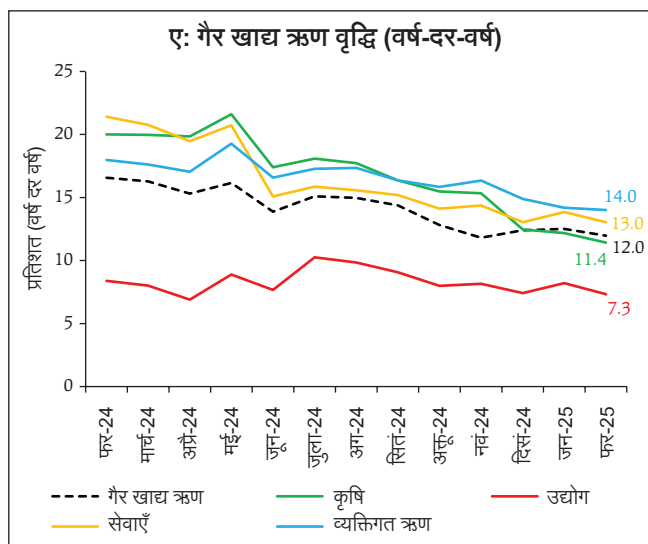


¹² डेटा महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित है। आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया।

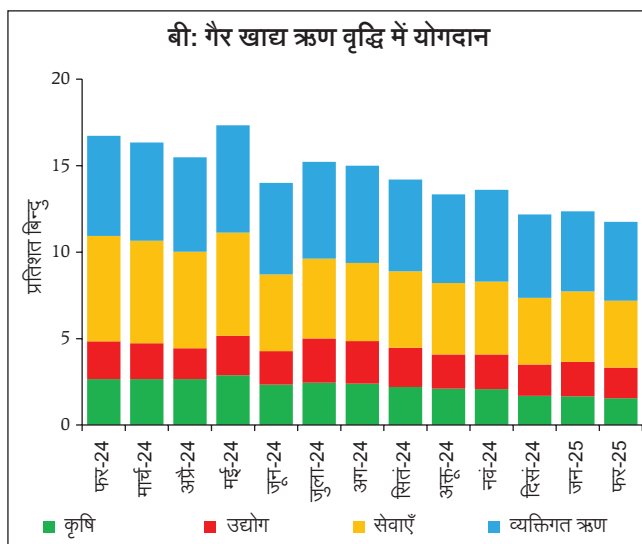
¹³ चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से एकत्र किए गए बैंक ऋणों के क्षेत्रीय नियोजन के आंकड़ों के आधार पर, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा नियोजित कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा है।

¹⁴ 2024-25 के दूसरे अर्ध-वर्ष के फरवरी 2025 तक का डेटा

चार्ट IV.25: बैंक ऋण का क्षेत्रीय परिनियोजन



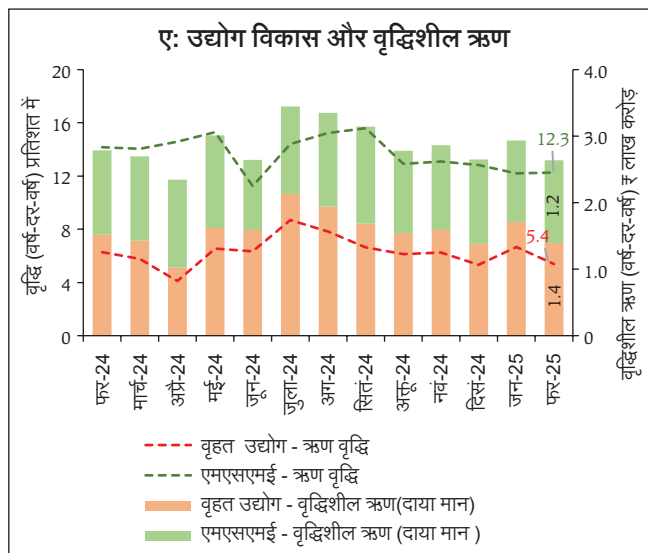
स्रोत : आरबीआई।



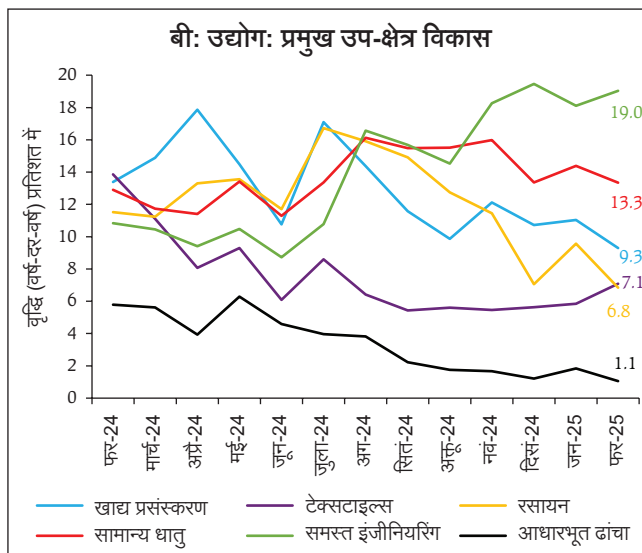
एमएसएमई¹⁵ खंड फरवरी 2025 में 12.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए मजबूत बना रहा। हालांकि, दूसरी छमाही में बड़े उद्योग खंड को ऋण में नरम वृद्धि दर्ज की गई। जहां उद्योग क्षेत्र को वृद्धिशील ऋण (वर्ष-दर-वर्ष) आम तौर पर बड़े उद्योग द्वारा संचालित था, वहीं एमएसएमई क्षेत्र को ऋण की स्थिति मजबूत

बनी रही। उद्योग क्षेत्र के भीतर मूल धातुओं और सभी इंजीनियरिंग क्षेत्र के ऋण में तीव्र वृद्धि देखी गई; तथापि, वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही में बुनियादी ढांचा क्षेत्र को प्रदत्त ऋण में उल्लेखनीय कमी देखी गई। (चार्ट IV.26)।

चार्ट IV.26: उद्योग क्षेत्र: ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष)



स्रोत : आरबीआई।

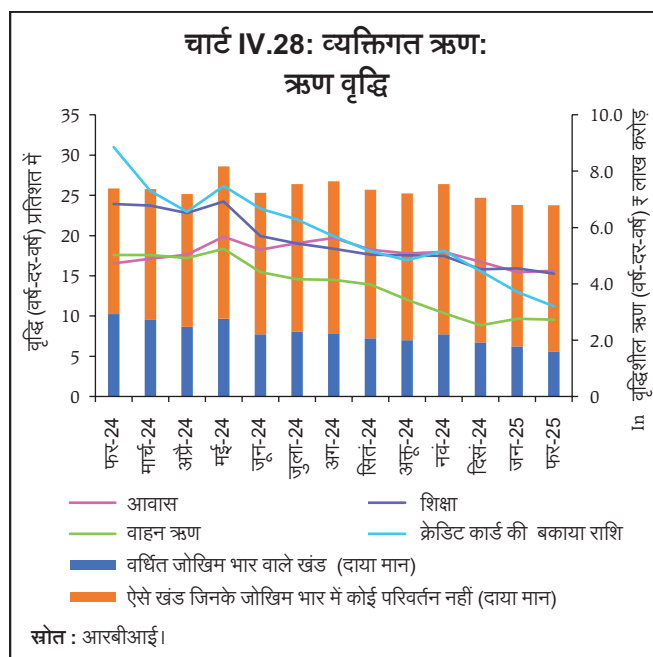


¹⁵ उद्योग के भीतर सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्रों को ऋण। केंद्रीय बजट 2025-26 ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की परिभाषा को संशोधित करने का प्रस्ताव दिया है। एमएसएमई वर्गीकरण के लिए निवेश सीमा 2.5 गुना बढ़ा दी गई है, जबकि टर्नओवर सीमा दोगुनी हो गई। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया है। आगे बढ़ते हुए, एमएसएमई क्षेत्र को वर्गीकरण और प्राथमिकता क्षेत्र ऋण उपचार में बदलाव के कारण ऋण में बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

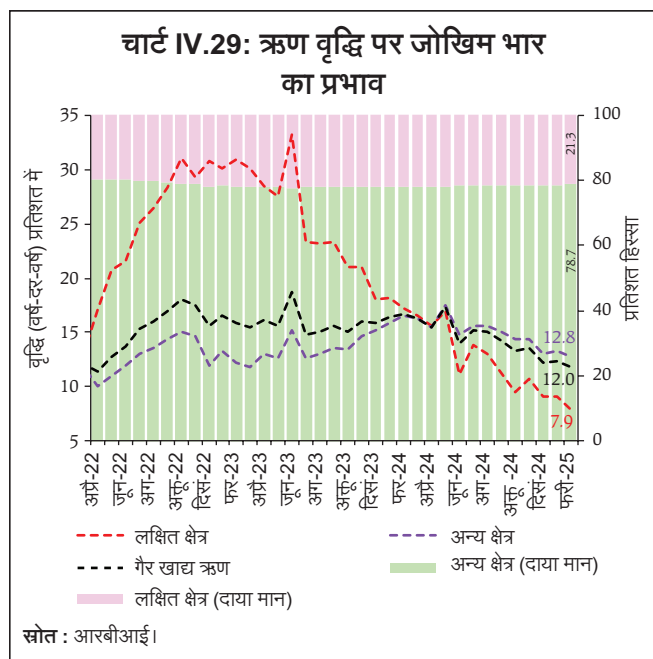
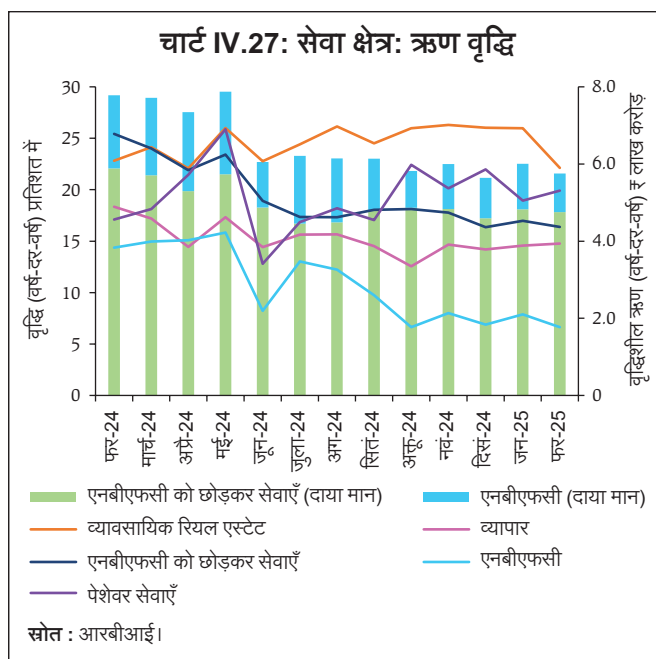
दूसरी छमाही में सेवा क्षेत्र की ऋण वृद्धि में नरमी रही, जिसका मुख्य कारण एनबीएफसी¹⁶ को दिए जाने वाले ऋण में कमी थी। हालांकि, व्यापार, वाणिज्यिक स्थावर संपदा और पेशेवर सेवाएं जैसे अन्य प्रमुख उप-क्षेत्रों में ऋण वृद्धि मोटे तौर पर स्थिर थी। इस प्रकार, एनबीएफसी को छोड़कर सेवा क्षेत्र को दिए जाने वाले वृद्धिशील ऋण (वर्ष-दर-वर्ष) की स्थिति मजबूत बनी रही (चार्ट IV.27)।

अपरिवर्तित जोखिम भार के साथ वैयक्तिक ऋण क्षेत्र में वृद्धिशील ऋण में उत्तरोत्तर सुधार हुआ, जबकि वर्द्धित जोखिम भार वाली ऋण श्रेणियों में यह कम हुआ। आवास ऋण – वैयक्तिक ऋणों का सबसे बड़ा खंड - कुछ नरमी के बावजूद मजबूत गति से बढ़ा, जबकि वाहन ऋणों की वृद्धि धीमी हो गई (चार्ट IV.28)।

मंदी के बावजूद, गैर-खाद्य बैंक ऋण 10-वर्षीय औसत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर (10.5 प्रतिशत) से ऊपर अच्छी गति से बढ़ता रहा। क्षेत्रवार देखा जाए तो उद्योग को ऋण अपने दीर्घकालिक औसत से ऊपर बढ़ता रहा जबकि वैयक्तिक ऋणों में धीमी वृद्धि दर्ज की गई। सेवाओं और कृषि क्षेत्रों में ऋण वृद्धि उनसे संबंधित दीर्घकालिक औसत के आसपास रही। जहाँ अपरिवर्तित जोखिम भार वाले खंडों के लिए ऋण वृद्धि मोटे तौर पर स्थिर बनी रही,



वहीं लक्षित क्षेत्रों, अर्थात 'गैर-जमानती वैयक्तिक ऋण' और 'एनबीएफसी को बैंक ऋण' की वृद्धि दर नवंबर 2023 में किए गए विनियामक उपायों के परिणामस्वरूप धीरे-धीरे नरम पड़ गई। (चार्ट IV.29 और सारणी IV.9)।



¹⁶ एनबीएफसी के प्रति एससीबी के एक्सपोजर पर जोखिम भार को 01 अप्रैल 2025 से उनके पूर्व-नवंबर 2023 स्तर पर बहाल कर दिया गया है, और यह बाहरी रेटिंग के अनुसार होगा। इस के अलावा, उपभोक्ता ऋण की प्रकृति में सूक्ष्म वित्त ऋणों को उच्च जोखिम भार की प्रयोज्यता से बाहर रखा जाएगा और 100 प्रतिशत के जोखिम भार के अधीन होगा। यह उम्मीद की जाती है कि एनबीएफसी के साथ-साथ सेवा क्षेत्र के प्रति 'बैंकों के ऋण' में ऋण वृद्धि में आगे सुधार हो सकता है।

सारणी IV.9: विवेकपूर्ण उपाय और क्षेत्रीय ऋण वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

क्षेत्र/उप-क्षेत्र [#]	दीर्घ अवधि*	कोविड के पश्चात **	नव-23	मार्च -24	जून-24	सित-24	दिसं-24	फर-25
विलय के बिना बैंक ऋण [§]	10.5	14.7	16.3	16.3	13.9	14.4	12.4	12.1 ^
विलय के साथ बैंक ऋण [§]	10.8	15.9	20.7	20.2	17.4	13.0	11.2	11.0 ^
कृषि (13.6)	11.8	15.9	18.1	20.0	17.4	16.4	12.5	11.4
उद्योग (23.2)	4.1	8.0	5.5	8.0	7.7	9.1	7.4	7.3
सेवाएँ (30.0)	13.4	18.7	22.2	20.8	15.1	15.2	13.0	13.0
एनबीएफसी को छोड़कर सेवाएँ (20.3)	11.8	18.4	24.3	24.0	18.9	18.1	16.4	16.4
एनबीएफसी (9.7)	19.0	19.6	18.5	15.0	8.2	9.7	6.9	6.6
व्यक्तिगत ऋण (33.2)	17.2	18.0	18.7	17.6	16.6	16.4	14.9	14.0
जोखिम भार में कोई बदलाव नहीं किए जाने वाले व्यक्तिगत ऋण खंड (21.6)	16.2	16.3	16.2	17.4	18.2	18.5	17.0	16.9
जोखिम भार में वृद्धि वाले व्यक्तिगत ऋण खंड (11.6)	19.5	21.5	23.3	18.1	13.7	12.6	11.1	9.0

#: अन्तिम डेटा, बैंक ऋण डेटा धारा-42 रिटर्न पर आधारित है।

*: साल-दर-साल वृद्धि का 10-वर्षीय औसत।

**: अप्रैल 2022 से साल-दर-साल वृद्धि का औसत।

\$: जुलाई 2023 में, एक गैर-बैंक का एक बैंक में विलय कर दिया गया।

^: 21 मार्च, 2025 को समाप्त पखवाड़े के डेटा से संबंधित है।

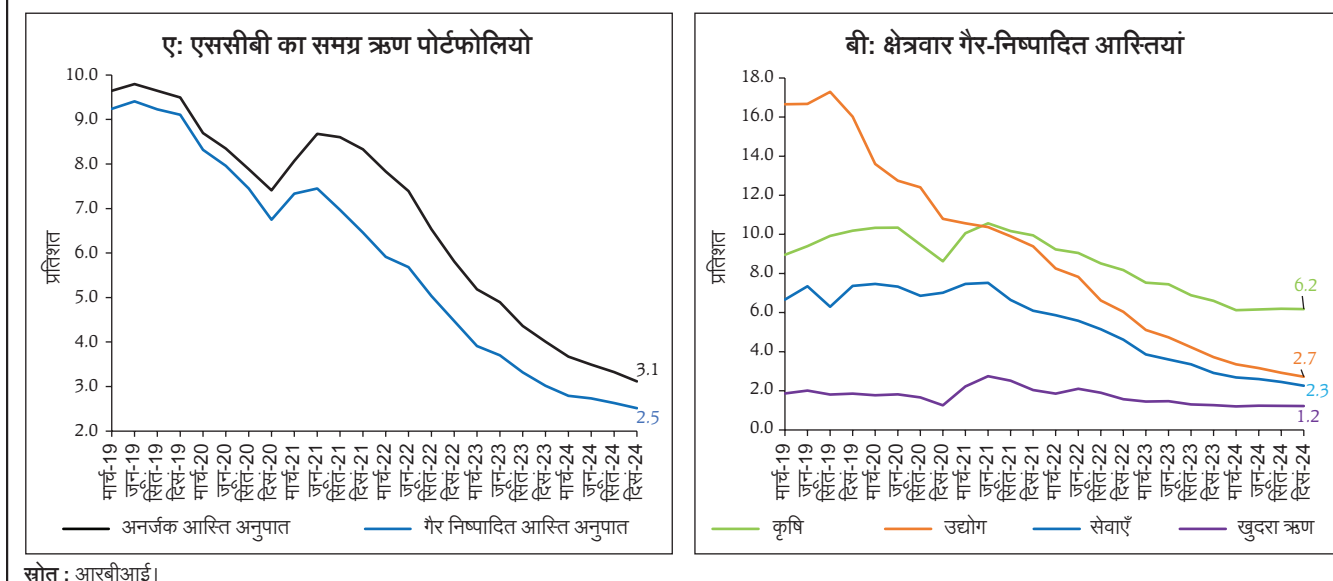
नोट: प्रत्येक क्षेत्र के सामने कोष्ठक में दिए गए आंकड़े 21 फरवरी, 2025 को समाप्त पखवाड़े के आंकड़ों के अनुसार कुल गैर-खाद्य ऋण में हिस्सेदारी दर्शाते हैं।

स्रोत: आरबीआई।

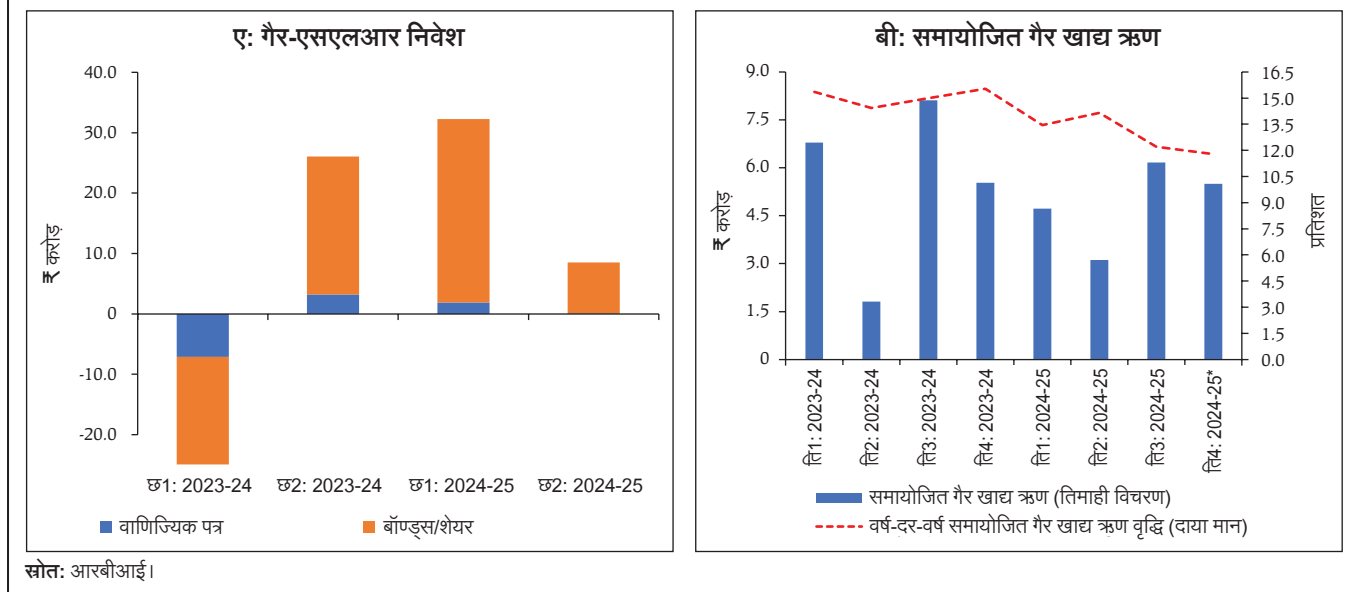
2024-25 (दिसंबर 2024 तक) के दौरान एससीबी की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ, कुल सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) अनुपात दिसंबर 2024 में 2.5 प्रतिशत तक गिर गया, जो एक साल पहले 3.0 प्रतिशत था (चार्ट IV.30.ए)। सभी प्रमुख क्षेत्रों में परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ (चार्ट IV.30.बी)।

बैंकों के गैर-एसएलआर¹⁷ निवेश (जिसमें सीपी, बॉण्ड, डिबेंचर और सार्वजनिक और निजी कॉरपोरेट्स के शेयरों में निवेश शामिल है) में 2024-25 के दूसरी छमाही में 1.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो 2024-25 की पहली छमाही में देखी गई 4.8 प्रतिशत की वृद्धि से कम है (चार्ट IV.31.ए)। समायोजित गैर-खाद्य ऋण (अर्थात्, बैंकों द्वारा गैर-खाद्य बैंक ऋण और गैर-एसएलआर निवेश) में

चार्ट IV.30: एससीबी की तनावग्रस्त आस्तियां और अनर्जक आस्तियां



17. सांविधिक चलनिधि अनुपात

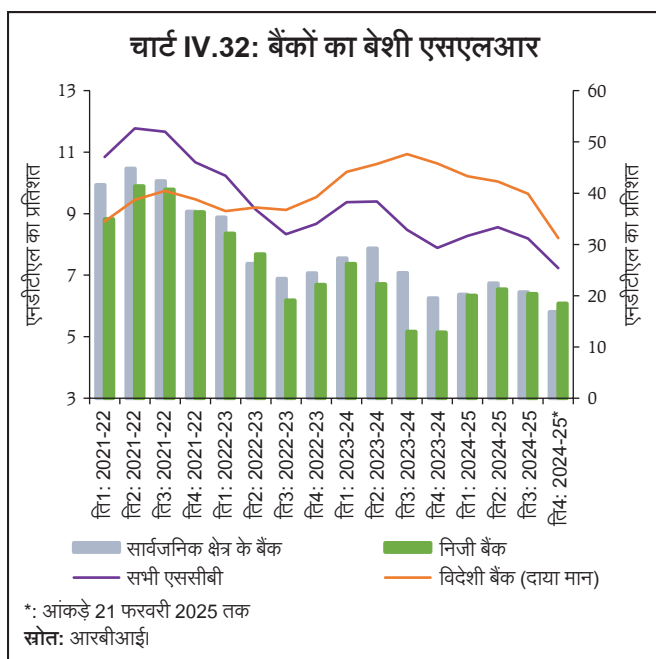
चार्ट IV.31: गैर-एसएलआर निवेश और समायोजित गैर-खाद्य ऋण


2023-24 की चौथी तिमाही में वृद्धि 15.5 प्रतिशत से घटकर 2024-25 की चौथी तिमाही में 11.8 प्रतिशत हो गई (चार्ट IV.31.बी)।

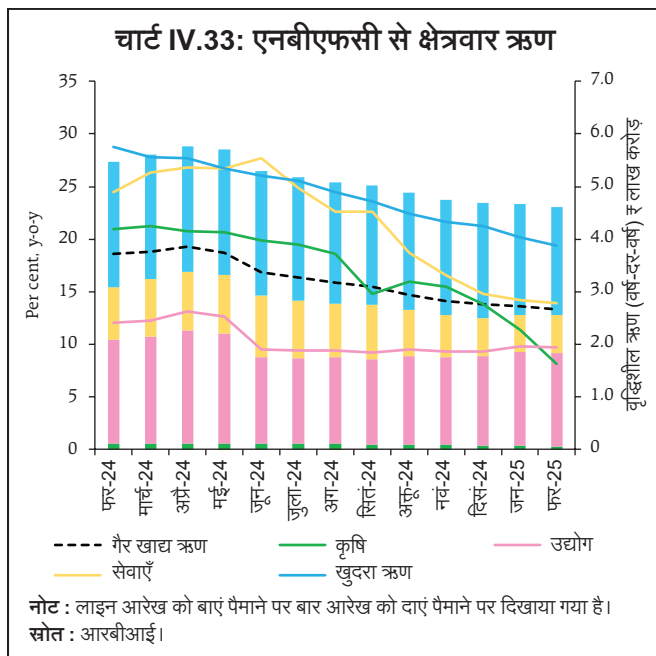
21 फरवरी, 2025 तक, एससीबी द्वारा सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) प्रतिभूतियों की अतिरिक्त होल्डिंग मार्च 2024 के अंत में 8.5 प्रतिशत से घटकर उनकी निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 7.3 प्रतिशत पर आ गई (चार्ट IV.32)। अतिरिक्त एसएलआर होल्डिंग्स चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) का एक घटक है। वे एलएएफ के तहत निधि प्राप्त करने के साथ-साथ टीआरआईपीएस और मार्केट रेपो खंड में थोक फंडिंग के लिए बैंकों को संपार्श्विक बफर भी प्रदान करते हैं।

एनबीएफसी ऋण¹⁸

एनबीएफसी द्वारा दिए गए ऋण की वृद्धि (वर्ष-दर-वर्ष) फरवरी 2024 में 18.6 प्रतिशत से फरवरी 2025 में घटकर 13.3 प्रतिशत हो गई, जो जोखिम भार में वृद्धि के प्रभाव को दर्शाती है, जो अब 01 अप्रैल, 2025 से प्रत्यावर्तित हो गया है। वृद्धिशील ऋण में सबसे बड़ा हिस्सा खुदरा ऋणों का रहा और उसके बाद उद्योग, सेवा एवं कृषि ऋण का था (चार्ट IV.33)।



18 चुनिंदा एनबीएफसी से बकाया ऋण के क्षेत्रीय विनियोजन के आंकड़े प्रत्येक माह के अंतिम दिन से संबंधित हैं। प्रायोगिक कार्य के रूप में, चुनिंदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से मासिक क्षेत्रीय ऋण सूचना एकत्र करने का कार्य शुरू किया गया है। ये एनबीएफसी ऊपरी और मध्यम स्तरों में सभी एनबीएफसी द्वारा दिए गए कुल ऋण का लगभग 88 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।

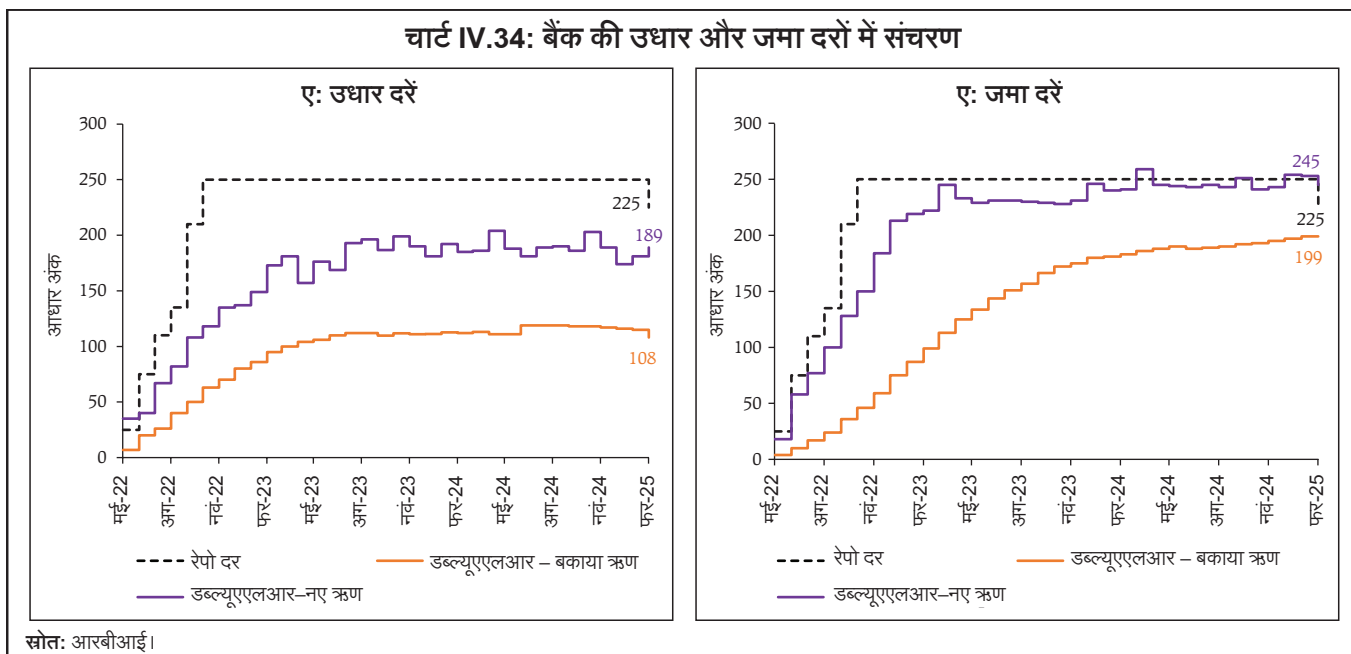


IV.3: मौद्रिक नीति संचरण

प्रसार को कम करके बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए बैंकों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान नीचे की ओर समायोजित करने से पहले उधार दरों में संचरण अपने चरम पर पहुंच गया (चार्ट IV.34.ए)। दूसरी ओर, सख्त चलनिधि की स्थिति और उच्च ऋण मांग (चार्ट IV.34.बी) के मद्देनजर जमा दरें बढ़ रही हैं।

हाल ही में सख्त चक्र, यानी मई 2022 से जनवरी 2025 के दौरान संचयी 250-बीपीएस दर वृद्धि के जवाब में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की 1-वर्षीय औसत सीमांत लागत आधारित उधार दर (एमसीएलआर) में 178 बीपीएस की वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, इस अवधि के दौरान नए और बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दरों (डब्ल्यूएलआर) में क्रमशः 181 बीपीएस और 115 बीपीएस की वृद्धि हुई। जमा पक्ष पर, उसी अवधि के दौरान नई और बकाया जमाओं पर भारित औसत घरेलू सावधि जमा दरों (डब्ल्यूएडीटीडीआर) में क्रमशः 253 बीपीएस और 199 बीपीएस की वृद्धि हुई। फरवरी 2025 में पॉलिसी रेपो रेट में 25 बीपीएस की कमी के बाद बैंकों ने अपनी रेपो लिंकड उधार दरों में इसी तरह की कटौती की है। इसके विपरीत, एमसीएलआर, जिसकी एक लंबी रीसेट अवधि है और फंड की लागत से जुड़ा हुआ है, कुछ विलंब के साथ समायोजन से गुजर सकता है। परिणामस्वरूप, बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दरों में 7 बीपीएस की गिरावट आई। हालांकि, नए ऋणों के मामले में, फरवरी 2025 के दौरान इसमें 8 बीपीएस की वृद्धि हुई है, जो इसमें एमसीएलआर के महत्वपूर्ण हिस्से को दर्शाती है (सारणी IV.10)।

एससीबी के कुल बकाया फ्लोटिंग दर ऋण में बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दर (ईबीएलआर) से जुड़े ऋण की हिस्सेदारी



सारणी IV.10: बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार अंक)

अवधि	रेपो दर	मियादी जमा दरें			उधार दरें			
		डब्ल्यूएडीटीडीआर – नया जमा		डब्ल्यूएडीटीडीआर – बकाया जमा	ईबीएलआर	1 वर्ष एमसीएलआर (माध्यिका)	डब्ल्यूएएलआर – नए रुपया ऋण	डब्ल्यूएएलआर – बकाया रुपया ऋण
		खुदरा जमा	खुदरा और थोक जमा	खुदरा और थोक जमा				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ढील का चरण फरवरी 2019 से मार्च 2022	-250	-209	-259	-188	-250	-155	-232	-150
सख्ती की अवधि मई 2022 से जनवरी 2025	+250	182	253	199	250	178	181	115
ढील का चरण फरवरी 2019 से मार्च* 2022	-25	-3	-8	0	-25	0	8	-7
मेमो:								
जन- 2025	0	4	-1	2	0	0	7	-1
फर- 2025	-25	-3	-8	0	-25	0	8	-7

नोट: 1. ईबीएलआर पर डेटा 32 घरेलू बैंकों से संबंधित है।

2. डब्ल्यूएएलआर और डब्ल्यूएडीटीडीआर से संबंधित डेटा फरवरी 2025 से संबंधित है।

डब्ल्यूएएलआर : भारत औसत उधार दर; डब्ल्यूएडीटीडीआर: भारत औसत घरेलू सावधि जमा दर;

एमसीएलआर: निधि की सीमांत लागत-आधारित उधार दर; ईबीएलआर: बाहरी बेंचमार्क-आधारित उधार दर।

स्रोत: एमपीडी 06 रिटर्न और आरबीआई।

दिसंबर 2024 के अंत में 60.6 प्रतिशत हो गई, जो मार्च 2024 के अंत में 56.6 प्रतिशत थी। नतीजतन, एमसीएलआर से जुड़े ऋण की हिस्सेदारी घटकर 35.9 प्रतिशत रह गई (सारणी IV.11)। उधार दरों में तेजी से समायोजन के साथ, ईबीएलआर प्रणाली ने मौद्रिक नीति संचरण की गति को तेज कर दिया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के मामले में एमसीएलआर से जुड़े ऋणों का एक महत्वपूर्ण अनुपात अभी भी है (चार्ट IV.35.ए)। ईबीएलआर-लिंकड ऋणों का हिस्सा निजी बैंकों

(पीवीबी) के बीच अधिक है (चार्ट IV.35.बी)। एमसीएलआर और अन्य परंपरागत दरों से जुड़े ऋणों की दृढ़ता - आंतरिक बेंचमार्क के आधार पर और लंबी रीसेट अवधि होने के कारण - समग्र मौद्रिक नीति संचरण के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करती है।

बैंक समूह-वार, पीएसबी के नए रुपया ऋणों पर डब्ल्यूएएलआर को पीवीबी की तुलना में अधिक था (चार्ट IV.36.ए)। इसके अलावा, यह बकाया ऋणों के लिए कम था, जिसे बकाया ऋणों के महत्वपूर्ण अनुपात के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो अभी भी आंतरिक बेंचमार्क-आधारित उधार दर से जुड़ा हुआ है। पीवीबी की उधार दरें पीएसबी (चार्ट IV.36.बी) से ऊपर रहीं। उधार दरों का अधिकतम पास-श्रु विदेशी बैंकों के मामले में देखा गया, जो कम लागत और कम परिपक्वता की थोक जमा राशियों में उनकी उच्च हिस्सेदारी को दर्शाता है। इसके अलावा, विदेशी बैंकों में ईबीएलआर-लिंकड ऋणों की उच्च हिस्सेदारी ने मौद्रिक नीति संचरण को और बढ़ाया है। इसके अलावा, विदेशी बैंकों में ईबीएलआर-लिंकड ऋणों की उच्च हिस्सेदारी ने मौद्रिक नीति संचरण को और बढ़ाया है¹⁹।

सारणी IV.11: ब्याज दर बेंचमार्क में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया अस्थिर दर रुपया ऋण

(Per cent)

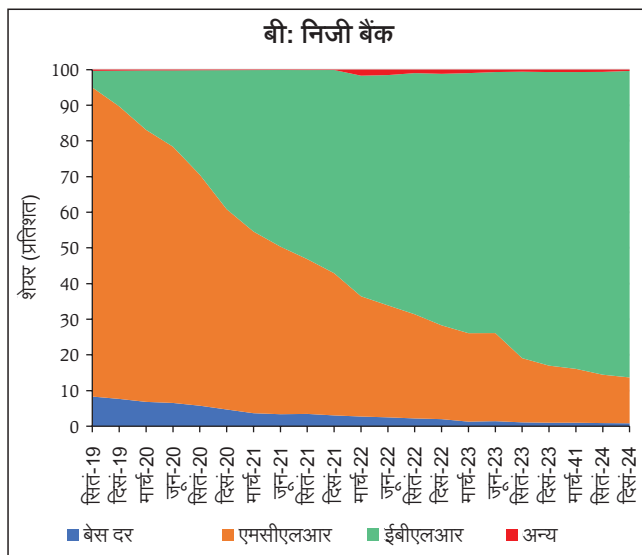
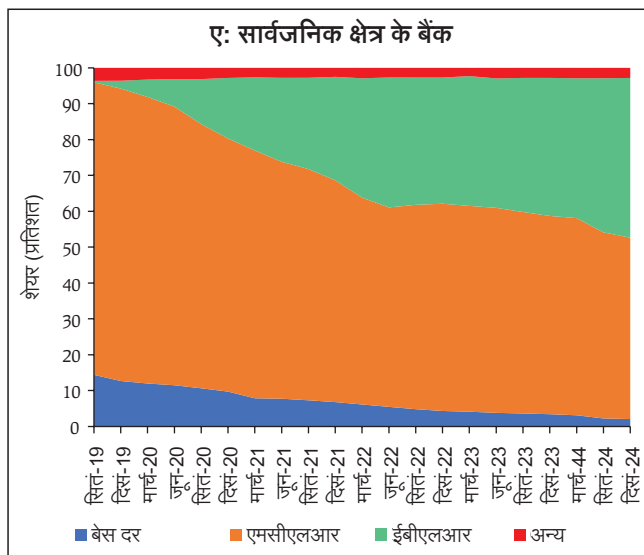
क्षेत्र	मार्च 2020	मार्च 2022	मार्च 2024	दिसंबर 2024
एमसीएलआर	78.3	48.7	39.2	35.9
ईबीएलआर	9.1	44.0	56.6	60.6
अन्य	12.6	7.3	4.2	3.5

नोट: 1. 'अन्य' में बेंचमार्क मूल उधार दर, आधार दर और अन्य आंतरिक बेंचमार्क शामिल हैं।

2. 73 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित आंकड़े।

स्रोत : आरबीआई

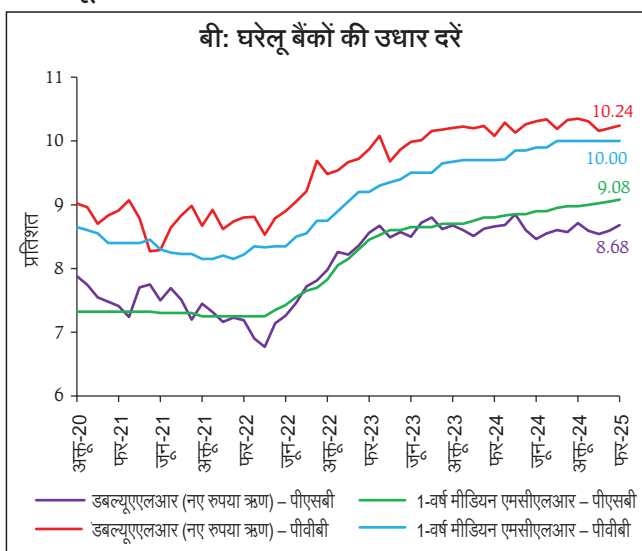
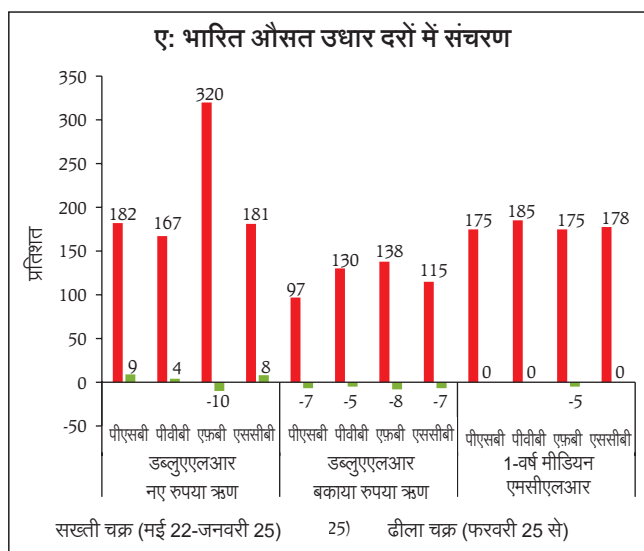
19 दिसंबर 2024 के अंत तक ईबीएलआर-लिंकड ऋणों का अनुपात विदेशी बैंकों (92.2 प्रतिशत) के लिए सबसे अधिक था, इसके बाद निजी बैंक (85.9 प्रतिशत) और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (44.6 प्रतिशत) थे।

चार्ट IV.35: ब्याज दर बेंचमार्क में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के बकाया फ्लोटिंग दर रुपया ऋण


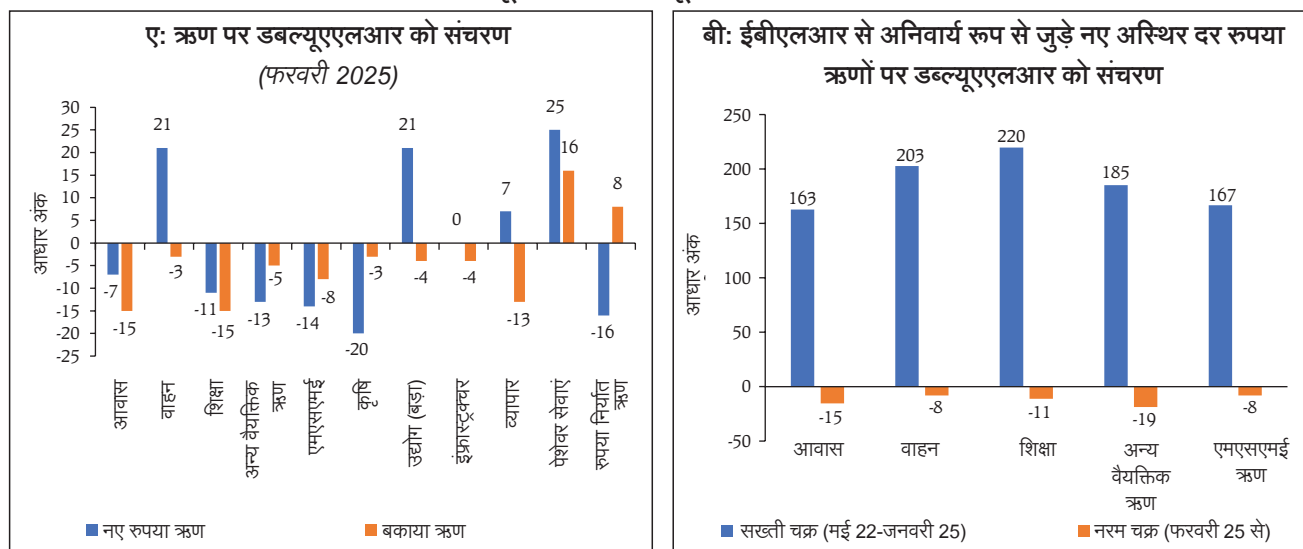
फरवरी 2025 के दौरान, नए और बकाया ऋणों पर डबल्यूएलआर को संचरण सभी क्षेत्रों में व्यापक आधार पर किया गया है। विभिन्न क्षेत्रों में संचरण की अंतर गति इस क्षेत्र में स्थिर और अस्थिर ब्याज दरों से जुड़े क्रेडिट पोर्टफोलियो के अनुपात और बैंकों द्वारा प्रभारित विभिन्न स्प्रेड के कारण है (चार्ट IV.37.ए)। फ्लोटिंग दर ऋण के मामले में, जो अनिवार्य रूप से ईबीएलआर से जुड़े हैं, घरेलू बैंकों के नए ऋण पर

डबल्यूएलआर फरवरी 2025 में 8-19 बीपीएस के स्तर में गिर गया। हालांकि, सख्ती बरतने के दौरान, इसमें शिक्षा ऋणों के लिए 220 बीपीएस, वाहन ऋण के लिए 203 बीपीएस, एमएसएमई ऋणों के लिए 167 बीपीएस और आवास ऋणों के लिए 163 बीपीएस की वृद्धि हुई थी (चार्ट IV.37.बी)।

बैंकों ने अपने स्प्रेड (ताजा फ्लोटिंग दर रुपया ऋणों पर डबल्यूएलआर का अंतर और उनकी बेंचमार्क दर) को कम कर

चार्ट IV.36: ऋण दरों में बैंक समूह-वार संचरण


चार्ट IV.37: घरेलू बैंकों के डबल्यूएलआर में क्षेत्र-वार संचरण



स्रोत: आरबीआई।

दिया है, जिससे संचरण की सीमा कम हो गई है (सारणी IV.12)। पॉलिसी रेपो दर से जुड़े ऋणों के लिए, नए रुपया ऋण (रेपो दर पर डबल्यूएलआर) पर संचरण शिक्षा ऋण के लिए सबसे अधिक था, इसके बाद अन्य व्यक्तिगत ऋण और एमएसएमई ऋण थे। घरेलू बैंक समूहों में, पीएसबी ने आवास, वाहन, शिक्षा और अन्य व्यक्तिगत ऋणों के लिए पीवीबी की तुलना में कम संचरण का शुल्क लिया। इसके विपरीत, पीएसबी ने पीवीबी की तुलना में एमएसएमई ऋणों के लिए अधिक स्प्रेड लिया।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) अब तक बैंक रहित क्षेत्रों में अंतिम चरण तक ऋण प्रदान करके और स्थावर संपदा और बुनियादी ढांचे से लेकर कृषि और सूक्ष्म ऋणों तक विभिन्न क्षेत्रों को विशिष्ट वित्तपोषण प्रदान करते हुए अर्थव्यवस्था

की ऋण जरूरतों को पूरा करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। एनबीएफसी अधिक उधारकर्ताओं को औपचारिक वित्तीय संस्थागत नेटवर्क में लाते हैं जो मौद्रिक संचरण के क्रेडिट चैनल की पहुंच को बढ़ाता है। इसलिए, बैंकों और एनबीएफसी दोनों की उधार दरों के लिए नीतिगत संकेत प्रदान करने और गति के संदर्भ में नीति संचरण का निरंतर मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। प्रमुख एनबीएफसी की उधार दरों के मासिक आंकड़ों से पता चलता है कि एनबीएफसी द्वारा प्रभारित ब्याज दरें अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में अधिक होती हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ उनकी देयता संरचना और उनके उधारकर्ताओं के जोखिम प्रोफाइल को दर्शाती हैं। इस प्रकार, मौद्रिक नीति संचरण की डिग्री एनबीएफसी और एससीबी (चार्ट IV.38) के बीच भिन्न है।

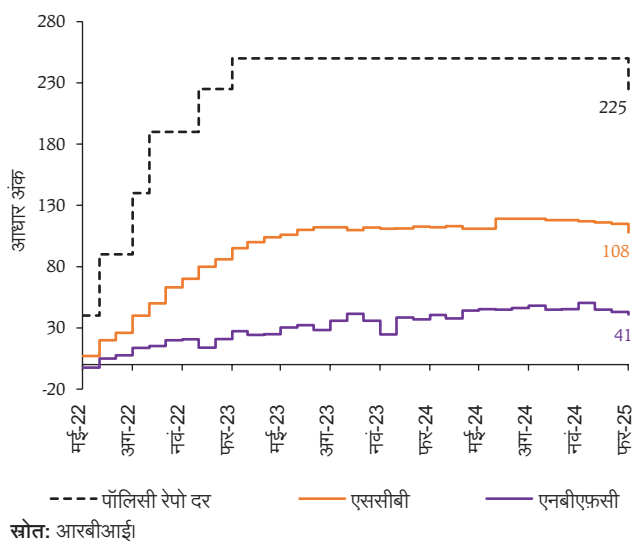
सारणी IV.12: बाहरी बेंचमार्क से जुड़े ऋणों के लिए रेपो दर पर डबल्यूएलआर (नए ऋण) का विस्तार

(Percentage points)

क्षेत्र	अप्रैल-22			फरवरी-25		
	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	घरेलू बैंक	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	घरेलू बैंक
एमएसएमई ऋण	4.27	3.93	4.04	3.38	3.37	3.37
वैयक्तिक ऋण						
आवास	2.91	3.32	3.21	2.15	2.59	2.43
वाहन	3.37	4.39	3.55	2.68	4.53	3.24
शिक्षा	4.42	5.71	4.71	3.79	5.19	4.55
अन्य वैयक्तिक ऋण	3.54	7.35	4.01	3.05	5.73	3.42

टिप्पणी: अन्य वैयक्तिक ऋणों में आवास, वाहन, शिक्षा और क्रेडिट कार्ड ऋण के अलावा अन्य ऋण शामिल हैं।

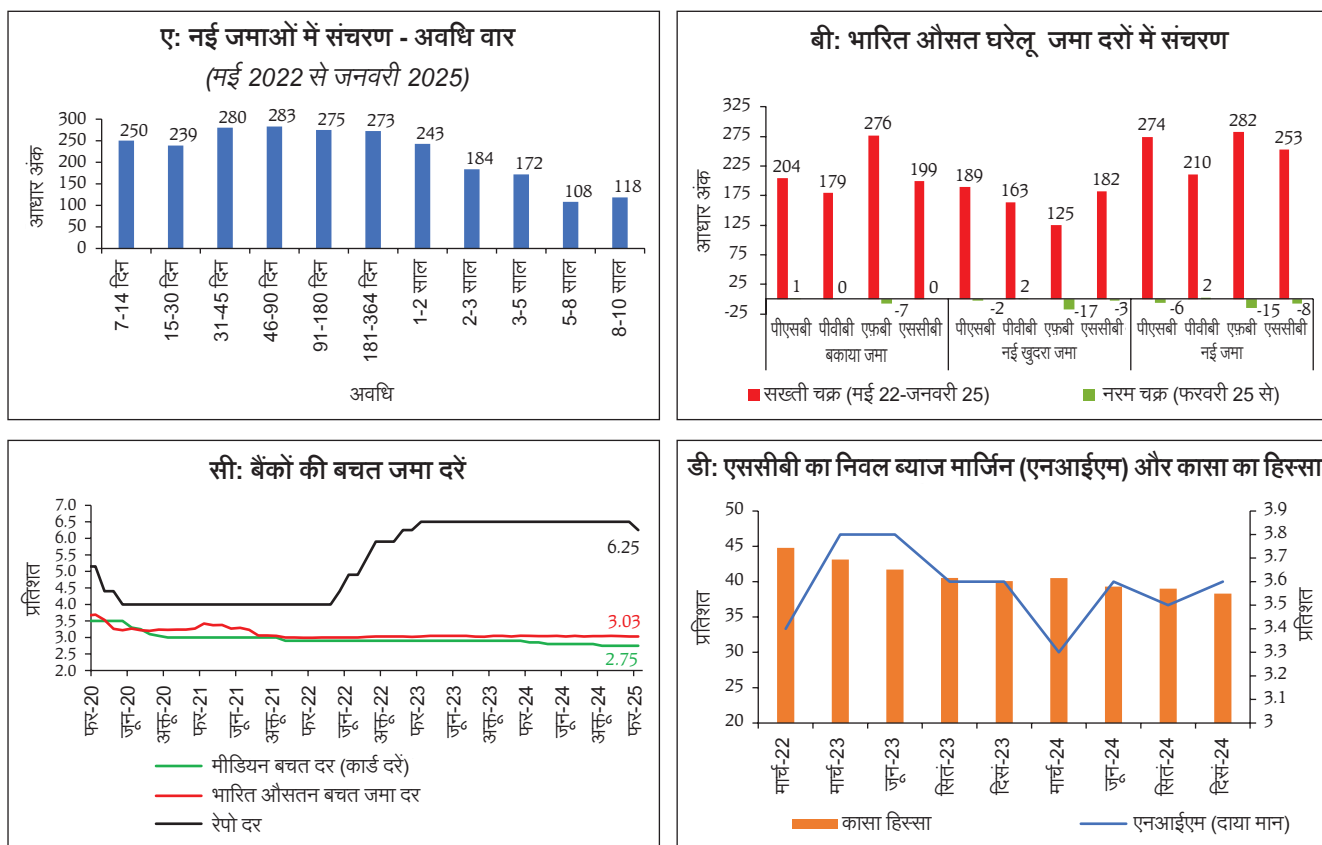
स्रोत: आरबीआई और आरबीआई स्टाफ अनुमान

चार्ट IV.38: एनबीएफसी की बकाया उधार दरों के लिए मौद्रिक नीति संचरण

प्रणालीगत चलनिधि विकास और ऋण वृद्धि की अपेक्षाकृत तेज गति ने बैंकों को अपनी मीयादी जमा दरों में वृद्धि करने के

लिए प्रेरित किया, विशेष रूप से छोटी अवधि की जमा राशियों में (चार्ट IV.39.ए)। बैंक समूहों में, नई और बकाया जमा दरों पर डब्ल्यूएडीटीडीआर का पास-थ्रू पीवीबी की तुलना में पीएसबी के लिए अधिक था (चार्ट IV.39.बी)। हालांकि, बचत बैंक जमा राशियों पर दरें, जो कुल जमा राशियों का लगभग 30 प्रतिशत हैं, अधिकांशतः जड़वत बनी हुई हैं और विकसित हो रही समष्टि-वित्तीय स्थितियों के अनुरूप नहीं रहीं (चार्ट IV.39.सी)। तदनुसार, जमा दरों का समग्र संचरण कम रहा क्योंकि बचत जमा दरें नीतिगत दर परिवर्तनों के प्रति अनुत्तरदायी रहीं। इसके अलावा, कुल जमा राशियों में चालू खाता और बचत खाता (सीएसए) जमा राशियों की हिस्सेदारी में गिरावट के साथ-साथ ऋण दरों की तुलना में सावधि जमा दरों में उच्चतर संचरण ने बैंकों के निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पर गिरावट का दबाव डाला है (चार्ट IV.39.डी)।

भारत सरकार ने विभिन्न लघु बचत साधनों पर ब्याज दरों की समीक्षा की, जो तुलनीय परिपक्वता के जी-सेक पर द्वितीयक बाजार प्रतिफल से जुड़ी हैं और इसे 2025-26 की पहली तिमाही

चार्ट IV.39: जमा दरें और बैंक की लाभप्रदता

स्रोत: आरबीआई

सारणी IV.13: लघु बचत लिखतों पर ब्याज दरें – तिमाही 1:2025-26

लघु बचत योजना	परिपक्वता (वर्ष)	बचत (प्रतिशत अंक) \$	समवर्ती परिपक्वता की औसत जी-सेक लाभ (%) (दिसंबर 2024- फरवरी 2025)	फॉर्मूला आधारित ब्याज दर (%) (ति 1: 2025-26 के लिए लागू)	ति1:2025-26 में सरकार द्वारा घोषित ब्याज दर	अंतर (प्रतिशत अंक)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7) = (6) - (5)
बचत जमा	-				4.00	-
पब्लिक प्रोविडेंट फंड	15	0.25	6.85	7.10	7.10	0.00
मीयादी जमा						
1 साल	1	0	6.45	6.45	6.90	0.45
2 साल	2	0	6.50	6.50	7.00	0.50
3 साल	3	0	6.54	6.54	7.10	0.56
5 साल	5	0.25	6.62	6.87	7.50	0.63
आवर्ती जमा खाता	5	0	6.54	6.54	6.70	0.16
मासिक आय योजना	5	0.25	6.59	6.84	7.40	0.56
किसान विकास पत्र	115 महीने	0	6.85	6.85	7.50	0.65
एनएससी VIII इश्यू	5	0.25	6.79	7.04	7.70	0.66
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना	5	1.00	6.62	7.62	8.20	0.58
सुकन्या समृद्धि खाता योजना	21	0.75	6.85	7.60	8.20	0.60

\$: फरवरी 2016 की भारत सरकार की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार लघु बचत दरों को तय करने के लिए स्प्रेड।

नोट: कंपाउंडिंग आवृत्ति उपकरणों में भिन्न होती है।

स्रोत: भारत सरकार; एफबीआईएल; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

के लिए अपरिवर्तित रखा। इन समायोजनों के साथ, अधिकांश लिखतों पर दरें अब 16-66 बीपीएस की सीमा में फॉर्मूला-आधारित दरों से ऊपर हैं (सारणी IV.13)।

IV.4 निष्कर्ष

घरेलू वित्तीय बाजारों ने 2024-25 की दूसरी छमाही में अस्थिर वैश्विक वित्तीय बाजार स्थितियों को व्यापक रूप से प्रतिबिंबित किया। अक्टूबर और नवंबर में अधिशेष में रहने के बाद, दिसंबर की दूसरी छमाही के दौरान प्रणालीगत चलनिधि, घरेलू और वैश्विक दोनों तरह के कई कारकों के कारण घाटे में बदल गई। रिजर्व बैंक ने व्यवस्थित बाजार स्थितियों को सुनिश्चित करने और मौद्रिक नीति संचरण को बढ़ाने के लिए चलनिधि बढ़ाने वाले कई उपाय किए। मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण में सुधार और भारत की आर्थिक संभावनाओं पर सकारात्मक वैश्विक भावना के बीच घरेलू दीर्घकालिक बॉण्ड प्रतिफल में कमी आई। विदेशी

पोर्टफोलियो निवेश के बहिर्वाह के कारण इक्विटी बाजार में तेज गिरावट देखी गई। भारतीय रुपये ने फरवरी तक गिरावट के साथ कारोबार किया, मार्च में कुछ नुकसान की भरपाई की और दूसरी छमाही के दौरान सबसे कम अस्थिर ईएमई करेंसियों में भारतीय रुपए की स्थिति में गिरावट की तरफ झुकाव बना रहा। बैंकों द्वारा नीति दर में कटौती का प्रतयुत्तर देने और अपने स्प्रेड को कम करके बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए प्रतिस्पर्धा के कारण उधार दरों में संचरण अपने चरम पर पहुंचने के बाद नीचे की ओर समायोजित हुआ। दूसरी ओर, सख्त चलनिधि स्थितियों और उच्च ऋण मांग के मद्देनजर जमा दरों में वृद्धि हुई। आगे भी, रिजर्व बैंक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बाजार परिचालनों के संचालन में चुस्त और तत्पर रहेगा तथा साथ ही अर्थव्यवस्था की उत्पादक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध कराएगा।

V. बाह्य परिवेश

व्यापार प्रतिबंधात्मक आर्थिक नीतियों के कार्यान्वयन और विकसित भू-राजनीति से उत्पन्न निकट अवधि के जोखिमों के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे जा रही है। सेवा क्षेत्र में बने रहने के कारण कई अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर है। केंद्रीय बैंकों ने सावधानीपूर्वक मौद्रिक नीति को सुलभ बनाया है, किन्तु कार्रवाई भिन्न-भिन्न बनी हुई है। वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं, जो वृद्धि-मुद्रास्फीति गति सिद्धांत को बदलने से प्रभावित हुए हैं। संरक्षणवादी टैरिफ की तीव्रता, बढ़ी हुई नीतिगत अनिश्चितता, सुस्त भू-राजनीतिक जोखिम, और मुद्रास्फीति की दृढ़ता वैश्विक विकास दृष्टिकोण के लिए नकारात्मक जोखिम पैदा करती है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था, निकट अवधि के दृष्टिकोण के साथ कई जोखिमों से घिरी हुई है और विशेष रूप से हाल ही में पारस्परिक टैरिफ लगाए जाने के मद्देनजर अपने दीर्घकालिक औसत से नीचे जा रही है। अवस्फीति की गति को रोकते हुए सतत सेवाओं और कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ऊर्जा को छोड़कर हेडलाइन) अधिकांश अर्थव्यवस्थाओं के लिए हेडलाइन मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है। कई केंद्रीय बैंकों ने मौद्रिक नीति संयम के अपने स्तर को कम कर दिया है, किन्तु मौद्रिक नीति कार्रवाई में विचलन बढ़ गया है। मौद्रिक नीति प्रक्षेपवक्र और व्यापार संबंधित अनिश्चितताओं पर उतार-चढ़ाव की धारणाओं के मद्देनजर जोखिम-विमुख रुझान भावना प्रदर्शित करते हुए वैश्विक वित्तीय बाजार अस्थिर बने हुए हैं। इक्विटी बाजार ने, जो अमेरिका में कर कटौती की उम्मीदों और लचीला डेटा रिलीज से उत्साहित थे, ने मार्च और अप्रैल की शुरुआत में बढ़ते व्यापार और नीतिगत अनिश्चितता के बीच विकास के दृष्टिकोण पर जोर देते हुए महत्वपूर्ण बिकवाली का अनुभव किया। बॉण्ड प्रतिफल में कमी आई और वर्ष 2025 की पहली तिमाही में और अप्रैल की शुरुआत में यूएस डॉलर पीछे हट गया क्योंकि टैरिफ की घोषणा ने वैश्विक मंदी को भड़काया।

V.1 वैश्विक आर्थिक स्थितियाँ

वर्ष 2024 की दूसरी छमाही में, वैश्विक अर्थव्यवस्था निभावकारी वित्तीय स्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पलटाव के बीच स्थिर रही। वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए उच्च आवृत्ति संकेतक वैश्विक आर्थिक विकास में मंदी को दर्शाते हैं, क्योंकि वर्ष 2023 की पिछली तिमाही से वैश्विक कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (पीएमआई)¹ का आउटपुट सूचकांक कमजोर रहा।

आर्थिक सहकार और विकास संगठन (ओईसीडी) ने अपने विश्व आर्थिक आउटलुक इंटेरिम रिपोर्ट (मार्च 2025) में, दिसंबर 2024 के पूर्वानुमानों से 2025 और 2026 के लिए विकास पूर्वानुमान को क्रमशः 2.0 बीपीएस और 3.0 बीपीएस से घटाकर 3.1 प्रतिशत और 3.0 प्रतिशत कर दिया।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के बीच, अमेरिकी अर्थव्यवस्था वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 2.4 प्रतिशत (तिमाही दर तिमाही, मौसमी रूप से समायोजित वार्षिक दरें (तिमाही-दर-तिमाही, एसएएआर)) बढ़ी (3.1 प्रतिशत की तीसरी तिमाही के आउटटर्न से कम) जो उपभोक्ता और सरकारी खर्च में वृद्धि और आयात में गिरावट द्वारा समर्थित और आंशिक रूप से निवेश में गिरावट से प्रति संतुलित थी (सारणी V.1)। श्रम बाजार व्यापक रूप से स्थिर रहा अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 के बीच 4.1 प्रतिशत के औसत को बनाए रखा। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स (एस एण्ड पी) यूएस कंपोजिट पीएमआई मार्च में तीन महीने के उच्च स्तर 53.5 पर पहुंच गया, जो सेवा क्षेत्र में एक मजबूत पलटाव से प्रेरित था और यह मार्च 54.4 तक बढ़ गया (फरवरी में 51.0)। इसके विपरीत, विनिर्माण क्षेत्र वृद्धि में कमी आई और पीएमआई में फरवरी में 52.7 से 50.2 तक कमी आई।

यूरो क्षेत्र में वास्तविक जीडीपी वृद्धि तीसरी तिमाही में 1.7 प्रतिशत की वृद्धि के बाद चौथी तिमाही में 0.9 प्रतिशत (तिमाही-दर-तिमाही, एसएएआर) कम हुई जो मालसूची, सकल अचल पूंजी निर्माण और सरकारी व्यय में गिरावट से प्रेरित थी। फरवरी 2025 में 6.1 प्रतिशत की ऐतिहासिक कम बेरोजगारी के साथ

¹ पीएमआई के संदर्भ एसएण्डपी ग्लोबल सूचकांकों के लिए हैं, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो।

सारणी V.1: वास्तविक जीडीपी संवृद्धि

(प्रतिशत)

देश	ति1- 2024	ति2- 2024	ति3- 2024	ति4- 2024	2023	2024 (ई)	2025 (पी)	2026 (पी)
तिमाही-दर-तिमाही, मौसमी रूप से समायोजित, वार्षिक दर (तिमाही-दर-तिमाही, एसएएआर)								
कनाडा	1.8	2.8	2.2	2.6				
यूरो क्षेत्र	1.3	0.7	1.7	0.9				
जापान	-2.1	3.2	1.4	2.2				
दक्षिण कोरिया	5.3	-0.9	0.4	0.3				
यू.के.	3.7	1.8	0.0	0.4				
यूएस	1.6	3.0	3.1	2.4				

वर्ष-दर-वर्ष

उन्नत अर्थव्यवस्थाएं

कनाडा	0.7	1.2	1.9	2.4	1.5	1.3	2.0	2.0
यूरो क्षेत्र	0.5	0.5	1.0	1.2	0.4	0.8	1.0	1.4
जापान	-0.7	-0.7	0.7	1.1	1.5	-0.2	1.1	0.8
दक्षिण कोरिया	3.3	2.3	1.5	1.2	1.4	2.2	2.0	2.1
यू.के.	0.7	1.1	1.2	1.5	0.4	0.9	1.6	1.5
यूएस	2.9	3.0	2.7	2.5	2.9	2.8	2.7	2.1

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं

ब्राजील	2.6	3.3	4.1	3.6	3.2	3.7	2.2	2.2
चीन	5.3	4.7	4.6	5.4	5.4	4.8	4.6	4.5
भारत	8.4	6.5	5.6	6.2	9.2	6.5	6.5	6.5
इंडोनेशिया	5.1	5.1	5.0	5.0	5.1	5.0	5.1	5.1
फिलिपींस	5.9	6.5	5.2	5.3	5.5	5.8	6.1	6.3
रूस	5.4	4.1	3.1		4.1	3.8	1.4	1.2
दक्षिण अफ्रीका	0.6	0.4	0.4	0.9	0.7	0.8	1.5	1.6
थाईलैंड	1.7	2.3	3.0	3.2	2.0	2.7	2.9	2.6

मेमो:

विश्व	2023	2024 (E)	2025 (P)	2026 (P)
वर्ष-दर-वर्ष				
उत्पादन	3.3	3.2	3.3	3.3
व्यापार की मात्रा	0.7	3.4	3.2	3.3

ई: अनुमान पी: पूर्वानुमान

टिप्पणी: भारत का डेटा वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) के अनुरूप है; उदाहरण के लिए, 2024 अप्रैल 2024-मार्च 2025 से संबंधित है।

स्रोत: आधिकारिक सांख्यिकीय एजेंसियां; ब्लूमबर्ग; आईएमएफ डब्ल्यूईओ अपडेट, जनवरी 2025 और आरबीआई स्टाफ।

श्रम बाजार लचीला रहा। यूरोज़ोन में, कंपोजिट पीएमआई फरवरी में 50.2 से बढ़कर मार्च में 50.9 हो गया, जो सेवा गतिविधि में विस्तार से प्रेरित था, 26 माह के उच्चतम स्तर 48.6 पहुंचने के बावजूद विनिर्माण क्षेत्र संकुचन क्षेत्र में रहा।

वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में, यूके की अर्थव्यवस्था में उछाल आया जो उत्पादन में गिरावट के बाद सेवाओं और निर्माण क्षेत्र में वृद्धि से इसकी क्षतिपूर्ति हुई। व्यय के संदर्भ में, शुद्ध व्यापार और सकल पूंजी निर्माण में गिरावट को माल-सूची में उल्लेखनीय वृद्धि से प्रति संतुलित किया गया था। श्रम बाजार में नरमी जारी रही और बेरोजगारी दर अगस्त के 4.1 प्रतिशत से बढ़कर जनवरी में 4.4 प्रतिशत हो गई। यूके कंपोजिट पीएमआई मार्च में छह महीने के उच्च स्तर 51.5 पर चढ़ गया, जो फरवरी में 51.0 से 52.5 तक मजबूत सेवाओं की पीएमआई वृद्धि से प्रेरित था और यह नवंबर 2023 के बाद से 44.9 पर सबसे तेज विनिर्माण संकुचन की भरपाई करता है। जापान की जीडीपी वृद्धि वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में बढ़कर 2.2 प्रतिशत (तिमाही-दर-तिमाही, एसएएआर) हो गई, जो तीसरी तिमाही में 1.4 प्रतिशत थी, जो बेहतर व्यापार निवेश और आयात में तेज गिरावट से प्रेरित थी। हालांकि, कंपोजिट पीएमआई (एयू जिबुन बैंक) नवंबर 2022 से अपने निम्नतम स्तर पर गिर गया, जो फरवरी में 52.0 से गिरकर मार्च में 48.9 हो गया, क्योंकि सेवा पीएमआई तटस्थ निशान तक फिसल गया जबकि विनिर्माण में और गिरावट आई।

ईएमई के बीच, चीन की वास्तविक जीडीपी वृद्धि वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में वर्ष-दर-वर्ष (व-द-व) बढ़कर 5.4 प्रतिशत हो गई, जो 2024 में सबसे मजबूत तिमाही विस्तार को चिह्नित करती है और यह इस प्रकार पूरे वर्ष के लिए सरकार के लगभग 5 प्रतिशत के वार्षिक वृद्धि लक्ष्य को पूरा करती है। वृद्धि तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्रों में विस्तार से प्रेरित थी, जो सितंबर के अंत से घोषित सरकारी प्रोत्साहन उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला द्वारा समर्थित थी और इसमें बेंचमार्क उधार दर में 25 बीपीएस दर में कटौती शामिल थी। निर्यात में तेजी के कारण वर्ष 2024 की दूसरी छमाही में वृद्धि हुई, जिसने तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में लगभग 45 प्रतिशत का योगदान दिया। औद्योगिक क्षमता उपयोग भी तीसरी तिमाही की तुलना में चौथी तिमाही में 1.1 प्रतिशत अंक बढ़ा। हालांकि, खपत कमजोर बनी रही, जिसमें जीडीपी में इसकी हिस्सेदारी वर्ष 2023 की चौथी तिमाही में 88.3 प्रतिशत से तेजी से गिरकर वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 29.7 प्रतिशत हो गई है। समग्र पीएमआई

(काईक्सन) फरवरी 2025 में जनवरी में 51.5 से बढ़कर 51.8 हो गया, जो विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में उत्पादन में जल्दी वृद्धि से प्रेरित है।

अन्य प्रमुख ईएमई में, ब्राजील की जीडीपी वृद्धि वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 3.6 प्रतिशत (व-द-व) तक कम हो गई, जबकि तीसरी तिमाही में यह 4.1 प्रतिशत थी, जो कृषि क्षेत्र में गिरावट से प्रेरित थी जो सेवाओं और औद्योगिक क्षेत्रों में विस्तार से इसकी भरपाई से अधिक थी। श्रम बाजार की स्थितियों में सुधार हुआ क्योंकि बेरोजगारी सूचकांक वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 6.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 6.7 प्रतिशत हो गया। समग्र पीएमआई मार्च 2025 से बढ़कर चार माह के उच्चतम 52.6 हो गया, जो बिक्री में मजबूत वृद्धि द्वारा समर्थित था। दक्षिण अफ्रीकी अर्थव्यवस्था तीसरी तिमाही में 0.4 प्रतिशत की तुलना में चौथी तिमाही 0.9 प्रतिशत से थोड़ी तेज गति से बढ़ी जो कृषि क्षेत्र में तेज सुधार तथा वित्त और व्यापार उद्योगों में वृद्धि से प्रेरित था। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका के लिए समग्र पीएमआई लगातार चौथे महीने मार्च में 48.3 पर संकुचन क्षेत्र में रहा, क्योंकि लगातार कमजोर मांग जारी रहने से उत्पादन और बिक्री पर चिंता बनी रही। रूसी अर्थव्यवस्था में वृद्धि वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में घटकर 3.1 प्रतिशत (व-द-व) हो गई (दूसरी तिमाही में 4.1 प्रतिशत) जो आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं में वृद्धि के कारण संचालित थी। मार्च 2025 में, कंपोजिट पीएमआई (49.1) और संकुचन क्षेत्र में विस्तार के बाद तटस्थ निशान के नीचे गया क्योंकि विनिर्माण पीएमआई अप्रैल 2022 से अपने निम्नतम स्तर 48.2 तक कम हो गया।

आसियान अर्थव्यवस्थाओं² ने वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में उच्च नए ऑर्डर और उत्पादन गतिविधि में बढ़ोतरी से प्रेरित लचीली वृद्धि प्रदर्शित की। कुल मिलाकर, दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के 2024 में स्वस्थ गति से बढ़ने की उम्मीद है, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में मजबूत विनिर्माण निर्यात और सार्वजनिक पूंजीगत खर्च द्वारा समर्थित है और वर्ष 2025 में विकास स्थिर रहने की उम्मीद है³। वर्ष 2025 की पहली तिमाही

में अब तक, मुद्रास्फीतिकारक दबावों में निरंतर गिरावट की प्रवृत्ति के बीच उत्पादन और नए ऑर्डर में बढ़ोतरी से वृद्धि मामूली रही है।

ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में, दक्षिण अफ्रीका और भारत को छोड़कर, जहां विकास में तेजी आने और स्थिर रहने की उम्मीद है, 2025 के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि मध्यम होने का अनुमान है (सारणी V.2)। 2025 में ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुद्रास्फीति दृष्टिकोण में भी सुधार होने की उम्मीद है, यह उच्च मुद्रास्फीति वालों के लिए घट रहा है, लेकिन चीन के लिए बढ़ रहा है, जो नियंत्रित उपभोक्ता भावना के बीच अपस्फीतिकारी दबावों से पीड़ित है।

उच्च आवृत्ति संकेतकों की ओर मुड़ते हुए, जनवरी 2025 के लिए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के समग्र अग्रणी संकेतकों (सीएलआई) ने प्रदर्शित किया कि अधिकांश अर्थव्यवस्थाएँ दीर्घकालिक रुझान से ऊपर रहीं हैं (चार्ट V.1ए)। वैश्विक समग्र पीएमआई फरवरी 2023 से तटस्थ निशान से ऊपर बना हुआ है (चार्ट V.1बी)। सेवा क्षेत्र में तेज विस्तार के बाद फरवरी में 51.5 से मार्च में 52.1 पर इसका विस्तार हुआ और 2025 में इसकी उच्चतम रीडिंग है। उत्पादन वृद्धि में कमी और नए ऑर्डर से वैश्विक विनिर्माण पीएमआई फरवरी में 50.6 से घटकर मार्च में 50.3 हो गया।

वैश्विक व्यापारिक व्यापार की मात्रा जनवरी 2025 में लगातार दसवें महीने बढ़ी, जो 5.0 प्रतिशत (व-द-व) तेजी से बढ़ रही है। यह गति 1.1 प्रतिशत (माह-दर-माह) तक पहुंच गई, जो सीधे चौथे महीने तक सकारात्मक रही, क्योंकि देशों ने टैरिफ लगाने की प्रत्याशा में अपने आयात को असमान किया। ईएमई वर्ष 2024 की चौथी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) में लगातार आठवीं तिमाही में विकास का प्रमुख कारक बना रहा, जिसमें ईई की व्यापार वृद्धि में मामूली सुधार हुआ। जनवरी 2025 में हालांकि, विश्व व्यापार वृद्धि में उन्नत अर्थव्यवस्थाएं (ईई) का योगदान महत्वपूर्ण रहा है (चार्ट V.2ए)। फ्रेटोस बाल्टिक ग्लोबल इंडेक्स - वैश्विक महासागर फ्रेट कंटेनर मूल्य निर्धारण सूचकांक

² दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।

³ एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के एशियाई विकास आउटलुक दिसंबर 2024 के अनुसार, दक्षिण पूर्व एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के 2025 में 4.7 प्रतिशत (2024 के समान) की स्थिर गति से बढ़ने का अनुमान है।

सारणी V.2: ब्रिक्स के लिए चुनिंदा समष्टिगत आर्थिक संकेतक

वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)	देश	2023	2024(ई)	2025(पी)	सामान्य सरकारी सकल ऋण (जीडीपी का प्रतिशत)*	देश	2024(ई)	2024(ई)	2025(पी)
	ब्राजील	3.2	3.7	2.2		ब्राजील	84.7	87.6	92.0
	रूस	4.1	3.8	1.4		रूस	19.5	19.9	20.4
	भारत	9.2	6.5	6.5		भारत	83.0	83.1	82.6
	चीन	5.4	4.8	4.6		चीन	84.4	90.1	93.8
	दक्षिण अफ्रीका	0.7	0.8	1.5		दक्षिण अफ्रीका	73.4	75.0	77.4
सीपीआई मुद्रास्फीति दर (वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)	देश	2023	2024(ई)	2025(पी)	चालू खाता शेष (जीडीपी का प्रतिशत)	देश	2023	2024(ई)	2025(पी)
	ब्राजील	4.6	4.3	3.6		ब्राजील	-1.0	-1.7	-1.8
	रूस	5.9	7.9	5.9		रूस	2.5	2.7	2.6
	भारत	5.4	4.4	4.1		भारत	-0.7	-1.1	-1.3
	चीन	0.2	0.4	1.7		चीन	1.4	1.4	1.6
	दक्षिण अफ्रीका	5.9	4.7	4.5		दक्षिण अफ्रीका	-1.6	-1.6	-1.9
सामान्य सरकारी ऋण देना/ऋण लेना (जीडीपी का प्रतिशत)	देश	2023	2024(ई)	2025(पी)	विदेशी मुद्रा भंडार* (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)	देश	2023	2024	2025
	ब्राजील	-7.6	-6.9	-7.3		ब्राजील	355.0	329.7	332.5
	रूस	-2.3	-1.9	-0.5		रूस	598.6	609.1	632.4
	भारत	-8.3	-7.8	-7.6		भारत	622.5	635.7	665.4
	चीन	-6.9	-7.4	-7.6		चीन	3449.7	3455.6	3498.6
	दक्षिण अफ्रीका	-5.8	-6.2	-6.3		दक्षिण अफ्रीका	62.5	65.5	66.3

ई: अनुमान पी: पूर्वानुमान

*: 2025 के लिए विदेशी मुद्रा भंडार भारत (मार्च 2025) को छोड़कर सभी देशों के लिए फरवरी 2025 से संबंधित है।

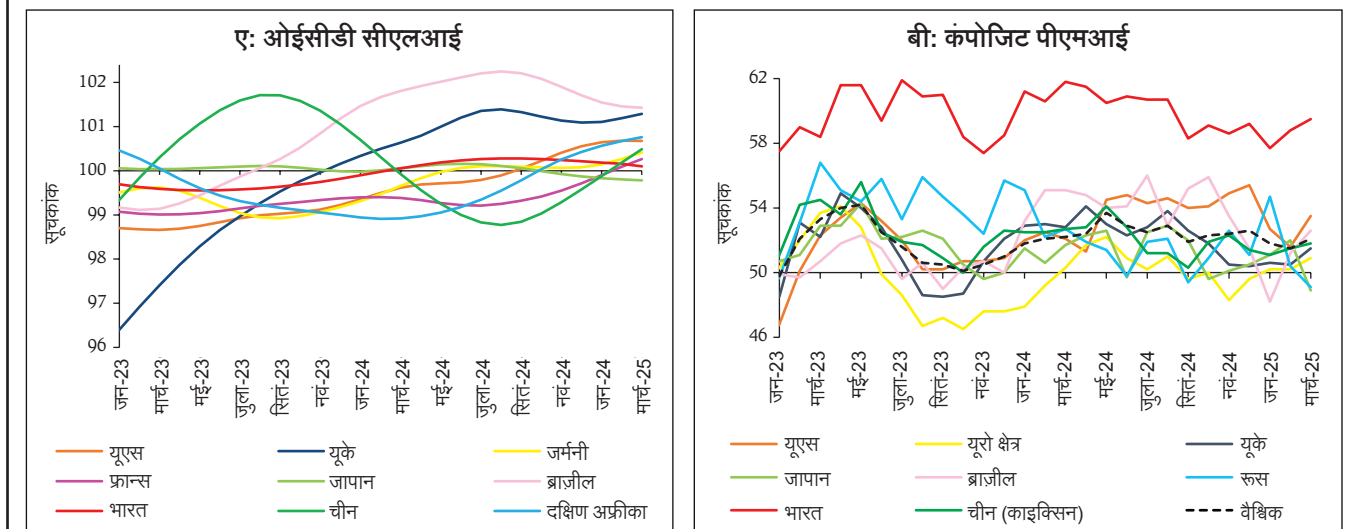
#: सकल ऋण का तात्पर्य गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र से है जिसमें इलेक्ट्रोब्रास और पेट्रोब्रास को छोड़कर केंद्रीय बैंक द्वारा धारित राष्ट्रीय कर्ज शामिल है।

टिप्पणी: विदेशी मुद्रा भंडार के आंकड़ों, जो कैलेंडर वर्ष के अनुसार हैं, को छोड़कर भारत के आंकड़े वित्त वर्ष (अप्रैल-मार्च) के अनुरूप हैं। वर्ष 2024 के लिए भारत का मुद्रास्फीति डाटा अप्रैल 2024 से फरवरी 2025 तक का है।

स्रोत: आधिकारिक सांख्यिकीय एजेंसियां; डब्ल्यूईओ अक्टूबर 2024 डेटाबेस और जनवरी 2024 अपडेट, आईएमएफ; इंटरनैशनल रिजर्व एंड फॉरेन करेंसी लिक्विडिटी (आईआरएफसीएल), आईएमएफ; और आरबीआई।

जो 40-फीट कंटेनर की कीमतों को मापता है – चीन में कमजोर मांग और शिपिंग उद्योग में नए गठजोड़ के बीच पोत क्षमता में वृद्धि के कारण मार्च 2025 में 23.1 प्रतिशत (व-द-व) की गिरावट आई (चार्ट V.2बी)। भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से उच्च निर्यात

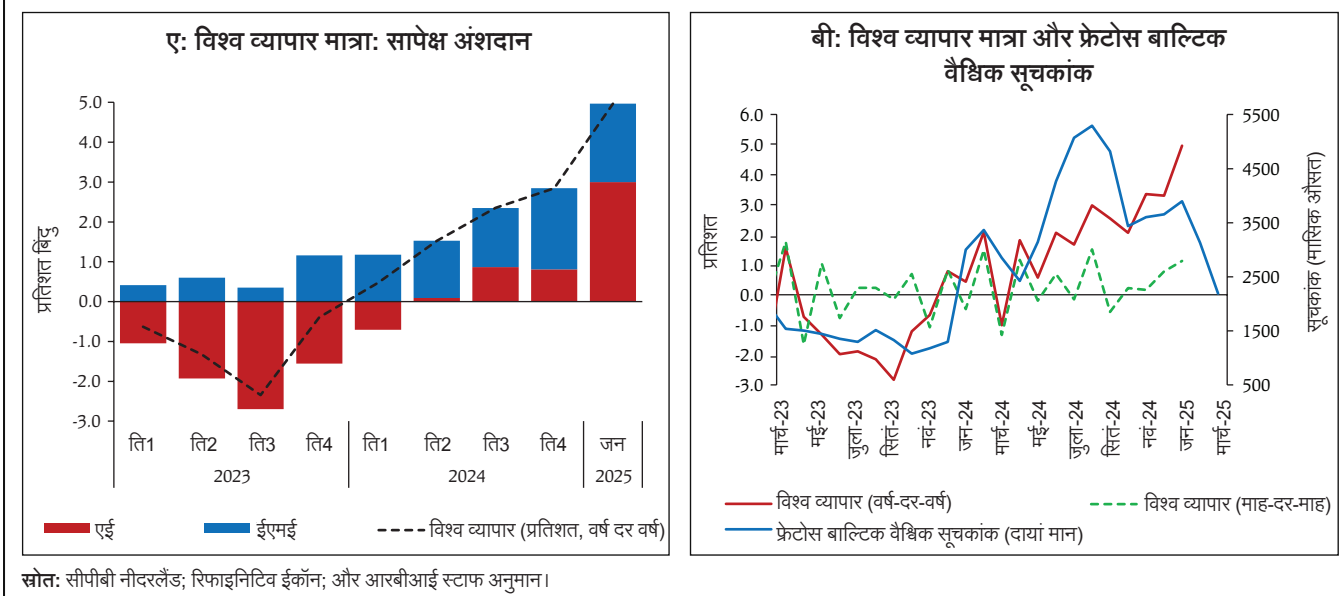
चार्ट V.1: सर्वेक्षण संकेतक



टिप्पणी: पीएमआई सूचकांकों के लिए 50 से ऊपर की रीडिंग पिछले महीने की तुलना में समग्र वृद्धि को दर्शाती है, और 50 से नीचे समग्र कमी है। सूचकांकों को मौसमी रूप से समायोजित किया जाता है।

स्रोत: ओईसीडी; और ब्लूमबर्ग।

चार्ट V.2: विश्व व्यापार मात्रा



के कारण व्यापारिक कारोबार (ति-द-ति) में लगभग आधे प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में वैश्विक व्यापार मूल्य का विस्तार जारी रहा (चार्ट V.2बी)। नवीनतम विश्व व्यापार संगठन का माल व्यापार बैरोमीटर (मार्च 2025) इंगित करता है कि वैश्विक व्यापारिक कारोबार की मात्रा वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के माध्यम से स्थिर गति से विस्तारित होगी और 2025 शुरुआती कुछ महीनों में बढ़ती रहने के लिए तैयार है। जनवरी 2025 के आईएमएफ के डब्ल्यूईओ अपडेट के अनुसार, वैश्विक व्यापार की मात्रा 2025 और 2026 में क्रमशः 3.2 प्रतिशत और 3.3 प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है। फिर भी, अमेरिका द्वारा घोषित टैरिफ की हालिया लहर और देशों की विभिन्न व्यापार प्रतिक्रियाएं आगे बढ़ने वाले वैश्विक गतिशीलता को आकार देंगी। विश्व व्यापार संगठन के प्रारंभिक अनुमान दर्शाते हैं कि वैश्विक व्यापारिक कारोबार की मात्रा में 2025 में एक प्रतिशत की गिरावट आएगी।⁴

V.2 पण्य कीमतें और मुद्रास्फीति

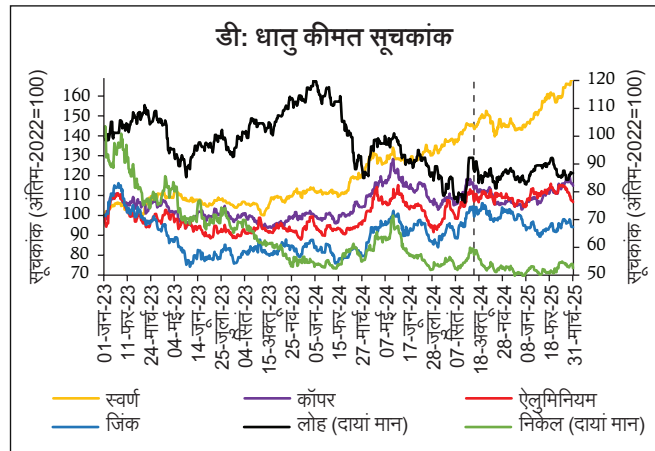
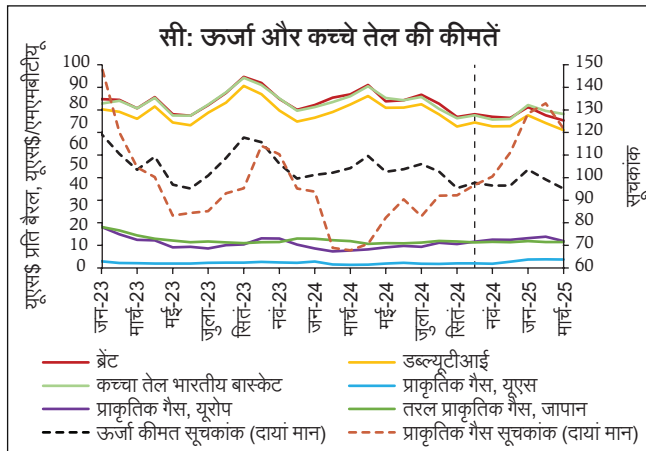
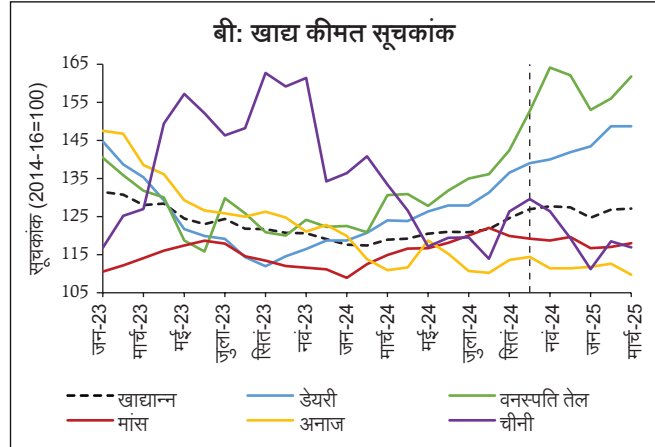
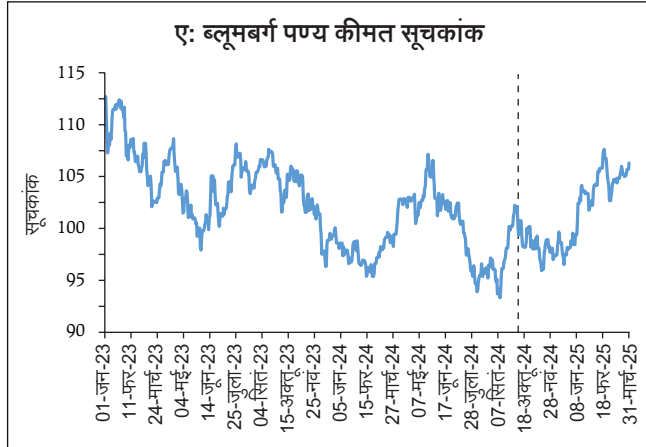
वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में, ब्लूमबर्ग कमोडिटी प्राइस इंडेक्स द्वारा मापी गई वैश्विक कमोडिटी की कीमतें, धातुओं

और कृषि कीमतों में नरमी के कारण 1.6 प्रतिशत से कम होकर अधोगामी झुकाव के साथ अस्थिर रहीं (चार्ट V.3ए)। हालांकि, यह गिरावट वर्ष 2025 की पहली तिमाही में भरपाई से अधिक थी, जब कृषि, ऊर्जा और धातु की कीमतें बढ़ने से कीमतों में 7.7 प्रतिशत की तेजी से वृद्धि हुई। अप्रैल की शुरुआत में यह प्रवृत्ति उलट गई, कमोडिटी की कीमतों में गिरावट आई, जिसमें मांग के दृष्टिकोण में गिरावट के कारण वैश्विक मंदी की आशंका बढ़ गई। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुसार, वैश्विक खाद्य कीमतों में वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 4.0 प्रतिशत (तिमाही-दर-तिमाही) की वृद्धि हुई, जो उच्च वनस्पति तेल और डेयरी कीमतों से प्रेरित थी। हालांकि, वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कीमतों में सुधार हुआ और इसमें 0.9 प्रतिशत की कमी आई जो मुख्य रूप से उच्चतम वनस्पति तेल की कीमतों के बावजूद चीनी की कीमतों में तेज गिरावट के कारण हुई (चार्ट V.3बी)।

मध्य पूर्व में बढ़े तनाव और अमेरिका में तूफान मिल्टन के कारण अक्टूबर के पहले पखवाड़े में कच्चे तेल की कीमतें 80 डॉलर प्रति बैरल से अधिक हो गईं। हालांकि, कीमतें घट गईं और उसके बाद वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में नियंत्रित रहीं, जो भू-राजनीतिक और आर्थिक कारकों के मिश्रण से प्रेरित \$74-76 प्रति बैरल की सीमा में मँडराती रहीं। तनाव घटने, उम्मीद से कम

⁴ 03 अप्रैल, 2025 को जारी विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के महानिदेशक के विवरण के अनुसार

चार्ट V.3: पण्य कीमतें



स्रोत: एफएओ; विश्व बैंक; और ब्लूमबर्ग; और पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार।

चीन के प्रोत्साहन उपायों और मध्य पूर्व में संभावित युद्धविराम की चर्चाओं ने कीमतों को नीचे खींचना जारी रखा, प्रतिबंधों की प्रत्याशाएं और रूस-यूक्रेन संघर्ष बढ़ने से कभी-कभी कीमतों में वृद्धि हुई। रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर प्रतिबंधों और ठंड के मौसम के कारण जनवरी में कीमतों में तेजी आनी शुरू हो गई। जनवरी के मध्य से गाजा में युद्धविराम के बाद और टैरिफ लगाने की आशंकाएं बढ़ने और तेल की आपूर्ति बढ़ने से कीमतें घट गईं। जब तक ओपीईसी प्लस द्वारा अन्वाइडिंग प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई, तब तक मार्च के प्रथम सप्ताह तक गिरावट जारी रही।⁵ वेनेजुएला और ईरान पर प्रतिबंध लगाने के बाद तेल की कीमतें फिर से बढ़ने लगीं, लेकिन विकास की धूमिल संभावनाओं और आश्चर्यजनक

ओपेक + घोषणा के बीच 3 साल के निचले स्तर पर आ गई (चार्ट V.3सी)।

वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में यूएस डॉलर को मजबूत होने और चीन की कमजोर मांग के कारण जो बेस मेटल का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, बेस मेटल की कीमतों में गिरावट आई, क्योंकि चीनी प्रोत्साहन उपाय उम्मीदों से काफी कम थे। बेस मेटल्स की कीमतें, हालांकि, चीन की प्रोत्साहन घोषणा से वर्ष 2025 की पहली तिमाही में बढ़ गईं किन्तु अमेरिका द्वारा लगाए जानेवाले आगे के टैरिफ से बचने से इसमें कमी आई। अमेरिकी चुनावों को लेकर अनिश्चितता बढ़ने और भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने से अक्टूबर में सोने की कीमतों में 4.9 प्रतिशत (माह-दर-

⁵ जनवरी 2024 में शुरू की गई और जून में समाप्त होने वाली स्वैच्छिक कटौती जो 2.2 मिलियन बैरल प्रति दिन को संदर्भित करती है, को कम कीमतों के कारण पांच बार स्थगित कर दिया गया। हालांकि, अन्वाइडिंग प्रक्रिया अंततः अप्रैल 2025 में शुरू हुई और 2026 के अंत तक इसके समाप्त होने की उम्मीद है

माह) की बढ़ोतरी हुई। नवंबर और दिसंबर में कीमतों में गिरावट से भारी तेजी, भरपाई से अधिक थी क्योंकि अमेरिकी डॉलर और ट्रेजरी यील्ड को मजबूत करने से सोने को रखने की अवसर लागत बढ़ गई, जिससे वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में सोने की कीमतों में 1.5 प्रतिशत (तिमाही-दर-तिमाही) की गिरावट आई। इसके बाद, वर्ष 2025 की पहली तिमाही में कीमतों में तेजी से वृद्धि हुई, 19.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और पहली बार 3,100 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के निशान को पार कर गया। बढ़ती अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की खरीद में वृद्धि के साथ टैरिफ लगने की प्रत्याशा में भौतिक बुलियन की मांग बढ़ी जिससे सोने की कीमतों को समर्थन मिला (चार्ट V.3डी)।

उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

अवस्फीति ने अपनी गति खो देने से उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति कई देशों में लक्ष्य से ऊपर रही। जबकि मुख्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति कम हो गई है, खासकर उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में सेवा मुद्रास्फीति पूर्व-महामारी के स्तर से ऊपर बनी हुई है। ओईसीडी ने मार्च 2025 की अपनी अंतरिम आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट में जी20 देशों के लिए अपने 2025 और 2026 को क्रमशः 3.8 प्रतिशत और 3.2 प्रतिशत तक संशोधित किया।

अमेरिका में, हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति मुख्य रूप से आश्रय स्थान की बढ़ती कीमतों के कारण सितंबर 2024 में 2.4 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2025 में 2.8 प्रतिशत हो गई, जबकि कोर सीपीआई मुद्रास्फीति सितंबर 2024 से जनवरी 2025 तक 3.3 प्रतिशत पर व्यापक रूप से स्थिर रहने के बाद फरवरी में 3.1 प्रतिशत तक कम हो गई (सारणी V.3)। व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) मूल्य सूचकांक के संदर्भ में मुद्रास्फीति - यूएस फेड की मुद्रास्फीति का पसंदीदा उपाय - सितंबर में 2.1 प्रतिशत से फरवरी में 2.5 प्रतिशत तक बढ़ गया (चार्ट V.4ए), जबकि कोर पीसीई इसी अवधि में 2.7 प्रतिशत से घटकर 2.8 प्रतिशत हो गया (चार्ट V.4बी)।

यूरो क्षेत्र में, सीपीआई मुद्रास्फीति अक्टूबर 2024 में 2.0 प्रतिशत से बढ़कर फरवरी 2025 में 2.2 प्रतिशत हो गई, जबकि कोर मुद्रास्फीति (ऊर्जा, खाद्य, शराब और तंबाकू को छोड़कर मुद्रास्फीति) सितंबर 2024 से जनवरी 2025 तक पांच महीने के लिए 2.7 प्रतिशत पर स्थिर रहने के बाद मार्च में घटकर 2.7 प्रतिशत हो गई। यूके में, सीपीआई हेडलाइन मुद्रास्फीति सितंबर

सारणी V.3: उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति

(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

देश	मुद्रास्फीति लक्ष्य	ति1:2024	ति2:2024	ति3:2024	ति4:2024	ति1:2025
उन्नत अर्थव्यवस्थाएं						
कनाडा	2.0 ± 1.0	2.9	2.8	2.0	1.9	2.3
यूरो क्षेत्र	2.0	2.6	2.5	2.2	2.2	2.3
जापान	2.0	2.6	2.7	2.8	2.9	3.9
दक्षिण कोरिया	2.0	3.0	2.7	2.1	1.6	2.1
यू.के.	2.0	3.5	2.1	2.0	2.5	2.9
यूएस	(2.0)	3.3	3.2	2.6	2.7	2.9
	(2.0)	(2.7)	(2.6)	(2.3)	(2.5)	(2.5)

उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाएं

ब्राजील	3.0 ± 1.5	4.3	4.0	4.4	4.8	4.8
रूस	4.0	7.6	8.2	8.9	9.0	10.0
भारत	4.0 ± 2.0	5.0	4.9	4.2	5.6	3.9
चीन		0.0	0.3	0.5	0.2	-0.1
दक्षिण अफ्रीका	3.0-6.0	5.4	5.2	4.3	2.9	3.2
मेक्सिको	3.0 ± 1.0	4.6	4.8	5.0	4.5	3.7
इंडोनेशिया	2.5 ± 1.0	2.8	2.8	2.0	1.6	0.6
फिलिपींस	3.0 ± 1.0	3.3	3.8	3.2	2.6	2.3
थाईलैंड	1.0-3.0	-0.8	0.8	0.6	1.0	1.1
तुर्की	5.0 ± 2.0	66.8	72.3	54.4	46.7	39.8

ज्ञापन:

	2023	2024(ई)	2025(पी)	2026(पी)
विश्व उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति	6.7	5.7	4.2	3.5

ई: अनुमान;

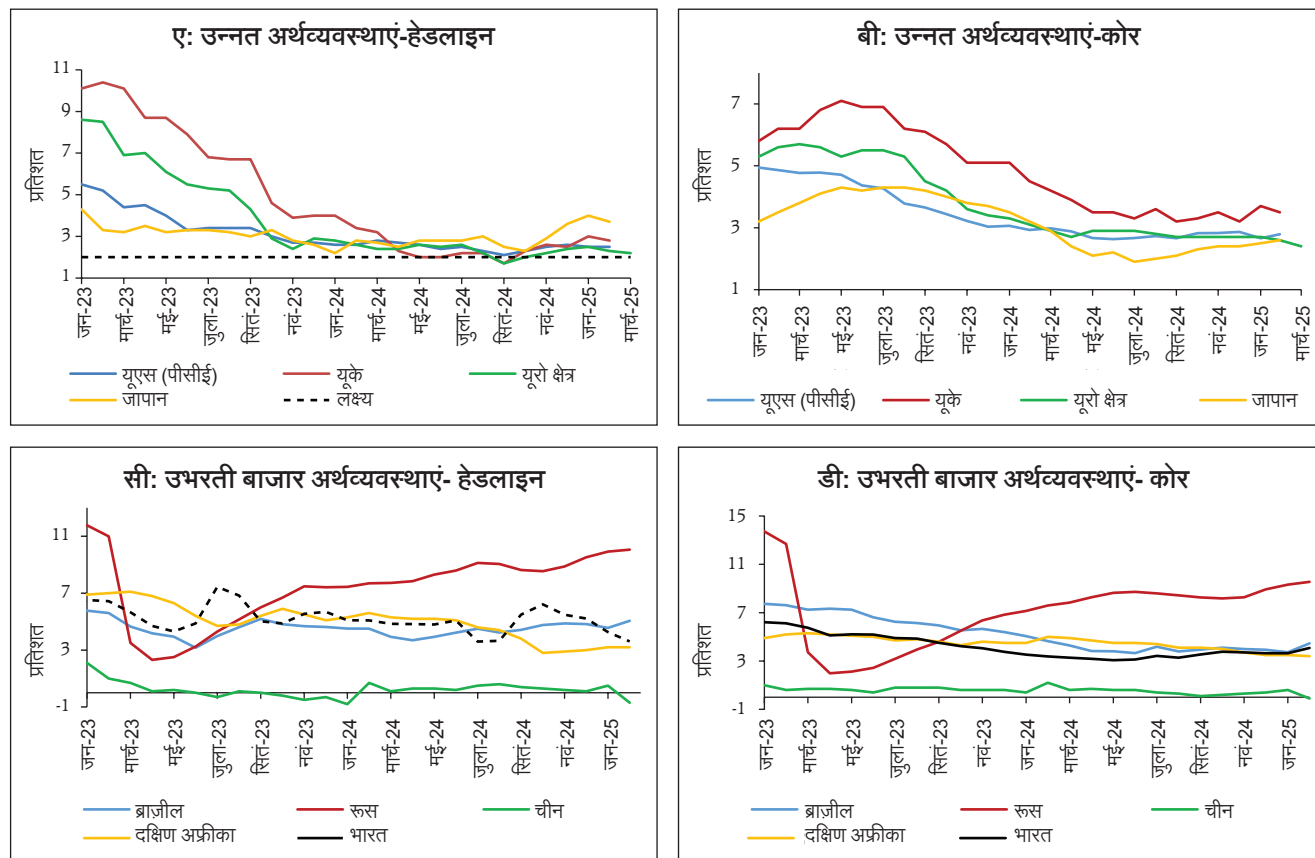
अ: अनंतिम

टिप्पणियाँ: (1) अमरीका के लिए कोष्ठक में दिए गए आंकड़े वार्षिक उपभोग व्यय (पीसीई) मूल्य सूचकांक में वर्ष-दर-वर्ष का परिवर्तन हैं।

(2) वर्ष 2025 की पहली तिमाही के लिए मुद्रास्फीति के आंकड़े यूरो क्षेत्र, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, थाईलैंड, इंडोनेशिया और तुर्की (मार्च 2025) को छोड़कर फरवरी 2025 तक के लिए हैं।

स्रोत: केंद्रीय बैंक की वेबसाइटें; आईएमएफ; और ब्लूमबर्ग।

2024 में 1.7 प्रतिशत से फरवरी 2025 में 110 बीपीएस बढ़कर 2.8 प्रतिशत हो गई, जबकि कोर मुद्रास्फीति इसी अवधि में 30 बीपीएस बढ़कर 3.5 प्रतिशत हो गई। जापान में, हेडलाइन मुद्रास्फीति फरवरी 2025 में 120 बीपीएस से बढ़कर 3.7 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर 2024 में 2.5 प्रतिशत थी। सीपीआई मुद्रास्फीति (ताजा खाद्य छोड़कर सभी) भी 60 बीपीएस तक बढ़ गई – सितंबर 2024 में 2.4 प्रतिशत से फरवरी 2025 में 3.0 प्रतिशत तक, जबकि कोर मुद्रास्फीति (ताजा खाद्य और ऊर्जा दोनों को छोड़कर मुद्रास्फीति), इसी अवधि में 2.1 प्रतिशत से 2.6 प्रतिशत तक बढ़ गई।

चार्ट V.4: सीपीआई मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) – चुनिंदा अर्थव्यवस्थाएं


टिप्पणी: भारत के लिए, कोर सीपीआई, यानी, खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई की गणना हेडलाइन सीपीआई से 'खाद्य और पेय पदार्थ' और 'ईंधन और प्रकाश' समूहों को हटाकर की जाती है।
स्रोत: आधिकारिक सांख्यिकीय एजेंसियां; ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

प्रमुख ईएमई के बीच, ब्राजील में सीपीआई मुद्रास्फीति फरवरी 2025 में बढ़कर 5.1 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर 2024 में 4.4 प्रतिशत थी (चार्ट V.4सी)। रूस में, पश्चिमी प्रतिबंधों और श्रमिकों की कमी से मजदूरी में वृद्धि के कारण इसी अवधि में यह 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 10.1 प्रतिशत हो गयी। हालांकि, दक्षिण अफ्रीका में, मुद्रास्फीति फरवरी 2025 में घटकर 3.2 प्रतिशत हो गई, जो सितंबर 2024 में 3.8 प्रतिशत थी। चीन ने सकारात्मक लेकिन मुद्रास्फीति के निम्न स्तर का अनुभव किया, जो सितंबर 2024 से जनवरी 2025 के दौरान 0.1 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत की सीमा में मँडरा रहा था, जो कमजोर मांग और कम उपभोक्ता विश्वास के कारण ज्यादातर नियंत्रित रही, लेकिन चंद्र नव वर्ष की छुट्टियों के दौरान उपभोक्ता खर्च में वृद्धि के कारण इसमें तेजी आई। हालांकि, फरवरी 2025 में, सीपीआई में (-) 0.7 प्रतिशत की गिरावट आई, जो अपस्फीति क्षेत्र में लौट आया और एक वर्ष

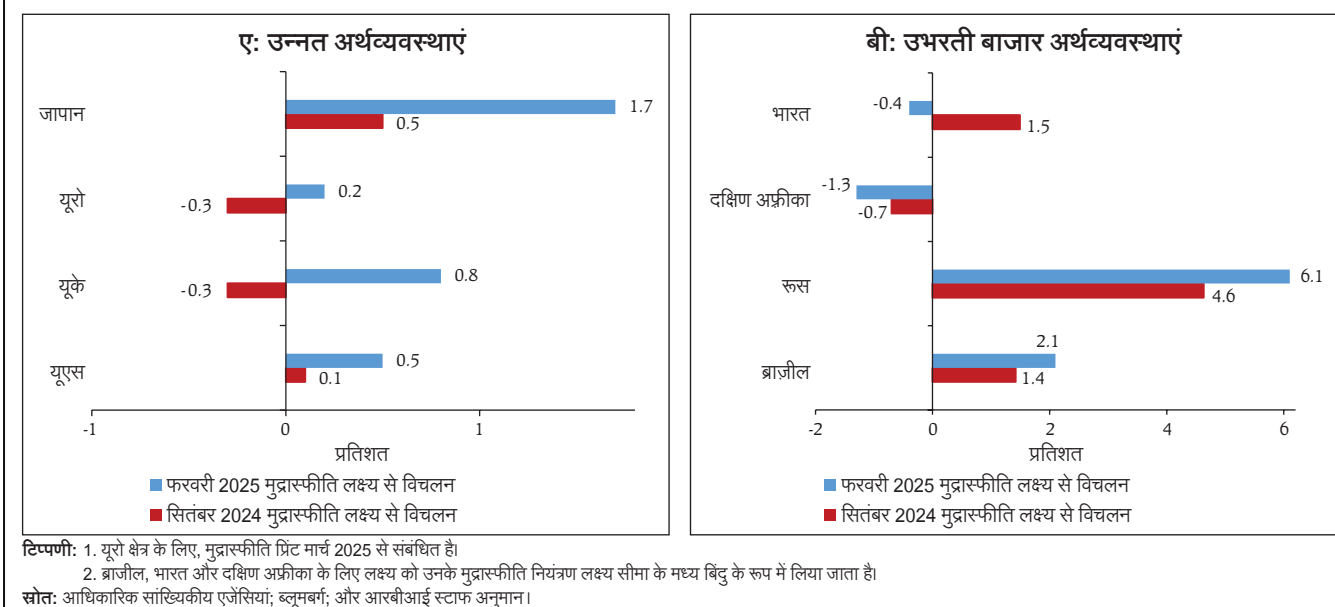
से अधिक समय में अपने निम्नतम स्तर को चिह्नित किया जो कमजोर घरेलू मांग से प्रेरित था। कोर मुद्रास्फीति संचालन ने ईएमई के लिए विचलन प्रदर्शित किया, कुछ देशों के लिए यह कम था लेकिन दूसरों के लिए यह तेजी भरा था (चार्ट V.4डी)।

अक्टूबर 2024 एमपीआर के बाद से अवस्फीति का अंतिम मील बढ़ रहा है, एई और अधिकांश ईएमई में अवस्फीति धीमी हो रही है (चार्ट V.5ए और 5बी)।

V.3 मौद्रिक नीति रुख

2022-23 में बहु-दशकीय उच्च मुद्रास्फीति का मुकाबला करने के लिए समकालीन सख्ती के बाद, केंद्रीय बैंकों ने 2023 और 2024 से अपनी नीति सामान्यीकरण शुरू किया। हालांकि, नरमी की गति भिन्न-भिन्न हो गई क्योंकि केंद्रीय बैंकों ने अपने स्वयं के विकसित वृद्धि-मुद्रास्फीति गतिशीलता का प्रत्युत्तर

चार्ट V.5: अवरुप्ति का अंतिम मील



दिया। अधिकांश केंद्रीय बैंक नीति में कम प्रतिबंधात्मक हो गए हैं, लेकिन भविष्य के निर्णयों के लिए डेटा पर निर्भर रहते हुए सतर्क रहना और सावधानी पर जोर देना जारी रखते हैं। फिर भी, 2024 की दूसरी छमाही और 2025 की शुरुआत में विचलन की सीमा और बढ़ गई क्योंकि कुछ देशों ने अपने नरमी चक्र को जारी रखा, कुछ नीतिगत दरों के अपेक्षाकृत निचले स्तर पर सतर्क रहे, जबकि कुछ ने मुद्रास्फीति में किसी भी वृद्धि को रोकने के लिए शुरू में ही वृद्धि शुरू कर दी।

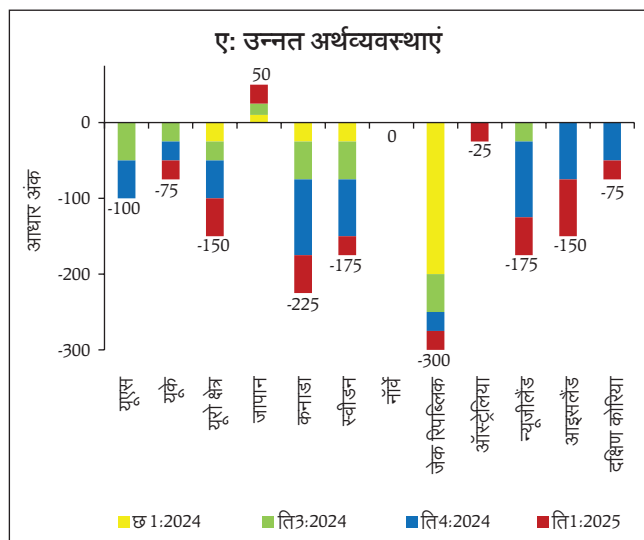
यूएस फेड ने सितंबर 2024 में नरमी चक्र शुरू किया और फेडरल निधि दर के लिए लक्ष्य सीमा को 50 बीपीएस घटाकर 4.75-5.00 प्रतिशत कर दिया (चार्ट V.6ए)। इसके बाद की दो बैठकों अर्थात् नवंबर और दिसंबर में फेडरल निधि दर को 25 बीपीएस घटाकर 4.25-4.50 प्रतिशत कर दिया। हालांकि, 2025 में, जनवरी और मार्च दोनों बैठकों में नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखा गया था। अपनी मार्च 2025 की बैठक में, फेड ने उल्लेख किया कि आर्थिक दृष्टिकोण के आसपास अनिश्चितता बढ़ गई थी और मात्रात्मक सख्ती कार्यक्रम की गति को धीमा करने की अपनी योजना की घोषणा की।⁶ मार्च की बैठक में जारी आर्थिक अनुमानों के सारांश के अनुसार, फेडरल ओपन मार्केट

कमेटी (एफओएमसी) ने उम्मीद की कि फेडरल निधि दरों के लिए लक्ष्य सीमा 2025 के अंत तक 3.75-4.00 प्रतिशत होगी, जो 2025 में और अधिक 50 बीपीएस दर में कटौती का संकेत देती है और यह दिसंबर 2024 के पूर्वानुमान से अपरिवर्तित है।

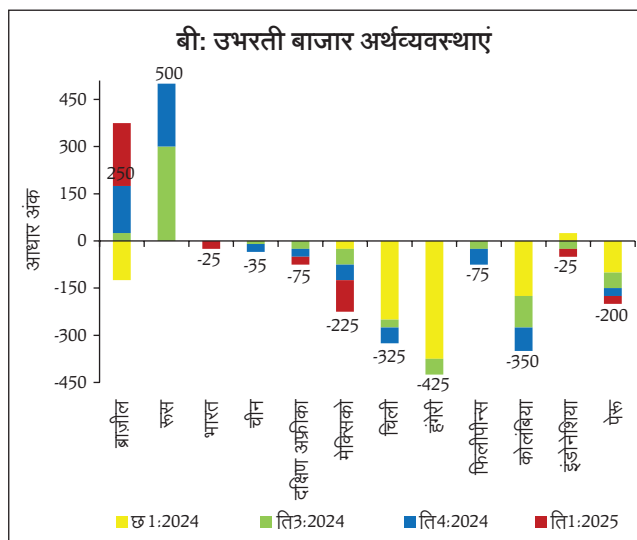
यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) ने अक्टूबर 2024 - मार्च 2025 के दौरान आयोजित अपनी चार बैठकों में से प्रत्येक में जमा सुविधा दर (डीएफआर) को 25 बीपीएस कम करते हुए, जून 2024 में अपना नरमी चक्र शुरू करने के बाद से बेंचमार्क दर को 150 बीपीएस तक कम करते हुए अपनी नीतिगत दर को कम करना जारी रखा। ईसीबी ने दोहराया कि यह उचित मौद्रिक नीति रुख निर्धारित करने के लिए डेटा-निर्भर और बैठक-दर-बैठक दृष्टिकोण का पालन करेगा। इसके अलावा, परिपक्व प्रतिभूतियों से मूल भुगतान अब पुनर्निवेश नहीं किए जाने के साथ, परिसंपत्ति खरीद कार्यक्रम (एपीपी) पोर्टफोलियो और महामारी आपातकालीन खरीद कार्यक्रम (पीईपीपी) पोर्टफोलियो दोनों एक अनुमानित गति से सिकुड़ते रहते हैं। हालांकि, बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई) अगस्त 2024-मार्च 2025 के बीच प्रत्येक दूसरी बैठक में अपनी नीतिगत दर को कम करते हुए, अपने नरमी चक्र में अधिक क्रमिक रहा है। मुद्रास्फीति के लिए मध्यावधि दृष्टिकोण के विकसित दृष्टिकोण के आधार पर, बीओई ने मौद्रिक नीति संयम

⁶ अप्रैल से शुरू होकर, एफओएमसी ट्रेजरी प्रतिभूतियों पर मासिक मोचन कैप को \$25 बिलियन से \$5 बिलियन तक कम करके अपनी प्रतिभूतियों की होल्डिंग में गिरावट की गति को धीमा कर देगा। हालांकि, समिति एजेंसी ऋण और एजेंसी बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों पर मासिक मोचन कैप को \$ 35 बिलियन पर बनाए रखेगी।

चार्ट V.6: नीति दर परिवर्तन – चुनिंदा प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं



स्रोत: ब्लूमबर्ग।



को और वापस लेने के लिए एक क्रमिक और सावधानीपूर्वक दृष्टिकोण का संकेत दिया।

अन्य प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एई) में, बैंक ऑफ कनाडा ने वर्ष 2024 की चौथी तिमाही और वर्ष 2025 की प्रथम तिमाही के दौरान अपनी बैठकों में अपनी नीतिगत दर को कुल मिलाकर 150 बीपीएस से कम कर दिया। वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में सभी बैठकों के दौरान, रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड (आरबीएनजेड) और बैंक ऑफ कोरिया (बीओके) ने अपनी बेंचमार्क दरों में क्रमशः 50 बीपीएस और 25 बीपीएस की कमी की। वर्ष 2025 की प्रथम तिमाही में, हालांकि, बीओके ने जनवरी में विराम के बाद फरवरी में अपनी नीतिगत दर को 25 बीपीएस तक कम कर दिया, जबकि आरबीएनजेड ने अपनी नीतिगत दर को 50 बीपीएस तक कम करना जारी रखा। रिज़र्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने दिसंबर 2023 से विस्तारित विराम के बाद, फरवरी 2025 में अपनी प्रमुख दर को 25 बीपीएस घटाकर 4.10 प्रतिशत करते हुए अपनी नीतिगत नरमी चक्र शुरू किया। सेंट्रल बैंक ऑफ आइसलैंड ने अक्टूबर 2024 में अपनी प्रमुख दर को 25 बीपीएस और इसके बाद की सभी बैठकों में 50 बीपीएस कम करके नीति में नरमी बरती। हालांकि, मार्च में इसने अपनी गति को 25 बीपीएस तक कम कर दिया। स्वेरिज रिक्सबैंक ने अपनी नवंबर 2024 बैठक में नीतिगत दर को 50 बीपीएस तक कम किया, दिसंबर 2024 और जनवरी 2025 बैठक में प्रत्येक में 25 बीपीएस तक

कम किया और इसे मार्च बैठक में स्थिर रखा। स्विस् नेशनल बैंक ने भी दिसंबर की बैठक में अपनी नीतिगत दर में 50 बीपीएस और मार्च की बैठक में 25 बीपीएस की कटौती की। चेक नेशनल बैंक ने अपनी नवंबर 2024 और फरवरी 2025 की बैठकों में अपनी प्रमुख दर में 25 बीपीएस की कमी की, लेकिन दिसंबर 2024 और मार्च 2025 की बैठकों में इसे स्थिर रखा। नॉर्गेस बैंक ने अभी तक अपनी नीति सामान्यीकरण प्रक्रिया शुरू नहीं की है और अपनी वर्ष 2024 की चौथी तिमाही और वर्ष 2025 की प्रथम तिमाही बैठकों के दौरान यथास्थिति बनाए रखी है। बैंक ऑफ इज़राइल ने भी इन तिमाहियों के दौरान अपनी नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखा, हालांकि उसने जनवरी 2024 में एक बार अपनी नीतिगत दर में कटौती की थी। इसके विपरीत, बैंक ऑफ जापान (बीओजे) ने जुलाई में अपनी मुख्य दर को 15 बीपीएस बढ़ाने के बाद, इसके बाद 2024 में अपनी अगली बैठकों में विराम की अवधि का अनुसरण किया। हालांकि, जनवरी 2025 की बैठक में, बीओजे ने नीतिगत वृद्धि को फिर से शुरू किया, नीतिगत दर को 25 बीपीएस बढ़ाया और इसे अपनी मार्च बैठक में स्थिर रखा।

ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं में, बैंको सेंट्रल डो ब्रासिल, जिसने सितंबर 2024 में नीतिगत सख्ती चक्र शुरू किया था, ने नवंबर 2024 में अपनी सेलिक दर को 50 बीपीएस और दिसंबर, जनवरी और मार्च के महीने में प्रत्येक में 100 बीपीएस तक बढ़ाना जारी रखा। दक्षिण अफ्रीकी रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2024 की चौथी

तिमाही और वर्ष 2025 की प्रथम तिमाही में अपनी नवंबर 2024 और जनवरी 2025 की प्रत्येक बैठकों में अपनी रेपो दर में 25 बीपीएस की कटौती की और मार्च में विराम लाया। सितंबर में घोषित कई उपायों की निरंतरता में, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना (पीबीओसी) ने अक्टूबर 2024 में अपनी एक साल की लोन प्राइम रेट (एलपीआर) और पांच साल से अधिक की एलपीआर को 25 बीपीएस घटाकर क्रमशः 3.1 प्रतिशत और 3.6 प्रतिशत कर दिया। तब से, इसने बाद की सभी बैठकों में यथास्थिति बनाए रखी है, लेकिन अपनी वर्ष 2024 की चौथी तिमाही की बैठक में संकेत दिया है कि घरेलू और बाहरी आर्थिक स्थितियों के आधार पर आरक्षित निधि अपेक्षाएं अनुपात और ब्याज दरों में और कटौती की जा सकती है। बैंक ऑफ रूस (बीओआर) ने अक्टूबर में अपनी नीतिगत दर में 200 बीपीएस की वृद्धि की, लेकिन इसके बाद मुद्रास्फीतिकारक दबाव के बीच प्रमुख दर को 21.00 प्रतिशत पर बनाए रखा।

एशियाई ईएमई केंद्रीय बैंकों में, बैंक ऑफ थाईलैंड ने अक्टूबर 2024 में पहली बार अपनी बेंचमार्क दर को 25 बीपीएस तक कम कर दिया, इसके बाद दिसंबर में विराम दिया लेकिन फरवरी 2025 की बैठक में फिर से 25 बीपीएस कम कर दिया। बैंक इंडोनेशिया ने वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में अपनी प्रमुख दर पर यथास्थिति बनाए रखी, इसके बाद जनवरी में 25 बीपीएस की कटौती की और बाद की बैठकों में विराम दिया। फिलीपींस के केंद्रीय बैंक ने अक्टूबर 2024 से प्रत्येक दूसरी बैठक में अपनी नीतिगत दर में 25 बीपीएस की कटौती की, अगस्त 2024 में दर नरमी चक्र शुरू होने के बाद से संचयी रूप से अपनी प्रमुख दर में 75 बीपीएस की कमी की। लैटिन अमेरिका में, बैंको डी मैक्सिको ने वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में अपनी बेंचमार्क दर में 50 बीपीएस और वर्ष 2025 की प्रथम तिमाही में 1000 बीपीएस की कमी की। कोलंबिया के केंद्रीय बैंक ने धीरे-धीरे अक्टूबर 2024 में अपनी बेंचमार्क दर को 50 बीपीएस और दिसंबर में 25 बीपीएस तक कम करके मौद्रिक नीति में नरमी की अपनी गति को कम किया, इसके बाद 2025 में अब तक विराम लाया। चिली ने वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में अपनी प्रत्येक बैठक में अपनी नीतिगत दर को 25 बीपीएस कम कर दिया, लेकिन वर्ष 2025 की प्रथम तिमाही में विराम लाया। पेरू ने नवंबर और जनवरी की बैठकों में अपनी संदर्भ दर में 25 बीपीएस की कटौती की, लेकिन अक्टूबर, दिसंबर, फरवरी और मार्च की बैठकों में यथास्थिति बनाए रखी।

यूरोपीय ईएमई के बीच, हंगरी और पोलैंड वर्ष 2024 की चौथी तिमाही और वर्ष 2025 की पहली तिमाही के दौरान आयोजित सभी बैठकों में अपनी नीतिगत दर को अपरिवर्तित रखा (चार्ट V.6बी)।

V.4 वैश्विक वित्तीय बाजार

वैश्विक वित्तीय बाजार 2024 की अंतिम तिमाही से अस्थिर बने हुए हैं, यह स्थिति आर्थिक, राजनीतिक और वित्तीय बाजार अनिश्चितता में घिरी हुई है और आने वाली जानकारी के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं। तेजी से बदलते वृद्धि-मुद्रास्फीति परिदृश्य के बीच मौद्रिक नीति को लेकर उम्मीदों में बदलाव से बाजार धारणा काफी हद तक प्रभावित हुई है। आघात-सह आर्थिक संकेतकों, कर कटौती की प्रत्याशाएं और चीन में एआई संचालित रैली के बीच इक्विटी को पिछले एमपीआर से कम लाभ प्राप्त हुआ और अस्थिर बनी रही किन्तु जोखिम-विमुख रुझान और टैरिफ प्रेरित व्यवधानों के बीच इक्विटी व्यापक रूप से पीछे हट गए हैं। वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में, बॉण्ड प्रतिफल में वृद्धि हुई थी, और यूएस में राजनीतिक संक्रमण और भू-राजनीतिक विकास के आसपास की अनिश्चितता और भविष्य की आर्थिक नीतियों के साथ यूएस डॉलर का एक के पीछे एक अधिमूल्यन हुआ। वर्ष 2025 की प्रथम तिमाही में, हालांकि, इस तरह की बढ़ी हुई आर्थिक अनिश्चितता के प्रतिकूल प्रभाव उपभोक्ता और कॉर्पोरेट भावनाओं को प्रभावित करने और विकास की चिंताओं को प्रज्वलित करने के लिए सामने आए, जिससे अमेरिका में बॉण्ड प्रतिफल में गिरावट आई और अमेरिकी डॉलर का मूल्यहास हुआ। ईएमई वित्तीय बाजार विशेष रूप से इस तरह के झटकों और संबंधित अनिश्चितता से स्पिलओवर के प्रति संवेदनशील रहते हैं जो दुविधा को बढ़ाता है और मौद्रिक नीति के संचालन को जटिल बनाता है (बॉक्स V.1)। तदनुसार, ईएमई मुद्राओं में 2024 की चौथी तिमाही में मूल्यहास हुआ, हालांकि 2025 की शुरुआत में आंशिक रूप से बहाली हुई।

मॉर्गन स्टेनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) वर्ल्ड इंडेक्स के संदर्भ में इक्विटी बाजार 2024 की अंतिम तिमाही में अस्थिर रहे, वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में 1.2 प्रतिशत की गिरावट आई, जिसमें ईएमई इक्विटी मार्केट आई (चार्ट V.7ए) के सापेक्ष खराब प्रदर्शन कर रहे थे। वर्ष 2025 की प्रथम तिमाही में, इक्विटी मार्केट ने अपनी बिक्री को बढ़ाया किन्तु रिवर्सिंग ट्रेंड के साथ क्योंकि ईएमई ने अपने आई समकक्षों से बेहतर प्रदर्शन

किया। ई के बीच, यूएस एस एण्ड पी 500 अक्टूबर के अधिकांश भाग के लिए उत्साहित रहा, जो यूएस फेडरल ओपन मार्केट कमेटी (एफओएमसी) द्वारा दर-कटौती चक्र की असामान्य रूप से आक्रामक शुरुआत से प्रेरित था, इसके बाद चुनाव से संबंधित अनिश्चितता के बीच अशांति थी। बहरहाल, चुनाव परिणाम घोषित होने के पश्चात इन उम्मीदों से प्रेरित था कि आने वाले प्रशासन की नीतियों से विकास को बढ़ावा मिलेगा, कम कर होंगे और विनियमन को कम किया जाएगा जिससे नवंबर में अमेरिकी शेयर बाजार में उछाल आया। हालांकि, इक्विटी बाजारों में नवंबर

के मध्य में मजबूत आर्थिक आंकड़ों के जारी होने और फेड की सख्त टिप्पणी के बाद रुक-रुक कर गिरावट देखी गयी, जिससे मौद्रिक नीति प्रक्षेपवक्र में पुनः समायोजन हुआ। बाजार में गिरावट आयी, हालाँकि, एफओएमसी बैठक के बाद दिसंबर के उत्तरार्ध में 2025 के लिए कुछ दर में कटौती का संकेत दिया गया था। गिरावट जनवरी 2025 के मध्य तक बनी रही, क्योंकि दिसंबर 2025 तक एक या कोई दर कटौती नहीं होने की संभावना बढ़ गई (चार्ट V.8ए)। अमेरिकी असाधारणता और मजबूत कॉर्पोरेट आय पर आशावाद ने इक्विटी बाजार की रैली को जनवरी के

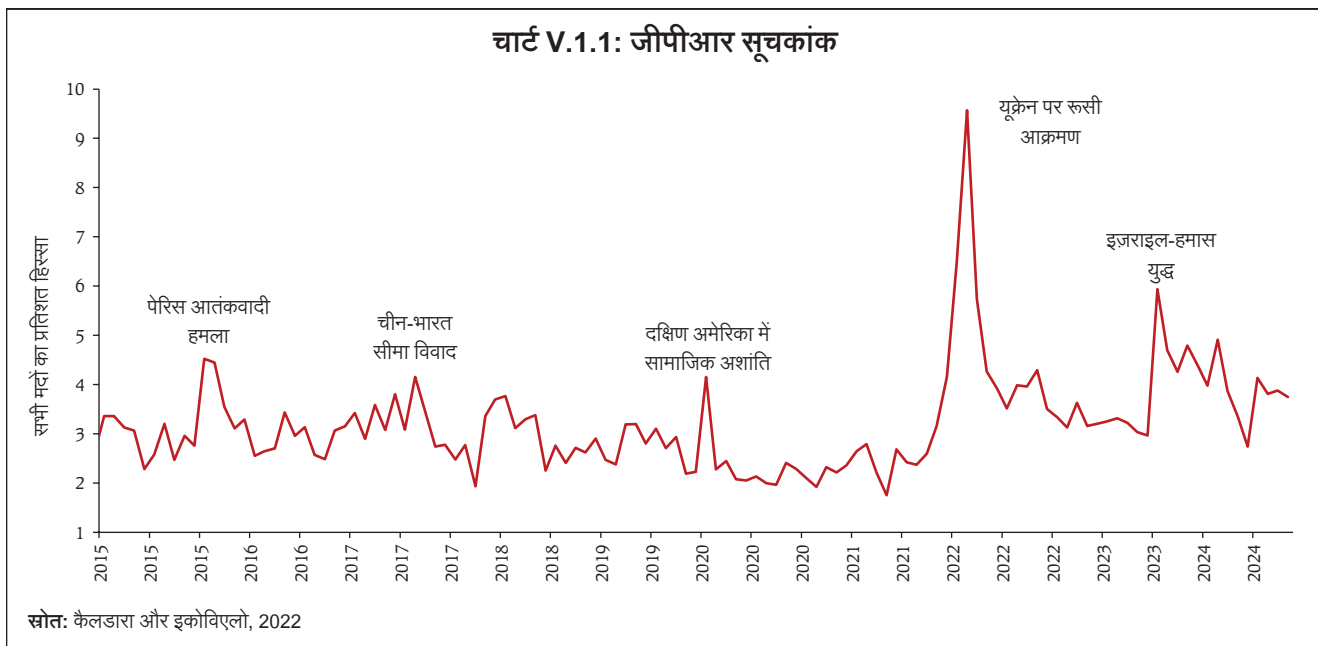
बॉक्स V.1: ईएमई के वित्तीय बाजारों पर भू-राजनीतिक स्पिलओवर आघात

भू-राजनीतिक तनाव और संघर्षों, युद्ध के साथ-साथ व्यापार युद्ध और संबंधित तनाव के कारण बढ़ी अनिश्चितताएं पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक परिदृश्य की एक परिभाषित विशेषता रही हैं, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके हानिकारक प्रभाव ने नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। इस तरह के प्रणालीगत भू-राजनीतिक आघात "फ्लाइंग होम इफेक्ट" (फेंग एट अल., 2022) को मजबूत करते हैं, जिससे खासकर ईएमई में वित्तीय प्रणाली कमजोर हो जाती है। भू-राजनीतिक घटनाएं विषम प्रभाव के साथ उन्नत और उभरते

बाजारों में (चोई, 2024) जोखिम विमुखता, निवेश पोर्टफोलियो में बदलाव, शेयर बाजार में मंदी, विनिमय दर मूल्यहास और बढ़ते जोखिम प्रीमियम (कैपोरेल और मेनला-अली, 2024) को तीव्र कर सकती हैं।

भू-राजनीतिक जोखिमों (जीपीआर) के आर्थिक प्रभावों का आकलन करने के लिए, जीपीआर इंडेक्स (चार्ट V.1.1), जो प्रमुख भू-राजनीतिक घटनाओं (केलडारा एण्ड लेकोविलो, 2022)⁷ से जुड़े एपिसोडिक उतार-चढ़ाव को कैच करता है, का उपयोग 10 वर्षों

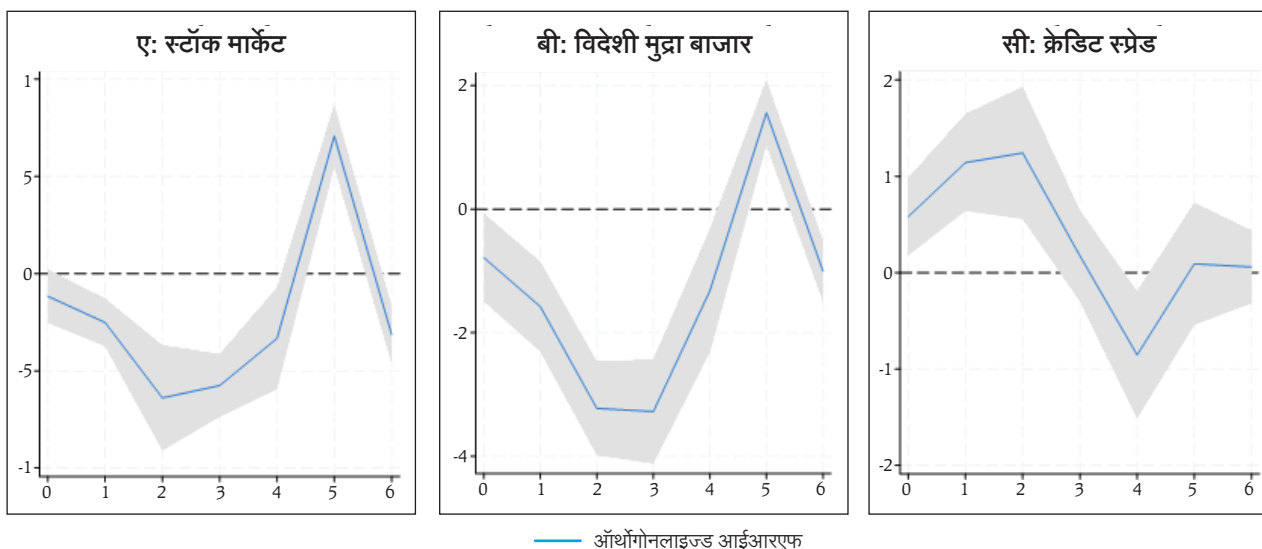
चार्ट V.1.1: जीपीआर सूचकांक



(जारी)

⁷ भू-राजनीतिक जोखिम सूचकांक 10 प्रमुख वैश्विक समाचार पत्रों में भू-राजनीतिक संबंधित सामग्री का विश्लेषण करके वैश्विक जोखिमों को कैच करता है। सूचकांक की गणना प्रत्येक महीने के लिए प्रत्येक समाचार पत्र में प्रतिकूल भू-राजनीतिक घटनाओं से संबंधित लेखों की संख्या (समाचार लेखों की कुल संख्या के हिस्से के रूप में) की गणना करके एक शब्दकोश-आधारित पद्धति का उपयोग करके की जाती है।

चार्ट V.1.2: जीपीआर आघात का प्रभाव



टिप्पणियाँ: ओआईआरएफ का छायांकित क्षेत्र न्यूई-वेस्ट मानक त्रुटियों का उपयोग करके 68 प्रतिशत विश्वास अंतराल का संकेत देता है। x-अक्ष महीनों को संदर्भित करते हैं और y-अक्ष प्रतिशत अंकों को संदर्भित करते हैं।

स्रोत: आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

(जनवरी 2015 से जनवरी 2025) तक फैले मासिक डेटा⁸ का उपयोग करके शेयर बाजारों, क्रेडिट स्प्रेड और ईएमई की विनिमय दरों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए किया जाता है। स्थानीय पूर्वानुमान मॉडल (जोर्ड, 2005) का उपयोग करते हुए, अगले छह महीनों के लिए प्रत्येक वित्तीय बाजार खंड में संचालन की भविष्यवाणी की जाती है। ऑर्थोगोनलाइज्ड इंपल्स रिस्पॉन्स फंक्शन (ओआईआरएफ) उचित नियंत्रण को नियोजित करने के बाद, ईएमई स्टॉक, बॉण्ड और मुद्रा बाजारों पर जीपीआर इंडेक्स में एक-इकाई वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन करते हैं (चार्ट V.1.2)।

परिणाम बताते हैं कि जीपीआर सूचकांक में एक प्रतिशत अंक की वृद्धि ईएमई वित्तीय स्थितियों में महत्वपूर्ण गिरावट की ओर ले जाती है, जिससे शेयर बाजारों में 0.25 प्रतिशत अंकों की गिरावट आती है, मुद्राओं में 0.16 प्रतिशत अंकों मूल्य ह्रास होता है, और क्रेडिट स्प्रेड पहले महीने में लगभग 1 आधार अंक तक बढ़ जाता है, जो उच्च भू-राजनीतिक अनिश्चितता के दौरान बढ़े हुए जोखिम प्रीमियम और परिणामतः सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन को दर्शाता है। दूसरे महीने के अंत तक बाजार के सभी तीनों खंडों में प्रभाव चरम पर है जिसमें शेयर बाजारों में 0.64 प्रतिशत की गिरावट, मुद्राओं में 0.32 प्रतिशत का मूल्य ह्रास और क्रेडिट स्प्रेड में लगभग 1.2 आधार अंकों की गिरावट हुई। इसके बाद इसका असर धीरे-धीरे खत्म हो जाता है। फिर भी, इस तरह के भू-राजनीतिक आघातों की बार-बार की घटनाएं, जो विभेदक प्रभाव के साथ अर्थव्यवस्था को

चोट करती है, ने जोखिमों को ऊंचा रखते हुए उथल-पुथल और अनिश्चितता को दृढ़ता प्रदान की है। निष्कर्ष मोटे तौर पर लैंग्स और कंट्रोल के लिए मजबूत हैं।

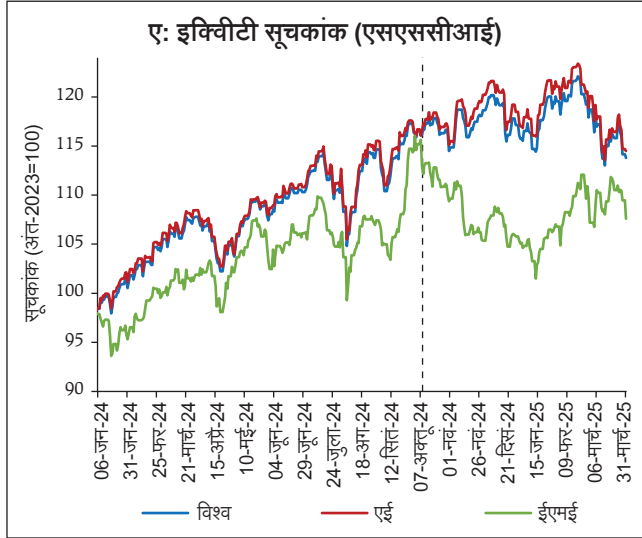
इस प्रकार, भू-राजनीतिक आघात ईएमई में वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिमों को आकार देते हैं, जो उनके मूल सिद्धांतों पर निर्माण करके और कमजोरियों को कम करके आघात-सहनीयता बढ़ाने के लिए रणनीतिक नीतिगत उपायों की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं।

संदर्भ:

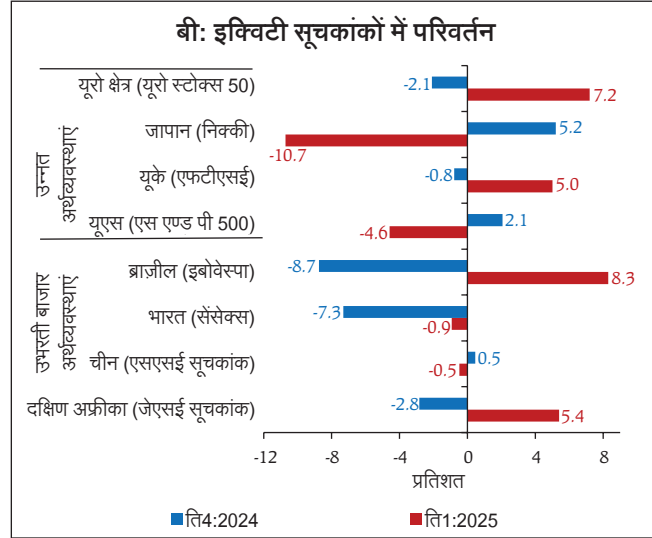
1. कालडारा, डी., एंड ईकाविलो, एम. (2022). "मेजरिंग जीयोपोलिटिकल रिस्क" *अमेरिकन ईकोनोमिक रिव्यू*, 2022
2. कैपरेल, जी.एम., एंड मेन्ला-ली, एफ. (2024). "जिओपोलिटिकल रिस्क एंड क्रॉस-बार्डर पोर्टफोलियो फ्लोज: ईफेक्ट्स एंड चैनल". सीईएसआईएफओ पेपर नं. 11337
3. चोई, एस., एंड हावेल, जे. (2025). "जिओपोलिटिकल रिस्क एंड यूएस फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट: ए टेल ऑफ अडवान्स्ड एंड इमर्जिंग मार्केट"। *जर्नल ऑफ इंटरनेशनल मनी एंड फाइनेंस*, 2025
4. फेंग, सी., हान, एल., विग्ने, एस., एंड जू, वाई. (2023). "जिओपोलिटिकल रिस्क एंड दि डायनामिक्स ऑफ इंटरनैशनल कैपिटल फ्लोज"। *जर्नल ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट्स, इंस्टीट्यूट्स एंड मनी*, जनवरी 2023
5. जोर्ड, ओ (2005). "एस्टीमेशन एंड इंफरेंस ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्सेज बाई लोकल प्रोजेक्शन्स"। *दि अमेरिकन ईकोनोमिक रिव्यू*, मार्च 2005

⁸ एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट्स करेंसी इंडेक्स और जेपी मॉर्गन ईएमबीआई ग्लोबल स्प्रेड का उपयोग क्रमशः इक्विटी मार्केट, विदेशी मुद्रा बाजार, क्रेडिट स्प्रेड का अनुसरण करने के लिए उभरते बाजारों में किया जाता है।

चार्ट V.7: इक्विटी बाजार



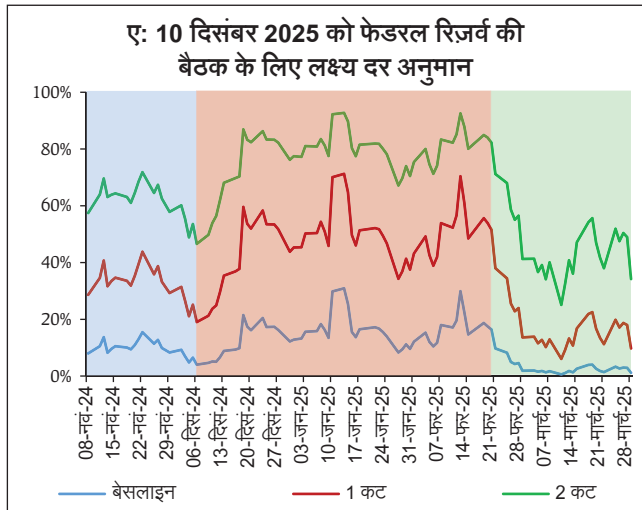
स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।



उत्तरार्ध में बढ़ावा दिया। फरवरी में सतर्कता बरतने के पश्चात मुद्रास्फीतिजनित मंदी की प्रारंभिक आशंकाओं और बढ़ती नीतिगत अनिश्चितताओं के बीच मार्च में बाजार में तेज गिरावट आई (चार्ट V.8बी)। कुल मिलाकर, यूएस एसएंडपी इंडेक्स वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के दौरान 2.1 प्रतिशत बढ़ा, लेकिन वर्ष 2025 की प्रथम तिमाही के दौरान 4.6 प्रतिशत कम लाभ प्राप्त हुआ।

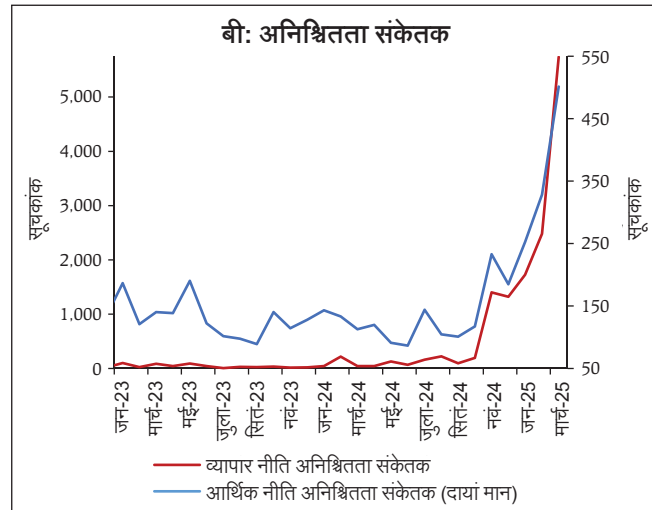
यूरोपीय शेयरों में वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में खराब प्रदर्शन किया क्योंकि टैरिफ की आशंका के कारण बाजार में गिरावट आई, लेकिन अमूर्त टैरिफ घोषणा, ईसीबी दर में कटौती की प्रत्याक्षाएं, रूस-यूक्रेन शांति सौदे की बढ़ती संभावनाओं, फ्रांस में एक मजबूत अर्थव्यवस्था जिसने 2025 में विवादास्पद बजट पारित किया और जर्मनी के राजकोषीय ओवरहॉल के बीच वर्ष 2025 की प्रथम तिमाही में अपने साथियों से बेहतर प्रदर्शन

चार्ट V.8: अनिश्चितता के स्रोत: मौद्रिक और आर्थिक नीति



स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

टिप्पणी: 1. चार्ट V.8ए में, लाल छायांकित क्षेत्र, कम हो रही विविध दरों में कटौती प्रत्याशाओं की अवधि का प्रतिनिधित्व करता है।
2. चार्ट 8ए में, बेसलाइन यूएस की नीति दर में कोई बदलाव नहीं को संदर्भित करता है, जबकि दर में कटौती की गति 25 बीपीएस मानी गई है।



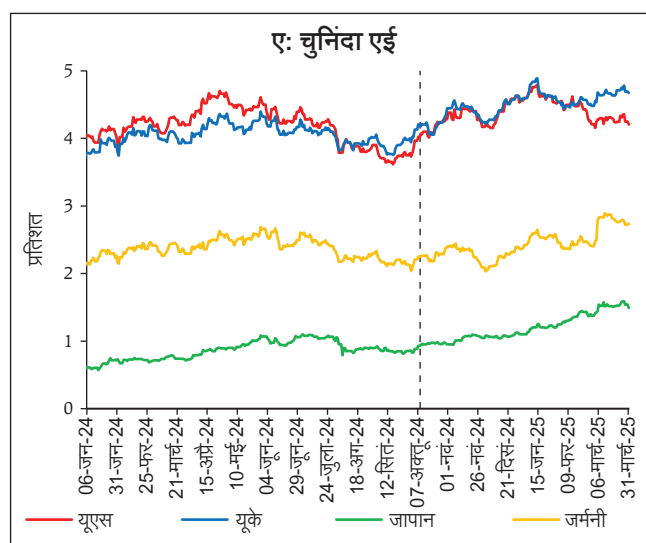
किया है। यूके के स्टॉक इंडेक्स ने व्यापक रूप से यूरोपीय बाजारों का अनुसरण किया, हालांकि छोटी मात्रा में वर्ष 2025 की पहली तिमाही में अब तक अच्छा प्रदर्शन किया जो बीओई द्वारा दर में कटौती की उच्च संभावनाओं द्वारा समर्थित है। जापानी बाजार ने वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में यूएस बाजार से बेहतर प्रदर्शन किया क्योंकि 2024 के अंत में येन की कमजोरी ने लार्ज-कैप निर्यातकों के लिए आय दृष्टिकोण को मजबूत किया, लेकिन 2025 में पीछे हट गया क्योंकि बीओजे द्वारा नीति सामान्यीकरण के कारण येन का अधिमूल्यन हुआ। वैश्विक संकेतों और व्यापार नीति अनिश्चितता का अनुसरण करते हुए चीन को छोड़कर, ईएमई इक्विटी ने वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में गिरावट आई (चार्ट V.7बी)। 2025 में अब तक, ईएमई इक्विटी मार्केट ने मिश्रित ट्रेंड प्रदर्शित किए क्योंकि मुद्रा मूल्यहास दबावों को कम करते हुए लाभ प्राप्त हुआ, लेकिन बढ़ती अनिश्चितता और मूर्खतापूर्ण कारकों के बीच वैश्विक संकेतों के बाद गिरावट आई।

अवरुद्ध मुद्रास्फीति और बढ़ती आर्थिक नीति अनिश्चितता के बीच ब्याज दरों के एक मजबूत भविष्य के मार्ग की उम्मीदों के जवाब में वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के बाद से अधिकांश प्रमुख आई में सॉवरेन बॉण्ड प्रतिफल में वृद्धि हुई है। अमेरिका में, बॉण्ड प्रतिफल में वर्ष 2024 की चौथी तिमाही में व्यापक रूप से वृद्धि हुई है, जिसमें 10-वर्ष की ट्रेजरी प्रतिफल 79 बीपीएस तक बढ़ गई है, क्योंकि पहले 100 बीपीएस की कटौती के मुकाबले 2025 के अंत तक डॉट प्लॉट प्रोजेक्शन में संशोधन के कारण

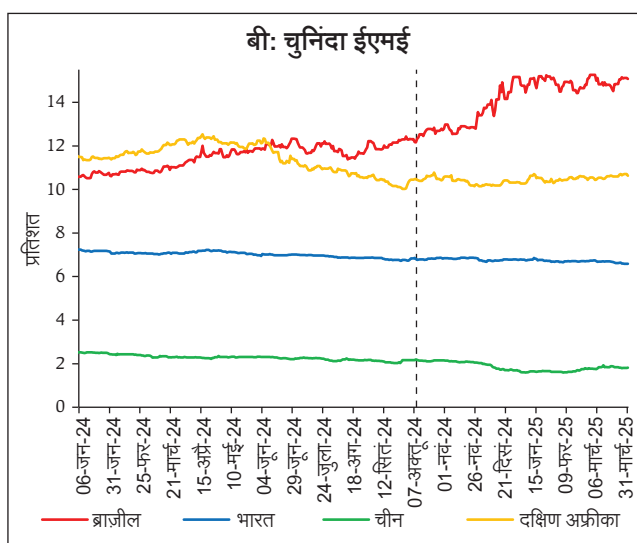
50 बीपीएस दर कटौती की। वर्ष 2025 की पहली तिमाही में, हालांकि, वृद्धि में कमी, बाजार में गिरावट और नीतिगत दरों और राजकोषीय घाटे की बदलती धारणाओं के डर से प्रेरित प्रतिफल में कमी आई। अक्टूबर 2024 से मार्च 2025 के बीच यूके 10-वर्षीय बॉण्ड प्रतिफल में व्यापक रूप से वृद्धि हुई। जर्मन 10-वर्ष की प्रतिफल में वर्ष 2024 की चौथी तिमाही से व्यापक रूप से वृद्धि हो गई और बड़े पैमाने पर राजकोषीय पैकेज की घोषणा के बाद मार्च में और अधिक वृद्धि हो गई। 10-वर्षीय जापानी सरकारी बॉण्ड प्रतिफल अक्टूबर से 63 बीपीएस तक मजबूत हो गई है, जो बीओजे की नीति सामान्यीकरण द्वारा संचालित है, जिसमें इसके आर्थिक दृष्टिकोण पर आगे की दर वृद्धि पर इसका रुख शामिल है (चार्ट V.9ए)। अक्टूबर 2024 – मार्च 2025 के दौरान, कई ईएमई में बॉण्ड प्रतिफल ने उर्ध्वगामी उतार-चढ़ाव दिखाया है, जो घरेलू राजकोषीय स्थितियों और वैश्विक कारकों (चार्ट V.9बी) द्वारा संचालित है। इसके विपरीत, चीन में और मौद्रिक नीति में नरमी की प्रत्याशाओं के बीच बॉण्ड प्रतिफल में थोड़ी कमी आई, जबकि भारत की बॉण्ड प्रतिफल इस अवधि के दौरान अपेक्षाकृत स्थिर रही।

मुद्रा बाजार में, अक्टूबर 2024 के बीच अमेरिकी डॉलर में 9.1 प्रतिशत की मूल्यवृद्धि हुई और 13 जनवरी, 2025 को अपने चरम पर रहा - 10 नवंबर, 2022 के बाद का उच्चतम स्तर - और यह नए अमेरिकी प्रशासन की नीतियों से उत्पन्न कई कारकों द्वारा संचालित था। निवेशकों ने व्यापार और टैरिफ नीतियों में बदलाव की प्रत्याशा में अपने पोर्टफोलियो को तेजी

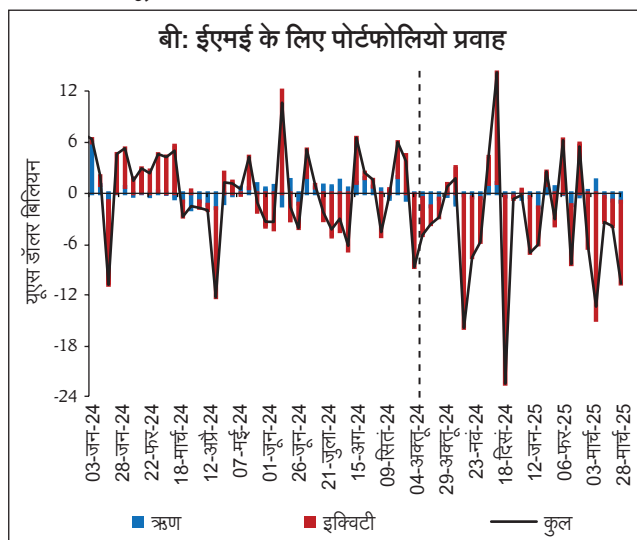
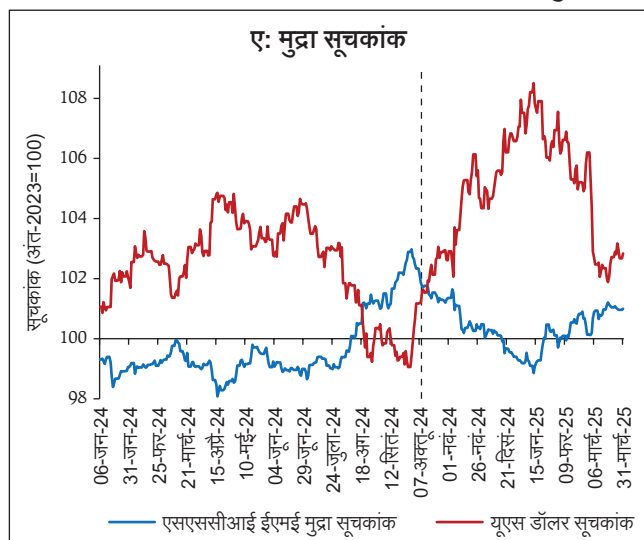
चार्ट V.9: 10-वर्षीय सरकारी बॉण्ड प्रतिफल



स्रोत: ब्लूमबर्ग



चार्ट V.10: मुद्रा उतार-चढ़ाव और पूंजी प्रवाह



स्रोत: ब्लूमबर्ग; और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान (आईआईएफ); और आरबीआई स्टाफ अनुमान।

से समायोजित किया, क्योंकि टैरिफ के मुद्रास्फीतिकारक प्रभाव ने यूएस फेड को दर में कटौती पर अधिक सतर्क रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया। इसी समय, बढ़े हुए व्यापार तनावों ने वैश्विक आर्थिक विकास दृष्टिकोण को धूमिल किया और सख्त आब्रजन नीतियों ने मुद्रास्फीति की चिंताओं को उठाया जिससे सभी अमेरिकी परिसंपत्तियों के पक्ष में पोर्टफोलियो पुनर्संतुलन के लिए परिणत हो गए। जनवरी के मध्य से, हालांकि, डॉलर अपने बहु-वर्षीय उच्चतम से पीछे हट गया है जो कमजोर विकास गति, बढ़ी हुई नीतिगत अनिश्चितता और अन्य आर्थिक नीतियों का गैर-कार्यान्वयन को इंगित करती है जिन्होंने पहले मूल्यवृद्धि दबावों को बढ़ावा दिया था (चार्ट V.10A)। इन उतार-चढ़ावों को ईएमई मुद्राओं में प्रतिबिंबित किया गया था, हालांकि पूंजी बहिर्वाह (चार्ट V.10B) के कारण उतार-चढ़ाव को सीमित कर दिया गया था। एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट करेंसी इंडेक्स वर्ष 2024 की चौथी तिमाही (3.6 प्रतिशत) में तेजी से मूल्यहास हुआ, लेकिन वर्ष 2025 की प्रथम तिमाही (26 मार्च, 2025 तक) में 1.7 प्रतिशत बढ़ गया।

V.5 निष्कर्ष

संरक्षणवादी टैरिफ के तेज होने और नीतिगत अनिश्चितता के कारण वैश्विक विकास को काफी प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका द्वारा व्यापक टैरिफ घोषणा और अन्य देशों द्वारा इसे परिणामी प्रतिशोध के रूप में लेने से एक पूर्ण विकसित व्यापार युद्ध में बढ़ने का जोखिम बन गया है जो संभावित रूप से मौजूदा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करेगा। ये आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान, अवरुद्ध अवरुद्ध प्रक्रिया को रोकने में और बाधा डाल सकते हैं और इस प्रकार यह मौद्रिक नीति को सुलभ बनाने की प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं को (ईएमई) को बढ़ा हुआ पूंजी बहिर्वाह, जोखिम प्रीमियम में वृद्धि और गहरी हो रही बाहरी कमजोरियों सहित काफी नकारात्मक जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, हाल ही में वित्तीय बाजार में गिरावट सिर्फ एक पूर्ववलोकन हो सकती है, जो बदलती व्यापार नीतियों के व्यापक प्रभावों को प्रदर्शित करती है।

भाषण

24वें फिमडा-पीडीएआई वार्षिक सम्मेलन में मुख्य भाषण
श्री संजय मल्होत्रा

01 अप्रैल 2025 को आरबीआई@90 स्मरणोत्सव समारोह में स्वागत भाषण
श्री संजय मल्होत्रा

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के निजी क्षेत्र सहयोग मंच पर संबोधन
श्री संजय मल्होत्रा

साझा दृष्टिकोण, साझी जिम्मेदारी – एनबीएफसी को मजबूत बनाना
श्री स्वामीनाथन जे

24वें फिमडा-पीडीएआई वार्षिक सम्मेलन में मुख्य भाषण*

श्री संजय मल्होत्रा

बाली में 24वें फिमडा-पीडीएआई वार्षिक सम्मेलन में उपस्थित होना मेरे लिए खुशी की बात है। यह एक ऐसा द्वीप है जिसकी भारत के साथ गहरी और समृद्ध विरासत है, तथा जिसके साथ सदियों पुराने सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संबंध हैं।

पिछले साल वैश्विक स्तर पर वित्तीय बाजारों के संबंध में बहुत सारी घटनाएं घटीं। शुरुआती आशावाद यह था कि वैश्विक केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में समकालिक ढील दिए जाने के लिए तैयार हैं, और बढ़ी हुई मुद्रास्फीति को नियंत्रण में लाने के अंतिम चरण तक पहुंच रहे हैं। लेकिन हाल के महीनों में अभूतपूर्व अनिश्चितता का माहौल बना रहा। इस पृष्ठभूमि में, यह सम्मेलन वित्तीय बाजार के प्रतिभागियों के लिए विचारों के उपयोगी आदान-प्रदान और जीवंत चर्चाओं के लिए एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। मैं फिमडा और पीडीएआई के आयोजकों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे सम्मेलन में भाग लेने और अपने विचार साझा करने का अवसर दिया।

भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय बाजारों ने उल्लेखनीय लचीलापन प्रदर्शित किया है, जबकि वे अनिश्चित और अस्थिर वैश्विक वातावरण की अनिश्चितताओं से अछूते नहीं हैं। मैंने हाल ही में, मौद्रिक नीति की घोषणा के बाद, अपने वक्तव्य में उल्लेख किया था कि हमारे घरेलू संवृद्धि-मुद्रास्फीति संतुलन में काफी सुधार हुआ है। हेडलाइन मुद्रास्फीति में निर्णायक सुधार हुआ है, और उसके वित्त वर्ष 26 में 4 प्रतिशत के लक्ष्य के अनुरूप रहने का अनुमान है लेकिन वैश्विक अनिश्चितताएँ और मौसम अवरोध मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण के लिए जोखिम पैदा करते हैं। भले ही हमने वित्त वर्ष 26 के लिए 6.5 प्रतिशत का कुछ कम वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है, भारत अभी भी सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। फिर भी, यह हमारी आकांक्षा से बहुत कम है। हमने दो बार रेपो दरों में कमी

की है और पर्याप्त चलनिधि उपलब्ध कराई है। तेजी से बदल रहे हालात को देखते हुए, विशेष रूप से वैश्विक मोर्चे पर, हम आर्थिक दृष्टिकोण की लगातार निगरानी और आकलन कर रहे हैं। हम हमेशा की तरह नीतिगत मोर्चे पर अपने कार्यों में चुस्त और सक्रिय रहेंगे।

भारतीय वित्तीय बाजारों की बात करें तो, विदेशी मुद्रा, जी-सेक, मुद्रा बाज़ार सहित सभी बाजार खंड काफी हद तक स्थिर रहे हैं। हालांकि कुछ महीने पहले रुपया थोड़ा दबाव में आया था, उसके बाद उसने बेहतर प्रदर्शन किया और खोया हुआ कुछ मूल्य वापस पा लिया। पूंजी बहिर्वाह में तेजी आई और इक्विटी बाजारों में बड़ी गिरावट देखी गई। यह प्रवृत्ति अधिकांश उभरते बाजारों में भी देखी गई। हालाँकि, सरकारी प्रतिभूति बाजार पूरे साल स्थिर रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र और राज्य सरकारों की कुल ₹24.7 लाख करोड़ की सकल बाजार उधारी सफल रही। केंद्र सरकार के लिए उधार लेने की लागत, जो वित्त वर्ष 24 में 7.24 प्रतिशत थी, 28 आधार अंकों की कमी के साथ वित्त वर्ष 25 में 6.96 प्रतिशत हो गई। जी-सेक में द्वितीयक बाजार गहरा और सक्रिय बना रहा, जिसे आंशिक रूप से वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में भारत के शामिल होने से मदद मिली।

इस बीच, हम भारत में परिवर्तन के एक रोमांचक चरण की दहलीज पर खड़े हैं - एक ऐसा परिवर्तन जिसने कई चुनौतियों का सामना किया है, लेकिन जो रोमांचक अवसरों से भरा हुआ है, जिसमें हमारा जनसांख्यिकीय लाभांश, हमारी कुशल जनशक्ति और समाज को बदलने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने और उसका उपयोग करने की हमारी क्षमता शामिल है। इस पृष्ठभूमि में, इस वर्ष के सम्मेलन का विषय - "भारत के वित्तीय बाजार: बदलती परिस्थितियों की चुनौतियाँ" समयानुकूल और प्रासंगिक है।

वित्तीय बाजार – पृष्ठभूमि और आगे की राह

यदि भारत को बदलती परिस्थितियों से निपटना है और अपनी आकांक्षाओं को पूरा करना है, तो वित्तीय बाजारों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। पूंजी जुटाने और वित्तीय परिसंपत्तियों के व्यापार के लिए बाजार के रूप में वित्तीय बाजार आर्थिक संवृद्धि के प्रमुख प्रवर्तक हैं। वित्तीय बाजारों का अस्तित्व सदियों से रहा है और समय के साथ-साथ उनमें

* 18 अप्रैल 2025 को बाली में दिया गया संबोधन।

परिवर्तन भी हुए हैं। वित्तीय बाजारों की जटिलताओं ने सदियों से मानवता को भ्रमित किया है। इतिहास के सबसे महान बुद्धिजीवियों से एक, सर आइजैक न्यूटन ने साउथ सी बबल में अपना भाग्य खोने के बाद कहा था, जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, कि "मैं आकाशीय पिंडों की गति की गणना कर सकता हूँ लेकिन लोगों के पागलपन की नहीं।"¹ संचालन की अखंडता और विश्वास को बनाए रखना किसी भी वित्तीय बाजार का मौलिक गुण होता है। ऐसे में बेंजामिन ग्राहम का कथन याद आता है – अल्पावधि में बाजार एक वोटिंग मशीन की तरह है, लेकिन दीर्घावधि में हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वह आकलन का एक माध्यम हो

भारत में वित्तीय बाजार एक विनियमित ढांचे के भीतर विकसित हुए हैं, जो बदलते विनियामक परिवेश और दृष्टिकोणों के अनुकूल हैं। 20वीं सदी के अंतिम दशक तक भारत के वित्तीय बाजार एक रूढ़िवादी वृहद-वित्तीय परिवेश में विकसित हुए। 1990 के दशक से मजबूत और कार्यकुशल वित्तीय बाजारों की नींव रखी जाने लगी। ब्याज दरों को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया। विनिमय दर को मुक्त कर दिया गया। चालू खाते में रुपया पूरी तरह से परिवर्तनीय हो गया। पूंजी खाते को उत्तरोत्तर उदार बनाया गया। इसके बाद के वर्षों में, जब भारत में वित्तीय बाजार विकसित हुए, तब भी व्यापक दृष्टिकोण समष्टि आर्थिक और वित्तीय स्थिरता की प्राथमिकता पर केंद्रित था। तथापि, हाल के वर्षों में, हमारी बढ़ती और अधिक परस्पर जुड़ी अर्थव्यवस्था ने वित्तीय बाजारों के महत्व को बढ़ा दिया है।

इस पृष्ठभूमि में, हाल के वर्षों में, रिजर्व बैंक के प्रयासों ने वित्तीय बाजारों को विकसित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया है। यहां मौजूद श्रोता हाल के वर्षों में किए गए विभिन्न विनियामक परिवर्तनों से अच्छी तरह वाकिफ हैं, इसलिए उस विवरण को दोहराने के बजाय, मैं इस बात पर ध्यान केंद्रित करूंगा कि हमने क्या हासिल किया है और अभी क्या काम बाकी है।

¹ ब्रुनमीयर, एम., और रीस, आर. (2023). "ए क्रेश कोर्स ऑन क्राइसेस: मैक्रोइकोनॉमिक कोन्सेप्ट्स फॉर रन-अप्स, कोलेपसेस, एंड रीकवरीज"।

वित्तीय बाजार: हालिया रुझान

पिछले कुछ वर्षों में हमने महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे हैं जिन्होंने हमारे बाजारों को एक गतिशील और लचीली ताकत में बदल दिया है। मैं इसे स्पष्ट करने के लिए कुछ आँकड़े देना चाहूंगा:

- एक दिवसीय मुद्रा बाजार में औसत दैनिक मात्रा में 80 प्रतिशत की वृद्धि, जो 2020 के लगभग ₹3 लाख करोड़ से बढ़कर 2024 में ₹5.4 लाख करोड़ से अधिक हो गई;
- इसी अवधि में सरकारी प्रतिभूति बाजार में औसत दैनिक कारोबार 40 प्रतिशत बढ़कर 66,000 करोड़ रुपये हो गया;
- विदेशी मुद्रा बाजार में औसत दैनिक कारोबार 2020 के 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर से लगभग दोगुना होकर 2024 में 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया;
- नोशनल आउटस्टैंडिंग ब्याज दर डेरिवेटिव में 2015 के लगभग ₹18 लाख करोड़ से 622 प्रतिशत की वृद्धि होकर वह वित्त वर्ष 25 के अंत में ₹130 लाख करोड़ से अधिक हो गई;
- एमआईबीओआर ओआईएस (सबसे अधिक तरल डेरिवेटिव उत्पाद) में औसत दैनिक ग्राहक मात्रा में 2,233 प्रतिशत की वृद्धि, 2015 के लगभग ₹600 करोड़ से बढ़कर 2024 में लगभग ₹14,000 करोड़ हो गई;
- पिछले दशक में एफएक्स फॉरवर्ड और स्वैप में औसत दैनिक मात्रा में 73 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 26 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक हो गई है; तथा
- हाल के महीनों में घरेलू बैंकों द्वारा नॉन-डिलीवरेबल फॉरवर्ड (एनडीएफ) कारोबार की दैनिक मात्रा लगभग 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर रही, जबकि 1 जून 2020 को जब पहली बार इसकी अनुमति दी गई थी, तब यह मात्रा नगण्य थी।

बाजार में प्रतिभागियों की संख्या में भी समान रूप से वृद्धि हुई है:

- कई एकल प्राथमिक व्यापारियों को अधिकृत डीलर लाइसेंस दिए गए। ब्याज दर और क्रेडिट डेरिवेटिव

बाजारों के लिए पात्र मार्केट-मेकर्स की सूची में विस्तार किया गया है, हालांकि इसमें रुचि कम दिखाई देती है।

- पिछले दशक में, ब्याज दर डेरिवेटिव के लिए सीसीआईएल ट्रेड रिपॉजिटरी में पंजीकृत ग्राहकों की संख्या लगभग 3,233 प्रतिशत बढ़कर लगभग 300 से 10,000 हो गई है और विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव के लिए 3,854 प्रतिशत बढ़कर 2,200 से 87,000 हो गई है। तथापि, यह हो सकता है कि सभी ग्राहक सक्रिय भागीदार न हों।
- जी-सेक बाजार में गैर-निवासियों की भागीदारी भी बढ़ी है, खास तौर पर वैश्विक बॉण्ड सूचकांकों में शामिल किए जाने के बाद। जी-सेक में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी अब 3.2 प्रतिशत है, जबकि अगस्त 2023 में पहली बार शामिल किए जाने की घोषणा से पहले यह हिस्सेदारी 1.7 प्रतिशत थी। डेरिवेटिव बाजारों में भी गैर-निवासियों की भागीदारी बढ़ रही है।

वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। रेपो और सरकारी प्रतिभूति बाजार मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं, और केंद्रीय रूप से समाशोधन किया जाता है। अधिकांश विदेशी मुद्रा स्पॉट और फॉरवर्ड लेनदेन के साथ-साथ अधिकांश एमआईबीओआर और संशोधित एमआईएफओआर आधारित ब्याज दर स्वैप भी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर खरीदे-बेचे जाते हैं और केंद्रीय रूप से समाशोधित किए जाते हैं। सभी ओटीसी डेरिवेटिव की सूचना एक ट्रेड रिपॉजिटरी को दी जाती है।

उत्पाद विविधता भी बढ़ रही है। हालांकि साधारण पारंपरिक उत्पाद डेरिवेटिव बाजारों पर हावी हैं, ब्याज दर और विदेशी मुद्रा डेरिवेटिव, दोनों में अनुकूलित उत्पादों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो विभिन्न हितधारकों की विविध हेजिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए गए हैं। हाल ही में सरकारी प्रतिभूतियों में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स को भी अनुमति दी गई है। संरचित उत्पादों, विशेष रूप से असममित भुगतान वाले उत्पादों के प्रति दृष्टिकोण सतर्क और जिम्मेदारीपूर्ण ही है। हम उसी दृष्टिकोण को जारी रखेंगे।

हमने अपने देश में वित्तीय बाजारों के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है। राष्ट्र की उभरती जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रेरित होकर और लगातार उभरे संकटों से सीख लेकर, हमारे बाजार परिपक्व और उन्नत हुए हैं। हमारा बाजार बुनियादी ढांचा अत्याधुनिक है। पारदर्शिता का स्तर दुनिया में सर्वश्रेष्ठ के बराबर है। सरकारी प्रतिभूतियों, विदेशी मुद्रा और प्रमुख डेरिवेटिव उत्पादों के बाजार अधिकांश समान अर्थव्यवस्थाओं, और यहां तक कि कई उन्नत देशों के सापेक्ष अत्यधिक तरल हैं। हाल के विनियामक सुधारों के बाद उत्पाद और प्रतिभागी विविधता बढ़ी है, और ऑनशोर और ऑफशोर बाजारों का एकीकरण बढ़ा है।

यह प्रगति आपके समर्पण, नवाचार और सहयोगात्मक प्रयासों का प्रमाण है। मैं इस संयुक्त प्रयास में आपके योगदान के लिए आप सभी को बधाई देता हूँ। आज, हमारे पास सक्रिय वित्तीय बाजार हैं जो न केवल भारत के आर्थिक विकास को बल देते हैं बल्कि वैश्विक आत्मविश्वास को भी प्रेरित करते हैं। लेकिन अभी और काम करना बाकी है। मैं इनमें से कुछ क्षेत्रों पर अपने विचार संक्षेप में बताना चाहूँगा।

मुद्दे और चिंताएँ

सरकारी प्रतिभूति बाजार

जी-सेक बाजार को वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक तरल बाजारों में से एक माना जाता है, जैसा कि कम बोली-मांग अंतर (लो बिड-आस्क स्प्रेड) और कम प्रभाव लागत से प्रमाणित होता है। हालाँकि, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों का टर्नओवर अनुपात (प्रतिभूतियों के बकाया स्टॉक बनाम वार्षिक टर्नओवर के रूप में मापा जाता है) मामूली रूप से एक (1) से थोड़ा अधिक रहा है। यदि कम तरल राज्य सरकार प्रतिभूतियों (एसजीएस) को शामिल किया जाता है, तो अनुपात एक (1) से नीचे चला जाता है। चलनिधि कुछ प्रतिभूतियों में केंद्रित बनी हुई है, जो लंबी परिपक्वता के लिए कम हो रही है। द्वितीयक बाजार व्यापार में बैंकों और प्राथमिक डीलरों का वर्चस्व है, जिसमें कई बड़े संस्थागत निवेशक "खरीदें और रखें" निवेशक बने हुए हैं। जी-सेक में 3,000 से अधिक संस्थागत निवेशकों में से, शीर्ष दस प्रतिभागियों ने 2024 के दौरान कुल टर्नओवर का एक तिहाई योगदान दिया।

रिज़र्व बैंक का एक निरंतर प्रयास सरकारी प्रतिभूति बाजार में खुदरा भागीदारी को बढ़ाना रहा है। नवंबर 2021 में 'आरबीआई रिटेल डायरेक्ट' सुविधा का आरंभ इस दिशा में एक पहल थी। हाल ही में रिटेल डायरेक्ट के लिए एक मोबाइल ऐप उपलब्ध कराया गया है। आरबीआई ने हाल ही में सेबी-पंजीकृत गैर-बैंक स्टॉकब्रोकर के खुदरा ग्राहकों को एनडीएस-ओएम के प्रयोग की अनुमति दी है। यह सब यह सुनिश्चित करने के लिए है कि ऐसे निवेशकों के लिए पर्याप्त द्वितीयक बाजार चलनिधि उपलब्ध हो ताकि वे उचित कीमतों पर बाजार में भाग ले सकें। सहकारी बैंकों, पेंशन और भविष्य निधि जैसे प्रतिभागियों के लिए भी चलनिधि और मूल्य निर्धारण में सुधार की आवश्यकता है, जिनके सौदे छोटे आकार के हैं। बैंकों और प्राथमिक डीलरों को इस दिशा में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है।

मुद्रा बाजार

देश में मुद्रा बाजार लगभग पूरी तरह से एक दिवसीय (ओवरनाइट) बने हुए हैं। कई वर्षों से आवधिक मुद्रा बाजार (टर्म मनी मार्केट) विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, अंतर-बैंक देनदारियों पर वैधानिक पूर्व-अधिकार को हटाकर, और अलग-अलग परिपक्वताओं के टर्म रेपो/रिवर्स रेपो का संचालन करके, विशेष रूप से 3 दिनों से तीन महीने के प्रकार में आवधिक बाजार तैयार किए जा सकते हैं, जिनकी अभी कमी है। हालाँकि एक दिवसीय सूचकांकित स्वैप दरों और ट्रेजरी बिलों पर प्रतिफल जैसे विकल्पों का उपयोग किया जा रहा है, ब्याज दर उत्पादों, जिसमें ऋण भी शामिल हैं, के मूल्य निर्धारण के लिए बेंचमार्क के रूप में कार्य करने के लिए जोखिम-मुक्त आवधिक संरचना के निर्माण की आवश्यकता बनी हुई है।

कॉल मनी मार्केट - जिसकी दर मौद्रिक नीति के लिए परिचालन लक्ष्य है - में घटती चलनिधि पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। यह बाजार एमआईबीओआर की मजबूती के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो ब्याज दर डेरिवेटिव बाजार के लिए बेंचमार्क है। चिंता का विषय यह भी है कि विभिन्न मुद्रा बाजार दरों के बीच कई बार विषमताएं पैदा होती हैं – जैसे कि जिस दर पर रिज़र्व बैंक चलनिधि उपलब्ध कराता है, कॉल मनी दर, बाजार रेपो दर और टीआरईपीएस दर। रिज़र्व बैंक के चलनिधि उपायों का व्यापक बाजार में तुरंत और निर्बाध रूप से प्रसारण

सुनिश्चित करने के लिए बैंकों द्वारा अधिक सक्रियता से कार्य करने की आवश्यकता है क्योंकि वे रिज़र्व बैंक की चलनिधि सुविधाओं, कॉल मनी मार्केट और रेपो मार्केट तक पहुंच रखने वाली एकमात्र संस्थाएं हैं।

विदेशी मुद्रा बाजार (एफएक्स)

विदेशी मुद्रा बाजार काफी हद तक तरल हैं और बोली-मांग का अंतर कम है। इस बाजार में पारदर्शिता बढ़ रही है। सभी एफएक्स डेरिवेटिव की रिपोर्ट ट्रेड रिपॉजिटरी को दी जाती है और नकद, टीओएम और स्पॉट लेनदेन की रिपोर्टिंग शुरू हो गई है।² एफएक्स स्पॉट लेनदेन के एक बड़े हिस्से का कारोबार इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म (ईटीपी) पर किया जाता है। फॉरवर्ड लेनदेन के लिए अधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसे लेनदेन द्विपक्षीय रूप से किए जाने को प्राथमिकता दी जाती है। ईटीपी पर ट्रेडिंग करने से पारदर्शिता और बाजार दक्षता बढ़ती है। हम ईटीपी पर किए जाने वाले लेनदेन का हिस्सा बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे।

जनवरी 2020 में बैंकों को ऑनशोर मार्केट समय से परे विदेशी मुद्रा में सौदा करने की अनुमति दी गई थी। हालांकि यह मात्रा अधिक नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि बैंक ऑनशोर मार्केट समय के पूर्व और पश्चात, दोनों समय लेन-देन करते हैं। हालाँकि, इस तरह का व्यापार मुख्य रूप से घरेलू विदेशी मुद्रा बाजार समय से ठीक पहले और बाद की अवधि तक ही सीमित है, जो यह दर्शाता है कि हम अभी भी एक वास्तविक 24*5 बाजार से कुछ दूरी पर हैं।

ग्राहकों के साथ उचित व्यवहार और छोटे तथा कम जानकारी रखने वाले ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता पर हमारा ध्यान है। इस मामले में और भी बहुत कुछ किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। छोटे और बड़े ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा बाजारों में मूल्य निर्धारण में भिन्नताएं, परिचालन संबंधी बातों द्वारा उचित ठहराए जाने से, कहीं अधिक व्यापक हैं। विदेशी मुद्रा लेनदेन करने के लिए एक

² "विदेशी मुद्रा लेनदेन की ट्रेड रिपोजिटरी में रिपोर्टिंग" पर दिनांक 8 नवंबर 2024 की अधिसूचना आरबीआई/2024-25/89/एफएमआरडी. एमआईओडी.07/02.05.002/2024-25 के अनुसार, प्राधिकृत डीलरों ने 10 फरवरी 2025 से सीसीआईएल की ट्रेड रिपोजिटरी में उनके द्वारा किए गए सभी अंतर-बैंक विदेशी मुद्रा अनुबंधों की जानकारी देना शुरू कर दिया है।

पारदर्शी प्लेटफॉर्म हैं - एफएक्स-रिटेल जिसे अभी तक अपेक्षित रूप से अपनाया नहीं गया है। हमारी जानकारी यह है कि यह काफी हद तक बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को यह प्लेटफॉर्म देने में अनिच्छा के कारण है। खुदरा ग्राहकों के लिए मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए नियम मौजूद हैं, जिसमें ग्राहकों को मध्य-बाजार या अंतर-बैंक दर का खुलासा करने का अधिदेश शामिल है। एक उद्योग के रूप में, बाजार निर्माताओं को आत्मनिरीक्षण करने और यह आकलन करने की आवश्यकता है कि वे किस तरह से इन विनियामक और प्रत्ययी आदेशों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं।

रिज़र्व बैंक ने हाल ही में घोषणा की है कि 'भारत कनेक्ट प्लेटफॉर्म' के माध्यम से भी एफएक्स रिटेल तक पहुंच प्रदान की जाएगी। पहले चरण में आम लोगों द्वारा अमेरिकी डॉलर की खरीद को सुविधाजनक बनाने के लिए एक पायलट योजना बनाई गई है। इसके बाद, प्राप्त अनुभव के आधार पर इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। मैं अधिकृत डीलरों सहित सभी वित्तीय बाजार प्रतिभागियों से अपील करता हूँ कि वे इस प्रायोगिक प्रयोग को सुचारु रूप से और सफलतापूर्वक लागू करने में अपना पूरा सहयोग दें।

हम यह भी पाते हैं कि बैंकिंग माध्यमों का इस्तेमाल अनधिकृत एफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर गतिविधियों के लिए किया जा रहा है। इस संबंध में बैंकों द्वारा अधिक सतर्कता बरतने, और ऐसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के खतरों के बारे में अपने ग्राहकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए मजबूत प्रयास किए जाने की आवश्यकता है³।

डेरिवेटिव बाजार

हालांकि डेरिवेटिव बाजार का आकार बढ़ रहा है, सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में यह छोटा है। आकार के अलावा अन्य मुद्दे भी हैं। उदाहरण के लिए, ब्याज दर डेरिवेटिव बाजारों में चलनिधि एक या दो उत्पादों तक सीमित है। पिछले कई वर्षों में किए गए कई प्रयासों के बावजूद ब्याज दर वायदा बाजार या क्रेडिट डेरिवेटिव बाजार में अभी भी तेजी नहीं आई है। बाजार निर्माण अभी भी बैंकों तक ही सीमित है, चाहे वह विदेशी मुद्रा हो या ब्याज दर डेरिवेटिव। हालांकि यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि भारतीय वित्तीय प्रणाली में बैंकों का वर्चस्व है। व्यापक

³ भारतीय रिज़र्व बैंक, अपनी ओर से, अनधिकृत विदेशी मुद्रा व्यापार प्लेटफॉर्मों की अलर्ट सूची को नियमित रूप से अद्यतन कर रहा है तथा उपयोगकर्ताओं को शिक्षित करने के लिए जागरूकता अभियान चला रहा है।

तौर पर विविध सहभागियों की उपस्थिति से बाजार की पैठ, विचारों की विविधता बढ़ सकती है और अधिक प्रतिस्पर्धा तथा दक्षता को बढ़ावा मिल सकता है। इस बीच, विभिन्न हितधारकों द्वारा जोखिमों के अधिक सक्रिय प्रबंधन की आवश्यकता तथा अन्य मोर्चों पर घटित गतिविधियों ने इन बाजारों का अधिक विकसित होना अनिवार्य बना दिया है।

इस संदर्भ में, आप जानते हैं कि बैंक ऋणों की बढ़ती संख्या बाहरी बेंचमार्क, खासकर पॉलिसी रेपो दर से निर्धारित हो रही है। एक दिवसीय दर पर आधारित स्वैप बाजार ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए सबसे उपयुक्त नहीं हो सकता, खासकर जब इसका उपयोग अपेक्षित मौद्रिक नीति परिवर्तन पर विचार व्यक्त करने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि एमआईबीओआर बेंचमार्क समिति ने पाया, अधिकांश विकसित देशों में कम से कम दो प्रमुख बेंचमार्क हैं - एक का उपयोग नीति दर के भावी परिवर्तन पर विचार करने के लिए किया जाता है और दूसरे का वास्तविक क्षेत्र (रियल सेक्टर) द्वारा जोखिमों को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। कम से कम, संबंधित आधार जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए आधार स्वैप साधनों के लिए एक बाजार विकसित किए जाने की आवश्यकता है। समिति ने रक्षित एकदिवसीय बाजार के आधार पर एक 'रक्षित एकदिवसीय रुपया दर' (एसओआरआर) विकसित किए जाने की भी सिफारिश की। मैं समझता हूँ कि फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड (एफबीआईएल) बेंचमार्क विकसित कर रहा है। भविष्य में डेरिवेटिव के आधार पर एसओआरआर विकसित करने की आवश्यकता होगी।

समापन टिप्पणी

आज, वित्तीय बाजार वैश्विक और घरेलू चुनौतियों, अभूतपूर्व अवसरों और बढ़ती लोक अपेक्षाओं के बीच परिवर्तन के मुहाने पर खड़े हैं। जब इस तरह के परिवर्तन होते हैं, तो उसके कई गतिशील पहलू होते हैं जिन्हें एक पहली के टुकड़ों की तरह एक साथ जोड़ने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसमें कई हितधारक होते हैं जिनकी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ होती हैं। फिमडा और पीडीएआई भारतीय वित्तीय बाजारों के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। कई मायनों में, हालांकि औपचारिक रूप से नहीं, फिमडा ने देश के निश्चित आय और मुद्रा बाजारों में एक स्व-नियामक संगठन (एसआरओ) के रूप में काम किया है। मुझे जानकारी है कि फिमडा ने रिज़र्व

बैंक द्वारा जारी 'वित्तीय बाजार एसआरओ मान्यता ढांचा' के तहत एसआरओ के रूप में मान्यता के लिए आवेदन किया है। हालांकि हम आवेदन की जांच कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि फिमडा और पीडीएआई भारत में वित्तीय बाजारों को और विकसित करने में हमें सहयोग देना जारी रखेंगे।

भारत उभरती वैश्विक व्यवस्था में अपना उचित स्थान लेने के लिए आगे बढ़ रहा है और इसमें वित्तीय बाजारों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होगी। वित्तीय बाजारों को देश की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए कुशल और लागत-प्रभावी वित्तपोषण की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। उन्हें वैश्विक और घरेलू उतार-चढ़ावों के बीच आर्थिक एजेंटों को अपने जोखिमों को अधिक कुशलता से प्रबंधित करने में सक्षम बनाने की आवश्यकता होगी। उन्हें आगे की योजना बनाते समय प्रत्येक हितधारक के लिए निष्पक्षता सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता

होगी और खुद को मजबूत, समुत्थानशील और भविष्य के लिए तैयार करना होगा।

अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं आपको वित्त जैसे विषय के उन जटिल और गतिशील आयामों पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूँ जो न केवल हमारे बाजारों को बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की नींव को भी आकार देते हैं। पारदर्शिता, विश्वास और नवाचार द्वारा संचालित इन आयामों के लिए प्रत्येक घटक - इस कमरे में मौजूद प्रत्येक प्रतिभागी - को प्रयोजनपूर्वक और ईमानदारी के साथ अपनी भूमिका निभाने की आवश्यकता है। आइए हम जोखिमों को समझदारी से प्रबंधित करने, विकास को जिम्मेदारी के साथ बढ़ावा देने और हमारे वित्तीय बाजारों की अखंडता सुनिश्चित करने की साझा प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ें।

धन्यवाद।

01 अप्रैल 2025 को आरबीआई@90 स्मरणोत्सव समारोह में स्वागत भाषण*

श्री संजय मल्होत्रा

भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी, महाराष्ट्र के माननीय राज्यपाल जी, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केन्द्रीय संचार मंत्री जी, महाराष्ट्र के माननीय उपमुख्यमंत्री जी, विशिष्ट अतिथिगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण तथा रिज़र्व बैंक के मेरे पूर्व एवं वर्तमान सहकर्मीगण।

भारतीय रिज़र्व बैंक की 90वीं वर्षगांठ के इस महत्वपूर्ण अवसर पर आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हम भारत के माननीय राष्ट्रपति की भागीदारी से बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। उनकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस अवसर के महत्व को बहुत बढ़ा दिया है और हमें बहुत प्रोत्साहित किया है। मैं उनके व्यस्त कार्यक्रम से हमारे लिए समय निकालने के लिए उनका आभारी हूँ। मैं इस समारोह में उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं महाराष्ट्र के महामहिम राज्यपाल, माननीय केन्द्रीय संचार मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्रियों का भी स्वागत करता हूँ। मैं अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों और अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ यहाँ उपस्थित होने के लिए समय निकाला है।

नब्बे साल पहले, भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थापना भारत की मौद्रिक और वित्तीय स्थिरता के संरक्षक के रूप में की गई थी। इन नौ दशकों में, हम बदलते आर्थिक परिदृश्य के साथ तालमेल बिठाते हुए विकसित हुए हैं और साथ ही अपने देश की आर्थिक प्रगति और जनता के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं।

ठीक एक साल पहले, जब हम 90वें वर्ष में प्रवेश कर रहे थे, हमने माननीय प्रधानमंत्री की उपस्थिति में उद्घाटन समारोह के साथ उत्सव की शुरुआत की। पूरे वर्ष के दौरान, हमने उभरती

प्रौद्योगिकियों और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना जैसे विषयों पर कई उच्च-स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किए। वैश्विक दक्षिण (ग्लोबल साउथ) के केंद्रीय बैंकों के सम्मेलन ने वैश्विक समुदाय में भारत के विचार नेतृत्व को मजबूत किया और आगे की चुनौतियों और अवसरों के बारे में हमारी समझ को गहरा किया।

जनता से जुड़ने के लिए, हमने आरबीआई@90 क्विज़ जैसी राष्ट्रव्यापी पहल की मेजबानी की, जिसमें देश भर के छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हमने एक कला प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें भारत की कलात्मक परंपराओं की रचनात्मकता और विरासत का जश्र मनाया गया। खेल आयोजन, टाउन हॉल मीटिंग, वृक्षारोपण अभियान और रक्तदान शिविरों ने हमारे कर्मचारियों और समुदायों को एक साथ लाया।

इन सभी आयोजनों ने सहयोग और सेवा की भावना को मजबूत किया जो रिज़र्व बैंक को परिभाषित करती है। हमने अपने अतीत का जश्र मनाया और भविष्य के लिए अपनी जिम्मेदारी की पुष्टि की। हमने अपनी उपलब्धियों और समृद्ध विरासत पर विचार किया और एक मजबूत, अधिक स्थिर और समावेशी वित्तीय प्रणाली पर निर्मित 'विकसित भारत' के स्वप्न को साकार करने के लिए खुद को फिर से प्रतिबद्ध किया।

इस मील के पत्थर को चिह्नित करते हुए, हम मानते हैं कि रिज़र्व बैंक की भूमिका अपने प्रारंभिक अधिदेश से कहीं अधिक विस्तारित हो गई है। आज, हम परंपरा और परिवर्तन के संगम पर खड़े हैं, जहाँ मूल्य स्थिरता, वित्तीय स्थिरता और आर्थिक विकास की अनिवार्यताएँ तेजी से हो रही तकनीकी प्रगति, वैश्विक अनिश्चितताओं, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और बढ़ती सार्वजनिक अपेक्षाओं के साथ जुड़ती हैं।

अगला दशक हमारी अर्थव्यवस्था के वित्तीय ढांचे को आकार देने में महत्वपूर्ण होगा। हम वित्तीय समावेशन का विस्तार करने और उसे गहरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम ग्राहक सेवाओं में निरंतर सुधार और ग्राहक सुरक्षा को मजबूत करने की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। वित्तीय स्थिरता और दक्षता के हितों को संतुलित करके हमारे विनियामक ढांचे

* 01 अप्रैल, 2025 को आरबीआई@90 स्मरणोत्सव समारोह में भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर, श्री संजय मल्होत्रा का स्वागत भाषण।

को अनुकूलित करने का हमारा प्रयास होगा। हम प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष का समर्थन करना जारी रखेंगे। हम सतर्क, अनुकूलनशील और दूरदर्शी बने रहेंगे। हम सभी हितधारकों - सरकारों और वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों, आदि के साथ प्रभावी रूप से सहयोग करना जारी रखेंगे। हम वित्तीय प्रणाली की पहुँच का विस्तार कर, इसकी दक्षता को बढ़ाकर और एक विकसित आर्थिक परिदृश्य में इसकी सुदृढ़ता को मजबूत कर, इसे बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।

भले ही हम नई तकनीक और आधुनिक विनियामक दृष्टिकोण को अपना रहे हों, लेकिन हमारे मूल मूल्य - ईमानदारी, पारदर्शिता और सार्वजनिक सेवा के प्रति प्रतिबद्धता - हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। भारत के लोगों का रिज़र्व बैंक पर जो भरोसा है, वह हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। हम इसे बनाए रखने और आने वाले वर्षों में इसे और मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। यह संस्था राष्ट्र की है। हम लोगों, वित्तीय प्रणाली

और अर्थव्यवस्था के हितों की सेवा करने के अटूट संकल्प से प्रेरित होकर हर निर्णय लेते रहेंगे।

जैसा कि हम इस वर्ष भर चलने वाले उत्सव का समापन कर रहे हैं और अपने शताब्दी दशक में कदम रख रहे हैं, हम ऐसा आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और स्पष्ट दृष्टि के साथ कर रहे हैं। आगे की यात्रा निरंतर अनुकूलन और चपलता; नई सोच और नवोन्मेष; सहयोग और समन्वय; और उत्कृष्टता और पूर्णता के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता की मांग करेगी। हम, रिज़र्व बैंक में, भारत की आर्थिक प्रगति में सक्रिय और उत्साह से योगदान देने के लिए सभी चुनौतियों का सामना करने और सभी अवसरों को भुनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

इन शब्दों के साथ, मैं पुनः भारत की महामहिम राष्ट्रपति तथा अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों और अतिथियों का इस स्मारक समारोह में स्वागत करता हूँ।

धन्यवाद। जय हिंद।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के निजी क्षेत्र सहयोग मंच पर संबोधन, 26 मार्च, 2025, मुंबई*

श्री संजय मल्होत्रा

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के निजी क्षेत्र सहयोग मंच (पीएससीएफ) 2025 में शामिल होना मेरे लिए खुशी की बात है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि यह पहली बार है जब यह फोरम भारत में आयोजित किया जा रहा है। हमें यह अवसर देने के लिए मैं एफएटीएफ का आभार व्यक्त करता हूँ। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में सचिव के रूप में अपनी पिछली भूमिका में, मुझे पिछले वर्ष हमारे पारस्परिक मूल्यांकन के दौरान एफएटीएफ के साथ निकटता से जुड़े रहने का अवसर मिला था।

एफएटीएफ

एफएटीएफ जो अवैध वित्तपोषण से निपटने के लिए मानक निर्धारण निकाय है, 1989 में अपनी स्थापना के बाद से एक लंबा सफर तय कर चुका है। पिछले कुछ वर्षों में, यह केवल 16 सदस्यों वाले संगठन से 40 सदस्यों वाले वैश्विक मंच में विकसित हुआ है। एफएटीएफ-शैली के क्षेत्रीय निकायों के माध्यम से¹, इसकी पहुंच और भी व्यापक हुई है। एफएटीएफ द्वारा विकसित मानकों का उपयोग 200 से अधिक न्यायालयों द्वारा, धन शोधन [मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल)], आतंकवाद का वित्तपोषण (टीएफ) और 'प्रसार वित्तपोषण' का प्रतिरोध करने के लिए किया जाता है। इन मानकों के कार्यान्वयन ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली को मजबूत करने और दुनिया को एक सुरक्षित स्थान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

एफएटीएफ द्वारा भारत का पारस्परिक मूल्यांकन

भारत, धन शोधन निवारण [एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एमएल)] और आतंकवाद वित्तपोषण का प्रतिरोध करने (सीएफटी)

* वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) के निजी क्षेत्र सहयोगी फोरम में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा का संबोधन, 26 मार्च 2025, मुंबई।

¹ अपने 40 सदस्यों के अतिरिक्त, एफएटीएफ को नौ एफएटीएफ-शैली क्षेत्रीय निकायों (एफएसआरबी) का भी समर्थन प्राप्त है।

को बहुत महत्व देता है। पिछले साल, एफएटीएफ द्वारा भारत का पारस्परिक मूल्यांकन किया गया था। भारत को 'नियमित अनुवर्ती' श्रेणी में रखा गया था, यह एक ऐसा सम्मान है जो केवल कुछ अन्य जी20 देशों को ही प्राप्त है²। यह हमारे प्रभावी एएमएल और सीएफटी ढांचे की स्वीकृति है। यह एएमएल और सीएफटी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह हमारे देश में वित्तीय प्रणाली के निर्माण और निरंतर सुधार एवं मजबूती के कई वर्षों का परिणाम है।

यह भारत सरकार के नेतृत्व में सभी हितधारकों के सहयोगात्मक प्रयासों के कारण संभव हुआ, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की वित्तीय संस्थाएं और नामित गैर-वित्तीय व्यवसाय और पेशे, विनियामक और राज्य सरकारें शामिल हैं। वित्तीय प्रणालियों को सुरक्षित रखने में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। समुचित सावधानी प्रक्रियाओं को लागू करने, मजबूत जोखिम आकलन करने, लेन-देन की निगरानी करने और संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट करने में उनकी भूमिका वित्तीय प्रणाली के दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है। वे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करते हैं और अवैध वित्त तंत्र (नेटवर्क) को नष्ट करने में सरकारी एजेंसियों की मदद करते हैं।

मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी वित्तीय प्रणाली की अखंडता की सुरक्षा के लिए आधार बनाती है। भारत में, हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हितधारकों के बीच घनिष्ठ सहयोग के महत्व को पहचानते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, भारत में वित्तीय प्रणाली के एक बड़े हिस्से के नियामक और पर्यवेक्षक के रूप में, एफएटीएफ की सिफारिशों के अनुरूप, वित्तीय प्रणाली के इस हिस्से में एक मजबूत एएमएल और सीएफटी ढांचे के कार्यान्वयन के निर्माण और सुनिश्चित करने की दिशा में लगन और लगातार काम कर रहा है। रिजर्व बैंक ने विभिन्न हितधारकों के साथ सहयोग और समन्वय बढ़ाने के लिए कई पहल की हैं। इसी तरह, वित्तीय आसूचना इकाई (एफआईयू)-भारत ने भी घनिष्ठ संपर्क और सहयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए सार्वजनिक-निजी सहयोग मंच – एफपीएसी³ की स्थापना

² <https://ptib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2056773>

³ एएमएल/सीएफटी (एफपीएसी) में भागीदारी के लिए एफआईयू-भारत पहल, एक सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) ढांचा, जनवरी 2022 में शुरू किया गया था, ताकि एएमएल/सीएफटी डोमेन में एफआईयू-भारत और अन्य हितधारकों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाया जा सके।

की है। इसने एआरआईएफसी⁴ की स्थापना का भी समर्थन किया है जो निजी क्षेत्र की रिपोर्टिंग संस्थाओं के बीच सहयोग करने के लिए एक अंतर-क्षेत्रीय (क्रॉस सेक्टरल) फोरम है।

इन सहयोगात्मक प्रयासों का ही नतीजा है कि हम एक मजबूत और सुदृढ़ एएमएल और सीएफटी ढांचा बनाने और प्रदर्शित करने में सक्षम हुए हैं। मैं सभी हितधारकों, विशेष रूप से वित्तीय क्षेत्र में विनियमित संस्थाओं के साथ-साथ नामित गैर-वित्तीय व्यवसायों और व्यवसायों को सफल पारस्परिक मूल्यांकन के लिए बधाई देता हूँ।

हालाँकि, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रीय और वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के लिए धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण से खतरे लगातार बढ़ रहे हैं और अधिक जटिल होते जा रहे हैं। यह मुख्य रूप से तकनीकी प्रगति के कारण है। इन खतरों का प्रभावी ढंग से प्रतिरोध करने के लिए हमें विभिन्न हितधारकों - सरकारी एजेंसियों, सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में वित्तीय संस्थाओं, नागरिक समाज और अन्य के बीच घनिष्ठ सहयोग जारी रखने की आवश्यकता है।

आपसी मूल्यांकन प्रक्रिया कठोर और विस्तृत थी। इसने हमें अपनी ताकत के बारे में मूल्यवान जानकारी प्रदान करते हुए, हमारे एएमएल-सीएफटी ढांचे में सुधार के कुछ क्षेत्रों पर प्रकाश डाला है। हम इस मूल्यांकन की संस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने और उनका प्रतिरोध करने हेतु अपनी वित्तीय प्रणाली को और मजबूत बनाने के लिए दृढ़ हैं। हम इस दिशा में निरंतर सुधार के लिए प्रयास जारी रखेंगे।

पीएससीएफ 2025 की कार्यसूची (एजेंडा) से संबंधित कुछ विचार

मुझे बताया गया है कि कल के सत्र बहुत ही रोचक थे और उनमें जीवंत चर्चा हुई। आज और कल की कार्यसूची को देखते हुए, मुझे विश्वास है कि समकालीन विषयों, जैसे - एएमएल-सीएफटी परिदृश्य, वित्तीय समावेशन और मानव चैनल, पर्यवेक्षण के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण, डिजिटलीकरण और सूचना साझाकरण, लाभकारी स्वामित्व और 'प्रसार वित्तपोषण' (घातक

⁴ एएमएल/सीएफटी के लिए भारत में रिपोर्टिंग संस्थाओं का गठबंधन (एआरआईएफसी) भारत में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित रिपोर्टिंग संस्थाओं के बीच एक निजी-निजी भागीदारी पहल है, जिसका उद्देश्य सूचना साझाकरण, ज्ञान उत्पादों का विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम और प्रमाणन को सुविधाजनक बनाना है।

हथियारों के विकास और प्रसार को वित्तपोषण) का प्रतिरोध करना, जैसे विषयों पर विचार-विमर्श भी रोमांचक होगा। मैं इन क्षेत्रों पर फोरम के लिए अपने कुछ विचारों को रेखांकित करना चाहता हूँ।

सबसे पहले, जबकि हम सभी अपने वित्तीय सिस्टम को धन शोधन और आतंकी वित्तपोषण के खिलाफ सुरक्षित और संरक्षित बनाना जारी रखते हैं, हमें नीति निर्माताओं के रूप में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे उपाय अति उत्साही न हों और वैध गतिविधियों और निवेशों को बाधित न करें। आप इस बात की सराहना करेंगे कि कई कानून और नियम, जिनमें से प्रत्येक की अपनी-अपनी बारीकियाँ हैं, विनियमित वित्तीय सेवा प्रदाताओं पर अनुपालन का उच्च स्तर का बोझ डालते हैं। यह एएमएल-सीएफटी के संदर्भ में भी प्रासंगिक है। इसलिए, हमें ऐसे कानून और नियम बनाने की ज़रूरत है जो सर्जिकल सटीकता के साथ केवल गैर-कानूनी और अवैध को लक्षित करें, बजाय इसके कि उन्हें कुंद औजारों के रूप में इस्तेमाल किया जाए जो अनजाने में ईमानदार लोगों को भी चोट पहुँचाते हैं।

इसी तरह, कानूनी ढांचे और विनियमों को लागू करते समय भी, हमें व्यक्तियों और व्यवसायों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखना होगा। इस संबंध में जोखिम-आधारित दृष्टिकोण की अनुशंसा की जाती है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि यह अनुपालन बोझ को कम करने की दिशा में एक कदम आगे है। हमें यह समझना चाहिए कि यह अंतिम समाधान नहीं है, क्योंकि कोई भी जोखिम-आधारित दृष्टिकोण परिपूर्ण नहीं होता; इसमें गलत सकारात्मक और गलत नकारात्मक परिणाम होंगे। हमें अपने जोखिम मूल्यांकन मॉडल को मजबूत बनाने के लिए इसे निरंतर परिष्कृत और बेहतर बनाते रहने की आवश्यकता है।

इन सुधारों को करने के लिए, हमें अपने डेटा की गुणवत्ता में सुधार करने और उभरती हुई तकनीकों का उपयोग करने की आवश्यकता है। इससे लेन-देन की स्क्रीनिंग और संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाने में मदद मिलेगी, जिससे गलत सकारात्मक और गलत नकारात्मक कम होंगे। ग्राहक व्यवहार में बदलाव और उत्पादों और सेवाओं के विकास के परिणामस्वरूप धन शोधन के क्षेत्र में विकसित परिदृश्य को देखते हुए, हमें एएमएल जोखिम मूल्यांकन ढांचे को लगातार बढ़ाने और एएमएल और अन्य जोखिमों के प्रभाव का आकलन करने के बाद नियमित

आधार पर उचित प्रणाली संवर्द्धन करने की आवश्यकता है। वित्तीय दुनिया में नवीनतम रुझानों और घटनाक्रमों को समझने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिसका अपराधियों द्वारा इसतेमाल किया जा सकता है और तदनुसार ऐसे उपकरण और सक्षम ढांचे विकसित किए जाने चाहिए जो हमें संदिग्ध लेनदेन और गतिविधियों का जल्द पता लगाने और अग्रसक्रिय कार्रवाई करने की अनुमति दें। नए तकनीकी उपकरणों और मॉडलों को अपनाने के साथ, मुझे यकीन है कि एएमएल-सीएफटी जोखिम आकलन को और भी बेहतर बनाया जा सकता है। मैं, आप सभी से एएमएल-सीएफटी जोखिमों की पहचान, शमन और पर्यवेक्षण में सर्वोत्तम प्रथाओं पर चर्चा करने और उन्हें साझा करने का आग्रह करूंगा। इससे न केवल विनियमित संस्थाओं पर अनुपालन का बोझ कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि पर्यवेक्षी संसाधनों का इष्टतम आबंटन भी होगा।

जबकि भारत ने वित्तीय समावेशन में उल्लेखनीय प्रगति की है, फिर भी हमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम इसे व्यापक और गहन बनाते रहें। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एफएटीएफ मानकों पर चर्चाओं में वित्तीय समावेशन और वित्तीय एकीकरण को संरेखित करने में आने वाली चुनौती का समाधान खोजने की आवश्यकता है, विशेष रूप से विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि विनियमन वित्तीय समावेशन में अनपेक्षित अवरोध पैदा न करें। हमें समुचित सावधानी बाध्यताओं को पूरा करते समय ग्राहक अधिकारों और सुविधा के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता है। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि मैक्सिकन प्रेसीडेंसी के तहत अनुशंसा 1 और उसकी व्याख्यात्मक टिप्पणी में संशोधन वित्तीय अखंडता से समझौता किए बिना वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का इरादा रखते हैं। मानवी सहायता का समर्थन करने वाले वित्तीय चैनलों की पहुँच बढ़ाने के लिए भी इसी तरह के दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

हाल के वर्षों में, डिजिटलीकरण का उपयोग ग्राहक ऑनबोर्डिंग और ग्राहक समुचित सावधानी (सीडीडी) प्रक्रियाओं में तेजी से किया जा रहा है। भारत ने इस संबंध में भी बड़ी प्रगति की है। डिजिटल केवाईसी और वीडियो केवाईसी इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। एक अरब से अधिक व्यक्तियों का रिकॉर्ड रखने वाली सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड्स रजिस्ट्री (सीकेवाईसीआर) इसका एक और उदाहरण है, जिसमें न केवल ग्राहकों के लिए बल्कि

विनियमित संस्थाओं के लिए भी ग्राहक पहचान और समुचित सावधानी पूरी करने को आसान और निर्बाध बनाकर ग्राहक ऑनबोर्डिंग के एक नए युग की शुरुआत करने की क्षमता है। मुझे बताया गया है कि ग्राहक समुचित सावधानी के क्षेत्र में तकनीकी समाधानों की स्थिति पर विचार-विमर्श करने के लिए एक अलग सत्र है। ये चर्चा सीकेवाईसीआर की क्षमता और उपयोगिता को कई गुना बढ़ाने में सहायक हो सकती हैं।

इसके अलावा, सीडीडी की प्रक्रिया के दौरान, रिपोर्टिंग संस्थाएँ ग्राहकों से बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करती हैं। इसके अलावा, वित्तीय आसूचना इकाइयों, विधि प्रवर्तन एजेंसियों और डेटा रजिस्ट्री के साथ जानकारी साझा करने की आवश्यकताएँ हैं, जिससे डेटा सुरक्षा और सहमति के बिना जानकारी साझा करने के बारे में चिंताएँ पैदा होती हैं। भारत ने हाल ही में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया है। विभिन्न न्यायालयों के अनुभवों के आदान-प्रदान से हमें अपने देश में कानून को बेहतर ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी।

एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र जिस पर चर्चा की आवश्यकता है, वह है 'यात्रा नियम'। आज की दुनिया में, तेज भुगतान प्रणालियाँ वित्तीय पहुँच में क्रांति ला रही हैं और वित्तीय समावेशन को गहन बना रही हैं। भारत जैसे विकासशील देशों ने डिजिटल भुगतान को सुलभ, किफायती और सुविधाजनक बनाने में बहुत प्रगति की है। जहाँ कार्ड नेटवर्क ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं को भुगतान प्रणालियों को बेहतर बनाने में मदद की है, वहीं तेज भुगतान प्रणालियों ने उभरते बाज़ार और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (ईएमडीई) को इस क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद की है। हमने कुछ देशों के साथ तेज भुगतान प्रणालियों का उपयोग करके सीमा पार भुगतान को भी सक्षम बनाया है। हम 2027 तक समावेशी सीमापार भुगतान की दिशा में जी20 रोडमैप के अगले चरण के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में काम करना जारी रखेंगे। इस संदर्भ में, एफएटीएफ अनुशंसा 16 (आर.16), जिसे 'यात्रा नियम' के रूप में जाना जाता है, पर चल रही चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है। सीमापार भुगतान को तेज़, सस्ता, अधिक पारदर्शी और अधिक समावेशी बनाने के जी20 उद्देश्य को पूरा करने के लिए, उनकी सुरक्षा और सुरक्षा को बनाए रखते हुए, 'यात्रा नियम' को प्रौद्योगिकी-तटस्थ बनाना वांछनीय होगा।

अंत में, 'प्रसार वित्तपोषण' से लड़ना और 'प्रतिबंधों से बचने की प्रवृत्ति' से निपटना विषयों की चर्चा में उन उत्पादों और सेवाओं जिनका सर्वाधिक दुरुपयोग होता है की पहचान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने और ऐसे उत्पादों से संबंधित जोखिमों को कम करने की आवश्यकता है। यह फोरम इस संबंध में सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ-साथ चुनौतियों पर भी चर्चा कर सकता है।

निष्कर्ष

अंत में, मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि अपने सहयोगी प्रयासों के माध्यम से, हम वैश्विक वित्तीय ढांचे को आधार देने वाले

विश्वास की रक्षा कर सकते हैं। साथ मिलकर, हम एक वित्तीय परितंत्र के निर्माण में सहयोग और नवोन्मेष जारी रखेंगे जो न केवल सुरक्षित और संरक्षित है बल्कि तेज, सुविधाजनक, सुलभ और किफायती भी है। आइए हम ऐसी वित्तीय प्रणाली बनाएं जो धन शोधन, आतंकवाद का वित्तपोषण और 'प्रसार वित्तपोषण' के प्रयासों को विफल करने के साथ-साथ वित्तीय समावेशन का समर्थन करे, नवोन्मेष को प्रोत्साहित करे और आर्थिक संवृद्धि को अवरोध रहित बनाए। अंत में, मैं उर्वर विचार-विमर्श की कामना करता हूँ।

धन्यवाद।

साझा दृष्टिकोण, साझी जिम्मेदारी – एनबीएफसी को मजबूत बनाना*

श्री स्वामीनाथन जे

सीए श्री चरणजोत सिंह नंदा, अध्यक्ष, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया; ऑडिट कमेटी ऑफ द बोर्ड के अध्यक्ष, एनबीएफसी के एमडी और सीईओ, और एनबीएफसी के सांविधिक लेखा परीक्षक, आरबीआई के कार्यकारी निदेशक और भारतीय रिजर्व बैंक के मेरे सहयोगियों, देवियों और सज्जनों। आप सभी को सुप्रभात।

एनबीएफसी इकोसिस्टम के प्रमुख स्तंभों का प्रतिनिधित्व करने वाली इस सम्मानित सभा को संबोधित करना एक सम्मान की बात है – जिम्मेदारी से व्यवसाय चलाने वाले सीईओ, बीमा की देखरेख करने वाली लेखा परीक्षा समितियों के अध्यक्ष, सांविधिक लेखा परीक्षक जो पारदर्शिता और अखंडता सुनिश्चित करते हैं, साथ ही विनियामकों और पर्यवेक्षकों को जो वित्तीय स्थिरता बनाए रखने और एक मजबूत विनियामक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज हमारे सम्मेलन का विषय – “साझा दृष्टिकोण, साझी जिम्मेदारी – एनबीएफसी को मजबूत करना” – इससे अधिक सामयिक या प्रासंगिक नहीं हो सकता था।

एनबीएफसी क्षेत्र का विकास वास्तव में उद्यमशीलता ऊर्जा, नवाचार और सामाजिक प्रभाव की कहानी है। हालांकि, जैसे-जैसे यह क्षेत्र पैमाने और प्रणालीगत महत्व में बढ़ता है, वैसे-वैसे इसकी नींव को मजबूत करने के हमारे प्रयासों को भी बढ़ाना चाहिए। एक आघात-सहनीय, ग्राहक-केंद्रित और अच्छी तरह से शासित एनबीएफसी क्षेत्र एक साझा आकांक्षा है – और इस पर हमारी जिम्मेदारी है।

एनबीएफसी ऋण के शक्तिशाली इंजन के रूप में उभरे हैं। पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली के पूरक के रूप में, उन्होंने ऋण तक पहुंच का काफी विस्तार किया है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए जो ऐतिहासिक रूप से कम सेवा प्राप्त या छूटे हुए हैं। प्रौद्योगिकी

* 28 मार्च 2025 को चेन्नई में आयोजित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के सम्मेलन में श्री स्वामीनाथन जे, उप गवर्नर का भाषण।

और स्थानीय अंतर्दृष्टि का उपयोग करने वाले अभिनव ऋण वितरण मॉडल के माध्यम से, एनबीएफसी विभिन्न उधारकर्ताओं की जरूरतों के अनुरूप अनुकूलित वित्तीय उत्पादों को डिजाइन करने में सक्षम हैं। उनकी फुर्ती और ग्राहकों के साथ घनिष्ठ जुड़ाव ने उन्हें एक ऐसी भूमिका निभाने में सक्षम बनाया है जो न केवल बैंकों द्वारा पारंपरिक रूप से निभाई जाने वाली भूमिका का पूरक है, बल्कि कई मामलों में, गहन मध्यस्थता और व्यापक अवसर की विशेषता वाले वित्तीय इकोसिस्टम के निर्माण में उत्प्रेरक है।

एनबीएफसी का महत्व केवल समय के साथ बढ़ा है। वास्तव में, पिछले एक दशक में, उनकी वृद्धि लगातार बैंकों से आगे निकल गई है – एक प्रवृत्ति जो पिछले कुछ वर्षों में और भी स्पष्ट हो गई है। यह तेजी से विकास क्षेत्र की प्रासंगिकता और आघात-सहनीयता का सबूत है – लेकिन इसमें कठिनाइयाँ भी हैं। जैसे-जैसे एनबीएफसी अधिक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण होते जाते हैं, अभिशासन, जोखिम प्रबंधन और उपभोक्ता से व्यवहार के मानकों को तदनुसार बढ़ाना चाहिए।

जोखिमों को समझना- जिम्मेदार नवाचार की आवश्यकता

एनबीएफसी का बिजनेस मॉडल प्रभावी होते हुए भी अपने संरचनात्मक जोखिम के साथ आता है। उनकी फंडिंग उनके उधार की परिपक्वता की तुलना में अल्पकालिक है या उच्च जोखिम वाले ग्राहक खंडों की ओर निर्देशित है।

यह परिपक्वता और ऋण परिवर्तन एनबीएफसी मॉडल के केंद्र में है - लेकिन यह जोखिम प्रबंधन पर अधिक ध्यान देने की भी मांग करता है। यदि सावधानी से प्रबंधित नहीं किया जाता है, तो यह भेद्यता पैदा कर सकता है, खासकर बाजार के दबाव या चलनिधि आघात की अवधि के दौरान।

जोखिम लेना बुद्धिमत्तापूर्ण और अच्छी तरह से योजनाबद्ध होना चाहिए, और संबंधित इकाई की जोखिम अवशोषण क्षमता से परे कभी नहीं होना चाहिए। चलनिधि और ऋण जोखिमों का कड़ाई से आकलन और प्रबंधन किया जाना चाहिए। आस्ति-देयता बेमेल, फंडिंग स्रोतों की प्रकृति और अवधि, और संकेंद्रण जोखिम सभी को बोर्ड-स्तरीय निरीक्षण की आवश्यकता होती है जिसे मजबूत आंतरिक नियंत्रणों द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

निष्पक्षता के साथ विकास: ग्राहक को सर्वोच्च प्राथमिकता

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि, जब हम पैमाने, गति और लाभ का पीछा करते हैं, तो हमें ग्राहक के प्रति निष्पक्षता की दृष्टि नहीं खोनी चाहिए - यह एक स्थायी व्यवसाय मॉडल की आधारशिला है। एनबीएफसी क्षेत्र को ग्राहकों के साथ गरिमा, पारदर्शिता और देखभाल के साथ व्यवहार करके समावेशन के अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए। इसमें छिपे हुए शुल्क या अत्यधिक ब्याज दरों से मुक्त पारदर्शी और आसानी से समझ में आने वाले मूल्य निर्धारण को सुनिश्चित करना शामिल है। चूक की घटनाओं में, वसूली प्रक्रियाओं को सहानुभूतिपूर्ण और सम्मानजनक तरीके से आयोजित किया जाना चाहिए।

दुर्भाग्य से, कुछ एनबीएफसी सोचते हैं कि वे एक व्यवसाय मॉडल अपना सकते हैं, जहां यह उस समय में त्वरित वृद्धि के लिए अत्यधिक और अस्थिर ब्याज दरों- कभी-कभी अग्रिम शुल्क या प्रसंस्करण शुल्क के रूप में युग्मित के साथ कमजोर हामीदारी का सहारा लेना उचित है- जिसके बाद चूक पर आक्रामक वसूली प्रक्रियाएँ की जाती हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ: यह कोई स्वीकार्य मॉडल नहीं है। वित्तीय समावेशन को वित्तीय शोषण के बहाने के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ कि आप अपने संस्थानों को अपने सभी लेन-देन में निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध करें।

निष्पक्ष आचरण के लिए यह जिम्मेदारी सीईओ, बोर्ड द्वारा साझा प्रतिबद्धता और किसी भी इकाई में आश्वासन प्रकार्यों की है। एक ग्राहक-उन्मुख संस्कृति को शीर्ष से संचालित किया जाना चाहिए और सभी स्तरों पर अंतर्निहित किया जाना चाहिए।

हम यह कैसे सुनिश्चित करें कि हमारा साझा दृष्टिकोण साकार हो और हमारी सामूहिक जिम्मेदारियां पूरी हों? सबसे प्रभावी तरीकों में से एक आंतरिक और बाहरी आश्वासन तंत्र दोनों को मजबूत करना है।

निगरानी को मजबूत करना: लेखा परीक्षा समिति की भूमिका

मैं बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) से शुरू करता हूँ। नियमित अनुपालन आवश्यकता होने से अलग, एसीबी संस्थागत निरीक्षण और दीर्घकालिक वित्तीय स्वास्थ्य की प्रमुख कड़ी है। यह अभिशासन को मजबूत करने, आश्वासन पर प्रबंधन का मार्गदर्शन करने और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की अखंडता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रभावी ढंग से

कार्य करते समय, यह कमजोरियों की पहचान करने और समय पर सुधारात्मक कार्रवाई शुरू करने के लिए एक सक्रिय मंच बन जाता है।

प्रभावी अभिशासन की दिशा तय करने में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित हों, स्पष्ट उद्देश्य के साथ आयोजित की जाएँ, और जवाबदेही तथा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उनका पूर्णतः दस्तावेजीकरण किया जाए।

समिति की प्रभावकारिता इसके विचार-विमर्श के सार में है। एसीबी को आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता और कामकाज की सक्रिय रूप से निगरानी करनी चाहिए – न केवल उनकी उपस्थिति की पुष्टि करने के लिए, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे व्यवहार में प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं। इसी तरह, लेखा परीक्षा टिप्पणियों को बैठक के मिनटों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए; उन्हें समय पर और सार्थक सुधारात्मक कार्रवाइयों में परिणत होना चाहिए। एक कुशल एसीबी ऑडिट निष्कर्षों को भी ट्रैक करता है और यह सुनिश्चित करता है कि सुधारात्मक उपायों को बिना देरी के लागू किया जाए।

बोर्ड या एसीबी की देखरेख में एक प्रभावी मुखबिर तंत्र की स्थापना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है जो कर्मचारियों को सशक्त बनाता है और उन्हें प्रतिशोध के डर के बिना अनैतिक या गैर-अनुपालन व्यवहार की रिपोर्ट करने के लिए गुमनामी प्रदान करता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग की अखंडता को बनाए रखने में सीईओ की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्हें सक्रिय रूप से किसी भी प्रयास को रोकना चाहिए - चाहे जानबूझकर या चतुराई से प्रच्छन्न - लेखांकन मानकों या विनियामक प्रावधानों को गलत तरीके से लागू करने के लिए किया गया। एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है जहां मुख्य वित्तीय अधिकारी और आंतरिक लेखा परीक्षा के प्रमुख बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति के साथ खुली, ईमानदार और पारदर्शी बातचीत में संलग्न होने के लिए सशक्त महसूस करें।

सांविधिक लेखा परीक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका

अब मैं सांविधिक लेखा परीक्षकों की भूमिका पर आता हूँ, जो आश्वासन इकोसिस्टम का एक अनिवार्य हिस्सा हैं। वास्तव में,

लेखा परीक्षकों की भूमिका कभी भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं रही है – न केवल अनुपालन की जांच में, बल्कि विश्वास को बनाए रखने में। और विश्वास, एक बार खो जाने के बाद, पुनर्निर्माण करना मुश्किल है।

लेखा परीक्षकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस बारे में एक स्वतंत्र, पेशेवर राय प्रदान करें कि क्या वित्तीय विवरण एनबीएफसी की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और विनियामक और लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं। हालांकि, आज के जटिल और गतिशील वातावरण में, यह अब पर्याप्त नहीं है।

भारत और विदेश दोनों में हाल की घटनाओं ने दिखाया है कि पारंपरिक वित्तीय लेखा परीक्षा विकसित होना चाहिए। लेखा परीक्षकों को अपने काम के लिए तकनीकी विशेषज्ञता, न्याय-संबंधी अंतर्दृष्टि और एक नैतिक दृष्टि लाना चाहिए। चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जटिल संरचनाओं, डेरिवेटिव, तुलन-पत्र से इतर मर्दे, संबंधित पार्टि लेनदेन और प्रावधान नीतियों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए।

विनियामकों और पर्यवेक्षकों की सुविधाजनक भूमिका

विनियामकों और पर्यवेक्षकों के रूप में, हम एक दोहरी जिम्मेदारी निभाते हैं - स्थिरता और अनुशासन की रक्षा करना, जबकि एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना जो नवाचार, समावेश और सतत विकास को प्रोत्साहित करता है। कुछ क्षेत्रों में धारणा के विपरीत, हमारा दृष्टिकोण सक्रिय रूप से सही संतुलन बनाने का प्रयास करता है। भारतीय रिज़र्व बैंक में, हम इस बात से पूरी तरह अवगत हैं कि विनियमन केवल नियंत्रण के बारे में नहीं है; यह एक अच्छी तरह से परिभाषित और पारदर्शी ढांचे के भीतर जिम्मेदार वित्तीय मध्यस्थता को सक्षम करने के बारे में है।

हाल के वर्षों में कई पहल विनियमन के लिए इस सुविधाजनक और आनुपातिक दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। एक वाणिज्यिक बैंकर के रूप में मेरी पिछली भूमिका में, मुझे ऐसी ही एक पहल-विनियमन समीक्षा प्राधिकारी 2.0 के साथ निकटता से जुड़ने का सौभाग्य मिला, जिसने विनियामक उद्देश्यों से समझौता किए बिना विनियामक बोझ को आसान बनाने और अनुपालन को सुव्यवस्थित करने के लिए आरबीआई की मजबूत प्रतिबद्धता को और मजबूत किया।

एनबीएफसी के लिए विनियामक ढांचा हाल के वर्षों में इस समझ के साथ विकसित हुआ है – धीरे-धीरे बैंकों के साथ अधिक

सामंजस्य की ओर बढ़ रहा है, जबकि वित्तीय प्रणाली में एनबीएफसी की अनूठी भूमिका के अनुकूल परिचालन लचीलेपन को संरक्षित करना अभी भी आवश्यक है। स्केल-आधारित विनियामक ढांचे की शुरुआत स्पष्ट रूप से मानती है कि विनियमन और पर्यवेक्षण की तीव्रता प्रणालीगत महत्व के अनुपात में होनी चाहिए। साथ ही, विनियामक संरचना इस क्षेत्र में जिम्मेदार नवाचार और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के विकास को प्रोत्साहित करती है।

इसी तरह, पर्यवेक्षक की भूमिका भी अधिक संवादात्मक और दूरदेशी हो गई है। यह केवल तथ्य के बाद अनुपालन उल्लंघनों की पहचान करने के बारे में नहीं है, बल्कि आंतरिक प्रणालियों को मजबूत करने, अभिशासन बढ़ाने और उभरते जोखिमों के खिलाफ आघात-सहनशीलता बनाने के लिए संस्थाओं के साथ जुड़ने के बारे में है। प्रत्यक्ष निरीक्षण, परोक्ष निगरानी, विषयगत समीक्षाओं और संरचित व्यस्तताओं के माध्यम से, पर्यवेक्षी प्रक्रिया का उद्देश्य वित्तीय क्षेत्र की दीर्घकालिक सुदृढ़ता में भागीदार बनना है - इसकी प्रगति में बाधा नहीं।

निष्कर्ष

हमारा साझा दृष्टिकोण स्पष्ट है: एक गतिशील, समावेशी और विश्वसनीय एनबीएफसी क्षेत्र जो बैंकिंग प्रणाली का पूरक है और भारतीय अर्थव्यवस्था की उभरती जरूरतों को पूरा करता है। और इसे प्राप्त करने का तरीका साझा जिम्मेदारी के माध्यम से है – अभिशासन में, ग्राहक संरक्षण में, वित्तीय विवेक में, और नैतिक आचरण में।

हम विनियामक समुदाय में इस यात्रा का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारा इरादा नवाचार को रोकना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि विकास सतत हो, जोखिम अच्छी तरह से प्रबंधित हों, और ग्राहक विश्वास से कभी समझौता न किया जाए। आरबीआई की ओर से, मैं आपको आश्वासित कर सकता हूँ कि विनियामकों और पर्यवेक्षकों के रूप में हम न केवल प्रहरी के रूप में, बल्कि एक मजबूत, समावेशी और भविष्य के लिए तैयार वित्तीय इकोसिस्टम के समर्थकों के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।

यह सम्मेलन हमें इस बात पर चिंतन करने का अवसर देता है कि हम इस साझा कार्य योजना में कैसे योगदान दे सकते हैं। चाहे कार्यनीतिक निर्णय लेना, ऑडिट समितियों की अध्यक्षता

करना, या वित्तीय पर हस्ताक्षर करना, नियमों का मसौदा तैयार करना या पर्यवेक्षण करना - हम इस क्षेत्र के भविष्य को आकार दे रहे हैं।

इसलिए, आइए हम एक साथ काम करें - उद्देश्य की स्पष्टता और कार्रवाई की एकता के साथ - एक मजबूत, निष्पक्ष और अधिक आघात-सहनीय एनबीएफसी इकोसिस्टम बनाने के लिए। धन सृजन केवल व्यक्तिगत या संस्थागत लाभ के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि समुदाय का समर्थन करने के लिए होना चाहिए, जो

हम सभी के बीच साझा जिम्मेदारी की भावना को दर्शाता है, सभी के लिए एक समावेशी विकास प्राप्त करने और विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने के हमारे प्रयास में।

इसके साथ, मैं इस सम्मेलन के दौरान आप सभी सफल और समृद्ध विचार-विमर्श के लिए शुभकामनाएं देता हूँ तथा उन विचारों और अंतर्दृष्टि की प्रतीक्षा करता हूँ जो हमारे साझा दृष्टिकोण के अनुसरण में उभरकर सामने आएंगे। इस अवसर के लिए धन्यवाद और आप सभी को शुभकामनाएं, जय हिंद!

आलेख

अर्थव्यवस्था की स्थिति

स्थायी जमा सुविधा के तीन वर्ष: कुछ विचार

जलवायु नीति अनिश्चितता और ऊर्जा वस्तु मूल्यों की बदलती गतिशीलता

भारत में ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास: अंतर को पाटना

अर्थव्यवस्था की स्थिति*

व्यापार और टैरिफ तनाव में वृद्धि और परिणामी वित्तीय बाज़ार की अस्थिरता ने निकट अवधि में वैश्विक संवृद्धि के कमजोर होने के बारे में चिंताओं को उठाया है। यद्यपि कमजोर वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण कमजोर बाह्य मांग के माध्यम से भारत की आर्थिक वृद्धि को प्रभावित कर सकता है, घरेलू विकास इंजन अर्थात् उपभोग और निवेश बाह्य प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति अपेक्षाकृत कम संवेदनशील हैं। 2025 के लिए सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून के पूर्वानुमान से कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं को बढ़ावा मिला है, जो कृषि आय में वृद्धि कर सकता है और खाद्य कीमतों को नियंत्रण में रख सकता है। खाद्य पदार्थों की कीमतों में कमी के कारण मार्च में मुद्रास्फीति घटकर 67 माह के न्यूनतम स्तर 3.3 प्रतिशत पर आ गई।

भूमिका

वैश्विक आर्थिक परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है, व्यापार नीति अनिश्चितता निकट अवधि के दृष्टिकोण के प्रमुख चालक के रूप में उभर रही है। 2 अप्रैल 2025 को, अमेरिका ने लगभग 60 देशों पर 10 प्रतिशत आधार टैरिफ और पारस्परिक लेवी की घोषणा की, जिससे औसत अमेरिकी टैरिफ एक सदी से अधिक समय में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 9 अप्रैल को उन देशों के लिए टैरिफ के कार्यान्वयन पर 90 दिनों के ठहराव की घोषणा की गई थी, जिन्होंने जवाबी कार्रवाई का सहारा नहीं लिया था। इन घटनाक्रमों ने वैश्विक व्यापार युद्ध की आशंकाओं को जन्म दिया है, और देश अभी भी इस अनिश्चित वातावरण में अपनी उचित प्रतिक्रिया पर काम कर रहे हैं। तथापि, वैश्विक वृद्धि पर इन बढ़ते व्यापार तनावों का हानिकारक प्रभाव अपरिहार्य है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुसार,

ये टैरिफ "सुस्त वृद्धि के समय वैश्विक दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण जोखिम का प्रतिनिधित्व करते हैं"¹। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने अपने नवीनतम वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण में आकलन किया है कि बढ़ते व्यापार प्रतिबंध उत्पादन और खपत दोनों के लिए उच्च लागत में योगदान देंगे²

आधारभूत आकलन यह है कि वैश्विक वृद्धि कमजोर होने की संभावना है जबकि उपभोक्ता कीमतों पर टैरिफ के संभावित स्थानांतरण मुद्रास्फीति को ऊंचा रख सकते हैं। यह अनुमान है कि आयात शुल्क में वृद्धि से शुरू हुआ व्यापार युद्ध वैश्विक उत्पादन को 0.5 प्रतिशत तक कमजोर करेगा³ पूर्वानुमानकर्ताओं ने अमेरिका में मंदी की संभावना भी बढ़ा दी है।⁴ जबकि तत्काल प्रभाव पहले से ही बाज़ार की अस्थिरता और आर्थिक पूर्वानुमानों में दिखाई दे रहे हैं, दीर्घकालिक परिणाम उद्योगों में व्यापक व्यवधान, कम निवेश, और दुनिया भर में आर्थिक सुधार को धीमा कर सकते हैं। हालांकि, कमोडिटी की कीमतों में गिरावट उन देशों पर आघात कम कर सकती है जो निवल आयातक हैं। वैश्विक वृद्धि दर में आशंकाओं के बीच तेल की कीमतें चार साल के निचले स्तर पर आ गई हैं और धातुओं की कीमतों में गिरावट आई है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के आकलन के अनुसार, वैश्विक व्यापार पर टैरिफ का तत्काल प्रभाव पर्याप्त होने की उम्मीद है, क्योंकि वैश्विक पण्य वस्तु व्यापार की मात्रा 2025 में लगभग 1 प्रतिशत तक घट सकती है, जो अमेरिका द्वारा घोषित नए टैरिफ के साथ-साथ वर्ष की शुरुआत में पेश किए गए हैं⁵ इस गिरावट का अधिकांश हिस्सा अमेरिका और चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार में 80 प्रतिशत की गिरावट से प्रेरित होने की उम्मीद है। खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2024-25 में अनाज में विश्व व्यापार पिछले वर्ष

* यह आलेख रेखा मिश्र, जीवी नथनएल, अर्पिता अग्रवाल, बिस्वजीत मोहंती, दुर्गा जी, गरिमा वाही, रमेश कुमार गुप्ता, हरेंद्र बेहरा, जेसिका मारिया एंथनी, आकाश राज, रचित सोलंकी, साक्षी चौहान, राधिका सिंह, सत्येंद्र कुमार, अगमणि साहा, मनु स्वर्णकार, सुभ्रदीप पॉल, डी सुगंथी, प्रतिभा केडिया, अवनीश कुमार, अपेक्षा शर्मा, राजस सरॉय, युवराज कश्यप, सत्यम कुमार, निखिल प्रकाश कोसे और अक्षरा अवस्थी द्वारा तैयार किया गया है। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों को नहीं दर्शाते हैं।

¹ आईएमएफ की प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जीवा का वक्तव्य, 3 अप्रैल, 2025।

² ओईसीडी, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, प्रेस विज्ञापन, 17 मार्च, 2025।

³ <https://www.bofbulletin.fi/en/2025/1/how-will-the-trade-war-hit-the-economy/>

⁴ गोल्डमैन सैक्स, 7 अप्रैल, 2025।

⁵ विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक डॉ. नोजी ओकोजो-इवेला का वक्तव्य, 3 अप्रैल, 2025।

के स्तर से 6.7 प्रतिशत की गिरावट का अनुमान है, जो वर्ष 2019-20 के बाद से सबसे कम है, जिससे अनाज आयातक देशों में मुद्रास्फीति की चिंता बढ़ गई है।

वैश्विक वित्तीय बाजार प्रवाह की स्थिति में हैं, जो गतिशील रूप से विकसित व्यापार नीति परिदृश्य के निहितार्थों को समझने के लिए कोशिश रहे हैं। व्यापक टैरिफ घोषणाओं ने वित्तीय बाजारों को वैश्विक स्तर पर एक असमंजस की स्थिति में भेज दिया। अमेरिका में, S&P 500 इंडेक्स 11 महीनों में अपने निम्नतम स्तर पर गिर गया, टैरिफ की घोषणा के बाद दो दिनों के भीतर बाजार मूल्य में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक कमी आई, लेकिन 9 अप्रैल को तेजी से पलट गया जब कार्यान्वयन पर 90 दिन के ठहराव की घोषणा की गई। अमेरिकी जंक बॉण्ड बाजार में 2020 के बाद से सबसे बड़ी बिकवाली देखी गई, यहां तक कि अमेरिकी डॉलर में लगभग 1.8 प्रतिशत की गिरावट आई। मार्च 2025 के दौरान वैश्विक बॉण्ड प्रतिफल में कमी आई क्योंकि निवेशक, सुरक्षा उपाय के लिए, जोखिम मुक्त सरकारी बॉण्ड में चले गए, इस डर के बीच कि बढ़ते व्यापार तनाव से टैरिफ-प्रेरित मंदी शुरू हो सकती है। जनवरी 2025 के मध्य में उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद अमेरिकी बॉण्ड प्रतिफल में कमी आई, क्योंकि अमेरिकी इक्विटी बाजार में निरंतर बिकवाली के बीच निवेशक के विचार नकारात्मक हो गए। हालांकि, अप्रैल के आरंभ में 10-वर्षीय अमेरिकी ट्रेजरी प्रतिफल में वृद्धि हुई, फिर भी सुरक्षित निवेश के रूप में अमेरिकी ट्रेजरी की प्रतिष्ठा पर भी चिंता उत्पन्न हो गई।⁷ इस बीच, यूरोप में, जर्मनी और पुर्तगाल जैसे कुछ देशों में रक्षा और अवसंरचना के व्यय के लिए खर्च के बड़े पैमाने पर आवंटन की घोषणा ने 10 वर्षीय बॉण्ड प्रतिफल में वृद्धि की है क्योंकि निवेशकों ने बड़े निवेशों में पैसे लगाए हैं। 10 वर्षीय जापानी बॉण्ड पर प्रतिफल शून्य के आसपास होने के वर्षों के बाद मार्च के दौरान बढ़ गया क्योंकि निवेशक सख्त मौद्रिक नीति के लिए तैयार रहे।

दुनिया भर के नीति निर्माता इन घटनाक्रमों से उत्पन्न कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। संभावित उच्च व्यापार लागत

और वृद्धि में अनुमानित मंदी के कारण, उन्हें मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिए बिना वृद्धि को बढ़ावा देने का विकल्प चुनना पड़ रहा है। उत्पादकता, बाजार प्रतिस्पर्धा और कल्याण पर इन घटनाक्रमों के दीर्घकालिक प्रभावों को भी नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।

इस अस्थिर बाह्य वातावरण से उत्पन्न चुनौतियों के ढेर के बीच, भारतीय अर्थव्यवस्था ने प्रशंसनीय आघात-सहनीयता प्रदर्शित की है, जिसमें वृद्धि छ1: 2024-25 के दौरान देखी गई अस्थायी समस्या से उबरने के लिए तैयार है। यद्यपि वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में मंदी कमजोर बाह्य मांग के माध्यम से समग्र वृद्धि को प्रभावित कर सकती है, भारत के घरेलू विकास इंजन अर्थात् उपभोग और निवेश बाह्य प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रति अपेक्षाकृत कम संवेदनशील हैं। जैसा कि खंड IV में विस्तार से चर्चा की गई है, भारत की बाह्य भेद्यता भी कम है, जैसा कि इसके 19 प्रतिशत के मामूली बाह्य ऋण-जीडीपी अनुपात और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार (लगभग 11 महीने के आयात कवर के बराबर) से पता चलता है। सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में भारत की स्थिति, और समष्टि आर्थिक स्थिरता, इसे वृद्धि में मंदी और व्यापक कमजोरियों से जूझ रहे विश्व में एक बेहतर निवेश गंतव्य बनाती है।⁸ इसके अतिरिक्त, एक स्थिर वित्तीय क्षेत्र सतत वृद्धि का आधार प्रदान करता है, क्योंकि भारतीय वित्तीय प्रणाली अधिक मजबूत और विविध हो गई है, जिसमें बैंक और एनबीएफसी भी शामिल हैं जो व्यापक वित्तीय आघातों के प्रति आघात-सहनीय हैं।⁹

रिज़र्व बैंक प्रणाली में चलनिधि बढ़ाने के लिए खुले बाजार परिचालन (ओएमओ), दैनिक परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर) नीलामियों और डॉलर/रुपया खरीद-बिक्री स्वैप नीलामियों सहित कई उपायों को सक्रिय रूप से लागू कर रहा है। जनवरी 2025 के मध्य से शुरू किए गए इन उपायों ने चलनिधि की स्थिति में सुधार के बीच दरों और स्प्रेड में कमी के साथ मुद्रा बाजार में व्यवस्थित स्थिति बनाए रखने में मदद

⁶ एफएओ अनाज आपूर्ति और मांग सारांश, 4 अप्रैल, 2025।

⁷ <https://www.nbcnewyork.com/news/business/money-report/2-year-treasury-drops-to-lowest-level-in-years-as-investors-digest-impacts-of-tariffs/6214561/?os=rebeckakelsey.comdfblog&ref=app>

⁸ वर्ष 2024-25 के दौरान, भारत ने उच्च प्रत्यावर्तन के कारण निवल एफडीआई प्रवाह में कमी के बावजूद मजबूत सकल एफडीआई प्रवाह प्राप्त किया।

⁹ भारत: वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम-वित्तीय प्रणाली स्थिरता आकलन, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, 28 फरवरी, 2025।

की है। 91-दिवसीय ट्रेजरी बिलों पर 3-माह के जमा प्रमाणपत्रों और 3-माह के वाणिज्यिक पत्रों का स्प्रेड भी कम हुआ है, जो चलनिधि की स्थिति में सुधार को दर्शाता है। एनबीएफसी को दिए जाने वाले वित्तपोषण में भी सुधार की उम्मीद है क्योंकि 1 अप्रैल 2025 से एनबीएफसी को दिए जाने वाले बैंक ऋणों पर कम जोखिम भार बहाल कर दिया गया है।

वास्तविक अर्थव्यवस्था पर, भारतीय उद्यमी अपनी व्यावसायिक संभावनाओं के बारे में अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में अधिक आश्वस्त हैं।¹⁰ भारत के क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) ने इस आशावादी दृष्टिकोण के अनुरूप अन्य देशों की तुलना में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है। रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए नवीनतम उद्यम सर्वेक्षण इस आकलन की पुष्टि करते हैं (अनुबंध 1)। सभी क्षेत्रों में सकारात्मकता बनी हुई है, विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग में वृद्धि और व्यावसायिक धारणा में सुधार देखने को मिल रहा है। सेवा और अवसंरचना फ़र्म माँग, मूल्य निर्धारण और लाभप्रदता को लेकर आशावादी बनी हुई हैं। भविष्य में, ग्रामीण क्षेत्रों से निरंतर माँग, शहरी खपत में प्रत्याशित सुधार, बढ़े हुए सरकारी पूंजीगत व्यय द्वारा समर्थित स्थायी पूंजी निर्माण में अपेक्षित सुधार, और कंपनियों और बैंकों के मजबूत तुलन पत्र से वृद्धि को गति मिलने की उम्मीद है।

मार्च 2025 में हेडलाइन सीपीआई मुद्रास्फीति घटकर 67 महीने के निचले स्तर 3.3 प्रतिशत पर आ गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य कीमतों में निरंतर कमी है। हालांकि, कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर सीपीआई) 4.1 प्रतिशत पर स्थिर रही, जिसमें स्वर्ण का योगदान 22.8 प्रतिशत रहा। वैश्विक वृद्धि में प्रत्याशित मंदी के कारण वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में हाल ही में आई गिरावट ने आयातित मुद्रास्फीति के कुछ दबावों को कम किया है। वर्ष 2025 के लिए सामान्य से अधिक दक्षिण-पश्चिम मानसून के पूर्वानुमान से कृषि क्षेत्र के लिए संभावनाओं को बढ़ावा मिला है, जो कृषि आय में वृद्धि कर सकता है और खाद्य कीमतों को नियंत्रण में रख सकता है।

¹⁰ ईवाई-पार्थेनन सीईओ आउटलुक सर्वे: ग्लोबल कॉन्फिडेंस इंडेक्स 2025।

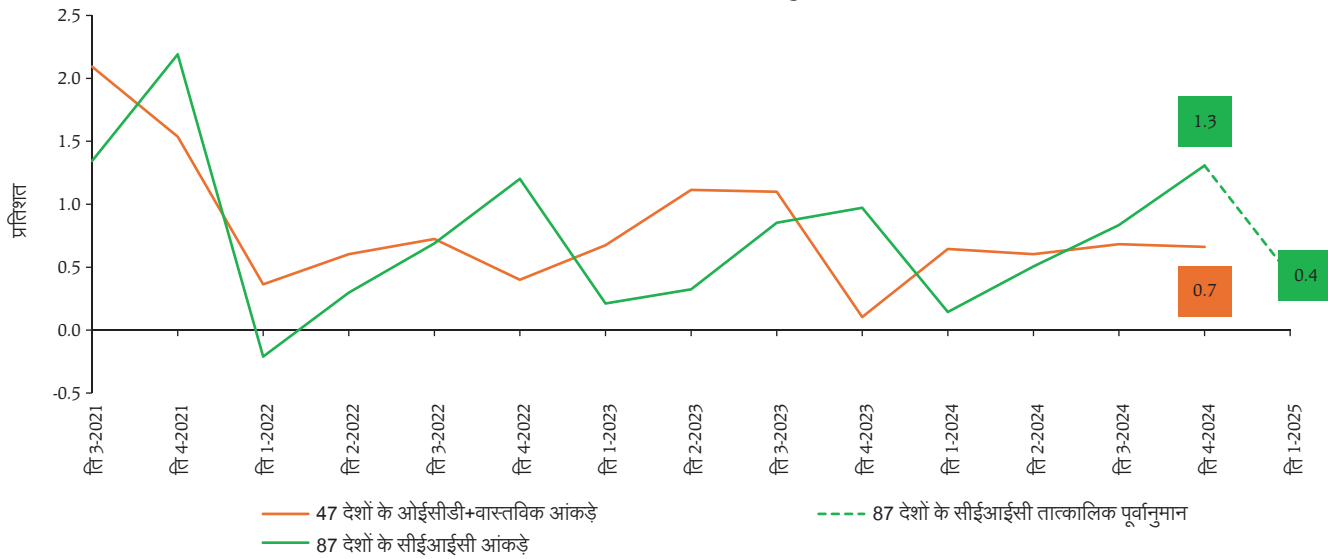
7-9 अप्रैल 2025 के दौरान आयोजित अपनी नवीनतम द्वि-मासिक मौद्रिक नीति बैठक में, रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने माना कि वैश्विक अर्थव्यवस्था असाधारण अनिश्चितताओं के दौर से गुजर रही है, जिससे शोर और अनिश्चित वातावरण से संकेत निकालना मुश्किल हो गया है। एमपीसी ने नोट किया कि मुद्रास्फीति वर्तमान में लक्ष्य से नीचे है और घरेलू मुद्रास्फीति परिदृश्य अगले वर्ष में 4 प्रतिशत के लक्ष्य के साथ हेडलाइन मुद्रास्फीति के टिकाऊ संरेखण का विश्वास प्रदान करता है। एमपीसी ने अपनी राय में कहा कि मुद्रास्फीति के अनुकूल परिदृश्य और विकास की धीमी गति के कारण मौद्रिक नीति का विकास को बढ़ावा देना अनिवार्य हो गया है। तदनुसार, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 25 आधार अंकों से घटाकर 6.00 प्रतिशत कर दिया और रुख को तटस्थ से उदार बनाकर सहजता के प्रभाव को और मजबूत किया।

इस पृष्ठभूमि में, शेष आलेख को चार खंडों में संरचित किया गया है। खंड II में वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे घटनाक्रमों को शामिल किया गया है। घरेलू समष्टि आर्थिक स्थितियों का आकलन खंड III में निर्धारित किया गया है। खंड IV भारत में वित्तीय स्थितियों को समाहित करता है, जबकि खंड V में निष्कर्ष है।

II. वैश्विक सेटिंग

बढ़ती नीतिगत अनिश्चितता और टैरिफ युद्ध में वृद्धि वैश्विक आर्थिक संभावनाओं पर भार डाल रही है, इस आशंका के बीच कि टैरिफ और अपेक्षित प्रतिक्रिया के संयुक्त प्रभाव से वैश्विक विकास के लिए प्रतिकूल प्रभाव अधिक जाएंगे। इस पृष्ठभूमि में वैश्विक जीडीपी वृद्धि, मुद्रास्फीति और व्यापार के अनुमानों को संशोधित कर नीचे किए जाने की संभावना है। हमारे मॉडल-आधारित तात्कालिक पूर्वानुमान भी ति1: 2025 में वैश्विक वृद्धि की गति में एक महत्वपूर्ण मंदी की ओर इशारा करते हैं (चार्ट II.1)।

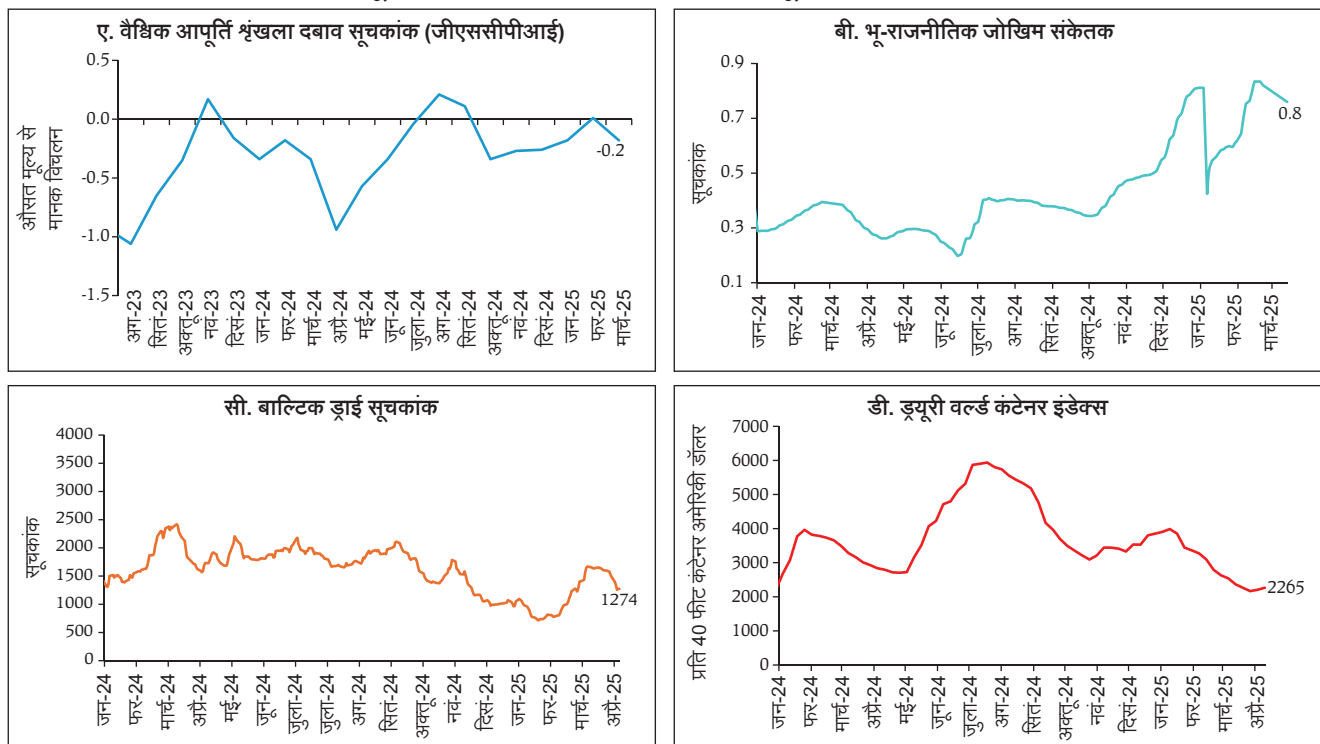
नीतिगत अनिश्चितता बढ़ने के साथ ही, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आपूर्ति पक्ष का दबाव कम होने के संकेत दे रहा है। वैश्विक

चार्ट II.1: वैश्विक जीडीपी वृद्धि का तात्कालिक अनुमान (तिमाही-दर-तिमाही)


स्रोत: सीईआईसी, ओईसीडी और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

आपूर्ति श्रृंखला दबाव सूचकांक (जीएससीपीआई) मार्च 2025 में कम परिवहन लागत और कम डिलीवरी समय के

कारण ऐतिहासिक औसत स्तर से नीचे आ गया (चार्ट II.2ए)। भू-राजनीतिक जोखिम संकेतक में भी मार्च में क्रमिक कमी दर्ज

चार्ट II.2: भू-राजनीतिक जोखिम और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला दबाव में रुझान


टिप्पणियाँ: 1. जीएससीपीआई परिवहन लागत और विनिर्माण संकेतकों पर डेटा दर्शाता है।

2. बाल्टिक ड्राई इंडेक्स समुद्र के द्वारा प्रमुख कच्चे माल को स्थानांतरित करने की कीमत के लिए एक बेंचमार्क प्रदान करता है और इसमें तीन उप-सूचकांक होते हैं जो सूखे थोक वाहक के विभिन्न आकारों को मापते हैं।

3. ड्रयूरी द्वारा साप्ताहिक मूल्यांकन किया गया डब्ल्यूसीआई प्रमुख पूर्व-पश्चिम व्यापार मार्गों के लिए वास्तविक स्पोर्ट कंटेनर माल डुलाई दरों की रिपोर्ट करता है। समग्र 8 शिपिंग मार्गों की मात्रा के भारत औसत को 40-फुट कंटेनर प्रति अमेरिकी डॉलर के रूप में दर्शाता है।

स्रोत: फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क; ब्लैकरोक इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूट, मार्च 2025; और ब्लूमबर्ग।

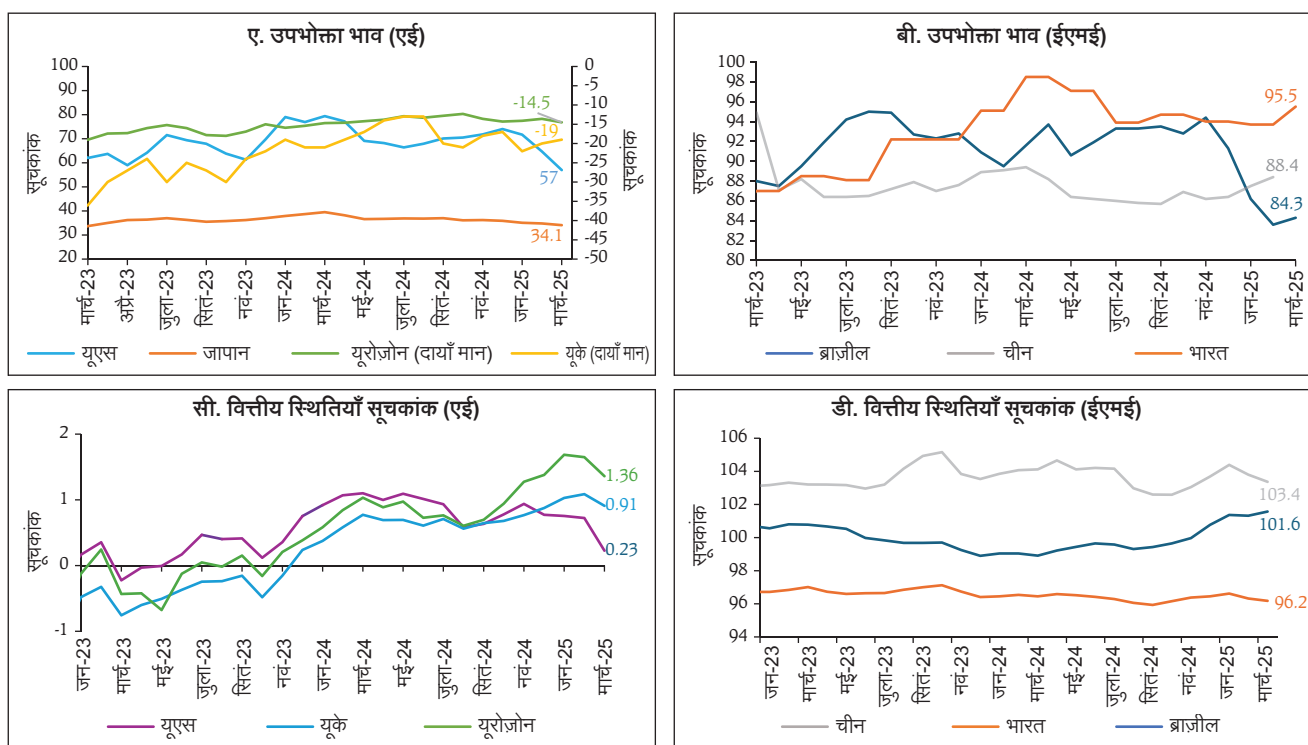
की गई, हालाँकि इसका स्तर अभी भी ऊँचा बना हुआ है (चार्ट 11.2बी)। बाल्टिक ड्राई सूचकांक (बीडीआई) फरवरी में मज़बूत उछाल के बाद थोड़ा कम हुआ, जो ड्राई बल्क शिपिंग की माँग में अस्थायी गिरावट का संकेत देता है (चार्ट 11.2सी)। हालाँकि, कंटेनर माल ढुलाई दरों में, जो पहले गिरावट की प्रवृत्ति पर थीं, अप्रैल की शुरुआत तक टैरिफ-संबंधी व्यवधानों और कम शिपिंग क्षमता जैसे कारकों के कारण थोड़ी वृद्धि देखी गई (चार्ट 11.2डी)।

व्यापार और नीतिगत अनिश्चितताओं ने भौगोलिक क्षेत्रों में उपभोक्ता भावनाओं को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। मार्च 2025 में अमेरिका में उपभोक्ता भावनाएं मुद्रास्फीति के बढ़ने की संभावनाओं, बिगड़ती व्यावसायिक स्थितियों और टैरिफ वृद्धि और अनिश्चित आर्थिक परिदृश्य के कारण

आहत हुईं, जो नवंबर 2022 के बाद से अपने निम्नतम स्तर पर पहुंच गईं। यूरोजोन ने भी कमी होते हुए देखा, जबकि यह यूके और ब्राजील में मामूली सुधार हुआ (चार्ट 11.3बी और सी)। वित्तीय स्थितियों ने भारत और चीन को छोड़कर प्रमुख आई और ईएमई में सख्ती की ओर रुख देखा गया (चार्ट 11.3सी और डी)।

मार्च 2025 में वैश्विक समग्र क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) में मामूली वृद्धि हुई क्योंकि विनिर्माण क्षेत्र में मंदी की भरपाई सेवा क्षेत्र की गतिविधि में तेज वृद्धि से हुई थी (चार्ट 11.4ए)। वैश्विक विनिर्माण पीएमआई में उत्पादन और नए ऑर्डर में गिरावट के रूप में नरमी आई, और व्यापार आशावाद तीन महीने के निचले स्तर पर गिर गया। हालांकि, वैश्विक सेवा पीएमआई में फरवरी के निचले स्तर से उबरकर तेजी से वृद्धि

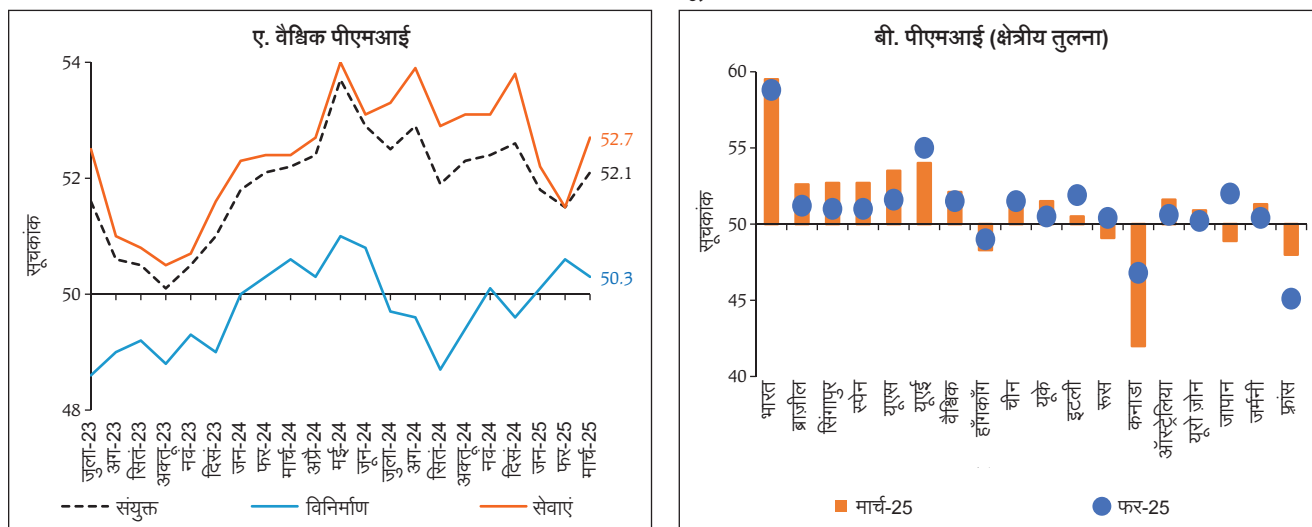
चार्ट 11.3: उपभोक्ता भाव और वित्तीय स्थितियां



टिप्पणियाँ: 1. जापान: 50 से ऊपर का स्कोर उपभोक्ता आशावाद को दर्शाता है, 50 से नीचे उपभोक्ता विश्वास की कमी को दर्शाता है और 50 तटस्थता को दर्शाता है।
2. यूरोजोन और यूके: -100 विश्वास की अत्यधिक कमी का संकेत देता है, 0 तटस्थता को दर्शाता है जबकि 100 अत्यधिक विश्वास को दर्शाता है।
3. भारत और अमेरिका: सूचकांक का मान जितना अधिक होगा, उपभोक्ता विश्वास उतना ही अधिक होगा।
4. वित्तीय स्थिति सूचकांक (गोल्डमैन सैक्स द्वारा निर्मित ईएमई से संबंधित) के लिए, 100 से नीचे की रीडिंग समायोजित है और इसके विपरीत। आई के लिए, ब्लूमबर्ग द्वारा निर्मित सूचकांक एक जेड-स्कोर है जहां एक सकारात्मक मूल्य समायोजन/आसान वित्तीय स्थितियों को इंगित करता है और इसके विपरीत।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।

चार्ट II.4 : क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)



टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने और 50 से ऊपर की रीडिंग विस्तार और इसके विपरीत दर्शाते हैं।

स्रोत: एस एंड पी वैश्विक।

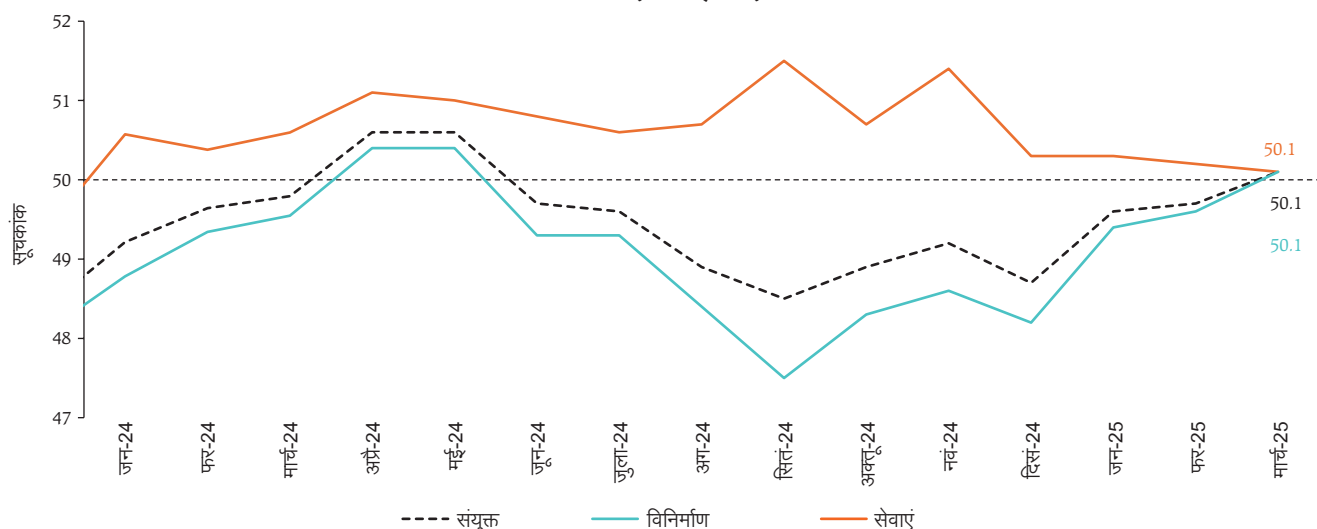
हुई। सभी क्षेत्रों में भारत अपने समकक्ष देशों की तुलना में मजबूत पीएमआई रीडिंग के साथ अलग रहा (चार्ट II.4बी)।

नए निर्यात ऑर्डरों के लिए समग्र पीएमआई में मार्च में क्रमिक वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें विनिर्माण और समग्र नए निर्यात ऑर्डर, दोनों ही जून 2024 से संकुचन क्षेत्र में रहने के बाद, विस्तार क्षेत्र में पहुँच गए। सेवाओं के निर्यात ऑर्डरों में क्रमिक मंदी के बावजूद विस्तार जारी रहा (चार्ट II.5)। हालाँकि, वैश्विक व्यापार परिदृश्य काफी अनिश्चितता से ग्रस्त है, जैसा

कि व्यापार नीति अनिश्चितता (टीपीयू) सूचकांक के ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुँचने से परिलक्षित होता है (चार्ट II.6)।

ब्लूमबर्ग कमोडिटी सूचकांक के अनुसार, मार्च में वैश्विक कमोडिटी कीमतों में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें धातु की कीमतें शामिल थीं, जो चीन के प्रोत्साहन पैकेज के कारण बढ़ते आशावाद के कारण बढ़ीं। हालाँकि, विघटनकारी टैरिफ युद्ध के मद्देनजर वैश्विक मंदी की प्रत्याशा में धूमिल मांग की स्थिति के कारण अप्रैल की शुरुआत में कमोडिटी की कीमतों में तेजी से

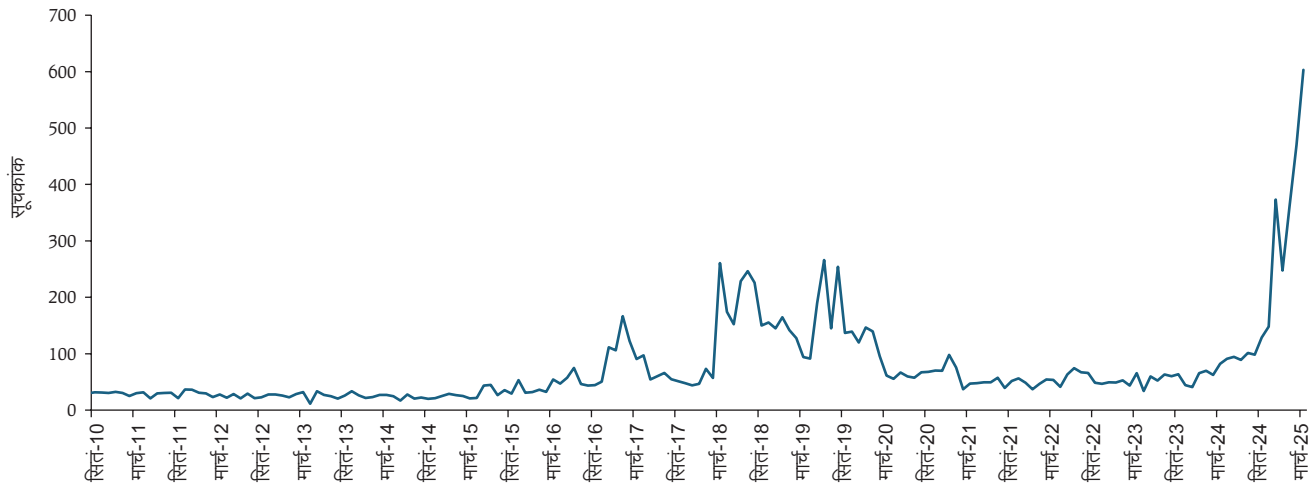
चार्ट II.5: वैश्विक पीएमआई: नए निर्यात आदेश



टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने और 50 से ऊपर की रीडिंग विस्तार और इसके विपरीत दर्शाते हैं।

स्रोत: एस एंड पी वैश्विक।

चार्ट II.6 : व्यापार नीति अस्थिरता (टीपीयू) सूचकांक



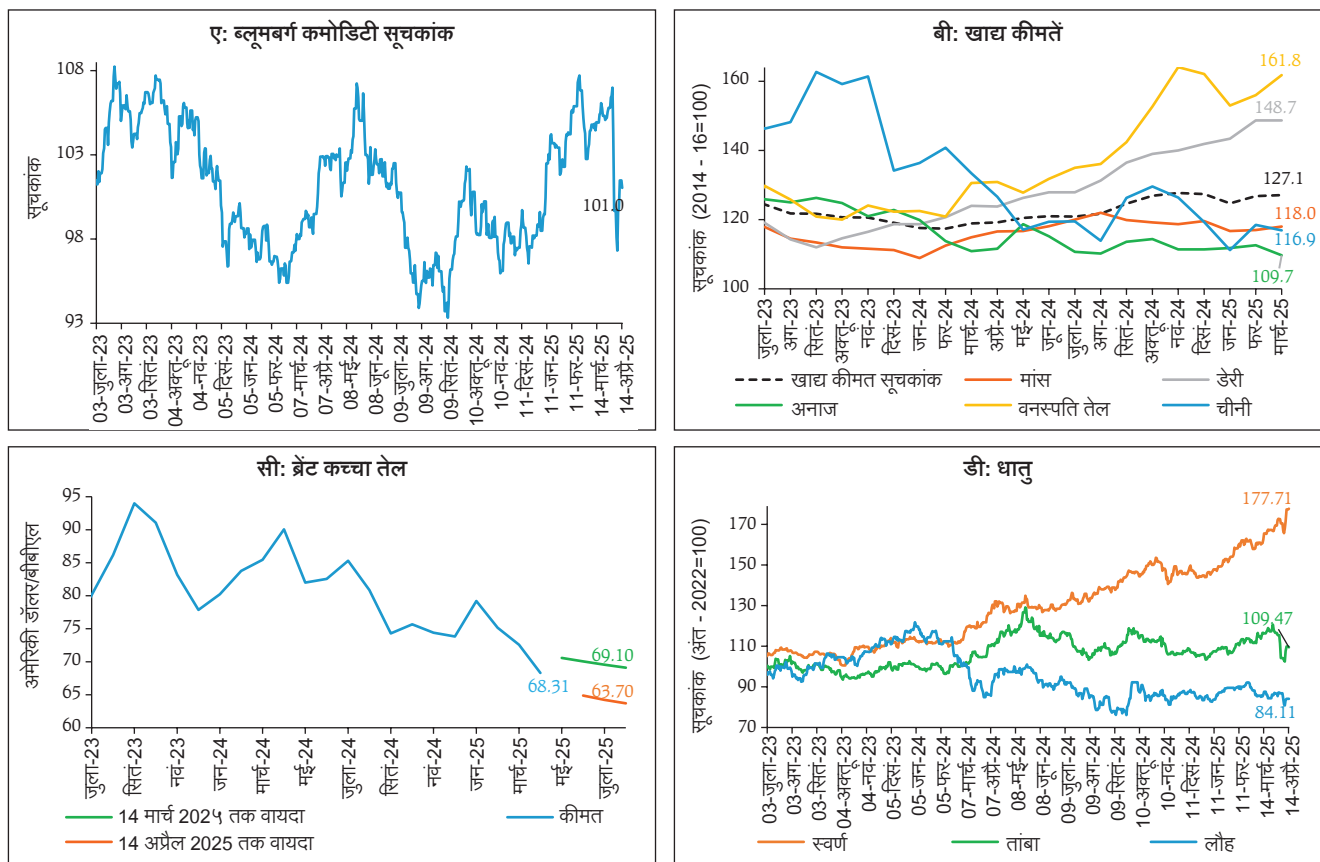
टिप्पणी: टीपीयू सूचकांक सात समाचार पत्रों के इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखागार की स्वचालित पाठ खोजों पर आधारित है: बोस्टन ग्लोब, शिकागो ट्रिब्यून, गार्जियन, लॉस एंजिल्स टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और वाशिंगटन पोस्ट। माप की गणना प्रत्येक समाचार पत्र के लिए व्यापार नीति अनिश्चितता (समाचार लेखों की कुल संख्या के हिस्से के रूप में) पर चर्चा करने वाले लेखों की मासिक आवृत्ति की गणना करके की जाती है।

स्रोत: [HTTPS://WWW.MATTEOIACOVIELLO.COM/TPU.HTM](https://www.matteoiacoviello.com/TPU.HTM)

गिरावट आई, हालांकि इसके बाद आंशिक रूप से सुधार हुआ (चार्ट II.7ए)।

एफएओ के खाद्य मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खाद्य कीमतों में मार्च में 0.3 प्रतिशत (एम-ओ-एम) की वृद्धि हुई, जो

चार्ट II.7: कमोडिटी और खाद्य कीमतें



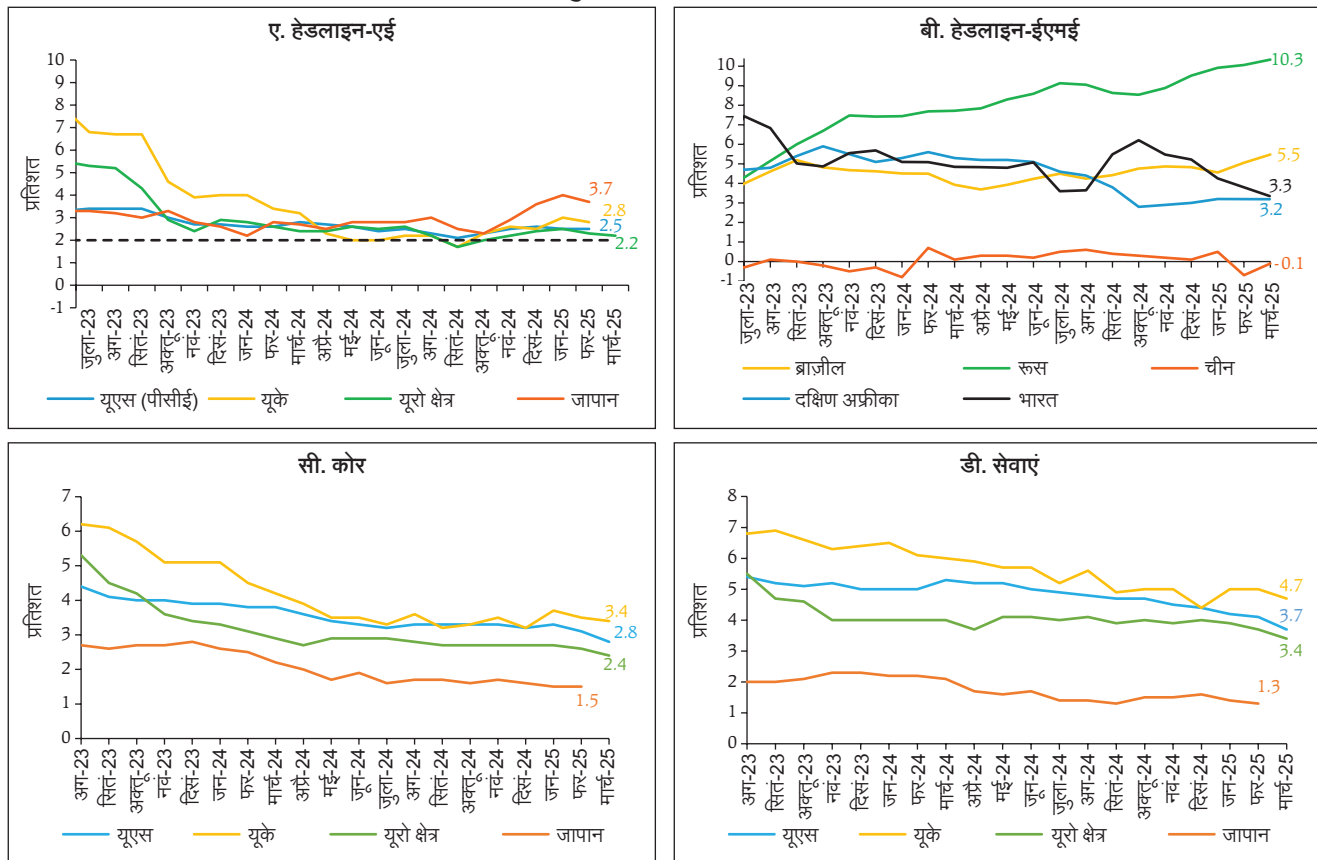
स्रोत: ब्लूमबर्ग; वर्ल्ड बैंक पिक शीट; और एफएओ।

मुख्य रूप से वनस्पति तेल की कीमतों में वृद्धि से प्रेरित थी, जो अनाज और चीनी की कीमतों में कमी से कुछ हद तक संतुलित थी (चार्ट 11.7बी)। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला और ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए जाने के बाद मार्च में कच्चे तेल की कीमतों में 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, अप्रैल में कीमतों में तेजी से गिरावट आई, ब्रेंट की कीमतें 9 अप्रैल को लगभग 63 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक गिर गईं - वृद्धि विघटनकारी टैरिफ युद्धों की आशंका के बीच लगभग चार वर्ष के निचले स्तर को छू गईं - (चार्ट 11.7सी)। इसके अलावा, ओपेक प्लस द्वारा तेल उत्पादन में कटौती को चरणबद्ध करने की अपनी योजना को आगे बढ़ाने की अप्रत्याशित घोषणा, जिससे मई से उत्पादन में वृद्धि हुई, ने भी कीमत में गिरावट में योगदान दिया। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर टैरिफ छूट के बाद, 14 अप्रैल को ब्रेंट ऑयल की कीमतें बढ़कर 67 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल हो गईं। वैश्विक मांग में अपेक्षित मंदी के कारण अप्रैल की शुरुआत में मूल धातु की कीमतों में भी भारी गिरावट आई, जिसके बाद मामूली सुधार हुआ। मार्च में स्वर्ण की कीमतें ऊँची बनी रहीं, बढ़ती व्यापारिक

अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित निवेश की माँग से उन्हें बल मिला। हालाँकि अप्रैल की शुरुआत में बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच स्वर्ण की कीमतों में कुछ कमी आई, लेकिन कीमतें फिर से बढ़कर 3200 अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर गईं (चार्ट 11.7डी)।

अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में हेडलाइन मुद्रास्फीति मध्यम बनी हुई है, हालांकि अंतिम उपभोक्ता कीमतों पर टैरिफ का प्रभाव-विस्तार एक प्रमुख अपसाइड जोखिम के रूप में उभरा है। अमेरिका में, सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च में 2.4 प्रतिशत (वाई-ओ-वाई) तक कम हो गई, जो फरवरी में 2.8 प्रतिशत थी। हालांकि, व्यक्तिगत उपभोग व्यय (पीसीई) अपस्फीतिकारक के संदर्भ में मुद्रास्फीति फरवरी में 2.5 प्रतिशत पर स्थिर रही। यूरो क्षेत्र में हेडलाइन मुद्रास्फीति फरवरी में 2.3 प्रतिशत से घटकर मार्च में 2.2 प्रतिशत हो गई। यूके और जापान में मुद्रास्फीति भी फरवरी में 20 बीपीएस और 30 बीपीएस से क्रमशः 2.8 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत तक कम हो गई (चार्ट 11.8ए)। ईएमई

चार्ट 11.8: मुद्रास्फीति – ईई और ईएमई



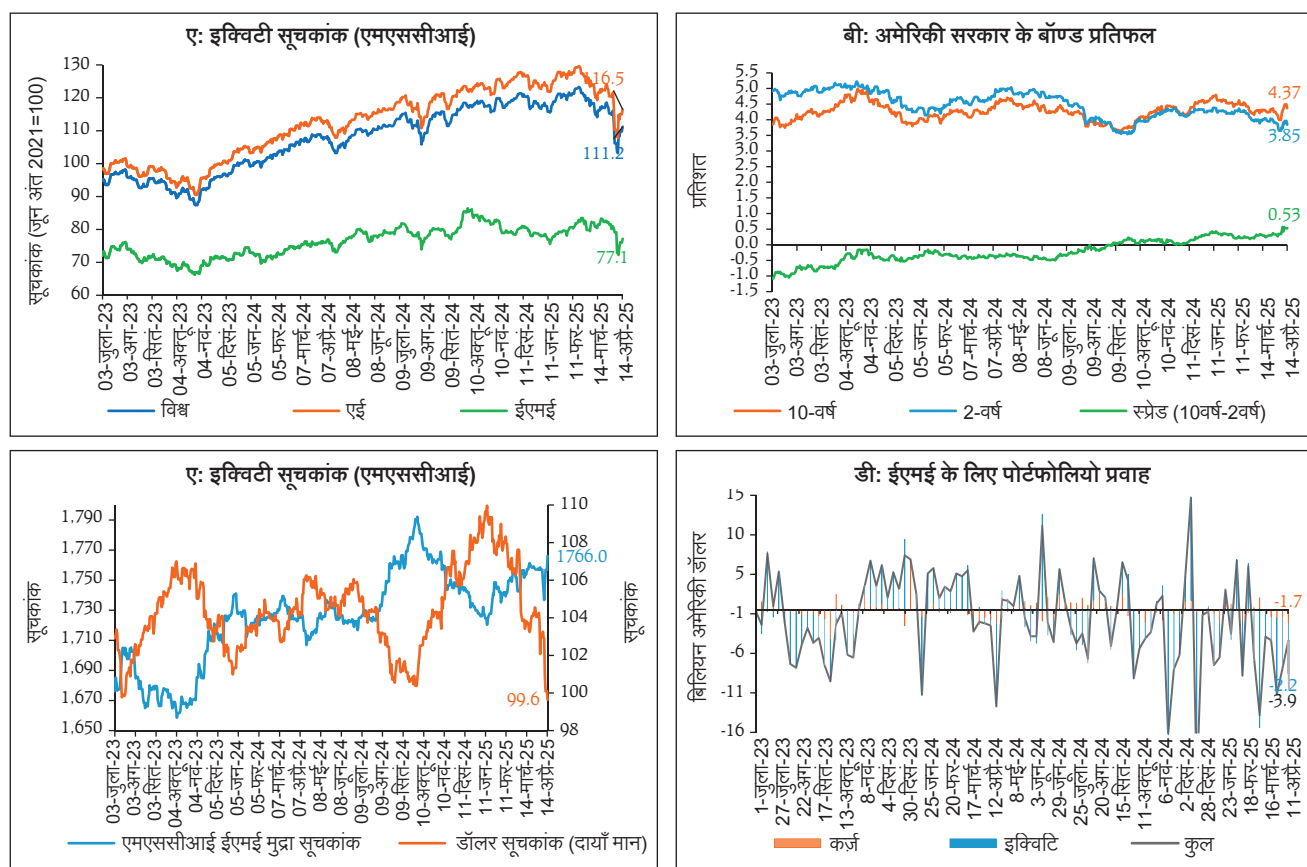
स्रोत: ब्लूमबर्ग; और ओईसीडी।

के बीच, ब्राजील और रूस में सीपीआई मुद्रास्फीति मार्च में बढ़ी, जबकि दक्षिण अफ्रीका में स्थिर रही। दूसरी ओर, चीन अपस्फीति में बना रहा, सीपीआई ने मार्च में 0.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट दर्ज की (चार्ट II.8बी)। जापान को छोड़कर, प्रमुख आई में कोर मुद्रास्फीति हेडलाइन से ऊपर रही, जबकि यूएस और यूरो क्षेत्र में सेवाओं की मुद्रास्फीति में कमी आई (चार्ट II.8सी और डी)।

व्यापार नीति की अनिश्चितता के बीच जोखिम-रहित भावना ने मार्च और अप्रैल की शुरुआत में शेयर बाजार में भारी गिरावट में योगदान दिया। मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल (एमएससीआई) विश्व शेयर सूचकांक ने मार्च में 4.1 प्रतिशत (मासिक) की बढ़त खो दी, जिसकी मुख्य वजह आई शेयर बाजारों में गिरावट थी। टैरिफ घोषणाओं के बाद शेयर बाजारों में बिकवाली तेज हो गई, जिससे व्यापक गिरावट आई और 8

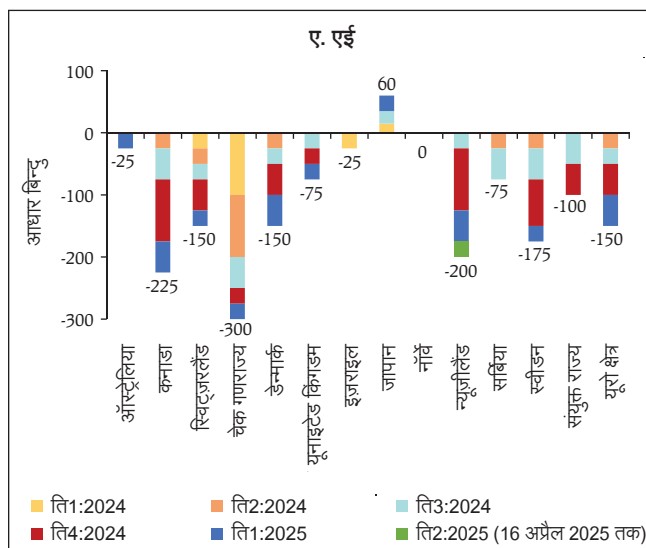
अप्रैल तक शेयर सूचकांक में 10.2 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई (चार्ट II.9ए)। टैरिफ कार्यान्वयन में ठहराव की घोषणा के बाद अधिकांश भौगोलिक क्षेत्रों में इक्विटी बाजारों ने तेजी से सुधार का मंचन किया, हालांकि अस्थिरता उच्च बनी हुई है। अमेरिकी सरकार की प्रतिभूतियों पर प्रतिफल मार्च में उतार-चढ़ाव बना रहा, क्योंकि एक अशांत वैश्विक वातावरण ने भावनाओं को प्रभावित किया। व्यापार युद्ध की आशंका तेज होने के बाद अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी प्रतिफल 6 अप्रैल को 4 प्रतिशत से नीचे आ गया, जिससे निवेशकों को सुरक्षित आस्तियों में धन लगाने के लिए प्रेरित किया गया (चार्ट II.9बी)। अगले सप्ताह तक प्रतिफल में सुधार हुआ, क्योंकि स्वर्ण और स्विस् फ्रैंक के लिए सुरक्षित स्थान की चाह बढ़ गई। अमेरिकी डॉलर सूचकांक (डीएक्सवाई) में मार्च में 3.2 प्रतिशत और अप्रैल (14 अप्रैल तक) में 4.4 प्रतिशत की गिरावट आई क्योंकि

चार्ट II.9: वैश्विक वित्तीय बाजार

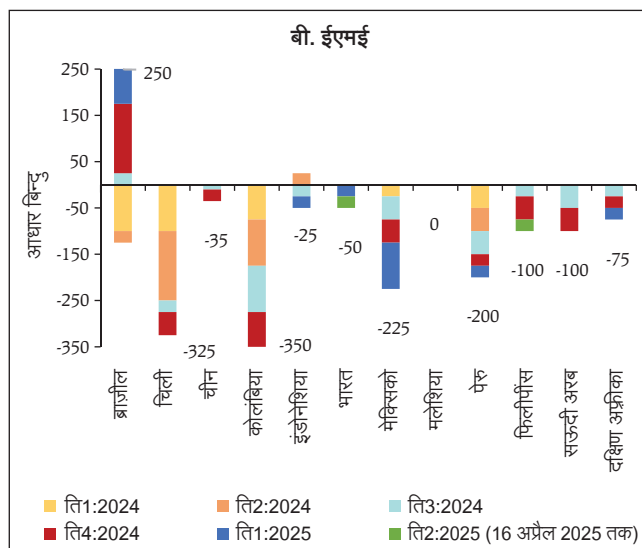


स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आईआईएफ।

चार्ट II.10: नीतिगत दरों में परिवर्तन



स्रोत: ब्लूमबर्ग।



निवेशकों ने अमेरिका में मंदी की उच्च संभावना जताई। ईएमई के लिए एमएससीआई मुद्रा सूचकांक मार्च में मामूली रूप से बढ़ा और अप्रैल (14 अप्रैल तक) में पूंजी बहिर्वाह के बावजूद, ऋण और इक्विटी दोनों में, बढ़ते नकारात्मक दबाव में मोटे तौर पर स्थिर रहा (चार्ट II.9सी और II.9डी)।

मौद्रिक नीति की कार्रवाइयों के संदर्भ में, अधिकांश देशों ने एक ठहराव बनाए रखा, जबकि कुछ ने सावधानी के साथ दरों में कमी की। ईई केंद्रीय बैंकों में, अमेरिका, जापान, यूके, स्वीडन, नॉर्वे और चेक गणराज्य ने मार्च में अपनी प्रमुख दरों को अपरिवर्तित रखा, जबकि ईसीबी और स्विट्जरलैंड ने इसे 25 बीपीएस घटा दिया। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इजराइल ने अपनी अप्रैल की बैठकों में यथास्थिति बनाए रखी जबकि न्यूजीलैंड ने अपनी आधिकारिक नकद दर में 25 बीपीएस की कटौती की (चार्ट II.10ए)। ईएमई केंद्रीय बैंकों में, पोलैंड और पेरू ने अप्रैल में यथास्थिति बनाए रखी, और चीन, रूस, हंगरी, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका और चिली ने मार्च में अपनी नीति दरों को अपरिवर्तित बनाए रखने का विकल्प चुना। मेक्सिको ने मार्च में अपनी नीतिगत दर में 50 बीपीएस की कटौती की और फिलीपींस ने अप्रैल में अपनी प्रमुख दर में 25 बीपीएस की कमी की। इसके विपरीत, ब्राजील ने मार्च में नीतिगत दर में 100 बीपीएस की बढ़ोतरी की (चार्ट II.10बी)।

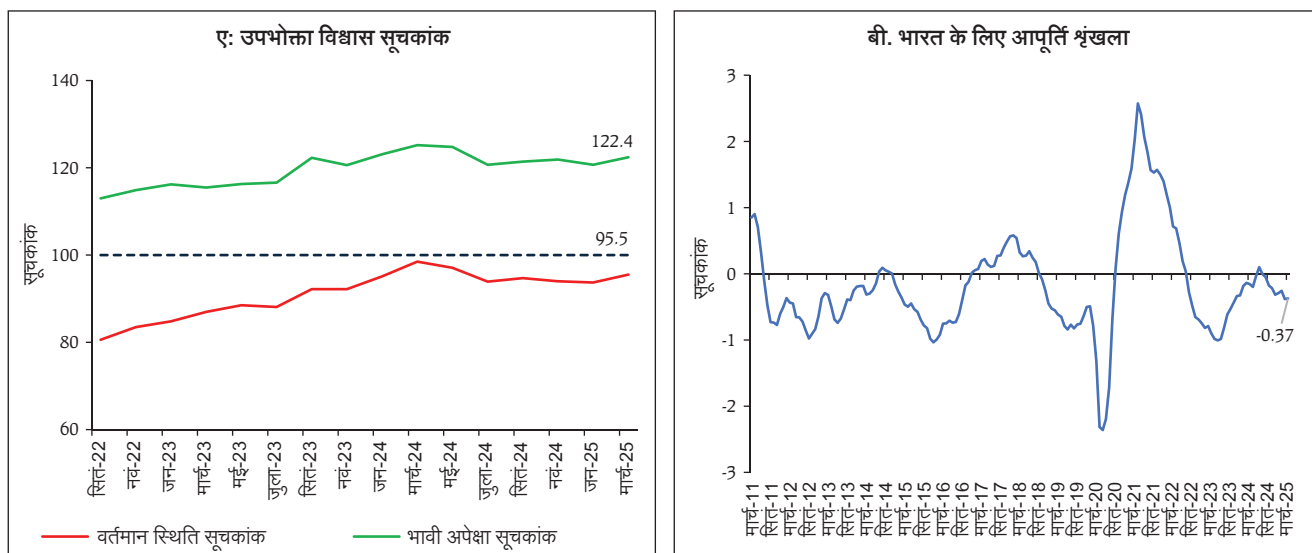
III. घरेलू घटनाक्रम

व्यापार तनावों से उत्पन्न मजबूत वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत घरेलू वृद्धि आवेगों और मजबूत समष्टि आधार पर आघात-सहनीय बनी हुई है। उपभोक्ता और व्यवसाय आर्थिक परिदृश्य के बारे में आशावादी बने हुए हैं। रिजर्व बैंक के नवीनतम उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण के अनुसार, वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई) में क्रमिक रूप से सुधार हुआ, हालांकि यह तटस्थ स्तर से नीचे रहा। इस बीच, भावी अपेक्षा सूचकांक (एफआईआई) और मजबूत हुआ, जो निवल आधार पर उत्तरदाताओं के आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है (चार्ट III.1ए)। आपूर्ति श्रृंखला दबाव मार्च में ऐतिहासिक औसत स्तरों से नीचे बने रहे (चार्ट III.1बी)।

कुल मांग

उच्च आवृत्ति संकेतक बताते हैं कि ति4: 2024-25 के दौरान कुल मांग मोटे तौर पर आघात-सहनीय बनी रही। ई-वे बिल और टोल संग्रह जैसे संकेतकों ने बाद में अनुक्रमिक कमी के बावजूद मार्च 2025 में दोहरे अंकों में मजबूत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की (चार्ट III.2ए और चार्ट III.2बी)।

चार्ट III.1: आर्थिक गतिविधि संकेतक



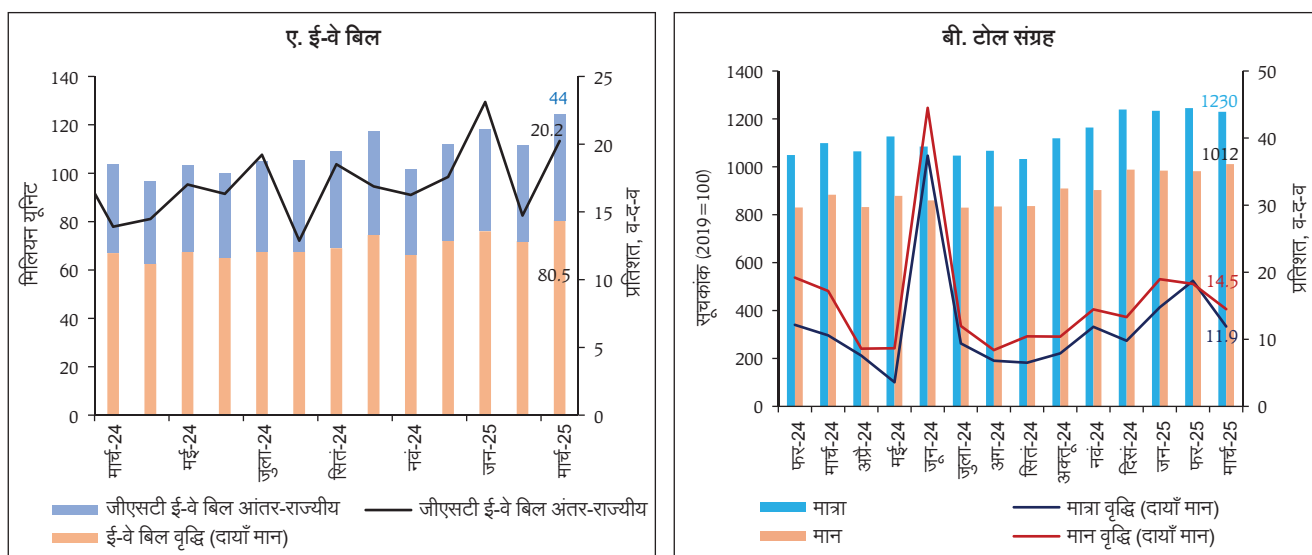
स्रोत: सीसीएस, आरबीआई; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

ऑटोमोबाइल सेक्टर ने मार्च में सुधार के संकेत दिखाए। थोक ऑटोमोबाइल बिक्री में मार्च में दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई; स्कूटर की बिक्री ने मजबूत ग्रामीण मांग (चार्ट III.3ए और 3बी) को दर्शाते हुए समग्र दोपहिया वाहनों की बिक्री में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ट्रैक्टर की बिक्री में भी लगातार चौथे महीने दो अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। अनुक्रमिक सुधार के बावजूद, वाहन पंजीकरण ने गैर-परिवहन और परिवहन वाहन

दोनों खंडों में वर्ष-दर-वर्ष संकुचन दर्ज किया (चार्ट III.3सी)। मार्च में पेट्रोलियम की खपत में 3.1 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई (चार्ट III.3डी)।

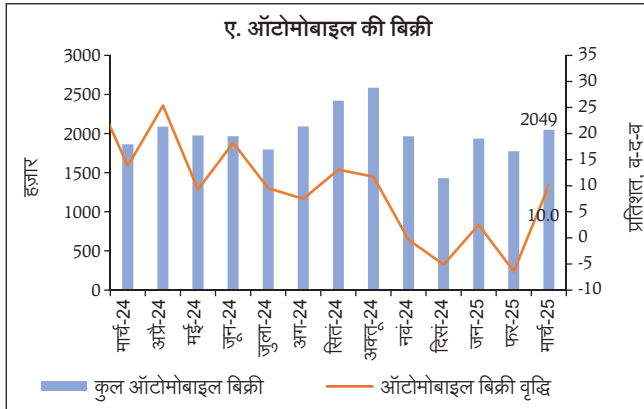
पीएमआई सर्वेक्षण के अनुसार, विस्तार की गति में क्रमिक मंदी के बावजूद संगठित विनिर्माण और सेवा दोनों क्षेत्रों में रोजगार सृजन में वृद्धि जारी रही (चार्ट III.4)।

चार्ट III.2: ई-वे बिल और टोल संग्रह

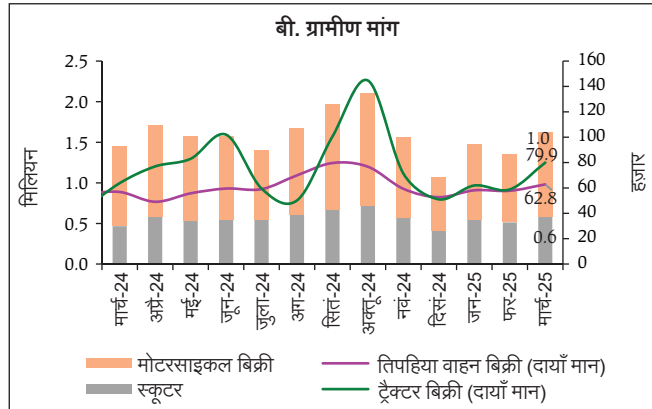


स्रोत: जीएसटीएन; आरबीआई।

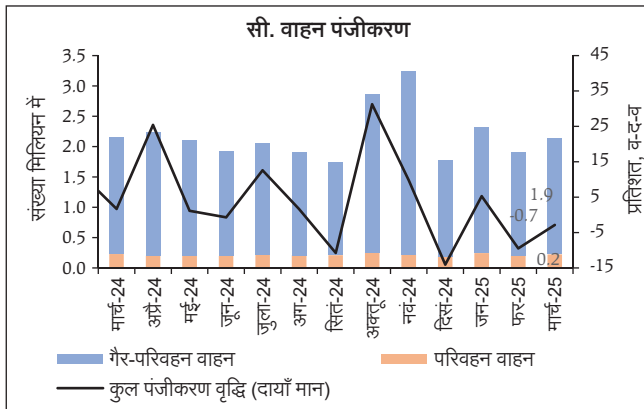
चार्ट III.3: ऑटोमोबाइल क्षेत्र संकेतक



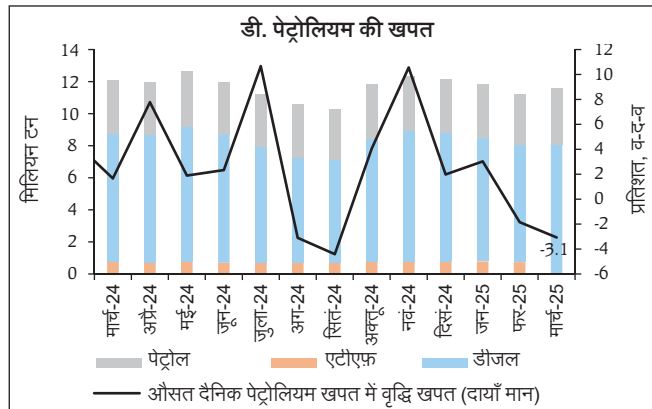
स्रोत: सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम)।



स्रोत: सियाम; और ट्रैक्टर मेकनाइजेशन एसोसिएशन (टीएमए)।

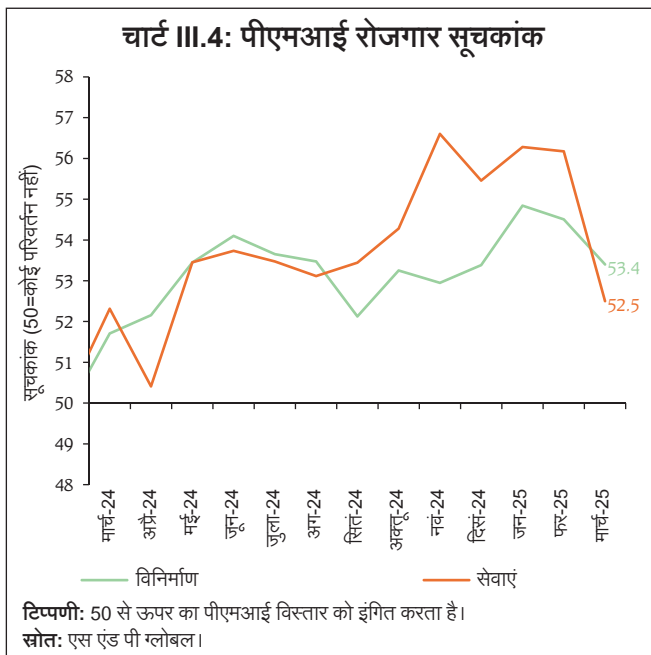


स्रोत: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय।



स्रोत: पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ।

रबी की फसल शुरू होने के साथ, महात्मा गांधी राष्ट्रीय

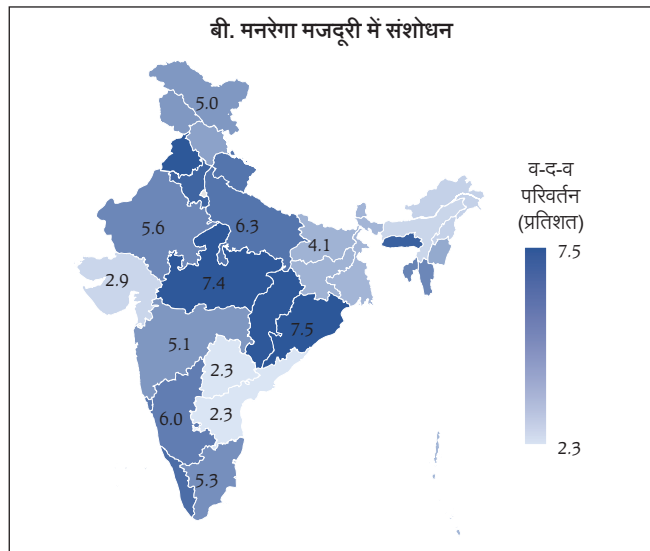
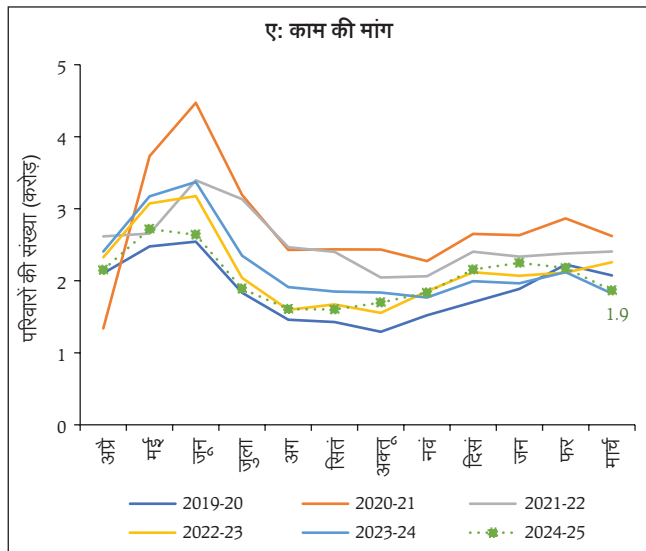


ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मार्च में काम की मांग में गिरावट आई। वर्ष 2024-25 के दौरान काम की वार्षिक मांग में पिछले वर्ष की तुलना में 7.4 प्रतिशत की गिरावट आई (चार्ट III.5ए), मनरेगा के तहत दैनिक मजदूरी 01 अप्रैल 2025 (चार्ट III.5बी) से राज्यों में 2.3 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत (₹7 - ₹26 प्रति दिन) के बीच बढ़ गई है।

मार्च 2025 में भारत का पण्य वस्तु निर्यात 0.7 प्रतिशत (व-द-व) बढ़कर 42.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया - जो गैर-तेल निर्यात में सुधार से प्रेरित - लगातार चार महीनों के संकुचन के बाद एक पलटाव को दर्शाता है (चार्ट III.6)।

30 प्रमुख वस्तुओं में से 18 का निर्यात (2023-24 में निर्यात बास्केट का 42.0 प्रतिशत हिस्सा) मार्च में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर बढ़ा। इलेक्ट्रॉनिक सामान, दवा और फार्मास्यूटिकल्स, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद और चावल ने मार्च में निर्यात वृद्धि का समर्थन किया, जबकि कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन,

चार्ट III.5: मनरेगा के तहत काम की मांग करने वाले परिवार



स्रोत: ग्रामीण विकास मंत्रालय।

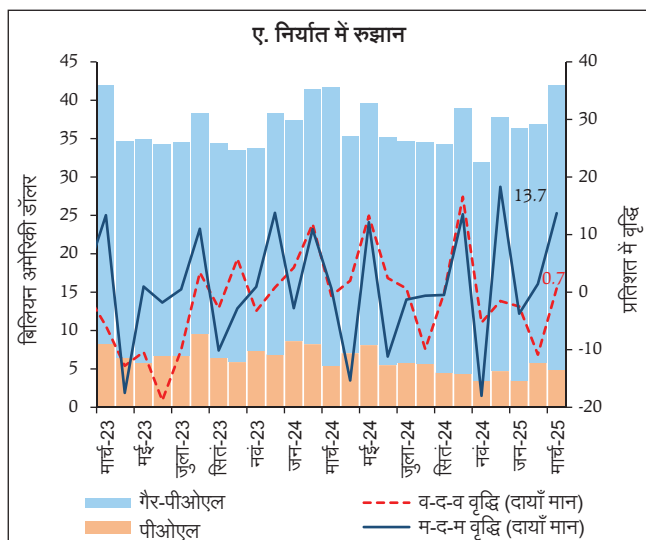
पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, हस्तनिर्मित कालीन को छोड़कर हस्तशिल्प, और मसालों ने नकारात्मक योगदान दिया (चार्ट III.7)।

वर्ष 2024-25 (अप्रैल-मार्च) के दौरान, भारत का पण्य वस्तु निर्यात 0.1 प्रतिशत बढ़कर 437.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जिसका मुख्य नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक सामान, इंजीनियरिंग सामान, दवा और फार्मास्यूटिकल्स, चावल और

वस्त्र ने किया, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों, रत्न और आभूषण और लौह अयस्क ने निर्यात को नीचे खींच लिया।

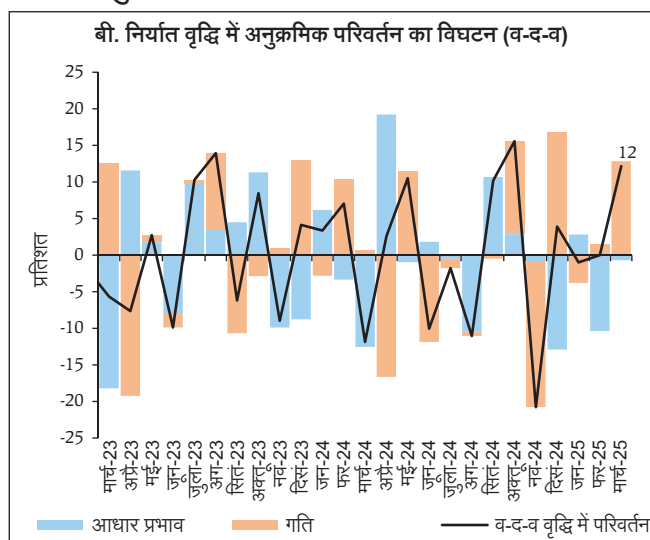
मार्च 2025 में 20 प्रमुख गंतव्यों में से 10 के निर्यात में विस्तार हुआ, जबकि 2024-25 के दौरान 20 प्रमुख गंतव्यों में से 13 में निर्यात का विस्तार हुआ, जिसमें अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात और नीदरलैंड शीर्ष तीन निर्यात गंतव्य थे।

चार्ट III.6: भारत का पण्य वस्तु निर्यात

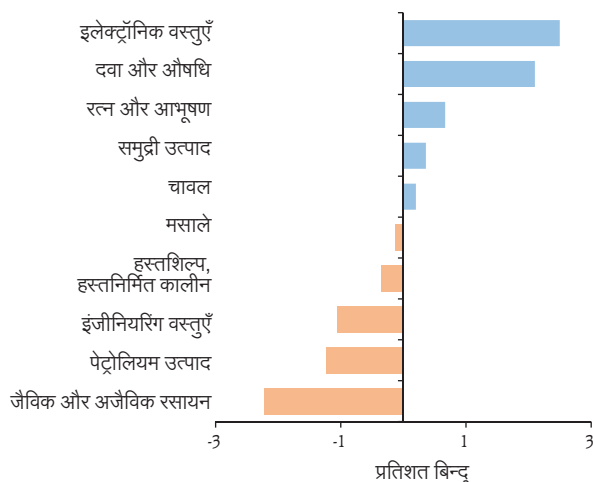


टिप्पणी: पीओएल: पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक।

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआई एंड एस; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

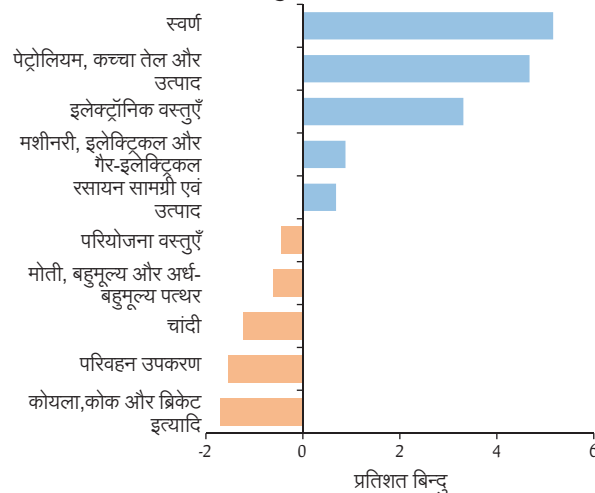


चार्ट III.7: भारत का पण्य वस्तु निर्यात-सापेक्ष योगदान
(मार्च 2024 की तुलना में मार्च 2025)



स्रोत: पीआईबी; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट III.9: भारत का पण्य वस्तु आयात – सापेक्ष योगदान
(मार्च 2024 की तुलना में मार्च 2025)



स्रोत: पीआईबी; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

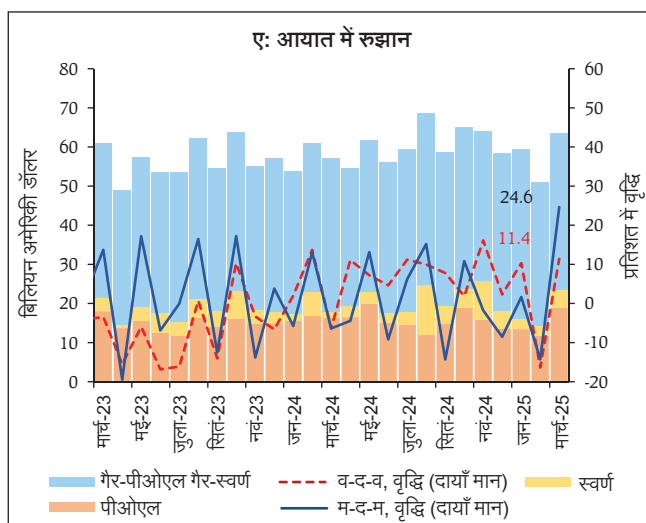
मार्च 2025 में 63.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के पण्य वस्तु आयात में 11.4 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण तेल, स्वर्ण और इलेक्ट्रॉनिक आयात का बढ़ना था। 30 प्रमुख वस्तुओं में से, 22 वस्तुओं (आयात बास्केट का 81.7 प्रतिशत हिस्सा) ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर विस्तार दर्ज किया (चार्ट III.8)।

स्वर्ण, पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, और रासायनिक सामग्री और उत्पादों ने

आयात वृद्धि का समर्थन किया, जबकि कोयला, कोक और ब्रिकेट, परिवहन उपकरण, चांदी, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थर और परियोजना के सामान ने आयात में कमी लाई (चार्ट III.9)।

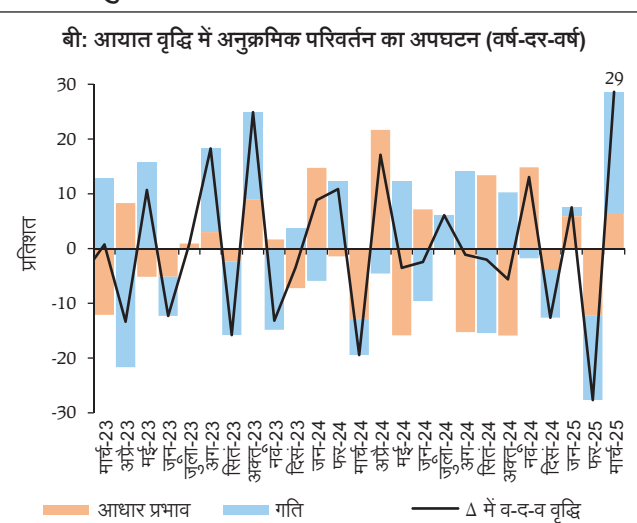
वर्ष 2024-25 के दौरान भारत के पण्य वस्तु आयात में 720.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई, जिसमें मुख्य रूप से स्वर्ण, इलेक्ट्रॉनिक सामान और पेट्रोलियम, कच्चा तेल और उत्पाद शामिल हैं, जबकि कोयला, कोक और ब्रिकेट

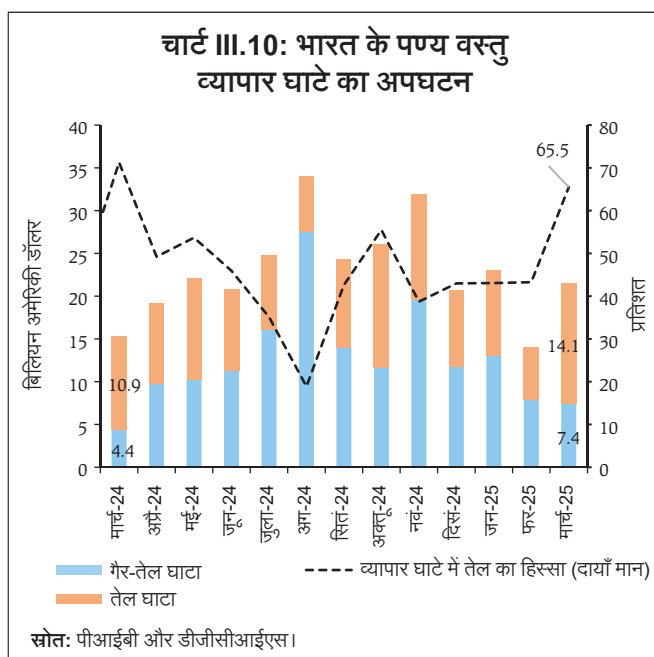
चार्ट III.8: भारत का पण्य वस्तु आयात



टिप्पणी: पीओएल; पेट्रोल, तेल और स्नेहक।

स्रोत: पीआईबी; डीजीसीआईएस; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।





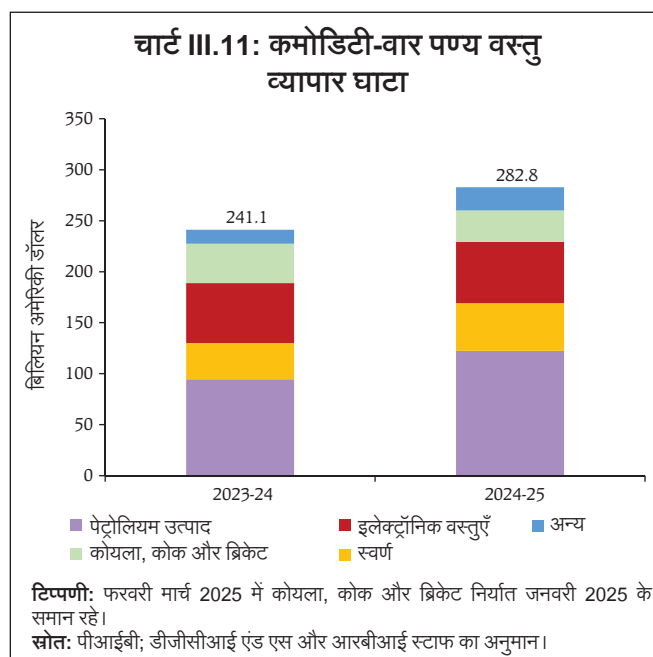
आदि, मोती, कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों ने नकारात्मक योगदान दिया।

मार्च 2025 में 20 प्रमुख स्रोत देशों में से 11 से आयात में संकुचन हुआ, जबकि 20 प्रमुख स्रोत देशों में से 13 से आयात वर्ष 2024-25 में बढ़ा। प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका से आयात में वृद्धि हुई, जबकि रूस से आयात में मार्च में गिरावट आई।

पण्य वस्तु व्यापार घाटा मार्च 2024 में 15.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर मार्च 2025 में 21.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। मार्च में तेल घाटा बढ़कर 14.1 अरब डॉलर हो गया, जो एक वर्ष पहले 10.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। हालांकि, कुल व्यापार घाटे में इसकी हिस्सेदारी मार्च में घटकर 65.5 प्रतिशत रह गई, जो एक वर्ष पहले 71.3 प्रतिशत थी। इसी प्रकार, गैर-तेल घाटा एक वर्ष पूर्व 4.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर मार्च में 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट III.10)।

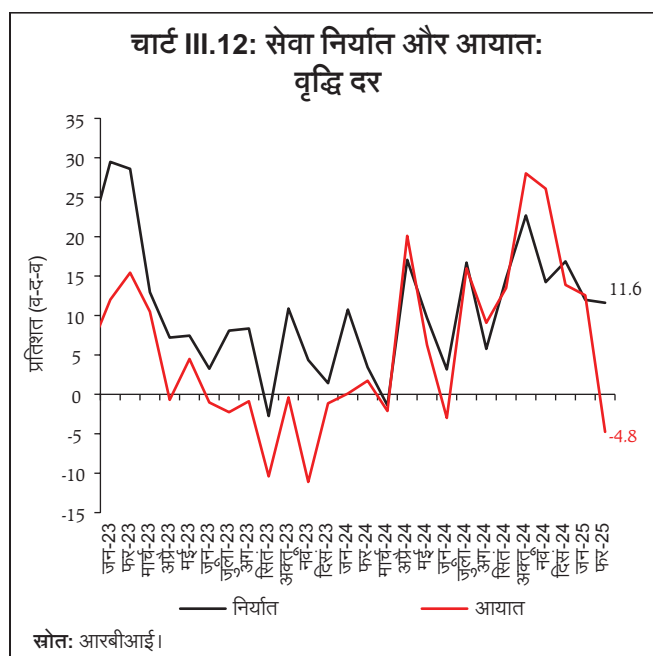
वर्ष 2024-25 के दौरान, पण्य वस्तु व्यापार घाटा एक वर्ष पहले के 241.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 282.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। घाटे का सबसे बड़ा स्रोत पेट्रोलियम उत्पाद थे, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक सामान और स्वर्ण थे (चार्ट III.11)।

फरवरी 2025 में, निवल सेवाओं के निर्यात आय में 30.6 प्रतिशत की मजबूत वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। सॉफ्टवेयर

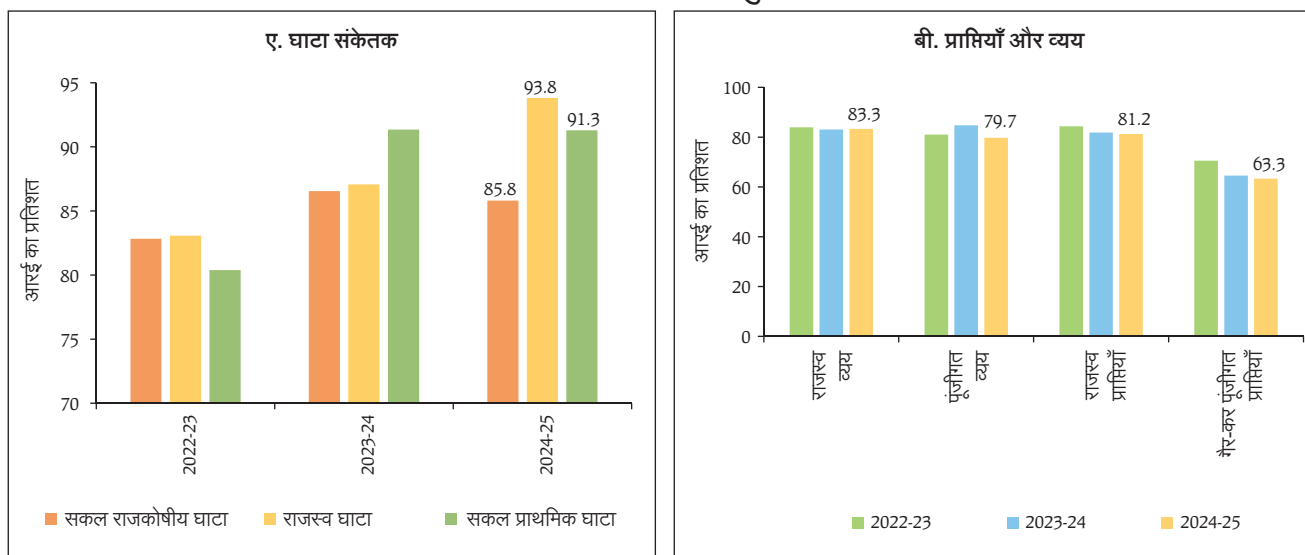


और व्यावसायिक सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के कारण सेवा निर्यात 11.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 31.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जबकि सेवा आयात 4.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) घटकर 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया (चार्ट III.12)।

अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान, सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) – संशोधित अनुमानों (आरई) के अनुपात के रूप में – कम था जबकि राजस्व घाटा (आरडी) पिछले वर्ष की



चार्ट III.13: अप्रैल-फरवरी के दौरान प्रमुख राजकोषीय संकेतक



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़; और सीजीए।

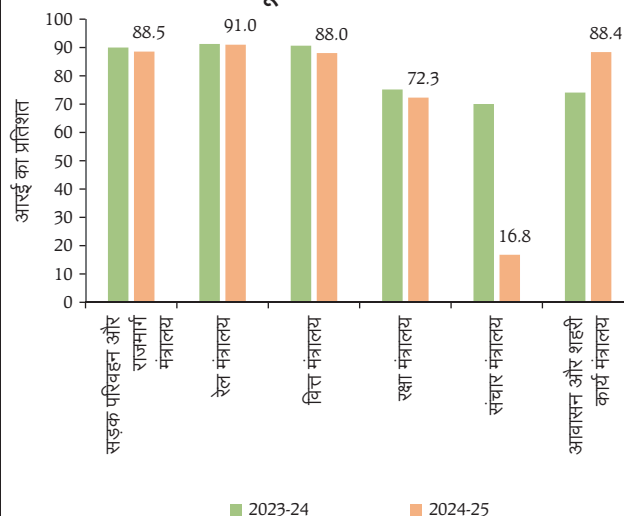
इसी अवधि की तुलना में अधिक था। तथापि, संशोधित अनुमान के अनुपात के रूप में सकल प्राथमिक घाटा पिछले वर्ष के समान ही रहा (चार्ट III.13ए)। अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान, प्राप्ति और व्यय के मोर्चे पर प्रमुख राजकोषीय संकेतक, जैसे राजस्व प्राप्ति, राजस्व व्यय और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति (2024-25 के लिए संशोधित अनुमान के प्रतिशत के रूप में) मोटे तौर पर पिछले वर्ष के पैटर्न के अनुरूप रहे (चार्ट III.13बी)।

अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान केंद्र सरकार के कुल व्यय में 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि अप्रैल-फरवरी 2023-24 के दौरान 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। व्यय घटकों के बीच, राजस्व व्यय ने अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान 4.7 प्रतिशत (व-द-व) की वृद्धि दर्ज की, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 1.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। ब्याज भुगतान और प्रमुख सब्सिडी को छोड़कर राजस्व व्यय में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 3.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसने 2024-25 (आरई) के लिए अपने लक्ष्य का 81.1 प्रतिशत प्राप्त किया। पूंजीगत व्यय में अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 0.8 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। 2024-25 के लिए संशोधित अनुमान के प्रतिशत के अनुसार, संचार मंत्रालय को छोड़कर, शीर्ष छह मंत्रालयों (पूंजीगत व्यय में उच्चतम

हिस्सेदारी के साथ) का पूंजीगत व्यय मोटे तौर पर 2023-24 (आरई) में देखे गए पैटर्न के अनुरूप था (चार्ट III.14)।

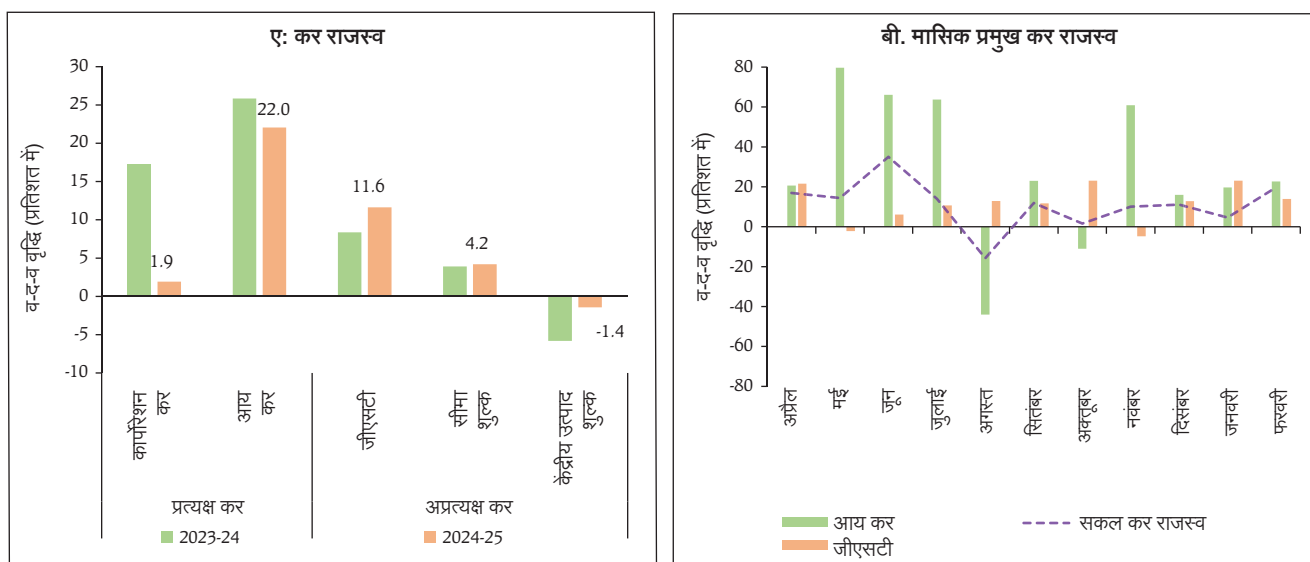
प्राप्ति के मामले में, केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति में अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान 13.5 प्रतिशत की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान दर्ज 11.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी। प्रत्यक्ष

चार्ट III.14: अप्रैल-फरवरी के दौरान मंत्रालय-वार पूंजीगत व्यय



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़; और सीजीए।

चार्ट III.15 : अप्रैल-फरवरी के दौरान कर प्राप्ति



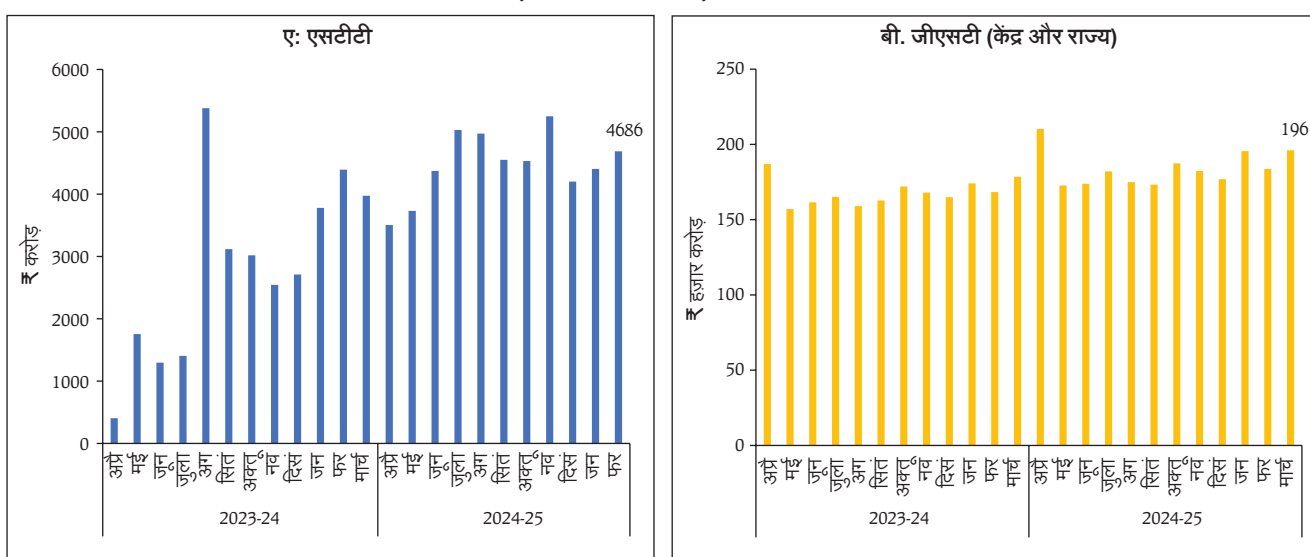
स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़; और सीजीए।

करों में वर्षानुवर्ष आधार पर 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि अप्रत्यक्ष करों में 7.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे सकल कर राजस्व में 10.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कर संग्रह में मजबूत वृद्धि मुख्य रूप से आयकर, जीएसटी और सीमा शुल्क द्वारा संचालित थी (चार्ट III.15ए)। इसी तरह, माह-वार प्रदर्शन के संदर्भ में, जीएसटी और आयकर से संग्रह ने अधिकांश

महीनों के लिए सकारात्मक वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की, जिससे 2024-25 में कर राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई (चार्ट III.15बी)।

अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) से संग्रह में वर्ष-दर-वर्ष 65.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चार्ट III.16ए)। रिज़र्व बैंक से 2.11 लाख करोड़ रुपये के अधिशेष हस्तांतरण के कारण, अप्रैल-फरवरी 2024-25 के

चार्ट III.16: एसटीटी और जीएसटी में मासिक रुझान



स्रोत: सीजीए; पत्र सूचना कार्यालय (पीआईबी); और जीएसटी पोर्टल।

दौरान गैर-कर राजस्व संग्रह में 36.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर, अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान कुल प्राप्तियों में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 10.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

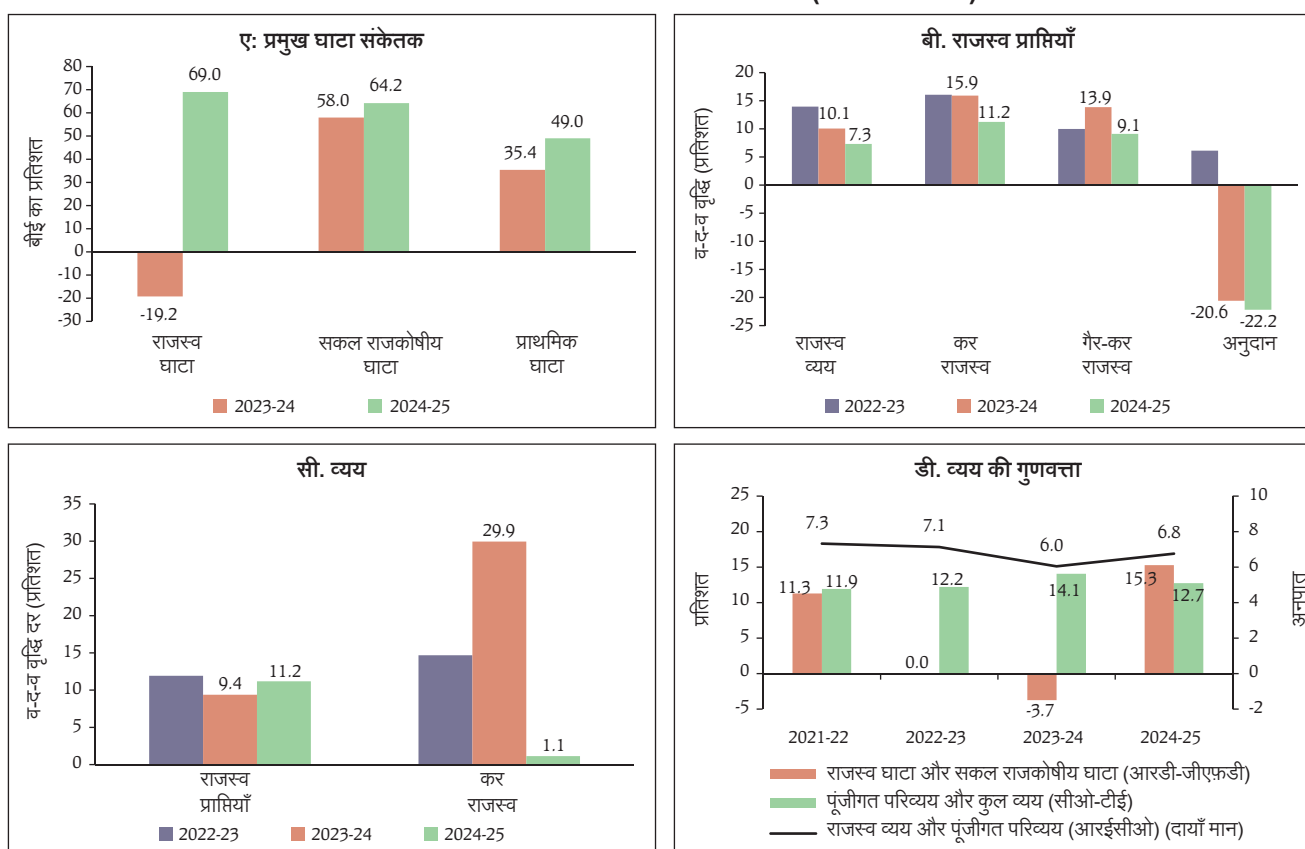
मार्च 2025 में, सकल जीएसटी संग्रह (केंद्र और राज्य) बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो 2017 से शुरुआत के बाद से दूसरा सबसे अधिक मासिक संग्रह है। वर्ष 2024-25 के दौरान संचयी जीएसटी संग्रह 22.09 लाख करोड़ रुपये था, जो 2023-24 की तुलना में 9.4 प्रतिशत अधिक है (चार्ट III.16बी)। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद, हाल के दिनों में मजबूत जीएसटी संग्रह घरेलू आर्थिक गतिविधि की आघात-सहनीयता को रेखांकित करता है।

फरवरी 2025 तक उपलब्ध अनंतिम आंकड़ों के अनुसार, राज्यों का संयुक्त जीएफडी 2024-25 के लिए अपने बजट

अनुमानों के 64.2 प्रतिशत तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष के 58.0 प्रतिशत के स्तर से अधिक है (चार्ट III.17ए)। वर्ष 2024-25 के दौरान राज्यों की राजस्व प्राप्तियों में 7.3 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई, जिसका मुख्य कारण केंद्र से अनुदान में गिरावट है। कर राजस्व आघात-सहनीय रहा, 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, हालांकि पिछले वर्ष में देखी गई 15.9 प्रतिशत की वृद्धि से कम रही (चार्ट III.17बी)। राज्यों के वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) में अच्छी वृद्धि हुई, जबकि राज्य उत्पाद शुल्क में गिरावट आई। इसके अतिरिक्त, बिक्री कर/वैट में पिछले वर्ष की गिरावट के बाद उछाल आया।

अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान राज्यों के राजस्व व्यय में 11.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि पूंजीगत व्यय में 1.1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई (चार्ट III.17सी)। अप्रैल-जनवरी 2024-25 के दौरान, केंद्र सरकार ने 'पूंजी निवेश के

चार्ट III.17: राज्यों की राजकोषीय स्थिति (अप्रैल-फरवरी)



टिप्पणी: डेटा 20 राज्यों से संबंधित है।

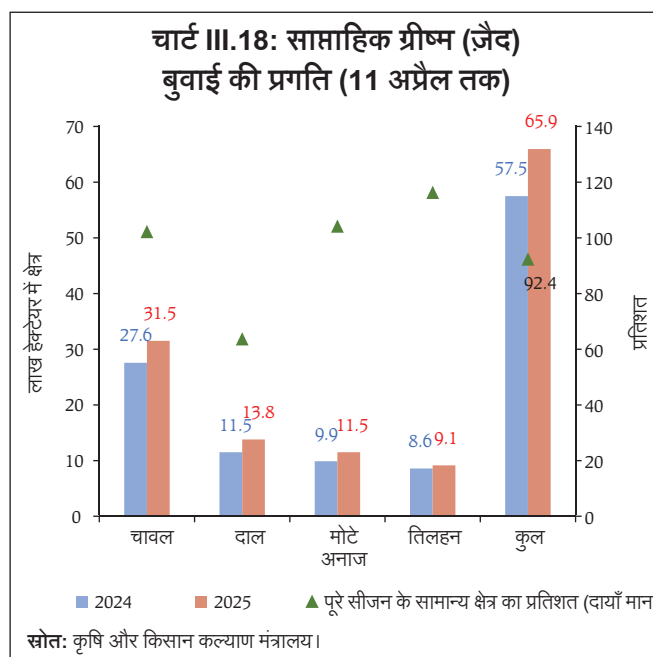
स्रोत: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।

लिए राज्यों को विशेष सहायता की योजना' के तहत वित्तीय सहायता के रूप में 1.1 लाख करोड़ रुपए जारी किए हैं, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान 1.25 लाख करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान का 88.6 प्रतिशत है। राजस्व व्यय में तेजी से वृद्धि के कारण अप्रैल-फरवरी 2024-25 के दौरान राज्यों का राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय (आरईसीओ) अनुपात बढ़कर 6.8 हो गया, जिससे व्यय की गुणवत्ता कमजोर हो गई (चार्ट III.17डी)। इसी तरह, कुल व्यय (सीओ-टीई) में पूंजीगत परिव्यय की हिस्सेदारी पिछले वर्ष के 14.1 प्रतिशत से घटकर 2024-25 के दौरान 12.7 प्रतिशत हो गई।

कुल आपूर्ति

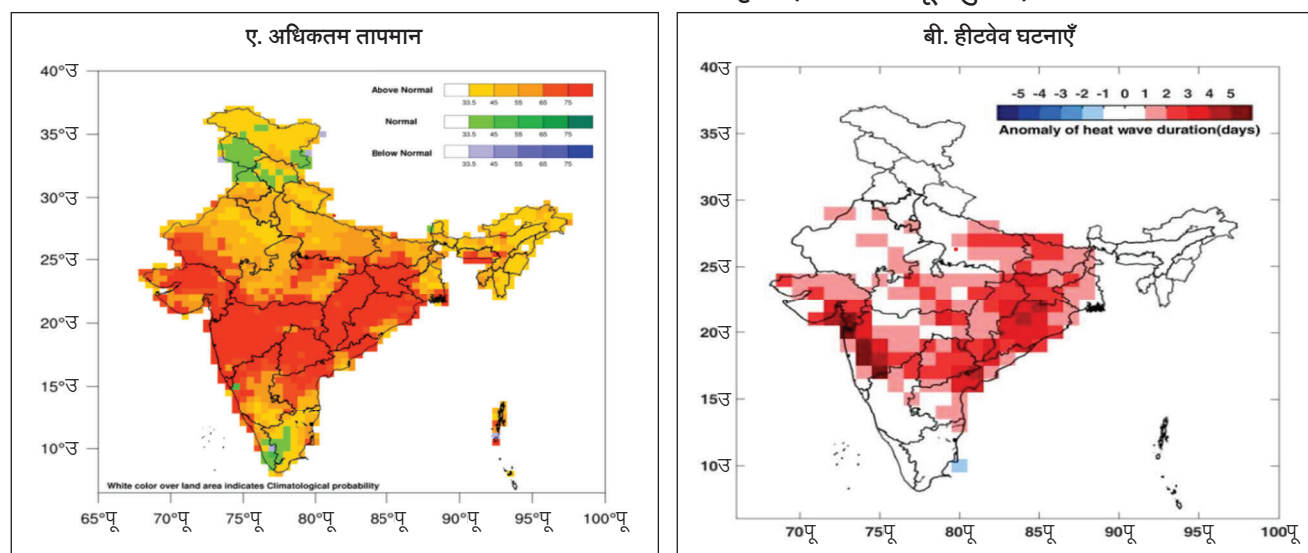
11 अप्रैल 2025 तक, ग्रीष्मकालीन बुवाई का 92.4 प्रतिशत पूरा हो गया और रकबा एक वर्ष पहले दर्ज किए गए स्तरों से 14.7 प्रतिशत अधिक था (चार्ट III.18)। सभी प्रमुख फसलों के तहत क्षेत्र में पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रकबा दर्ज किया गया।

गर्मी के महीनों (अप्रैल से जून) के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान (अधिकतम और न्यूनतम) और सामान्य से अधिक हीटवेव दिनों की संख्या का अनुमान



लगाया जाता है, जिससे गर्मियों की फसलों पर चिंता बढ़ जाती है (चार्ट III.19)। बहरहाल, पश्चिमी विक्षोभ के कारण चयनित क्षेत्रों में बारिश तापमान वृद्धि को नियंत्रण में रख सकती है। इसके अतिरिक्त, अधिकांश रबी फसलों (अर्थात गेहूं, रेपसीड, सरसों और चना) की कटाई अप्रैल तक पूरी होने की उम्मीद है, जिससे हीटवेव उनके लिए चिंता का विषय कम हो जाएगी (चार्ट III.19)।

चार्ट III.19: अप्रैल के लिए तापमान परिदृश्य (संभाव्यता पूर्वानुमान)



जलाशय स्तर (161 प्रमुख जलाशयों पर आधारित) कुल जलाशय क्षमता (11 अप्रैल 2025 तक) का 37 प्रतिशत था, जो पिछले वर्ष के साथ-साथ दशकीय औसत स्तरों से अधिक है (चार्ट III.20)।

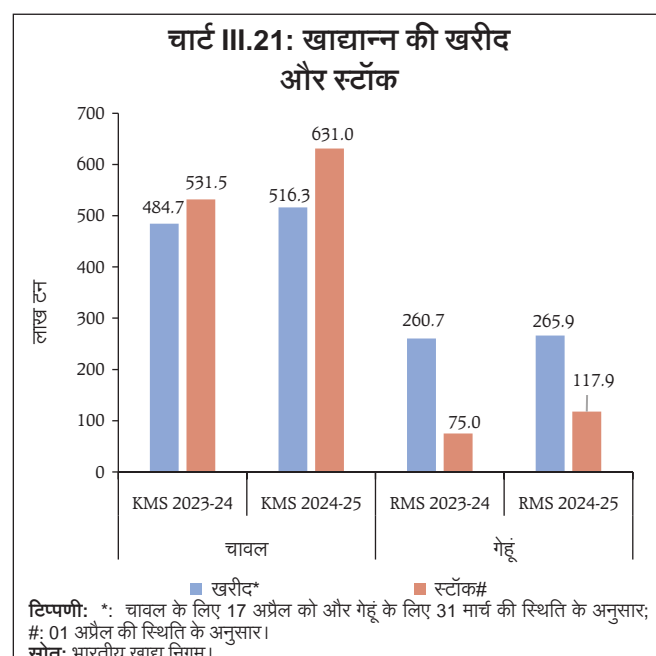
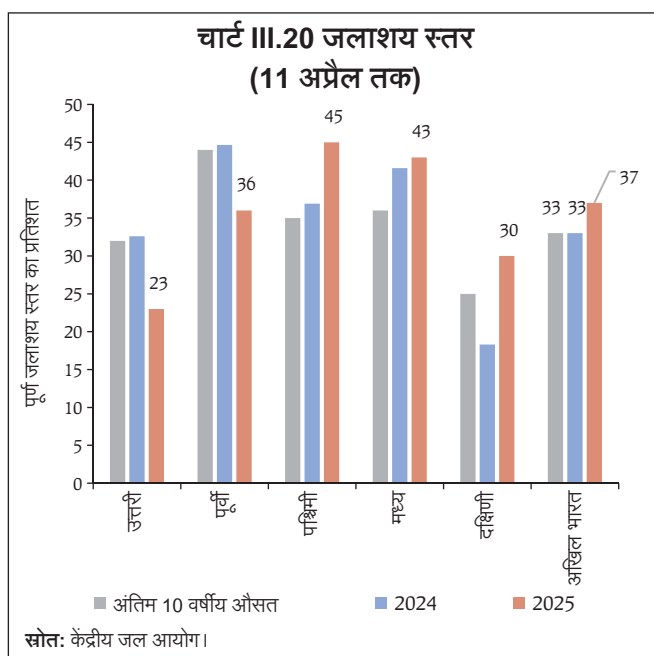
आईएमडी के पहले चरण के दीर्घकालिक पूर्वानुमान के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून के मौसम (जून-सितंबर 2025) के दौरान वर्षा दीर्घावधि औसत के 105 प्रतिशत (± 5 प्रतिशत की मॉडल त्रुटि के साथ) सामान्य से अधिक होने की संभावना है। तटस्थ अल-नीनो-दक्षिणी दोलन (ला नीना के समान विशेषताओं के साथ), तटस्थ हिंद महासागर द्विध्रुव, और जनवरी-मार्च 2025 के दौरान उत्तरी गोलार्ध और यूरेशिया पर सामान्य से कम बर्फ का आवरण मानसून वर्षा के लिए अन्य अनुकूल कारक हैं। इन घटनाक्रमों ने आगामी खरीफ मौसम के लिए फसल संभावनाओं को बढ़ावा दिया है।

खरीफ विपणन सीजन 2024-25 (अक्टूबर-सितंबर) के लिए चावल की खरीद 516.3 लाख टन (17 अप्रैल 2025 तक) पिछले वर्ष की तुलना में 6.5 प्रतिशत अधिक थी। रबी विपणन सीजन (आरएमएस) 2024-25 के लिए गेहूं की खरीद 265.9 लाख टन पर समाप्त हुई (जो पिछले वर्ष की तुलना में 2 प्रतिशत

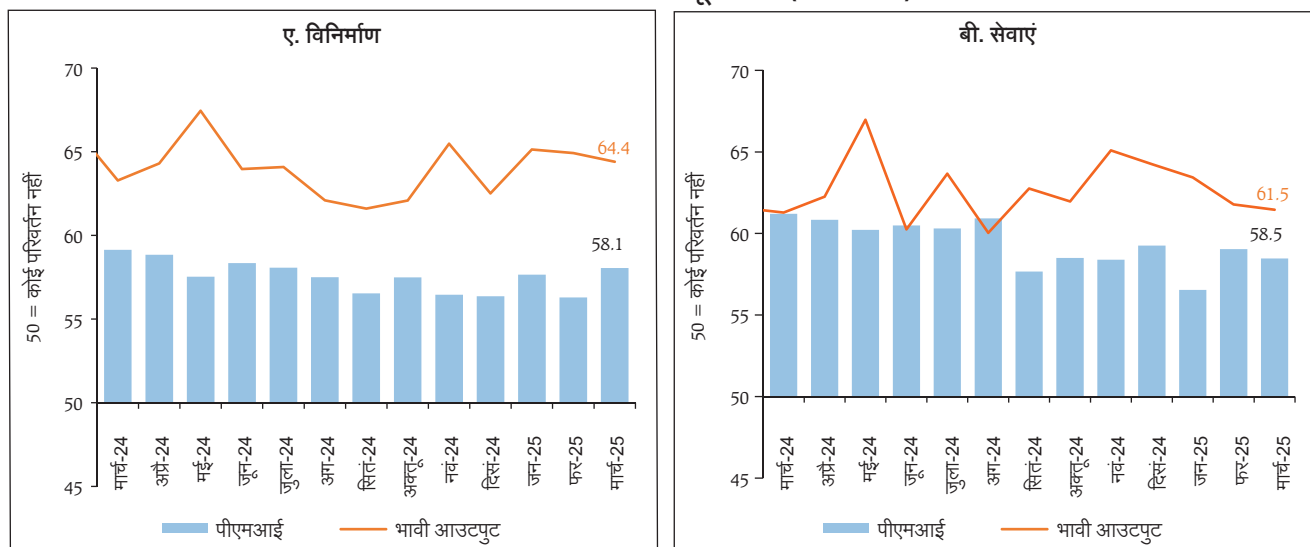
अधिक है)। इसके अतिरिक्त, आरएमएस 2025-26 के लिए गेहूं की खरीद शुरू हो गई है और 17 अप्रैल 2025 तक 48.02 लाख टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है।

भारतीय खाद्य निगम (1 अप्रैल 2025 तक) के पास चावल का स्टॉक 631 लाख टन तक पहुंच गया, जो कि बफर आवश्यकताओं का 4.6 गुना है। गेहूं का स्टॉक 118 लाख टन था, जो बफर मानदंडों का 1.6 गुना है। समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने और अटकलों को रोकने के लिए, केंद्र सरकार ने व्यापारियों/थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रोसेसर को 01 अप्रैल 2025 को और बाद में प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं की अपनी स्टॉक स्थिति घोषित करना अनिवार्य किया (चार्ट III.21)।

मार्च 2025 में भारत का विनिर्माण पीएमआई आठ महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गया, जो नए ऑर्डर और आउटपुट में तेजी को दर्शाता है (चार्ट III.22ए)। तथापि, सेवा पीएमआई ने मार्च में मामूली मंदी दर्ज की, यद्यपि यह विस्तारवादी क्षेत्र में मजबूती से बना रहा (चार्ट III.22बी)। विनिर्माण और सेवाओं के लिए व्यावसायिक अपेक्षाओं/भविष्य के आउटपुट आकलन में थोड़ा सुधार हुआ।



चार्ट III.22: क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई)



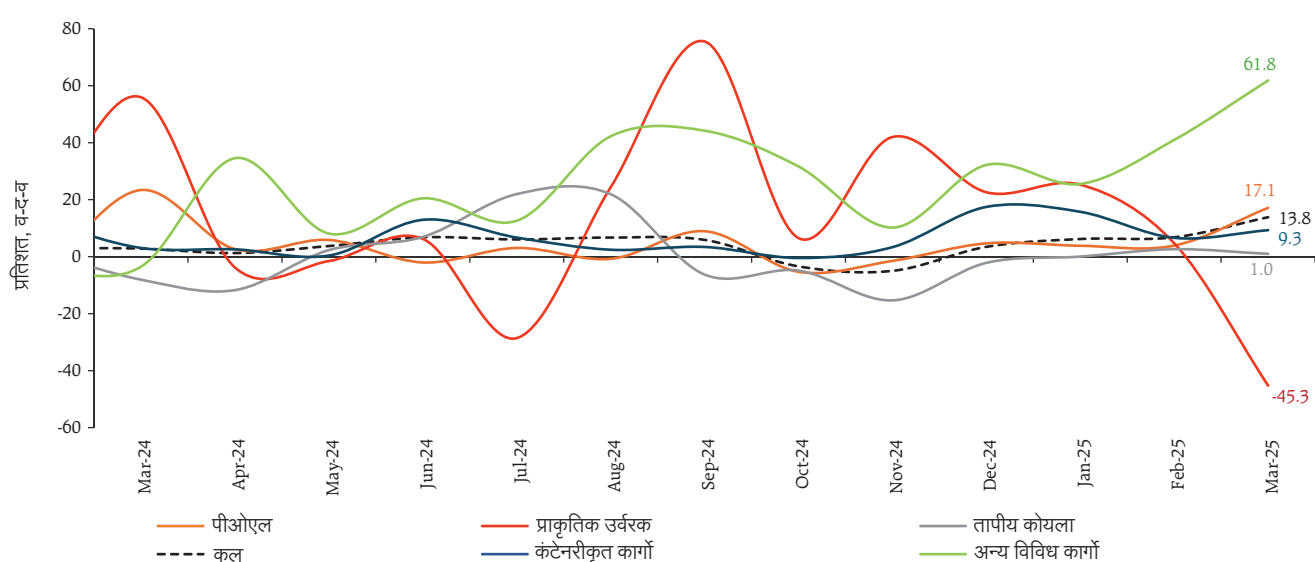
टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने के अनुरूप है और 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।

स्रोत: एस एंड पी ग्लोबल।

औद्योगिक गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतकों में, मार्च 2025 में बंदरगाह यातायात में वृद्धि में तेजी आई, जो पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक (पीओएल) और अन्य विविध कार्गो में उच्च वृद्धि से प्रेरित है (चार्ट III.23)।

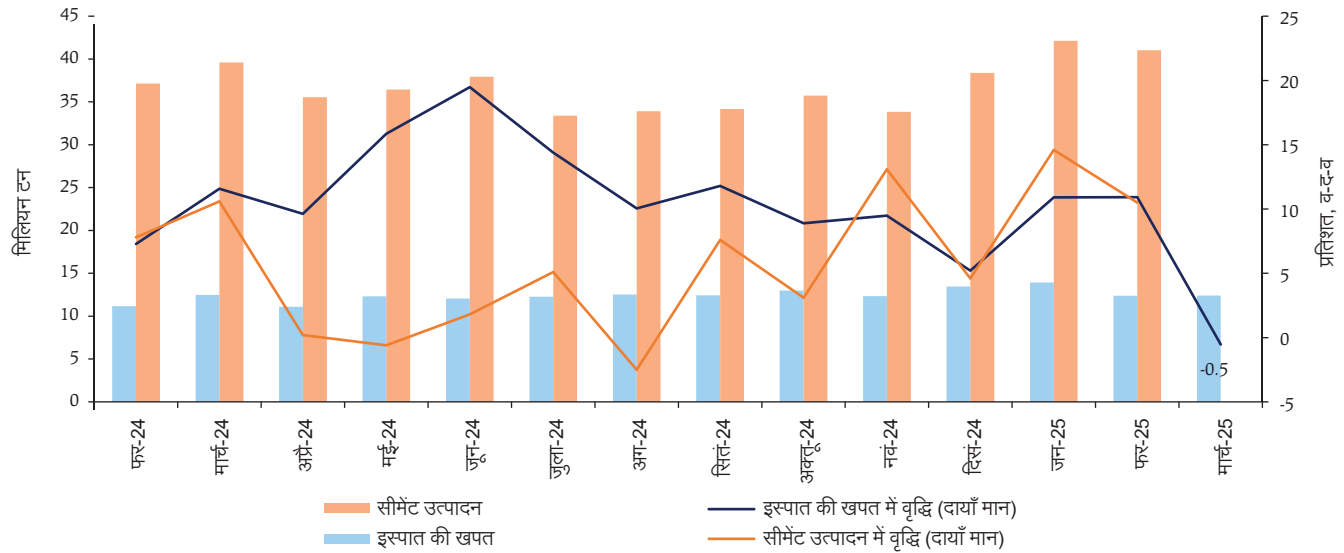
निर्माण क्षेत्र ने मिश्रित तस्वीर को प्रतिबिंबित किया क्योंकि सीमेंट उत्पादन ने फरवरी में दो अंकों की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की जबकि मार्च में इस्पात की खपत में गिरावट दर्ज की गई (चार्ट III.24)।

चार्ट III.23: पोर्ट कार्गो



स्रोत: इंडियन पोर्ट्स एसोसिएशन।

चार्ट III.24: इस्पात की खपत और सीमेंट उत्पादन



स्रोत: संयुक्त संयंत्र समिति; और आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सेवा क्षेत्र के लिए उपलब्ध उच्च आवृत्ति संकेतक मार्च हैं (सारणी III.1)।
में आर्थिक गतिविधियों में व्यापक आधार वृद्धि को दर्शाते

सारणी III.1 : उच्च आवृत्ति संकेतक - सेवाएं

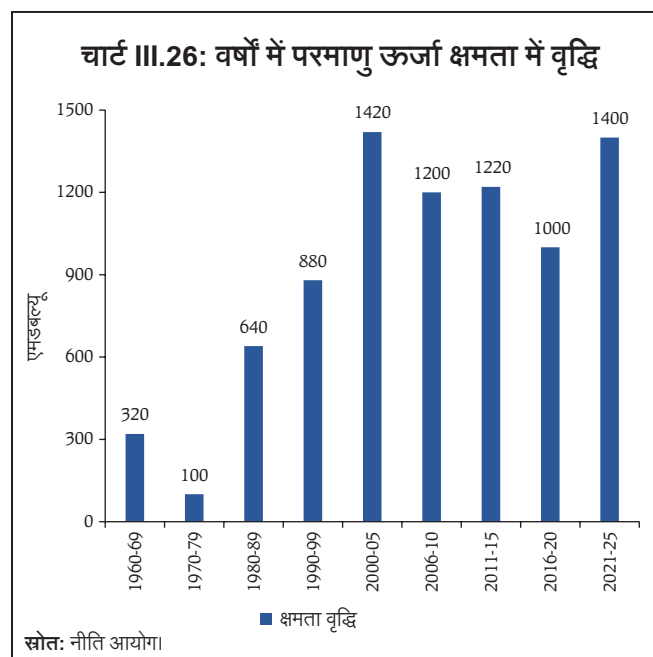
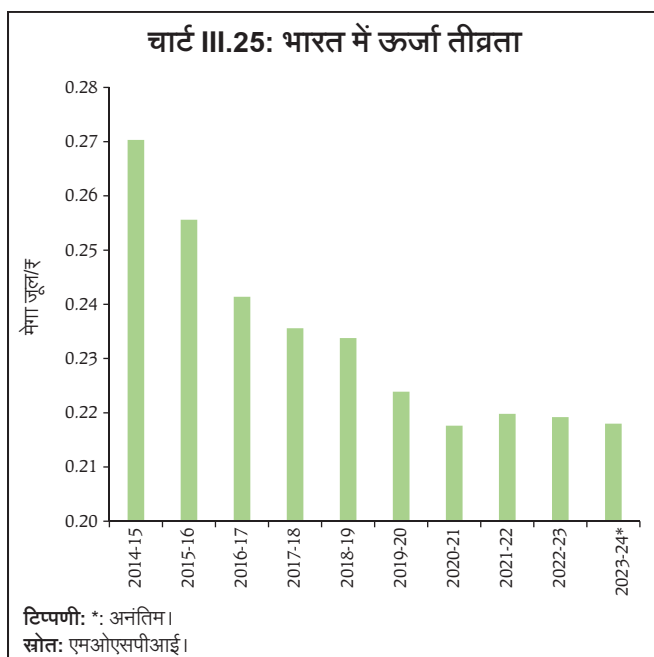
(वर्ष-दर-वर्ष, प्रतिशत)

क्षेत्र	संकेतक	मार्च-24	अप्रै-24	मई-24	जून-24	जुल-24	अग-24	सित-24	अक्टू-24	नव-24	दिस-24	जन-25	फर-25	मार्च-25
ग्रामीण मांग	यात्री वाहनों की बिक्री	8.9	1.2	4.3	4.9	-2.0	-1.6	-0.4	1.1	4.4	11.4	3.5	3.7	3.7
	दोपहिया वाहनों की बिक्री	15.3	30.8	10.1	21.3	12.5	9.3	15.8	14.2	-1.1	-8.8	2.1	-9.0	11.4
	तिपहिया वाहनों की बिक्री	4.3	14.5	14.4	12.3	5.1	8.0	6.7	-0.7	-1.3	3.5	8.6	4.7	10.5
	ट्रैक्टर की बिक्री	-23.1	-3.0	0.0	3.6	1.6	-5.8	3.7	22.4	-1.3	14.0	11.4	35.9	25.4
व्यापार, होटल, परिवहन, संचार	वाणिज्यिक वाहनों की बिक्री	-3.8		3.5			-11.0			1.3			1.6	
	रेलवे मालभाड़ा यातायात	8.6	1.4	3.7	10.1	4.5	0.0	-5.8	1.5	1.2				
	पोर्ट कार्गो यातायात	2.7	1.3	3.8	6.8	5.9	6.7	5.8	-3.4	-4.9	3.4	7.6	3.6	13.8
	घरेलू हवाई कार्गो यातायात	8.7	0.3	10.3	10.3	8.8	0.6	14.0	8.9	0.3	4.3	6.9	-2.5	
	अंतरराष्ट्रीय हवाई कार्गो यातायात	22.5	16.2	19.2	19.6	24.4	20.7	20.5	18.4	16.1	10.5	7.1	-6.3	
	घरेलू हवाई यात्री यातायात	4.7	3.8	5.9	6.9	7.6	6.7	7.4	9.6	13.8	10.8	14.1	12.1	10.1
	अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्री यातायात	15	16.8	19.6	11.3	8.8	11.1	11.2	10.3	10.7	9.0	11.1	7.7	4.7
	जीएसटी ई-वे बिल (कुल)	13.9	14.5	17.0	16.3	19.2	12.9	18.5	16.9	16.3	17.6	23.1	14.7	20.2
	जीएसटी ई-वे बिल (आंतर राज्यीय)	15.8	17.3	18.9	16.4	19.0	13.1	19.0	18.3	5.4	17.9	23.3	14.9	20.3
	जीएसटी ई-वे बिल (अंतर-राज्यीय)	10.7	9.6	13.6	16.3	19.6	12.5	17.7	14.4	44.1	17.1	22.8	14.4	20.1
	होटल अधिवास दर	2.7	-1.4	-2.6	-3.1	3.6	0.7	2.1	-5.3	11.1	-0.2	1.2	0.6	
	प्रति कमरा औसत राजस्व	6.7	4.8	1.8	2.8	7.6	5.2	3.5	4.8	10.7	8.9	8.7	14.0	
	पर्यटकों का आगमन	8.0	7.7	0.3	9.0	-1.3	-4.2	0.4	-1.4	-0.1	-6.6	-0.2	-8.6	
	पर्यटकों का आगमन	8.0	7.7	0.3	9.0	-1.3	-4.2	0.4	-1.4	-0.1	-6.6	-0.2	-8.6	
निर्माण	इस्पात की खपत	11.6	9.6	15.9	19.5	14.4	10.0	11.8	8.9	9.5	5.2	10.9	10.9	-0.5
	सीमेंट उत्पादन	10.6	0.2	-0.6	1.8	5.1	-2.5	7.6	3.1	13.1	4.6	14.6	10.5	
पीएमआई सूचकांक #	सेवाएं	61.2	60.8	60.2	60.5	60.3	60.9	57.7	58.5	58.4	59.3	56.5	59.0	58.5

<<संकुचन-----विस्तार>>

टिप्पणी: #: डेटा स्तरों में है। *: मार्च 2025 का डेटा दैनिक आंकड़ों के मासिक औसत के आधार पर है। जुलाई 2021 से अब तक के प्रत्येक संकेतक के लिए हीट-मैप बनाया गया है।

स्रोत: सीएमआईई; रेल मंत्रालय; ट्रैक्टर और मशीनीकरण संघ; भारतीय पोर्ट संघ; वित्तीय सलाहकार का कार्यालय; जीएसटीएन; भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण; एचवीएस एनरॉक; पर्यटन मंत्रालय; संयुक्त संयंत्र समिति; और आईएसएस मार्किट।



भारत जलवायु परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाने और उससे होने वाले जोखिमों को कम करने की दिशा में लगन से काम कर रहा है। ऊर्जा संरक्षण के लिए भारत की जलवायु संबंधी गतिविधियाँ अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से ऊर्जा-कुशल बन रही है, ऊर्जा तीव्रता¹¹ 2014-15 में 0.27 मेगा जूल/रुपये से घटकर 2023-24 में 0.22 मेगा जूल/रुपये हो गई है (चार्ट III.25)। सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे प्रमुख ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रमों में ऊर्जा-प्रधान उद्योगों के लिए प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) योजना; ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) द्वारा उपकरणों के लिए मानक और लेबलिंग योजना; सभी के लिए किफायती एलईडी द्वारा उन्नत ज्योति (उजाला) योजना; और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाना शामिल हैं।

भारत के ऊर्जा सांख्यिकी 2025 के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 21,09,655 मेगावाट (एमडब्ल्यू) आंकी गई है। ऊर्जा उत्पादन की सबसे अधिक क्षमता पवन (55.17 प्रतिशत) से आती है, इसके बाद सौर ऊर्जा (35.50 प्रतिशत) और वृहत जलविद्युत

(6.32 प्रतिशत) का स्थान आता है। भारत गैर-नवीकरणीय स्रोतों से बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता भी बढ़ा रहा है। भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 2010-11 के 4,780 मेगावाट से बढ़कर 2024 में 8,180 मेगावाट हो गई है, जो 70 प्रतिशत से अधिक है। इसके अलावा, भारत की योजना 2031-32 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को 22,480 मेगावाट तक बढ़ाने की है (चार्ट III.26)। केंद्रीय बजट 2025-26 में ₹20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों (एसएमआर) के अनुसंधान और विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन और 2047 तक 100 गीगावाट (जीडब्ल्यू) की परमाणु ऊर्जा क्षमता के विकास की घोषणा की गई है।¹²

मुद्रास्फीति

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई)¹³ में वर्ष-दर-वर्ष बदलावों के आधार पर मापी गई हेडलाइन मुद्रास्फीति, फरवरी के 3.6 प्रतिशत से मार्च 2025 में घटकर 3.3 प्रतिशत हो गई, जो लगातार चौथी मासिक गिरावट और

¹¹ ऊर्जा तीव्रता को स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की एक इकाई उत्पन्न करने के लिए खपत ऊर्जा की मात्रा के रूप में परिभाषित किया गया है।

¹² <https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2099244>

¹³ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 15 अप्रैल, 2025 को जारी अंतिम आंकड़ों के अनुसार।

अगस्त 2019 के बाद से सबसे कम रीडिंग है (चार्ट III.27)। हेडलाइन मुद्रास्फीति में लगभग 30 आधार अंकों (बीपीएस) की गिरावट पूरी तरह से मार्च में किसी भी आधार प्रभाव की अनुपस्थिति में लगभग 30 बीपीएस की नकारात्मक मूल्य गति से आई।¹⁴ प्रमुख समूहों में, सीपीआई खाद्य ने महीने के दौरान लगभग (-)0.7 प्रतिशत की नकारात्मक गति दर्ज की, जबकि सीपीआई ईंधन और कोर (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) समूहों में गति क्रमशः 0.1 और 0.2 प्रतिशत पर सकारात्मक थी।

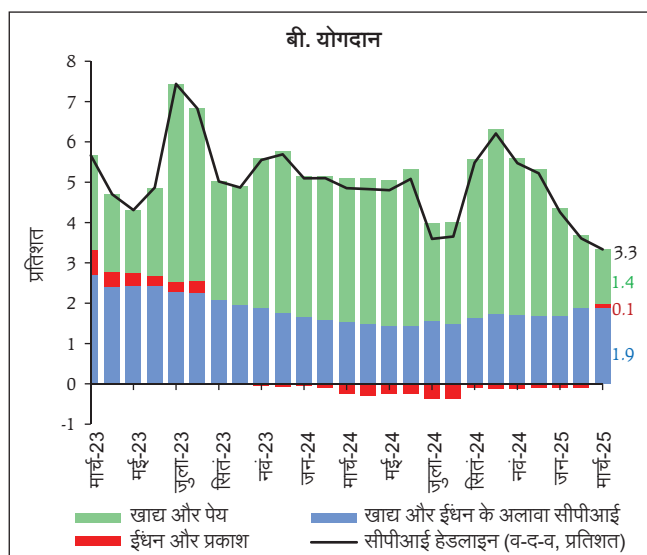
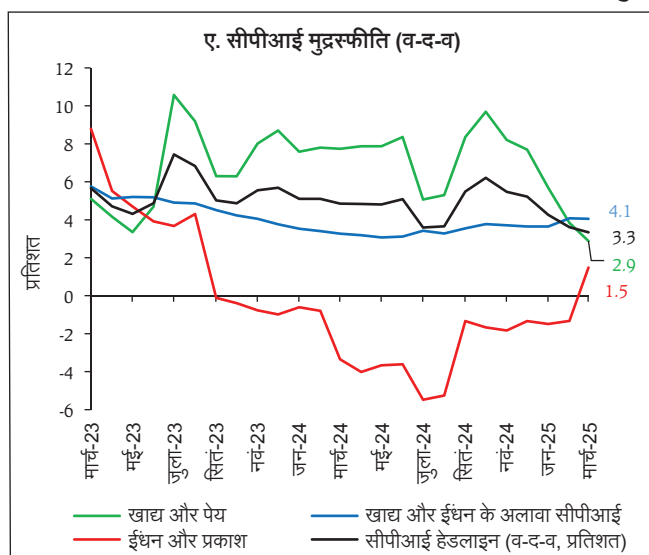
खाद्य समूह में वार्षिक मुद्रास्फीति फरवरी के 3.8 प्रतिशत से मार्च में तेज़ी से घटकर 2.9 प्रतिशत हो गई। उप-समूहों के संदर्भ में, सब्जियों, दालों और अंडों में और भी अधिक अपस्फीति देखी गई। मसालों में अपस्फीति बनी रही, हालाँकि धीमी गति से। अनाज, मांस और मछली, तथा दूध और उससे बने उत्पादों में मुद्रास्फीति में कमी जारी रही। हालाँकि, तेल और वसा, फल, चीनी और मिठाइयाँ, गैर-मादक पेय पदार्थ, और तैयार भोजन में मुद्रास्फीति में वृद्धि जारी रही (चार्ट III.28)।

ईंधन और प्रकाश समूह में मार्च में 1.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) मुद्रास्फीति दर्ज की गई, जबकि फरवरी में इसमें (-)1.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी। लगातार अठारह महीनों की अपस्फीति के बाद ईंधन समूह के लिए यह पहली सकारात्मक वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि थी। केरोसिन की कीमतों में अपस्फीति से बाहर आने, बिजली की कीमतों में मुद्रास्फीति की उच्च दर और रसोई गैस की कीमतों में अपस्फीति की कम दर ने इस बदलाव को गति दी।

मार्च 2025 में कोर सीपीआई मुद्रास्फीति 4.1 प्रतिशत पर स्थिर रही, हालाँकि उप-समूहों में विपरीत रुझान देखे गए। पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों, आवास, स्वास्थ्य, परिवहन और संचार तथा शिक्षा में मुद्रास्फीति बढ़ी, जबकि कपड़े और जूते, मनोरंजन और आमोद-प्रमोद, व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव तथा घरेलू सामान और सेवाओं में मुद्रास्फीति कम हुई (चार्ट III.29)।

क्षेत्रीय वितरण के संदर्भ में, ग्रामीण और शहरी मुद्रास्फीति मार्च 2025 में क्रमशः 3.25 प्रतिशत और 3.43 प्रतिशत

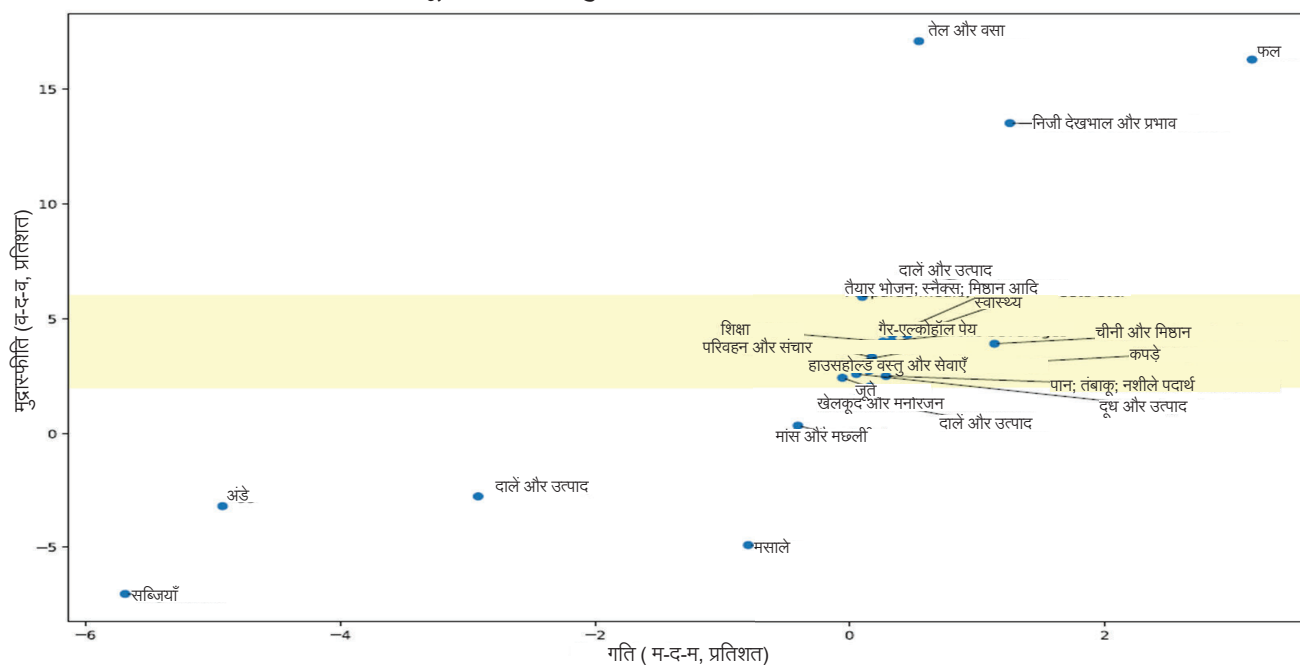
चार्ट III.27: सीपीआई मुद्रास्फीति के रुझान और वाहक



स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

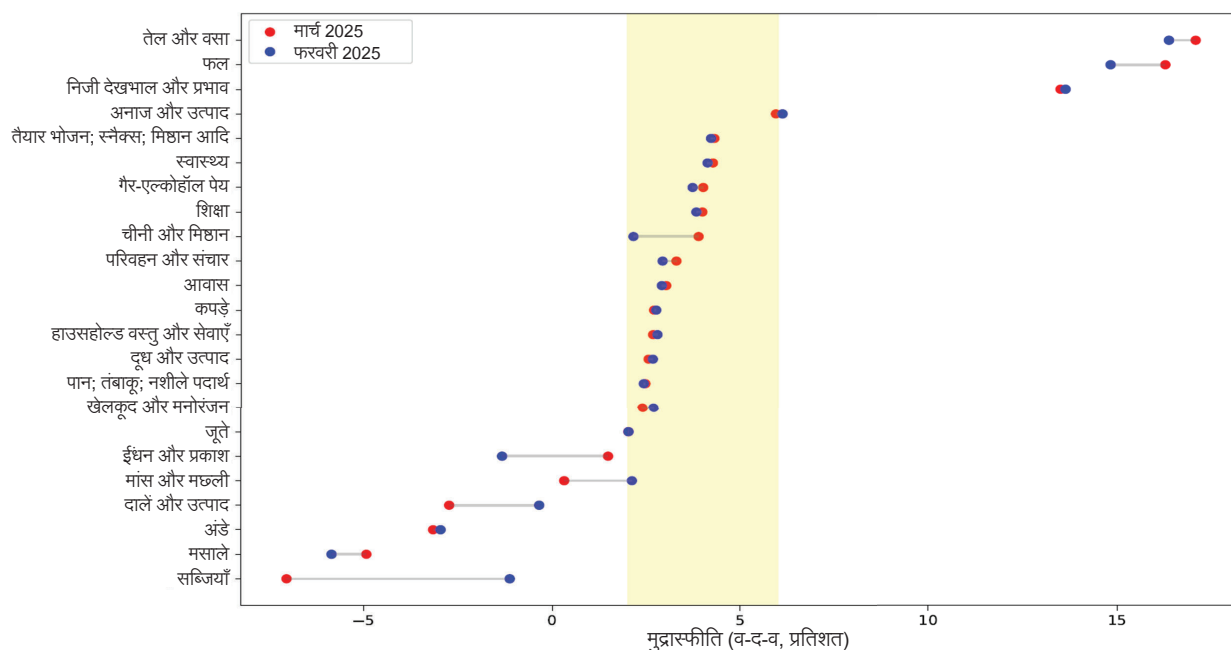
¹⁴ बेस इफेक्ट, यानी, वर्तमान व-द-व मुद्रास्फीति पर पिछले वर्ष के दौरान सूचकांक में परिवर्तन का प्रभाव, मार्च में शून्य था क्योंकि सीपीआई 2024 में फरवरी और मार्च के बीच अपरिवर्तित रहा।

चार्ट III.28: उपसमूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) और गति (एम-ओ-एम)

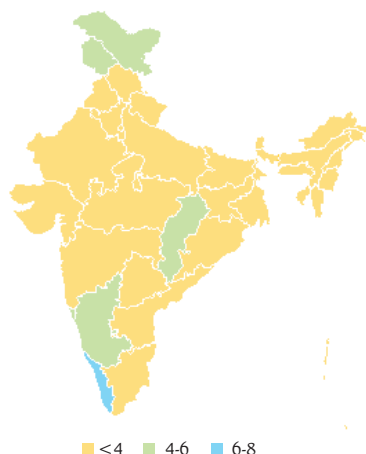


तक कम हो गई। राज्य स्तर पर सीपीआई मुद्रास्फीति 1.1 राज्यों में 4 प्रतिशत से कम मुद्रास्फीति दर्ज की गई प्रतिशत से 6.6 प्रतिशत के बीच रही, जिसमें अधिकांश (चार्ट III.30)।

चार्ट III.29 : उपसमूहों में वार्षिक मुद्रास्फीति (फरवरी 2025 की तुलना में मार्च 2025)



**चार्ट III.30 : मुद्रास्फीति का स्थानिक वितरण:
मार्च 2025
(सीपीआई-संयुक्त)**



टिप्पणी: मानचित्र केवल दृष्टांत उद्देश्यों के लिए है।

स्रोत: एनएसओ; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

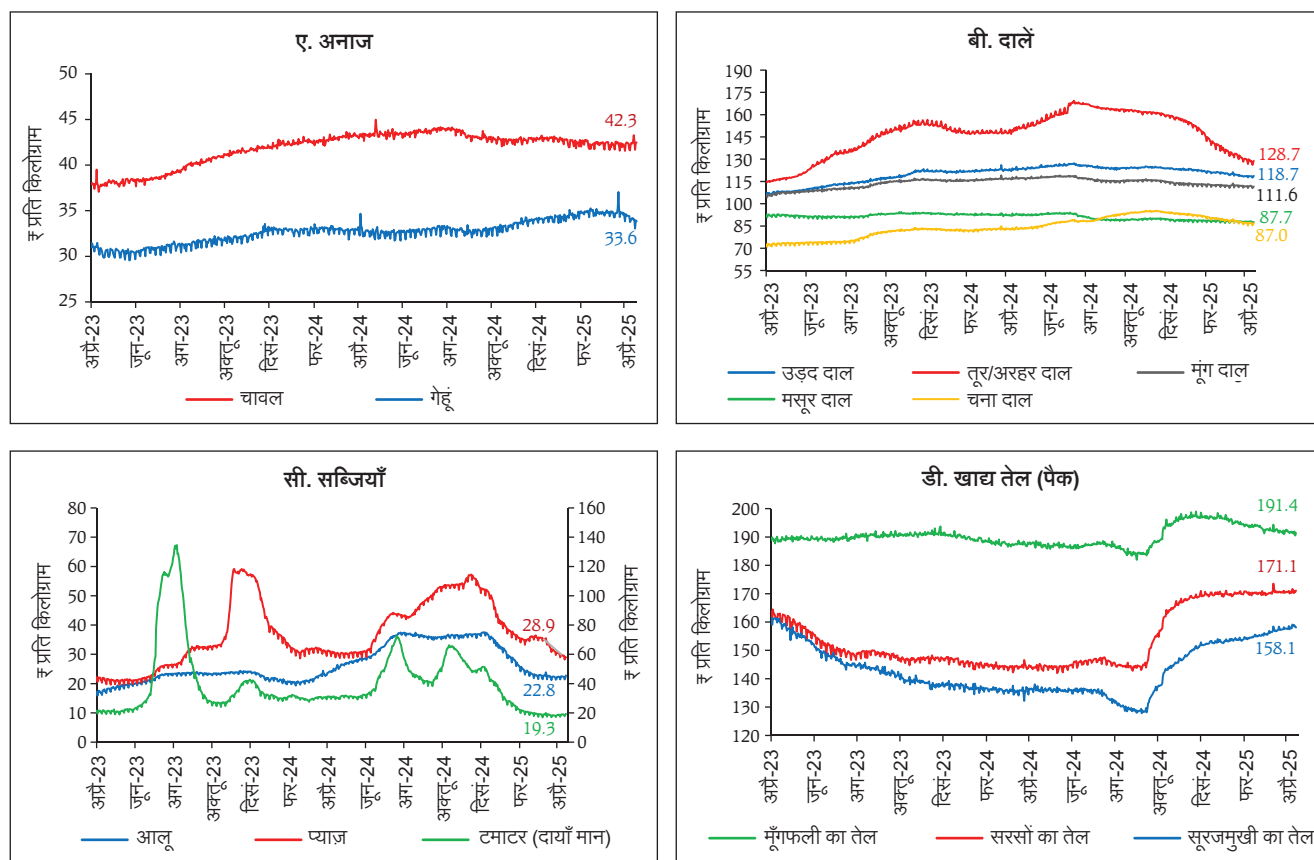
अप्रैल के अब तक (15 तारीख तक) उच्च आवृत्ति वाले खाद्य मूल्य आँकड़े चावल और गेहूँ, दोनों के लिए अनाज की

कीमतों में कमी दर्शाते हैं। दालों की कीमतों में भी व्यापक कमी दर्ज की गई। दूसरी ओर, खाद्य तेलों की कीमतों में मजबूती आई है - मुख्यतः ताड़, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल की कीमतों में। प्रमुख सब्जियों में, आलू और प्याज की कीमतों में और सुधार दर्ज किया गया, जबकि टमाटर की कीमतों में मामूली वृद्धि देखी गई (चार्ट III.31)।

अप्रैल में अब तक (15 तारीख तक) पेट्रोल और डीज़ल की खुदरा बिक्री कीमतें अपरिवर्तित रही हैं। केरोसिन की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई है, जबकि 8 अप्रैल 2025 को रसोई गैस की कीमतों में ₹50 प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी की गई (सारणी III.2)।

मार्च 2025 के पीएमआई ने विनिर्माण क्षेत्र के लिए इनपुट कीमतों में वृद्धि की दर में वृद्धि दर्ज की, जबकि सेवा क्षेत्र के लिए

चार्ट III.31: डीसीए आवश्यक कमोडिटी की कीमतें



स्रोत: उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

सारणी III.2: पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें

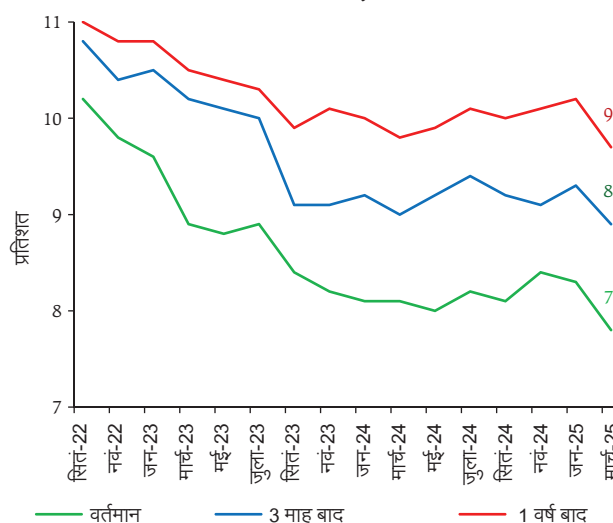
मद	इकाई	घरेलू कीमतें			माह-दर-माह (प्रतिशत)	
		फर-25	मार्च-25	अप्रै-25 ^	मार्च-25	अप्रै-25 ^
पेट्रोल	₹/लीटर	101.02	101.02	101.02	0.0	0.0
डीजल	₹/लीटर	90.48	90.48	90.48	0.0	0.0
केरोसिन (छूट सहित)	₹/लीटर	46.37	46.23	46.56	-0.3	0.7
एलपीजी (छूट सहित)	₹/सिलेंडर	813.25	813.25	863.25	0.0	6.1

टिप्पणीयाँ: 1. ^: 1-15 अप्रैल 2025 के लिए।

2. केरोसिन तेल के अलावा, कीमतें चार प्रमुख महानगरों (दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई) में औसत इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की कीमतों का प्रतिनिधित्व करती हैं। केरोसिन के लिए, कीमतें कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में सब्सिडी वाली कीमतों के औसत को दर्शाती हैं।

स्रोत: आईओसीएल; पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी); और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

चार्ट III.33: परिवारों की औसत मुद्रास्फीति अपेक्षाएँ



स्रोत: आईईएसएच, आरबीआई।

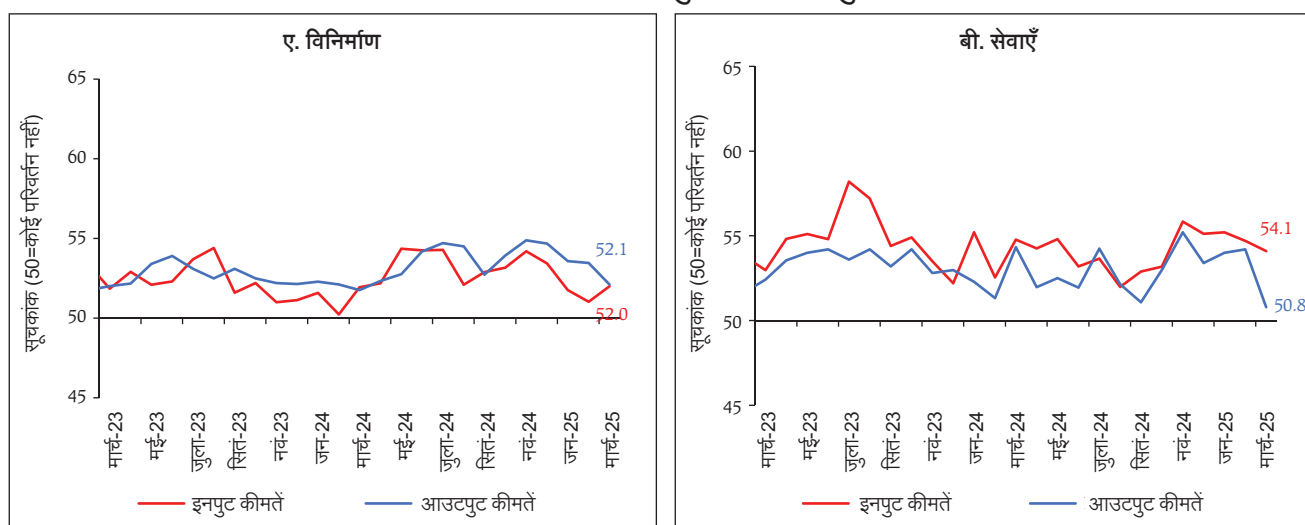
यह अपेक्षाकृत स्थिर रही। हालाँकि, मार्च में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की कंपनियों में विक्रय मूल्य दबाव कम हुआ (चार्ट III.32)।

मौजूदा मुद्रास्फीति के बारे में परिवारों की धारणा 50 आधार अंक घटकर 7.8 प्रतिशत रह गई। उनकी मुद्रास्फीति संबंधी अपेक्षाएँ भी कम हुईं, अगले तीन महीनों और एक वर्ष के लिए क्रमशः 40 आधार अंक और 50 आधार अंक की कमी आई (चार्ट III.33)।

IV. वित्तीय स्थितियाँ

संचलन में मुद्रा में मौसमी वृद्धि और आरबीआई के विदेशी मुद्रा परिचालन, वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही के दौरान चलनिधि की तंगी के प्रमुख कारण थे। बैंकिंग प्रणाली की चलनिधि आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने जनवरी 2025 के मध्य तक दैनिक परिवर्तनीय दर रेपो (वीआरआर)

चार्ट III.32: पीएमआई: इनपुट और आउटपुट कीमतें



टिप्पणी: 50 का स्तर गतिविधि में कोई बदलाव नहीं होने के अनुरूप है और 50 से ऊपर का स्तर विस्तार को दर्शाता है और इसके विपरीत।

स्रोत: एस एंड पी।

नीलामियों के संचालन के अलावा, टिकाऊ चलनिधि प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं। परिणामस्वरूप, बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि घाटा फरवरी-मार्च 2025 के दौरान कम हुआ, और चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अंतर्वेशन जनवरी 2025 के ₹2.0 लाख करोड़ की तुलना में मार्च 2025 में घटकर ₹1.1 लाख करोड़ रह गया।

जनवरी 2025 से, रिज़र्व बैंक ने अब तक खुले बाजार परिचालन (ओएमओ) खरीद, लंबी अवधि की वीआरआर नीलामी और विदेशी मुद्रा स्वैप के संयोजन के माध्यम से लगभग ₹7.9 लाख का टिकाऊ चलनिधि अंतर्वेशन किया है (सारणी IV.1)। आरबीआई के चलनिधि बढ़ाने के उपायों के साथ-साथ माह के अंत में सरकारी नकदी शेष की सामान्य निकासी के कारण तीन महीने से अधिक के अंतराल के बाद,

29 मार्च 2025 से प्रणाली चलनिधि अधिशेष में बदल गई। इसके अलावा, स्थायी चलनिधि सुविधा (एसएलएफ) के तहत स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स (एसपीडी) के लिए उपलब्ध कुल सीमा 2 अप्रैल 2025 से ₹10,000 करोड़ से बढ़ाकर ₹15,000 करोड़ कर दी गई और अप्रैल 2025 के लिए खुले बाजार खरीद परिचालन का कैलेंडर दिया गया।

रिज़र्व बैंक 16 जनवरी 2025 से दैनिक वीआरआर नीलामियाँ आयोजित कर रहा है और स्टैंडअलोन प्राथमिक डीलरों (एसपीडी) को इन नीलामियों में भाग लेने की अनुमति दी गई है। 16 मार्च से 17 अप्रैल 2025 के दौरान 1 से 5 दिनों की परिपक्वता अवधि वाले उन्नीस फाइन-ट्यूनिंग वीआरआर परिचालनों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में कुल ₹10.2 लाख करोड़ की राशि डाली गई।

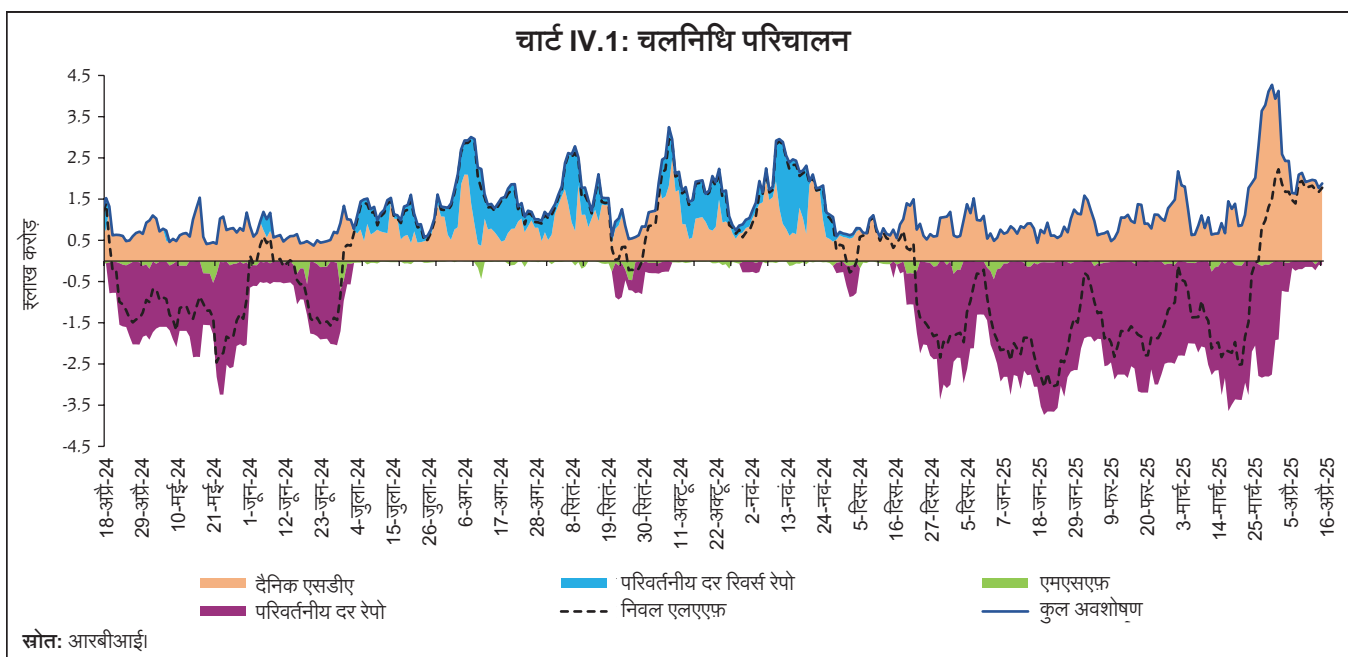
सारणी IV.1: जनवरी 2025 से टिकाऊ चलनिधि उपाय

(राशि ₹ करोड़ में)

उपाय	नीलामी की तारीख	विवरण	बिड कवर अनुपात	चलनिधि अंतर्वेशन
ओएमओ खरीद	जनवरी से मार्च, 2025	एनडीएस-ओएम के माध्यम से		38,825
ओएमओ खरीद नीलामी	जनवरी 30, 2025	अधिसूचित राशि: 20,000	6.03	20,020
	फरवरी 13, 2025	अधिसूचित राशि: 40,000	4.53	40,000
	फरवरी 20, 2025	अधिसूचित राशि: 40,000	4.69	40,000
	मार्च 12, 2025	अधिसूचित राशि: 50,000	2.51	50,000
	मार्च 18, 2025	अधिसूचित राशि: 50,000	2.02	50,000
	मार्च 25, 2025	अधिसूचित राशि: 50,000	1.35	44,541
	अप्रैल 3, 2025	अधिसूचित राशि: 20,000	4.04	20,000
	अप्रैल 8, 2025	अधिसूचित राशि: 20,000	3.51	20,000
	अप्रैल 17, 2025	अधिसूचित राशि: 40,000	2.03	40,000
मीयादी रेपो नीलामी	फरवरी 07, 2025	56-दिवसीय वीआरआर नीलामी अधिसूचित राशि: 50,000	2.17	50,010
	फरवरी 14, 2025	49-दिवसीय वीआरआर नीलामी अधिसूचित राशि: 75,000	1.33	75,003
	फरवरी 21, 2025	45-दिवसीय वीआरआर नीलामी अधिसूचित राशि: 75,000	0.77	57,951
	अप्रैल 17, 2025	43-दिवसीय वीआरआर नीलामी अधिसूचित राशि: 1,50,000	0.17	25,731
यूएसडी/आईएनआर स्वैप खरीद/बिक्री नीलामी	जनवरी 31, 2025 (4 फरवरी 2025 को निपटान)	अवधि: 3 साल अधिसूचित राशि: USD 5 बिलियन	5.12	44,000*
	फरवरी 28, 2025 (4 मार्च 2025 को निपटान)	अवधि: 3 साल अधिसूचित राशि: USD 10 बिलियन	1.62	88,000*
	मार्च 24, 2025 (मार्च 26, 2025 को निपटान)	अवधि: 3 साल अधिसूचित राशि: 10 बिलियन अमरीकी डालर	2.23	86,000*
कुल				7,90,081*

टिप्पणी: *: अनुमानित मूल्य इंगित करता है।

स्रोत: आरबीआई, और मौद्रिक नीति रिपोर्ट, अप्रैल 2025।



चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण 16 मार्च से 17 अप्रैल 2025 के दौरान ₹0.31 लाख करोड़ रहा, जबकि 16 फरवरी से 15 मार्च 2025 के दौरान औसत दैनिक निवल अंतर्वेशन ₹1.46 लाख करोड़ था (चार्ट IV.1)। इस अवधि के दौरान बैंकों द्वारा स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) के तहत औसतन ₹2.13 लाख करोड़ का निवेश किया गया, जो पिछले महीने के ₹1.12 लाख करोड़ से अधिक है। दिसंबर 2024 के मध्य से मार्च 2025 के अंत तक एसडीएफ के तहत घाटे की चलनिधि की स्थिति और पर्याप्त फंड प्लेसमेंट का सह-अस्तित्व बैंकिंग प्रणाली के भीतर चलनिधि के असममित वितरण का सुझाव देता है। इस बीच, इस अवधि के दौरान सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के तहत दैनिक औसत उधार मामूली रूप से घटकर ₹0.04 लाख करोड़ रह गया।

भारित औसत कॉल दर (डबल्यूएसीआर) - मौद्रिक नीति का परिचालन लक्ष्य - वर्ष के अंत में आई तेज़ी को छोड़कर, मोटे तौर पर नीतिगत दायरे में ही रही। 16 मार्च और 16 अप्रैल 2025 के दौरान नीतिगत रेपो दर पर डबल्यूएसीआर का प्रसार औसतन (-)1 आधार अंक (बीपी) रहा, जबकि 16 फरवरी से 15 मार्च 2025 के दौरान यह 5 आधार अंक था (चार्ट IV.2ए)। चलनिधि की स्थिति में सुधार के कारण संपार्श्विक खंड में भी

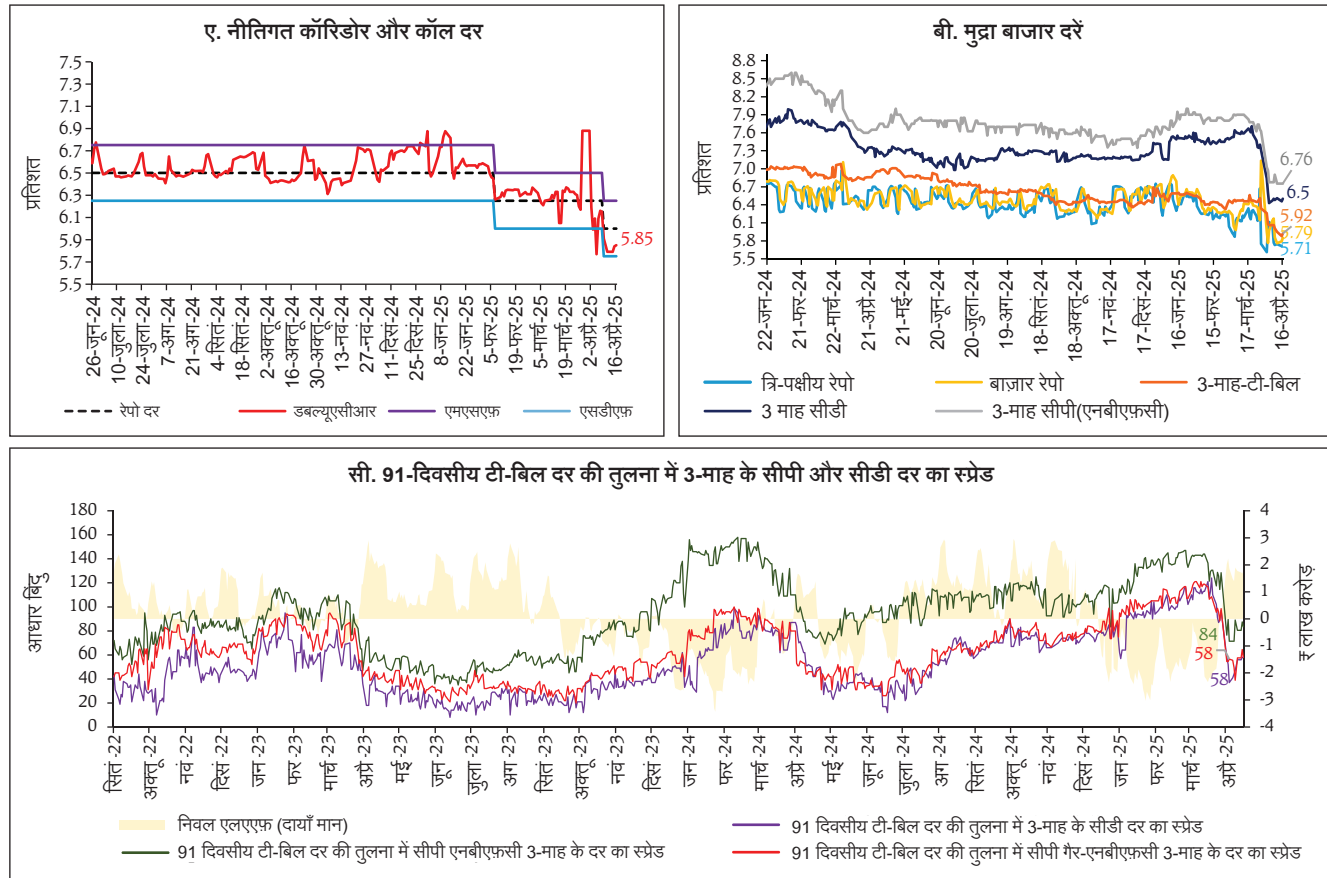
दरें कम हुईं।

संपूर्ण सावधि मुद्रा बाज़ार खंड में, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) द्वारा जारी 3-माह के जमा प्रमाणपत्रों (सीडी), 3-माह के वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) और 91-दिवसीय टी-बिलों पर दरें दिसंबर 2024 के मध्य से ऊँची रहने के बाद मार्च के उत्तरार्ध से कम हुई (चार्ट IV.2बी)। मुद्रा बाज़ार (3-माह के सीपी [एनबीएफसी] से 91-दिवसीय टी-बिल घटाकर) में औसत जोखिम प्रीमियम 16 मार्च से 16 अप्रैल 2025 के दौरान 142 बीपीएस से घटकर वर्तमान अवधि में 104 बीपीएस हो गया (चार्ट IV.2सी)।

16 मार्च से 16 अप्रैल 2025 के दौरान, सीपी की भारित औसत छूट दर (डबल्यूएडीआर) और सीडी की भारित औसत प्रभावी ब्याज दर (डबल्यूआईआईआर) एक वर्ष पहले दर्ज किए गए स्तरों की तुलना में क्रमशः 59 बीपीएस और 6 बीपीएस कम रहीं (चार्ट IV.3)।

प्राथमिक बाज़ार में, वर्ष 2024-25 (21 मार्च 2025 तक) के दौरान सीडी का निर्गमन ₹11.75 लाख करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुँच गया [चार्ट IV.4]। मार्च में अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकों की सीडी पर निर्भरता भी एक मौसमी घटना है। इसी प्रकार, वर्ष 2024-25

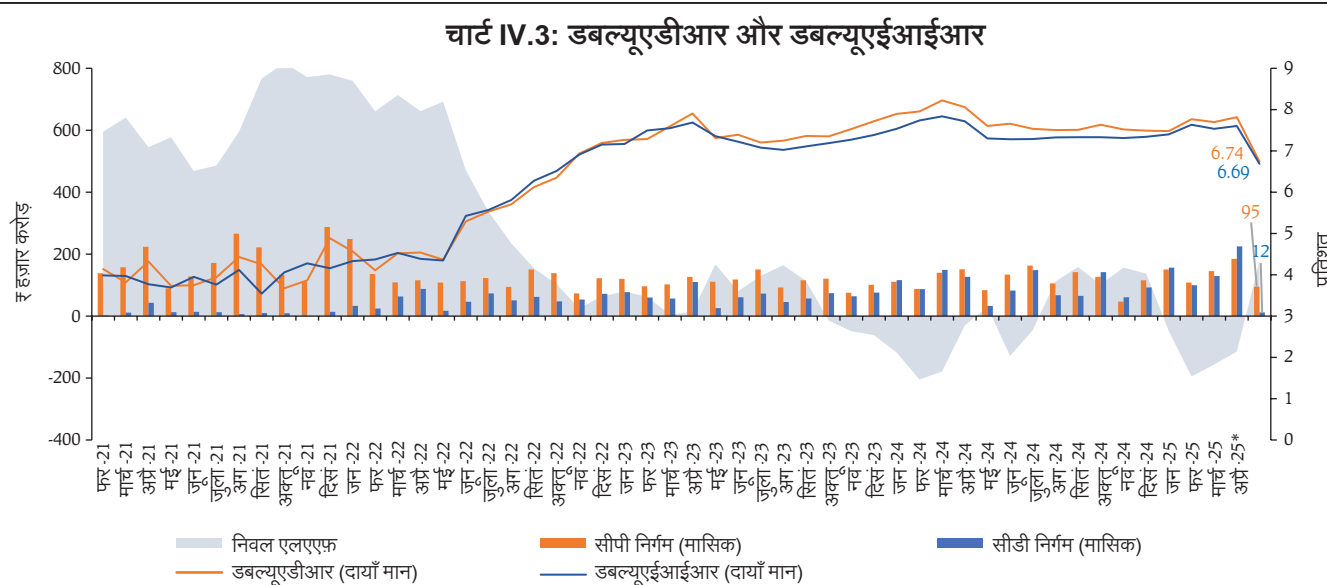
चार्ट IV.2 : नीतिगत कॉरिडोर और मुद्रा बाजार दरें



स्रोत: आरबीआई; सीसीआईएल; और ब्लूमबर्ग

(31 मार्च, 2025 तक) के दौरान ₹15.74 लाख करोड़ के सीपी निर्गमन 14.5 प्रतिशत अधिक थे।

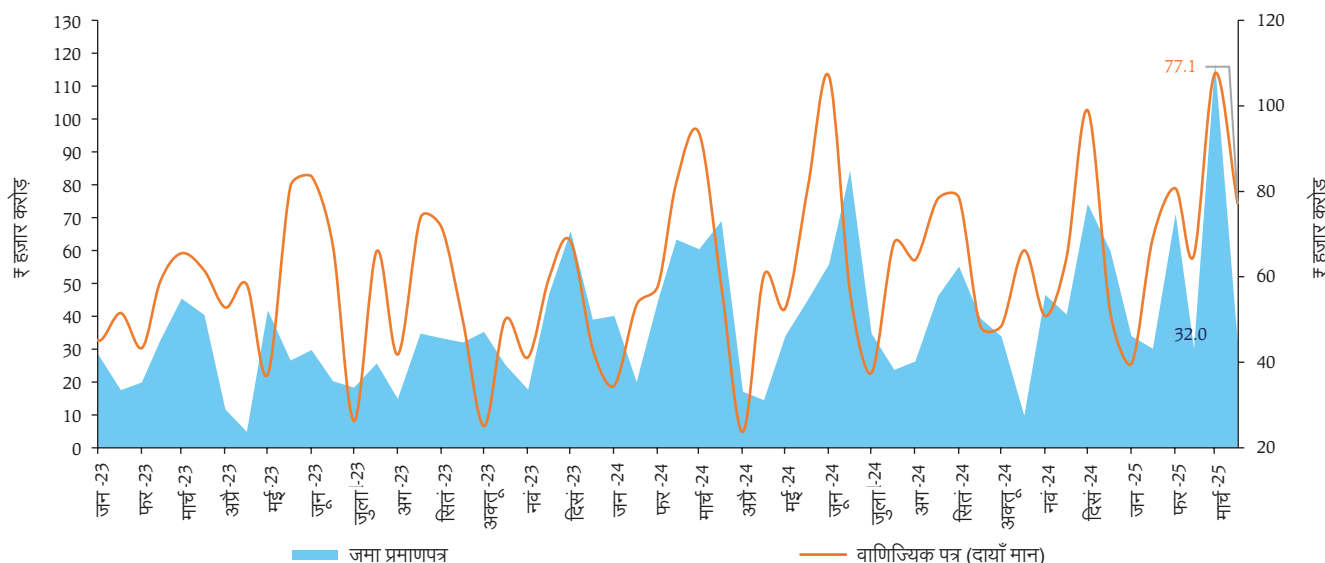
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों के बेंचमार्क पर प्रतिफल 16 अप्रैल 2025 को 6.39 प्रतिशत तक कम हो गया, जबकि



टिप्पणी: *: 16 अप्रैल 2025 तक।

स्रोत: आरबीआई; और सीसीआईएल- एफटीआरएसी।

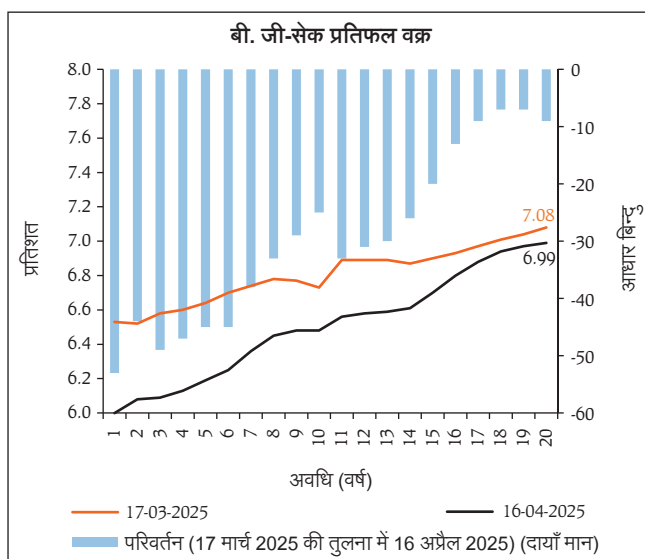
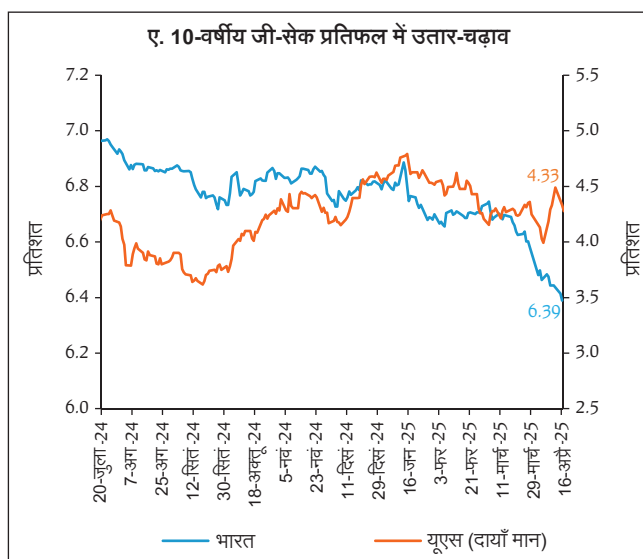
चार्ट IV.4: जमा प्रमाणपत्र (सीडी) और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) - पाक्षिक निर्गम

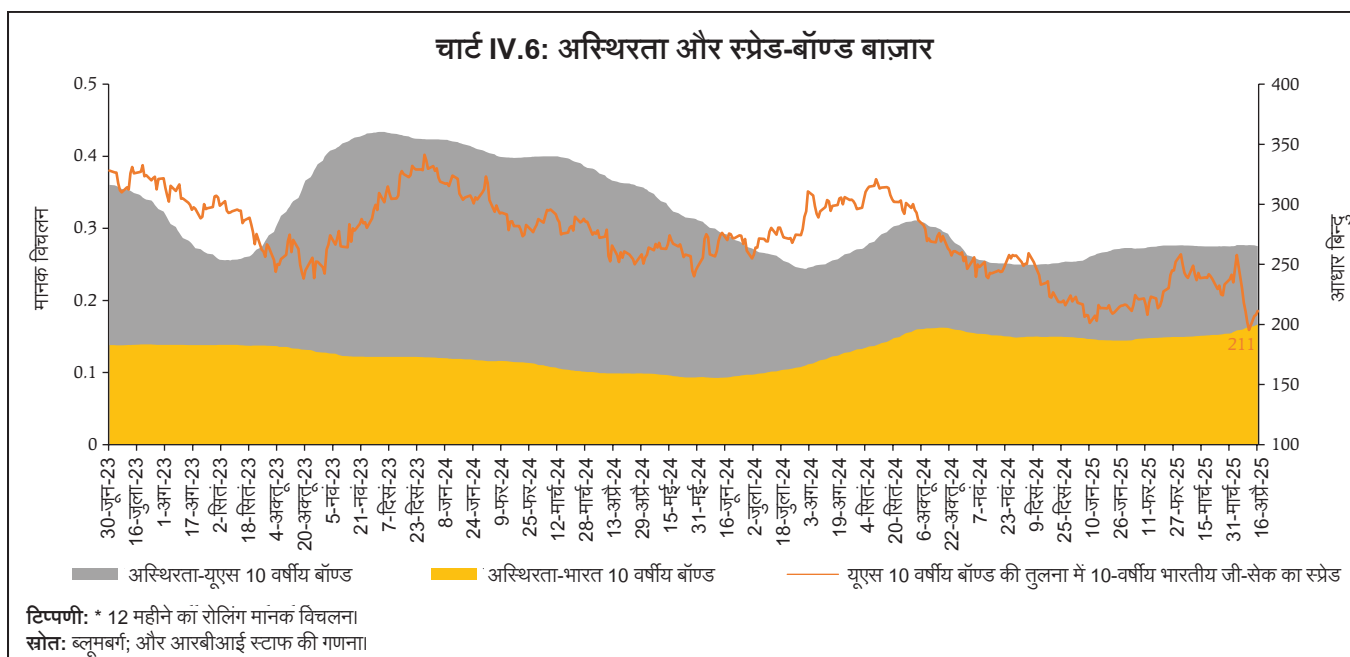


17 मार्च 2025 को यह 6.70 प्रतिशत था (चार्ट IV.5ए)। यह कमी अपेक्षा से कम मुद्रास्फीति, रिज़र्व बैंक द्वारा खुले बाजार में परिचालन और वैश्विक बॉण्ड प्रतिफल में कमी के कारण हुई। घरेलू प्रतिफल वक्र समूची अवधि संरचना में कम हुआ (चार्ट IV.5बी)। 16 मार्च और 16 अप्रैल 2025 के बीच, औसत अवधि प्रसार (10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों का प्रतिफल से 91-दिवसीय टी-बिल प्रतिफल घटाकर प्राप्त) पिछली अवधि के 27 आधार अंकों की तुलना में मामूली रूप से बढ़कर 29 आधार अंकों तक पहुँच गया।

भारतीय बॉण्ड प्रतिफल में गिरावट के कारण, 10-वर्षीय भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल और 10-वर्षीय अमेरिकी बॉण्ड प्रतिफल के बीच का अंतर मार्च में कम हुआ। अप्रैल में अब तक (16 अप्रैल 2025 तक) यह अंतर कम हुआ है, जिसका मुख्य कारण अमेरिकी बॉण्ड प्रतिफल में तेजी है। अमेरिकी ट्रेजरी बॉण्ड की तुलना में भारत में प्रतिफल में अस्थिरता कम रही (चार्ट IV.6)।

चार्ट IV.5: जी-सेक बाजार में गतिविधियां





वर्ष 2024-25 (फरवरी तक) के दौरान ₹8.77 लाख करोड़ मूल्य के कॉर्पोरेट बॉण्ड जारी किए गए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 16.3 प्रतिशत अधिक थे। मार्च के उत्तरार्ध से 15 अप्रैल 2025 तक, विभिन्न रेटिंग स्पेक्ट्रम और अवधियों में कॉर्पोरेट बॉण्ड प्रतिफल में कमी आई, जबकि संबंधित जोखिम प्रीमियम में मिश्रित रुझान देखने को मिला (सारणी IV.2)।

नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में परिवर्तन के पहले दौर के प्रभाव हेतु समायोजित आरक्षित मुद्रा (आरएम) में 11 अप्रैल 2025 तक 6.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई (एक वर्ष पूर्व 6.3 प्रतिशत) [चार्ट IV.7]। संचलन में मुद्रा (सीआईसी), जो आरएम का सबसे बड़ा घटक है, में वृद्धि दर

5.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) रही, जबकि एक वर्ष पूर्व यह 3.8 प्रतिशत थी।

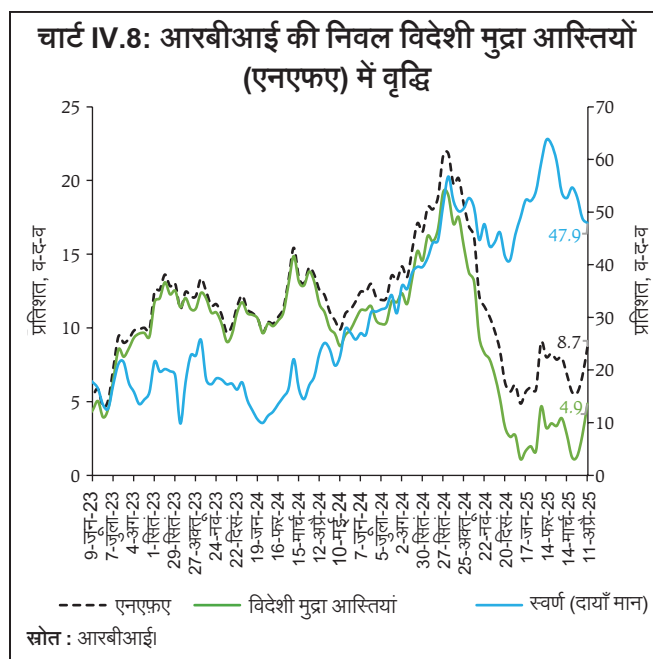
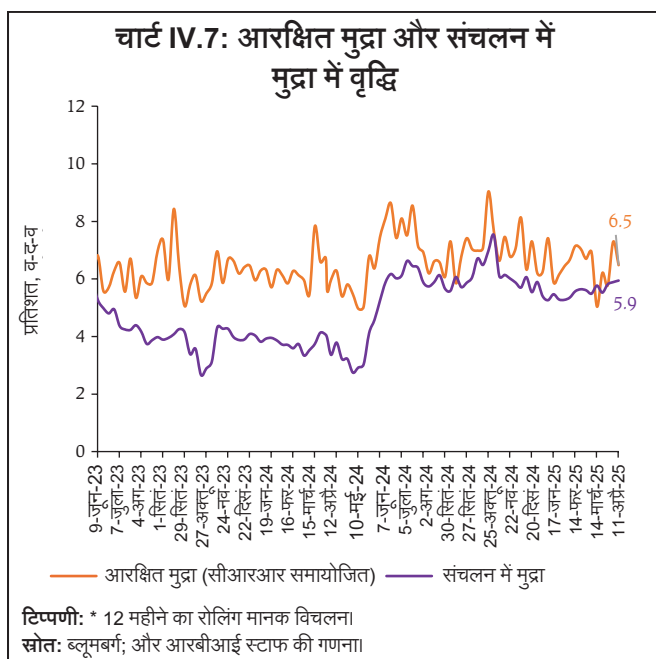
आरएम के स्रोत पक्ष (आस्तियों) में, जिसमें आरबीआई की निवल विदेशी आस्तियां (एनएफए) और निवल घरेलू आस्तियां (एनडीए) दोनों शामिल हैं, 11 अप्रैल 2025 तक विदेशी मुद्रा आस्तियों में 4.9 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की मामूली वृद्धि हुई, जबकि स्वर्ण में 47.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसका मुख्य कारण स्वर्ण की ऊँची कीमतों के कारण पुनर्मूल्यन में वृद्धि थी (चार्ट IV.8)। इसके परिणामस्वरूप एनएफए में इसकी हिस्सेदारी मार्च 2024 के अंत तक 8.3 प्रतिशत से बढ़कर 11 अप्रैल 2025 तक 12.1 प्रतिशत हो गई।

सारणी IV.1: वित्तीय बाजार - दरें और स्प्रेड

लिखत	ब्याज दरें (प्रतिशत)			स्प्रेड (आधार बिंदु)		
	(संबंधित जोखिम पर - मुक्त दर)					
	16 फर 2025 – 13 मार्च 2025	16 मार्च 2025-15 अप्रै 2025	भिन्नता	16 फर 2025 – 13 मार्च 2025	16 मार्च 2025-15 अप्रै 2025	भिन्नता
1	2	3	(4 = 3-2)	5	6	(7 = 6-5)
कॉर्पोरेट बॉण्ड						
(i) एएए (1-वर्ष)	7.85	7.43	-42	121	99	-22
(ii) एएए (3-वर्ष)	7.65	7.44	-21	96	94	-2
(iii) एएए (5-वर्ष)	7.60	7.42	-18	84	86	2
(iv) एए (3 वर्ष)	8.43	8.27	-16	174	177	3
(v) बीबीबी-(3-वर्ष)	12.08	11.93	-15	539	543	4

टिप्पणी: प्रतिफल और स्प्रेड की गणना मासिक औसत के रूप में की जाती है।

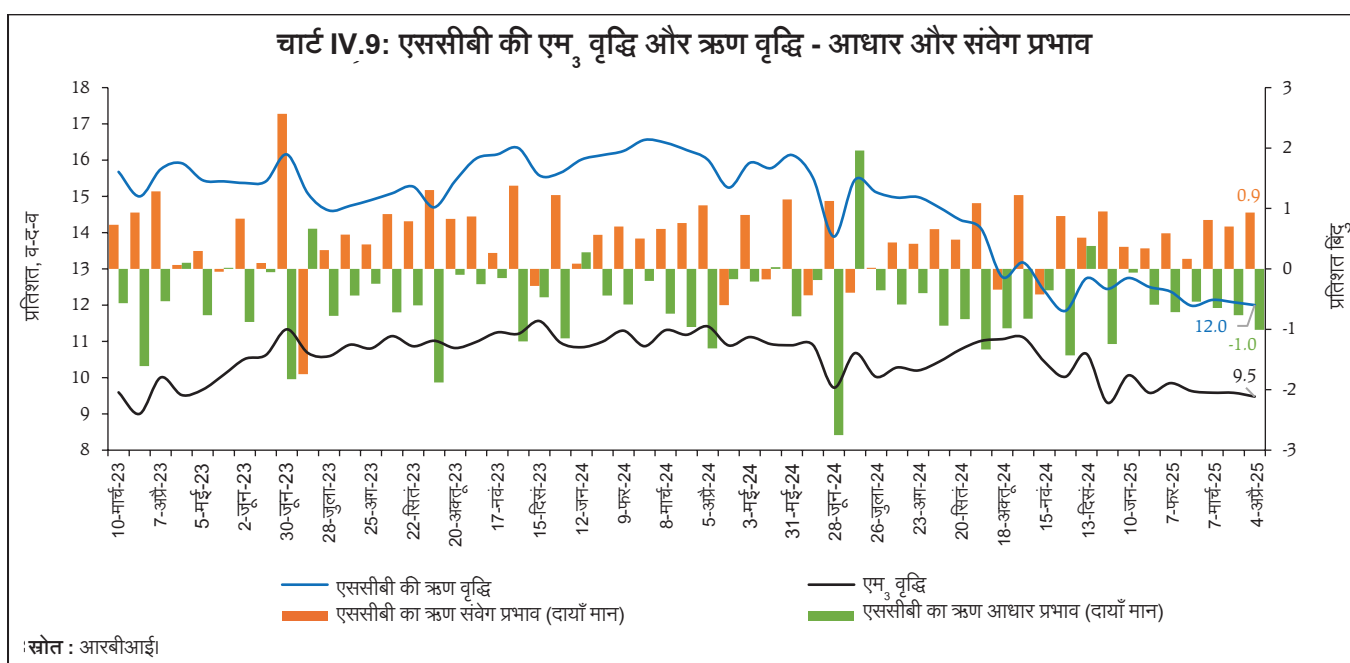
स्रोत: एफआईएमएडीए; और ब्लूमबर्ग।



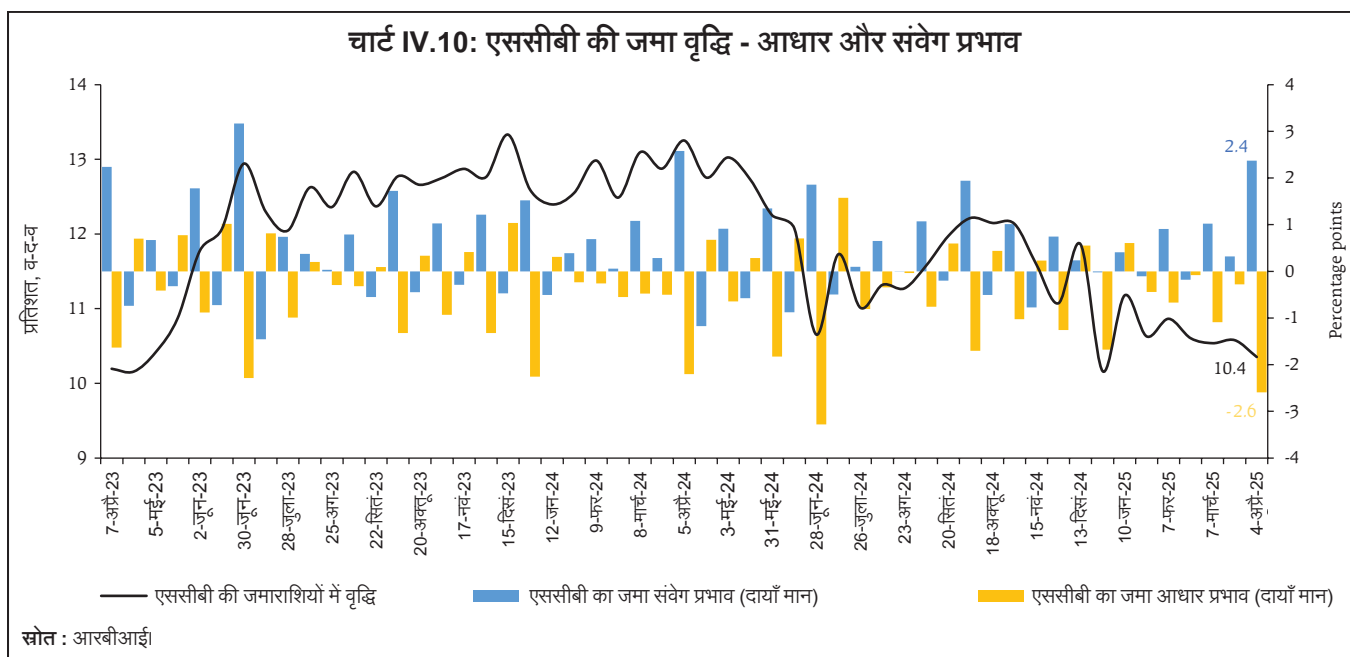
4 अप्रैल 2025 तक मुद्रा आपूर्ति (एम₃) में 9.5 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई (एक वर्ष पूर्व 11.4 प्रतिशत)¹⁵ बैंकों के पास कुल जमा, जो एम₃ का लगभग 86.5 प्रतिशत है, में 9.9 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 12.7 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की ऋण वृद्धि 4 अप्रैल 2025 तक 12.0 प्रतिशत (एक वर्ष पूर्व 16.0

प्रतिशत) तक कम हो गई, जो प्रतिकूल आधार प्रभाव के कारण हुई, जिसने सकारात्मक गति को संतुलित कर दिया (चार्ट IV.9)।

4 अप्रैल 2025 तक, एससीबी की जमा वृद्धि (विलय के प्रभाव को छोड़कर) एक वर्ष पहले के 13.3 प्रतिशत से घटकर 10.4 प्रतिशत हो गई (चार्ट IV.10)।



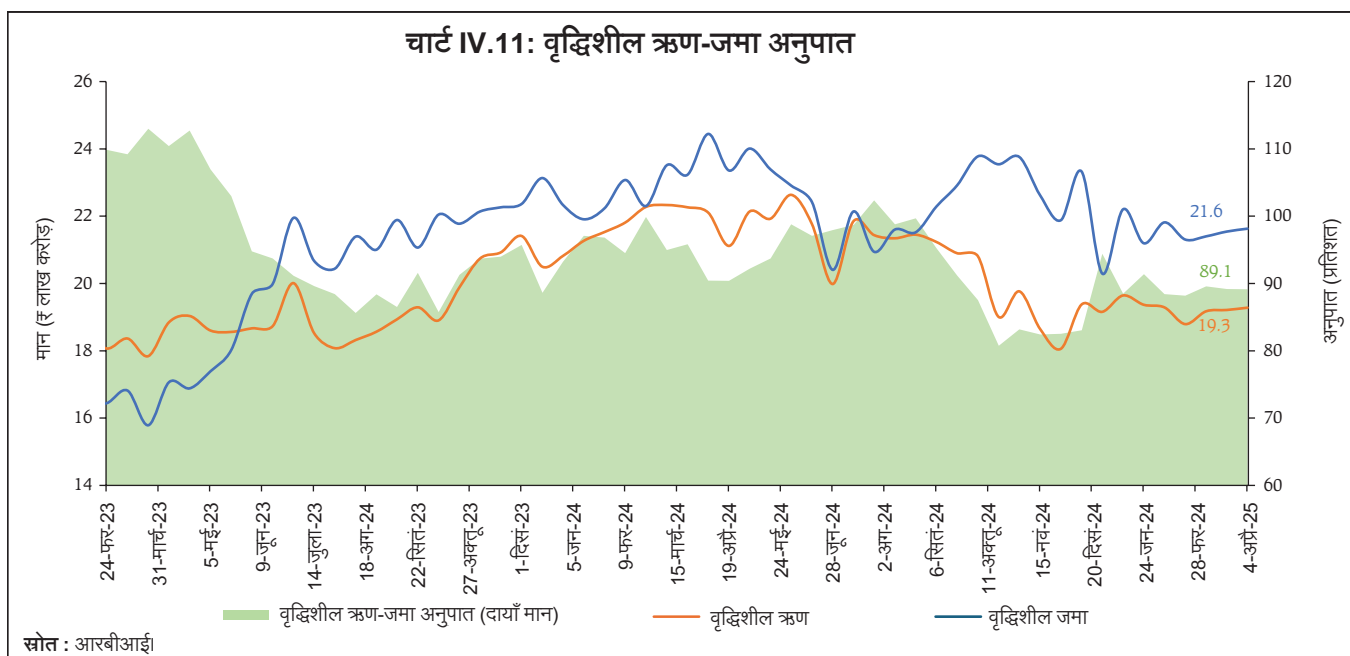
¹⁵ बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय के प्रभाव को छोड़कर (1 जुलाई, 2023 से प्रभावी)।



एससीबी का वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात 18 अक्टूबर 2024 के 80.7 प्रतिशत के निम्नतम स्तर से बढ़कर 4 अप्रैल 2025 को 89.1 प्रतिशत हो गया।

फरवरी 2025 से नीतिगत रेपो दर में 50-बीपीएस की कटौती की प्रतिक्रिया में, बैंकों ने अपने रेपो-लिंकड ईबीएलआर में लगभग इतनी ही कमी की है। सीमांत निधि लागत-आधारित उधार दर (एमसीएलआर), जिसकी पुनर्निर्धारण अवधि

लंबी होती है और जो निधि की लागत से संबंधित होती है, कुछ अंतराल के साथ समायोजित हो सकती है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के बकाया रुपया ऋणों पर भारित औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) में 7 बीपीएस की गिरावट आई है; हालाँकि, फरवरी में नए रुपया ऋणों के लिए इसमें 8 बीपीएस की वृद्धि हुई है (सारणी IV.3)। जमाराशियों के मामले में, इसी अवधि के दौरान नई जमाराशियों पर भारित औसत



सारणी IV.3: बैंकों की जमा और उधार दरों में संचरण

(आधार बिंदु)

अवधि	रेपो दर	मीयादी जमा दरें		उधार दरें			
		मीयादी जमा दरें	डबल्यूएडीटीडीआर – नई जमाराशियाँ	ईबीएलआर	1-वर्षीय एमसीएलआर (माध्यिका)	डबल्यूएलआर – नया रुपया ऋण	डबल्यूएलआर- बकाया रुपया ऋण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सहज अवधि फरवरी 2025 से मार्च* 2025	-25	-8	0	-25	0	8	-7
सख्त अवधि मई 2022 से जन 2025	+250	253	199	250	178	181	115
सहजता अवधि फर 2019 से मार्च 2022	-250	-259	-188	-250	-155	-232	-150

टिप्पणी: 1. ईबीएलआर पर डेटा 32 घरेलू बैंकों से संबंधित है।

*: एमसीएलआर पर डेटा फरवरी 2025 से संबंधित है।

डबल्यूएलआर: भारत औसत उधार दर; डबल्यूएडीटीडीआर: भारत औसत घरेलू मीयादी जमा दर;

एमसीएलआर: निधि-आधारित उधार दर की सीमांत लागत; ईबीएलआर: बाह्य बेंचमार्क-आधारित उधार दर।

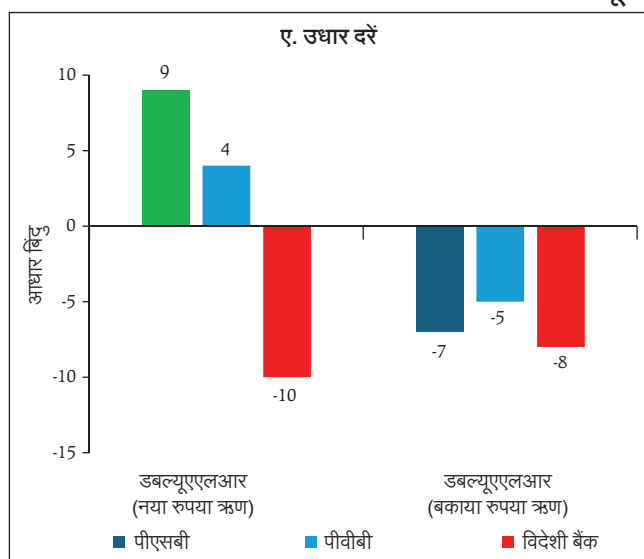
स्रोत: आरबीआई।

घरेलू सावधि जमा दर (डबल्यूएडीटीडीआर) में 8 बीपीएस की कमी आई।

निजी बैंकों की तुलना में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) में डबल्यूएलआर में वृद्धि अधिक थी; हालाँकि, बकाया ऋणों के मामले में, फरवरी 2025 के दौरान पीएसबी में संचरण अधिक था (चार्ट IV.12)। डबल्यूएडीटीडीआर के मामले में, पीएसबी और विदेशी बैंकों, दोनों ने अपनी नई जमा दरों में कमी की है।

भारत सरकार ने विभिन्न लघु बचत लिखतों पर ब्याज दरों की समीक्षा की है, जो तुलनीय परिपक्वताओं की सरकारी प्रतिभूतियों पर द्वितीयक बाजार प्रतिफल से जुड़े हैं और इसे ति1:2025-26 के लिए अपरिवर्तित रखा है।¹⁶ परिणामस्वरूप, अधिकांश लिखतों पर दरें अब 16-66 बीपीएस की सीमा में सूत्र-आधारित दरों से ऊपर हैं।¹⁷ दर सहजता चक्र में जब जमा दरों में कमी आने की उम्मीद है, उच्च लघु बचत

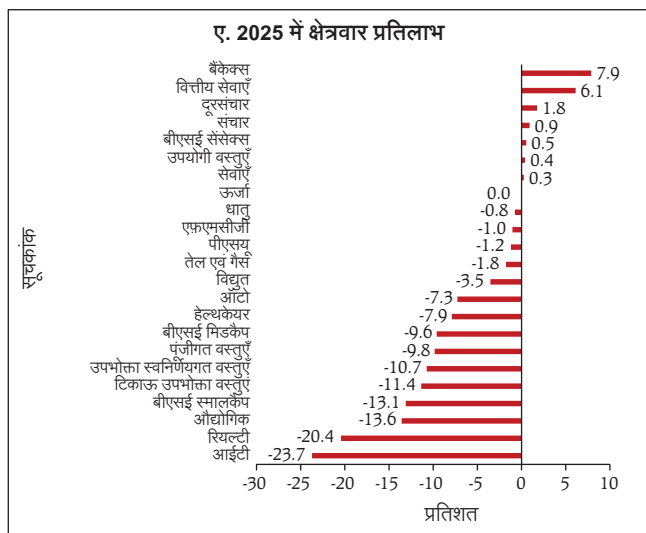
चार्ट IV.12: बैंक समूहों में संचरण (फरवरी 2025)



स्रोत : आरबीआई।

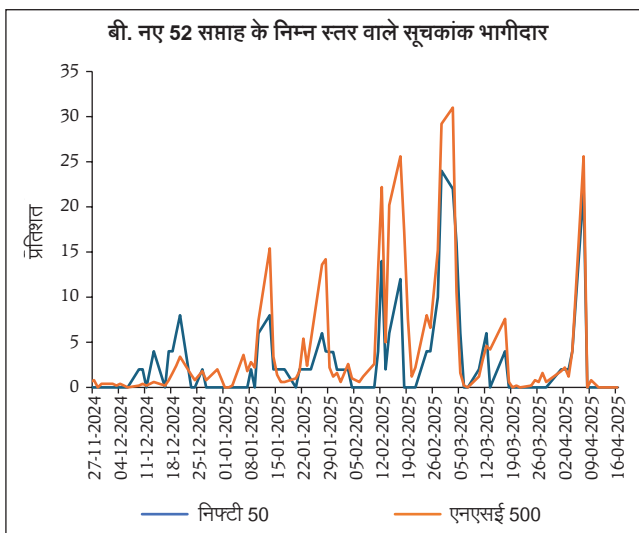
¹⁶ <https://dea.gov.in/sites/default/files/Revision%20of%20RoI.pdf>¹⁷ आरबीआई मौद्रिक नीति रिपोर्ट- अप्रैल 2025, अध्याय IV.

चार्ट IV.13: इक्विटी बाज़ार का प्रदर्शन



टिप्पणी: 17 अप्रैल 2025 तक डेटा।

स्रोत: ब्लूमबर्ग।



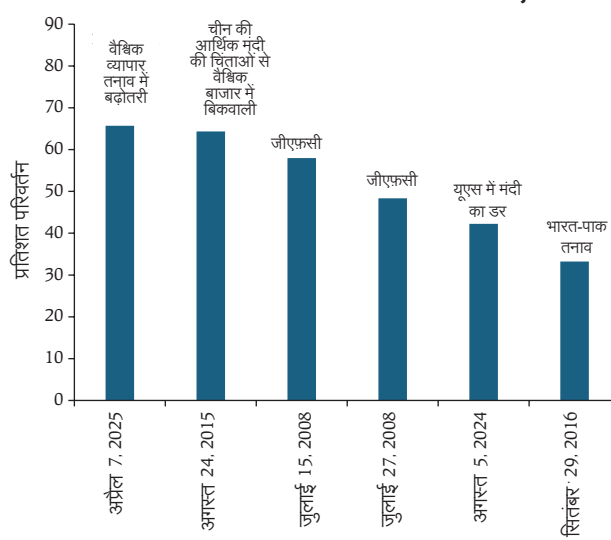
दरें बैंक जमा वृद्धि के लिए चिंता का एक संभावित स्रोत हो सकती हैं।

मार्च के उत्तरार्ध में भारतीय शेयर बाजारों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के निवेश, आघात-सहनीय आर्थिक गतिविधियों और मुद्रास्फीति में कमी के कारण बढ़त दर्ज की गई। हालाँकि, अप्रैल की शुरुआत में शेयर बाजारों में भारी गिरावट देखी गई, जो अमेरिका द्वारा पारस्परिक शुल्क लगाए जाने के कारण वैश्विक बाजारों में आई गिरावट के अनुरूप थी। 7 अप्रैल को हुई भारी बिकवाली ने मार्च के उत्तरार्ध में दर्ज बढ़त को लगभग खत्म कर दिया, क्योंकि निफ्टी 50 के 22 प्रतिशत और एनएसई 500 के 26 प्रतिशत शेयरों ने उस दिन 52-सप्ताह के नए निचले स्तर दर्ज किए (चार्ट IV.13)। यह अत्यधिक अस्थिरता से भी जुड़ा था क्योंकि भारत VIX ने 7 अप्रैल 2025 को (नवंबर 2007 के बाद से) अपनी उच्चतम एकल-दिवसीय प्रतिशत वृद्धि दर्ज की [चार्ट IV.14]। अमेरिका द्वारा पारस्परिक शुल्कों में विराम की घोषणा के बाद वैश्विक बाजारों में हुई बढ़त के अनुरूप, घरेलू शेयर बाजारों में भी तेजी आई। मार्च 2025 में घरेलू उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति में गिरावट के समर्थन से, वित्तीय क्षेत्र के शेयरों ने इस सुधार का नेतृत्व

किया। घरेलू और वैश्विक दोनों इक्विटी बाजारों में अनिश्चितता इक्विटी निर्गमों के माध्यम से संसाधन जुटाने पर भारी पड़ रही है (चार्ट IV.15ए)। मार्च 2025 में कोई मेनबोर्ड आईपीओ जारी नहीं हुआ - फरवरी 2023 के बाद ऐसा पहला उदाहरण था (चार्ट IV.15बी)।

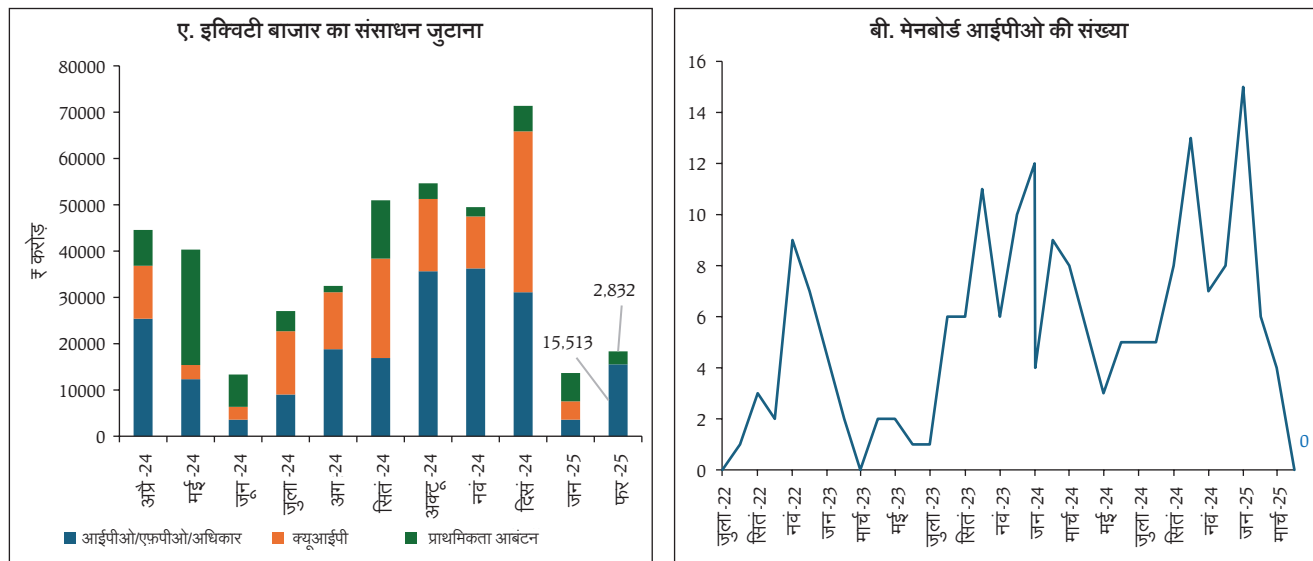
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) द्वारा संकलित क्षेत्रीय इक्विटी बाजार सूचकांकों के विश्लेषण से

चार्ट IV.14: भारत VIX: तीव्र अस्थिरता के एपिसोड



स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

चार्ट IV.15: प्राथमिक बाजार गतिविधि



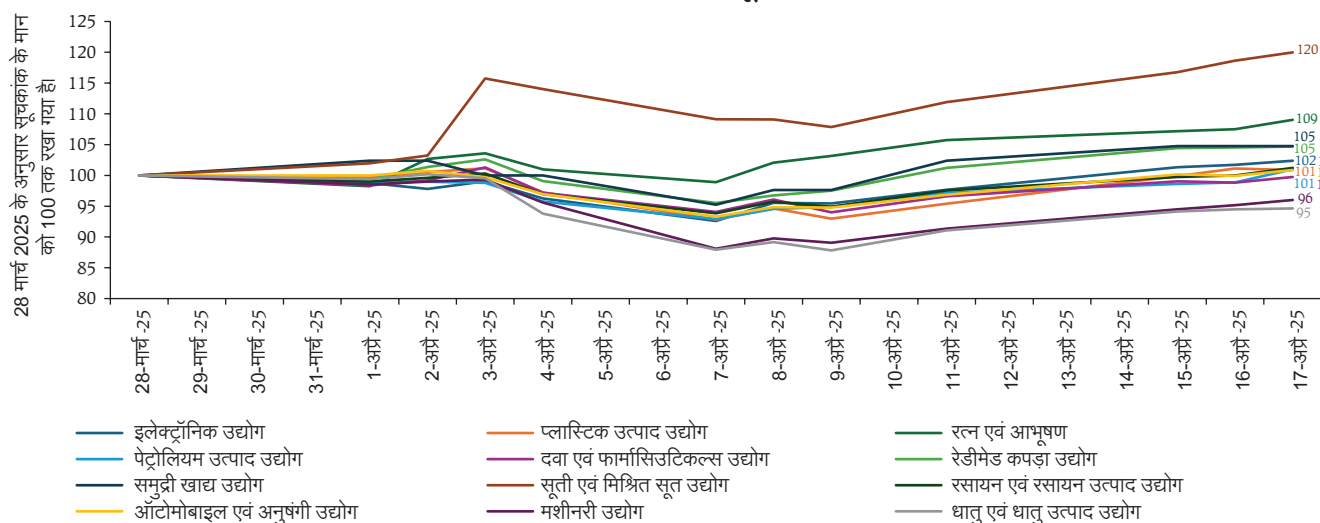
स्रोत: सेबी।

संकेत मिलता है कि अमेरिका के लिए पर्याप्त निर्यात जोखिम वाले क्षेत्र अप्रैल 2025 में अब तक अत्यधिक अस्थिर रहे हैं (चार्ट IV.16)।

भारतीय इक्विटी ऐतिहासिक रूप से अन्य उभरती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) की तुलना में प्रीमियम पर कारोबार करती रही हैं। विभिन्न सूचकांकों में अग्रिम मूल्य-और-आय (पीई) अनुपातों के 10-वर्षीय औसत के सापेक्ष प्रीमियम/

डिस्काउंट द्वारा मापे गए बाज़ार मूल्यांकन के विश्लेषण से पता चलता है कि वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के शुरुआती महीनों में अग्रिम पीई अनुपात अपने 10-वर्षीय औसत से काफी ऊपर चढ़ गए। तब से भारतीय इक्विटी बाज़ारों में आए सुधार के बाद, ये अनुपात अब अपने दीर्घकालिक औसत के करीब पहुँच गए हैं, जो बाज़ार मूल्यांकनों में और अधिक स्थायी स्तरों पर कमी का संकेत देता है (चार्ट IV.17)।

चार्ट IV.16: सीएमआईई क्षेत्रीय सूचकांकों का प्रदर्शन



टिप्पणी: 17 अप्रैल 2025 तक के आंकड़े।

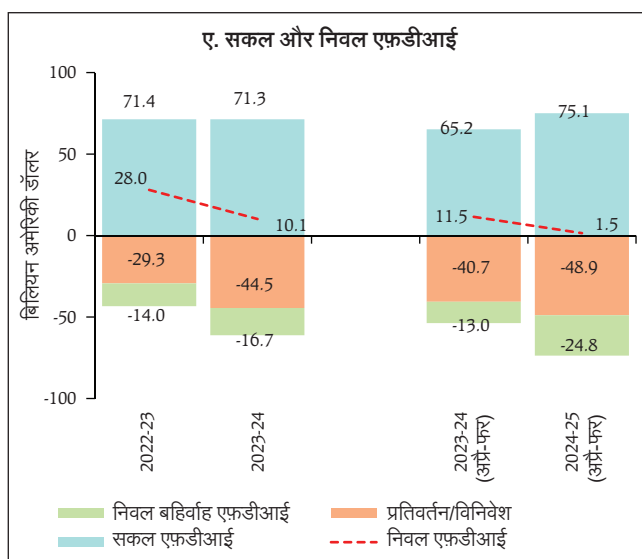
स्रोत: सीएमआईई; और आरबीआई स्टाफ की गणना।

चार्ट IV.17: 12-माह वायदा पीई मल्टीपल प्रीमियम/ डिस्काउंट 10 वर्षीय औसत से अधिक

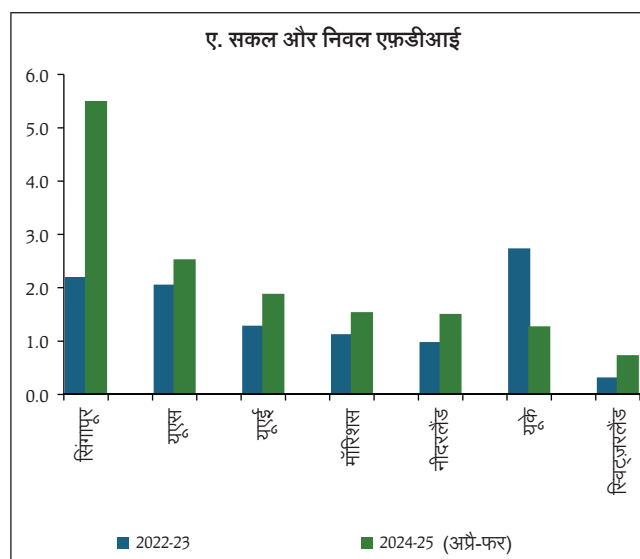

स्रोत: ब्लूमबर्ग; और आरबीआई स्टार्फ की गणना।

वर्ष 2024-25 (अप्रैल-फरवरी) के दौरान सकल आवक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) 15.2 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) बढ़कर 75.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया [चार्ट IV.18ए]। सिंगापुर 29.8 प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ इक्विटी प्रवाह का सबसे बड़ा स्रोत था, उसके बाद मॉरीशस और अमेरिका का स्थान था। एफडीआई प्रवाह में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक (24.1 प्रतिशत) थी, उसके

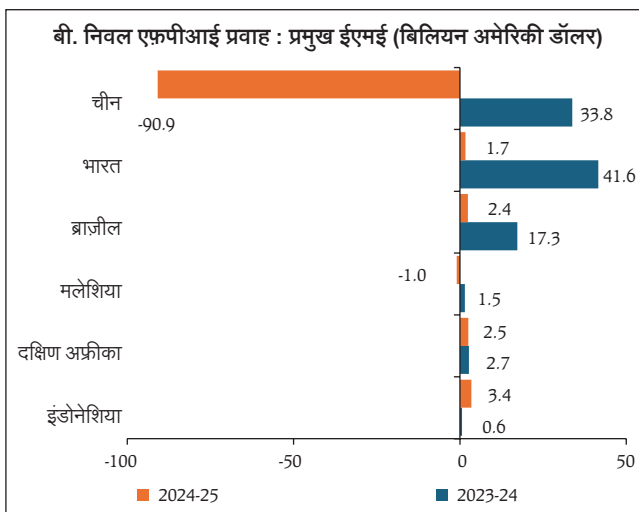
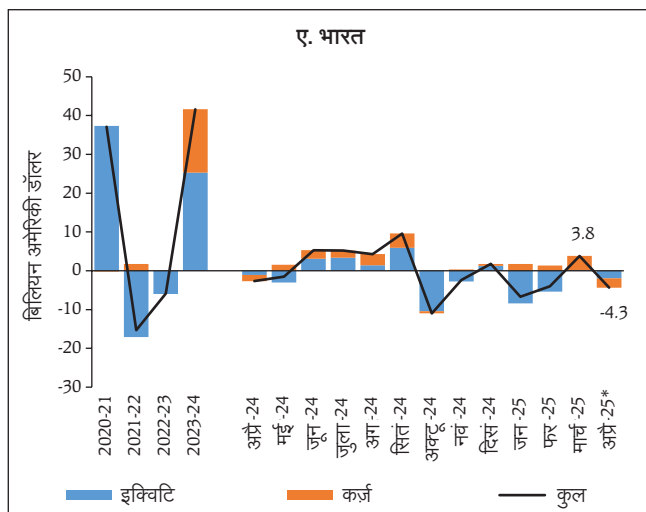
बाद वित्तीय सेवाओं और बिजली का स्थान था। भारत से उच्च प्रत्यावर्तन और जावक एफडीआई के कारण इस अवधि के दौरान निवल एफडीआई घटकर 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर रह गया। वैश्विक स्तर पर, अमेरिका आवक एफडीआई के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य बना हुआ है और हाल के वर्षों में भारत से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (ओडीआई) के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है (चार्ट IV.18बी)।

चार्ट IV.18: विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह


स्रोत: आरबीआई; और आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय।



चार्ट IV.19: निवल पोर्टफोलियो निवेश



टिप्पणियाँ: 1. ऋण में हाइब्रिड लिखतों के तहत निवेश भी शामिल हैं।

2. *: डेटा 16 अप्रैल 2025 तक है।

स्रोत: नेशनल सिक्क्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल); और अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान।

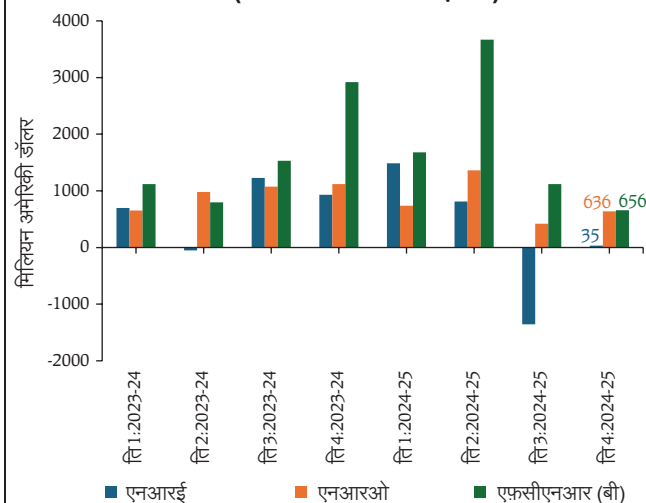
मार्च 2025 में एफपीआई प्रवाह में 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के अंतर्वाह के कारण बदलाव देखा गया, जो ज्यादातर डेट सेगमेंट (3.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर) द्वारा संचालित था [चार्ट IV.19ए]। मार्च में इक्विटी सेगमेंट में 0.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मामूली अंतर्वाह देखा गया, जिसने पिछले दो महीनों में देखे गए बहिर्वाह की प्रवृत्ति को उलट दिया। वर्ष 2024-25 में पूरी तरह से सुलभ मार्ग (एफएआर) के माध्यम से 9.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डेट एफपीआई सरकारी प्रतिभूतियों में प्रवाहित हुई है।¹⁸ मौजूदा वैश्विक व्यापार अनिश्चितताओं के बीच बढ़ते जोखिम-रहित भावनाओं के कारण वर्ष 2024-25 की दूसरी छमाही के दौरान इक्विटी सेगमेंट में बहिर्वाह के बावजूद, वर्ष 2024-25 के दौरान निवल एफपीआई प्रवाह 1.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर पर सकारात्मक रहा, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम है (चार्ट IV.19बी)।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए अनिवासी जमा (एनआरडी) के प्रवाह में पिछली तिमाही की तुलना में वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में सुधार देखा गया [चार्ट IV.20]। वर्ष 2024-25 के लिए, सभी उप-घटकों, अर्थात् विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) (एफसीएनआर(बी)), अनिवासी (बाह्य) रुपया खाते (एनआर(ई)

आरए) और अनिवासी साधारण (एनआरओ) खातों में एनआरडी का निवल प्रवाह सकारात्मक रहा।

संचयी आधार पर, अप्रैल 2024 - फरवरी 2025 के दौरान बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) पंजीकरण (50.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) और संवितरण (46.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर) पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में क्रमशः 8.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर और 13.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक रहे। 25.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर के मूलधन

चार्ट IV.20: एससीबी के एनआरडी के घटकों का तिमाही प्रवाह (आरआरबी को छोड़कर)

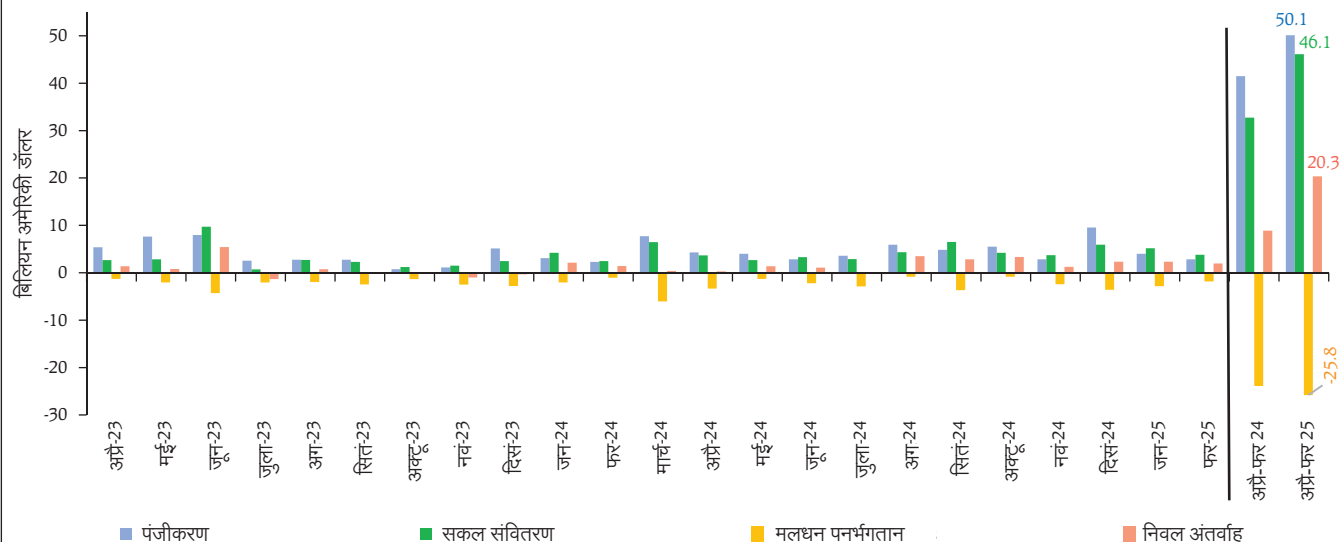


टिप्पणी: ति 4: 2024-25 के लिए डेटा अंतिम है।

स्रोत: आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 42 (2) के तहत फॉर्म ए रिटर्न।

¹⁸ स्रोत: <https://www.fpi.nsdil.co.in/web/Reports/Yearwise.aspx?RptType=5>

चार्ट IV.21: बाह्य वाणिज्यिक उधार- पंजीकरण और प्रवाह



स्रोत: फॉर्म ईसीबी, आरबीआई।

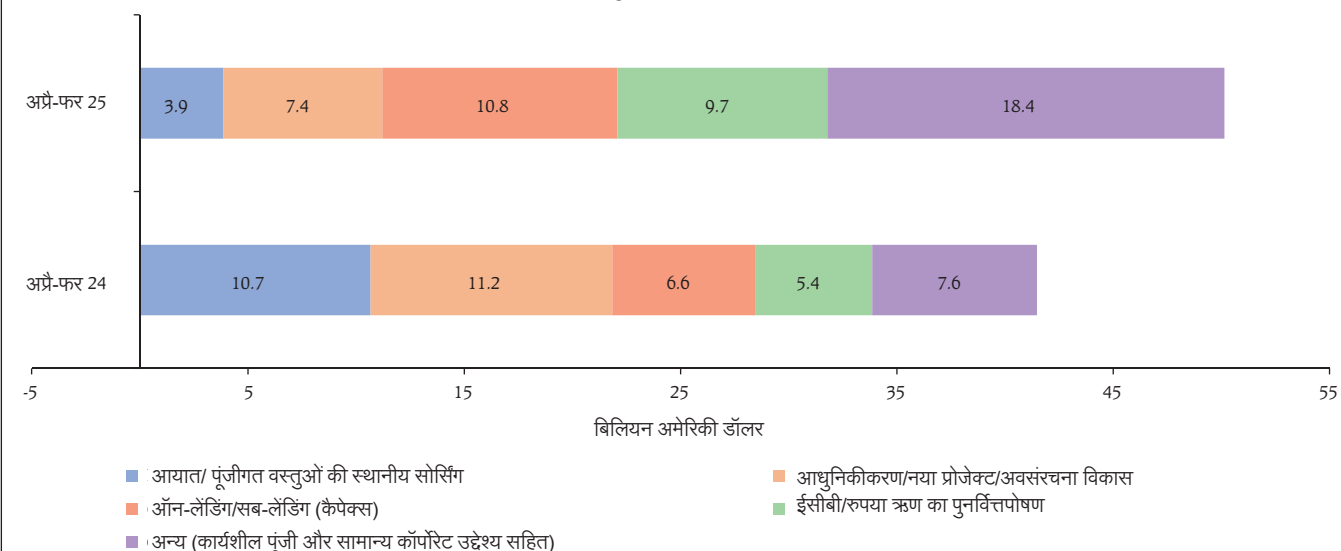
पुनर्भुगतान के समायोजन के बाद, चालू वित्त वर्ष के दौरान निवल ईसीबी अंतर्वाह (20.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर) काफी अधिक रहा - एक वर्ष पहले दर्ज किए गए स्तर से दोगुने से भी अधिक (चार्ट IV.21)।

अप्रैल 2024-फरवरी 2025 के दौरान पंजीकृत कुल ईसीबी का लगभग 44 प्रतिशत पूंजीगत व्यय के लिए था, जिसमें ऋण/उप-ऋण भी शामिल है (चार्ट IV.22)।

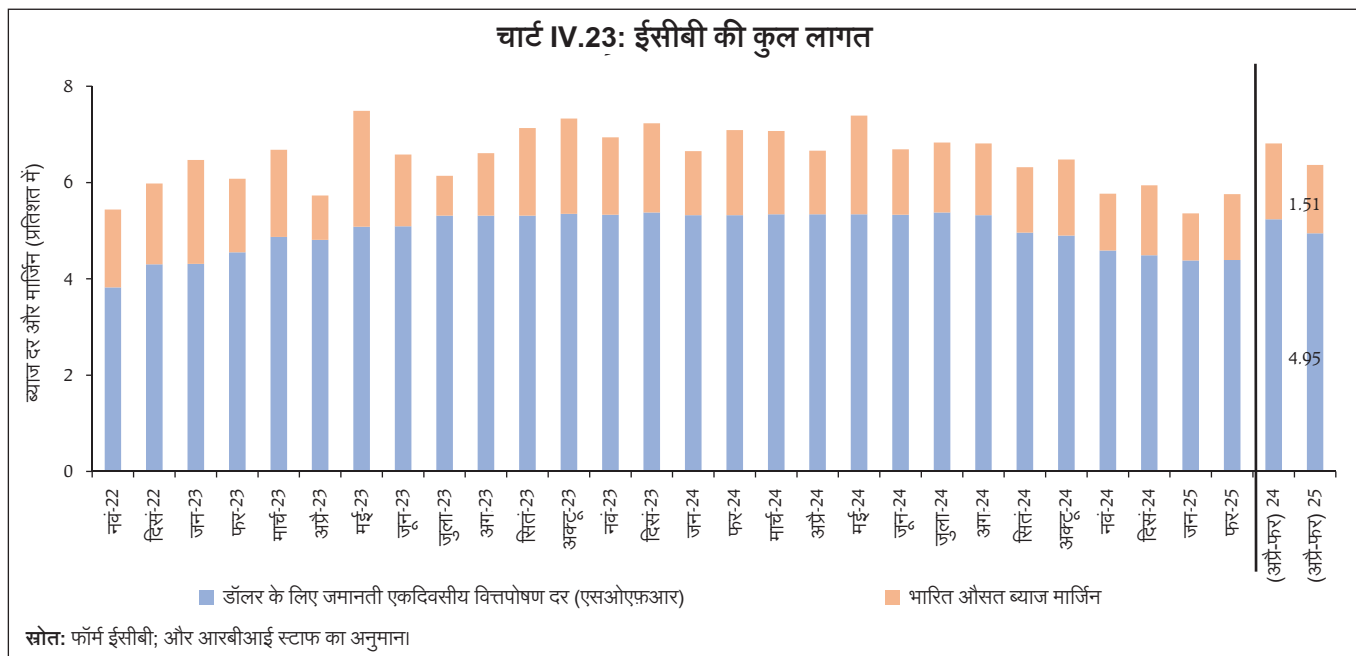
वर्ष के दौरान पंजीकृत ईसीबी की कुल लागत में 35 बीपीएस की गिरावट आई, जो वैश्विक बेंचमार्क ब्याज दरों - प्रतिभूतित एकदिवसीय वित्तपोषण दर (एसओएफआर) और भारत औसत ब्याज मार्जिन (डब्ल्यूएआईएम) दोनों में कमी के कारण हुई [चार्ट IV.23]।

मार्च 2025 के दौरान भारतीय रुपए (आईएनआर) में 0.5 प्रतिशत (मा-मा-मा) की वृद्धि हुई, जिसे एफपीआई अंतर्वाह और अंतर-कंपनी उधार से वर्ष के अंत में डॉलर प्राप्तियों का

चार्ट IV.22: पंजीकृत ईसीबी का अंतिम उपयोग



स्रोत: आरबीआई।

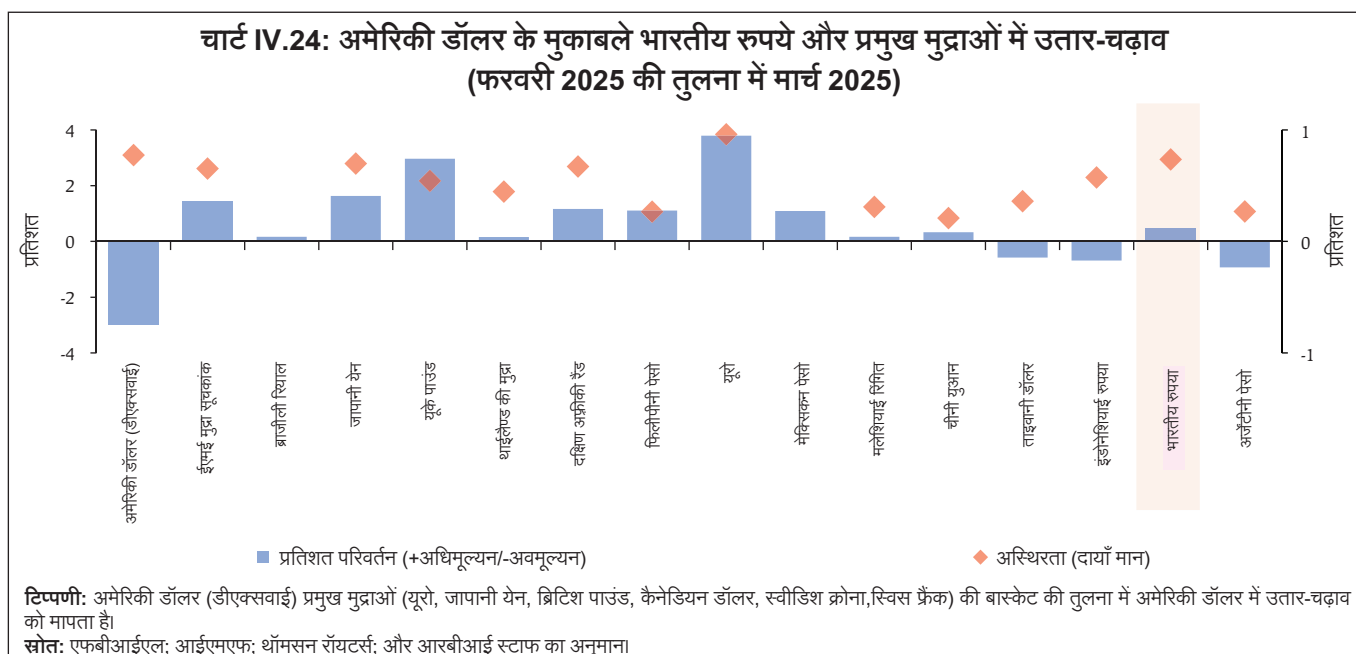


समर्थन प्राप्त हुआ; हालांकि, वैश्विक अनिश्चितता बढ़ने के कारण रुपये में अस्थिरता बढ़ी (चार्ट IV.24)।

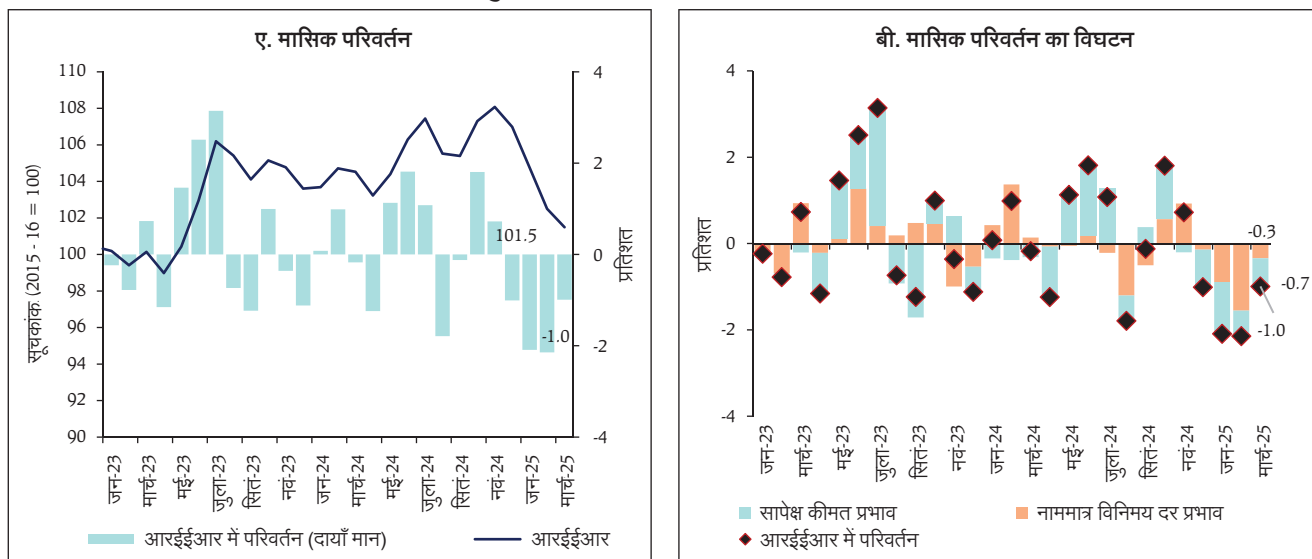
मार्च 2025 में 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) के संदर्भ में भारतीय रुपये में 1.0 प्रतिशत (माह-माह) की गिरावट आई, जिसका कारण नाममात्र प्रभावी शर्तों में भारतीय रुपये का मूल्यहास और भारत के अपने प्रमुख व्यापारिक भागीदारों के साथ मुद्रास्फीति अंतर का बढ़ना है (चार्ट IV.25)।

11 अप्रैल 2025 तक, भारत के पास 677.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार था, जो लगभग 11 महीनों के आयात और दिसंबर 2024 के अंत तक बकाया विदेशी ऋण के 94 प्रतिशत के लिए पर्याप्त था (चार्ट IV.26ए)। अपने वर्तमान स्तर पर, भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है (चार्ट IV.26बी)।

भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही के 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का



चार्ट IV.25: 40-मुद्रा वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में उतार-चढ़ाव



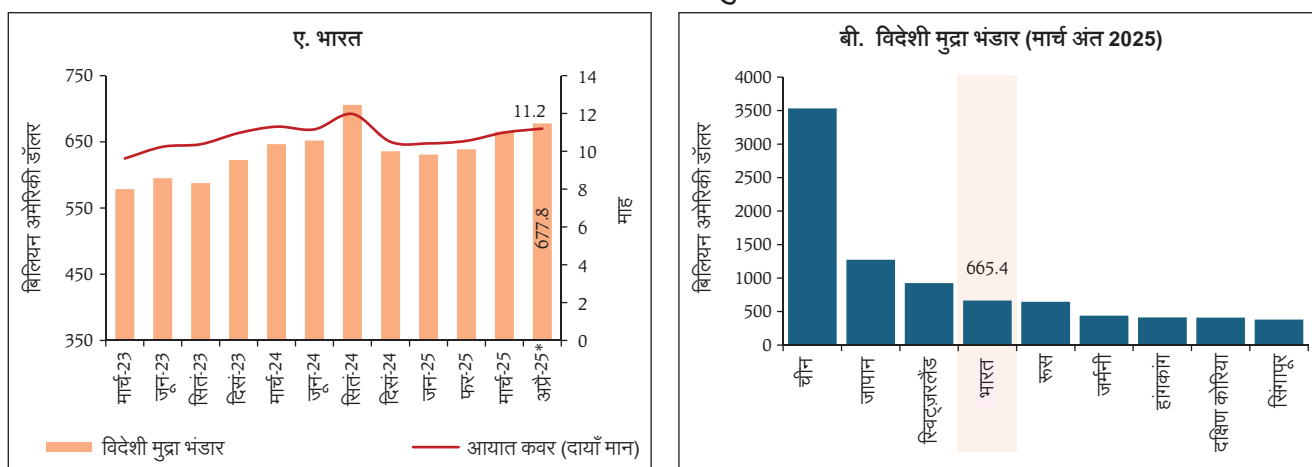
स्रोत: आरबीआई

1.8 प्रतिशत) से घटकर वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 11.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.1 प्रतिशत) हो गया, लेकिन यह 2023-24 की तीसरी तिमाही के 10.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 1.1 प्रतिशत) से अधिक था। व्यापार, कंप्यूटर, परिवहन और यात्रा, सेवाओं के निर्यात में मजबूत वृद्धि के साथ-साथ उच्च प्रेषण प्राप्तियों ने बढ़ते पण्य वस्तु व्यापार घाटे के प्रभाव को कम किया। वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में 26.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवल

पूंजी बहिर्वाह मुख्य रूप से भारत में एफपीआई और एफडीआई के बहिर्वाह से प्रेरित था। सीएडी और निवल पूंजी बहिर्वाह के कारण तीसरी तिमाही के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार (बीओपी आधार पर) में 37.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमी हुई (चार्ट IV.27)।

भारत का बाह्य ऋण मार्च 2024 के अंत में 668.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का 18.5 प्रतिशत) से बढ़कर दिसंबर 2024 के अंत में 717.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर (जीडीपी का

चार्ट IV.26: विदेशी मुद्रा भंडार

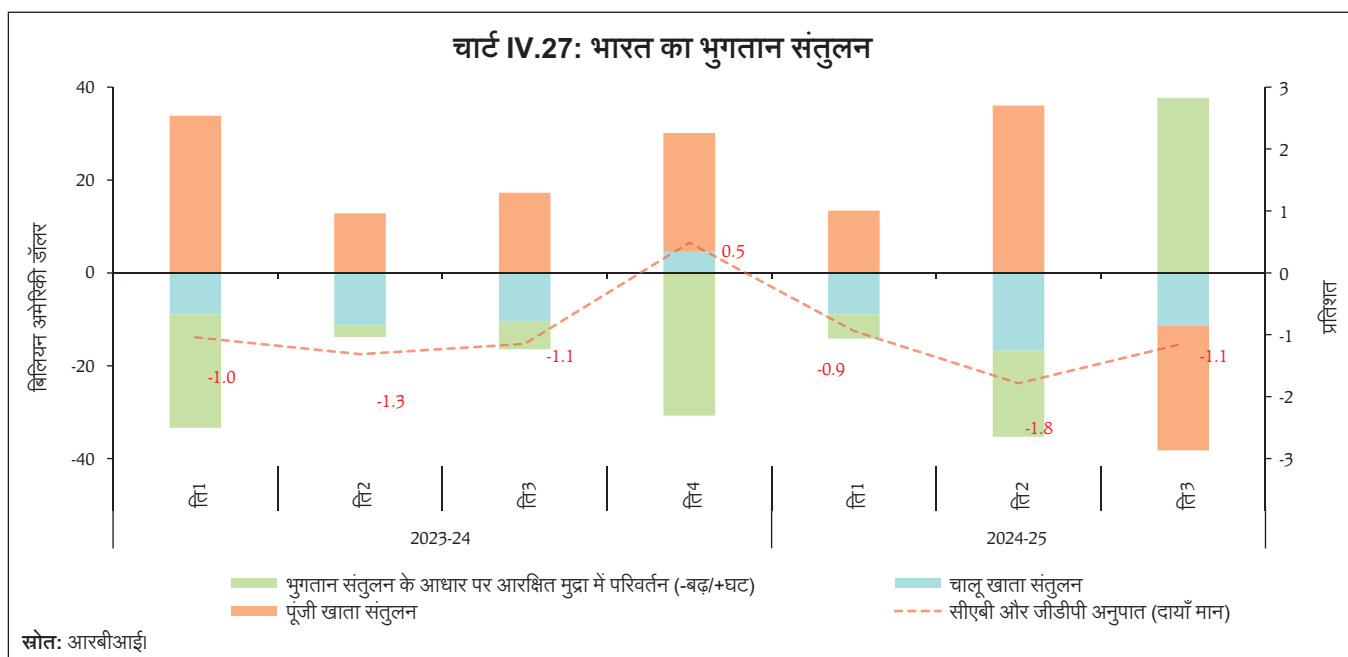


टिप्पणियाँ: 1. *: 11 अप्रैल तक डेटा।

2. भुगतान संतुलन के आंकड़ों के आधार पर दिसंबर 2024 और जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 के लिए आयात कवर डेटा दिसंबर 2024 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए वार्षिक पण्य वस्तुओं के आयात पर आधारित है।

3. स्विट्जरलैंड के डेटा फरवरी 2025 के हैं।

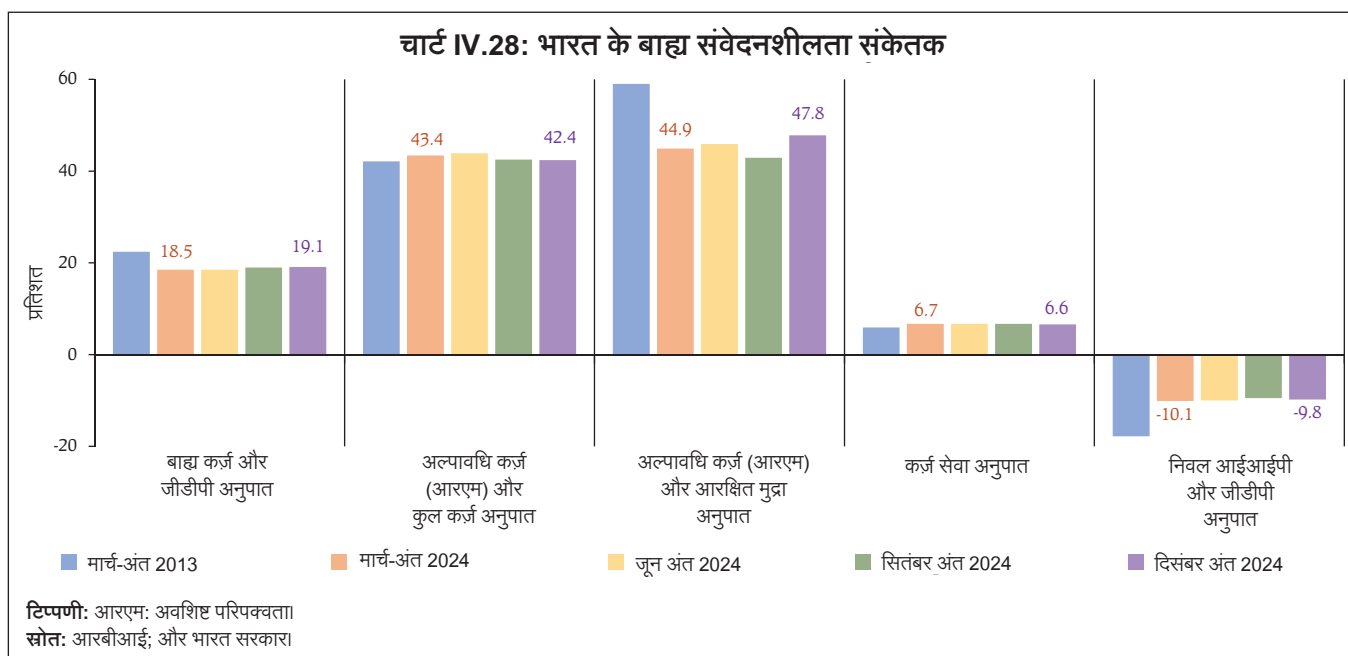
स्रोत: आरबीआई; संबंधित केंद्रीय बैंक की वेबसाइट; और आरबीआई स्टाफ का अनुमान।

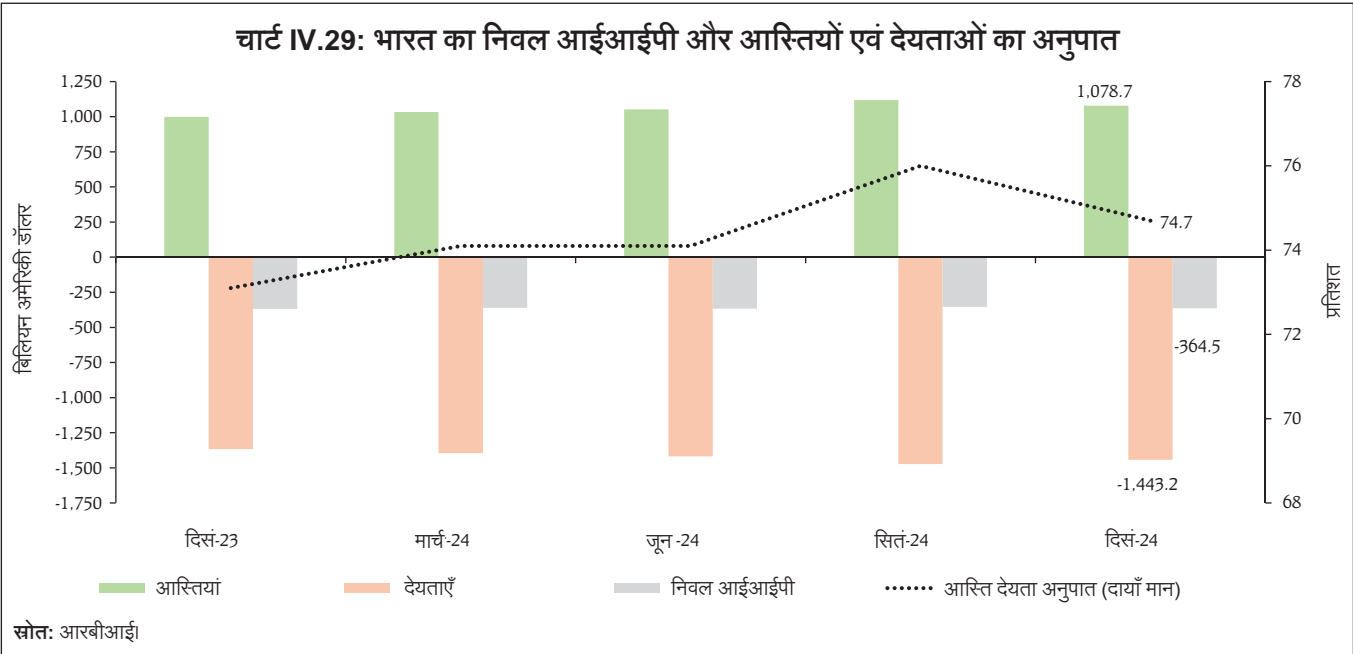


19.1 प्रतिशत) हो गया। हालाँकि, अन्य बाह्य भेद्यता संकेतकों में इसी अवधि के दौरान सुधार देखा गया, जो चुनौतीपूर्ण वैश्विक वातावरण के बीच भारत के बाह्य क्षेत्र की आघात-सहनीयता पर जोर देता है (चार्ट IV.28)।

भारत की निवल अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति (आईआईपी) वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही के दौरान 11 बिलियन

अमेरिकी डॉलर बढ़कर 364.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। हालाँकि इस तिमाही के दौरान भारतीय निवासियों की विदेशी आस्तियों और भारत की विदेशी देयताओं, दोनों में गिरावट आई, लेकिन अंतरराष्ट्रीय देयताओं के मुकाबले अंतरराष्ट्रीय आस्तियों का अनुपात दिसंबर 2024 में एक वर्ष पहले के 73.1 प्रतिशत से बढ़कर 74.7 प्रतिशत हो गया (चार्ट IV.29)।





भुगतान प्रणाली

मार्च 2025 में विभिन्न भुगतान माध्यमों से डिजिटल लेनदेन में वृद्धि हुई, जिसका नेतृत्व एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) के माध्यम से खुदरा लेनदेन ने किया [सारणी IV.4]। तत्काल सकल निपटान (आरटीजीएस) के माध्यम से बड़े मूल्य के लेनदेन में मात्रा और मूल्य दोनों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। बीबीपीएस में भी मात्रा और मूल्य दोनों में निरंतर वृद्धि देखी गई, और मार्च 2025 तक इसमें निरंतर वृद्धि देखी गई, जो

डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपभोक्ता बिल भुगतान में लगातार बदलाव का संकेत है।

यूपीआई भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य की आधारशिला बना हुआ है, जो मार्च 2025 में 18.3 बिलियन लेनदेन के साथ प्रमुख भुगतान प्रणालियों में दूसरी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज कर रहा है। यूपीआई लेनदेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खरीदारी पर खर्च किया जाता है, जिसमें जीवनशैली से संबंधित और आवश्यक खरीदारी दोनों शामिल हैं।¹⁹

सारणी IV.4: चुनिंदा भुगतान प्रणालियों में वृद्धि

(व-द-व प्रतिशत में)

भुगतान प्रणाली संकेतक	लेनदेन की मात्रा				लेनदेन का मूल्य			
	फर-24	फर-25	मार्च-24	मार्च-25	फर-24	फर-25	मार्च-24	मार्च-25
आरटीजीएस	18.8	2.5	12.3	10.3	21.2	10.2	12.4	18.1
एनईएफटी	47.3	11.0	45.2	13.5	25.1	2.0	15.2	12.3
यूपीआई	60.6	33.1	55.3	36.2	47.9	20.2	40.8	25.2
आईएमपीएस	19.4	-24.3	16.8	-20.5	21.2	-0.9	16.2	5.2
एनएसीएच	13.1	6.8	22.8	12.3	15.6	20.0	15.8	18.4
एनईटीसी	12.1	18.7	10.6	11.9	19.2	18.3	17.2	14.5
बीबीपीएस	29.8	87.3	25.4	85.7	85.8	240.6	82.8	265.0

टिप्पणी : आरटीजीएस: तत्काल सकल निपटान, एनईएफटी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण, यूपीआई: एकीकृत भुगतान इंटरफेस, आईएमपीएस: त्वरित भुगतान सेवा, एनएसीएच: राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह, एनईटीसी: राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, बीबीपीएस: भारत बिल भुगतान प्रणाली।
स्रोत: आरबीआई।

¹⁹ पर्फियोस और पीडब्ल्यूसी (2025), भारत कैसे खर्च करता है: उपभोक्ता खर्च व्यवहार में एक गहरा गोता। पर्फियोस, फरवरी।

भुगतान और फिनटेक क्षेत्र तक अपनी निरंतर पहुंच के हिस्से के रूप में, रिज़र्व बैंक ने मार्च 2025 में 5वां डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह (डीपीएडबल्यू) मनाया।²⁰ 'भारत डिजिटल रूप से भुगतान करता है' विषय के तहत आयोजित और 'हर भुगतान डिजिटल' मिशन के साथ संरेखित, इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना है। 9 अप्रैल 2025 के विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर अपने वक्तव्य में, रिज़र्व बैंक ने प्रस्ताव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) उपयोगकर्ता की बदलती जरूरतों के आधार पर व्यक्ति से व्यापारी (पी2एम) भुगतान के लिए यूपीआई लेनदेन की सीमा को संशोधित कर सकता है। बैंकों के पास एनपीसीआई फ्रेमवर्क के भीतर आंतरिक सीमाएँ निर्धारित करने का विवेकाधिकार बना रहेगा। इस बीच, विनियामक सैंडबॉक्स 'थीम न्यूट्रल' और 'ऑन टैप' हो जाएगा, जिससे विभिन्न श्रेणियों में योग्य फिनटेक नवाचारों का निरंतर परीक्षण संभव हो सकेगा।

V. निष्कर्ष

निकट भविष्य में, वैश्विक वृद्धि का परिदृश्य निराशाजनक बना हुआ है, क्योंकि टैरिफ से संबंधित अनिश्चितता और विभिन्न देशों की व्यक्तिगत नीतिगत प्रतिक्रियाओं के परिणामस्वरूप निवेश व्यय में कमी, उपभोक्ता विश्वास में कमी और वैश्विक व्यापार में मंदी आ सकती है। वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा पर इन घटनाक्रमों के दीर्घकालिक प्रभाव अत्यधिक अनिश्चित बने हुए हैं क्योंकि टैरिफ के दायरे, समय और तीव्रता के बारे में अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। आगे चलकर, वैश्विक वित्तीय स्थितियाँ अस्थिर बनी रहने की संभावना है और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएँ फीडबैक लूप और प्रभाव-विस्तार के प्रति संवेदनशील हैं, जिससे वैश्विक मुद्रास्फीति फिर से बढ़ सकती है। हालाँकि, वैश्विक कमोडिटी कीमतों में गिरावट कमोडिटी आयातक देशों में मुद्रास्फीति के दबाव को कम कर सकती है,

हालाँकि मुद्रा दबाव इन लाभों को आंशिक रूप से कम कर सकता है।

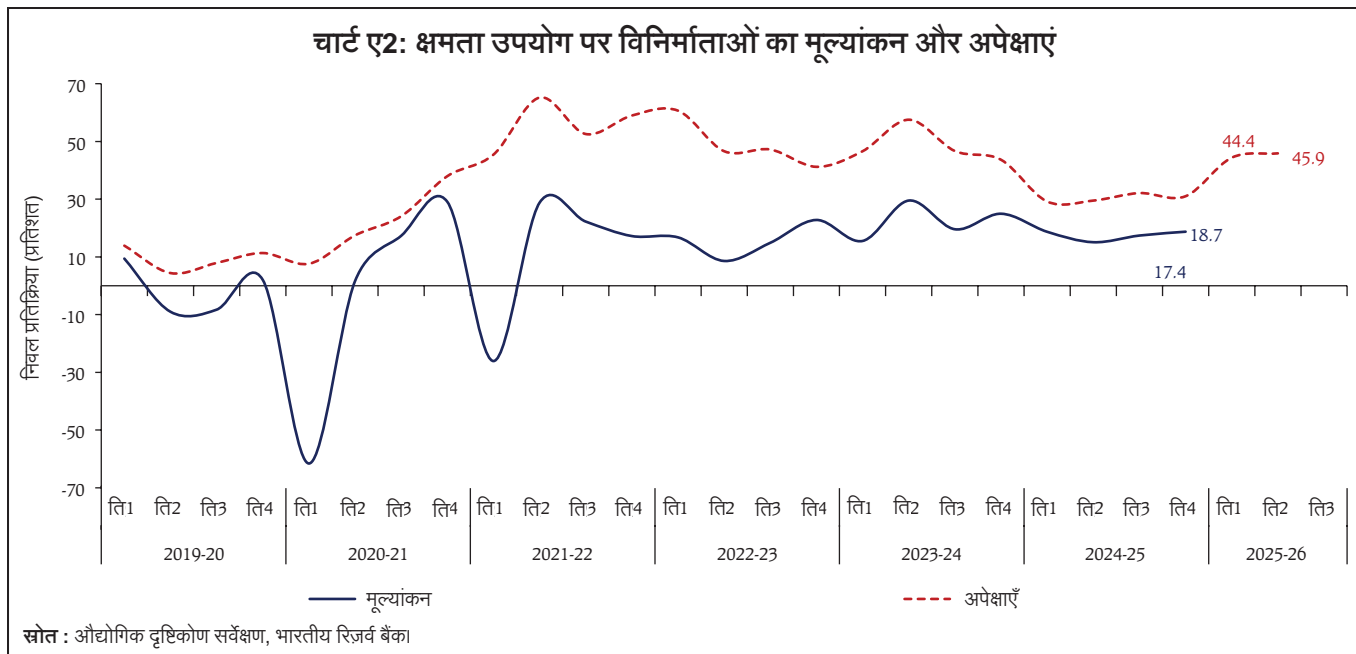
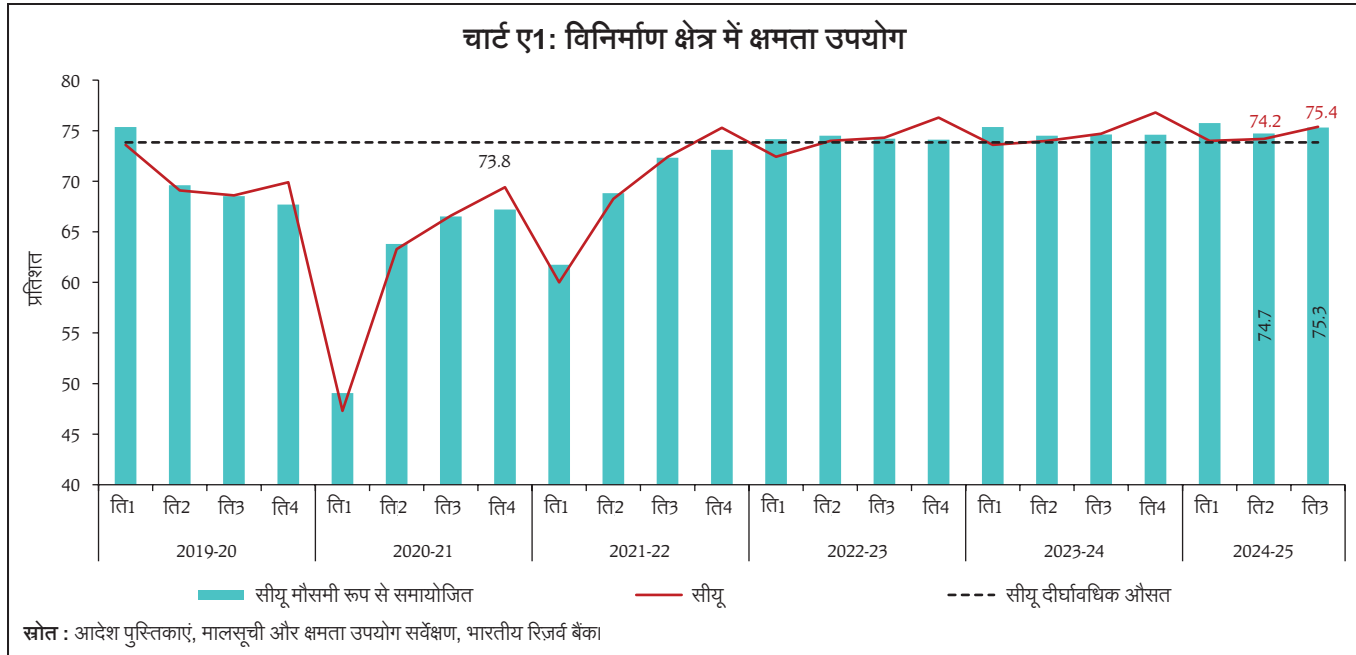
भारत की इन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता, एक मजबूत समष्टिआर्थिक फ्रेमवर्क और कम होती मुद्रास्फीति, तथा मजबूत घरेलू विकास इंजन द्वारा पोषित, इसकी मजबूत वृद्धि दर से प्राप्त होती है। भारत में कृषि क्षेत्र अपनी गति बनाए रखने के लिए तैयार है, जिसे बंपर खरीफ और रबी की फसल और बेहतर जलाशयों की स्थिति के साथ-साथ गर्मियों में अधिक बुवाई का समर्थन प्राप्त है। हालाँकि, सामान्य स्तर से ऊपर तापमान में वृद्धि और चालू ग्रीष्म ऋतु (अप्रैल-जून) में लू की संभावना से उत्पन्न जोखिमों पर नज़र रखने की आवश्यकता है। औद्योगिक और सेवा गतिविधियाँ लगातार आघात-सहनीय बनी हुई हैं। कई उद्योग निकायों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और बैंकों सहित उद्योग संघों के प्रतिनिधियों के बीच किए गए सर्वेक्षण के नतीजे मुद्रास्फीति में कमी, ग्रामीण उपभोग में निरंतर वृद्धि और शहरी उपभोग में सुधार से समर्थित आर्थिक गतिविधियों में आशावाद दर्शाते हैं। हालाँकि, वैश्विक अनिश्चितताएँ इस परिदृश्य के लिए नकारात्मक जोखिम के रूप में कार्य करती हैं।

आगे भारत आपूर्ति श्रृंखला पुनर्संरक्षण, विविध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्रोतों, और आघात-सहनीयता व पैमाने की तलाश में वैश्विक निवेशकों के साथ जुड़ाव से लाभान्वित होने के लिए तैयार है, क्योंकि उसके व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं। इसके अलावा, सेवा निर्यात और धन प्रेषण प्रवाह में भारत की निरंतर मजबूती चालू खाते के लिए एक महत्वपूर्ण बफर प्रदान करती रहेगी। संतुलित नीतिगत समर्थन भारत को वैश्विक अस्थिरता को अवसर में बदलने और उभरते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद कर सकता है।

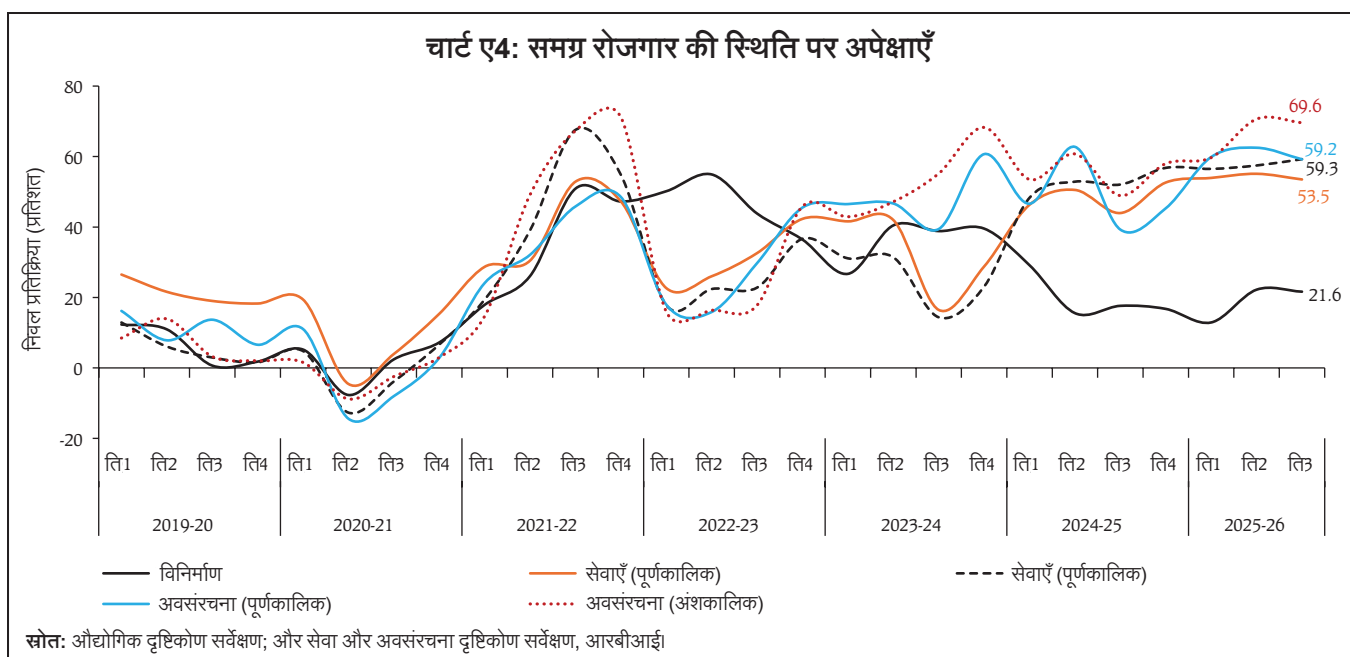
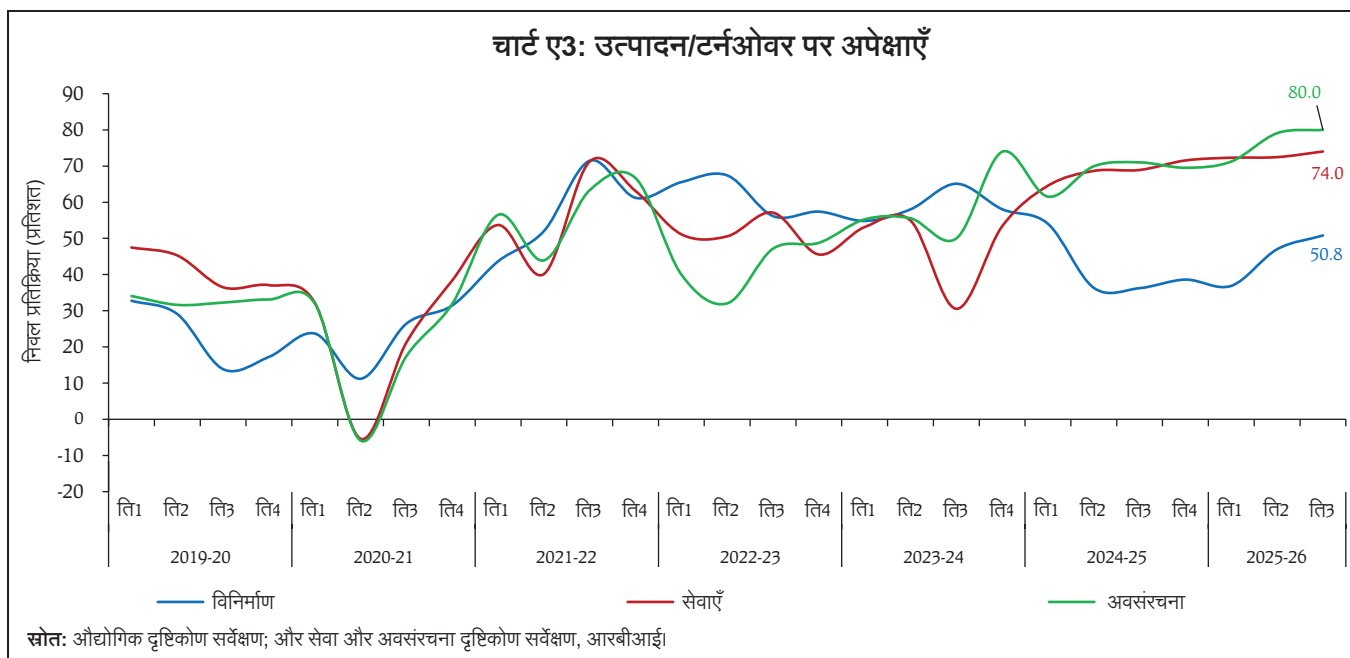
²⁰ आरबीआई प्रेस विज्ञप्ति। 10 मार्च, 2025। डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2025।

अनुबंध 1: आरबीआई के उद्यम सर्वेक्षण से प्रमुख निष्कर्ष

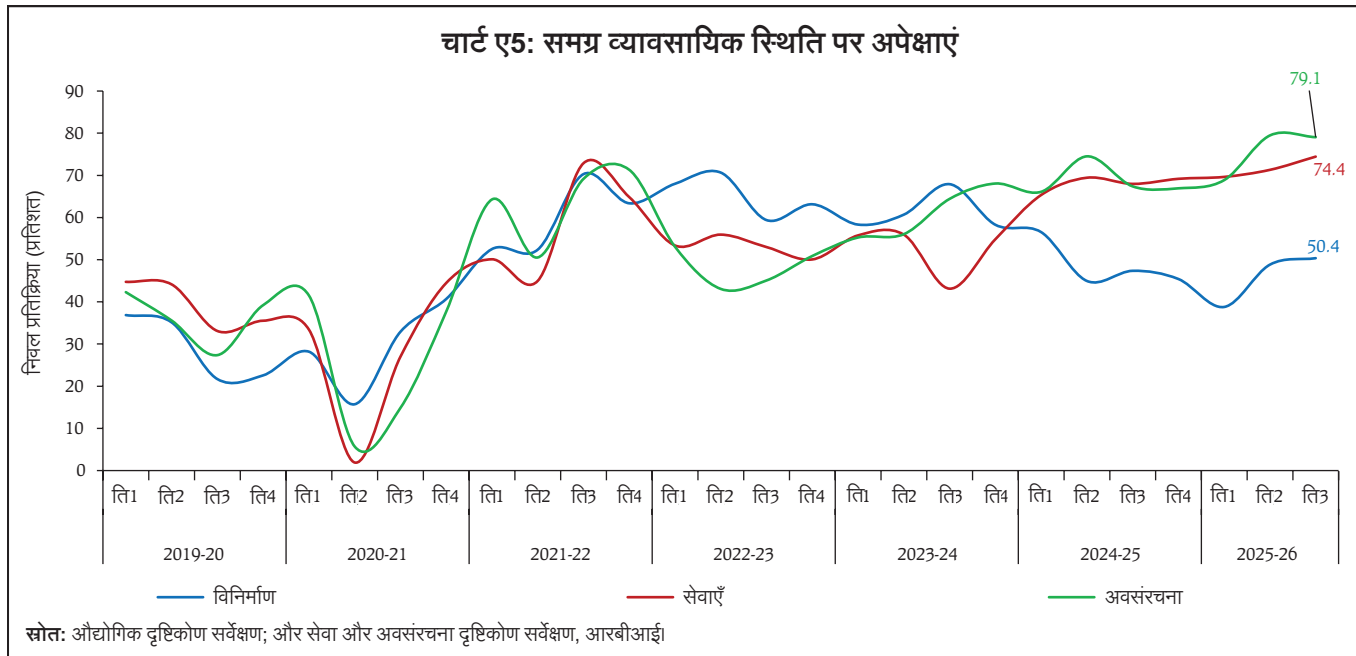
विनिर्माण क्षेत्र में क्षमता उपयोग (सीयू) में 120 बीपीएस की वृद्धि हुई, जबकि मौसमी रूप से समायोजित सीयू में ति3: 2024-25 में 60 बीपीएस की वृद्धि हुई (चार्ट ए1)। निर्माताओं ने आगामी तिमाहियों के लिए सीयू पर सकारात्मक दृष्टिकोण की रिपोर्ट करना जारी रखा (चार्ट ए2)।



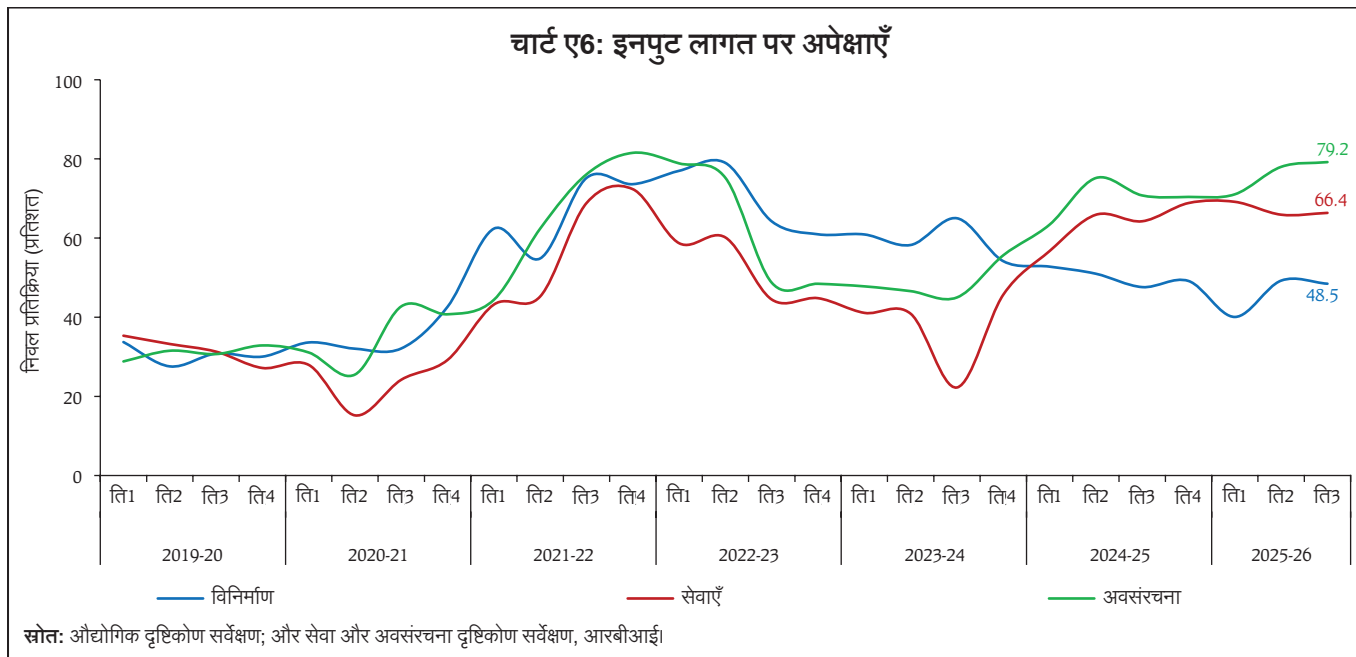
मांग की स्थिति पर निर्माताओं के आशावाद ने ति1: 2025-26 में मौसमी कमी दर्ज की, लेकिन आगामी तिमाहियों में सुधार दर्ज किया। सेवाओं और अवसंरचना फर्मों ने मांग की स्थिति पर अधिक आशावादी दृष्टिकोण की रिपोर्ट करना जारी रखा (चार्ट ए3)। रोजगार की स्थिति पर अपेक्षाएं काफी हद तक मांग की स्थितियों के साथ तालमेल में विकसित हुईं (चार्ट ए4)।



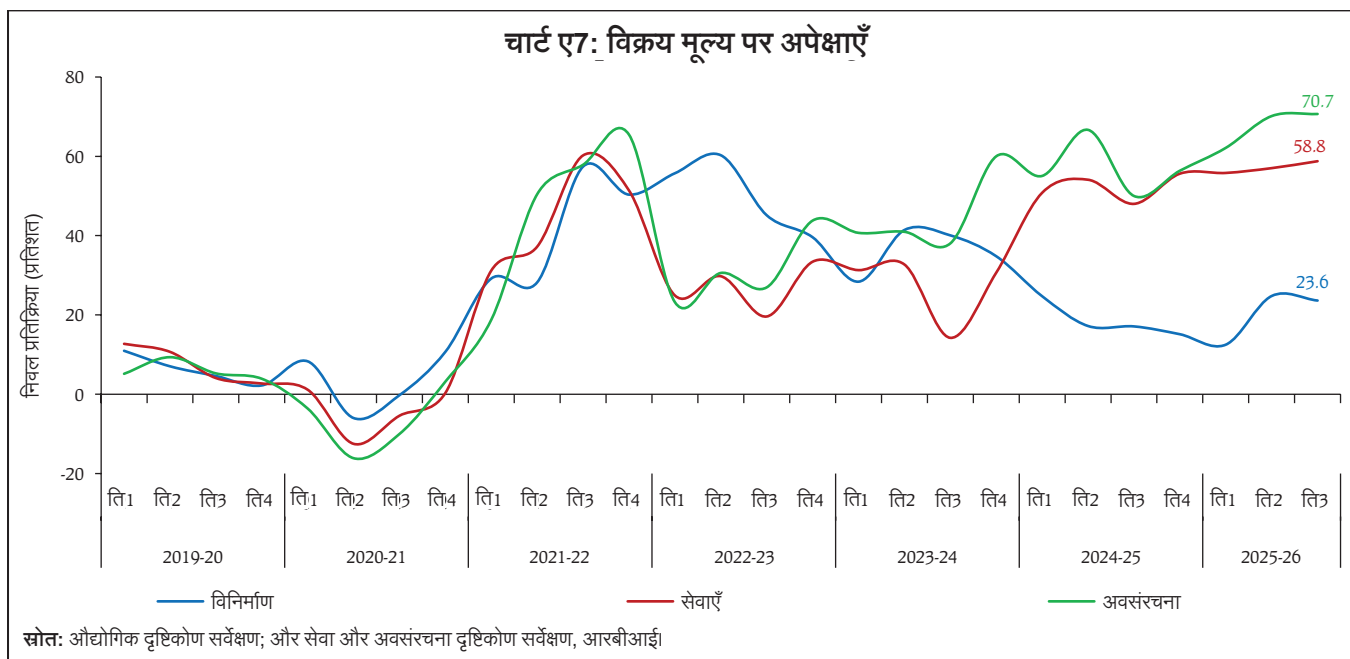
व्यापक क्षेत्रों में फर्म ति3: 2025-26 के माध्यम से समग्र व्यावसायिक स्थिति के बारे में आशावादी बनी हुई हैं (चार्ट ए5)।



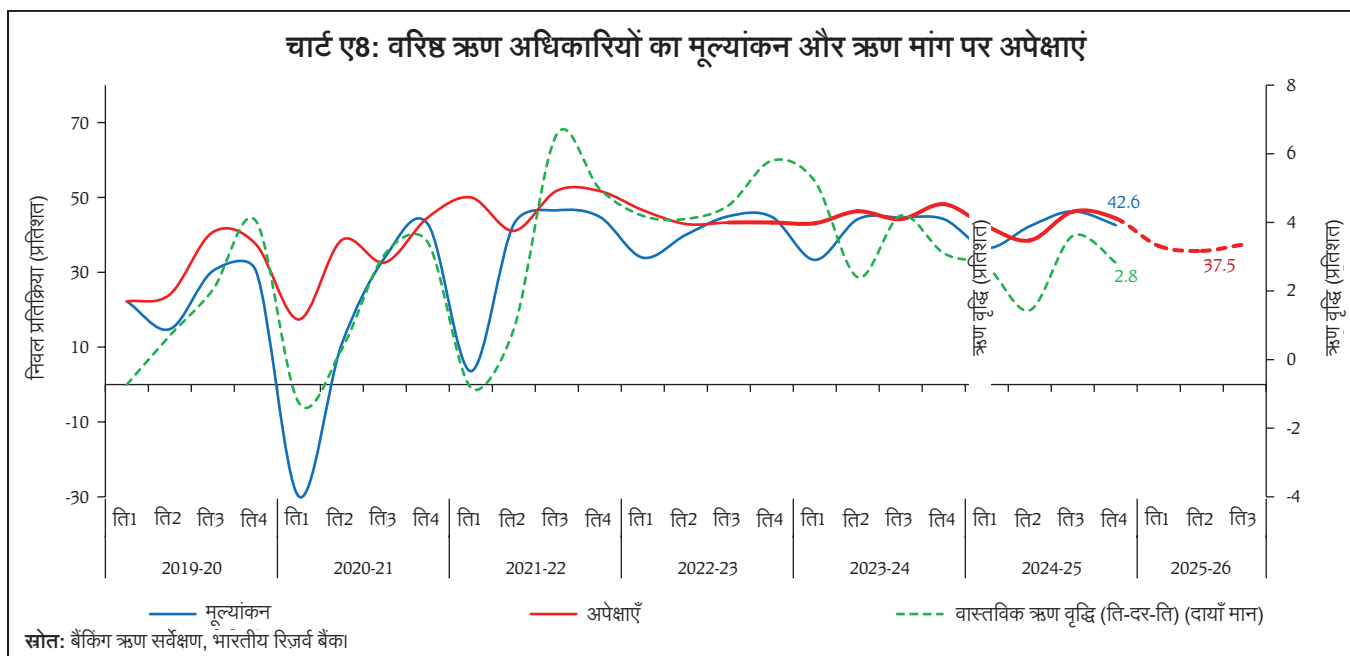
ति1: 2025-26 के दौरान सेवाओं और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों के लिए इनपुट लागत दबाव उच्च रहने की संभावना है; जबकि विनिर्माण क्षेत्र लागत दबावों में कुछ कमी की अपेक्षा करता है (चार्ट ए6)।



ति1: 2025-26 में बिक्री मूल्य और लाभ मार्जिन की वृद्धि कम मांग स्थितियों के अनुरूप विनिर्माण उद्यमों के लिए मध्यम होने की संभावना है। हालांकि, सेवा और अवसंरचना फर्म, इसी अवधि के दौरान बिक्री मूल्य और लाभ मार्जिन दोनों में बेहतर वृद्धि की उम्मीद करते हैं (चार्ट ए7)।



ऋण मांग पर बैंकों का आशावाद ति1:2025-26 के दौरान मध्यम हुआ (चार्ट ए8)।



टिप्पणी: 'निवल प्रतिक्रिया' की गणना आशावाद की रिपोर्ट करने वाले उत्तरदाताओं के प्रतिशत और निराशावाद की रिपोर्टिंग के बीच अंतर के रूप में की जाती है। वृद्धि विकल्प (I) लागत से संबंधित मापदंडों को छोड़कर, सभी मापदंडों के लिए एक आशावादी प्रतिक्रिया है, जैसे कच्चे माल की लागत, आदि, जहां कमी विकल्प (डी) एक प्रतिक्रिया कंपनी के दृष्टिकोण से आशावाद को दर्शाता है।

स्थायी जमा सुविधा के तीन वर्षः कुछ विचार

अवनीश कुमार, प्रियंका सचदेवा और इंद्रनील भट्टाचार्य[^]

अपनी शुरुआत के तीन साल पूरे होने पर, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) भारतीय रिज़र्व बैंक के चलनिधि प्रबंधन ढांचे की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है, जिसने एलएएफ कॉरिडोर के तल के रूप में निश्चित दर रिवर्स रेपो की जगह ली है। यह आलेख केंद्रीय बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई स्थायी सुविधाओं के समग्र संदर्भ में भारत में एसडीएफ का मूल्यांकन करता है। एसडीएफ की स्थापना आम तौर पर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है, जिसमें जमा सुविधाएं असंपार्श्विक जमा के रूप में होती हैं। साक्ष्यजन्य परिणाम एलएएफ कॉरिडोर में डब्ल्यूएसीआर के स्थान का निर्धारण करने में चलनिधि की स्थिति, चलनिधि अनिश्चितता और बाजार सूक्ष्म संरचना के महत्व की पुष्टि करते हैं।

परिचय

चलनिधि प्रबंधन संचालन और अभ्यास, मौद्रिक नीति के संचालन के मूल में हैं - «इसकी वास्तुकला में प्लंबिंग» (पात्र और अन्य, 2016)। केंद्रीय बैंकिंग की भाषा में, मौद्रिक नीति की संचालन प्रक्रिया का तात्पर्य उचित चलनिधि प्रबंधन संचालन के माध्यम से मौद्रिक नीति के दैनिक कार्यान्वयन से है। परिचालन ढांचे में परिचालन लक्ष्य और वे उपकरण शामिल हैं जिनका उपयोग केंद्रीय बैंक नीति दर के साथ परिचालन लक्ष्य को संरेखित करने के अपने उद्देश्य के अनुसरण में बैंक रिज़र्व के लिए अंतर-बैंक बाजार में चलनिधि की स्थिति का प्रबंधन करने के लिए करता है। इन उपकरणों में शामिल हैं (i) स्थायी सुविधाएँ - उधार और जमा दोनों सुविधाएँ - जिनका उपयोग

[^] लेखक भारतीय रिज़र्व बैंक से हैं। वे टिप्पणियों के लिए एक अनाम रेफरी और डेटा समर्थन के लिए दर्शन पी. बोधले के आभारी हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

वाणिज्यिक बैंक अपने विवेक से कर सकते हैं; (ii) खुले बाजार संचालन (ओएमओ) - पुनर्खरीद अनुबंधों के माध्यम से एकमुश्त और प्रतिवर्ती दोनों का संचालन - जो केंद्रीय बैंक के विवेक पर संचालित होते हैं; और (iii) केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम आरक्षित आवश्यकताएँ और साथ ही इसकी रखरखाव प्रक्रिया।

भारतीय संदर्भ में, भारित औसत कॉल मनी दर (डब्ल्यूएसीआर), जो मुद्रा बाजार के असंपार्श्विक खंड की दर है और बैंकिंग प्रणाली में चलनिधि बेमेल को दर्शाती है, मई 2011 में संस्थागत ब्याज दर कॉरिडोर ढांचे में परिचालन लक्ष्य है (आरबीआई, 2011)। इस ढांचे के तहत, बैंक सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के माध्यम से संपार्श्विक गिरवी रखकर रात भर के आधार पर नीति दर से अधिक दंडात्मक दर पर केंद्रीय बैंक से चलनिधि प्राप्त कर सकते हैं, जबकि वे फिक्स्ड रेट रिवर्स रेपो (एफआरआरआर) के तहत संपार्श्विक के खिलाफ नीति दर से कम दर पर रात भर के आधार पर केंद्रीय बैंक के पास धन रख सकते हैं। इस प्रकार, चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत इन दोनों सुविधाओं पर ब्याज दरों ने ब्याज दर कॉरिडोर को परिभाषित किया, जिसमें एमएसएफ दर छत के रूप में, एफआरआरआर को फ्लोर के रूप में और पॉलिसी रेपो दर कहीं बीच में थी। यह ढांचा 8 अप्रैल, 2022 तक चालू था, जब स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) ने एलएएफ कॉरिडोर के फ्लोर के रूप में एफआरआरआर को बदल दिया। हालांकि, एफआरआरआर के विपरीत, एसडीएफ एक असंपार्श्विक सुविधा है जो केंद्रीय बैंक को संपार्श्विक भार से मुक्त करती है और इस प्रकार चलनिधि प्रबंधन में इसकी लचीलापन बढ़ाती है।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) द्वारा नीति रेपो दर की घोषणा किए जाने के बाद, डब्ल्यूएसीआर को नीति रेपो दर के अनुरूप बनाने के लिए चलनिधि प्रबंधन संचालन किए जाते हैं। मुख्य चलनिधि प्रबंधन संचालन को रिज़र्व रखरखाव चक्र के साथ समन्वयित किया जाता है। इसके अलावा, अस्थायी चलनिधि बेमेल को ऑफसेट करने और डब्ल्यूएसीआर को नीति दर के करीब स्थिर करने के लिए रिज़र्व बैंक के विवेक पर

फाइन ट्यूनिंग संचालन किए जाते हैं। मौद्रिक नीति कार्यान्वयन में चलनिधि प्रबंधन के महत्वपूर्ण महत्व को देखते हुए, एसडीएफ की स्थापना के साथ परिचालन प्रक्रिया में बड़े सुधार किए गए हैं।

यह आलेख केंद्रीय बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई गई स्थायी सुविधाओं के समग्र संदर्भ में भारत में स्थायी जमा सुविधा का मूल्यांकन प्रस्तुत करता है। इस आलेख की संरचना इस प्रकार है: खंड II में केंद्रीय बैंकों की स्थायी सुविधाओं पर वैश्विक प्रथाओं का एक स्नैपशॉट प्रस्तुत किया गया है, उसके बाद खंड III में एसडीएफ के साथ भारतीय अनुभव की चर्चा की गई है। साक्ष्यजन्य कार्यप्रणाली, परिणाम और उनके निहितार्थ खंड IV में प्रस्तुत किए गए हैं, तथा खंड V में कुछ निष्कर्षात्मक टिप्पणियां दी गई हैं।

II. केंद्रीय बैंक स्थायी सुविधाएं - वैश्विक प्रथाएं

परिचालन लक्ष्य में स्वीकार्य परिवर्तनशीलता के संदर्भ में, मौद्रिक नीति परिचालन ढाँचों को सीलिंग, कॉरिडोर या फ्लोर सिस्टम के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों ने आम तौर पर कॉरिडोर या फ्लोर सिस्टम को अपनाया है। क्रॉस कंट्री अनुभव से पता चलता है कि सभी प्रमुख केंद्रीय बैंकों के पास स्थायी सुविधाएँ हैं जो बैंकों और अन्य पात्र प्रतिपक्षों को रात भर की चलनिधि प्रदान करने या अवशोषित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के तहत अपनी पहल पर उपलब्ध हैं (बिंदसेइल, 2014)।

एक तरल अंतरबैंक बाजार और एक सुदृढ़ भुगतान और निपटान प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि बाजार संतुलन एक साथ व्यक्तिगत वित्तीय संस्थान स्तर पर संतुलन की ओर ले जाया जाता है, इस प्रकार स्थायी सुविधाओं का सहारा कम से कम होता है। ऐसे परिदृश्य में, एक केंद्रीय बैंक की ऋण सुविधा किसी भी दिन के अंत में असंतुलन को निधि देने के लिए एक ओवरड्राफ्ट सुविधा के रूप में कार्य करती है, जिसमें नियमित पुनर्वित्त संचालन (नीति दर) की तुलना में अधिक दंडात्मक दर वसूल कर नियमित पहुँच को हतोत्साहित किया जाता है। इसी तरह, जमा सुविधा पर कम ब्याज दर का उद्देश्य केंद्रीय बैंक के साथ निष्क्रिय निधियों की तैनाती को हतोत्साहित करना है; इसके बजाय, प्रतिभागियों को एक-दूसरे के साथ लेनदेन करना

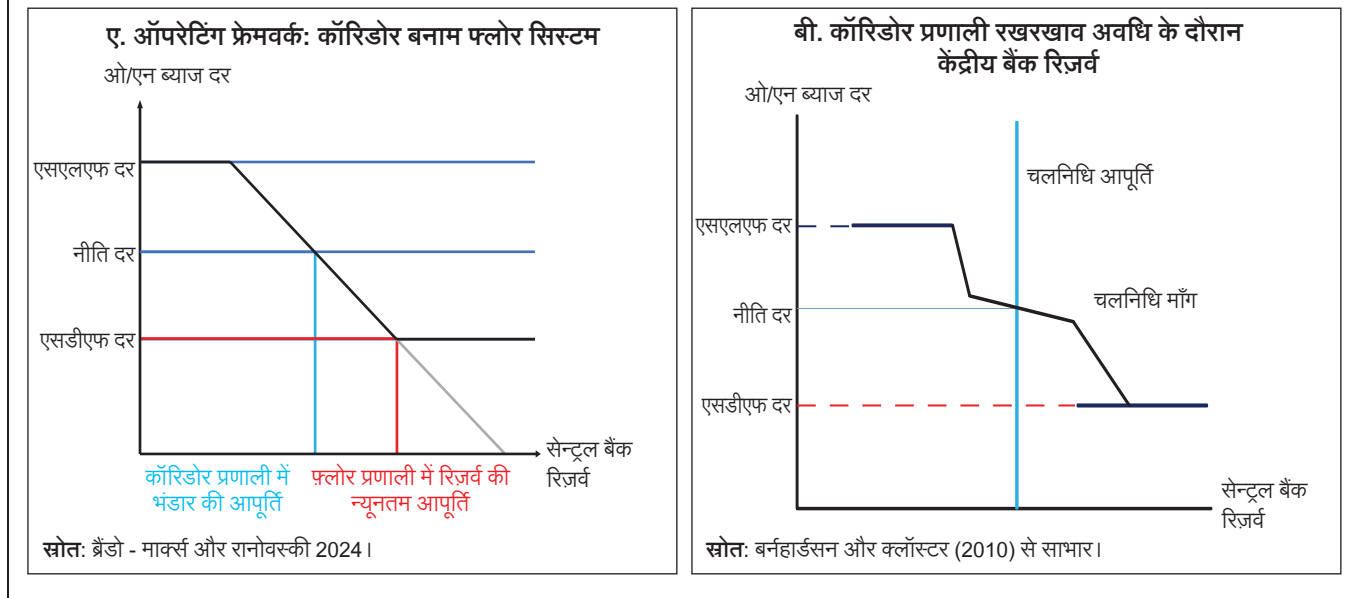
चाहिए जो एक तरल अंतर-बैंक बाजार विकसित करने में मदद करता है। दंडात्मक दरें सुनिश्चित करती हैं कि स्थायी सुविधाएँ चलनिधि प्रबंधन के लिए एक सुरक्षा वाल्व के रूप में कार्य करती हैं (मोहन, 2006)।

चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत स्थायी सुविधाओं पर ब्याज दरें कॉरिडोर की रूपरेखा को परिभाषित करती हैं। नीति दर के दोनों ओर एक समान मार्जिन एक सममित कॉरिडोर का निर्माण करता है। एक गलियारा प्रणाली बैंकों को अपने चलनिधि बफर को अधिक सख्ती से प्रबंधित करने और अंतर-बैंक बाजार में अधिक गतिविधि की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि मुद्रा बाजार दरें नीति दर के करीब रहें, इसके लिए अपेक्षाकृत अधिक लगातार केंद्रीय बैंक संचालन की आवश्यकता होती है। वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी) के बाद से बड़ी और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक फ़्लोर सिस्टम आदर्श रहा है। इस प्रणाली के तहत, केंद्रीय बैंक चलनिधि संचालन के माध्यम से प्रचुर मात्रा में भंडार की आपूर्ति करते हैं, और जमा सुविधा के माध्यम से भंडार (ब्याज दर) की कीमत के लिए एक फ़्लोर प्रदान करते हैं। फ़्लोर सिस्टम का लाभ यह है कि केंद्रीय बैंक अल्पकालिक मुद्रा बाजार दरों को मुख्य दर से नीचे धकेले बिना बैंकिंग प्रणाली को चलनिधि की आपूर्ति बढ़ा सकता है (ब्रैंडाओ-माक्स और रत्नोवस्की, 2024)। इस प्रकार, केंद्रीय बैंक के पास दो स्वतंत्र उपकरण हैं - ब्याज दर और आपूर्ति की गई चलनिधि की मात्रा (चार्ट 1.ए)।

हालांकि, आंशिक रिज़र्व प्रणाली में, रिज़र्व आवश्यकताएँ रिज़र्व रखरखाव के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के आधार पर चलनिधि को ठीक करने की आवश्यकता की जांच कर सकती हैं। यदि बैंकों को रिज़र्व औसत के अधीन किया जाता है, यानी, वे रखरखाव अवधि के दौरान रखरखाव को न्यूनतम दैनिक औसत स्तर तक कम कर सकते हैं, तो बैंक रिज़र्व के लिए मांग वक्र कॉरिडोर के मध्य के पास ब्याज दरों के लिए सपाट हो जाता है (चार्ट 1.बी)।

उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में, यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी), बैंक ऑफ कनाडा (बीओसी), रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड

चार्ट 1: चलनिधि प्रबंधन की परिचालन प्रक्रिया



(आरबीएनजेड) और रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया (आरबीए) वर्ष 2000 के आसपास सममित गलियारा प्रणाली के अग्रदूत थे। जहां ईसीबी ने अपनी स्थायी जमा सुविधा को एक महीने की आरक्षित रखरखाव अवधि के साथ जोड़ा, वहीं अन्य तीन केंद्रीय बैंक बिना आरक्षित औसत के संचालित हुए (व्हाइटसेल, 2006)। नॉर्जेस बैंक ने अक्टूबर 2011 तक फ्लोर सिस्टम के अपेक्षाकृत निवल संस्करण के माध्यम से मौद्रिक नीति को लागू किया; उसके बाद, यह कोटा-आधारित प्रणाली में स्थानांतरित हो गया - फ्लोर सिस्टम और कॉरिडोर सिस्टम¹ के बीच एक समझौता। बैंक ऑफ कनाडा (बीओसी) और रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड (आरबीएनजेड) जैसे केंद्रीय बैंकों ने 2020 में फ्लोर सिस्टम को अपनाया एक है रिजर्व बैलेंस पर ब्याज, जो बैंकों या अन्य पात्र प्रतिपक्षों के रिजर्व बैलेंस पर दी जाने वाली दर है। दूसरी है ओवरनाइट रिवर्स रेपो सुविधा पर मिलने वाली दर जो कई वित्तीय संस्थानों को दी जाती है (अफोसो और अन्य, 2023)।

¹ नई व्यवस्था के तहत, केंद्रीय बैंक के पास प्रत्येक बैंक की जमा राशि की केवल एक निश्चित राशि - एक कोटा - को मुख्य नीति दर पर पारिश्रमिक दिया जाता है। कोटा से अधिक जमा राशि पर कम दर, आरक्षित दर पर पारिश्रमिक दिया जाता है।

हाल के समय में, हालांकि, बीओसी, बैंक ऑफ इंग्लैंड (बीओई), ईसीबी और आरबीए सभी ने तब तक भंडार कम करने की योजना की घोषणा की है जब तक कि केंद्रीय बैंक से उधारी नहीं बढ़ जाती और बाजार दरें केंद्रीय बैंक द्वारा जमा पर भुगतान की जाने वाली ब्याज दर से थोड़ी अधिक नहीं हो जाती, अनिवार्य रूप से एक गलियारा प्रणाली की ओर लौटना, हालांकि वे इसे «कॉरिडोर» नहीं कहते हैं (नेल्सन, 2024)। एक संकीर्ण प्रसार के साथ नए «नरम» तल ढांचे को एक संकर प्रणाली के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो संरचनात्मक और ठीक-ठीक संचालन दोनों के साथ सबसे छोटी संभव केंद्रीय बैंक बैलेंस शीट को जोड़ता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रचुर अतिरिक्त चलनिधि की स्थिति से कम पर्याप्त चलनिधि की स्थिति में संक्रमण में अल्पकालिक मुद्रा बाजार दरों के प्रभावी नियंत्रण की अनुमति देना है अल्पावधि मुद्रा बाजार दर में उच्च अस्थिरता से बचने के लिए, हाइब्रिड सिस्टम जमा सुविधा को स्थायी उधार सुविधा या लगातार निश्चित दर पूर्ण-आबंधन उधार संचालन के साथ पूरक बनाता है, जिसकी कीमत जमा सुविधा दर पर या उससे थोड़ी अधिक होती है, जो ऊपर से मुद्रा बाजार ब्याज दर को सीमित करती है और इस तरह ढांचे

को शून्य-चौड़ाई या लगभग शून्य-चौड़ाई वाला गलियारा बनाती है। आरबीए ने पर्याप्त भंडार प्रणाली में जाने की योजना का समर्थन किया है जिसमें बैंकों की भंडार की मांग को खुले बाजार रेपो संचालन के माध्यम से नकद दर लक्ष्य के करीब की कीमत पर संतुष्ट किया जाता है, जिसे पूर्ण आवंटन नीलामी के रूप में जाना जाता है। एक्सचेंज सेटलमेंट (ईएस) दर द्वारा प्रदान की गई मंजिल के साथ, इन परिचालनों को नकद दर को लक्ष्य² के करीब रखना चाहिए।

ऐतिहासिक रूप से, केंद्रीय बैंक केवल चलनिधि प्रदान करने वाली सुविधा का ही उपयोग करते थे - या तो छूट या अग्रिम सुविधा। हालाँकि, केंद्रीय बैंकों ने 1990 के दशक के अंत में चलनिधि अवशोषण सुविधाओं को शुरू किया (बिंडसेइल और जेबलेकी, 2011)। केंद्रीय बैंक आम तौर पर वित्तीय संस्थानों को संपार्श्विक लेनदेन के माध्यम से उधार देते हैं, यानी, खुद को क्रेडिट जोखिम से बचाने और प्रतिपक्षियों के समान उपचार सुनिश्चित करने के लिए पुनर्खरीद समझौते (चाइलौक्स और अन्य, 2008)। प्रतिपक्षियों को उधार देते समय, केंद्रीय बैंक (i) उन प्रतिभूतियों को निर्दिष्ट करके जोखिम की सीमा के बारे में स्पष्ट होता है जिसे वह संपार्श्विक के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार है; और (ii) इन प्रतिभूतियों पर वह हेयरकट/मार्जिन जो वह चार्ज करेगा। यह अभ्यास वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के अलावा केंद्रीय बैंक की बैलेंस शीट की गुणवत्ता की रक्षा करता है। केंद्रीय बैंकों को कभी भी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता है जहाँ वे डिफॉल्ट करते हैं - इस प्रकार, बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास धन जमा करते समय कोई प्रतिपक्ष जोखिम नहीं होता है। हालाँकि, एक केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों के लिए बाजार बनाने के लिए बिक्री या रिवर्स रीपरचेज अनुबंधों के माध्यम से संपार्श्विक के रूप में सुरक्षा प्रदान करना चुन सकता है (नियम, 2012)।

III. भारत में स्थायी जमा सुविधा

भारतीय संदर्भ में, मौद्रिक नीति ढांचे को संशोधित करने और उसे मजबूत बनाने के लिए विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) की पहली बार सिफारिश की गई थी (अध्यक्ष: डॉ. उर्जित आर. पटेल, 2014) मौद्रिक नीति के परिचालन ढांचे के ओवरहाल के हिस्से के रूप में।

² क्रिस्टोफर केंट (2024), 'मौद्रिक नीति कार्यान्वयन के लिए भविष्य की प्रणाली', ब्लूमबर्ग ऑस्ट्रेलिया ब्रीफिंग। भाषण <https://www.rba.gov.au/speeches/2024/sp-ag-2024-04-02.html> से लिया गया।

समिति ने सिफारिश की कि सिस्टम से अधिशेष चलनिधि के अवशोषण के लिए एक (कम) पारिश्रमिक वाले एसडीएफ को पेश किया जा सकता है, लेकिन बदले में संपार्श्विक प्रदान करने की आवश्यकता के बिना, नीति लक्ष्य दर के संदर्भ के बिना ब्याज दर निर्धारित करने के विवेक के साथ। एसडीएफ को स्ट्रलाइजेशन ऑपरेशन के लिए भी इस्तेमाल करने का प्रस्ताव था क्योंकि इसमें अवशोषण के लिए संपार्श्विक के प्रावधान की आवश्यकता नहीं होगी - जो पूंजी प्रवाह में निरंतर उछाल के सामने रिवर्स रेपो सुविधा पर एक बाध्यकारी बाधा हो सकती है (आरबीआई, 2014)। वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोटों को संचलन से हटा दिया गया और इसके परिणामस्वरूप चलनिधि की अधिकता ने पारंपरिक साधनों से जुड़ी संपार्श्विक बाधाओं को भी प्रदर्शित किया, जिसके कारण बैंकिंग प्रणाली से बड़ी मात्रा में अधिशेष चलनिधि को निकालने के लिए निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) में वृद्धि पर 100 प्रतिशत की वृद्धिशील नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) लगाने और बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) के तहत बांड जारी करने जैसे अपरंपरागत उपायों की शुरुआत की आवश्यकता थी। ऐसे विकल्पों की अनुपस्थिति में, प्रचुर मात्रा में चलनिधि के बीच अंतर-बैंक दरों के शून्य स्तर तक गिरने का जोखिम है, जो वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम पैदा करता है।

आरबीआई अधिनियम की धारा 17 में संशोधन ने रिजर्व बैंक को एसडीएफ को संस्थागत बनाने में सक्षम बनाया। एसडीएफ को अप्रैल 2022 में पेश किया गया और इसने एलएफ कॉरिडोर के फ्लोर के रूप में एफआरआरआर को प्रतिस्थापित किया। एसडीएफ की स्थापना के साथ, 3.35 प्रतिशत पर बनाए रखा गया एफआरआरआर, पॉलिसी रेपो दर से अलग हो गया, हालाँकि यह रिजर्व बैंक के टूलकिट का हिस्सा बना हुआ है और इसका इस्तेमाल उसके विवेक पर किया जा सकता है। एसडीएफ दर, जो बिना संपार्श्विक रातोंरात जमा पर लागू होती है, पॉलिसी रेपो दर से 25 आधार अंक (बीपीएस) नीचे निर्धारित की गई थी। इसने, रेपो दर से 25 बीपीएस ऊपर एमएसएफ दर के साथ, एलएफ कॉरिडोर की चौड़ाई को 50 बीपीएस के अपने पूर्व-महामारी स्तर पर बहाल कर दिया। इस प्रकार, एलएफ कॉरिडोर के दोनों सिरों पर स्थायी सुविधाएँ

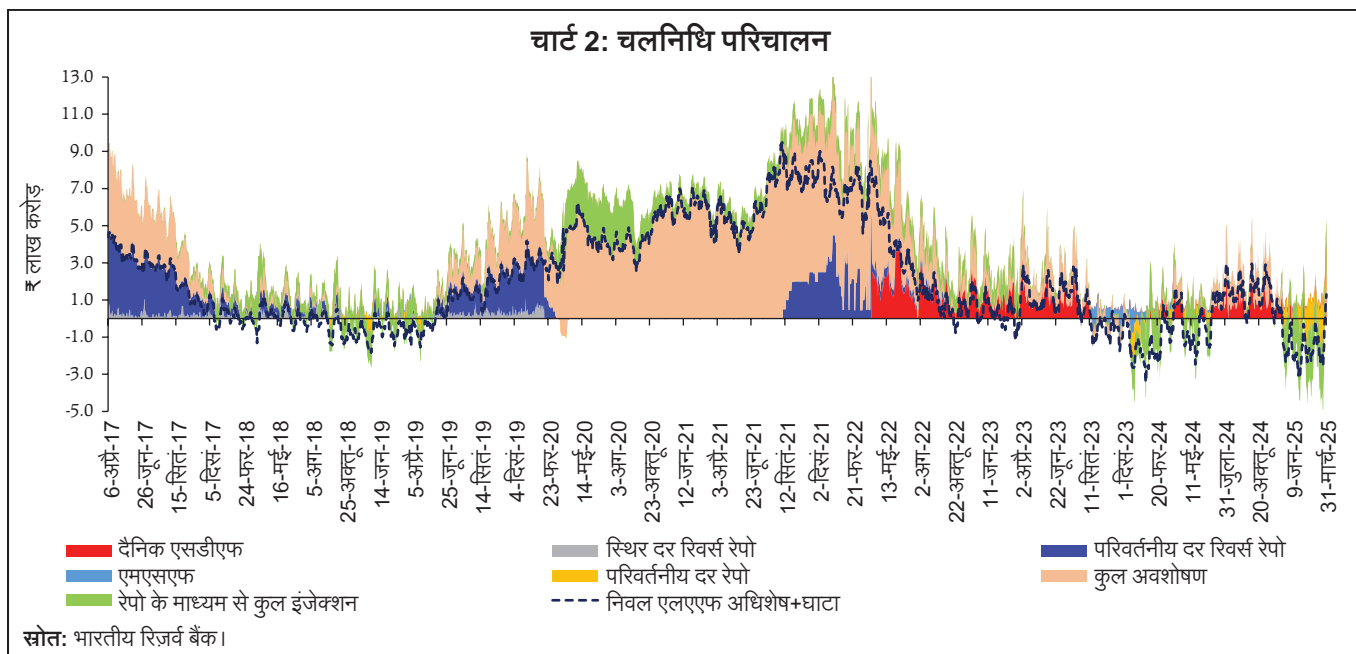
³ केंद्रीय बजट 19-2018 में आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 17 में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था, जो भारतीय रिजर्व बैंक को चलनिधि प्रबंधन के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर केंद्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित स्थायी जमा सुविधा योजना के तहत बैंकों या किसी अन्य व्यक्ति से ब्याज के साथ चुकाने योग्य जमा के रूप में धन स्वीकार करने की अनुमति देता है।

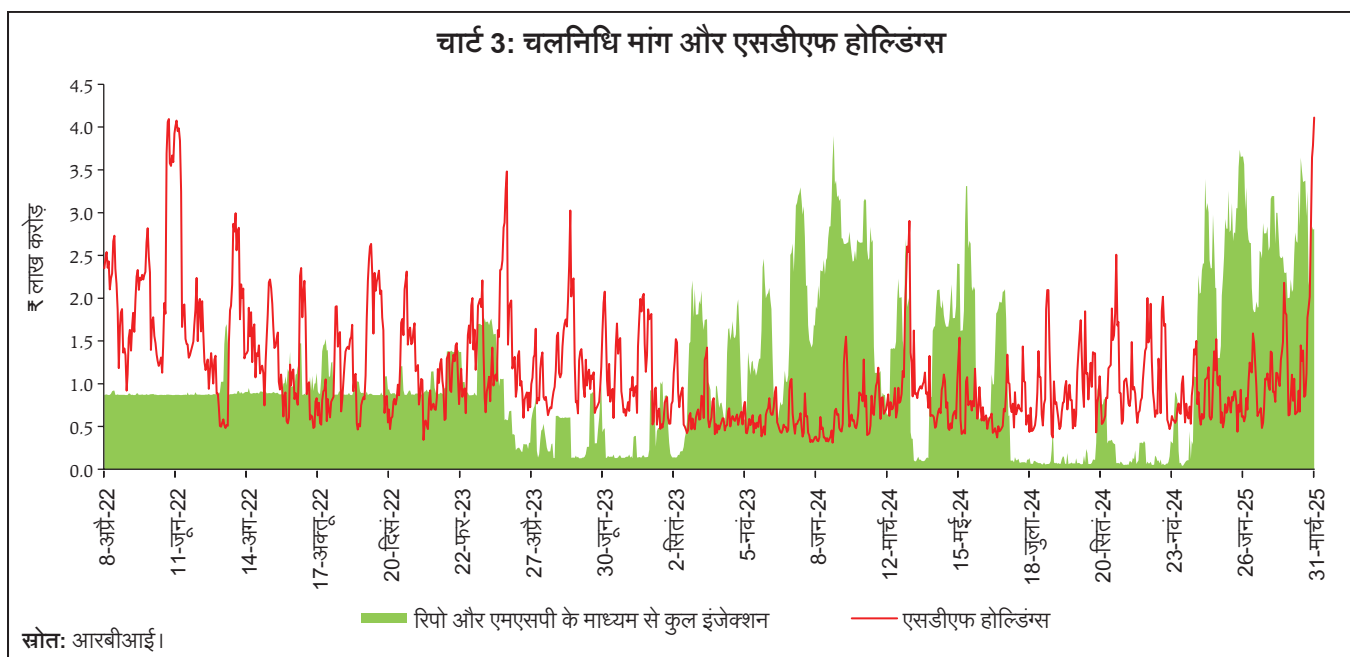
स्थापित की गई - एक को अवशोषित करने के लिए और दूसरी को चलनिधि को इंजेक्ट करने के लिए, जिससे परिचालन ढांचा सममित हो गया। इसके अलावा, पुनर्खरीद लेनदेन, एकमुश्त ओएमओ और सीआरआर के विपरीत, एसडीएफ और एमएसएफ तक पहुंच बैंकों के विवेक पर है, जो रिजर्व बैंक के विवेक पर संचालित होते हैं। इसके अलावा, आरबीआई ने एसडीएफ के तहत उचित मूल्य निर्धारण के साथ लंबी अवधि के लिए चलनिधि को अवशोषित करने की लचीलापन बरकरार रखा है, जब भी जरूरत होती है। बाध्यकारी संपार्श्विक बाधा को हटाकर जो केंद्रीय बैंक के चलनिधि प्रबंधन कार्यों को बाधित कर सकता था, एसडीएफ ने मौद्रिक नीति के परिचालन ढांचे को मजबूत किया है। यह रातोंरात अंतर-बैंक बाजार दरों के लिए एक मंजिल प्रदान करके वित्तीय स्थिरता उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। एसडीएफ की संस्था आम तौर पर वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है जिसमें जमा सुविधाएं असुरक्षित जमा के रूप में होती हैं।

कोविड19- के बाद, रिजर्व बैंक ने वास्तविक अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों नीति उपायों के माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में पर्याप्त चलनिधि डाली। मार्च 2020 से जनवरी 2021 के दौरान ओवरनाइट एफआरआरआर के माध्यम से अधिशेष को पूरी तरह से हटा दिया गया। इसके बाद, जनवरी 2021 में सामान्य चलनिधि संचालन फिर से शुरू होने पर, अधिशेष चलनिधि का

बड़ा हिस्सा विभिन्न आकारों और अवधियों के परिवर्तनीय दर रिवर्स रेपो (वीआरआरआर) फाइन ट्यूनिंग संचालन के माध्यम से अवशोषित किया गया। चलनिधि की अधिकता और उसके बाद आवश्यक सामान्यीकरण ने अप्रैल 2022 में एसडीएफ की शुरुआत के लिए एक उपयुक्त समय प्रदान किया। तब से, अधिशेष चलनिधि को बड़े पैमाने पर एसडीएफ के माध्यम से हटा दिया गया है, जबकि वीआरआरआर संचालन के माध्यम से अवशोषण की हिस्सेदारी घट रही है। मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव के साथ समायोजन को वापस लेने के साथ -2022 23 में अधिशेष चलनिधि की स्थिति कम हो गई। बैंकों द्वारा एमएसएफ का अधिक सहारा लेने तथा साथ ही एसडीएफ के तहत बड़ी अधिशेष निधि जमा करने को ध्यान में रखते हुए, एसडीएफ तथा एमएसएफ दोनों के तहत चलनिधि सुविधाओं को सप्ताहांत तथा छुट्टियों के दौरान भी वापस लेने की अनुमति दी गई, जो 30 दिसंबर, 2023 से प्रभावी है, जिससे बैंकों को अपने परिचालन में अधिक लचीलापन प्राप्त हुआ। अप्रैल 2022 से मार्च 2025 तक 1.7९ लाख करोड़ के औसत चलनिधि अवशोषण में से लगभग 65 प्रतिशत एसडीएफ के माध्यम से था, जबकि शेष वीआरआरआर नीलामी के माध्यम से प्राप्त किया गया था, जबकि 7 अप्रैल, 2017 से 20 मार्च, 2020 के दौरान एफआरआरआर के तहत केवल 16 प्रतिशत अवशोषित किया गया था (चार्ट 2)।

एसडीएफ के तहत पर्याप्त निधि प्लेसमेंट के साथ-साथ



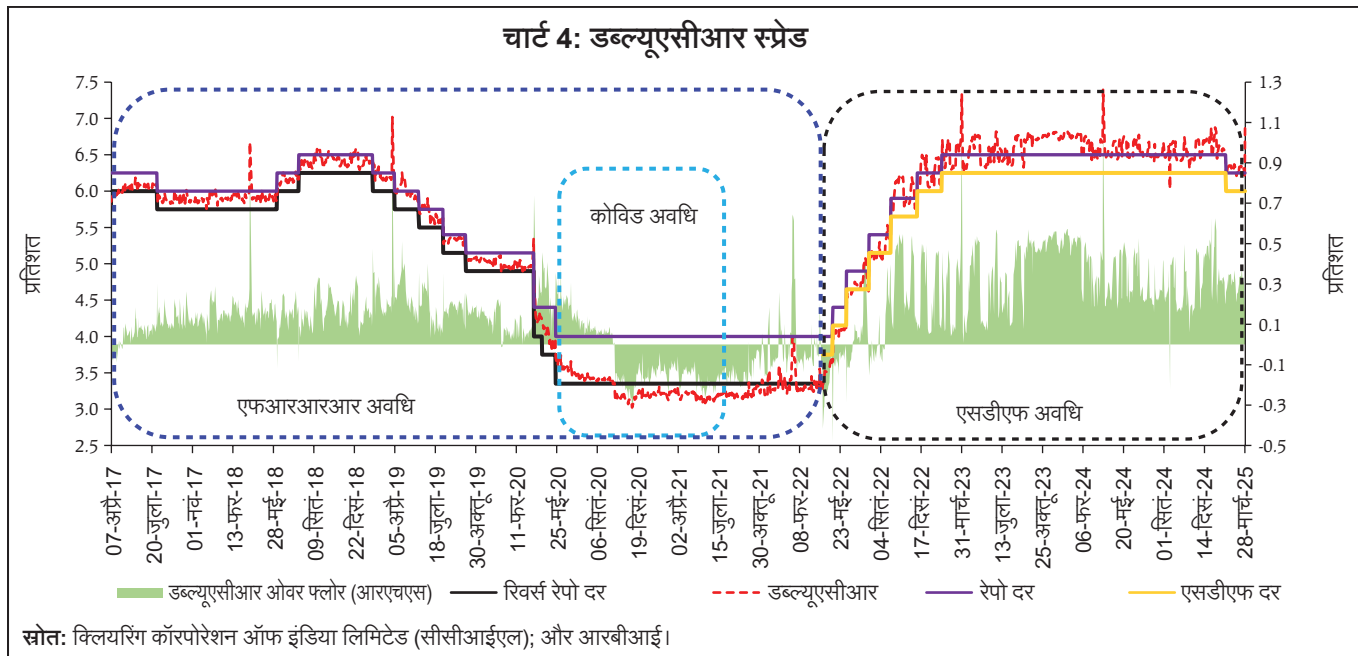


चलनिधि घाटे की स्थिति की एक साथ घटना बैंकिंग प्रणाली के भीतर चलनिधि के विषम वितरण और बैंकों की बढ़ती चलनिधि वरीयता का सुझाव देती है (चार्ट 3)। रिज़र्व बैंक द्वारा कुल अवशोषण के अनुपात के रूप में एसडीएफ शेष राशि के हिस्से में वृद्धि बैंकों द्वारा निधियों की एहतियाती मांग में वृद्धि को दर्शाती है। 24/7/365 भुगतान प्रणालियों के मद्देनजर उच्च चलनिधि बीमा की आवश्यकता की पृष्ठभूमि में, बैंकों को अपने दिन-प्रतिदिन के लेन-देन में अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि देर रात में उच्च मूल्य के लेन-देन के परिणामस्वरूप रिज़र्व रखरखाव में कमी हो सकती है। इसके अलावा, खजाने से अंतिम लाभार्थी को समय पर धनराशि जारी करने से बैंकों के पास पहले उपलब्ध फ्लोट मनी काफी कम हो गई है। इस प्रकार, हाल के वर्षों में बैंक प्रतिदिन बड़ी शेष राशि रखने को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो एसडीएफ चरण के साथ मेल खाता है। इसके परिणामस्वरूप बैंकों ने एलएएफ के तहत लंबी अवधि के वीआरआरआर संचालन के माध्यम से केंद्रीय बैंक के पास अधिशेष निधि पार्क करने में कम रुचि दिखाई है।

स्थायी सुविधा केंद्रीय बैंकों द्वारा परिचालन लक्ष्य के स्तर और अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक प्राथमिक उपकरण है। लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) को औपचारिक रूप से अपनाने के

बाद से, डब्ल्यूएसीआर ने कोविड अवधि को छोड़कर बड़े पैमाने पर कॉरिडोर के तल से ऊपर कारोबार किया। बड़े पूंजी प्रवाह के साथ-साथ कोविड-19 संबंधित उपायों के कारण चलनिधि की अधिकता ने डब्ल्यूएसीआर को एफआरआरआर (कॉरिडोर के लेयर) से नीचे धकेल दिया, जैसा कि एफआरआरआर के मुकाबले डब्ल्यूएसीआर के बड़े नकारात्मक प्रसार में परिलक्षित होता है। यह नकारात्मक प्रसार अप्रैल से अगस्त 2022 के दौरान एसडीएफ के कार्यान्वयन के बाद बना रहा, जिसमें जुलाई 2022 अपवाद रहा। इसके बाद, डब्ल्यूएसीआर धीरे-धीरे एसडीएफ दर से ऊपर चला गया (चार्ट 4)।

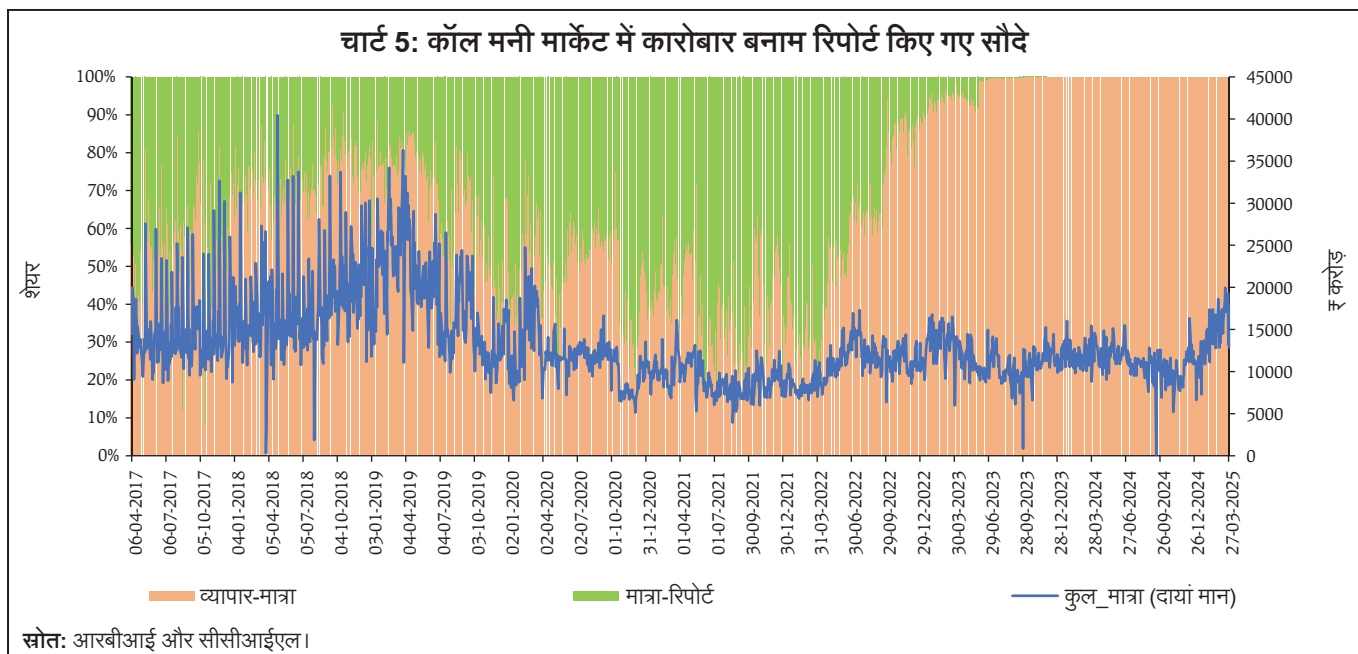
सिस्टम लिक्विडिटी और कॉरिडोर की चौड़ाई के अलावा, बाजार की सूक्ष्म संरचना और विनियामक सुझाव, डब्ल्यूएसीआर के स्तर और इसकी परिवर्तनशीलता को निर्धारित करते हैं। बैंकों में लिक्विडिटी का विषम वितरण मध्यस्थता के अवसरों को प्रोत्साहित कर सकता है जिसके परिणामस्वरूप डब्ल्यूएसीआर की कठोरता और प्रसार का विस्तार हो सकता है। इसके अलावा, सभी पात्र कॉल मनी प्रतिभागियों (सहकारी बैंकों सहित) को नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम-कॉल (एनडीएस-कॉल) सदस्यता प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक के निर्देश के संबंध में विनियामक विकास के परिणामस्वरूप प्रतिभागियों का एनडीएस-कॉल प्लेटफॉर्म की ओर पलायन हुआ है - इस प्रकार



ट्रेडेड डील में वृद्धि हुई है। कॉल मनी मार्केट लेनदेन या तो एनडीएस-कॉल पर ट्रेड किए गए थे या काउंटर (ओटीसी) पर ट्रेड किए जाने के बाद एनडीएस-कॉल पर रिपोर्ट किए गए थे। ट्रेडेड वॉल्यूम का हिस्सा जो 2020-22 के दौरान घट गया था, तब से धीरे-धीरे बढ़ गया है और अक्टूबर 2023 से सभी लेनदेन ट्रेडेड सेगमेंट में हो रहे हैं (चार्ट 5)। इससे पहले, रिपोर्ट किए गए सौदों पर कम दर के कारण डब्ल्यूएसीआर को अनुपातहीन रूप

से नीचे खींच लिया गया था, क्योंकि छोटे सहकारी बैंक - रिपोर्ट किए गए सौदों में प्रमुख ऋणदाता और जिनके पास एनडीएस-कॉल तक पहुंचने के लिए अपेक्षित सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) बुनियादी ढांचा नहीं था - आमतौर पर बाजार के समय के करीब कम दरों पर द्विपक्षीय रूप से ऋण देते थे।

इसके अलावा, कॉल मनी मार्केट में मार्केट टाइमिंग की बहाली और सामंजस्य ने बाजार की विसंगति को दूर किया



जिससे रिपोर्ट किए गए सौदे कम हुए और ट्रेड किए गए सौदे बढ़े। कोविड19- द्वारा उत्पन्न परिचालन अव्यवस्थाओं और स्वास्थ्य जोखिमों के उच्च स्तर को देखते हुए रिज़र्व बैंक द्वारा विनियमित विभिन्न बाजारों के लिए ट्रेडिंग घंटों में 7 अप्रैल, 2020 से संशोधन किया गया था। चलनिधि की अधिकता की अवधि के दौरान, बैंक सहकारी बैंकों से बेहद कम दरों पर धन उधार ले सकते थे और उन्हें एफआरआरआर/एसडीएफ विंडो के तहत उच्च दरों पर रख सकते थे। रिज़र्व बैंक ने नवंबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से बाजार के घंटों को बहाल किया⁴।

IV. साक्ष्यजन्य विश्लेषण

जैसा कि पहले बताया गया है, डब्ल्यूएसीआर के स्तर को निर्धारित करने में कई कारक भूमिका निभाते हैं, और इस प्रकार एलएएफ कॉरिडोर के फ़्लोर पर इसका प्रसार होता है। यह खंड 8 अप्रैल 2022 से 28 मार्च 2025 की अवधि के दौरान दैनिक डेटा के आधार पर एसडीएफ पर डब्ल्यूएसीआर प्रसार के निर्धारकों का आकलन करने का प्रयास करता है, और इसे कॉरिडोर की चौड़ाई (50 बीपीएस) की समान विशेषता के साथ एफआरआरआर अवधि के साथ बेंचमार्क करता है, यानी 6 अप्रैल 2017 से 20 मार्च 2020 तक।⁵ दोनों व्यवस्थाओं के तहत एलएएफ कॉरिडोर के फ़्लोर पर कॉल दर के प्रसार के निर्धारकों की जांच करने के लिए एक साक्ष्यजन्य विश्लेषण किया गया है, जो कि चलनिधि को प्रभावित करने वाले कारकों के साथ-साथ बाजार सूक्ष्म संरचना के तत्वों द्वारा निर्धारित होता है। मौजूदा साहित्य (कुमार, और अन्य, 2017; प्रभु और भट्टाचार्य, 2023) के आधार पर, चलनिधि की स्थिति (LIQ_Cond), चलनिधि वितरण (LIQ_Dist) और चलनिधि अनिश्चितता (LIQ_Unc) के साथ-साथ असंपार्श्विक बाजार में कुल सौदों में कारोबार के अनुपात (TRDtoTot) को स्वतंत्र चर के रूप में शामिल किया गया था।

चलनिधि की स्थिति को बैंकिंग प्रणाली की निवल मांग

⁴ आरबीआई द्वारा बाजार में कारोबार के घंटे बढ़ाने पर 8 फरवरी, 2023 की प्रेस विज्ञप्ति; https://rbi.org.in/Scripts/BS_PressReleaseDisplay.aspx?prid=55180

⁵ साक्ष्यजन्य विश्लेषण में, एफआरआरआर अवधि के लिए नमूने में 20 मार्च, 2020 के बाद की अवधि शामिल नहीं है, क्योंकि विभिन्न पारंपरिक और अपरंपरागत उपायों के माध्यम से कोविड19- प्रेरित प्रोत्साहन के कारण चलनिधि की अधिकता है। नमूने से कोविड अवधि को बाहर रखने से साक्ष्यजन्य विश्लेषण के लिए विचार की गई दोनों समय अवधि के लिए निश्चित चौड़ाई वाले कॉरिडोर का भी ध्यान रखा जाता है।

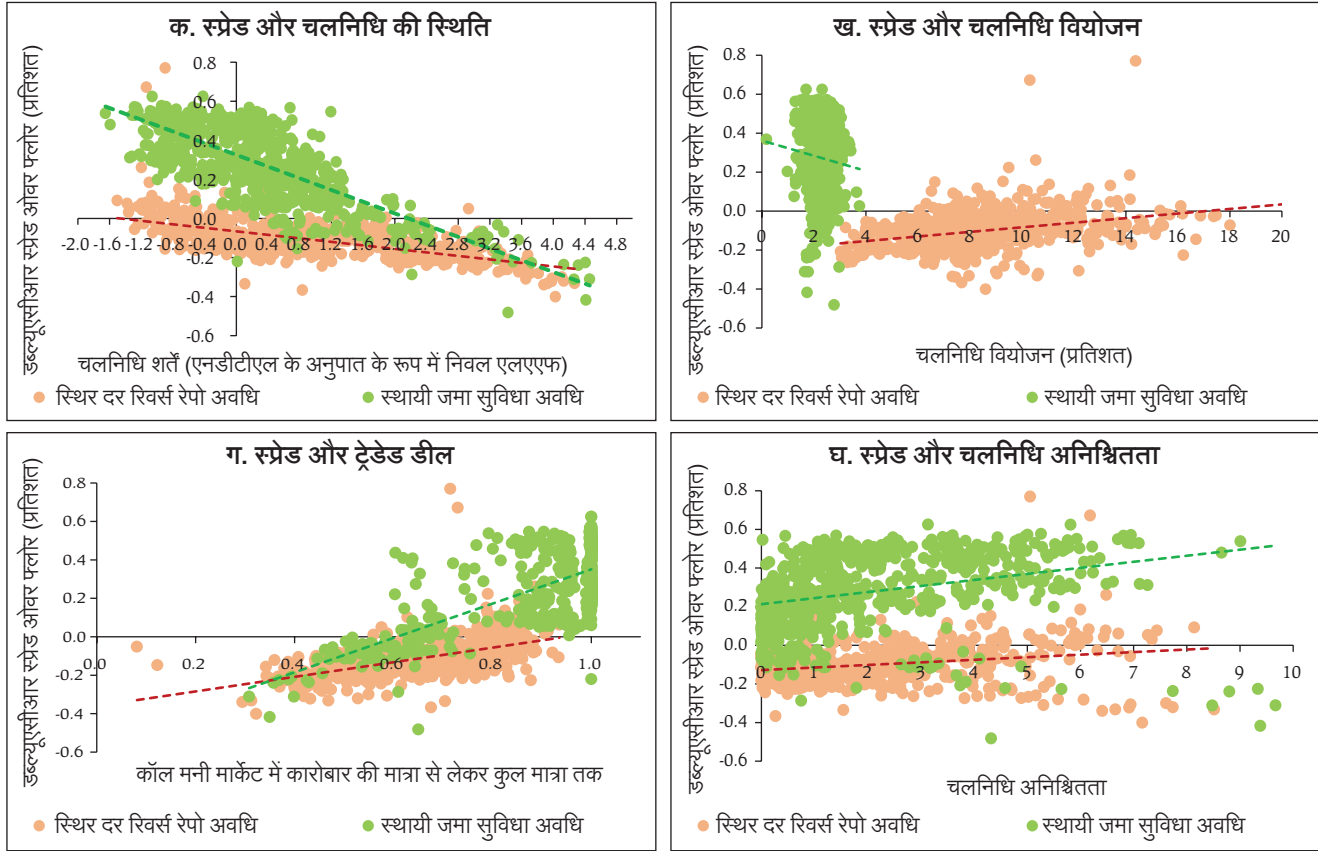
⁶ वीआरआरआर और एसडीएफ के माध्यम से चलनिधि के कुल अवशोषण के रूप में परिभाषित, रेपो और एमएसएफ के माध्यम से इंजेक्शन के निवल।

और समय देयताओं (एनडीटीएल) के अनुपात के रूप में दैनिक निवल एलएएफ स्थिति⁶ के रूप में परिभाषित किया गया है। एलएएफ परिचालनों का लक्ष्य प्रणाली में क्षणिक/घर्षण चलनिधि बेमेल को संबोधित करना है। प्रणालीगत चलनिधि घाटे के दौरान, पर्याप्त संपार्श्विक वाले बैंक रिज़र्व बैंक से चलनिधि प्राप्त कर सकते हैं। इसके विपरीत, आसान चलनिधि की स्थिति के परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक से चलनिधि का कम सहारा मिलता है। एनडीटीएल के लिए सकारात्मक निवल एलएएफ का अर्थ है बैंकिंग प्रणाली के भीतर अधिशेष चलनिधि और इसके विपरीत। इस अनुपात में वृद्धि से डब्ल्यूएसीआर और एसडीएफ दर पर इसका प्रसार कम हो जाएगा। चलनिधि वितरण एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि चलनिधि के विषम वितरण के परिणामस्वरूप प्रणालीगत दृष्टिकोण से कॉल मनी बाजार पर अधिक निर्भरता होने की संभावना है इस अभ्यास में, ओवरनाइट मनी मार्केट की कुल मात्रा के अनुपात के रूप में असंपार्श्विक अंतर-बैंक कॉल मनी मार्केट वॉल्यूम के अनुपात द्वारा चलनिधि वितरण का अनुमान लगाया जाता है। एसडीएफ अवधि के दौरान निवल एलएएफ के औसत विचलन के वर्ग के रूप में कैप्चर की गई चलनिधि अनिश्चितता, डब्ल्यूएसीआर को मजबूत करती है, जिससे एसडीएफ दर पर इसका प्रसार बढ़ जाता है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, कुल सौदों में कारोबार का हिस्सा भी प्रसार को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की उम्मीद है। दोनों नमूना अवधियों के लिए चयनित चर के सारांश आँकड़े अनुलग्नक सारणी 2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

आरंभ में, आश्रित और व्याख्यात्मक चरों के बीच संबंधों के प्रारंभिक मूल्यांकन के लिए स्कैटर प्लॉट प्रस्तुत किए गए हैं। स्कैटर प्लॉट दिखाते हैं कि डब्ल्यूएसीआर का प्रसार एसडीएफ और एफआरआरआर अवधि दोनों के दौरान चलनिधि की स्थितियों के साथ नकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है, जबकि कुल सौदों और चलनिधि अनिश्चितता के लिए कारोबार सकारात्मक रूप से सहसंबद्ध है। हालाँकि, डब्ल्यूएसीआर प्रसार और चलनिधि वितरण के बीच सहसंबंध अस्पष्ट है (चार्ट 6)।

डब्ल्यूएसीआर, और इस प्रकार इसका प्रसार, उच्च अस्थिरता दृढ़ता प्रदर्शित करता है (सिंह, 2020)। एक

चार्ट 6: डब्ल्यूएसीआर स्प्रेड (एलएएफ फ्लोर पर) और व्याख्यात्मक चर के बीच संबंध



ऑटोरिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोसेडैस्टिसिटी (आर्क) मॉडल (एंगल और बोलर्सलेव, 1986) का अनुमान प्रसार के निर्धारकों का विश्लेषण करने के लिए लगाया जाता है। माध्य समीकरण के अलावा, आर्क मॉडल में एक विचरण समीकरण (θ) होता है जिसे इसके पिछले वर्ग त्रुटि अवधि के भारित औसत के एक फ़ंक्शन के रूप में व्यक्त किया जाता है, अर्थात् आर्क अवधि (ε_{t-1}^2) और पिछली सशर्त विचरण अवधि (σ_{t-1}^2)। विचरण समीकरण में गुणांकों की व्याख्या ऑटोकोरिलेशन कारक (θ) और अस्थिरता दृढ़ता ($\theta + \varphi$) कारक के रूप में की जा सकती है। पहले चर्चा किए गए चरों को नियंत्रित करते हुए, माध्य और विचरण समीकरणों का अनुमान अधिकतम संभावना विधि का उपयोग करके SDF और FRRR अवधि के लिए आर्क ढांचे में लगाया जाता है। प्रसार में परिवर्तनशीलता पर नीति घोषणा के प्रभाव को देखने के लिए नीति रेपो दर ($Repo_t$) को विचरण

समीकरण में शामिल किया जाता है। LIQ_Unct विचरण समीकरण में भी शामिल है। मॉडल नीचे निर्दिष्ट किया गया है और परिणाम सारणी 1 और सारणी 2 में प्रस्तुत किए गए हैं।

माध्य समीकरण

$$Spread_t = c + \alpha Spread_{t-1} + \beta_1 LIQ_Cond_t + \beta_2 LIQ_Dist_t + \beta_3 TRDtoTot_t + \beta_4 LIQ_Unct_t + \varepsilon_t$$

विचरण समीकरण

$$\sigma_t^2 = c_0 + \theta \varepsilon_{t-1}^2 + \mu_1 LIQ_Unct_t + \mu_2 (Repo)_t, \text{ where } \theta > 0$$

सारणी 1 से, यह देखा गया है कि नमूना अवधि के दौरान चलनिधि की स्थिति का डब्ल्यूएसीआर (एसडीएफ दर पर) के प्रसार पर नकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, यानी बैंकिंग प्रणाली में अधिशेष चलनिधि अंतरबैंक कॉल दर को नरम

⁷ आर्क मॉडल समय के साथ भिन्नता को बदलने की अनुमति देते हैं और अक्सर छोटी लेकिन अत्यधिक अस्थिर अवधि को चिह्नित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं।

सारणी 1: एसडीएफ अवधि के दौरान प्रसार को प्रभावित करने वाले कारक

आश्रित चर: प्रसार (डब्ल्यूएसीआर बनाम एसडीएफ दर)			
माध्य समीकरण		विचरण समीकरण	
व्याख्यात्मक चर			
प्रसार (-1)	0.770***	सी	-0.009***
चलनिधि की शर्तें	-0.027***	रेसिड(-1) ²	0.825***
कुल कारोबार मात्रा	0.044***	रेपो	0.002***
चलनिधि वितरण	0.011***	चलनिधि अनिश्चितता	0.001***
चलनिधि अनिश्चितता	0.007***		
निदान			
आर्क एलएम (6) (पी-वैल्यू)	0.99		
क्यू (6) (पी-वैल्यू)	0.67		
समायोजित आर ²	0.75		

टिप्पणी: '***', '**' और '*' क्रमशः 1, 5 और 10 प्रतिशत पर महत्व दर्शाते हैं।

स्रोत: लेखकों का अनुमान।

कर देती है, जिससे प्रसार कम हो जाता है। चलनिधि वितरण और चलनिधि अनिश्चितता का सकारात्मक गुणांक भी अपेक्षित रेखाओं पर है - अधिक विषम वितरण और अधिक अनिश्चितता डब्ल्यूएसीआर को मजबूत करती है जिससे प्रसार बढ़ता है। डब्ल्यूएसीआर प्रसार और चलनिधि वितरण के बीच सकारात्मक संबंध कॉल मनी बाजार में गहराई की कमी को दर्शाता है जहां कुछ खिलाड़ी अक्सर बाजार की गतिशीलता को संचालित करते हैं (कुमार और अन्य, 2017)। कारोबार किए गए सौदों की हिस्सेदारी में वृद्धि भी पहले बताए गए कारणों से प्रसार में वृद्धि के साथ जुड़ी हुई है। चूंकि इंटरबैंक ओवरनाइट मार्केट में अस्थिरता क्लस्टरिंग की विशेषता होती है, इसलिए दृढ़ता को इंगित करने वाला विलंबित प्रसार, प्रसार से सकारात्मक रूप से संबंधित है। विचरण समीकरण के परिणाम बताते हैं कि तरलता अनिश्चितता प्रसार की अस्थिरता को बढ़ाती है जबकि नीति घोषणा का प्रसार पर सकारात्मक और महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

सारणी 2 से स्पष्ट है, एफआरआरआर अवधि के औसत समीकरण में विलंबित प्रसार, चलनिधि की स्थिति और चलनिधि वितरण के गुणांकों के संकेत एसडीएफ अवधि के समान हैं। कारोबारी सौदों और चलनिधि अनिश्चितता का प्रभाव एसडीएफ के विपरीत एफआरआरआर के तहत महत्वपूर्ण नहीं पाया गया

सारणी 2: एफआरआरआर अवधि के दौरान प्रसार को प्रभावित करने वाले कारक

आश्रित चर: प्रसार (स्थिर दर रिवर्स रेपो पर डब्ल्यूएसीआर)			
माध्य समीकरण		विचरण समीकरण	
व्याख्यात्मक चर			
प्रसार (-1)	0.609***	सी	-0.002
चलनिधि की शर्तें	-0.007***	रेसिड (-1) ²	0.342***
कुल कारोबार मात्रा	-0.008	रेपो	0.001***
चलनिधि वितरण	0.007***	चलनिधि अनिश्चितता	0.001***
चलनिधि अनिश्चितता	-0.002		
निदान			
आर्क एलएम (6) (पी-वैल्यू)	0.99		
क्यू (6) (पी-वैल्यू)	0.17		
समायोजित आर ²	0.47		

टिप्पणी: '***', '**' और '*' क्रमशः 1, 5 और 10 प्रतिशत पर महत्व दर्शाते हैं।

स्रोत: लेखकों का अनुमान।

है। एफआरआरआर अवधि के दौरान, बैंकों को रिजर्व रखरखाव पखवाड़े के दौरान आयोजित चार-14 दिवसीय परिवर्तनीय दर अवधि रेपो नीलामियों के माध्यम से दैनिक आधार पर अपनी स्वयं की निवल मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 0.25 प्रतिशत तक और बैंकिंग प्रणाली एनडीटीएल के 0.75 प्रतिशत तक निश्चित दर रेपो तक पहुंच थी, जिससे सुनिश्चित चलनिधि की एक मात्रा उपलब्ध हुई। इस प्रकार, इस अवधि के दौरान प्रसार के स्तर पर चलनिधि अनिश्चितता का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं था। हालांकि, प्रसार की परिवर्तनशीलता पर चलनिधि अनिश्चितता का महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव पड़ता पाया गया है।

V. निष्कर्ष

एसडीएफ की शुरुआत भारतीय संदर्भ में मौद्रिक नीति कार्यान्वयन में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। यह केंद्रीय बैंक को संपार्श्विक उपलब्धता से बाधित हुए बिना चलनिधि प्रबंधन में अधिक लचीलापन प्रदान करता है - एक तथ्य जो असाधारण चलनिधि की अधिकता की अवधि के दौरान पहले भी उल्लेख किया गया था। इसके अलावा, एसडीएफ उचित मूल्य निर्धारण के साथ लंबी अवधि में चलनिधि को

अवशोषित करने की लचीलापन प्रदान करता है। इस प्रकार, अतिरिक्त चलनिधि का नसबंदी आगे के प्रवाह को ट्रिगर किए बिना किया जा सकता है, जो कि बार-बार ओएमओ बिक्री के माध्यम से संभव है जो ब्याज दरों को ऊंचा रखता है और ब्याज दर अंतर को बनाए रखता है।

साक्ष्यजन्य परिणाम डब्ल्यूएसीआर और इसके प्रसार को निर्धारित करने में चलनिधि की स्थिति, चलनिधि अनिश्चितता और चलनिधि वितरण के महत्व की पुष्टि करते हैं, जिसकी पुष्टि ओवरनाइट इंटर-बैंक मनी मार्केट में हाल के घटनाक्रमों से होती है। परिणाम सहकारी बैंकों को एनडीएस-कॉल प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने में रिज़र्व बैंक की नियामक पहलों की प्रभावकारिता के बारे में भी साक्ष्य प्रदान करते हैं, जिसने पहले देखी गई डब्ल्यूएसीआर के मूल्य निर्धारण में विकृतियों को कम किया है। इसके अलावा, जनवरी 2025 के मध्य से दैनिक वीआरआर की शुरुआत ने चलनिधि अनिश्चितता को कम कर दिया है। बाजार की गतिशीलता और वित्तीय बाजार साधनों के मूल्य निर्धारण से संकेत निकालने की सुविधा के लिए बाजार सूक्ष्म संरचना और मौद्रिक नीति की परिचालन प्रक्रिया में इस तरह के परिशोधन वास्तव में आवश्यक हैं।

संदर्भ:

Afonso, G., Cipriani, M., Spada, G. L. & Prastakos, P. (2023). "The Federal Reserve's Two Key Rates: Similar but Not the Same?," *Liberty Street Economics* 20230814, Federal Reserve Bank of New York.

Bernhardsen, T., & Kloster, A. (2010). Liquidity management system: Floor or corridor. Norges Bank Staff Memo No 4

Bindseil, U. and Jablecki, J. (2011), "The Optimal Width of the Central Bank Standing Facilities Corridor and Banks' day-to-day Liquidity Management

Bindseil, U. (2014). Monetary Policy Operations and the Financial System, Oxford University Press.

BIS (2022). MC Compendium, Monetary policy frameworks and central bank market operations.

Brandao-Marques L., and L. Ratnovski (2024): The ECB's Future Monetary Policy Operational Framework - Corridor or Floor? IMF Working Paper WP/24/56, March.

Chailloux, A., Gray, S., & McCaughrin, R. (2008). Central Bank collateral frameworks: Principles and policies. *International Monetary Fund Working Paper* No. 222.

Engle, R.F. and T. Bollerslev, (1986), "Modelling the Persistence of Conditional Variance", *Econometric Reviews*, 5, 1-50.

Höflmayr M., and D. Kläffling (2024): A new operational framework for the European Central Bank, European Parliamentary Research Service, May.

Kumar, S., Prakash, A., & Kushawaha, K. M. (2017). What explains call money rate spread in India? *RBI Working Paper Series*: 07/2017.

Mohan, R., (2006). Coping with Liquidity Management in India: A Practitioner's View. *RBI Bulletin*, April.

Nelson, B. (2024). From the Floor Back to the Corridor: Why the Choice of Monetary Policy Implementation Framework Matters? Bank Policy Institute Blog, September 30. <https://bpi.com/from-the-floor-back-to-the-corridor-why-the-choice-of-monetary-policy-implementation-framework-matters/>

Patra M.D., Kapur M., Kavediya R., & Lokare, S.M. (2016). Liquidity Management and Monetary Policy: From Corridor Play to Marksmanship in Ghate C.& Kletzer K. (eds) *Monetary Policy in India*, Springer, New Delhi, 257-296.

Prabu, E. and Bhattacharyya, I. (2023). Regime-Dependent Determinants of the Uncollateralised Overnight Rate: The Interplay of Operating Procedure and Market Microstructure. *RBI Working Paper Series*, WPS(DEPR):07/2023.

Reserve Bank of India (2014). Report of the Expert Committee to Revise and Strengthen the Monetary Policy Framework, January.

Reserve Bank of India (2011). Report of the Working Group on Operating Procedure of Monetary Policy (Chairman: Deepak Mohanty), March.

Rule, G. (2012). "Collateral management in central bank policy operations," Handbooks, *Centre for Central Banking Studies*, Bank of England, number 31, April.

Singh, B. (2020). Liquidity Shocks and Overnight Interest Rates in Emerging Markets: Evidence from GARCH Models for India. *RBI Working Paper Series*, WPS(DEPR):06/2020.

Whitesell, W. (2006). Interest Rate Corridors and Reserves. *Journal of Monetary Economics* 53, 1177-1195.

अनुबंध

सारणी 1: स्थायी जमा सुविधाएं: सीमा पार

देश	नाम	रूप	मूल्य निर्धारण विधि	पहुंच सीमित है
ऑस्ट्रेलिया	विनिमय निपटान खाता	आरबीए जमा दर	नकद लक्ष्य दर – 10 बीपीएस	एक्सचेंज सेटलमेंट खाता पात्रता
ब्राज़िल	स्थायी सुविधा	रिवर्स रेपो	बेस सेलिक दर – 35 बीपीएस	वित्तीय संस्थाएं जो प्राथमिक डीलर हैं; पात्र संपादिक
कनाडा	जमा सुविधा	जमा	ऑपरेटिंग बैंड की निचली सीमा पर स्थिर;	एलवीटीएस भुगतान प्रणाली में भागीदार
यूरो प्रणाली	जमा सुविधा	जमा	निश्चित दर	कोई सीमा नहीं
भारत	स्थायी जमा सुविधा	असंपादिक जमा	पॉलिसी दर - 25 बीपीएस	एससीबी; चुनिंदा यूसीबी, आरआरबी, चुनिंदा एसएससीबी और प्राथमिक डीलर
इंडोनेशिया	जमा सुविधा	जमा	पॉलिसी दर - 75 बीपीएस	मौद्रिक परिचालन में भागीदार के रूप में पंजीकृत बैंक
कोरिया	चलनिधि समायोजन जमा	जमा	आधार दर – 50बीपीएस	रिजर्व डिपॉजिटरी संस्थाएँ
मलेशिया	स्थायी सुविधा	जमा	ओपीआर - 25बीपीएस	वित्तीय संस्थाएं जो अंतरबैंक भागीदार हैं
मेक्सिको	स्थायी सुविधा	जमा	पारिश्रमिक नहीं दिया गया	वाणिज्यिक और विकास बैंक
न्यूजीलैंड	स्थायी सुविधा	जमा	आधिकारिक नकद दर से नीचे तय	वाणिज्यिक बैंक और वित्तीय संस्थाएं
नॉर्वे	स्थायी सुविधा	अतिरिक्त रिजर्व	वेतन	वाणिज्यिक बैंक, निपटान बैंक और विशेष वित्तीय संस्थान
फिलिपींस	जमा सुविधा	रातोंरात जमा	निश्चित दर	बैंक, NBQBs, और ट्रस्ट संस्थाएं
सिंगापुर	स्थायी सुविधा	जमा	संदर्भ दर 50 बी.पी. से कम, 0 प्रतिशत पर स्थिर	MEPS+ सहभागी बैंक
दक्षिण अफ्रीका	स्थायी सुविधा रिवर्स रेपो	दिन के अंत में स्वचालित स्क्वायर ऑफ सुविधा	रेपो 100 बीपीएस से कम	समाशोधन बैंक
स्वीडन	स्थायी सुविधा	जमा	रेपो दर माइनस 10 बीपीएस	मौद्रिक नीति प्रतिपक्ष और रिक्सबैंक की भुगतान प्रणाली RIX में कुछ प्रतिभागी
थाईलैंड	दिन के अंत में जमा सुविधा	जमा	नीति दर माइनस 50बीपी	बैंक, वित्त कम्पनियाँ, विशेष वित्तीय संस्थाएँ और बीओटी द्वारा अनुमत अन्य विधिक व्यक्ति
यूनाइटेड किंगडम	परिचालन स्थायी जमा सुविधा	जमा	बैंक दर माइनस 25बीपी	बैंक, बिल्डिंग सोसायटी, सीसीपी और ब्रोकर डीलर, असीमित आकार
संयुक्त राज्य अमेरिका	स्थायी सुविधा	आरक्षित शेष पर ब्याज	मार्च 2025 तक, 440 बीपीएस	जमा करने वाली संस्थाओं

स्रोत: बीआईएस; और केंद्रीय बैंक की वेबसाइटें।

सारणी 2: सांख्यिकी सारांश								
	स्प्रेड (डब्ल्यूएसीआर – फ्लोर)		चलनिधि की शर्तें		चलनिधि वितरण		कुल सौदों के लिए कारोबार	
	एफआरआरआर	एसडीएफ	एफआरआरआर	एसडीएफ	एफआरआरआर	एसडीएफ	एफआरआरआर	एसडीएफ
माध्य	0.15	0.28	0.82	0.34	8.32	2.23	0.67	0.91
माध्यिका	0.14	0.29	0.48	0.25	7.92	2.19	0.71	0.99
अधिकतम	1.02	1.16	4.27	4.46	29.83	3.76	0.94	1.0
न्यूनतम	-0.15	-0.48	-1.50	-1.65	3.02	0.17	0.08	0.23
मानक विचलन	0.09	0.20	1.28	0.99	2.76	0.40	0.13	0.15
स्कीनेस	2.11	-0.33	0.51	1.24	1.40	0.22	-0.73	-1.91
कुटोसिस	19.7	3.53	2.27	5.70	8.77	4.37	3.27	5.7
प्रेक्षण	712	721	712	721	712	721	712	721

टिप्पणी: एफआरआरआर अवधि 6 अप्रैल, 2017 से 20 मार्च, 2020 तक है; एसडीएफ अवधि 8 अप्रैल, 2022 से 28 मार्च, 2025 तक है।

स्रोत: लेखकों का अनुमान।

जलवायु नीति अनिश्चितता और ऊर्जा वस्तु मूल्यों की बदलती गतिशीलता

सताद्रु दास और विद्या कामते द्वारा ^

यह आलेख गैवरिलिडिस (2021) द्वारा विकसित जलवायु नीति अनिश्चितता (सीपीयू) सूचकांक का उपयोग करके मापे गए जलवायु परिवर्तन और वैश्विक ऊर्जा वस्तुओं कीमतों के बीच विकसित होते संबंधों और भारत की घरेलू मुद्रास्फीति पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करता है। मासिक डेटा का उपयोग कर किए गए सांख्यिकीय परीक्षण संकेत देते हैं कि सीपीयू सूचकांक और वैश्विक ऊर्जा वस्तुओं कीमतों के बीच संबंध मार्च 2017 के आसपास एक संरचनात्मक विराम से गुजरा। जबकि मार्च 2017 से पहले, दोनों चर के बीच संबंध धनात्मक था, यह तब से ऋणात्मक है। स्थानीय रेखीय प्रक्षेपण (एलएलपी) ढांचे का उपयोग करके डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि सीपीयू और ऊर्जा वस्तुओं कीमतों के बीच गतिशीलता में इस बदलाव ने हाल के वर्षों में भारत में घरेलू कीमतों पर वैश्विक जलवायु नीति अनिश्चितता को प्रतिचक्रीय बनाया है।

परिचय

जीवाश्म ईंधन जैसे ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों ने वैश्विक आर्थिक विस्तार में योगदान दिया है। जीवाश्म ईंधन के निरंतर उपयोग के साथ-साथ प्रतिकूल पर्यावरणीय परिणामों के परिणामस्वरूप जलवायु परिवर्तन की घटना के प्रति वैश्विक नीति चिंता उत्पन्न हुई है। 2016 में पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद से वैश्विक तापमान में वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम तक सीमित करने के उद्देश्य से, बढ़ती संख्या में देश स्वैच्छिक उत्सर्जन में कमी और अन्य विकास रणनीतियों के लिए रोडमैप तैयार कर रहे हैं ताकि «निवल शून्य उत्सर्जन» के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। इसलिए, वैश्विक ऊर्जा उपयोग और ऊर्जा वस्तुओं की कीमतें जलवायु नीति परिवर्तनों से संबंधित अनिश्चितताओं के

साथ जटिल रूप से जुड़ी हुई हैं। उपर्युक्त अंतर्संबंधों के प्रकाश में, यह पत्र वैश्विक ऊर्जा कीमतों पर जलवायु नीति अनिश्चितता के प्रभाव और संबंधित रूप से, भारत में घरेलू मुद्रास्फीति के लिए इन गतिशीलता के प्रभावों का विश्लेषण करता है।

जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा की कीमतों के बीच संबंध धनात्मक या ऋणात्मक हो सकते हैं। जलवायु विनियमन प्रेरित अनिश्चितता को हरित ऊर्जा में फर्म निवेश से धनात्मक रूप से संबंधित पाया गया है, जो अपने कार्बन पदचिह्न को कम करने की इच्छा से प्रेरित है (रोड्रिगज लोपेज़ और अन्य, 2017)। निवेशक बढ़ती जलवायु परिवर्तन चिंताओं के जवाब में ब्राउन फर्मों से दूर चले जाते हैं और ग्रीन फर्मों में चले जाते हैं, जिससे ग्रीन स्टॉक की तुलना में ब्राउन स्टॉक का प्रदर्शन कम होता है (पास्टर और अन्य, 2021, बोरी और अन्य, 2022)। इसके विपरीत, अनिश्चितता के तहत निवेश निर्णयों के लिए वास्तविक विकल्प दृष्टिकोण एजेंटों को निवेश करने के लिए प्रतीक्षा करने के विकल्प मूल्य को बढ़ाकर अपने निवेश को स्थगित करने के लिए निर्देशित करता है (बर्नानके, 1983; दीक्षित और अन्य, 1994)। कई अध्ययनों में हरित या निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों में इस तरह के निवेश स्थगन के डेटा साक्ष्य मिले हैं (फ़स और अन्य, 2009; ब्लिथ और अन्य, 2007; केटुनेन और अन्य, 2011)। दो विरोधी दृष्टिकोण, जिनमें से एक का तर्क है कि अनिश्चितता फर्मों को निवेश करने से हतोत्साहित करती है, जबकि दूसरा सुझाव देता है कि अनिश्चितता निवेश को प्रोत्साहित करती है, ऊर्जा वस्तुओं की कीमतों के लिए विपरीत प्रभाव हो सकते हैं और इसलिए, आगे के डेटा विश्लेषण की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन जोखिम संबंधी नीतियों से ऊर्जा की कीमतों पर असर पड़ने की संभावना है। निवेश की मांग और मुद्रास्फीति की उम्मीदों पर जलवायु नीति अनिश्चितता के प्रभाव से मुद्रास्फीति संबंधी दबाव पैदा हो सकते हैं (एडेडिरन और अन्य, 2023)। जलवायु परिवर्तन से संबंधित भौतिक जोखिम खाद्य, आवास और ऊर्जा की कीमतों के संबंध में मुद्रास्फीति की अस्थिरता को बढ़ा सकते हैं, जिसका मुद्रास्फीति पर विषम प्रभाव हो सकता है (RBI, 2023)। इसलिए, जलवायु नीति अनिश्चितता के कारण ऊर्जा मूल्य परिवर्तनों के घरेलू मुद्रास्फीति पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण हो जाता है।

^ लेखक आर्थिक एवं नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर) से हैं। लेखक, मनीष कपूर, सौरभ घोष और हरेंद्र कुमार बेहरा को उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। इस आलेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिजर्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

इस पृष्ठभूमि के साथ, आलेख का शेष भाग इस प्रकार व्यवस्थित है। खंड II जलवायु परिवर्तन नीति और ऊर्जा कीमतों के बीच संबंधों का विश्लेषण करने वाले साहित्य का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है। खंड III विश्लेषण में उपयोग किए गए डेटा और चर के चयन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। खंड IV और V में कार्यप्रणाली और पेपर में प्राप्त मुख्य डेटा परिणामों पर चर्चा की गई है। खंड VI कुछ मुख्य निष्कर्षों और नीति सुझावों के साथ समाप्त होता है।

II. साहित्य समीक्षा

मौजूदा साहित्य ने जलवायु परिवर्तन और तेल उद्योग के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण किया है। जलवायु परिवर्तन नीतियों में संक्रमण जोखिमों और कच्चे तेल के उपयोग और नवीकरणीय ऊर्जा खपत की सापेक्ष लागतों पर उनके प्रभाव के माध्यम से तेल क्षेत्र के लिए जोखिम प्रीमियम को बदलने की क्षमता है (डियाज़-रैनी और अन्य, 2021)। जीवाश्म ईंधन फर्मों को उच्च अनिश्चितता के कारण गैर-जीवाश्म ईंधन फर्मों की तुलना में अपेक्षाकृत बड़ी बैंक उधारी लागत का सामना करना पड़ता है (डेलिस और अन्य, 2019)। कार्बन-गहन उद्योगों पर जलवायु परिवर्तन का वित्तीय बाजार प्रभाव कई अध्ययनों का विषय रहा है। भविष्यवाणी बाजारों से डेटा का उपयोग करते हुए, मंग (2017) विश्लेषण करते हैं कि शेयर बाजार द्वारा कार्बन विनियमन की संभावना में परिवर्तन कैसे मापा जाता है। श्वेन्कर और टेलर (2021) ऊर्जा उद्योगों की लाभप्रदता पर भविष्य की जलवायु नीतियों की अपेक्षाओं के प्रभाव को उजागर करते हैं। पास्टर और अन्य (2022) ग्रीन बॉन्ड के उच्च प्रदर्शन का श्रेय पर्यावरणीय चिंताओं में मजबूत वृद्धि को देते हैं न कि उच्च अपेक्षित रिटर्न को। अर्डिया और अन्य में भी इसी तरह का निष्कर्ष निकाला गया है। (2023) एसएंडपी 500 कंपनियों के डेटा का उपयोग करते हुए। बोल्टन और कैस्पर्सकी (2021) ने अमेरिकी स्टॉक रिटर्न के क्रॉस सेक्शन का विश्लेषण किया और पाया कि उच्च कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन वाली फर्मों के स्टॉक उच्च रिटर्न कमाते हैं, जो कार्बन उत्सर्जन जोखिम के संपर्क में आने के लिए निवेशकों द्वारा मांगे जाने वाले बढ़े हुए मुआवजे को उजागर करता है।

ऐसा कोई भी उपकरण नहीं है जो जलवायु परिवर्तन को उसके पूर्ण आयाम में पकड़ सके। इस चुनौती से पार पाने के लिए, गैवरिलिडिस (2021) ने एक जलवायु नीति अनिश्चितता (सीपीयू) सूचकांक विकसित किया। सीपीयू सूचकांक न केवल जलवायु पर दृष्टिकोण परिवर्तन को ध्यान में रखता है बल्कि ऊर्जा क्षेत्र में संक्रमण जोखिमों से संबंधित संकेत भी प्रदान करता है। विभिन्न आर्थिक संकेतकों के साथ सूचकांक के संबंध का विश्लेषण करने वाला साहित्य बढ़ रहा है। बौरी और अन्य (2022) ने पाया कि हरित बनाम भूरी ऊर्जा शेयरों के प्रदर्शन में अंतर जलवायु नीति अनिश्चितता से प्रेरित है। ट्रीपोंगकरुना और अन्य (2023) बताते हैं कि सीपीयू के कम जोखिम वाले शेयरों के जोखिम-समायोजित भविष्य के रिटर्न उच्च सीपीयू जोखिम वाले शेयरों की तुलना में अधिक हैं और इस प्रकार यह प्रमाण प्रदान करते हैं कि सीपीयू की कीमत अलग-अलग शेयरों के क्रॉस-सेक्शन में निर्धारित की गई है। (2023) ने जलवायु नीति अनिश्चितता, तेल की कीमतों और नवीकरणीय ऊर्जा खपत के बीच संबंधों की जांच करने के लिए स्टोकेस्टिक अस्थिरता (टीपीपी-एसवी-वीएआर) के साथ एक समय-भिन्न पैरामीटर वेक्टर ऑटोरिग्रेसिव मॉडल विकसित किया। दाई और झांग (2023) ने पाया कि सीपीयू वाणिज्यिक बैंकों में दिवालियापन के जोखिम को बढ़ाता है। तियान और अन्य (2022) ने यू.एस., यूरोप और चीन में ग्रीन बॉन्ड की कीमतों पर सीपीयू के असममित प्रभावों को उजागर किया। घरेलू कीमतों पर सीपीयू इंडेक्स के पास-श्रु प्रभाव को अपेक्षाकृत कम समझा गया है और यह लेख भारत के संदर्भ में उस कमी को पूरा करता है।

III. आँकड़े

आर्थिक परिणामों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के किसी भी विश्लेषण के लिए जलवायु परिवर्तन के पर्याप्त माप की आवश्यकता होगी जो वायुमंडल, भूमि की सतह, बर्फ और बर्फ, महासागरों और पानी के अन्य निकायों और जीवित चीजों से मिलकर जलवायु प्रणाली के सभी पहलुओं को पकड़ने में सक्षम हो। यह देखते हुए कि भारत वैश्विक ऊर्जा बाजारों में एक मूल्य लेने वाला देश है, वैश्विक जलवायु नीति से संबंधित सीपीयू सूचकांक एक उपयुक्त उपाय हो सकता है। सीपीयू सूचकांक का उपयोग

अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाओं (रेन और अन्य, 2022; दाई और झांग, 2023) के संदर्भ में विश्लेषण में वैश्विक जलवायु जोखिम के लिए एक बेंचमार्क के रूप में किया गया है। एक और लाभ यह है कि अन्य जलवायु परिवर्तन चर की तुलना में, सीपीयू सूचकांक उच्च आवृत्ति (मासिक) पर उपलब्ध है।

सीपीयू इंडेक्स का निर्माण बेकर और अन्य (2016) में उल्लिखित कार्यप्रणाली पर आधारित है। विशेष रूप से, जलवायु परिवर्तन अनिश्चितता से संबंधित कीवर्ड के लिए आठ प्रमुख अमेरिकी समाचार पत्रों की खोज की गई और सूचकांक के निर्माण के लिए प्रासंगिक लेखों की मानकीकृत स्केल की गई संख्या के औसत पर विचार किया गया। मासिक ऊर्जा मूल्य सूचकांक डेटा विश्व बैंक पिक शीट वस्तुओं बाजारों के आंकड़ों से प्राप्त किया जाता है। ऊर्जा सूचकांक में कोयला, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का भारित मूल्य सूचकांक शामिल है। विश्लेषण में उपयोग की गई नमूना अवधि जनवरी -1991 अक्टूबर 2022 है।

डब्ल्यूपीआई पर डेटा सीईआईसी से प्राप्त किया जाता है और जनवरी 1991 से अक्टूबर 2022 तक एक सुसंगत समय श्रृंखला 2005-2004, 94-1993 और 2012-2011 में आधार वर्ष परिवर्तनों को देखते हुए स्प्लिसिंग के माध्यम से प्राप्त की जाती है। नवीनतम श्रृंखला को बेंचमार्क के रूप में उपयोग करके ऐतिहासिक श्रृंखला का निर्माण किया गया है।

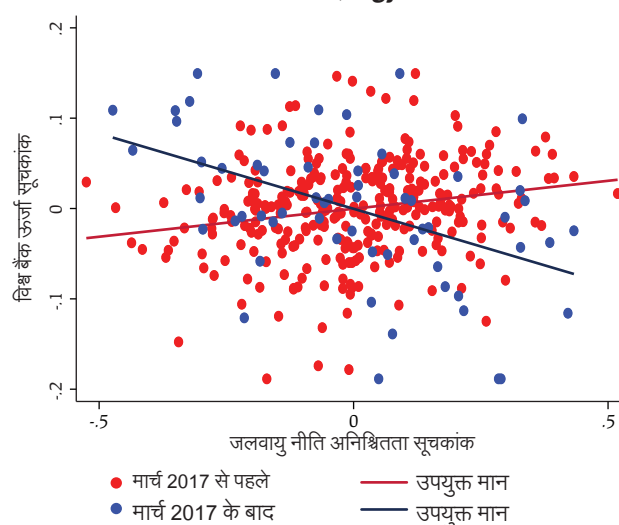
बैक्सटर किंग फ़िल्टर का उपयोग करके तीनों चरों को डी-सीजनलाइज़, लॉग-ट्रांसफ़ॉर्म और डीट्रेंड किया जाता है और चक्र निकाले जाते हैं। डीट्रेंडिंग के कारण नमूने की शुरुआत और अंत में कुछ महीनों के अवलोकन खो जाते हैं, और अंतिम नमूना मई 1991 और मई 2022 के बीच की अवधि का होता है। आगामी अनुभागों में सभी डेटा विश्लेषण श्रृंखला के निकाले गए चक्रों पर किए जाते हैं।

IV. प्रविधि और परिणाम

सीपीयू, तेल की कीमत और नवीकरणीय ऊर्जा खपत के बीच संबंध गतिशील और समय के साथ बदलता रहता है (झोउ और अन्य, 2023)। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सीपीयू और ऊर्जा की कीमतों के बीच संबंध धनात्मक या ऋणात्मक

हो सकता है, जिसमें एक दृष्टिकोण यह तर्क देता है कि जलवायु संबंधी अनिश्चितता फर्मों को हरित ऊर्जा में निवेश करने से हतोत्साहित करती है, जबकि दूसरा दृष्टिकोण जलवायु संबंधी चिंताओं के जवाब में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश बढ़ाने के लिए समर्थन प्रदान करता है। नतीजतन, सीपीयू के कारण पारंपरिक ऊर्जा की कीमत भी किसी भी दिशा में प्रभावित हो सकती है। हरित ऊर्जा में कम/अधिक निवेश का अर्थ हरित ऊर्जा में देरी/तेजी से बदलाव हो सकता है और इससे तेल, प्राकृतिक गैस और कोयले जैसी ऊर्जा वस्तुओं की कीमतें बढ़/घट सकती हैं। यह भी संभव है कि जलवायु नीति संबंधी चर्चा के आधार पर समय के साथ संबंध विकसित और बदल रहा हो। इसलिए, सीपीयू और ऊर्जा मूल्य सूचकांक के बीच गतिशील संबंध का विश्लेषण करने के लिए, संरचनात्मक ब्रेक की उपस्थिति की पहचान करने के लिए एक सुप्रीमम वाल्ड परीक्षण किया गया था, यदि कोई हो। परीक्षण के परिणाम मार्च 2017 के आसपास एक संरचनात्मक ब्रेक को उजागर करते हैं (अनुलग्नक सारणी ए1)। दो नमूनों में दो चरों के बीच एक स्कैटर प्लॉट भी संरचनात्मक विराम और रिश्ते में बदलाव की पुष्टि करता है। जबकि चरों के बीच मार्च 2017 से पहले का संबंध धनात्मक है, 2017 के बाद का संबंध ऋणात्मक है (चार्ट 1)। संबंधों में बदलाव डेटा को विंसेराइज़ करने के लिए मज़बूत है और इसलिए, कुछ बाहरी टिप्पणियों से प्रेरित नहीं है।

चार्ट 1: सीपीयू सूचकांक और विश्व बैंक ऊर्जा सूचकांक के बीच संबंध



स्रोत: गैवरिलिडिस (2021); विश्व बैंक; और लेखकों की गणना।

¹ सीपीयू सूचकांक के निर्माण की विस्तृत व्याख्या के लिए, गैवरिलिडिस (2021) देखें।

परिणाम मौजूदा डेटा साक्ष्य के अनुरूप हैं जो सीपीयू सूचकांक और ऊर्जा कीमतों के बीच समय-भिन्न गतिशील संबंध का सुझाव देते हैं। झोउ और अन्य (2023) दिखाता है कि तेल की कीमतों पर सीपीयू का प्रभाव विषम और गतिशील है। समय-भिन्न ग्रेंजर परीक्षणों का उपयोग करते हुए, रेन और अन्य (2023) ने पाया कि चरम जलवायु घटनाओं या प्रमुख जलवायु-संबंधी नीति परिवर्तनों के बाद सीपीयू और ऊर्जा कीमतों के बीच कारण संबंध काफी बढ़ जाता है।

धनात्मक से ऋणात्मक में संबंध में बदलाव का एक संभावित स्पष्टीकरण नवंबर 2016 में प्रभावी हुए पेरिस समझौते के बाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन नीति प्रयासों में वृद्धि हो सकती है। पेरिस समझौता एक ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है ताकि इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया जा सके और वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के साधनों का अनुसरण किया जा सके। समझौते के तहत, सभी प्रमुख उत्सर्जक देशों ने अपने जलवायु प्रदूषण में कटौती करने की प्रतिबद्धता जताई। पेरिस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद, कई देशों ने विस्तृत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) जारी किए हैं जो उत्सर्जन में कटौती करने और जलवायु प्रभावों के अनुकूल होने के लिए उनकी संबंधित जलवायु कार्य योजना की रूपरेखा तैयार करते हैं। पेरिस समझौते से पहले, जलवायु नीति में अनिश्चितता हरित संक्रमण की संभावना के बारे में रही होगी। यदि अनिश्चितता में वृद्धि हुई थी, तो यह सुझाव दिया जा सकता है कि संक्रमण की अवधि या तो स्थगित कर दी जाएगी या अपरिवर्तित रहेगी। इससे हरित परियोजनाओं में निवेश को रोकना और ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों का लंबे समय तक उपयोग करना हो सकता है। 2016 के बाद, जलवायु नीति पहले से अनुमानित संक्रमण से अधिक तेजी से निवल शून्य में बदल सकती है। वर्तमान परिदृश्य में, अनिश्चितता में किसी भी वृद्धि का अर्थ यह लगाया जा सकता है कि क्या संक्रमण समय-सीमा में तेजी लाई जाएगी या प्रत्याशित रूप से बनी रहेगी। इससे हरित ऊर्जा निवेश के प्रति अधिक प्रोत्साहन मिल सकता है और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए मंदी का दृष्टिकोण बन सकता है। परिणामस्वरूप, ऊर्जा मूल्य सूचकांक और जलवायु नीति अनिश्चितता के बीच

संबंध चक्रीय से प्रतिक्रिय हो गया है। दोनों के बीच संबंधों में यह परिवर्तन और भारत के लिए इसके निहितार्थों का औपचारिक रूप से निम्नलिखित अनुभाग में विश्लेषण किया गया है।

V. सीपीयू और ऊर्जा मूल्यों की विकासशील गतिशीलता का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

अब तक के विश्लेषण से पता चला है कि सीपीयू सूचकांक और ऊर्जा सूचकांक के बीच संबंध में संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है और मार्च 2017 के बाद यह धनात्मक से ऋणात्मक हो गया है। इसके बाद, दो उप-नमूनों के लिए तीन चरों का उपयोग करके अर्थमतीय मॉडलों की एक शृंखला का अनुमान लगाया जाता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि इस संबंध में परिवर्तन भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है या नहीं। विचाराधीन तीन चर सीपीयू सूचकांक, ऊर्जा वस्तुओं मूल्य सूचकांक और भारत का मुख्य थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) हैं। हम निम्नलिखित रूप के स्थानीय रैखिक प्रक्षेपण (एलएलपी) मॉडल का अनुमान लगाते हैं

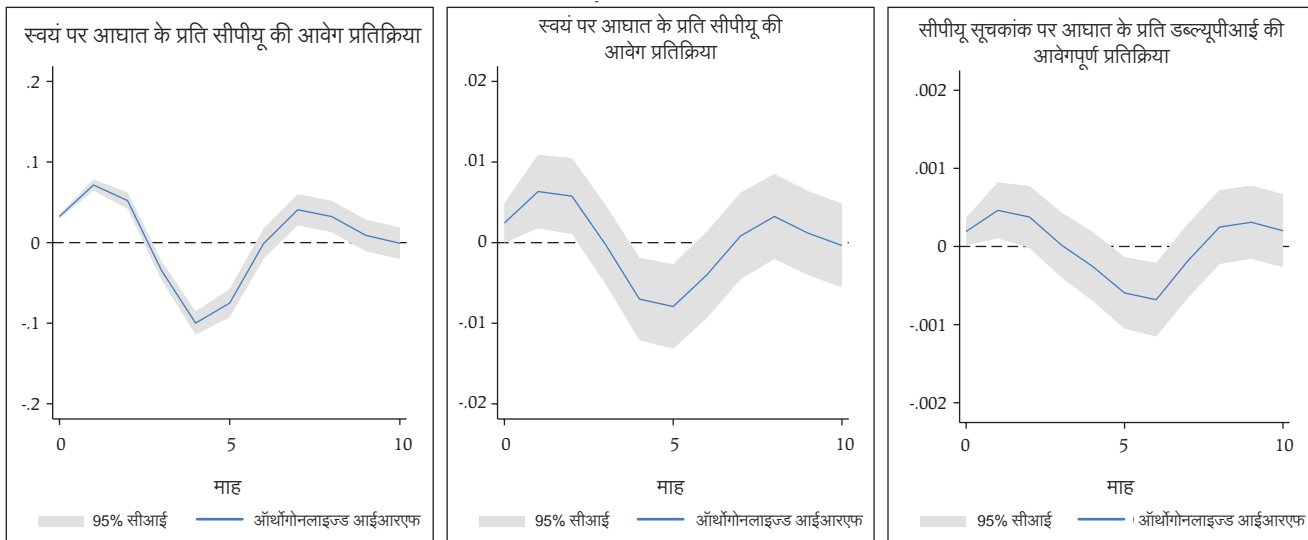
$$y_{t+k} = \alpha_k + \beta_k CPU_t + \sum_{j=t-12}^{t-1} \gamma_{kj} X_j + \epsilon_{i,t} \text{ where } k = 1, 2, \dots, 10$$

विश्लेषण की इकाई एक महीने में आश्रित चर का प्रेक्षित मूल्य है। आश्रित चर सीपीयू, वैश्विक ऊर्जा सूचकांक या डब्ल्यूपीआई है। आवेग प्रतिक्रिया फंक्शन उत्पन्न करने के लिए, हमें विभिन्न बाद के समय क्षितिज पर आश्रित चर पर जलवायु नीति आघात के प्रभाव को मापने की आवश्यकता है। तदनुसार, आश्रित चर के k -लीड्स के साथ k -संख्या के अलग-अलग प्रतिगमन चलाए जाते हैं, जहाँ $k=10, \dots, 1, 0$ महीने। मुख्य व्याख्यात्मक चर सीपीयू सूचकांक में समकालीन चक्र है। नियंत्रण चर में सीपीयू सूचकांक के बारह अंतराल और आश्रित चर शामिल हैं।

आवेग प्रतिक्रिया कार्य दर्शाते हैं कि मार्च 2017 से पहले, सीपीयू सूचकांक और डब्ल्यूपीआई के बीच संबंध महत्वपूर्ण थे, जिसमें सीपीयू वृद्धि (कमी) के परिणामस्वरूप डब्ल्यूपीआई वृद्धि (कमी) होती थी। हालांकि, मार्च 2017 से सीपीयू के लिए ऊर्जा सूचकांक और डब्ल्यूपीआई की प्रतिक्रिया उलट गई है। जबकि यह मार्च 2017 से पहले प्रोसाइक्लिक था (चार्ट2), यह

चार्ट 2: मार्च 2017 से पहले सीपीयू सूचकांक, ऊर्जा सूचकांक और डब्ल्यूपीआई के बीच संबंध

मई 1991-मार्च 2017



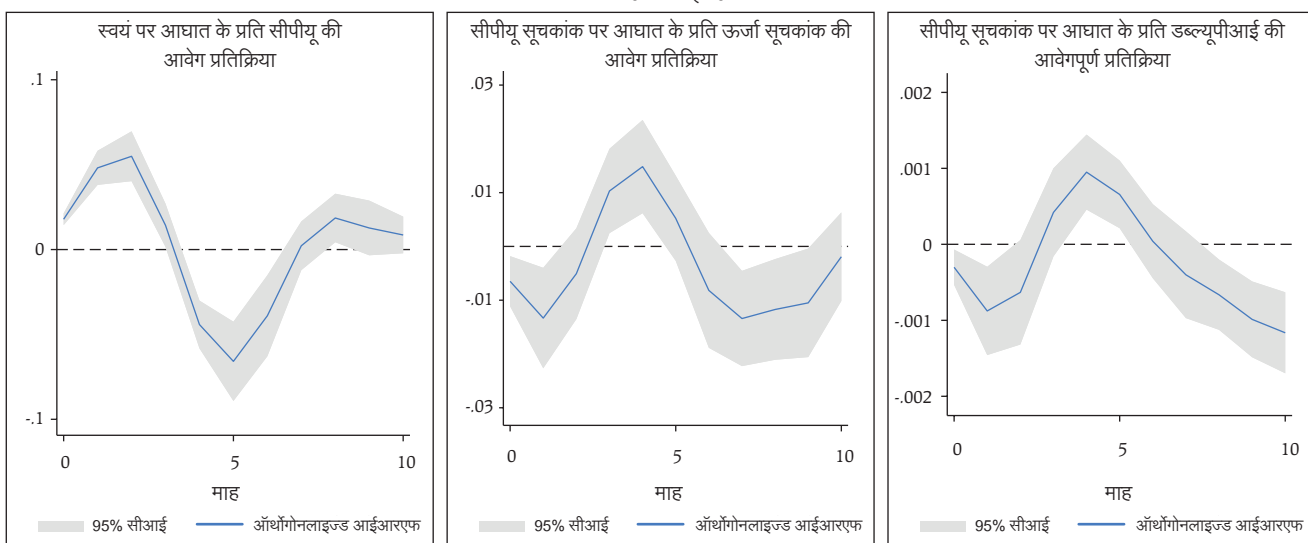
स्रोत: लेखकों की गणना।

तब से काउंटरसाइक्लिक बन गया है (चार्ट 3)। मार्च 2017 के बाद, ऊर्जा की कीमतों और डब्ल्यूपीआई पर धनात्मक सीपीयू आघात का ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। परिणामों की मजबूती की जांच के लिए वैकल्पिक अर्थमितीय मॉडल का अनुमान लगाया गया। एक एक्सोजेनस शॉक के रूप में उपयोग किए गए सीपीयू

इंडेक्स के चक्रों के साथ एक वीएआरएक्स मॉडल और चोल्स्की ऑर्डरिंग के साथ एक एसवीएआर मॉडल दोनों गुणात्मक रूप से समान परिणाम देते हैं। परिणाम पूर्वोक्त मांग सूचक के बिना वाले मॉडलों से महत्वपूर्ण रूप से भिन्न नहीं हैं (अनुलग्नक चार्ट ए2-ए5)।

चार्ट 3: मार्च 2017 के बाद सीपीयू इंडेक्स, ऊर्जा सूचकांक और डब्ल्यूपीआई के बीच संबंध

अप्रैल 2017 - मई 2022



स्रोत: लेखकों की गणना।

VI. निष्कर्ष

दुनिया के आर्थिक विकास की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन के निरंतर उपयोग के परिणामस्वरूप न केवल ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के भंडार में कमी आई है, बल्कि चरम जलवायु घटनाओं की एक तेज़ और अप्रत्याशित श्रृंखला और वैश्विक तापमान में वृद्धि की प्रवृत्ति भी हुई है। इसके परिणामस्वरूप जलवायु से संबंधित चिंताओं के लिए वैश्विक आह्वान हुआ है और दुनिया भर के कई देशों को हरित अर्थव्यवस्था में संक्रमण की योजनाओं को विकसित करने और उनका पालन करने के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है। इस संदर्भ में, यह पेपर सीपीयू सूचकांक और ऊर्जा वस्तुओं की कीमतों का उपयोग करके जलवायु नीति अनिश्चितता के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है।

सीपीयू सूचकांक और ऊर्जा वस्तुओं सूचकांक के बीच संबंध समय के साथ बदलता रहता है। मार्च 2017 के आसपास धनात्मक संबंध में संरचनात्मक गिरावट आई जिसके बाद यह ऋणात्मक हो गया। इन बदले हुए गतिकी के कारण भारत में डब्ल्यूपीआई पर जलवायु नीति अनिश्चितता के प्रभाव की अलग-अलग विकसित गतिकी भी सामने आई है।

निष्कर्षों के महत्वपूर्ण नीतिगत प्रभाव हैं। सबसे पहले, हरित ऊर्जा संक्रमण से संबंधित नीतियों को तैयार करते समय जलवायु नीतियों के ऊर्जा मूल्यों पर प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा, जबकि जलवायु नीति का विभिन्न अन्य चैनलों के माध्यम से भारत की वृहद अर्थव्यवस्था पर प्रभाव हो सकता है, ब्राउन ऊर्जा मूल्यों के माध्यम से घरेलू डब्ल्यूपीआई में नीति अनिश्चितता के पारित होने के चैनल में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। मध्यम अवधि में, भारत को वैश्विक नीतिगत कार्रवाइयों से लाभ हो सकता है क्योंकि इनका वैश्विक ऊर्जा मूल्यों पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है। हालाँकि, इन चरों के बीच संबंध लगातार विकसित हो रहा है और इसकी नियमित निगरानी की आवश्यकता है। वर्तमान विश्लेषण ऊर्जा सूचकांक पर सीपीयू के प्रभाव पर समग्र रूप से विचार करता है। विभिन्न प्रकार के ऊर्जा स्रोतों की कीमतों पर सीपीयू के प्रभाव की विविधता भविष्य के शोध के लिए एक संभावित दिशा हो सकती है।

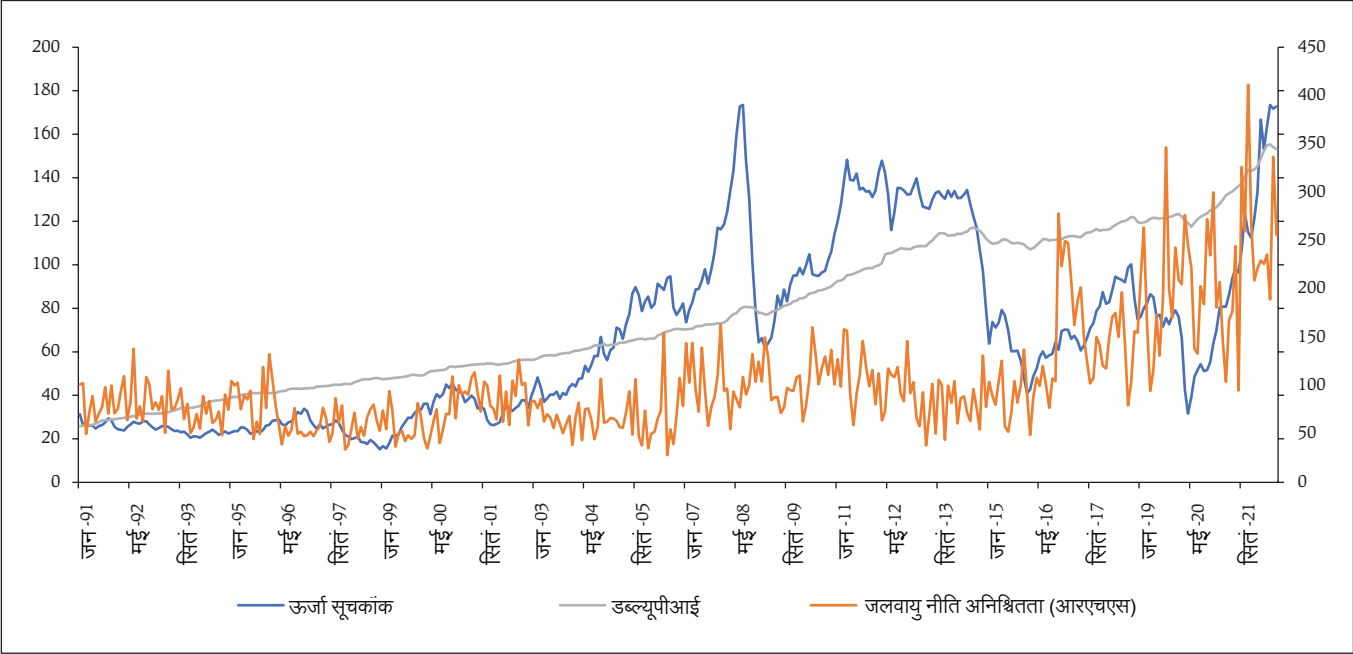
संदर्भ:

- Adediran, I. A., Isah, K. O., Ogbonna, A. E., & Badmus, S. K. (2023). A global analysis of the macroeconomic effects of climate change. *Asian Economics Letters*, 4
- Ardia, D., Bluteau, K., Boudt, K., & Inghelbrecht, K. (2023). Climate change concerns and the performance of green vs. brown stocks. *Management Science*, 69(12), 7607-7632.
- Baker, S. R., Bloom, N., & Davis, S. J. (2016). Measuring economic policy uncertainty. *The Quarterly Journal of Economics*, 131(4), 1593-1636.
- Bernanke, B. S. (1983). Irreversibility, uncertainty, and cyclical investment. *The Quarterly Journal of Economics*, 98(1), 85-106.
- Bolton, P., & Kacperczyk, M. (2021). Do investors care about carbon risk?. *Journal of Financial Economics*, 142(2), 517-549.
- Bouri, E., Iqbal, N., & Klein, T. (2022). Climate policy uncertainty and the price dynamics of green and brown energy stocks. *Finance Research Letters*, 47, 102740.
- Blyth, W., Bradley, R., Bunn, D., Clarke, C., Wilson, T., & Yang, M. (2007). Investment risks under uncertain climate change policy. *Energy Policy*, 35(11), 5766-5773.
- Delis, M. D., De Greiff, K., & Ongena, S. (2019). Being stranded with fossil fuel reserves? Climate policy risk and the pricing of bank loans. *Climate Policy Risk and the Pricing of Bank loans* (September 10, 2019). EBRD Working Paper, (231).
- Dixit, R. K., Dixit, A. K., & Pindyck, R. S. (1994). *Investment under uncertainty*. Princeton university press.
- Gavriilidis, K. (2021). Measuring climate policy uncertainty. Available at SSRN 3847388.
- Fuss, S., Johansson, D. J., Szolgayova, J., & Obersteiner, M. (2009). Impact of climate policy uncertainty on the adoption of electricity generating technologies. *Energy Policy*, 37(2), 733-743.

- Dai, Z., & Zhang, X. (2023). Climate policy uncertainty and risks taken by the bank: evidence from China. *International Review of Financial Analysis*, 87, 102579.
- Diaz-Rainey, I., Gehricke, S. A., Roberts, H., & Zhang, R. (2021). Trump vs. Paris: The impact of climate policy on US listed oil and gas firm returns and volatility. *International Review of Financial Analysis*, 76, 101746.
- He, M., & Zhang, Y. (2022). Climate policy uncertainty and the stock return predictability of the oil industry. *Journal of International Financial Markets, Institutions and Money*, 81, 101675.
- Kettunen, J., Bunn, D. W., & Blyth, W. (2011). Investment propensities under carbon policy uncertainty. *The Energy Journal*, 32(1).
- Lopez, J. M. R., Sakhel, A., & Busch, T. (2017). Corporate investments and environmental regulation: The role of regulatory uncertainty, regulation-induced uncertainty, and investment history. *European Management Journal*, 35(1), 91-101.
- Meng, K. C. (2017). Using a free permit rule to forecast the marginal abatement cost of proposed climate policy. *American Economic Review*, 107(3), 748-784.
- Pástor, L., Stambaugh, R. F., & Taylor, L. A. (2021). Sustainable investing in equilibrium. *Journal of Financial Economics*, 142(2), 550-571.
- Pástor, L., Stambaugh, R. F., & Taylor, L. A. (2022). Dissecting green returns. *Journal of Financial Economics*, 146(2), 403-424.
- RBI (2023), Report on Currency and Finance 2022-23, Towards a Greener Cleaner India.
- Ren, X., Zhang, X., Yan, C., & Gozgor, G. (2022). Climate policy uncertainty and firm-level total factor productivity: Evidence from China. *Energy Economics*, 113, 106209.
- Ren, X., Li, J., He, F., & Lucey, B. (2023). Impact of climate policy uncertainty on traditional energy and green markets: Evidence from time-varying granger tests. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 173, 113058.
- Schlenker, W., & Taylor, C. A. (2021). Market expectations of a warming climate. *Journal of financial economics*, 142(2), 627-640.
- Tian, H., Long, S., & Li, Z. (2022). Asymmetric effects of climate policy uncertainty, infectious diseases-related uncertainty, crude oil volatility, and geopolitical risks on green bond prices. *Finance Research Letters*, 48, 103008.
- Treepongkaruna, S., Chan, K. F., & Malik, I. (2023). Climate policy uncertainty and the cross-section of stock returns. *Finance Research Letters*, 103837.
- Zhou, D., Siddik, A. B., Guo, L., & Li, H. (2023). Dynamic relationship among climate policy uncertainty, oil price and renewable energy consumption—findings from TVP-SV-VAR approach. *Renewable Energy*, 204, 722-732.

अनुबंध

चार्ट ए1: तीन सूचकांकों की समय श्रृंखला



सारणी ए2: ऊर्जा सूचकांक और सीपीयू के बीच संबंध में संरचनात्मक विराम के लिए सुप्रीमम वाल्ड परीक्षण

ऊर्जा सूचकांक	
सीपीयू सूचकांक	0.0065 (0.0173)
स्थिरांक	-0.0001 (0.0030)
एन	372
*पी < 0.1, **पी < 0.05, ***पी < 0.01.	

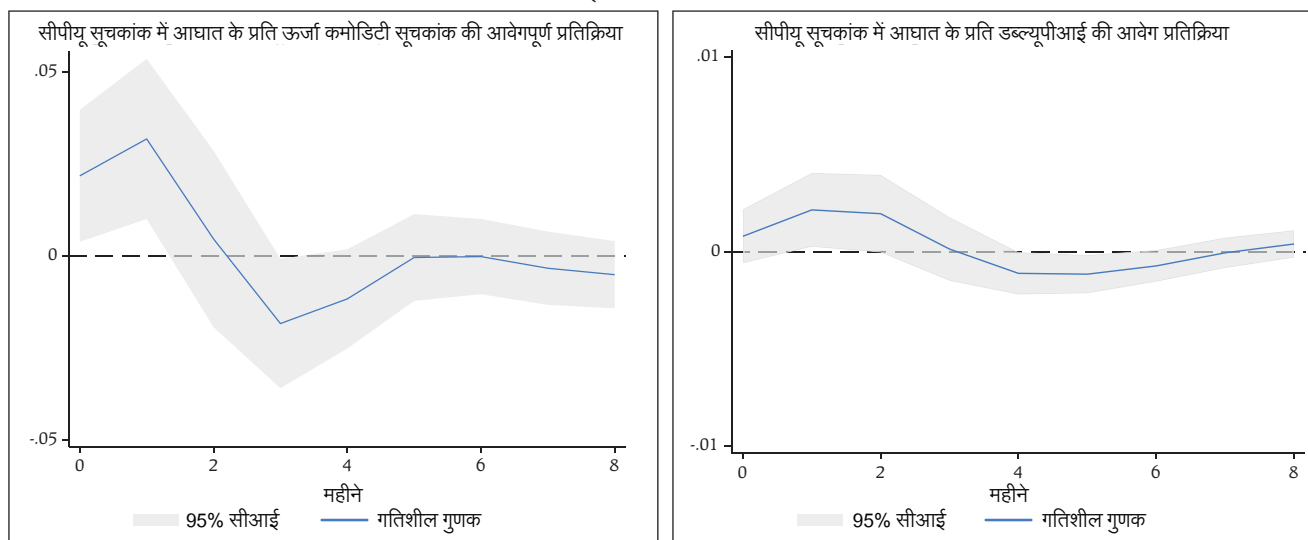
पूर्ण नमूना:	1991m5 - 2022m4	
अनुमानित विराम तिथि	2017m3	
एचओ:	कोई संरचनात्मक ब्रेक नहीं	
परीक्षा	सांख्यिकीय	पी-मूल्य
स्वाल्ड	31.5702	0.0000
बहिर्जात चर:	सीपीयू इंडेक्स	
सीपीयू इंडेक्स:	सीपीयू इंडेक्स; स्थिर	

वैकल्पिक विनिर्देशों से परिणाम (जी20 अर्थव्यवस्थाओं के लिए ओईसीडी समग्र आर्थिक संकेतक शामिल हैं)

1. सीपीयू सूचकांक के चक्रों के साथ वीएआरेक्स मॉडल का उपयोग बहिर्जात आघात के रूप में किया जाता है

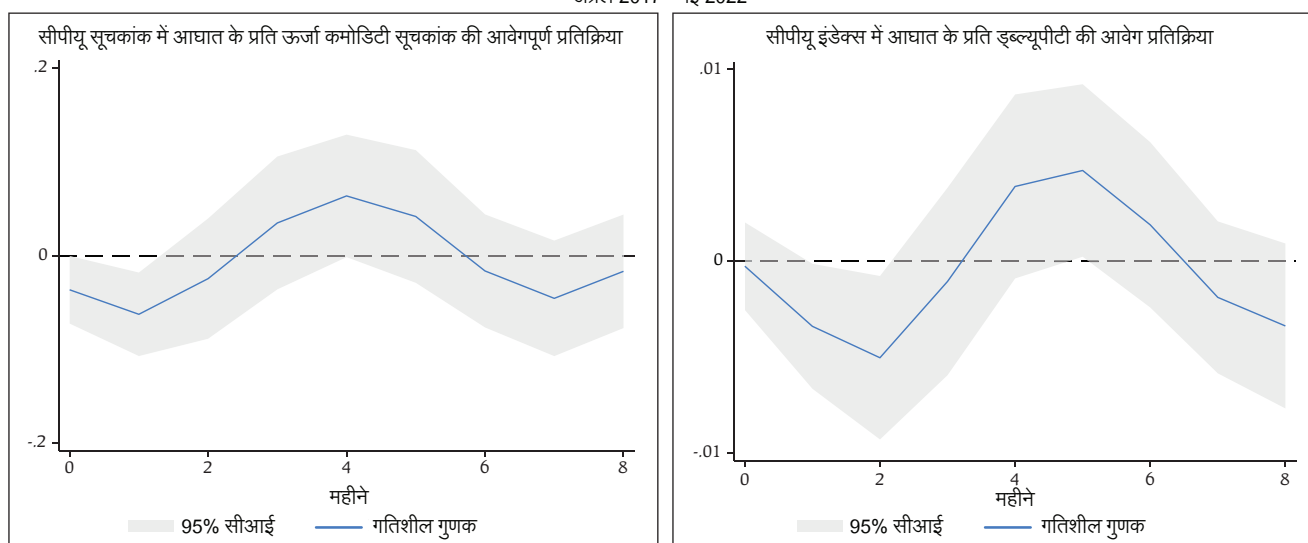
चार्ट ए2: मार्च 2017 से पहले सीपीयू इंडेक्स, ऊर्जा सूचकांक और डब्ल्यूपीआई के बीच संबंध

मई -1991 - मार्च 2017



चार्ट ए3: मार्च 2017 के बाद सीपीयू इंडेक्स, ऊर्जा सूचकांक और डब्ल्यू के बीच संबंध

अप्रैल 2017 - मई 2022



परिणाम एलएलपी का उपयोग करके प्राप्त परिणामों के समान हैं, यद्यपि 2017 के बाद की अवधि के गुणांक बढ़ते विश्वास अंतराल के कारण सांख्यिकीय रूप से कम महत्वपूर्ण हैं।

1. चॉलेस्की ऑर्डरिंग के साथ एसवीएआर

तीन चरों, अर्थात् सीपीयू सूचकांक, ऊर्जा वस्तुओं मूल्य सूचकांक और डब्ल्यूपीआई का उपयोग करके एक संरचनात्मक वीएआर का अनुमान लगाया जाता है। प्रतिगमन का संरचनात्मक रूप इस प्रकार है:

$$B_0 y_t = A + B_1 y_{t-1} + B_2 y_{t-2} + B_3 y_{t-3} + \dots B_s y_{t-s} + u_t$$

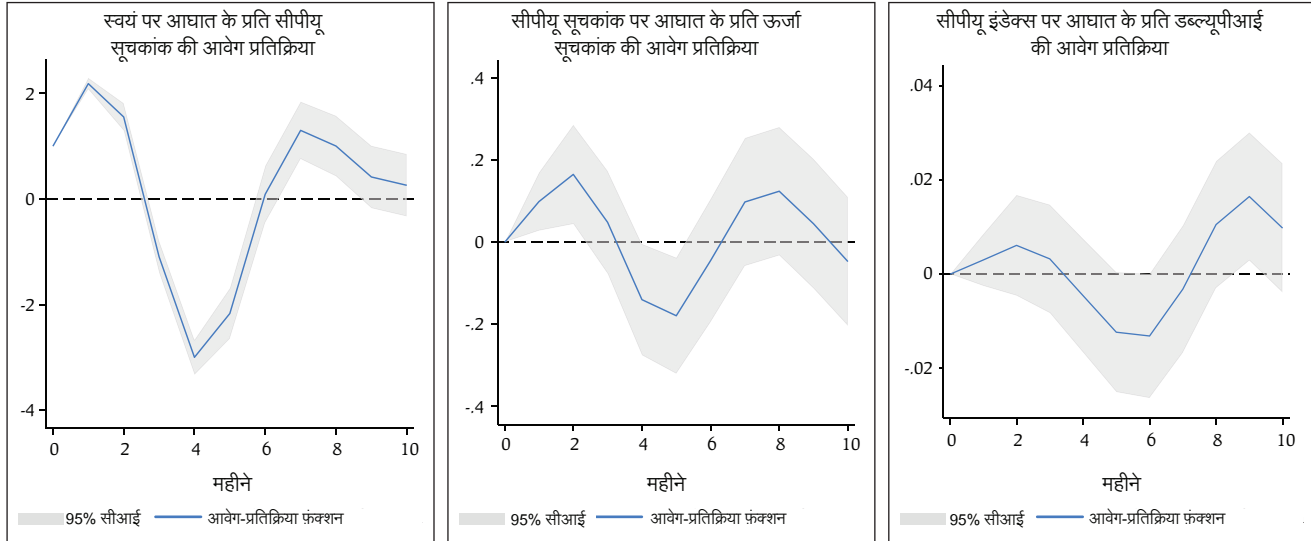
जहाँ y t चरों का एक $n \times 1$ सदिश है, A स्थिरांकों का एक $n \times 1$ सदिश है, B s गुणांकों का एक $n \times n$ मैट्रिक्स है जहाँ $s = 1, 2, 3, \dots, p$ अंतरालों की संख्या है, और u t संरचनात्मक गड़बड़ी का एक $n \times 1$ सदिश है।

हम पहचान के लिए चोल्स्की अपघटन को मानते हैं। इसलिए, पहचान योजना निम्नलिखित है:

$$\begin{bmatrix} u_t^{CPU} \\ u_t^{Global Activity Index} \\ u_t^{Energy Index} \\ u_t^{WPI} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{11} & 0 & 0 & 0 \\ b_{21} & b_{22} & 0 & 0 \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} & 0 \\ b_{41} & b_{42} & b_{43} & b_{44} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \epsilon_t^{CPU} \\ \epsilon_t^{Global Activity Index} \\ \epsilon_t^{Energy Index} \\ \epsilon_t^{WPI} \end{bmatrix}$$

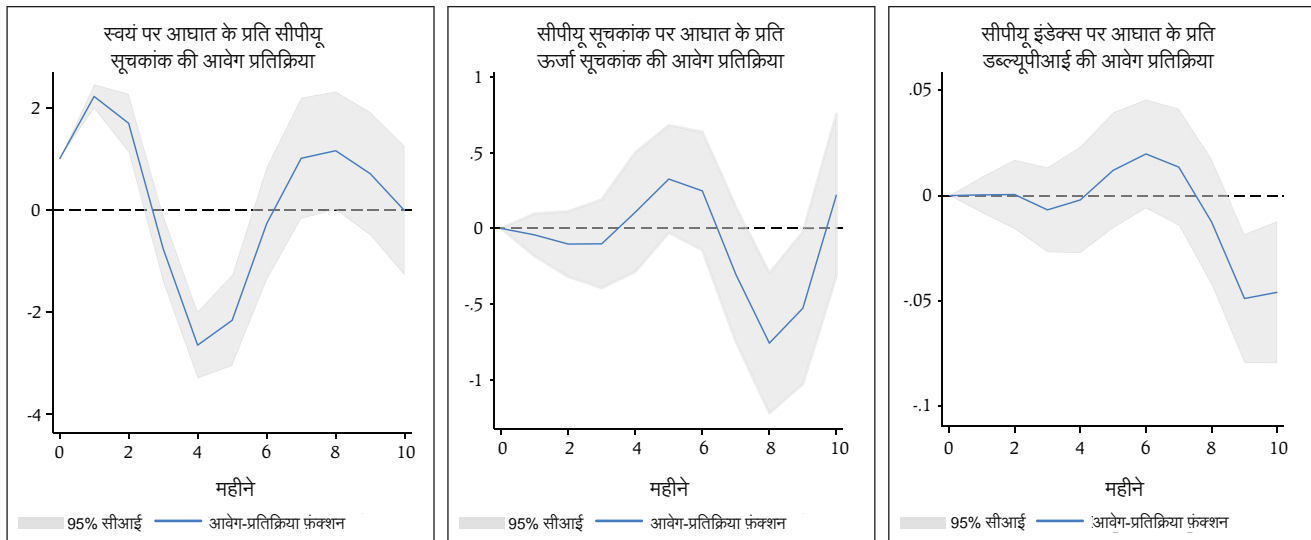
चार्ट ए4: मार्च 2017 से पहले सीपीयू इंडेक्स, ऊर्जा सूचकांक और डब्ल्यूपीआई के बीच संबंध

मई -1991 - मार्च 2017



चार्ट ए5: मार्च 2017 के बाद सीपीयू इंडेक्स, एनर्जी इंडेक्स और डब्ल्यूपीआई के बीच संबंध

अप्रैल -2017 - मई 2022



एसवीएआर मॉडल से प्राप्त परिणाम एलएलपी से प्राप्त परिणामों के समान हैं, लेकिन व्यापक विश्वास अंतराल के कारण इनका सांख्यिकीय महत्व कम है।

भारत में ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास: अंतर को पाटना

सौरज्योति सरदार, मनु स्वर्णकार, अयान पॉल और तुषार बी दास द्वारा ^

रिजर्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के बारे में ग्रामीण रुझानों को सम्मिलित रूप से समझने के लिए 2022 में ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (आरसीसीएस) की शुरुआत की। सर्वेक्षण से पता चलता है कि सामान्य आर्थिक और रोजगार स्थितियों की धारणाओं में सुधार हुआ है जिसमें भविष्य के दृष्टिकोण लगातार आशावादी हैं। अविरत चिंताओं के बावजूद, परिवार भविष्य की आय और लचीले खर्च व्यवहार में मजबूत विश्वास प्रदर्शित करते हैं। मुद्रास्फीति की धारणाएँ और प्रत्याशाएँ उच्च बनी हुई हैं, लेकिन उनमें एक नरमी की प्रवृत्ति दिखती है। वर्तमान स्थिति सूचकांक में लगातार सुधार हुआ है, जबकि भविष्य का प्रत्याशा सूचकांक स्थिर आशावाद दर्शाता है। आरसीसीएस ग्रामीण आवाज़ को सबसे आगे लाकर नीति निर्माण दृष्टिकोण को समृद्ध करता है, उनकी उभरती प्रत्याशाओं और आर्थिक लचीलेपन को उजागर करता है।

परिचय

भारत के आर्थिक परिदृश्य में, 'ग्रामीण' क्षेत्र एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो देश की वृद्धि और विकास को गति देता है। भारतीय ग्रामीण बाजारों का महत्व इस तथ्य से स्पष्ट है कि लगभग 56-60 प्रतिशत जीडीपी, 53 प्रतिशत तेजी से बढ़ती उपभोक्ता वस्तुओं की मांग और 59 प्रतिशत उपभोक्ता टिकाऊ मांग ग्रामीण क्षेत्रों से उत्पन्न होती है (अंकारानी, फैबियो, तथा अन्य., 2014)। भारत की ग्रामीण आबादी संस्कृति, सामाजिक-आर्थिक स्थिति

^ लेखक भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और आरबीआई के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

1 भारतीय रिजर्व बैंक की बैंकिंग अवसंरचना सूचना प्रणाली (सीआईएसबीआई) से जनसंख्या समूहों का वर्गीकरण, जैसे ग्रामीण, अर्ध-शहरी, शहरी और महानगरीय, प्राप्त किया जाता है। 9,999 तक की आबादी वाले क्षेत्रों को 'ग्रामीण' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, 10,000 से 99,999 तक की आबादी को 'अर्ध-शहरी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, 1,00,000 से 9,99,999 की आबादी को 'शहरी' के रूप में नामित किया गया है, और 10 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले क्षेत्रों को 'महानगरीय' के रूप में नामित किया गया है। आरबीआई द्वारा किए गए शहरी सर्वेक्षण, अर्थात् आईईएसएच और सीसीएस, शहरी और महानगरीय केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि आरसीसीएस विशेष रूप से ग्रामीण और अर्ध-शहरी स्थानों में किए जाते हैं।

और भौगोलिक विस्तार में विविधतापूर्ण है और अर्थव्यवस्था के बारे में ग्रामीण और अर्ध-शहरी परिवारों की भावना आर्थिक दृष्टिकोण, क्रय व्यवहार और समग्र कल्याण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है।

रिजर्व बैंक उपभोक्ता रुझानों का आकलन करने के लिए परिवारों के मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण (आईईएसएच) और उपभोक्ता विश्वास सर्वेक्षण (सीसीएस) जैसे घरेलू सर्वेक्षण आयोजित करता रहा है। हालाँकि, ये प्रयास मुख्य रूप से शहरी उपभोक्ताओं पर केंद्रित रहे हैं। सितंबर 2022 में द्वि-मासिक आरसीसीएस शुरू करके गैर-शहरी क्षेत्रों में घरेलू सर्वेक्षणों का दायरा बढ़ाया गया। सर्वेक्षण में ग्रामीण उपभोक्ताओं की आय और व्यय पैटर्न, मौजूदा मूल्य स्थिति और व्यापक आर्थिक वातावरण तथा रोजगार दृष्टिकोण पर उनकी भावनाओं के बारे में उनकी धारणाओं को स्पष्ट किया गया है। सर्वेक्षण का डिजाइन और कार्यान्वयन सर्वेक्षणों पर तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएस) के मार्गदर्शन में किया गया।

यह आलेख अब तक एकत्र किए गए आरसीसीएस डेटा के आधार पर वर्णनात्मक सांख्यिकी के संदर्भ में पृष्ठभूमि, सर्वेक्षण पद्धति और परिणामों का संक्षिप्त अवलोकन प्रदान करता है। शेष आलेख निम्नानुसार सुव्यवस्थित किया है। आलेख का खंड II आरसीसीएस के विकास पर पृष्ठभूमि प्रदान करता है। बाद के खंडों में सर्वेक्षण पद्धति और दायरे (खंड III) और सर्वेक्षण परिणामों की प्रस्तुति (खंड IV) का विस्तृत अवलोकन शामिल है। प्रमुख निष्कर्षों का सारांश देकर और खंड V में उनके नीतिगत निहितार्थों पर चर्चा करके लेख का समापन होता है।

II. पृष्ठभूमि

रिजर्व बैंक ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए घरेलू सर्वेक्षणों के विस्तार की संभावना तलाश रहा है और मार्च 2022 में, ग्रामीण क्षेत्रों में भी सीसीएस के कवरेज का विस्तार करने का निर्णय लिया गया। इसके बाद, विभिन्न मैक्रो मापदंडों पर ग्रामीण उपभोक्ताओं की भावनाओं को इकट्ठा करने के लिए एक मसौदा प्रश्नावली तैयार की गई। शहरी घरेलू सर्वेक्षणों के लगभग समान एक संभावित नमूना डिजाइन और एक विस्तृत नमूना फ्रेम के साथ, इस पर बैंक की टीएसीएस की कई बैठकों के दौरान विचार-विमर्श किया गया और ऑन-फील्ड

कार्यान्वयन के लिए अंतिम रूप दिया गया (टीएसीएस पर चर्चा के लिए अनुलग्नक 1 देखें)।

सर्वेक्षण प्रश्नावली की प्रभावशीलता की जांच करने के लिए जून 2022 के अंतिम सप्ताह के दौरान पुणे जिले के अंतर्गत मालवली गांव में एक प्रायोगिक सर्वेक्षण किया गया था। एकत्रित अंतर्दृष्टि के आधार पर, प्रश्नावली को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया और जुलाई 2022 में आरसीसीएस का एक अन्वेषणात्मक दौर शुरू किया गया। अन्वेषणात्मक दौर से प्राप्त सबक, जैसे शहरी सर्वेक्षणों की तुलना में अधिक समय की आवश्यकता, कई गांवों में लक्ष्य नमूना आकार को प्राप्त करने में चुनौतियां और 2011 की जनगणना से उपलब्ध आंकड़ों से जमीनी स्थिति में बेमेलता को नमूनाकरण रणनीति को संशोधित करने के लिए ध्यान में रखा गया।

संशोधित नमूनाकरण रणनीति के आधार पर, पहला पायलट सर्वेक्षण सितंबर 2022 में शुरू किया गया था, जिसमें 19 राज्यों के 42 जिलों को शामिल किया गया था, जिसका लक्ष्य नमूना आकार 6,100 था। जिलों का चयन आरबीआई कार्यालयों के आस-पास की पहुंच योग्य परिधि में किया गया था, जिससे एजेंसी के जांचकर्ता सर्वेक्षण करने के स्थानों पर आराम से यात्रा कर सकें और आरबीआई के अधिकारी समय पर सत्यापन पूरा कर सकें, जिससे डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। नमूनाकरण फ्रेम ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों के बीच लगातार 3:2 अनुपात बनाए रखा। विविधता सुनिश्चित करने के लिए एक गाँव से प्रतिक्रियाएँ एकत्र करने के इरादे से प्रत्येक ग्रामीण या अर्ध-शहरी केंद्र में साक्षात्कारों की लक्षित संख्या 15 निर्धारित की गई थी। सर्वेक्षण में एक राज्य के भीतर जिलों के एक निश्चित पैल का इस्तेमाल किया गया।

सितंबर 2022, नवंबर 2022 और जनवरी 2023 में तीन प्रायोगिक दौर आयोजित किए गए। इसके अलावा, सामान्य प्रायोगिक सर्वेक्षण दौरों के साथ-साथ दोहराए गए सर्वेक्षणों के दो दौर मई और जुलाई 2023 में आयोजित किए गए, जिसमें पिछले दौरों के दौरान सर्वेक्षण में भाग लेने वाले उत्तरदाताओं से एक ही प्रश्नावली ली गई ताकि सभी दौरों में 'प्रतिक्रिया स्थिरता' का परीक्षण किया जा सके। दोहराए गए सर्वेक्षणों के परिणाम लगभग सभी मापदंडों के लिए संबंधित प्रायोगिक सर्वेक्षण दौरों के साथ संगति दर्शाते हैं। शहरी सर्वेक्षणों के समान पहले से ही परीक्षण

की गई सत्यापन प्रक्रियाओं के माध्यम से डेटा गुणवत्ता पहलू भी सुनिश्चित किया गया था।

सितंबर 2023 में, आरसीसीएस पायलट राउंड की समीक्षा के बाद सर्वेक्षण कवरेज का विस्तार किया गया था। प्रतिनिधित्व में सुधार के लिए नमूना फ्रेम में सात अतिरिक्त राज्य जोड़े गए, जिससे लक्षित नमूना आकार 8,100 हो गया। एक साल बाद, कवरेज को चार पूर्वोत्तर राज्यों जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख सहित पांच नए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) तक बढ़ा दिया गया, जिसमें 500 अतिरिक्त परिवारों को लक्षित किया गया। इन अतिरिक्त नमूनों और मौजूदा राज्यों में नमूनों को और जोड़ने के साथ, ग्रामीण सर्वेक्षण अब 100 जिलों के 610 गांवों के 9000 परिवारों को शामिल करता है, जो सभी 28 भारतीय राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करता है और द्वि-मासिक आधार पर आयोजित किया जाता है।

आंकड़ों की गुणवत्ता और स्थिरता सहित सर्वेक्षण प्रक्रिया के गहन परीक्षण के एक भाग के रूप में, कठोर सांख्यिकीय डेटा लेखा परीक्षा (एसडीए) करने का कार्य आईएसआई, कोलकाता को सौंपा गया था (अनुबंध 2)। डेटा लेखा परीक्षा के निष्कर्षों ने सर्वेक्षण की मजबूती की पुष्टि की। सर्वेक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने के सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया तथा सर्वेक्षण प्रत्युत्तरों की बेहतर अभिव्यक्ति और समझ के लिए कंप्यूटर सहायता प्राप्त व्यक्तिगत साक्षात्कार (सीएपीआई) स्क्रिप्ट में संशोधन किए गए।

डेटा की गुणवत्ता पर उचित परिश्रम और विभिन्न दौरों में परिणामों में स्थिरता के अवलोकन के बाद, यह निर्णय लिया गया कि आरसीसीएस से डेटा विभिन्न हितधारकों की आसान पहुंच के लिए सार्वजनिक डोमेन में जारी किया जाएगा। यह सार्वजनिक डोमेन में सूचना प्रसारित करने की प्रथा के अनुरूप है, जैसा कि रिजर्व बैंक द्वारा किए गए अन्य सर्वेक्षणों के मामले में है।

III. सर्वेक्षण ढांचा और कार्यप्रणाली अवलोकन

III.1 प्रश्नावली और संबंधित विवरण

आरसीसीएस प्रश्नावली दो प्रमुख शहरी सर्वेक्षणों अर्थात् सीसीएस और आईईएसएच के सर्वेक्षण कार्यक्रमों से तैयार की गई है। चार अलग-अलग ब्लॉक में संरचित, प्रश्नावली का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी उत्तरदाताओं से व्यापक जानकारी एकत्र

करना है। प्रश्नों की सटीक प्रकृति और मूल्यांकन के तरीकों के बारे में विवरण के लिए सर्वेक्षण प्रश्नावली अनुलग्नक 3 में दी गई है।

प्रश्नावली के ब्लॉक I में आवश्यक जनसांख्यिकीय विवरण, कमाने वाले सदस्यों की संख्या, औसत मासिक आय और कृषि भूमि का कब्जा शामिल है। ब्लॉक II सामान्य आर्थिक स्थितियों, रोजगार दृष्टिकोण और मुद्रास्फीति सहित मूल्य स्तरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अर्थव्यवस्था पर उत्तरदाताओं के विचारों और प्रत्याशाओं का पूरक है। ब्लॉक III प्रतिभागियों की अपने घर की आय और खर्च के बारे में धारणाओं और प्रत्याशाओं पर गहराई से चर्चा करता है। तीन-बिंदु पैमाने का उपयोग करते हुए, उत्तरदाता एक साल पहले की तुलना में वर्तमान स्थिति और अगले वर्ष के लिए उनकी प्रत्याशाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं। अंत में, प्रश्नावली का ब्लॉक IV मुद्रास्फीति की धारणाओं और प्रत्याशाओं के मात्रात्मक आकलन पर केंद्रित है।

III.2 कवरेज

जुलाई 2024 से, अद्यतन सर्वेक्षण योजना में सभी भारतीय राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 100 से अधिक जिलों को शामिल किया गया है, जिसका लक्ष्य नमूना आकार 9,000 है। नमूना आकार पर पहुंचने के लिए, एक आनुपातिक नमूना योजना का उपयोग किया गया था। इस प्रक्रिया में, प्रत्येक राज्य के भीतर ग्रामीण और अर्ध-शहरी आबादी के संबंधित अनुपात के आधार पर राज्य-स्तरीय नमूना आकार निर्धारित किया गया था। यह नमूना योजना सर्वेक्षण में अधिकांश राज्यों और जनसंख्या की विविधता को शामिल करना सुनिश्चित करती है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर उपभोक्ता भावना सर्वेक्षणों में अद्वितीय प्रयासों में से एक बन जाता है। अनुलग्नक 4 में सारणी ए1 आरसीसीएस द्वारा शामिल किए गए राज्यों की एक व्यापक सूची उनके संबंधित लक्ष्य नमूना आकारों के साथ प्रदान करती है।

III.3 नमूनाकरण योजना

आरसीसीएस नमूनाकरण योजना शहरी सर्वेक्षणों के समान दो-चरणीय दृष्टिकोण अपनाती है। दो-चरणीय नमूनाकरण योजना के अनुरूप, डेटा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित समय के भीतर सत्यापन पूरा करने का प्रतिनिधित्व और व्यवहार्यता दोनों को ध्यान में रखते हुए एक राज्य के भीतर जिलों के एक निश्चित समूह को पैनलबद्ध किया जाता है। जिलों का चयन इस प्रकार किया गया है कि लक्ष्य नमूना आकार प्राप्त करने

के लिए पर्याप्त ग्रामीण और अर्ध-शहरी केन्द्रों को इसमें शामिल किया जा सके।

पहले चरण में, प्राथमिक नमूनाकरण इकाइयाँ (पीएसयू) जिन्हें 'प्रथम-चरण इकाइयाँ (एफएसयू) भी कहा जाता है, जिनमें ग्रामीण गाँव और अर्ध-शहरी केंद्र शामिल होते हैं, और जो जिले के भीतर एक व्यवस्थित यादृच्छिक नमूनाकरण तकनीक के माध्यम से चुने जाते हैं। ग्रामीण और अर्ध-शहरी केंद्रों का चयन बैंकिंग बुनियादी ढांचे के न्यूनतम स्तर की मौजूदगी के आधार पर किया जाता है ताकि दूसरे चरण की इकाइयों (एसएसयू), अर्थात् परिवारों के लिए पर्याप्त संख्या में नमूने सुनिश्चित किए जा सकें। यदि कोई चुना गया गाँव प्रतिबंधित क्षेत्र में आता है, तो नमूना प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखने के लिए निकटतम संभव गाँव का चयन किया जाता है।

प्रत्येक चयनित गांव या अर्ध-शहरी केंद्रों में 15 परिवारों का साक्षात्कार लिया जाता है। प्रारंभिक परिवार को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, और बाद के परिवारों को दाहिने हाथ के नियम का उपयोग करके चुना जाता है, प्रत्येक सफल साक्षात्कार के बाद पांच परिवारों को स्किप किया जाता है, जिससे केंद्र के भीतर नमूने का प्रसार सुनिश्चित होता है। साक्षात्कार के लिए अगले उपलब्ध परिवार का चयन करके गैर-प्रतिक्रिया स्थितियों का प्रबंधन किया जाता है। बहुमंजिला इमारतों या अपार्टमेंट में, प्रति इमारत अधिकतम दो साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं।

III.4 कार्यप्रणाली

III.4.ए शुद्ध प्रतिक्रिया और सारांश सूचकांक

पारंपरिक जनमत सर्वेक्षणों में, उत्तरदाताओं को आम तौर पर तीन विकल्प दिए जाते हैं, जैसे, वृद्धि, यथास्थिति और घटा। तीनों की व्याख्या करना चुनौतीपूर्ण, बल्कि समझना मुश्किल हो सकता है। इसलिए, विचाराधीन पैरामीटर की गति की सामान्य समझ के लिए एक एकल मात्रात्मक उपाय पर पहुंचना आवश्यक है। इस परिवर्तन के लिए एक सामान्य तरीका 'निवल प्रतिक्रियाओं' के माध्यम से है, जिसे 'बकाया' या 'निवल बकाया' के रूप में भी जाना जाता है। इस मीट्रिक की गणना बिगड़ती (नकारात्मक) रिपोर्ट करने वाले उत्तरदाताओं के प्रतिशत को सुधार (सकारात्मक) रिपोर्ट करने वाले प्रतिशत से घटाकर की जाती है और यह -100 से +100 तक हो सकती है।

आरसीसीएस में, दो अलग-अलग समय क्षितिजों पर उपभोक्ता विश्वासों को दर्शाने वाले दो प्रमुख सूचकांक अर्थात एक वर्ष पहले की तुलना में वर्तमान धारणाओं को दर्शानेवाला वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई) और आगामी वर्ष की प्रत्याशाओं को दर्शानेवाला भविष्य प्रत्याशा सूचकांक (एफईआई) प्राप्त करने के लिए 'निवल प्रतिक्रिया' का उपयोग किया जाता है। दोनों सारांश सूचकांकों की गणना के लिए निम्न सूत्र का अनुसरण किया जाता है:

समग्र सूचकांक = 100 + औसत (चयनित कारकों की निवल प्रतिक्रिया),

जहाँ, निवल प्रतिक्रिया = सकारात्मक धारणा (प्रतिशत में) - नकारात्मक धारणा (प्रतिशत में)

विभिन्न कारकों, जैसे आर्थिक स्थिति, रोजगार, मूल्य स्तर, आय और व्यय पर वर्तमान धारणाओं पर औसत निवल प्रतिक्रियाओं का उपयोग सीएसआई की गणना के लिए किया जाता है, जबकि इन कारकों पर आने वाले वर्ष की प्रत्याशाओं पर औसत निवल प्रतिक्रियाओं का उपयोग एफईआई की गणना के लिए किया जाता है। सीएसआई और एफईआई की सीमा 0 से 200 के बीच होती है, जिसमें 100 से नीचे के सूचकांक मूल्य निराशावाद को दर्शाते हैं और 100 से ऊपर के आंकड़े आशावाद का संकेत देते हैं

III.4.बी माध्यिका मूल्यों का अनुमान

मात्रात्मक मुद्रास्फीति धारणाओं और प्रत्याशाओं के लिए औसत मूल्यों का एकत्रीकरण प्रतिस्थापन के साथ दो-चरणीय सरल यादृच्छिक नमूनाकरण का उपयोग करता है, जिसे K बार दोहराया जाता है। प्रत्येक पुनरावृत्ति में, मुद्रास्फीति धारणाओं/प्रत्याशाओं का औसत मूल्य की पुनः नमूना किए गए डेटा से गणना की जाती है। इन K औसत मूल्यों का अंकगणितीय माध्य कुल मुद्रास्फीति धारणाओं/प्रत्याशाओं के रूप में गणना की जाती है। इन K औसत मूल्यों और उनके अंकगणितीय माध्य का उपयोग करके, कुल-स्तरीय मानक त्रुटि की गणना बाद में की जाती है।

$$\hat{Y} = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K \hat{Y}_k \quad (I)$$

$$SE(\hat{Y}) = \sqrt{\frac{1}{K-1} \sum_{k=1}^K (\hat{Y}_k - \hat{Y})^2} \quad (II)$$

कार्यप्रणाली को स्पष्ट करने के बाद, इस लेख का शेष भाग सर्वेक्षण के परिणाम प्रस्तुत करता है।

IV. सर्वेक्षण परिणाम²

IV.1 उत्तरदाताओं का प्रोफाइल

मार्च 2025 का सर्वेक्षण दौर विभिन्न राज्यों में उल्लेखनीय विविधताओं के साथ पुरुष-से-महिला उत्तरदाता अनुपात 3:2 दर्शाता है। सर्वेक्षण में शामिल लगभग 83 प्रतिशत परिवारों ने मासिक घरेलू आय ₹25,000 से कम बताई, जबकि लगभग 5 प्रतिशत ने ₹50,000 मासिक से अधिक आय की सूचना दी (चार्ट 1ए)। शिक्षा योग्यता के संदर्भ में, लगभग 60 प्रतिशत ने 10वीं कक्षा पूरी की, जिनमें से लगभग 40 प्रतिशत डिग्री या उच्च शिक्षा प्राप्त थे। गृहिणी और स्व-नियोजित व्यक्ति, जो कुल मिलाकर 50 प्रतिशत से अधिक थे, प्रमुख व्यावसायिक समूह थे, जिनमें दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी उत्तरदाताओं की तीसरी सबसे बड़ी श्रेणी का प्रतिनिधित्व करते थे (चार्ट 1बी)। 30 प्रतिशत से अधिक परिवारों के पास आय-उत्पादक कृषि भूमि थी। विस्तृत जनसांख्यिकीय वितरण अनुलग्नक 4 में सारणी ए2 में दिया गया है

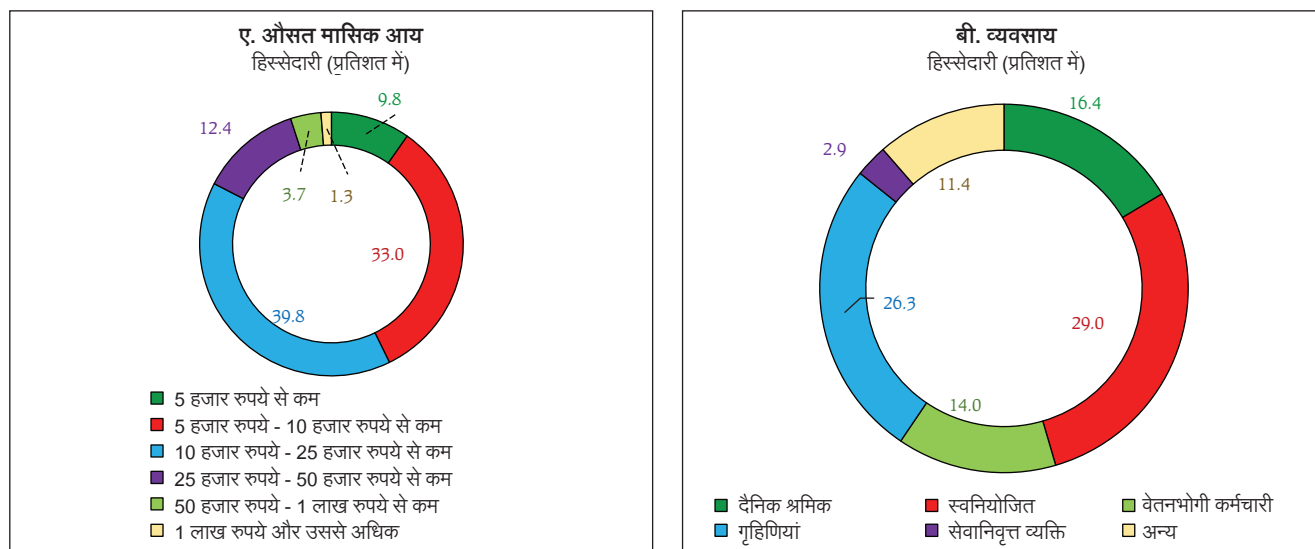
IV.2 समष्टि आर्थिक स्थितियों पर विचार

IV.2.ए सामान्य आर्थिक स्थिति

ग्रामीण और अर्ध-शहरी परिवारों ने सितंबर 2022 में समग्र आर्थिक स्थिति के बारे में अपनी धारणाओं के बारे में उल्लेखनीय रूप से नकारात्मक भावना (-27.7) व्यक्त की, जो मुख्य रूप से कोविड-19 महामारी के लंबे समय तक चलने वाले संकट का संदर्भ देती है। समय के साथ, उनकी भावना में धीरे-धीरे सुधार होता गया और सितंबर 2023 में पहली बार वह आशावादी बन गई। यह ऊपर की ओर का रुझान मार्च 2024 तक जारी रहा, जो सितंबर 2022 में प्रारंभिक सर्वेक्षण दौर से उल्लेखनीय 43 अंकों की वृद्धि को दर्शाता है। हालाँकि, वर्तमान आर्थिक स्थिति की धारणाएँ उसके बाद कम होने लगीं, जनवरी 2025 के सर्वेक्षण दौर से सुधार दिखाने से पहले निवल प्रतिक्रिया मार्च 2024 में 14.9 से घटकर नवंबर 2024 में 1.1 हो गई।

इन उतार-चढ़ावों के बावजूद, ग्रामीण उत्तरदाताओं ने सर्वेक्षण की शुरुआत से ही एक साल के आर्थिक दृष्टिकोण के

² यह ध्यान दिया जा सकता है कि यहां प्रस्तुत जनसांख्यिकीय और साथ ही सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल सर्वेक्षण उत्तरदाताओं से मेल खाती है और इसे जनसंख्या विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए।

चार्ट 1: उत्तरदाताओं का जनसांख्यिकीय वितरण (मार्च 2025)

स्रोत: आरबीआई की आरसीसीएस; और लेखकों की गणना।

बारे में लगातार आशावाद बनाए रखा। अधिकांश दौरों में, आधे से ज्यादा उत्तरदाताओं ने सामान्य आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई (चार्ट 2; और अनुलग्नक 5 में सारणी बी1)।

IV.2बी रोजगार की स्थिति

रोजगार की स्थितियों के बारे में ग्रामीण और अर्ध-शहरी परिवारों के बीच मौजूदा भावना सामान्य आर्थिक स्थिति में देखी गई भावना के समान पैटर्न को दर्शाती है। सितंबर 2022 में

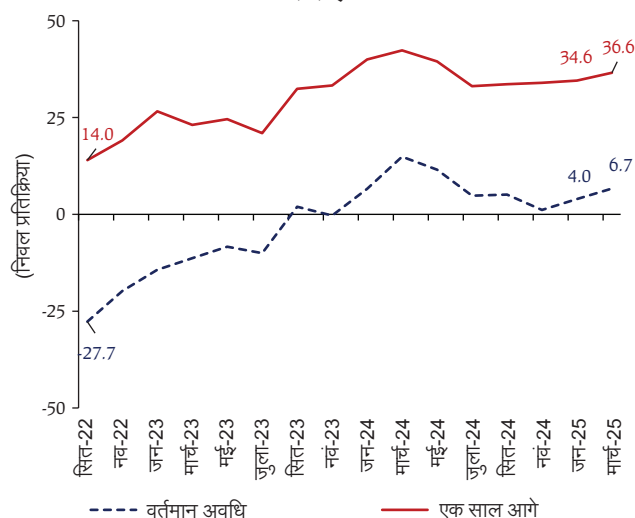
निवल नकारात्मक भावना से शुरू होकर, वर्तमान रोजगार स्थिति की धारणाओं में धीरे-धीरे सुधार होकर 2024 की शुरुआत में सकारात्मक हो गई। यह सुधार मार्च 2024 तक जारी रहा, लेकिन उसके बाद कम होने लगा। जुलाई और नवंबर 2024 के बीच, जनवरी 2025 से आशावादी होने से पहले भावना निराशावादी बनी रही।

भविष्य की ओर देखते हुए, उत्तरदाता रोजगार की स्थिति के लिए एक साल के दृष्टिकोण के बारे में अत्यधिक आशावादी बने हुए हैं। लगातार, आधे से अधिक ग्रामीण उत्तरदाताओं ने भविष्य की रोजगार संभावनाओं के बारे में सकारात्मकता व्यक्त की है, यह आंकड़ा मार्च 2024 से 55 प्रतिशत से अधिक है (चार्ट 3; और अनुलग्नक 5 में सारणी बी2)।

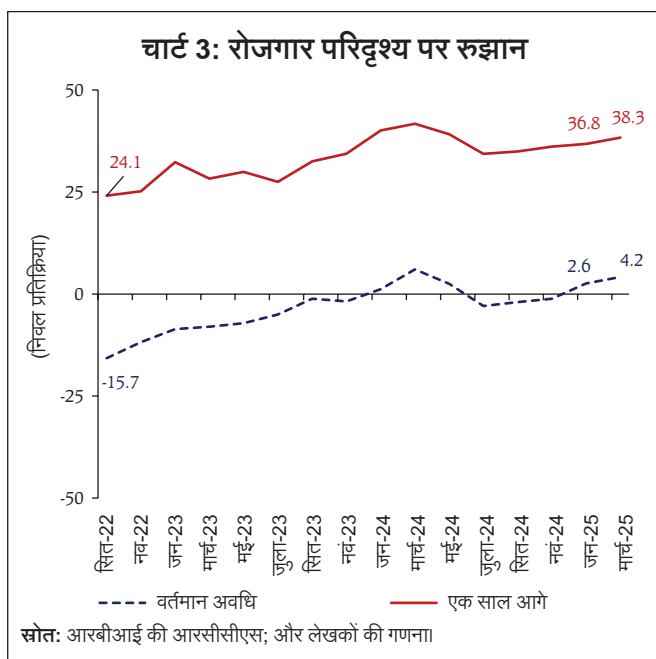
IV.3 परिवारों द्वारा अपनी आय और व्यय की स्थिति का आकलन

IV.3.ए आय परिदृश्य

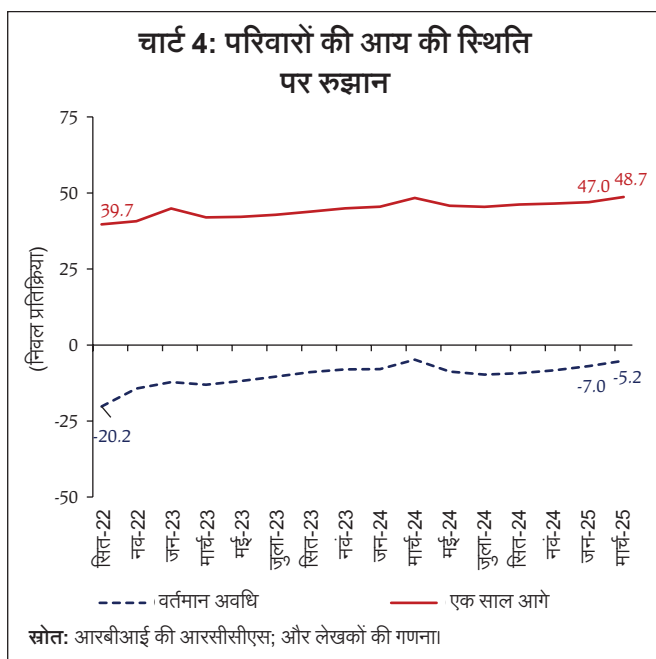
ग्रामीण और अर्ध-शहरी उपभोक्ताओं के बीच उनकी वर्तमान घरेलू आय स्थिति के बारे में भावना निराशावादी क्षेत्र में बनी रही, जिसमें दौरों के दौरान निराशावाद में धीरे-धीरे कमी आई। हालांकि, मई 2024 से, प्रगति धीमी हो गई क्योंकि सबसे हाल के तीन सर्वेक्षण दौरों में कम होने से पहले वर्तमान आय स्थिति के बारे में निराशावाद बढ़ गया।

चार्ट 2: सामान्य आर्थिक स्थिति पर रुझान

स्रोत: आरबीआई की आरसीसीएस; और लेखकों की गणना।



इसके विपरीत, ग्रामीण परिवारों ने सर्वेक्षण अवधि के दौरान भविष्य की आय संभावनाओं पर लगातार अत्यधिक आशावादी दृष्टिकोण बनाए रखा। उल्लेखनीय रूप से, लगभग 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं को अगले वर्ष में अपने घरेलू आय में किसी भी गिरावट की आशंका नहीं है, जो उनकी भविष्य की आय में



मजबूत आत्मविश्वास को दर्शाता है (चार्ट 4; और अनुलग्नक 5 में सारणी बी5)।

जबकि ग्रामीण और अर्ध-शहरी आबादी मौजूदा आय-संबंधी चिंताओं से जूझ रही है, परिवारों के बीच भविष्य की आय प्रक्षेपवक्र के बारे में उत्साहजनक दृष्टिकोण आर्थिक लचीलेपन और आत्मविश्वास की एक आशाजनक अंतर्प्रवाह का संकेत देता है, जो गतिशील आर्थिक दृष्टिकोणों के बीच विकसित हो रहे उपभोक्ता विश्वास का संकेत देता है।

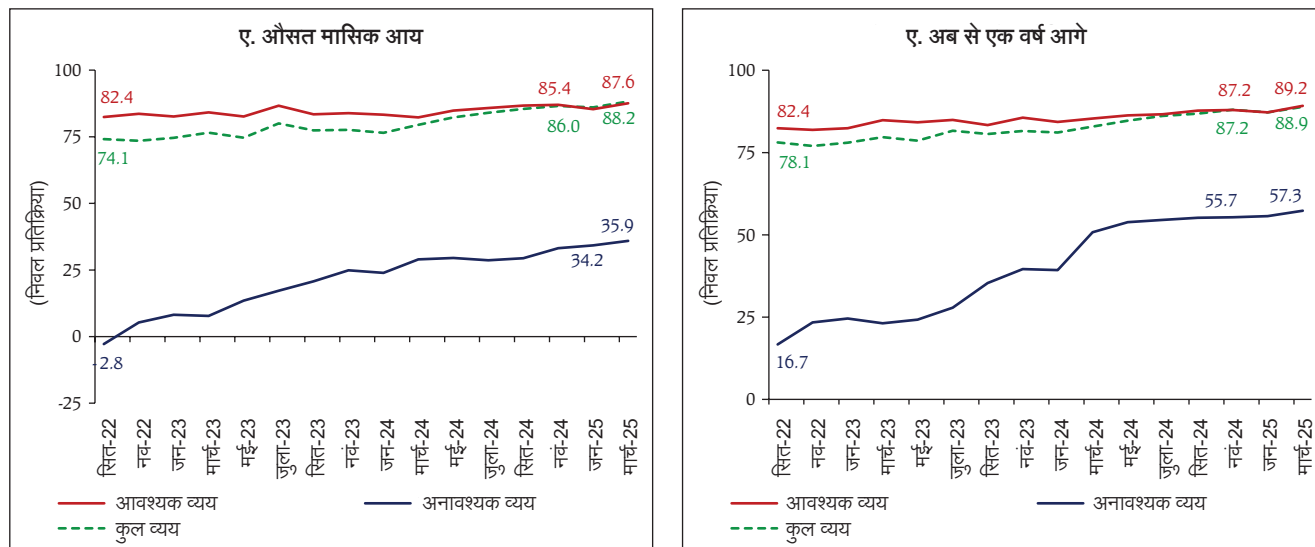
IV.3.बी खर्च की स्थिति

सितंबर 2022 से, ग्रामीण और अर्ध-शहरी परिवारों ने लगातार वर्तमान खर्च के प्रति उल्लेखनीय रूप से उत्साहजनक भावना प्रदर्शित की है, जिसकी निवल प्रतिक्रिया मार्च 2025 में 88.2 के शिखर पर पहुंच गई है। आवश्यक खर्च इस समग्र व्यय का प्राथमिक चालक रहा है, हालांकि गैर-आवश्यक व्यय ने भी समग्र व्यय को बढ़ाने में भूमिका निभाई है। सितंबर 2022 में नकारात्मक क्षेत्र से शुरू होकर, गैर-आवश्यक व्यय के आसपास की भावना में उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जो मार्च 2025 तक निवल आधार पर लगभग 38.7 अंकों की वृद्धि के साथ 35.9 अंक तक पहुंच गया। जबकि मुद्रास्फीति ने उच्च आवश्यक खर्च में योगदान दिया हो सकता है, आय की स्थिति में सुधार और खरीद पैटर्न के मौसमी धक्का वर्तमान अवधि के दौरान गैर-आवश्यक व्यय में भी वृद्धि का संकेत देते हैं। इसी तरह, भविष्य के व्यय पर दृष्टिकोण उच्च आशावाद के दायरे में बना रहा, जो आवश्यक और गैर-आवश्यक दोनों खर्चों से प्रेरित था। यह उल्लेखनीय है कि निवल आधार पर, वर्तमान अवधि और आगामी एक वर्ष दोनों के लिए गैर-आवश्यक व्यय के संबंध में भावना में सुधार देखा गया, यद्यपि यह आवश्यक व्यय की तुलना में काफी कम स्तर पर था (चार्ट 5; और अनुलग्नक 5 में सारणी बी6-बी8)।

IV.4 मूल्य स्तर और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर आकलन

IV.4.ए मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं का मात्रात्मक आकलन

अधिकांश ग्रामीण और अर्ध-शहरी परिवार बढ़ती कीमतों को लेकर चिंतित हैं। सितंबर 2022 से मई 2024 तक मौजूदा समग्र

चार्ट 5: परिवारों की व्यय स्थिति पर रुझान


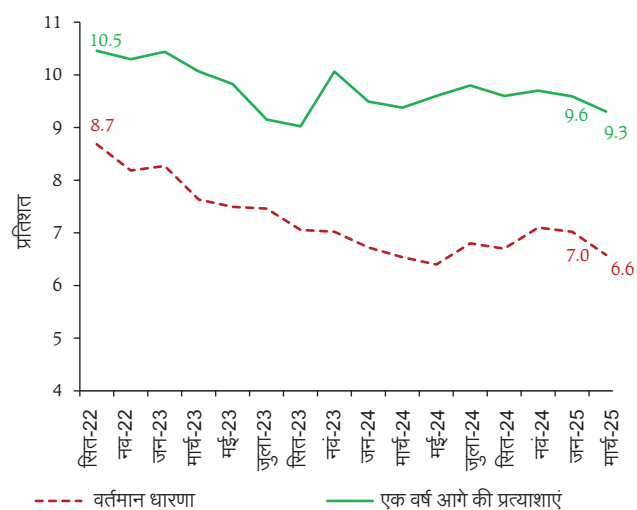
स्रोत: आरबीआई की आरसीसीएस; और लेखकों की गणना

मुद्रास्फीति की उनकी धारणा में 230 आधार अंकों (बीपीएस) की संचयी गिरावट के बावजूद, ग्रामीण और अर्ध-शहरी परिवार साल-दर-साल मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं के बारे में सतर्क रहे, क्योंकि इसी अवधि के दौरान इसमें केवल 90 बीपीएस की कमी आई। जुलाई 2024 से, मुद्रास्फीति की धारणाएँ ऊपर की ओर बढ़ी हैं, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से सब्जियों की बढ़ती कीमतें हैं। हालाँकि, जैसे-जैसे खाद्य कीमतों में कमी आने लगी, जनवरी 2025 के सर्वेक्षण में इन धारणाओं में नरमी दिखाई दी। मार्च 2025 तक, परिवारों की मौजूदा मुद्रास्फीति धारणा पिछले दौर की तुलना में 40 बीपीएस घटकर 6.6 प्रतिशत हो गई। आगामी वर्ष के लिए मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं में भी पिछले दो सर्वेक्षण दौरों की तुलना में 40 बीपीएस की संचयी गिरावट दर्ज की गई, हालाँकि मार्च 2025 में स्तर 9.3 प्रतिशत के उच्च स्तर पर बना रहा (चार्ट 6)।

IV.4.बी मूल्य स्तर और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं पर गुणात्मक मूल्यांकन

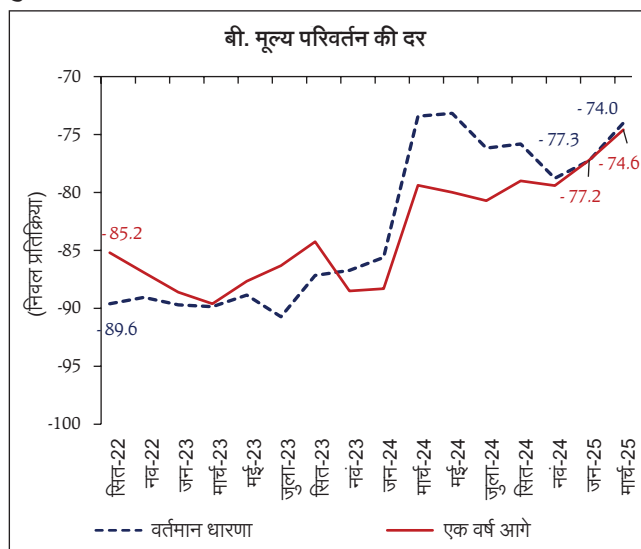
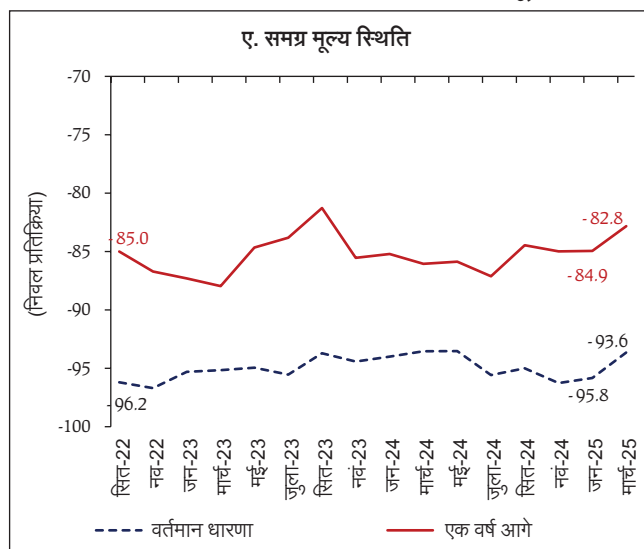
सर्वेक्षणों के सभी दौरों में सामान्य मूल्य स्तर के बारे में परिवारों की भावना लगातार निराशावादी बनी रही है। अधिकांश परिवारों ने कीमतों में वृद्धि की सूचना दी है और अनुमान लगाया है कि अगले वर्ष भी वे ऊँचे स्तर पर बने रहेंगे। वर्तमान मुद्रास्फीति और इसके भविष्य के प्रक्षेपवक्र दोनों का गुणात्मक मूल्यांकन

उनके मात्रात्मक मूल्यांकन के समान प्रवृत्ति का अनुसरण करता है। हालाँकि, मार्च 2025 के सर्वेक्षण में सितंबर 2022 की तुलना में मुद्रास्फीति की वर्तमान धारणा में निराशावाद में 15.6 अंकों की निवल कमी दिखाई गई। हालाँकि, एक वर्ष-आगे के दृष्टिकोण ने निराशावाद में कम परिमाण (10.6 अंक) की निवल कमी दर्ज की (चार्ट 7; और अनुलग्नक 5 में सारणियाँ बी3-बी4)।

चार्ट 6: औसत मुद्रास्फीति दर - धारणाएँ और प्रत्याशाएँ


स्रोत: आरबीआई की आरसीसीएस; और लेखकों की गणना

चार्ट 7: मूल्य स्तर और मुद्रास्फीति पर रुझान



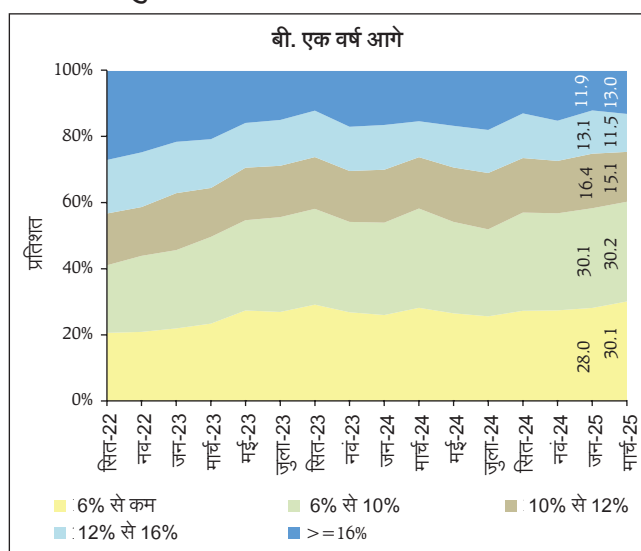
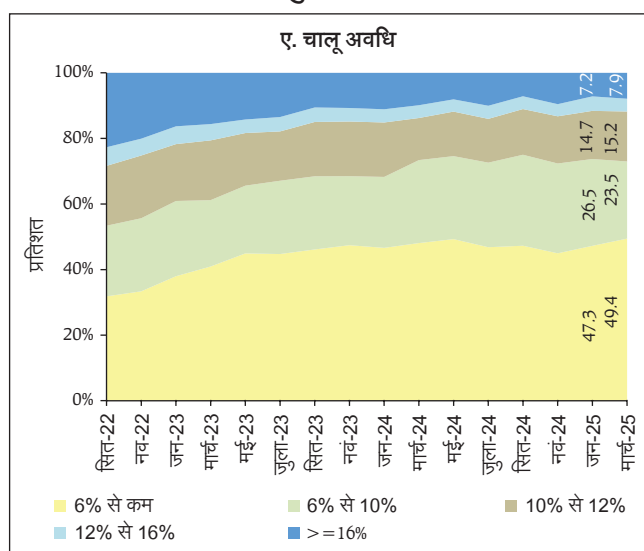
स्रोत: आरबीआई की आरसीसीएस; और लेखकों की गणना।

IV.4.सी मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं द्वारा प्रतिक्रियाओं का वितरण

विभिन्न मुद्रास्फीति वर्गों में उत्तरदाताओं के वितरण की कालानुक्रमिक प्रस्तुति समय के साथ मुद्रास्फीति की बदलती धारणाओं में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। उल्लेखनीय रूप से, जबकि सर्वेक्षण किए गए परिवारों में से आधे से थोड़ा अधिक ने सितंबर 2022 में मुद्रास्फीति को 10 प्रतिशत से कम माना, मार्च

2025 में आयोजित नवीनतम सर्वेक्षण दौर में लगभग तीन-चौथाई उत्तरदाताओं ने अब 10 प्रतिशत से कम मुद्रास्फीति को माना है। यह स्पष्ट है कि यह बदलाव मुख्य रूप से उच्चतम मुद्रास्फीति वर्ग से आया है। इसी तरह, आने वाले वर्ष में मुद्रास्फीति के 10 प्रतिशत से नीचे रहने की आशंका जताने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात भी इसी तरह की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है, हालांकि यह हिस्सा मौजूदा धारणाओं से बहुत कम है (चार्ट 8)।

चार्ट 8: मुद्रास्फीति की धारणाओं और प्रत्याशाओं के अनुसार प्रतिक्रियाओं का वितरण



स्रोत: आरबीआई की आरसीसीएस; और लेखकों की गणना।

IV.4.डी आय और व्यवसाय श्रेणी के अनुसार मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएँ

आय और व्यवसाय श्रेणियों में मुद्रास्फीति की धारणाएँ और प्रत्याशाएँ अलग-अलग होती हैं। मार्च 2025 में, सेवानिवृत्त व्यक्तियों ने अपेक्षाकृत उच्च वर्तमान अवधि की मुद्रास्फीति की सूचना दी, जबकि गृहणियों और सेवानिवृत्त व्यक्ति दोनों ने भविष्य की मुद्रास्फीति के बारे में चिंताएँ व्यक्त कीं। इसी तरह, पिछले तीन सर्वेक्षण दौरों में, सेवानिवृत्त लोगों ने वर्तमान मुद्रास्फीति और भविष्य की प्रत्याशाओं दोनों के बारे में चिंताएँ जताईं। हालाँकि, यह पैटर्न सभी सर्वेक्षण दौरों में लगातार नहीं रहता है (सारणी 1; और अनुलग्नक 6 में सारणियाँ सी1-सी2)।

मुद्रास्फीति की धारणा और प्रत्याशाओं के बारे में घरेलू भावनाओं के संबंध में विभिन्न अन्य सामाजिक-आर्थिक वर्गों में भिन्नता स्पष्ट है। अनुलग्नक 6 में आगे के विवरण दिए गए हैं।

सारणी 1: मार्च 2025 में औसत मुद्रास्फीति की धारणाएँ और प्रत्याशाएँ

(प्रतिशत में)

औसत मासिक आय वार				
आय वर्ग	वर्तमान		एक साल आगे	
	माध्यिका	स्टैंडर्ड त्रुटि	माध्यिका	स्टैंडर्ड त्रुटि
₹5 हजार से कम	6.2	0.38	9.9	0.34
₹5 हजार - ₹10 हजार से कम	6.6	0.28	8.9	0.22
₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	6.3	0.27	9.2	0.29
₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	7.0	0.46	9.3	0.43
₹50 हजार - ₹1 लाख से कम	6.0	0.26	8.8	0.57
₹1 लाख और उससे अधिक	6.3	0.45	8.0	0.47
व्यवसाय के अनुसार				
आय वर्ग	वर्तमान		एक साल आगे	
	माध्यिका	स्टैंडर्ड त्रुटि	माध्यिका	स्टैंडर्ड त्रुटि
दैनिक कार्यकर्ता	6.6	0.39	9.3	0.36
स्व-नियोजित	6.9	0.38	9.0	0.34
वेतनभोगी कर्मचारी	6.5	0.35	9.1	0.32
गृहस्थ	6.4	0.29	9.5	0.31
सेवानिवृत्त व्यक्ति	7.6	0.83	9.5	0.79
अन्य	6.1	0.25	8.8	0.29

नोट: आंकड़े 31 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के आधार पर संकलित किए गए हैं।

स्रोत: आरबीआई का आरसीसीएस और लेखकों की गणना।

IV.5 सारांश सूचकांक

IV.5.ए वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई)

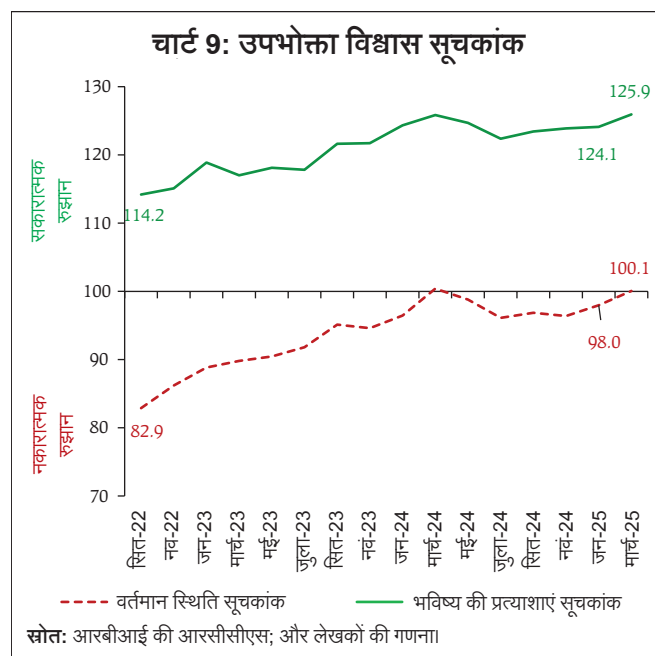
सीएसआई ने समय के साथ लगातार और उल्लेखनीय सुधार दिखाया है। सितंबर 2022 में निराशावादी क्षेत्र में 82.9 से शुरू होकर, मार्च 2024 के सर्वेक्षण दौर में सकारात्मक क्षेत्र (100.4) में प्रवेश करते हुए सीएसआई ने पर्याप्त सुधार किया है। 2024 की दूसरी छमाही के दौरान सीएसआई में गति धीमी हो गई, जो नकारात्मक क्षेत्र में रहते हुए तटस्थ रेखा के पास मँडरा रही थी। जनवरी 2025 के दौर से वर्तमान भावना में फिर से सुधार दिखा (चार्ट 9)।

IV.5.बी भविष्यकालीन प्रत्याशा सूचकांक (एफआईआई)

एफआईआई एक दूरदर्शी परिप्रेक्ष्य प्रदान करता है, जो समय के साथ लगातार सकारात्मकता और क्रमिक सुधार का संकेत देता है। सितंबर 2022 से परिवारों के दृष्टिकोण में संचयी रूप से 9.9 अंकों का सुधार हुआ, जो मार्च 2025 में 125.9 तक पहुँच गया (चार्ट 9)।

IV.5.सी विभिन्न आय समूहों और व्यवसाय श्रेणियों के बीच विश्वास

एक मजबूत सर्वेक्षण ढांचे में, विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के बीच आर्थिक धारणाओं और प्रत्याशाओं में विविधता का अनुमान लगाना स्वाभाविक है।



सामान्य तौर पर, उच्च आय वर्गों से प्राप्त प्रतिक्रियाएँ लगातार बेहतर आर्थिक दृष्टिकोण का सुझाव देती हैं, जो सारांश सूचकांकों (अनुलग्नक 7 में सारणी डी1) में भी दिखाई देती है।

वेतनभोगी वर्ग वर्तमान आर्थिक स्थिति में विश्वास के संबंध में समूहों में सबसे अधिक आशावादी बनकर उभरता है। इसके विपरीत, एफईआई के अनुसार, वेतनभोगी वर्ग और गृहिणियाँ दोनों ही उच्च स्तर का आशावाद प्रदर्शित करते हैं (अनुलग्नक 7 में सारणी डी2)।

V. निष्कर्ष

आर्थिक स्थितियों के बारे में आर्थिक एजेंटों की भावनाओं के विकास को समझना साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे सर्वेक्षणों को और अधिक समावेशी बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, रिज़र्व बैंक ने शहरी परिवारों के मौजूदा सर्वेक्षणों के अनुरूप ग्रामीण भावनाओं को मापने के लिए 2022 में आरसीसीएस की शुरुआत की। यह लेख ग्रामीण उपभोक्ता विश्वास और मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं में देखे गए रुझानों के आधार पर परिणामों के साथ-साथ आरसीसीएस की नमूना रूपरेखा और कार्यप्रणाली प्रस्तुत करता है।

विभिन्न सर्वेक्षण दौरों के परिणामों से पता चलता है कि सामान्य आर्थिक स्थिति और रोजगार की स्थिति के बारे में

परिवारों की धारणाओं में बीच-बीच में आने वाली बाधाओं के बावजूद 2022 से उल्लेखनीय सुधार हुआ है। भविष्य की आय संभावनाओं के बारे में आशावाद एक प्रमुख आकर्षण बना हुआ है, ग्रामीण परिवार लगातार अगले वर्ष बेहतर आय की उम्मीद कर रहे हैं। खर्च करने की भावना मजबूत बनी हुई है, जो मुख्य रूप से आवश्यक खर्च से प्रेरित है, जबकि गैर-आवश्यक व्यय में भी क्रमिक सुधार दिखा है, जो चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदृश्य में लचीलेपन को दर्शाता है।

खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ी चिंता के कुछ संक्षिप्त प्रकरणों को छोड़कर मौजूदा मुद्रास्फीति के बारे में धारणाओं में समय के साथ गिरावट की प्रवृत्ति दिखी है। इनसे मुद्रास्फीति की प्रत्याशाएं भी कम हुई हैं, हालांकि गिरावट की दर धीमी रही है। उपभोक्ता भावनाओं के व्यापक उपायों, जैसे कि सीएसआई ने हाल के दौर में तटस्थ स्तरों के आसपास मँडराते हुए उल्लेखनीय सुधार दिखाया है, जबकि एफईआई मजबूत आशावाद का संकेत देता है। इस सर्वेक्षण की शुरुआत के साथ, नीति निर्माण के लिए उपलब्ध जानकारी का दायरा बढ़ गया है, क्योंकि समावेशी आर्थिक प्रगति के एक प्रमुख माध्यम ग्रामीण उपभोक्ताओं के आकलन और आकांक्षाओं को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।

अनुबंध 1: सर्वेक्षणों पर तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएस)

घरेलू मुद्रास्फीति प्रत्याशाओं को मापने के लिए, आरबीआई देश भर के प्रमुख शहरी केंद्रों में विभिन्न जनसंख्या समूहों में 2005 से आईएसएच सर्वेक्षण कर रहा है। सर्वेक्षण के परिणाम नियमित रूप से त्रैमासिक मौद्रिक नीति रणनीति बैठकों में प्रस्तुत किए गए, जिसमें मौद्रिक नीति पर तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसीएमपी) की बैठक के दौरान महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि साझा की गई। डेटा की संवेदनशील प्रकृति को देखते हुए, विशेष रूप से इसके सार्वजनिक प्रकटीकरण से पहले, जनवरी 2007 में सातवीं टीएसीएमपी बैठक में सर्वेक्षण की पद्धतिगत अखंडता, गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया गया। परिणामस्वरूप, मार्च 2007 में, विभिन्न सर्वेक्षणों पर संरचित तकनीकी मार्गदर्शन की आवश्यकता को पहचानते हुए, रिज़र्व बैंक ने तत्कालीन उप गवर्नर डॉ. राकेश मोहन की अध्यक्षता में टीएसीएस का गठन किया। इस उच्च स्तरीय समिति में प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर) और बाजार विश्लेषकों के साथ-साथ संबंधित उपयोगकर्ता विभागों जैसे आर्थिक अनुसंधान और नीति विभाग (डीईपीआर) और मौद्रिक नीति विभाग (एमपीडी) के प्रतिनिधि शामिल थे। वर्तमान में, टीएसीएस की अध्यक्षता उप गवर्नर द्वारा की जाती है, जबकि ईडी उपाध्यक्ष होते हैं। वर्तमान में बाहरी विशेषज्ञों के पैनल में शामिल आईएसआई; आईजीआईडीआर; नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीईआर); और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), भारत सरकार टीएसीएस का हिस्सा है।

अनुबंध 2: सांख्यिकीय डेटा लेखा परीक्षा

आरबीआई विनियामक और पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग के माध्यम से और विभिन्न संरचित सर्वेक्षणों से भी व्यापक आर्थिक और वित्तीय आंकड़े एकत्र करता है, जो सूचित निर्णय लेने और नीति निर्माण के लिए आधार बनाते हैं। डेटा गुणवत्ता की नींव को बेहतर बनाने के लिए, आरबीआई ने ऐसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान डेटा के सांख्यिकीय डेटा लेखा परीक्षा (एसडीए) करने के लिए एक व्यवस्था स्थापित की है। यह संरचित सांख्यिकीय लेखा परीक्षा सांख्यिकीय डेटा की स्थिरता, अखंडता और विश्वसनीयता का मूल्यांकन करती है, इसके उपयोग में पारदर्शिता और पेशेवर सटीकता सुनिश्चित करता है। हालांकि, मजबूत डेटा प्रबंधन प्रोटोकॉल के साथ आंतरिक डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा आरबीआई के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रही।

भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई), जिसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है, सैद्धांतिक और व्यावहारिक सांख्यिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीआई ने बैंक द्वारा उपयोग किए गए सर्वेक्षण डेटा के लिए सांख्यिकीय डेटा लेखा परीक्षा करने के लिए आईएसआई के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) में प्रवेश किया है। पहले संदर्भ के रूप में, आईएसआई को आरसीसीएस के छह पायलट राउंड के डेटा का सांख्यिकीय लेखा परीक्षा करने का काम सौंपा गया था। प्रमुख कार्यों में डेटा स्रोतों का मूल्यांकन, डेटा क्लिनिंग पर रिपोर्ट, नमूनाकरण पद्धति की समीक्षा, सांख्यिकीय विश्लेषण तकनीकों का अनुप्रयोग, परिणामों का सत्यापन, मान्यताओं और सीमाओं की जांच, पुनःप्राप्त डेटा का दस्तावेजीकरण, अनुपालन सत्यापन और सिफारिशों के साथ लेखापरीक्षा सारांश शामिल थे।

आईएसआई ने अपनी रिपोर्ट में, कार्य की सराहना की है और भारत में ग्रामीण और अर्ध-शहरी गांवों में क्षेत्र सर्वेक्षण करने के मुद्दों और चुनौतियों को पहचाना है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि आरसीसीएस एक गहन सर्वेक्षण है और सीमित संसाधनों के साथ द्विमासिक आवृत्ति में इसे आयोजित करना अपने आप में एक चुनौती है। आईएसआई के डेटा लेखा परीक्षा का सारांश नीचे दिया गया है:

- ए. आरसीसीएस के सर्वेक्षण मापदंडों के वितरण के स्टोकेस्टिक प्रभुत्व के पैटर्न की स्थिरता सर्वेक्षण की औचित्य की धारणा के अनुरूप है और इस प्रकार, निष्कर्ष निकाला गया कि ग्रामीण सर्वेक्षण का गुणात्मक डेटा सुसंगत है।
- बी. सर्वेक्षण की डेटा संगतता सुनिश्चित करने के लिए सीएपीआई स्क्रिप्ट की अंतर्निहित सत्यापन जांच पर रिपोर्ट में विस्तार से चर्चा की गई थी।

टीएसएस ने इन टिप्पणियों के आधार पर सर्वेक्षण को मौजूदा नमूना डिजाइन के साथ जारी रखने और व्यापक परिचालन के लिए सार्वजनिक डोमेन में डेटा प्रकाशित करने पर विचार करने की सिफारिश की।

अनुबंध 3: सर्वेक्षण प्रश्नावली

आरबीआई हर दो महीने में चुनिंदा राज्यों में परिवारों के बीच राष्ट्रीय आरसीसीएस आयोजित करता है, जिसका उद्देश्य कीमतों और मुद्रास्फीति सहित विभिन्न आर्थिक मापदंडों पर उनकी वर्तमान धारणाओं और भविष्य की प्रत्याशाओं का आकलन करना है। सभी प्रतिकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी गोपनीय रखी जाती है और प्रसारित नहीं की जाती है; केवल समेकित परिणाम प्रकाशित किए जाते हैं।

क्या आप सर्वेक्षण में भाग लेने के इच्छुक हैं?								हां/नहीं	
ब्लॉक I: प्रतिकर्ताओं का विवरण									
नाम									
पता	पता 1 - मकान नंबर/भवन का नाम								
	पता2 - कॉलोनी/सड़क/गांव								
	लैंडमार्क								
	गांव/जिला	पिन कोड							
टेलीफोन नंबर									
प्रतिकर्ताओं की आयु	(पूर्ण वर्ष, 21 वर्ष और उससे अधिक में)								
लिंग	पुरुष	महिला	अन्य						
व्यवसाय	वेतनभोगी कर्मचारी [1]	अन्य स्व-नियोजित [2]	गृह निर्माता [3]						
	दैनिक कार्यकर्ता [4]	सेवानिवृत्त व्यक्ति [5]	अन्य (बेरोजगार, छात्र आदि) [6]						
कृषि भूमि	हाँ	नहीं							
परिवार के सदस्य	1 or 2 [1]	3 or 4 [2]	5 और अधिक [3]						
कमाने वाले सदस्यों की संख्या									
औसत मासिक आय	₹5 हजार से कम [1]	₹5 हजार - ₹10 हजार [2]	₹10 हजार - ₹25 हजार [3]						
	₹25 हजार - ₹50 हजार [4]	₹50 हजार - ₹1 लाख [5]	₹1 लाख और उससे अधिक [6]						
शैक्षिक योग्यता	निरक्षर [1]	5वीं कक्षा से नीचे [2]	5वीं कक्षा-10वीं कक्षा से नीचे [3]						
	10वीं कक्षा-12वीं कक्षा से नीचे [4]	12वीं कक्षा कक्षा [5]	स्नातक [6]	स्नातकोत्तर [7]					

ब्लॉक II: अर्थव्यवस्था के बारे में प्रतिकर्ताओं की धारणाएं और प्रत्याशाएं

प्रश्न सं.		एक वर्ष पहले की तुलना में			अब से एक वर्ष बाद		
		सुधार/वृद्धि	यथास्थिति	बिगड़ी/घटी	सुधार/वृद्धि होगी	यथास्थिति रहेगी	बिगड़/घट जाएगी
1	सामान्य आर्थिक स्थिति	[1]	[2]	[3]	[1]	[2]	[3]
2	रोजगार पारिदृश्य	[1]	[2]	[3]	[1]	[2]	[3]

ब्लॉक III: परिवार के बारे में धारणाएं और प्रत्याशाएं

प्रश्न सं.		एक वर्ष पहले की तुलना में			अब से एक वर्ष बाद		
		सुधार/वृद्धि	यथास्थिति	बिगड़ी/घटी	सुधार/वृद्धि होगी	यथास्थिति रहेगी	बिगड़/घट जाएगी
3	घरेलू आय	[1]	[2]	[3]	[1]	[2]	[3]
4ए	आवश्यक वस्तुओं पर व्यय	[1]	[2]	[3]	[1]	[2]	[3]
4बी	गैर-आवश्यक वस्तुओं पर व्यय	[1]	[2]	[3]	[1]	[2]	[3]
4	कुल खर्च	[1]	[2]	[3]	[1]	[2]	[3]

Q5 [यदि ति4_1 = <वृद्धि/घट>] क्यों आपने अपने (या अन्य परिवार के सदस्यों) के खर्च में वृद्धि/घट की है? (सभी लागू उत्तर चुनें)

		हाँ	नहीं
ए.	क्योंकि आपकी आय में <वृद्धि/घट> हुई है।	[1]	[2]
बी.	क्योंकि आपके निवेश/धन में <वृद्धि/घट> हुई है। है।	[1]	[2]
सी.	क्योंकि रियल एस्टेट, कार, उपभोक्ता उपयोगी वस्तुओं जैसी बड़ी टिकट खरीद पर आपका खर्च में <वृद्धि/घट> हुई है।	[1]	[2]
डी.	क्योंकि उपभोक्ता वस्तुओं की लागत, सेवाओं की लागत (जैसे, चिकित्सा, शिक्षा, परिवहन, आदि) बढ़ गई/घट गई है।	[1]	[2]
ई.	अन्य (कृपया निर्दिष्ट करें)	[1]	[2]

प्र.6	परिवारों की वर्तमान वित्तीय स्थिति	बहुत अधिक बचत	कम बचत	बस गुजारा हो रहा है	पिछली बचत पर गुजारा करना	वर्तमान कर्ज
-------	------------------------------------	---------------	--------	---------------------	--------------------------	--------------

ब्लॉक IV: कीमतों और मूल्य परिवर्तन की दर के बारे में धारणाएं और प्रत्याशाएं

प्रश्न सं.		एक साल पहले की तुलना में					अब से एक साल बाद			
		वृद्धि	यथावत	घट	वृद्धि	यथावत	घट			
7	वस्तुओं और सेवाओं की कुल कीमतें	[1]	[2]	[3]	[1]	[2]	[3]			
8	मूल्य परिवर्तन की दर*	[1]	[2]	[3]	[1]	[2]	[3]			
8ए	वर्तमान मुद्रास्फीति दर [#]	< 1 प्रतिशत	1-2 प्रतिशत	2-3 प्रतिशत	3-4 प्रतिशत	4-5 प्रतिशत	5-6 प्रतिशत	6-7 प्रतिशत	7-8 प्रतिशत	8-9 प्रतिशत
		9-10 प्रतिशत	10-11 प्रतिशत	11-12 प्रतिशत	12-13 प्रतिशत	13-14 प्रतिशत	14-15 प्रतिशत	15-16 प्रतिशत	>=16 प्रतिशत	कोई विचार नहीं
8बी	1 वर्ष के बाद मुद्रास्फीति की दर [#]	< 1 प्रतिशत	1-2 प्रतिशत	2-3 प्रतिशत	3-4 प्रतिशत	4-5 प्रतिशत	5-6 प्रतिशत	6-7 प्रतिशत	7-8 प्रतिशत	8-9 प्रतिशत
		9-10 प्रतिशत	10-11 प्रतिशत	11-12 प्रतिशत	12-13 प्रतिशत	13-14 प्रतिशत	14-15 प्रतिशत	15-16 प्रतिशत	>=16 प्रतिशत	कोई विचार नहीं

*- यदि आप प्रश्न 7 में (1) चुनते हैं, तो कृपया प्रश्न 8 का उत्तर दें।

[#]- मुद्रास्फीति दर मूल्य परिवर्तन की वार्षिक दर है। कृपया प्रत्येक प्रश्न के लिए प्रासंगिक विकल्पों पर टिक करें।

अनुबंध-4

सारणी ए1: राज्यवार लक्ष्य नमूना आकार

राज्य	लक्षित नमूना आकार
आंध्र प्रदेश*	300
अरुणाचल प्रदेश**	100
असम	200
बिहार	800
छत्तीसगढ़	150
दिल्ली	100
गोवा*	100
गुजरात	550
हरियाणा	200
हिमाचल प्रदेश*	100
जम्मू और कश्मीर	100
झारखंड	200
कर्नाटक	500
केरल	200
लद्दाख (केंद्र शासित प्रदेश)**	100
मध्य प्रदेश	400
महाराष्ट्र	1000
मणिपुर**	100
मेघालय*	100
मिजोरम**	100
नागालैंड**	100
ओडिशा	300
पंजाब	150
राजस्थान	400
सिक्किम*	100
तमिलनाडु	450
तेलंगाना	300
त्रिपुरा*	100
उत्तर प्रदेश	1000
उत्तराखंड*	100
पश्चिम बंगाल	600
कुल	9000

टिप्पणियाँ: **: जुलाई 2024 से जोड़ा गया। *: सितंबर 2023 से जोड़ा गया।

स्रोत: आरबीआई के आरसीसीएस; और लेखकों की गणना।

सारणी ए2: मार्च 2025 में उत्तरदाताओं का जनसांख्यिकीय वितरण

(प्रतिशत में)

	उत्तरदाताओं का हिस्सा
लिंग वार	
महिला	41.9
पुरुष	58.1
आयु वर्ग वार	
21-29 वर्ष	27.8
30-39 वर्ष	26.8
40-59 वर्ष	33.4
60 वर्ष और उससे अधिक	12.1
व्यवसाय समूह वार	
दैनिक कर्मचारी	16.4
स्व-नियोजित	29.0
वेतनभोगी कर्मचारी	14.0
गृहिणियां	26.3
सेवानिवृत्त व्यक्ति	2.9
अन्य	11.4
औसत मासिक आय वार	
₹5 हजार से कम	9.8
₹5 हजार - ₹10 हजार से कम	33.0
₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	39.8
₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	12.4
₹50 हजार - ₹1 लाख से कम	3.7
₹1 लाख और उससे अधिक	1.3
शैक्षिक पात्रता वार	
अशिक्षित	6.1
5वीं कक्षा से नीचे	6.1
5वीं कक्षा से <10वीं कक्षा तक	28.6
10वीं से <12वीं कक्षा तक	18.3
12 वीं कक्षा	18.4
स्नातक	17.8
स्नातकोत्तर	4.7
कृषि भूमि वाले परिवारों का हिस्सा*	32.0

टिप्पणियाँ: * कृषि भूमि से आय प्राप्त होती है।

स्रोत: आरबीआई के आरसीसीएस; और लेखकों की गणना।

अनुबंध-5

सारणी बी1: सामान्य आर्थिक स्थिति के संबंध में धारणाएँ और प्रत्याशाएं

(प्रतिशत प्रतिक्रियाएं)

सर्वेक्षण दौर	वर्तमान धारणाएं				एक साल आगे प्रत्याशाएं			
	सुधारित	यथावत	बिगड़ी हुई	निवल प्रतिक्रिया	सुधारित	यथावत	बिगड़ी हुई	निवल प्रतिक्रिया
सितं-22	27.6	17.1	55.3	-27.7	48.3	17.4	34.3	14.0
नवं-22	30.8	18.6	50.6	-19.8	51.4	16.4	32.3	19.1
जन-23	32.5	20.7	46.8	-14.3	54.5	17.7	27.8	26.6
मार्च-23	33.7	21.3	45.0	-11.3	52.5	18.2	29.3	23.1
मई-23	33.7	24.3	42.0	-8.4	52.4	19.7	27.9	24.6
जुला-23	34.1	21.8	44.1	-10.0	51.2	18.6	30.2	21.0
सितं-23	40.8	20.4	38.8	2.0	58.0	16.5	25.6	32.4
नवं-23	39.0	21.7	39.3	-0.3	58.5	16.4	25.2	33.3
जन-24	41.7	23.3	35.1	6.6	61.8	16.4	21.8	40.0
मार्च-24	45.9	23.1	31.0	14.9	63.3	15.8	20.9	42.4
मई-24	44.6	22.4	33.0	11.6	61.2	17.2	21.7	39.5
जुला-24	39.6	25.6	34.8	4.8	58.1	16.9	25.0	33.1
सितं-24	39.9	25.4	34.8	5.1	57.2	19.2	23.6	33.6
नवं-24	38.2	24.7	37.1	1.1	57.9	18.1	24.0	34.0
जन-25	39.4	25.2	35.4	4.0	58.8	17.0	24.2	34.6
मार्च-25	41.4	23.8	34.7	6.7	60.0	16.6	23.4	36.6

नोट: जुलाई-23 तक, आंकड़े 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, सितंबर 2023 से, आंकड़े 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर आधारित हैं; जुलाई 2024 से, आंकड़े 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आधार पर संकलित किए गए हैं।

स्रोत: आरबीआई के आरसीसीएस; और लेखकों की गणना।

सारणी बी2: रोजगार पर धारणाएँ और प्रत्याशाएं

(प्रतिशत प्रतिक्रियाएं)

सर्वेक्षण दौर	वर्तमान धारणाएं				एक साल आगे प्रत्याशाएं			
	सुधारित	यथावत	बिगड़ी हुई	निवल प्रतिक्रिया	सुधारित	यथावत	बिगड़ी हुई	निवल प्रतिक्रिया
सितं-22	31.7	21.0	47.4	-15.7	51.9	20.3	27.8	24.1
नवं-22	34.0	20.2	45.8	-11.8	53.1	18.9	27.9	25.2
जन-23	33.6	24.2	42.2	-8.6	56.1	20.0	23.9	32.3
मार्च-23	34.2	23.6	42.2	-8.0	53.7	20.8	25.5	28.3
मई-23	33.2	26.4	40.4	-7.2	54.5	21.0	24.6	29.9
जुला-23	34.7	25.6	39.7	-5.0	52.8	21.9	25.3	27.5
सितं-23	36.9	25.1	38.1	-1.2	56.3	19.9	23.8	32.5
नवं-23	36.9	24.4	38.7	-1.8	57.7	19.0	23.3	34.4
जन-24	37.8	25.6	36.6	1.2	61.0	18.1	20.9	40.1
मार्च-24	40.6	24.8	34.6	6.0	62.1	17.5	20.4	41.7
मई-24	39.4	23.8	36.8	2.5	60.4	18.5	21.2	39.2
जुला-24	35.0	27.1	37.9	-2.9	57.7	19.0	23.3	34.4
सितं-24	35.9	26.2	37.9	-2.0	57.1	20.9	22.1	35.0
नवं-24	36.6	25.6	37.8	-1.2	58.4	19.4	22.2	36.1
जन-25	38.4	25.8	35.8	2.6	58.9	19.0	22.1	36.8
मार्च-25	39.6	24.9	35.4	4.2	59.8	18.8	21.5	38.3

नोट: जुलाई-23 तक, आंकड़े 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, सितंबर 2023 से, आंकड़े 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर आधारित हैं; जुलाई 2024 से, आंकड़े 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आधार पर संकलित किए गए हैं।

स्रोत: आरबीआई के आरसीसीएस; और लेखकों की गणना।

सारणी बी3: मूल्य स्तर पर धारणाएँ और प्रत्याशाएँ

(प्रतिशत प्रतिक्रियाएँ)

सर्वेक्षण दौर	वर्तमान धारणाएँ				एक साल आगे प्रत्याशाएँ			
	सुधारित	यथावत	बिगड़ी हुई	निवल प्रतिक्रिया	सुधारित	यथावत	बिगड़ी हुई	निवल प्रतिक्रिया
सितं-22	96.8	2.5	0.7	-96.2	89.9	5.1	4.9	-85.0
नवं-22	97.2	2.4	0.5	-96.7	90.8	5.1	4.1	-86.7
जन-23	96.1	3.1	0.8	-95.3	91.2	4.9	3.9	-87.3
मार्च-23	96.0	3.2	0.8	-95.2	91.2	5.6	3.2	-88.0
मई-23	95.9	3.2	0.9	-95.0	89.8	5.0	5.2	-84.7
जुला-23	96.3	3.0	0.7	-95.5	89.8	4.3	6.0	-83.8
सितं-23	94.9	3.9	1.2	-93.7	87.8	5.7	6.5	-81.3
नवं-23	95.4	3.7	0.9	-94.4	90.2	5.2	4.6	-85.5
जन-24	94.7	4.6	0.7	-94.0	90.0	5.2	4.8	-85.2
मार्च-24	94.6	4.3	1.1	-93.5	90.2	5.7	4.1	-86.1
मई-24	94.6	4.3	1.1	-93.5	90.3	5.3	4.4	-85.9
जुला-24	96.2	3.2	0.6	-95.6	91.2	4.7	4.1	-87.1
सितं-24	96.1	2.7	1.1	-95.0	89.6	5.2	5.2	-84.5
नवं-24	96.6	3.0	0.4	-96.3	90.0	5.0	5.0	-85.0
जन-25	96.2	3.3	0.4	-95.8	90.0	5.0	5.1	-84.9
मार्च-25	95.1	3.4	1.5	-93.6	88.7	5.4	5.9	-82.8

नोट: जुलाई-23 तक, आंकड़े 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, सितंबर 2023 से, आंकड़े 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर आधारित हैं; जुलाई 2024 से, आंकड़े 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आधार पर संकलित किए गए हैं।

स्रोत: आरबीआई के आरसीसीएस; और लेखकों की गणना।

सारणी बी4: मूल्य स्तर (मुद्रारूपीति) में परिवर्तन की दर पर धारणाएं और प्रत्याशाएं*

(प्रतिशत प्रतिक्रियाएं)

सर्वेक्षण दौर	वर्तमान धारणाएं				एक साल आगे प्रत्याशाएं			
	पिछले साल से अधिक मूल्य वृद्धि	पिछले साल के समान मूल्यवृद्धि	पिछले साल से कम मूल्यवृद्धि	निवल प्रतिक्रिया	पिछले साल से अधिक मूल्य वृद्धि	पिछले साल के समान मूल्यवृद्धि	पिछले साल से कम मूल्यवृद्धि	निवल प्रतिक्रिया
सितं-22	91.5	6.6	1.9	-89.6	88.7	7.9	3.5	-85.2
नवं-22	91.7	5.7	2.6	-89.1	89.9	7.0	3.0	-86.9
जन-23	91.6	6.6	1.9	-89.7	90.9	6.8	2.3	-88.6
मार्च-23	91.3	7.3	1.4	-89.9	91.3	7.1	1.7	-89.6
मई-23	91.0	6.9	2.1	-88.9	90.6	6.5	2.9	-87.7
जुला-23	92.8	5.1	2.1	-90.7	90.4	5.6	4.1	-86.3
सितं-23	89.9	7.5	2.7	-87.2	88.8	6.6	4.6	-84.3
नवं-23	89.8	7.1	3.1	-86.7	91.4	5.7	2.9	-88.5
जन-24	88.8	8.0	3.2	-85.6	91.6	5.1	3.3	-88.3
मार्च-24	78.1	17.2	4.7	-73.4	82.5	14.3	3.1	-79.4
मई-24	78.9	15.4	5.7	-73.2	82.3	15.3	2.4	-80.0
जुला-24	80.5	15.2	4.3	-76.2	83.6	13.5	2.9	-80.7
सितं-24	80.6	14.6	4.8	-75.8	81.8	15.4	2.8	-79.0
नवं-24	82.3	14.2	3.5	-78.8	83.6	12.3	4.2	-79.4
जन-25	80.4	16.5	3.1	-77.3	80.5	16.3	3.2	-77.2
मार्च-25	78.3	17.4	4.3	-74.0	79.3	16.0	4.7	-74.6

नोट: जुलाई-23 तक, आंकड़े 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, सितंबर 2023 से, आंकड़े 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर आधारित हैं; जुलाई 2024 से, आंकड़े 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आधार पर संकलित किए गए हैं।

*केवल उन उत्तरदाताओं के लिए लागू है जिन्हें लगता है कि कीमत बढ़ गई है/कीमत बढ़ जाएगी।

स्रोत: आरबीआई के आरसीसीएस; और लेखकों की गणना।

सारणी बी5: आय पर धारणाएं और प्रत्याशाएं

(प्रतिशत प्रतिक्रियाएं)

सर्वेक्षण दौर	वर्तमान धारणाएं				एक साल आगे प्रत्याशाएं			
	वृद्धि	यथावत	कमी	निवल प्रतिक्रिया	बढ़ेगी	यथावत रहेगी	घटेगी	निवल प्रतिक्रिया
सितं-22	20.1	39.7	40.2	-20.2	52.2	35.3	12.5	39.7
नवं-22	22.0	41.6	36.4	-14.3	52.6	35.6	11.9	40.7
जन-23	22.0	43.9	34.2	-12.2	55.6	33.8	10.7	44.9
मार्च-23	21.2	44.6	34.3	-13.1	54.2	33.6	12.2	42.0
मई-23	21.1	45.9	33.0	-11.8	54.2	33.8	12.0	42.1
जुला-23	22.7	44.3	33.1	-10.4	54.8	33.2	12.0	42.8
सितं-23	23.6	43.9	32.5	-8.9	55.8	32.3	11.9	43.9
नवं-23	24.5	43.1	32.4	-8.0	56.8	31.3	11.9	45.0
जन-24	22.4	47.3	30.3	-7.9	57.4	30.7	11.9	45.5
मार्च-24	23.8	47.6	28.6	-4.8	59.0	30.3	10.7	48.4
मई-24	22.5	46.4	31.2	-8.7	57.4	31.0	11.6	45.8
जुला-24	22.7	45.0	32.4	-9.7	57.5	30.5	12.0	45.5
सितं-24	23.3	44.1	32.6	-9.3	57.1	31.9	11.0	46.2
नवं-24	24.2	43.3	32.5	-8.3	58.2	30.1	11.7	46.5
जन-25	23.7	45.6	30.7	-7.0	58.4	30.1	11.5	47.0
मार्च-25	24.7	45.3	29.9	-5.2	59.0	30.8	10.3	48.7

नोट: जुलाई-23 तक, आंकड़े 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, सितंबर 2023 से, आंकड़े 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर आधारित हैं; जुलाई 2024 से, आंकड़े 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आधार पर संकलित किए गए हैं।

स्रोत: आरबीआई के आरसीसीएस; और लेखकों की गणना।

सारणी बी6: खर्च पर धारणाएं और प्रत्याशाएं

(प्रतिशत प्रतिक्रियाएं)

सर्वेक्षण दौर	वर्तमान धारणाएं				एक साल आगे प्रत्याशाएं			
	वृद्धि	यथावत	कमी	निवल प्रतिक्रिया	बढ़ेगी	यथावत	घटेगी	निवल प्रतिक्रिया
सितं-22	80.1	14.0	6.0	74.1	82.2	13.7	4.1	78.1
नवं-22	79.5	14.5	6.0	73.5	81.4	14.2	4.4	77.0
जन-23	79.4	15.7	4.9	74.6	81.9	14.2	3.9	78.0
मार्च-23	80.7	15.2	4.1	76.6	82.9	13.9	3.2	79.7
मई-23	80.5	13.6	5.9	74.7	83.5	11.7	4.9	78.6
जुला-23	83.4	13.3	3.4	80.0	84.8	12.0	3.2	81.6
सितं-23	81.2	15.0	3.8	77.4	84.2	12.3	3.5	80.6
नवं-23	80.8	16.0	3.2	77.6	84.6	12.4	3.0	81.6
जन-24	80.0	16.5	3.5	76.5	84.4	12.2	3.3	81.1
मार्च-24	82.5	14.4	3.1	79.5	85.7	11.6	2.8	82.9
मई-24	85.0	12.3	2.7	82.3	87.1	10.4	2.5	84.7
जुला-24	86.2	11.5	2.2	84.0	88.5	9.1	2.4	86.1
सितं-24	87.9	9.7	2.5	85.4	88.8	9.2	2.0	86.9
नवं-24	88.5	9.6	1.9	86.6	90.0	8.0	2.0	88.0
जन-25	87.9	10.3	1.9	86.0	89.0	9.3	1.8	87.2
मार्च-25	90.5	7.3	2.2	88.2	90.8	7.4	1.9	88.9

नोट: जुलाई-23 तक, आंकड़े 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, सितंबर 2023 से, आंकड़े 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर आधारित हैं; जुलाई 2024 से, आंकड़े 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आधार पर संकलित किए गए हैं।

स्रोत: आरबीआई के आरसीसीएस; और लेखकों की गणना।

सारणी बी7: खर्च पर धारणाएं और प्रत्याशाएं- आवश्यक वस्तुएं

(प्रतिशत प्रतिक्रियाएं)

सर्वेक्षण दौर	वर्तमान धारणाएं				एक साल आगे प्रत्याशाएं			
	वृद्धि	यथावत	कमी	निवल प्रतिक्रिया	बढ़ेगी	यथावत	घटेगी	निवल प्रतिक्रिया
सितं-22	86.8	8.9	4.3	82.4	85.9	10.6	3.5	82.4
नवं-22	87.5	8.7	3.9	83.6	85.3	11.4	3.4	81.9
जन-23	86.4	9.7	3.8	82.6	85.6	11.3	3.2	82.4
मार्च-23	87.1	10.0	2.9	84.1	87.4	10.1	2.6	84.8
मई-23	86.8	8.9	4.2	82.6	87.6	9.0	3.4	84.2
जुला-23	89.1	8.5	2.4	86.7	87.6	9.8	2.7	84.9
सितं-23	86.5	10.4	3.1	83.4	86.8	9.9	3.4	83.4
नवं-23	86.8	10.3	2.9	83.9	88.2	9.2	2.6	85.6
जन-24	85.8	11.7	2.5	83.3	87.4	9.5	3.1	84.3
मार्च-24	85.1	12.1	2.8	82.3	88.0	9.4	2.6	85.4
मई-24	87.2	10.4	2.4	84.8	88.8	8.6	2.5	86.3
जुला-24	88.1	9.6	2.3	85.8	89.2	8.4	2.5	86.7
सितं-24	89.1	8.5	2.4	86.7	89.9	8.0	2.1	87.8
नवं-24	89.1	8.9	2.1	87.0	90.0	7.9	2.1	87.9
जन-25	87.9	9.5	2.6	85.4	89.5	8.2	2.3	87.2
मार्च-25	89.8	8.0	2.2	87.6	91.2	6.9	2.0	89.2

नोट: जुलाई-23 तक, आंकड़े 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, सितंबर 2023 से, आंकड़े 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर आधारित हैं; जुलाई 2024 से, आंकड़े 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आधार पर संकलित किए गए हैं।

स्रोत: आरबीआई के आरसीसीएस; और लेखकों की गणना।

सारणी बी8: खर्च पर धारणाएं और प्रत्याशाएं- गैर-आवश्यक वस्तुएं

(प्रतिशत प्रतिक्रियाएं)

सर्वेक्षण दौर	वर्तमान धारणाएं				एक साल आगे प्रत्याशाएं			
	वृद्धि	यथावत	कमी	निवल प्रतिक्रिया	बढ़ेगी	यथावत	घटेगी	निवल प्रतिक्रिया
सितं-22	34.8	27.7	37.6	-2.8	43.7	29.2	27.0	16.7
नवं-22	37.2	30.9	31.9	5.3	46.4	30.5	23.1	23.4
जन-23	39.1	30.0	30.9	8.2	47.7	29.2	23.1	24.6
मार्च-23	40.1	27.5	32.4	7.8	48.3	26.6	25.1	23.2
मई-23	41.8	29.9	28.3	13.5	47.8	28.7	23.5	24.2
जुला-23	43.7	29.8	26.5	17.2	50.0	28.0	22.1	27.9
सितं-23	44.4	31.9	23.7	20.7	53.6	28.1	18.3	35.4
नवं-23	47.2	30.5	22.3	24.9	56.1	27.5	16.4	39.6
जन-24	46.5	30.9	22.6	23.9	56.4	26.5	17.1	39.3
मार्च-24	51.8	25.5	22.8	29.0	63.8	23.2	13.0	50.8
मई-24	53.6	22.3	24.1	29.5	66.3	21.3	12.5	53.9
जुला-24	53.9	21.0	25.2	28.7	67.5	19.6	12.9	54.5
सितं-24	55.6	18.3	26.1	29.4	68.2	18.7	13.0	55.2
नवं-24	57.3	18.5	24.2	33.2	68.1	19.1	12.8	55.4
जन-25	57.3	19.7	23.1	34.2	68.1	19.6	12.4	55.7
मार्च-25	58.4	19.1	22.5	35.9	69.6	18.2	12.3	57.3

नोट: जुलाई-23 तक, आंकड़े 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों, सितंबर 2023 से, आंकड़े 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर आधारित हैं; जुलाई 2024 से, आंकड़े 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आधार पर संकलित किए गए हैं।

स्रोत: आरबीआई के आरसीसीएस; और लेखकों की गणना।

अनुबंध-6

सारणी सी1: औसत मासिक आय-वार मुद्रास्फीति धारणा और प्रत्याशाएं

सर्वेक्षण दौर	परिवारों की औसत मासिक आय	वर्तमान		एक वर्ष आगे	
		माध्यिका आईई	एसई	माध्यिका आईई	एसई
सित-22	₹5 हजार से कम	9.0	0.68	10.4	0.28
	₹5 हजार - ₹10 हजार से कम	8.6	0.39	10.4	0.15
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	9.2	0.44	10.7	0.20
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	9.0	0.58	10.8	0.50
	₹50 हजार - ₹1 लाख से कम	9.7	0.92	11.5	1.36
	₹1 लाख और उससे अधिक	8.9	0.53	7.2	1.39
नव-22	₹5 हजार से कम	9.0	0.65	10.5	0.31
	₹5 हजार - ₹10 हजार से कम	8.0	0.30	10.3	0.20
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	8.3	0.37	10.4	0.17
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	8.4	0.56	10.0	0.51
	₹50 हजार - ₹1 लाख से कम	9.0	0.86	9.7	1.20
	₹1 लाख और उससे अधिक	7.2	0.98	10.3	0.50
जन-23	₹5 हजार से कम	8.0	0.85	9.9	0.68
	₹5 हजार - ₹10 हजार से कम	8.2	0.52	10.4	0.19
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	8.3	0.41	10.6	0.15
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	7.9	0.94	10.3	0.40
	₹50 हजार - ₹1 लाख से कम	7.8	0.93	10.0	0.57
	₹1 लाख और उससे अधिक	7.0	0.97	9.5	0.78
मार्च-23	₹5 हजार से कम	8.9	1.03	10.2	0.69
	₹5 हजार - ₹10 हजार से कम	7.2	0.49	10.1	0.40
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	7.6	0.56	9.8	0.44
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	7.5	0.88	9.9	0.67
	₹50 हजार - ₹1 लाख से कम	8.4	0.73	11.2	1.07
	₹1 लाख और उससे अधिक	9.4	0.82	11.3	0.74
मई-23	₹5 हजार से कम	6.7	0.80	9.5	0.59
	₹5 हजार - ₹10 हजार से कम	7.1	0.55	9.1	0.58
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	7.7	0.63	10.0	0.42
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	8.0	0.71	10.4	0.28
	₹50 हजार - ₹1 लाख से कम	9.1	0.94	10.2	0.95
	₹1 लाख और उससे अधिक	6.6	0.45	9.0	1.00

सर्वेक्षण दौर	परिवारों की औसत मासिक आय	वर्तमान		एक वर्ष आगे	
		माध्यिका आईई	एसई	माध्यिका आईई	एसई
जुला-23	₹5 हजार से कम	6.4	0.51	8.3	0.51
	₹5 हजार - ₹10 हजार से कम	7.8	0.38	9.6	0.48
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	7.7	0.39	9.7	0.57
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	7.5	0.53	9.7	0.51
	₹50 हजार - ₹1 लाख से कम	5.9	0.23	9.5	1.08
	₹1 लाख और उससे अधिक	9.1	1.44	9.7	1.20
सितं-23	₹5 हजार से कम	6.3	0.36	8.6	0.32
	₹5 हजार - ₹10 हजार से कम	7.5	0.38	9.5	0.44
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	6.8	0.48	8.9	0.33
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	7.7	0.60	9.2	0.49
	₹50 हजार - ₹1 लाख से कम	8.2	0.92	9.0	0.66
	₹1 लाख और उससे अधिक	6.0	0.58	5.7	0.65
नवं-23	₹5 हजार से कम	6.3	0.55	10.2	0.52
	₹5 हजार - ₹10 हजार से कम	6.9	0.37	10.0	0.33
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	7.3	0.29	10.0	0.28
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	7.6	0.94	10.1	0.50
	₹50 हजार - ₹1 लाख से कम	6.8	0.69	8.5	0.64
	₹1 लाख और उससे अधिक	9.2	0.24	10.5	0.54
जन-24	₹5 हजार से कम	6.7	0.35	8.8	0.39
	₹5 हजार - ₹10 हजार से कम	6.5	0.28	9.2	0.37
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	6.9	0.34	9.8	0.41
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	7.6	0.56	10.3	0.32
	₹50 हजार - ₹1 लाख से कम	7.7	0.60	10.4	0.21
	₹1 लाख और उससे अधिक	5.9	0.41	8.8	0.76
मार्च-24	₹5 हजार से कम	6.7	0.50	9.7	0.42
	₹5 हजार - ₹10 हजार से कम	6.3	0.26	9.4	0.28
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	6.4	0.26	9.7	0.26
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	6.9	0.52	9.6	0.41
	₹50 हजार - ₹1 लाख से कम	6.5	0.62	8.9	0.78
	₹1 लाख और उससे अधिक	8.8	0.19	11.5	1.02

सर्वेक्षण दौर	परिवारों की औसत मासिक आय	वर्तमान		एक वर्ष आगे	
		माध्यिका आईई	एसई	माध्यिका आईई	एसई
मई-24	₹5 हजार से कम	6.4	0.51	10.1	0.30
	₹5 हजार - ₹10 हजार से कम	6.7	0.39	9.8	0.26
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	6.4	0.21	9.6	0.38
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	6.2	0.44	9.4	0.65
	₹50 हजार - ₹1 लाख से कम	6.4	0.34	9.0	0.40
	₹1 लाख और उससे अधिक	5.4	0.30	9.3	1.59
जुला-24	₹5 हजार से कम	6.2	0.28	9.4	0.43
	₹5 हजार - ₹10 हजार से कम	7.1	0.30	9.9	0.28
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	7.2	0.30	9.8	0.24
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	6.7	0.57	9.1	0.54
	₹50 हजार - ₹1 लाख से कम	7.9	0.66	10.1	0.51
	₹1 लाख और उससे अधिक	7.3	0.56	10.1	0.65
सितं-24	₹5 हजार से कम	6.7	0.48	9.5	0.57
	₹5 हजार - ₹10 हजार से कम	6.7	0.29	9.3	0.31
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	7.0	0.28	9.6	0.31
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	7.0	0.34	9.3	0.37
	₹50 हजार - ₹1 लाख से कम	7.0	0.34	9.9	0.37
	₹1 लाख और उससे अधिक	6.6	0.42	9.0	0.78
नवं-24	₹5 हजार से कम	7.0	0.58	9.6	0.45
	₹5 हजार - ₹10 हजार से कम	7.3	0.26	9.8	0.31
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	7.2	0.27	9.8	0.28
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	7.0	0.39	9.4	0.39
	₹50 हजार - ₹1 लाख से कम	6.0	0.35	7.8	0.55
	₹1 लाख और उससे अधिक	6.8	0.70	9.2	0.58
जन-25	₹5 हजार से कम	6.9	0.35	9.5	0.52
	₹5 हजार - ₹10 हजार से कम	7.0	0.25	9.4	0.30
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	7.1	0.21	9.6	0.27
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	7.6	0.35	10.0	0.28
	₹50 हजार - ₹1 लाख से कम	6.9	0.54	8.9	0.34
	₹1 लाख और उससे अधिक	6.6	0.52	8.7	0.64

सर्वेक्षण दौर	परिवारों की औसत मासिक आय	वर्तमान		एक वर्ष आगे	
		माध्यिका आईई	एसई	माध्यिका आईई	एसई
मार्च-25	₹5 हजार से कम	6.2	0.38	9.9	0.34
	₹5 हजार - ₹10 हजार से कम	6.6	0.28	8.9	0.22
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	6.3	0.27	9.2	0.29
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	7.0	0.46	9.3	0.43
	₹50 हजार - ₹1 लाख से कम	6.0	0.26	8.8	0.57
	₹1 लाख और उससे अधिक	6.3	0.45	8.0	0.47

टिप्पणियाँ: 1. जुलाई-23 तक, आंकड़े 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर आधारित हैं, सितंबर 2023 से, आंकड़े 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर आधारित हैं; जुलाई 2024 से, आंकड़े 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आधार पर संकलित किए गए हैं।
2. सारणी मात्रात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए अनुमान और मानक त्रुटियां प्रदान करती है।
स्रोत: आरबीआई के आरसीसीएस; और लेखकों की गणना।

सारणी सी2: व्यवसाय वार मुद्रास्फीति की धारणाएं और प्रत्याशाएं

सर्वेक्षण दौर	उत्तरदाताओं की व्यवसाय श्रेणियाँ	वर्तमान		एक वर्ष आगे	
		माध्यिका आईई	एसई	माध्यिका आईई	एसई
सितं-22	भूमि के मालिक किसान^	10.0	0.63	11.4	1.06
	दैनिक कार्यकर्ता	10.1	0.34	11.5	0.61
	स्व-नियोजित	9.7	0.53	10.8	0.50
	वेतनभोगी कर्मचारी	10.0	0.33	11.3	0.71
	गृहस्थ	8.2	0.57	10.1	0.42
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	9.2	0.69	12.3	1.36
	अन्य	9.2	0.66	10.8	0.43
नवं-22	भूमि के मालिक किसान^	9.5	0.75	11.1	0.89
	दैनिक कार्यकर्ता	8.4	0.63	10.3	0.36
	स्व-नियोजित	9.0	0.78	11.4	0.77
	वेतनभोगी कर्मचारी	8.7	0.56	10.6	0.54
	गृहस्थ	8.3	0.30	10.3	0.26
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	7.2	0.38	9.1	0.48
	अन्य	7.9	0.54	10.2	0.47
जन-23	भूमि के मालिक किसान^	8.9	0.84	10.8	0.41
	दैनिक कार्यकर्ता	9.4	0.80	11.2	0.81
	स्व-नियोजित	8.0	0.77	9.9	0.59
	वेतनभोगी कर्मचारी	7.7	0.49	10.4	0.20
	गृहस्थ	7.6	0.50	10.2	0.17
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	8.4	0.83	10.5	0.58
	अन्य	8.3	0.72	10.4	0.24
मार्च-23	भूमि के मालिक किसान^	9.6	0.85	10.6	1.14
	दैनिक कार्यकर्ता	7.5	0.87	10.0	0.55
	स्व-नियोजित	8.7	1.02	10.0	0.73
	वेतनभोगी कर्मचारी	6.6	0.51	9.3	0.58
	गृहस्थ	7.4	0.72	9.9	0.57
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	8.5	0.96	10.0	0.95
	अन्य	7.2	0.52	9.9	0.44
मई-23	दैनिक कार्यकर्ता	7.5	0.81	9.8	0.65
	स्व-नियोजित	7.3	0.64	9.6	0.52
	वेतनभोगी कर्मचारी	8.3	0.60	10.4	0.24
	गृहस्थ	7.0	0.76	9.5	0.70
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	6.9	0.65	9.3	0.75
	अन्य	7.2	0.40	9.6	0.60

सर्वेक्षण दौर	उत्तरदाताओं की व्यवसाय श्रेणियाँ	वर्तमान		एक वर्ष आगे	
		माध्यिका आईई	एसई	माध्यिका आईई	एसई
जुला-23	दैनिक कार्यकर्ता	7.0	0.53	9.3	0.53
	स्व-नियोजित	7.4	0.45	9.3	0.65
	वेतनभोगी कर्मचारी	8.2	0.54	10.5	0.46
	गृहस्थ	6.9	0.47	9.0	0.60
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	6.9	0.93	9.3	1.01
	अन्य	7.8	0.41	9.8	0.43
सितं-23	दैनिक कार्यकर्ता	6.9	0.51	9.3	0.54
	स्व-नियोजित	6.9	0.41	8.6	0.34
	वेतनभोगी कर्मचारी	7.5	0.41	9.0	0.34
	गृहस्थ	7.3	0.48	9.3	0.47
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	5.9	0.17	8.2	0.25
	अन्य	6.7	0.35	8.8	0.32
नवं-23	दैनिक कार्यकर्ता	7.2	0.54	10.5	0.35
	स्व-नियोजित	6.9	0.52	10.1	0.25
	वेतनभोगी कर्मचारी	7.0	0.36	9.4	0.44
	गृहस्थ	7.0	0.61	9.6	0.53
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	6.8	0.55	10.1	0.33
	अन्य	6.5	0.43	9.8	0.49
जन-24	दैनिक कार्यकर्ता	6.7	0.32	9.3	0.54
	स्व-नियोजित	7.5	0.41	9.9	0.38
	वेतनभोगी कर्मचारी	6.7	0.43	9.3	0.60
	गृहस्थ	6.2	0.24	8.8	0.34
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	7.6	0.55	10.2	0.54
	अन्य	6.6	0.40	9.5	0.48
मार्च-24	दैनिक कार्यकर्ता	6.4	0.34	9.8	0.29
	स्व-नियोजित	6.3	0.27	9.5	0.33
	वेतनभोगी कर्मचारी	6.8	0.39	9.9	0.26
	गृहस्थ	6.8	0.34	9.7	0.32
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	6.5	0.53	9.6	0.48
	अन्य	6.4	0.35	9.0	0.44

सर्वेक्षण दौर	उत्तरदाताओं की व्यवसाय श्रेणियाँ	वर्तमान		एक वर्ष आगे	
		माध्यिका आईई	एसई	माध्यिका आईई	एसई
मई-24	दैनिक कार्यकर्ता	6.4	0.31	9.5	0.39
	स्व-नियोजित	6.4	0.38	9.5	0.41
	वेतनभोगी कर्मचारी	6.4	0.41	9.8	0.45
	गृहस्थ	6.2	0.24	9.8	0.30
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	6.7	0.68	9.1	1.01
	अन्य	6.2	0.37	9.9	0.31
जुला-24	दैनिक कार्यकर्ता	6.8	0.33	9.7	0.36
	स्व-नियोजित	7.5	0.34	9.8	0.29
	वेतनभोगी कर्मचारी	6.9	0.49	9.6	0.41
	गृहस्थ	6.5	0.31	9.9	0.25
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	6.8	0.65	9.4	0.64
	अन्य	7.1	0.36	10.0	0.28
सितं-24	दैनिक कार्यकर्ता	6.6	0.36	9.5	0.47
	स्व-नियोजित	7.1	0.39	9.3	0.30
	वेतनभोगी कर्मचारी	6.9	0.39	9.8	0.35
	गृहस्थ	6.3	0.30	9.4	0.34
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	7.6	0.60	10.0	0.63
	अन्य	7.0	0.33	9.7	0.38
नवं-24	दैनिक कार्यकर्ता	7.4	0.34	9.9	0.37
	स्व-नियोजित	7.3	0.29	9.7	0.41
	वेतनभोगी कर्मचारी	7.6	0.33	9.3	0.33
	गृहस्थ	6.8	0.27	9.5	0.31
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	8.7	0.97	10.5	1.39
	अन्य	7.1	0.36	9.4	0.47
जन-25	दैनिक कार्यकर्ता	7.0	0.43	9.4	0.45
	स्व-नियोजित	7.1	0.37	9.3	0.32
	वेतनभोगी कर्मचारी	7.6	0.35	10.0	0.30
	गृहस्थ	6.7	0.24	9.6	0.31
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	9.3	0.61	9.9	0.66
	अन्य	7.2	0.25	9.1	0.33

सर्वेक्षण दौर	उत्तरदाताओं की व्यवसाय श्रेणियाँ	वर्तमान		एक वर्ष आगे	
		माध्यिका आईई	एसई	माध्यिका आईई	एसई
मार्च-25	दैनिक कार्यकर्ता	6.6	0.39	9.3	0.36
	स्व-नियोजित	6.9	0.38	9.0	0.34
	वेतनभोगी कर्मचारी	6.5	0.35	9.1	0.32
	गृहस्थ	6.4	0.29	9.5	0.31
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	7.6	0.83	9.5	0.79
	अन्य	6.1	0.25	8.8	0.29

टिप्पणियाँ: 1. जुलाई-23 तक, आंकड़े 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर आधारित हैं;, सितंबर 2023 से, आंकड़े 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर आधारित हैं; जुलाई 2024 से, आंकड़े 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आधार पर संकलित किए गए हैं।
2. - ^: मई 2023 से बंद किया।
3. सारणी मात्रात्मक प्रतिक्रियाओं के लिए अनुमान और मानक त्रुटियां प्रदान करती है।
स्रोत: आरबीआई के आरसीसीएस; और लेखकों की गणना।

अनुबंध-7

सारणी डी1: आय समूहवार उपभोक्ता विश्वास सूचकांक

दौर	मासिक औसत घरेलू आय ब्रैकेट	वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई)	भविष्यकालीन प्रत्याशाएं सूचकांक (एफईआई)
सितं-22	₹10 हजार से कम	76.3	110.1
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	86.4	116.4
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	93.2	120.4
	₹50 हजार और उससे अधिक	102.1	124.8
	कुल	82.9	114.2
नव-22	₹10 हजार से कम	80.7	109.6
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	87.7	117.5
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	94.6	121.6
	₹50 हजार और उससे अधिक	103.7	128.0
	कुल	86.2	115.1
जन-23	₹10 हजार से कम	82.4	113.7
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	92.2	121.6
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	97.0	125.7
	₹50 हजार और उससे अधिक	104.2	129.3
	कुल	88.8	118.9
मार्च-23	₹10 हजार से कम	83.5	111.5
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	91.7	119.4
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	102.9	127.7
	₹50 हजार और उससे अधिक	109.9	127.1
	कुल	89.8	117.0
मई-23	₹10 हजार से कम	85.3	114.0
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	92.6	120.4
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	99.1	124.8
	₹50 हजार और उससे अधिक	108.6	124.9
	कुल	90.5	118.1
जुला-23	₹10 हजार से कम	86.4	114.1
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	94.8	120.3
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	101.0	123.8
	₹50 हजार और उससे अधिक	107.8	124.4
	कुल	91.8	117.8

दौर	मासिक औसत घरेलू आय ब्रैकेट	वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई)	भविष्यकालीन प्रत्याशाएं सूचकांक (एफईआई)
सितं-23	₹10 हजार से कम	91.0	118.5
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	97.3	123.5
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	105.0	128.0
	₹50 हजार और उससे अधिक	107.9	132.1
	कुल	95.1	121.6
नव-23	₹10 हजार से कम	88.9	117.7
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	98.1	125.4
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	105.1	126.0
	₹50 हजार और उससे अधिक	111.4	129.3
	कुल	94.6	121.7
जन-24	₹10 हजार से कम	92.1	120.8
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	94.3	122.8
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	98.2	126.7
	₹50 हजार और उससे अधिक	112.9	131.6
	कुल	96.5	124.3
मार्च-24	₹10 हजार से कम	96.4	122.7
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	98.5	124.6
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	102.1	127.7
	₹50 हजार और उससे अधिक	113.6	133.0
	कुल	100.4	125.9
मई-24	₹10 हजार से कम	94.8	120.4
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	96.3	122.6
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	100.2	127.6
	₹50 हजार और उससे अधिक	108.7	127.5
	कुल	98.8	124.7
जुला-24	₹10 हजार से कम	90.3	117.7
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	91.5	119.9
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	98.4	124.6
	₹50 हजार और उससे अधिक	111.5	130.7
	कुल	96.1	122.4

दौर	मासिक औसत घरेलू आय ब्रैकेट	वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई)	भविष्यकालीन प्रत्याशाएं सूचकांक (एफईआई)
सितं-24	₹10 हजार से कम	91.3	120.3
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	93.0	123.0
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	99.0	125.1
	₹50 हजार और उससे अधिक	108.3	127.4
	कुल	96.9	123.4
नव-24	₹10 हजार से कम	90.2	119.7
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	92.2	121.9
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	98.8	126.5
	₹50 हजार और उससे अधिक	110.8	130.3
	कुल	96.4	123.9
जन-25	₹10 हजार से कम	92.1	119.6
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	94.3	121.8
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	100.1	127.3
	₹50 हजार और उससे अधिक	113.6	131.1
	कुल	98.0	124.1
मार्च-25	₹10 हजार से कम	94.3	121.7
	₹10 हजार - ₹25 हजार से कम	96.1	123.4
	₹25 हजार - ₹50 हजार से कम	101.6	127.7
	₹50 हजार और उससे अधिक	114.3	133.0
	कुल	100.1	125.9

टिप्पणियाँ: 1. जुलाई-23 तक, आंकड़े 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर आधारित हैं; सितंबर 2023 से, आंकड़े 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर आधारित हैं; जुलाई 2024 से, आंकड़े 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आधार पर संकलित किए गए हैं।

2. ₹5 हजार से कम और ₹5 हजार से कम - ₹10 हजार से कम मासिक आय वर्ग का विलयन किया जाता है। इसी तरह, ₹50 हजार - ₹1 लाख से कम और ₹1 लाख और उससे अधिक मासिक आय वर्ग का विलयन किया जाता है।

स्रोत: आरबीआई के आरसीसीएस; और लेखकों की गणना।

सारणी डी2: व्यवसाय समूहवार उपभोक्ता विश्वास सूचकांक

दौर	व्यवसाय श्रेणी	वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई)	भविष्य की उम्मीदें सूचकांक (एफईआई)
सितं-22	दैनिक कर्मचारी	80.2	111.5
	स्व-नियोजित	81.7	110.8
	वेतनभोगी कर्मचारी	89.0	118.5
	गृहिणियां	83.1	118.2
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	81.4	105.4
	अन्य	81.2	114.5
	कुल	82.9	114.2
नवं-22	दैनिक कर्मचारी	81.8	109.6
	स्व-नियोजित	83.7	111.2
	वेतनभोगी कर्मचारी	91.4	116.9
	गृहिणियां	87.9	119.7
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	85.0	110.6
	अन्य	85.1	117.2
	कुल	86.2	115.1
जन-23	दैनिक कर्मचारी	82.8	112.1
	स्व-नियोजित	88.4	116.0
	वेतनभोगी कर्मचारी	93.7	122.4
	गृहिणियां	90.5	124.1
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	85.9	111.8
	अन्य	87.0	117.5
	कुल	88.8	118.9
मार्च-23	दैनिक कर्मचारी	86.2	112.9
	स्व-नियोजित	89.8	113.8
	वेतनभोगी कर्मचारी	95.7	119.5
	गृहिणियां	88.8	121.0
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	97.6	113.9
	अन्य	86.2	117.4
	कुल	89.8	117.0
मई-23	दैनिक कर्मचारी	83.2	111.5
	स्व-नियोजित	90.7	117.1
	वेतनभोगी कर्मचारी	98.6	120.9
	गृहिणियां	90.0	122.1
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	90.5	111.9
	अन्य	90.5	118.1
	कुल	90.5	118.1

दौर	व्यवसाय श्रेणी	वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई)	भविष्य की उम्मीदें सूचकांक (एफईआई)
जुला-23	दैनिक कर्मचारी	86.4	114.7
	स्व-नियोजित	92.2	117.2
	वेतनभोगी कर्मचारी	98.9	121.4
	गृहिणियां	91.1	119.1
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	88.1	108.3
	अन्य	93.0	118.9
	कुल	91.8	117.8
सितं-23	दैनिक कर्मचारी	91.7	118.0
	स्व-नियोजित	95.1	120.5
	वेतनभोगी कर्मचारी	101.2	124.0
	गृहिणियां	93.5	123.4
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	98.3	119.4
	अन्य	95.7	124.3
	कुल	95.1	121.6
नवं-23	दैनिक कर्मचारी	89.3	117.8
	स्व-नियोजित	94.8	120.6
	वेतनभोगी कर्मचारी	102.1	124.1
	गृहिणियां	94.0	124.7
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	96.5	116.2
	अन्य	94.7	121.5
	कुल	94.6	121.7
जन-24	दैनिक कर्मचारी	89.4	118.1
	स्व-नियोजित	98.1	123.8
	वेतनभोगी कर्मचारी	103.5	126.9
	गृहिणियां	95.6	128.7
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	98.4	115.3
	अन्य	96.9	123.2
	कुल	96.5	124.3
मार्च-24	दैनिक कर्मचारी	95.7	122.4
	स्व-नियोजित	101.2	123.8
	वेतनभोगी कर्मचारी	107.0	127.7
	गृहिणियां	100.2	129.1
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	99.5	119.3
	अन्य	98.8	127.8
	कुल	100.4	125.9

दौर	व्यवसाय श्रेणी	वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई)	भविष्य की उम्मीदें सूचकांक (एफईआई)
मई-24	दैनिक कर्मचारी	93.6	122.1
	स्व-नियोजित	101.2	123.9
	वेतनभोगी कर्मचारी	103.9	126.7
	गृहिणियां	98.8	128.3
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	105.4	123.1
	अन्य	94.4	120.7
	कुल	98.8	124.7
जुला-24	दैनिक कर्मचारी	90.7	118.7
	स्व-नियोजित	98.7	122.6
	वेतनभोगी कर्मचारी	103.1	124.5
	गृहिणियां	95.3	124.7
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	96.3	119.9
	अन्य	93.2	121.1
	कुल	96.1	122.4
सितं-24	दैनिक कर्मचारी	92.0	121.2
	स्व-नियोजित	97.0	123.1
	वेतनभोगी कर्मचारी	104.4	125.3
	गृहिणियां	96.6	125.4
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	98.8	116.3
	अन्य	95.3	123.0
	कुल	96.9	123.4
नवं-24	दैनिक कर्मचारी	90.2	122.3
	स्व-नियोजित	97.3	122.5
	वेतनभोगी कर्मचारी	105.4	128.4
	गृहिणियां	94.6	125.0
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	96.9	116.2
	अन्य	96.1	123.4
	कुल	96.4	123.9
जन-25	दैनिक कर्मचारी	91.9	121.6
	स्व-नियोजित	99.1	121.5
	वेतनभोगी कर्मचारी	105.1	125.6
	गृहिणियां	97.5	128.2
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	96.5	117.9
	अन्य	98.1	123.5
	कुल	98.0	124.1

दौर	व्यवसाय श्रेणी	वर्तमान स्थिति सूचकांक (सीएसआई)	भविष्य की उम्मीदें सूचकांक (एफईआई)
मार्च-25	दैनिक कर्मचारी	95.5	124.4
	स्व-नियोजित	100.2	123.0
	वेतनभोगी कर्मचारी	107.8	127.5
	गृहिणियां	97.8	129.1
	सेवानिवृत्त व्यक्ति	101.7	122.2
	अन्य	101.8	127.2
	कुल	100.1	125.9

टिप्पणियाँ: 1. जुलाई-23 तक, आंकड़े 19 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर आधारित हैं; सितंबर 2023 से, आंकड़े 26 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों पर आधारित हैं; जुलाई 2024 से, आंकड़े 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के आधार पर संकलित किए गए हैं;

2. भू-मालिक किसानों और स्व-नियोजित श्रेणियों को मार्च 2023 तक मिला दिया गया है। भू-मालिक किसानों की श्रेणी मई 2023 से बंद कर दी गई है।

स्रोत: आरबीआई के आरसीसीएस; और लेखकों की गणना।

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक

भारतीय रिज़र्व बैंक

मुद्रा और बैंकिंग

मूल्य और उत्पादन

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

वित्तीय बाजार

बाह्य क्षेत्र

भुगतान और निपटान प्रणालियाँ

आवसरिक श्रृंखलाएं

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिंदा आर्थिक संकेतक	247
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	248
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	249
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	250
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	251
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	251
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	252
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	253
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	254
9	कुल चलनिधि राशियाँ	255
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	256
11	आरक्षित मुद्रा- घटक और स्रोत	256
12	वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण	257
13	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश	257
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	258
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन	259
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	260
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	261
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	262
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	262
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	262
21	थोक मूल्य सूचकांक	263
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	267
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	267
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	268
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	268
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	269
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	270
28	वाणिज्यिक पत्र	270
29	चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	270
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	271

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	272
32	विदेशी मुद्रा भंडार	272
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ	272
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	275
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण	275
36	भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक	274
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण	275
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	276
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (₹ करोड़)	277
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	278
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (₹ करोड़)	279
42	भारत की अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	280
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	281
	आवसरिक शृंखलाएं	
44	लघु बचत	283
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	284
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियाँ और संवितरण	285
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	286
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	287
49	राज्य सरकारों की बाजार उधारियाँ	288
50 (ए)	हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह-लिखत-वार	289
50 (बी)	हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक-चुनिंदा संकेतक	292

टिप्पणियाँ: .. = उपलब्ध नहीं।

– = शून्य/नगण्य

प्रा/अ = प्रारंभिक/अनंतिम

आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1: चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2023-24	2023-24		2024-25	
		ति1	ति2	ति1	ति2
	1	2	3	4	5
1 वास्तविक क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	8.6	9.2	8.0	5.8	6.2
1.1.1 कृषि	2.7	3.7	1.5	4.1	5.6
1.1.2 उद्योग	11.0	15.3	12.6	2.0	3.5
1.1.3 सेवाएं	9.2	8.3	8.5	7.4	7.3
1.1ए अंतिम खपत व्यय	5.9	5.1	5.3	5.6	7.1
1.1बी सकल नियत पूंजी निर्माण	8.8	11.7	9.3	5.8	5.7
	2023-24	2024		2025	
		जन.	फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	5.9	4.2	5.6	5.2	2.9
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक					
2.1.1 जमाराशियाँ	12.9 (13.5)	12.5 (13.2)	12.5 (13.1)	11.7 (11.4)	11.1 (10.8)
2.1.2 ऋण#	16.3 (20.2)	16.1 (20.3)	16.6 (20.5)	12.9 (11.8)	12.6 (11.6)
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण#	16.3 (20.2)	16.2 (20.4)	16.6 (20.6)	12.9 (11.8)	12.6 (11.5)
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	11.1 (12.8)	13.2 (15.0)	11.6 (13.3)	10.4 (9.6)	10.2 (9.4)
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	5.6	6.3	6.1	4.4	5.3
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	11.1 (11.6)	11.0 (11.5)	10.9 (11.4)	9.6 (9.3)	9.6 (9.4)
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.50	4.50	4.00	4.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	5.0 (5.0)	5.1 (5.1)	4.9 (4.9)	4.5 (4.5)	4.5 (4.5)
3.4 ऋण-जमा अनुपात	78.1 (80.3)	77.7 (80.0)	78.0 (80.2)	78.5 (80.3)	78.7 (80.4)
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात#	95.8 (113.4)	95.6 (117.5)	97.8 (117.5)	83.2 (80.5)	85.0 (82.1)
3.6 निवेश-जमा अनुपात	29.5 (29.8)	29.5 (29.8)	29.6 (29.9)	29.4 (29.5)	29.4 (29.5)
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	25.8 (28.4)	24.5 (27.7)	26.5 (29.3)	27.6 (26.2)	27.8 (26.5)
4 ब्याज दरें (%)					
4.1 नीति रेपो दर	6.50	6.50	6.50	6.50	6.25
4.2 स्थायी रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
4.3 स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर*	6.25	6.25	6.25	6.25	6.00
4.4 सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.50
4.5 बैंक दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.50
4.6 आधार दर	9.10/10.25	9.10/10.25	9.10/10.25	9.10/10.40	9.10/10.40
4.7 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	8.00/8.60	8.00/8.60	8.00/8.60	8.15/8.45	8.15/8.45
4.8 मीयादी जमा दर >1 वर्ष	6.50/7.25	6.50/7.25	6.50/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25
4.9 बचत जमा दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
4.10 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	6.85	6.77	6.64	6.57	6.33
4.11 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	-	7.04	6.96	6.56	6.45
4.12 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	7.28	7.18	7.17	6.67	6.60
4.13 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) प्रतिफल	7.31	7.15	7.12	6.63	6.54
4.14 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों सममूल्य प्रतिफल (एफबीआईएल)	7.31	7.15	-	6.71	6.73
5 संदर्भ दर और वायदा प्रीमियम					
5.1 भा.रु.-अमेरिकी डालर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.37	83.12	82.89	86.64	87.40
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	90.22	90.42	89.71	90.01	90.78
5.3 अमेरिकी डॉलर का वायदा प्रीमियम					
1-माह (%)	1.00	1.30	1.19	2.80	3.21
3-माह (%)	1.11	1.59	1.51	2.69	2.46
6-माह (%)	1.31	1.60	1.50	2.30	2.20
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.4	5.1	5.1	4.3	3.6
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	5.19	4.6	4.9	3.1	2.6
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	-0.7	0.3	0.2	2.5	2.4
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	3.5	4.1	4.6	4.6	2.8
6.3.2 ईंधन और बिजली	-4.7	-0.4	-1.7	-1.9	-0.7
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	-1.7	-1.2	-1.3	2.6	2.9
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	-5.3	2.0	13.7	10.3	-16.3
7.2 निर्यात	-3.1	4.3	11.9	-2.5	-10.9

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 31 मार्च 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार 31 मार्च 2018 से जी सेक बेचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।
#: 3 दिसंबर 2021 से 18 नवंबर 2022 तक सभी पखवाड़ों के लिए चुनिंदा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) द्वारा बैंक ऋण वृद्धि और संबंधित अनुपात को पिछली रिपोर्टिंग वृत्तियों के लिए समायोजित किया जाता है।
कोष्ठकों में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।
*: दिनांक 8 अप्रैल 2022 की प्रेस प्रकाशी सं. 2022-2023/41 के अनुसार।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2: भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2023-24	2024	2025				
			मार्च	फर. 28	मार्च 07	मार्च 14	मार्च 21
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	3482333	3482333	3615574	3647904	3664012	3678235	3683836
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	11	11	14	11	14	10	11
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	3482344	3482344	3615588	3647915	3664026	3678245	3683847
1.2 आस्तियां							
1.2.1 स्वर्ण	162996	162996	226730	228343	228871	234862	235379
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	3318885	3318885	3388603	3419210	3434861	3442976	3448129
1.2.3 रुपया सिक्का	463	463	255	362	293	407	340
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियाँ	1782333	1782333	1445017	1451336	1547433	1650887	1709285
2.1.1.1 केंद्र सरकार	101	101	101	100	100	101	100
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना			-	-	-	-	-
2.1.1.3 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42	42	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	1008618	1008618	927189	887267	920156	882415	943060
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	10092	10092	7452	7710	7872	7527	7776
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6412	6412	4814	5191	5473	5189	5963
2.1.1.7 अन्य बैंक	48725	48725	46630	46007	46144	46820	46963
2.1.1.8 अन्य	545400	545400	363484	405365	471847	601877	593085
2.1.1.9 भारत के बाहर के वित्तीय संस्थान	162944	162944	95305	99655	95799	106916	112296
2.1.2 अन्य देयताएं	1804747	1804747	2173208	2196579	2201871	2178906	2150508
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	3587080	3587080	3618225	3647915	3749304	3829793	3859793
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	11	11	14	11	14	10	11
2.2.2 विदेशों में धारित राशियाँ	1480408	1480408	1402695	1457309	1447300	1393592	1413591
2.2.3 ऋण और अग्रिम							
2.2.3.1 केन्द्र सरकार	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.2 राज्य सरकारें	2300	2300	22937	39684	23828	19192	26284
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	266021	266021	229480	183436	256883	311466	251984
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.6 नाबार्ड	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.7 एक्विजम बैंक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3.8 अन्य	12398	12398	28827	25071	29527	33761	36426
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	162650	162650	94847	99405	95285	106639	111768
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल							
2.2.4.1 आंतरिक	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	-	-	-	-	-	-	-
2.2.5 निवेश	1365425	1365425	1401615	1402259	1454050	1510787	1560630
2.2.6 अन्य आस्तियां	297868	297868	437810	440740	442418	454345	459101
2.2.6.1 स्वर्ण	272028	272028	414488	417437	418402	429357	429510

* डेटा अनंतिम हैं।

सं. 3: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6 -8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तन- शील रेपो दर	परिवर्तन- शील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
फर. 1, 2025	-	-	-	-	517	119511	-	-	-	-118994
फर. 2, 2025	-	-	-	-	202	99712	-	-	-	-99510
फर. 3, 2025	-	-	48785	-	1170	113121	-	-	-	-63166
फर. 4, 2025	-	-	25001	-	378	158816	-	-	-	-133437
फर. 5, 2025	-	-	21180	-	408	147577	-658	-	-	-126647
फर. 6, 2025	-	-	21674	-	163	122506	-570	-	-	-101239
फर. 7, 2025	-	-	183023	-	13020	96591	-	-	-	99452
फर. 8, 2025	-	-	-	-	5172	43861	-	-	-	-38689
फर. 9, 2025	-	-	-	-	5686	47110	-	-	-	-41424
फर. 10, 2025	-	-	201310	-	4125	67439	-	-	-	137996
फर. 11, 2025	-	-	200036	-	3498	71434	428	-	-	132528
फर. 12, 2025	-	-	193865	-	2561	48110	-	-	-	148316
फर. 13, 2025	-	-	235619	-	1988	54539	-	-	-	183068
फर. 14, 2025	-	-	225019	-	641	71090	798	-	40000	195368
फर. 15, 2025	-	-	-	-	422	101167	-	-	-	-100745
फर. 16, 2025	-	-	-	-	91	84644	-	-	-	-84553
फर. 17, 2025	-	-	157427	-	1471	112137	-	-	-	46761
फर. 18, 2025	-	-	71773	-	1359	97359	-460	-	-	-24687
फर. 19, 2025	-	-	-	-	6529	85144	-	-	-	-78615
फर. 20, 2025	-	-	132938	-	760	137648	-	-	-	-3950
फर. 21, 2025	-	-	193924	-	500	135990	-	-	40000	98434
फर. 22, 2025	-	-	-	-	285	64888	-	-	-	-64603
फर. 23, 2025	-	-	-	-	286	64977	-	-	-	-64691
फर. 24, 2025	-	-	36775	-	2400	78791	-	-	-	-39616
फर. 25, 2025	-	-	75012	-	895	112841	-	-	-	-36934
फर. 26, 2025	-	-	-	-	443	101569	-	-	-	-101126
फर. 27, 2025	-	-	49955	-	1334	103098	-	-	-	-51809
फर. 28, 2025	-	-	16258	-	8943	97238	-	-	-	-72037

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमेरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय

i) तटीय/ अपतटीय ओटीसी खंड में परिचालन

मद	2023-24	2024	2025	
		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	41271	8557	-11139	-1621
1.1 क्रय (+)	194296	8557	49145	45030
1.2 विक्रय (-)	153025	0	60284	46651
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (₹ करोड़)	339528	70981	-95388	-14024
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	41271	28022	-47245	-48866
(₹ करोड़)	339528	229505	-401795	-415819
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	-541	9694	-77528	-88753

ii) मुद्रा वायदा खंड में परिचालन

मद	2023-24	2024	2025	
		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमेरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	7930	0	3703	4071
1.2 विक्रय (-)	7930	0	3703	4071
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमेरिकी डॉलर)	-1080	0	-2683	-1002

**सं. 4ए: भारतीय रिज़र्व बैंक के बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमेरिकी डॉलर)**

मद	28 फरवरी 2025 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	10062	24808	-14746
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	0	18830	-18830
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	0	45115	-45115
4. 1 वर्ष से अधिक	0	10062	-10062
कुल (1+2+3+4)	10062	98815	-88753

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(₹ करोड़)

मद	रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार की स्थिति						
	2023-24	2024				2025	
		मार्च 22	अक्टू. 18	नव. 29	दिसं. 27	जन. 24	फर. 21
	1	2	3	4	5	6	7
1 सीमांत स्थायी सुविधा	49906	49906	4216	18513	31127	3232	500
2 अनुसूचित बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त							
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा							
3.1 सीमा	9900	9900	9900	9900	9900	9900	9900
3.2 बकाया	9810	9810	7223	8428	8459	9556	9096
4 अन्य							
4.1 सीमा	76000	76000	76000	76000	76000	76000	76000
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	59716	59716	11439	26941	39586	12788	9596

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31 /माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2023-24	2024	2025		
			फर. 23	जन. 24	फर. 07
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	3410276	3361633	3503602	3537301	3558434
1.1 संचलन में नोट	3477795	3423064	3563413	3595771	3614508
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	32689	32455	34940	35274	35274
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	101185	94830	96376	95355	92995
2 जनता की जमाराशियाँ	2681424	2594337	2756006	2745975	2778287
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियाँ	2586888	2510518	2651712	2634048	2664975
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	83819	104294	111927	113312
3 एम1 (1+2)	6091700	5955970	6259608	6283276	6336721
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियाँ	195777	191692	200889	200889	200889
5 एम2 (3+4)	6287477	6147662	6460497	6484165	6537610
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियाँ	18739918	18538143	20369151	20588910	20515359
	(18848160)	(18650930)	(20433390)	(20651913)	(20577221)
7 एम3 (3+6)	24831618	24494113	26628759	26872185	26852080
	(24939860)	(24606900)	(26692999)	(26935188)	(26913942)
8 कुल डाकघर जमाराशियाँ	1313366	1298796	1379283	1379283	1379283
9 एम4 (7+8)	26144984	25792909	28008042	28251468	28231363
	(26253226)	(25905696)	(28072282)	(28314471)	(28293225)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 7: मुद्रा भंडार (एम₃) के स्रोत

(₹ करोड़)

स्रोत	मार्च 31 / माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2024	2025		
		फर. 23	जन. 24	फर. 07	फर. 21
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	7512016	7223794	7937526	8156863	8099668
1 सरकार को निवल बैंक ऋण (विलय सहित)	(7603571)	(7315467)	(7988402)	(8207744)	(8150550)
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	1193213	964996	1047893	1220379	1193390
1.1.1 सरकार पर दावे	1370428	1377351	1309316	1353481	1421675
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1363828	1362541	1288822	1318026	1399564
1.1.1.2 राज्य सरकारें	6600	14809	20495	35454	22112
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाराशियाँ	177215	412355	261423	133102	228285
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	177172	412313	261381	133059	228243
1.1.2.2 राज्य सरकारें	42	42	42	42	42
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	6318803	6258798	6889633	6936484	6906278
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण (विलय सहित)	(6410358)	(6350471)	(6940509)	(6987365)	(6957160)
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	16672145	16434572	18230417	18330843	18368384
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (विलय सहित)	(17202832)	(16970977)	(18672006)	(18766485)	(18801586)
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	14406	11121	22760	20792	28593
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	16657739	16423451	18207657	18310051	18339790
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंक ऋण (विलय सहित)	(17188426)	(16959856)	(18649246)	(18745693)	(18772993)
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण	15901477	15677730	17426890	17527786	17556777
2.2.1 वाणिज्यिक बैंकों द्वारा बैंक ऋण (विलय सहित)	(16432164)	(16214135)	(17868479)	(17963429)	(17989979)
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	738194	728279	761677	763241	764165
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	18068	17443	19091	19024	18849
2.2.3 वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश (विलय सहित)	(18068)	(17443)	(19091)	(19024)	(18849)
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	5567504	5284622	5634421	5786688	5759028
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	5241083	4985065	5272023	5424290	5396630
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	5241083	4985066	5272019	5424286	5396628
3.1.2 विदेशी देयताएं	0	0	-4	-4	-2
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	326421	299557	362398	362398	362398
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	33198	35683	36017	36017
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	4953478	4482073	5209288	5438225	5411018
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (विलय सहित)	(5467477)	(4997364)	(5637513)	(5861747)	(5833239)
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1790134	1699563	1986997	2108359	2108450
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	3163344	2782510	3222291	3329867	3302567
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट) (विलय सहित)	(3677343)	(3297801)	(3650516)	(3753388)	(3724789)
एम₃ (1+2+3+4-5)	24831618	24494113	26628759	26872185	26852080
एम ₃ (1+2+3+4-5) (विलय सहित)	(24939860)	(24606900)	(26692999)	(26935188)	(26913942)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2024	2025		
		फर. 23	जन. 24	फर. 07	फर. 21
	1	2	3	4	5
समग्र मौद्रिक राशियाँ					
एनएम ₁ (1.1 + 1.2.1+1.3)	6091700	5955970	6259608	6283276	6336721
एनएम ₂ (एनएम ₁ + 1.2.2.1)	14424855	14201318	15296176	15412810	15437569
एनएम ₂ (एनएम ₁ + 1.2.2.1) (विलय सहित)	(14473564)	(14252072)	(15325083)	(15441161)	(15465407)
एनएम ₃ (एनएम ₂ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5)	25387764	25057984	27294849	27511689	27461802
एनएम ₃ (एनएम ₂ + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4 - 2.5) (विलय सहित)	(25496006)	(25170771)	(27359088)	(27574692)	(27523665)
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	3410276	3361633	3503602	3537301	3558434
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियाँ	21105009	20833514	22732973	22921903	22889082
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियाँ (विलय सहित)	(21213252)	(20946301)	(22797212)	(22984906)	(22950944)
1.2.1 मांग जमाराशियाँ	2586888	2510518	2651712	2634048	2664975
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ	18518121	18322995	20081261	20287855	20224106
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(18626364)	(18435782)	(20145500)	(20350858)	(20285969)
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ	8333155	8245348	9036567	9129535	9100848
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(8381864)	(8296102)	(9065475)	(9157886)	(9128686)
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	369399	368278	503843	525557	513746
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ	10184967	10077647	11044693	11158320	11123259
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ (विलय सहित)	(10244500)	(10139680)	(11080025)	(11192972)	(11157283)
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	83819	104294	111927	113312
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	777942	779019	953980	940558	900975
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	25295986	24781264	27384392	27710331	27688336
2.1 देशी ऋण (विलय सहित)	(25918227)	(25409342)	(27876856)	(28196855)	(28172420)
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	7512016	7223794	7937526	8156863	8099668
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण (विलय सहित)	(7603571)	(7315467)	(7988402)	(8207744)	(8150550)
2.1.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1193213	964996	1047893	1220379	1193390
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	6318803	6258798	6889633	6936484	6906278
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण (विलय सहित)	(6410358)	(6350471)	(6940509)	(6987365)	(6957160)
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	17783970	17557470	19446866	19553468	19588668
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण (विलय सहित)	(18314656)	(18093875)	(19888454)	(19989111)	(20021871)
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई ऋण	14406	11121	22760	20792	28593
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	17769564	17546349	19424106	19532676	19560075
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण (विलय सहित)	(18300250)	(18082754)	(19865694)	(19968319)	(19993278)
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियाँ)	1089184	1101595	1201967	1198287	1206485
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	33198	35683	36017	36017
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5111079	4907388	5321759	5475205	5428386
2.3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5241083	4985065	5272023	5424290	5396630
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	-130004	-77678	49737	50915	31756
2.4 पूंजी खाता	3912897	3961198	4467201	4559639	4551061
2.5 अन्य मदें (निवल)	1653834	1217958	1408009	1573746	1562098

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 9: चलनिधि समग्र राशियाँ

(₹ करोड़)

समग्र राशियाँ	2023-24	2024		2025	
	1	फर.	दिसं.	जन.	फर.
		2	3	4	5
1 एनएम ₃	25387764 (25496006)	25057984 (25170771)	27183290 (27249981)	27294849 (27359088)	27461802 (27523665)
2 डाकघर जमाराशियाँ	729246	717215	732774	732774	732774
3 एल ₁ (1 + 2)	26117010 (26225252)	25775199 (25887986)	27916064 (27982755)	28027623 (28091862)	28194576 (28256439)
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	85150	62974	73559	75298	80416
4.1 सावधि मुद्रा उधार	2375	678	16	16	16
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	70245	50143	59920	61430	66365
4.3 सावधि जमाराशियाँ	12531	12152	13622	13852	14035
5 एल ₂ (3 + 4)	26202160 (26310403)	25838173 (25950960)	27989623 (28056313)	28102921 (28167160)	28274993 (28336855)
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियाँ	102994	..	116921
7 एल ₃ (5 + 6)	26305155	..	28106544

टिप्पणी : 1. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2024	2025		
		फर. 23	जन. 24	फर. 7	फर. 21
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	3511461	3456463	3599978	3632655	3651428
1.2 आरबीआई के पास बैंकों की जमाराशियाँ	1025449	971038	948414	937590	947488
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	956011	909400	889895	878388	888462
1.3 आरबीआई के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	83819	104294	111927	113312
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	4631446	4511319	4652687	4682172	4712229
2 स्रोत					
2.1 आरबीआई के देशी ऋण	1147066	1192619	1331978	1330223	1388031
2.1.1 सरकार को निवल आरबीआई ऋण	1193213	964996	1047893	1220379	1193390
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल आरबीआई ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	1186655	950229	1027441	1184967	1171321
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.1.1.1.2 खजाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1363369	1362249	1288414	1317755	1399251
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियाँ	1363369	1362249	1288414	1317755	1399251
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	459	293	408	271	313
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियाँ	177172	412313	261381	133059	228243
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल आरबीआई ऋण	6557	14767	20452	35412	22069
2.1.2 बैंकों पर आरबीआई के दावे	-60553	216502	261325	89052	166048
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को ऋण और अग्रिम	-60553	216502	261325	89052	166048
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को आरबीआई के ऋण	14406	11121	22760	20792	28593
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	9358	9066	9556	8328	9096
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	33198	35683	36017	36017
2.3 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5241083	4985065	5272023	5424290	5396630
2.3.1 स्वर्ण	439319	396913	600379	631357	646668
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4801764	4588153	4671640	4792929	4749960
2.4 पूंजी खाता	1589134	1646592	1870465	1959117	1950057
2.5 अन्य मदें (निवल)	201000	52971	116532	149241	158394

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	2023-24	मार्च 31/माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2024	2025				
		फर. 23	जन. 31	फर. 7	फर. 14	फर. 21	फर. 28
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	4631446	4511319	4689418	4682172	4763405	4712229	4750684
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	3511461	3456463	3600982	3632655	3642063	3651428	3651880
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियाँ	1025449	971038	982697	937590	1011925	947488	986086
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियाँ	94536	83819	105739	111927	109417	113312	112718
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	1193213	964996	1189067	1220379	1242028	1193390	1274102
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-60553	216502	154192	89052	190264	166048	132244
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	14406	11121	22953	20792	25935	28593	30888
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5241083	4985065	5305327	5424290	5363066	5396630	5432063
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	33432	33198	36017	36017	36017	36017	36306
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1790134	1699563	2018138	2108359	2093905	2108450	2154920

सं. 12: वाणिज्यिक बैंक सर्वेक्षण

(₹ करोड़)

मद	माह के रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार / माह के रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2023-24	2024	2025		
		फर. 23	जन. 24	फर. 7	फर. 21
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियाँ	20145188	19876895	21774443	21961350	21931190
	(20253430)	(19989682)	(21838682)	(22024353)	(21993052)
1.1.1 मांग जमाराशियाँ	2443853	2368307	2510913	2492532	2524095
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियाँ	17701334	17508587	19263530	19468818	19407095
	(17809577)	(17621374)	(19327769)	(19531821)	(19468957)
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियाँ	7965600	7878864	8668588	8760968	8733193
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र (सीडी)	369399	368278	503843	525557	513746
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियाँ	9735734	9629723	10594941	10707850	10673902
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधीयन	777942	779019	953980	940558	900975
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	23019606	22748921	25219289	25373200	25368511
	(23641847)	(23376999)	(25711754)	(25859724)	(25852596)
2.1.1 सरकार को ऋण	6014054	5956167	6584147	6630994	6599626
	(6105610)	(6047841)	(6635022)	(6681876)	(6650507)
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	17005551	16792754	18635143	18742205	18768886
	(17536238)	(17329159)	(19076731)	(19177848)	(19202088)
2.1.2.1 बैंक ऋण	15901477	15677730	17426890	17527786	17556777
	(16432164)	(16214135)	(17868479)	(17963429)	(17989979)
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	15878397	15637228	17370711	17473841	17509329
	(16409083)	(16173633)	(17812300)	(17909484)	(17942532)
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	22904	21566	14744	24601	14063
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	949	825	504	494	524
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	1080222	1092632	1193005	1189325	1197522
2.2 वाणिज्यिक बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	-130004	-77678	49737	50915	31756
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	241661	269656	520849	529865	501065
2.2.2 अनिवासो विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियाँ	221796	215148	287890	301055	291252
2.2.3 ओवरसीज विदेशी मुद्रा उधार	149868	132186	183222	177895	178057
2.3 निवल बैंक रिजर्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	893350	775943	713399	873183	803573
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	931483	909400	889895	878388	888462
2.3.2 उपलब्ध नकदी	89433	83045	84829	83847	81159
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	127566	216502	261325	89052	166048
2.4 पूंजी खाता	2299592	2290436	2572565	2576351	2576834
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	560230	500838	681437	819038	794842
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	787560	789201	807699	863841	843551
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	197781	180617	153034	124618	116845

कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश

(₹ करोड़)

मद	22 मार्च, 2024 की स्थिति	2024	2025		
		फर. 23	जन. 24	फर. 7	फर. 21
		1	2	3	4
1 एसएलआर प्रतिभूतियाँ	6106558 (6015003)	6048666 (5956993)	6635526 (6584651)	6682369 (6631488)	6651031 (6600149)
2 अन्य सरकारी प्रतिभूतियाँ (गैर-एसएलआर)	177136	177882	164435	162963	163938
3 वाणिज्यिक पत्र	61175	53516	58059	60605	56570
4 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
4.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	8475	8636	13079	13174	12782
4.2 निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	77722	79935	96841	96613	96188
4.3 अन्य	5624	5620	7505	7520	7518
5 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
5.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम	103070	96898	125694	122613	125644
5.2 निजी कॉरपोरेट क्षेत्र	287596	288205	234947	233488	237406
5.3 अन्य	124690	114923	154889	156727	156229
6 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
6.1 म्यूचुअल फंड	62499	89916	141035	146709	145589
6.2 वित्तीय संस्थाएं	172340	176856	194810	188912	195657

टिप्पणी: कॉलम सं. (1), (2) व (3)में दिया गया डेटा अंतिम है और कॉलम सं.(4) व (5)में दिया गया डेटा अनंतिम है।

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में, एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय के प्रभाव शामिल हैं।

2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक

(₹ करोड़)

मद	अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार (मार्च के संबंध में) / अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक			
	2023-24	2024	2025		2023-24	2024	2025	
		फर.	जन.	फर.		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5	6	7	8
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	210	210	208	208	137	137	135	135
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	554117	520348	454438	443848	549351	516165	448851	438922
1.1 बैंकों से माँग और मीयादी जमाराशियाँ	298452	269766	283393	287294	294471	266228	278365	282773
1.2 बैंकों से उधार राशि	182566	178124	140182	118234	182429	178119	139965	118149
1.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	73100	72458	30863	38320	72452	71818	30521	38000
2 अन्य के प्रति देयताएं	22664868	22367660	24925459	25091193	22190597	21905235	24441212	24603927
2.1 कुल जमाराशियाँ	20932067	20650054	22955228	23098180	20475226	20204830	22489507	22630598
	(20823825)	(20537267)	(22891563)	(23037055)	(20366984)	(20092042)	(22425841)	(22569473)
2.1.1 माँग	2492916	2416163	2720203	2753855	2443853	2368307	2672172	2705279
2.1.2 मीयादी	18439151	18233891	20235026	20344326	18031373	17836522	19817335	19925320
2.2 उधार	782260	783905	898159	889316	777942	779019	893564	884179
2.3 अन्य माँग और मीयादी देयताएं	950541	933701	1072072	1103696	937428	921387	1058140	1089150
3 रिज़र्व बैंक से उधार	222716	256409	256989	229480	222716	256374	256989	229480
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	222716	256409	256989	229480	222716	256374	256989	229480
4 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	1043272	1014767	1040685	1031337	1020916	992445	1019995	1010913
4.1 उपलब्ध नकदी	91886	85534	98194	86176	89433	83045	95912	83724
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	951386	929232	942491	945160	931483	909400	924083	927189
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	455057	428737	394269	414392	374474	357114	321056	335331
5.1 अन्य बैंकों के पास शेषराशि	246384	238384	251177	260695	198327	191943	198663	206428
5.1.1 चालू खाते में	12010	11228	12679	12981	8971	8458	10105	10370
5.1.2 अन्य खातों में	234373	227156	238498	247714	189357	183484	188558	196058
5.2 माँग और अल्पसूचना पर मुद्रा	39614	33371	34389	42526	12355	13834	20195	25496
5.3 बैंकों को अग्रिम	51325	49373	42801	44597	48368	46054	39363	39833
5.4 अन्य आस्तियां	117734	107609	65903	66574	115424	105284	62835	63574
6 निवेश	6256962	6196793	6785965	6830178	6106558	6048666	6633890	6676664
	(6165407)	(6105120)	(6735083)	(6779497)	(6015003)	(5956993)	(6583008)	(6625984)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	6249319	6190053	6777698	6821889	6105610	6047841	6633347	6676060
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	7643	6740	8267	8289	949	825	544	604
7 बैंक ऋण	16866336	16646357	18512453	18667299	16432164	16214135	18053607	18202174
	(16335650)	(16109952)	(18074198)	(18238110)	(15901477)	(15677730)	(17615353)	(17772985)
7ए खाद्यान्न ऋण	72282	89704	105577	96468	23081	40502	54961	45854
7.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	16565348	16365960	18180682	18334125	16134303	15936696	17725261	17872448
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	60471	52922	76574	75858	60467	52912	74880	74221
7.3 देशी बिल- भुनाए गए	199761	188407	216630	218916	197358	186108	215511	217743
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	16662	16657	16870	15279	16412	16405	16645	15032
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	24094	22411	21696	23120	23624	22014	21310	22730

टिप्पणी: कॉलम सं. (4) व (8) में दिया गया डेटा अनंतिम है।

- जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय के प्रभाव शामिल हैं।
- कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 22, 2024	2024	2025		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
		फर. 23	जन. 24	फर. 21	2024-25	2025
		1	2	3	4	%
I. बैंक ऋण (II+III)	16432164 (15901477)	16214135 (15677730)	17874756 (17433167)	17989988 (17556785)	9.5 (10.4)	11.0 (12.0)
II. खाद्यान्न ऋण	23081	40502	56179	47448	105.6	17.2
III. गैर-खाद्यान्न ऋण	16409083 (15878397)	16173633 (15637228)	17818577 (17376988)	17942540 (17509338)	9.3 (10.3)	10.9 (12.0)
1. कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	2071251	2032170	2253510	2264312	9.3	11.4
2. उद्योग (सूक्ष्म और लघु, मध्यम और बड़े)	3652804 (3635810)	3616918 (3599906)	3874601 (3862535)	3875386 (3863437)	6.1 (6.3)	7.1 (7.3)
2.1 सूक्ष्म और लघु	726315	715104	778391	784802	8.1	9.7
2.2 मध्यम	303998	298923	345986	352907	16.1	18.1
2.3 बड़े	2622490	2602890	2750224	2737676	4.4	5.2
3. सेवाएं	4592227 (4490467)	4515479 (4412072)	5013597 (4941743)	5056929 (4987504)	10.1 (11.1)	12.0 (13.0)
3.1 परिवहन परिचालक	230175	227697	253917	257630	11.9	13.1
3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	25917	27023	33729	33062	27.6	22.3
3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	77513	76132	81478	82022	5.8	7.7
3.4 शिपिंग	7067	6856	7180	7411	4.9	8.1
3.5 विमानन	43248	43720	44788	45928	6.2	5.0
3.6 पेशेवर सेवाएं	167234	161758	190859	192799	15.3	19.2
3.7 व्यापार	1025752	1009471	1131031	1157875	12.9	14.7
3.7.1 थोक व्यापार ¹	538744	531859	612701	632612	17.4	18.9
3.7.2 खुदरा व्यापार	487008	477612	518330	525263	7.9	10.0
3.8 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	469013 (400470)	463452 (393894)	523535 (476106)	526161 (481011)	12.2 (20.1)	13.5 (22.1)
3.9 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (एनबीएफसी) ² जिसमें से	1548027	1514950	1618650	1612332	4.2	6.4
3.9.1 आवास वित्त कंपनियाँ (एचएफसी)	325626	337759	325646	324575	-0.3	-3.9
3.9.2 सार्वजनिक वित्त संस्थाएँ (पीएफआई)	226963	213661	219865	217593	-4.1	1.8
3.10 अन्य सेवाएं ³	998281 (978198)	984420 (963850)	1128430 (1112253)	1141708 (1125683)	14.4 (15.1)	16.0 (16.8)
4. व्यक्तिगत ऋण	5331290 (4919468)	5263896 (4847945)	5831547 (5473924)	5878918 (5527053)	10.3 (12.4)	11.7 (14.0)
4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	23713	23969	23508	24506	3.3	2.2
4.2 आवास	2718715 (2331935)	2680411 (2289957)	2950974 (2614403)	2978759 (2647643)	9.6 (13.5)	11.1 (15.6)
4.3 मीयादी जमा राशि की जमानत पर अग्रिम	125239	120192	135900	134519	7.4	11.9
4.4 शेयरों और बॉण्डों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	8492	8401	9765	9808	15.5	16.7
4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	257016	258107	292084	287047	11.7	11.2
4.6 शिक्षा	119380	118708	135864	136821	14.6	15.3
4.7 वाहन ऋण	573398	565741	615236	619783	8.1	9.6
4.8 स्वर्ण आभूषण पर ऋण	102562	102008	178861	191198	86.4	87.4
4.9 अन्य व्यक्तिगत ऋण	1402775 (1377966)	1386360 (1361145)	1489354 (1468357)	1496477 (1475779)	6.7 (7.1)	7.9 (8.4)
5. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (मेमो)	-	-	-	-	-	-
(i) कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियाँ ⁴	2081856	2049198	2248829	2256770	8.4	10.1
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यम ⁵	1974191	1958526	2191766	2223843	12.6	13.5
(iii) मध्यम उद्यम ⁶	490703	480987	574228	584585	19.1	21.5
(iv) आवास	755222 (660572)	754645 (658400)	747261 (664181)	747435 (664855)	-1.0 (0.6)	-1.0 (1.0)
(v) शिक्षा ऋण	62235	62106	63056	62831	1.0	1.2
(vi) नवीकरणीय ऊर्जा	5991	5868	7559	8491	41.7	44.7
(vii) सामाजिक अवसंरचना	2613	2592	983	1233	-52.8	-52.4
(viii) निर्यात ऋण	11256	11075	12739	11827	5.1	6.8
(ix) अन्य	61336	62553	53143	50007	-18.5	-20.1
(x) नेट पीएसएलसी- एसएफ /एमएफ सहित कमजोर वर्ग	1647778	1624823	1793997	1789945	8.6	10.2

टिप्पणियाँ:

- (1) आंकड़े अंतिम हैं। बैंक ऋण, खाद्य ऋण और गैर-खाद्य ऋण आंकड़े धारा-42 रिटर्न पर आधारित हैं, जो सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) को कवर करता है, जबकि क्षेत्रीय गैर-खाद्य ऋण आंकड़े क्षेत्रवार और उद्योगवार बैंक ऋण (एसआईबीसी) रिटर्न पर आधारित हैं, जो महीने के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार से संबंधित, सभी एससीबी द्वारा दिए गए कुल गैर-खाद्य ऋण का लगभग 95 प्रतिशत हिस्सा देने वाले चुनिंदा बैंकों को कवर करता है।
- (2) 28 जुलाई, 2023 से आंकड़ों में एक गैर-बैंक के बैंक में विलय का प्रभाव शामिल है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विलय के प्रभाव को शामिल नहीं करते हैं।
1. थोक व्यापार में खाद्य ऋण संघ के बाहर खाद्य खरीद ऋण शामिल है।
2. एनबीएफसी में एचएफसी, पीएफआई, माइक्रोफाइनेंस संस्थान (एमएफआई), स्वर्ण ऋण देने वाली एनबीएफसी और अन्य शामिल हैं।
3. "अन्य सेवाओं" में म्यूचुअल फंड (एमएफ), एनबीएफसी और एमएफ के अलावा बैंकिंग और वित्त, और अन्य सेवाएं शामिल हैं जो सेवाओं के तहत कहीं और इंगित नहीं की गई हैं।
4. मई 2024 से, एक बैंक ने खुदरा खंड के तहत कृषि ऋण की एक श्रेणी के वर्गीकरण को "सोने के आभूषणों के खिलाफ ऋण" में बदल दिया है।
5. प्राथमिकता क्षेत्र के तहत "कृषि और संबद्ध गतिविधियाँ" में प्राथमिकता क्षेत्र ऋण प्रमाणपत्र (पीएसएलसी) भी शामिल हैं।
6. प्राथमिकता क्षेत्र के तहत "सूक्ष्म और लघु उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को ऋण शामिल हैं और इसमें पीएसएलसी भी शामिल हैं।
7. प्राथमिकता क्षेत्र के तहत "मध्यम उद्यम" में उद्योग और सेवा क्षेत्रों में मध्यम उद्यमों को ऋण शामिल है।

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन

(₹ करोड़)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 22, 2024	2024	2025		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			फर. 23	जन. 24		
	1	2	3	4	2025-26	2025
					%	%
2 उद्योग (2.1 से 2.19)	3652804 (3635810)	3616918 (3599906)	3874601 (3862535)	3875386 (3863437)	6.1 (6.3)	7.1 (7.3)
2.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	54166	54487	53191	53021	-2.1	-2.7
2.2 खाद्य प्रसंस्करण	208864	200451	217363	219092	4.9	9.3
2.2.1 चीनी	26383	23837	23147	26872	1.9	12.7
2.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	19700	18759	21313	21082	7.0	12.4
2.2.3 चाय	5692	5661	6116	6069	6.6	7.2
2.2.4 अन्य	157089	152194	166786	165068	5.1	8.5
2.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	31136	29929	30468	31296	0.5	4.6
2.4 वस्त्र	256048	255689	267676	273728	6.9	7.1
2.4.1 सूती वस्त्र	99199	98931	101271	106116	7.0	7.3
2.4.2 जूट से बने वस्त्र	4280	4275	4328	4329	1.2	1.3
2.4.3 मानव - निर्मित वस्त्र	45111	45974	49071	48906	8.4	6.4
2.4.4 अन्य वस्त्र	107458	106509	113005	114377	6.4	7.4
2.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	12588	12327	12711	12982	3.1	5.3
2.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	23839	23669	26895	27292	14.5	15.3
2.7 कागज और कागज से बने उत्पाद	46426	46405	51885	51942	11.9	11.9
2.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आणविक ईंधन	132356	135817	154402	154419	16.7	13.7
2.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	249347	246408	265385	263166	5.5	6.8
2.9.1 उर्वरक	37569	36366	31244	30527	-18.7	-16.1
2.9.2 औषधि और दवाइयां	81036	80768	88010	88941	9.8	10.1
2.9.3 पेट्रो केमिकल्स	23157	23008	27832	25742	11.2	11.9
2.9.4 अन्य	107584	106266	118299	117956	9.6	11.0
2.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	90420	90019	100175	101706	12.5	13.0
2.11 कांच और कांच के सामान	12090	11666	12611	13198	9.2	13.1
2.12 सीमेंट और सीमेंट से बने उत्पाद	59757	60574	60576	60313	0.9	-0.4
2.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	384447	381371	434354	431320	12.2	13.1
2.13.1 लोहा और स्टील	273803	270540	308145	301743	10.2	11.5
2.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	110645	110831	126210	129576	17.1	16.9
2.14 सभी अभियांत्रिकी	196643	195280	229142	232448	18.2	19.0
2.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	43175	44134	51243	49647	15.0	12.5
2.14.2 अन्य	153468	151146	177899	182801	19.1	20.9
2.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	113185	110497	117775	117109	3.5	6.0
2.16 रत्न और आभूषण	84860	81651	86364	83040	-2.1	1.7
2.17 निर्माण	133520	133235	145199	149730	12.1	12.4
2.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1304096	1292329	1309202	1302686	-0.1	0.8
2.18.1 बिजली	644042	645097	664682	660874	2.6	2.4
2.18.2 दूरसंचार	138192	127825	124061	116448	-15.7	-8.9
2.18.3 सड़क	318072	317768	314494	315924	-0.7	-0.6
2.18.4 हवाई अड्डा	7280	7384	8682	8799	20.9	19.2
2.18.5 बंदरगाह	6681	7838	5465	5879	-12.0	-25.0
2.18.6 रेलवे	13062	12144	13306	13293	1.8	9.5
2.18.7 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	176767	174274	178513	181469	2.7	4.1
2.19 अन्य उद्योग	259016	255113	299228	296900	14.6	16.4

टिप्पणी : 28 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक गैर-बैंक के बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है। कोष्ठक में दिए गए आंकड़ों में विलय के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(₹ करोड़)

मद	रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति								
	2023-24	2024					2025		
		जन. 26	नव. 15	नव. 29	दिसं. 13	दिसं. 27	जन. 10	जन. 24	जन. 31
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
रिपोर्टिंग बैंकों की संख्या	33	33	34	34	34	34	34	34	34
1 कुल जमाराशियाँ (2.1.1.2+2.2.1.2)	138788.9	135053.7	138073.1	138154.1	131867.2	140702.2	141951.5	140580.6	137422.7
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	30226.7	28067.3	26021.8	26562.1	26329.5	25817.1	25505.2	24519.2	25128.9
2.1.1 जमाराशियाँ									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	9101.3	7628.0	7239.1	6670.1	6850.3	6676.5	6951.0	6903.9	6389.8
2.1.1.2 अन्य	15000.4	14877.1	13293.6	13187.7	12967.4	13201.0	12879.1	12582.5	12576.7
2.1.2 बैंकों से उधार	130.0	99.9	449.8	1454.3	1576.4	997.9	791.7	12.0	789.3
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	5995.0	5462.2	5039.2	5249.9	4935.4	4941.7	4883.3	5020.9	5373.1
2.2 मीयादी देयताएं	198141.8	181797.1	178177.3	176625.0	168281.8	179599.5	182473.8	182418.4	178875.8
2.2.1 जमाराशियाँ									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	72308.4	58233.2	51788.5	50047.3	47748.7	50440.5	51697.4	52718.8	52326.4
2.2.1.2 अन्य	123788.5	120176.6	124779.5	124966.4	118899.8	127501.2	129072.3	127998.0	124846.0
2.2.2 बैंकों से उधार	673.6	2181.3	651.9	651.9	651.9	651.9	650.8	650.8	650.8
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	1371.3	1206.0	957.3	959.5	981.4	1005.9	1053.3	1050.8	1052.6
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	100.0							
4 अधिसूचित बैंक/ सरकार से उधार	95914.5	90881.7	173712.9	112111.7	114646.7	112137.9	112172.3	114464.9	111993.8
4.1 मांग	27317.7	23859.7	102827.6	45109.3	44426.4	44100.3	43778.8	44280.0	44397.3
4.2 मीयादी	68596.8	67022.0	70885.3	67002.4	70220.3	68037.6	68393.5	70184.9	67596.4
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	16263.7	11043.1	12004.2	11145.5	12024.9	11868.9	10869.4	10837.2	11244.6
5.1 उपलब्ध नकदी	960.0	742.4	772.6	821.1	773.9	845.0	763.4	699.7	777.4
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेषराशि	15303.7	10300.8	11231.6	10324.4	11251.0	11023.9	10106.0	10137.5	10467.2
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेषराशि	2088.1	1446.5	1035.0	1118.1	1287.5	1010.4	1217.9	1262.1	1204.8
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	77700.5	73701.6	75275.2	75074.9	74143.9	74779.2	75371.7	75514.9	75052.7
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	34355.3	27662.3	15588.7	12457.8	13852.0	12854.5	17090.8	15819.4	12239.3
9 बैंक ऋण (10.1+11)	135141.9	132726.7	167629.4	166666.0	141596.3	168136.4	169458.4	170580.3	170245.1
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	134936.8	132569.3	167432.0	166480.4	141403.7	167935.8	169247.9	170385.3	170045.3
10.2 बैंकों से प्राप्त राशि	142185.2	136927.3	113950.8	111546.4	110681.2	110877.6	110955.4	112689.7	112047.0
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	205.1	157.5	197.4	185.6	192.6	200.6	210.4	195.0	199.8

कीमत और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2023-24			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	मार्च 24	फर. 25	मार्च 25 (अ)	मार्च 24	फर. 25	मार्च 25 (अ)	मार्च 24	फर. 25	मार्च 25 (अ)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	185.9	192.7	188.4	188.5	195.4	194.0	194.4	201.3	200.1	190.7	197.6	196.2
1.1 अनाज और उत्पाद	181.4	181.7	181.5	189.3	200.6	200.8	188.5	198.6	198.9	189.0	200.0	200.2
1.2 मांस और मछली	213.0	221.3	215.9	217.9	219.1	218.1	226.7	229.0	228.3	221.0	222.6	221.7
1.3 अंडा	185.4	189.5	187.0	192.7	194.9	185.3	194.3	200.0	190.3	193.3	196.9	187.2
1.4 दूध और उत्पाद	181.4	181.5	181.4	183.2	187.6	187.9	183.6	188.4	188.3	183.3	187.9	188.0
1.5 तेल और चर्बी	165.3	158.7	162.9	160.2	188.9	189.7	154.7	176.0	177.4	158.2	184.2	185.2
1.6 फल	172.1	179.9	175.7	172.8	195.1	201.6	176.7	198.7	204.7	174.6	196.8	203.0
1.7 सब्जी	183.9	229.9	199.5	182.5	181.2	171.0	222.6	216.8	204.3	196.1	193.3	182.3
1.8 दाल और उत्पाद	192.2	196.5	193.7	199.7	200.2	194.3	205.0	205.1	199.3	201.5	201.9	196.0
1.9 चीनी और उत्पाद	126.2	128.1	126.9	128.0	131.4	133.1	130.1	133.8	135.0	128.7	132.2	133.7
1.10 मसाले	238.0	228.4	234.8	236.3	224.8	222.9	228.2	222.1	220.5	233.6	223.9	222.1
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	180.7	168.2	175.5	182.1	188.3	188.9	170.3	177.3	178.0	177.2	183.7	184.3
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	193.3	200.9	196.8	195.9	202.4	202.9	204.6	214.0	214.9	199.9	207.8	208.5
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	202.0	207.1	203.3	204.0	209.0	209.7	210.2	213.4	213.8	205.7	210.2	210.8
3 कपड़ा और जूते	192.9	181.5	188.4	195.1	199.8	200.0	183.8	188.6	189.0	190.6	195.4	195.6
3.1 कपड़ा	193.5	183.5	189.6	195.8	200.7	201.0	185.8	190.8	191.2	191.9	196.8	197.1
3.2 जूते	189.4	170.2	181.4	191.1	194.1	194.3	172.3	176.2	176.7	183.3	186.7	187.0
4 आवास	--	176.7	176.7	--	--	--	178.2	183.7	183.6	178.2	183.7	183.6
5 ईंधन और बिजली	183.0	178.9	181.4	181.0	182.8	182.7	167.4	171.0	171.3	175.8	178.3	178.4
6 विविध	181.7	173.7	177.8	184.2	192.9	193.5	176.0	183.8	184.6	180.2	188.5	189.2
6.1 घरेलू सामान और सेवा	181.5	171.8	176.9	183.3	187.7	187.3	174.0	179.1	179.6	178.9	183.6	183.7
6.2 स्वास्थ्य	190.8	185.2	188.7	194.3	201.6	202.4	189.1	196.3	197.4	192.3	199.6	200.5
6.3 परिवहन और संचार	171.1	161.4	166.0	172.0	177.7	178.1	161.9	166.6	166.9	166.7	171.9	172.2
6.4 मनोरंजन	175.8	171.1	173.2	177.8	181.9	181.1	172.8	177.3	177.7	175.0	179.3	179.2
6.5 शिक्षा	184.0	179.1	181.1	186.1	192.6	193.1	181.2	188.2	188.6	183.2	190.0	190.5
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और संबंधित सामन	186.3	187.4	186.8	191.3	214.2	216.8	192.8	216.3	219.2	191.9	215.1	217.8
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	185.6	182.4	184.1	187.8	194.5	193.9	183.6	190.1	189.9	185.8	192.5	192.0

स्रोत : केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

अ: अंतिम

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2023-24	2024	2025	
				फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2016	2.88	137.9	139.2	143.2	142.8
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	1229	1258	1316	1309
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	-	1240	1269	1328	1321

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में स्वर्ण और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2023-24	2024	2025	
	1	फर.	जन.	फर.
		2	3	4
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	60624	62017	79079	84995
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	72243	70328	90020	95524

स्रोत: मुंबई में स्वर्ण और चांदी के मूल्य के लिए इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि. मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक
(आधार: 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2024	2025		
			मार्च	जन.	फर.(अ)	मार्च (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	100.000	151.4	151.4	155.0	154.8	154.5
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	183.0	183.2	189.7	186.6	184.6
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	191.3	191.4	199.8	195.8	194.4
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+दाल)	3.462	193.8	202.3	213.2	212.1	210.1
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	210.2	197.2	210.7	198.1	196.4
1.1.1.3 दूध	4.440	180.3	184.2	187.0	186.4	186.8
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	172.1	168.9	174.7	171.5	170.1
1.1.1.5 मसाले	0.529	235.4	233.5	231.6	213.1	201.1
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	189.5	198.8	217.1	223.0	223.1
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	162.4	160.0	167.5	166.8	162.8
1.1.2.1 फाइबर	0.839	168.0	165.0	161.5	161.8	162.4
1.1.2.2 तिलहन	1.115	185.0	178.7	183.4	178.9	179.3
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	134.9	133.7	142.7	143.1	142.0
1.1.2.4 पुष्पोत्पादन	0.204	279.7	291.0	343.7	349.2	274.6
1.1.3 खनिज	0.833	217.7	221.6	227.2	227.2	227.9
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	204.2	212.6	216.3	216.3	214.6
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	265.0	253.2	265.7	265.5	274.7
1.1.4 कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस	2.410	153.6	157.1	150.9	148.7	145.1
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	152.0	152.1	152.0	153.8	152.4
1.2.1 कोयला	2.138	136.4	135.8	135.6	135.6	135.6
1.2.1.1 कुकिंग कोयला	0.647	143.4	143.4	143.4	143.4	143.4
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोयला	1.401	124.8	125.8	125.8	125.8	125.8
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	267.6	236.0	231.0	231.0	231.2
1.2.2 खनिज तेल	7.950	159.0	159.4	155.0	157.9	156.8
1.2.3 बिजली	3.064	145.0	144.6	155.8	156.1	152.5
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	140.2	140.1	143.4	143.8	144.4
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	160.5	162.1	177.5	177.8	179.4
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	145.3	151.3	157.3	158.1	160.0
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियन, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	142.9	149.6	145.4	146.0	146.6
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	130.4	130.2	132.8	132.3	133.8
1.3.1.4 सब्जियां और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	145.0	145.7	187.5	188.5	190.8
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	179.1	178.8	181.9	182.8	182.9
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	175.6	182.7	190.4	189.8	188.8
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	157.1	166.2	164.1	162.8	161.1
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	165.4	165.8	174.9	174.9	176.1
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	134.6	136.7	138.6	141.4	143.4
1.3.1.10 कोकोआ, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	139.8	142.4	171.7	172.2	174.5
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, और कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	149.9	148.8	161.0	159.2	171.5
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	176.2	161.9	161.8	156.1	178.9
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	192.1	195.5	194.1	192.1	188.8
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	146.3	146.9	155.4	154.7	155.5
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	179.1	174.9	189.5	188.1	186.5
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	208.3	203.9	199.0	197.4	195.5
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	131.5	132.5	134.4	134.5	134.6
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	133.3	134.1	136.9	137.4	137.6
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	135.6	136.6	138.9	138.9	139.1
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी का उत्पादन	0.275	125.5	126.7	126.8	126.5	126.4
1.3.3 तंबाकू उत्पादों का विनिर्माण	0.514	173.5	176.3	181.2	180.0	180.2
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	173.5	176.3	181.2	180.0	180.2

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2024	2025		
			मार्च	जन.	फर.(अ)	मार्च (अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	134.6	134.3	137.0	137.0	136.6
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	120.1	119.8	120.8	120.8	120.6
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	157.5	156.3	160.9	161.1	159.5
1.3.4.3 बुने हुए और क्रोशिए से बना कपड़ा	0.193	120.0	120.6	124.1	124.8	124.4
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	156.6	158.7	162.0	160.4	161.9
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	139.2	137.6	146.1	147.8	147.6
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	129.6	131.6	136.6	136.5	137.2
1.3.5 तैयार वस्त्र का विनिर्माण	0.814	150.8	151.5	154.2	154.3	154.5
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर, तैयार वस्त्र (बुने हुए) का विनिर्माण	0.593	148.7	148.7	151.4	151.8	152.2
१.३.५.२ बुने हुए और क्रोशिए से बने वस्त्र	0.221	156.6	159.0	161.6	161.2	160.6
1.3.6 चमड़ा और संबंधित उत्पाद का विनिर्माण	0.535	124.1	123.7	127.5	125.8	126.2
१.३.६.१ चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगाई	0.142	107.3	104.8	112.2	107.7	107.0
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और हार्नेस	0.075	140.9	140.7	142.3	143.0	143.0
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	127.7	128.1	130.9	129.9	130.8
१.३.७ लकड़ी व लकड़ी और कॉर्क के उत्पादों का विनिर्माण	0.772	146.6	149.1	149.6	148.8	150.0
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	137.8	139.4	141.7	141.6	141.3
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड, लैमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पैनल और बोर्ड का विनिर्माण	0.493	146.1	149.0	149.0	147.5	149.7
1.3.7.3 बिल्डरों की बढईगिरी	0.036	206.4	214.1	214.5	215.1	215.1
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	139.8	140.0	140.6	141.7	140.7
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पादों का विनिर्माण	1.113	140.3	138.0	139.5	140.8	141.3
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और पेपर बोर्ड	0.493	147.6	144.5	144.5	145.2	145.8
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	140.9	143.4	149.0	150.8	150.6
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	128.0	121.8	121.6	123.7	124.4
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	182.3	184.6	190.0	190.7	189.9
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	182.3	184.6	190.0	190.7	189.9
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पादों का विनिर्माण	6.465	136.9	135.6	136.8	137.1	136.9
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	139.9	136.5	139.7	140.7	141.2
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	142.8	142.6	142.9	143.6	142.4
1.3.10.3 प्लास्टिक और प्राथमिक रूप में सिंथेटिक रबड़	1.001	132.3	132.4	133.8	134.1	133.9
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकेमिकल उत्पाद	0.454	132.8	130.5	129.2	129.2	129.9
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	143.7	141.0	139.1	138.5	138.4
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	139.7	138.0	140.6	140.8	141.2
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	134.4	134.5	135.5	135.1	134.1
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	103.6	103.6	104.7	104.1	104.9
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	142.9	143.4	145.0	145.0	145.2
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	142.9	143.4	145.0	145.0	145.2
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पादों का विनिर्माण	2.299	127.5	128.2	129.3	129.7	129.7
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रिट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	113.7	113.8	117.1	117.2	117.0
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	107.3	108.6	112.6	113.0	112.6
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	137.3	138.2	137.8	138.3	138.4
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	134.7	133.1	132.2	132.6	132.7
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	163.8	163.9	163.7	163.8	163.4
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	119.7	119.7	125.2	126.2	126.0
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	123.9	119.9	134.5	132.4	133.5
1.3.13.4 चीनी मिट्टी और चीनी मिट्टी के उत्पाद	0.222	122.3	124.4	125.1	125.1	124.7
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	137.3	134.3	130.2	131.2	131.6

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2024	2025		
			मार्च	जन.	फर.(अ)	मार्च.(अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.13.6 कंक्रीट, सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	137.7	137.2	140.4	140.4	138.8
1.3.13.7 पत्थरों को काटना, आकार देना और संवारना	0.234	130.3	131.7	135.4	136.0	136.8
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	102.4	100.9	94.1	92.2	92.3
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	141.0	138.7	137.2	137.6	139.1
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	140.3	134.6	129.4	129.2	131.1
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	153.6	147.4	131.5	131.6	136.3
1.3.14.3 नरम इस्पात - अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	119.9	117.0	117.3	117.3	118.2
1.3.14.4 नरम इस्पात - लंबे उत्पाद	1.081	141.3	138.9	138.5	138.4	140.1
1.3.14.5 नरम इस्पात - चपटे उत्पाद	1.144	143.4	138.7	128.9	129.6	129.5
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	137.6	134.3	132.7	132.1	133.6
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील - अर्ध निर्मित	0.924	136.4	131.1	127.5	127.4	131.0
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	169.7	169.8	163.7	164.1	164.5
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	144.8	146.4	158.6	160.8	161.4
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	141.0	146.1	144.2	144.6	144.7
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	173.3	170.8	172.4	169.7	174.2
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	138.6	136.2	135.3	136.2	136.4
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	132.3	130.6	130.2	132.0	131.2
1.3.15.2 धातु से बने टैंक, जलाशय और डिब्बे	0.660	157.6	155.3	147.2	147.0	148.5
1.3.15.3 वाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलर्स को छोड़कर	0.145	106.3	106.0	108.1	108.0	110.9
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैम्पिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	141.4	136.8	137.9	139.6	139.7
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	108.4	101.5	102.3	102.5	102.4
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	143.8	142.3	145.3	145.6	145.7
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	119.3	120.4	121.5	121.5	121.1
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	115.0	115.5	118.6	119.0	119.5
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	135.3	135.3	132.7	131.0	131.8
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	136.1	139.5	146.3	146.2	146.5
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	103.6	103.7	99.9	100.6	99.1
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	113.8	118.2	121.9	121.9	121.9
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	157.2	159.9	172.7	172.2	172.0
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	108.3	108.4	116.1	117.0	110.3
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	103.8	105.2	107.9	108.3	108.3
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	131.4	131.9	134.0	134.1	134.4
1.3.17.1 विद्युत मोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	130.1	130.6	133.1	133.0	133.5
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	137.8	140.4	140.9	141.5	141.8
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	123.4	121.2	114.3	115.9	116.0
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	146.1	146.9	155.0	155.2	156.6
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	116.8	117.6	118.1	117.8	117.5
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	133.8	133.3	131.8	132.0	131.3
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	120.9	121.8	124.7	124.8	123.8
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	129.0	129.9	131.1	131.2	131.5
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	128.9	130.6	132.6	134.5	134.3
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	131.9	132.3	135.6	135.7	135.7
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	117.4	117.7	118.9	119.0	119.0
१.३.१८.४ बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	127.7	129.6	129.7	128.6	129.1
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	83.7	85.3	88.3	87.3	88.4
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने – उतारने वाले उपकरण	0.285	128.6	129.9	130.1	130.0	130.7

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)

(आधार: 2011-12=100)

पण्य वस्तुएँ	भार	2023-24	2024	2025		
			मार्च	जन.	फर.(अ)	मार्च.(अ)
	1	2	3	4	5	6
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	130.2
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	145.2	144.6	141.9	140.3	142.7
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	142.5	143.9	146.6	147.0	146.5
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	122.5	122.4	124.1	123.3	123.5
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	88.6	89.3	91.0	91.3	91.5
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	124.4	124.4	126.9	127.1	126.8
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	137.2	137.7	145.1	145.1	147.1
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	144.7	146.4	144.0	144.2	144.4
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	70.8	69.7	69.0	69.3	69.3
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	4.969	128.4	129.9	130.1	130.2	130.3
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	128.5	130.6	131.0	131.0	131.2
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	128.2	129.0	129.0	129.3	129.3
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	143.1	143.6	145.7	145.9	148.5
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली – वस्तुओं का निर्माण	0.117	163.7	163.7	188.4	188.4	188.4
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	107.4	108.5	109.2	109.3	109.6
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	144.7	145.3	146.0	146.2	149.4
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	137.9	137.6	134.4	134.5	135.4
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	159.2	158.5	165.7	164.9	165.5
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	159.6	158.4	161.8	162.0	161.9
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	159.6	158.4	161.8	162.0	161.9
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	158.2	164.1	187.8	197.0	201.7
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	157.9	164.3	189.7	199.5	204.4
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	187.0	192.0	197.2	199.9	201.4
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	155.2	154.5	167.7	168.2	168.1
1.3.22.4 खेल और खेलौने	0.005	159.6	160.0	164.8	164.9	164.5
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और संबंधित सामग्री	0.049	163.1	161.2	156.5	156.5	158.6
2 खाद्य सूचकांक	24.378	179.8	180.4	191.5	189.0	188.8

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भार	2022-23	2023-24	अप्रै-फरवरी		फरवरी	
				2023-24	2024-25	2024	2025
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	138.5	146.7	145.5	151.4	147.1	151.3
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन	14.37	119.9	128.9	126.4	130.5	139.7	141.9
1.2 विनिर्माण	77.63	137.1	144.7	143.6	149.5	144.4	148.6
1.3 बिजली	7.99	185.2	198.3	197.8	207.6	187.2	194.0
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	139.2	147.7	146.3	152.0	148.2	152.3
2.2 पूंजीगत माल	8.22	100.3	106.6	104.3	110.5	106.7	115.5
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	149.4	157.3	156.2	163.0	157.6	159.9
2.4 इन्फ्रास्ट्रक्चर/निर्माण वस्तुएं	12.34	160.7	176.3	174.6	185.7	179.5	191.3
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	114.5	118.6	117.5	127.1	121.9	126.5
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	147.7	153.7	153.6	151.5	149.9	146.7

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी लेखा और खजाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार का लेखा - एक नज़र में

(₹ करोड़)

Item	वित्तीय वर्ष	अप्रैल-फरवरी			
	2024-25 (संशोधित अनुमान)	2024-25 वास्तविक आंकड़े	2023-24 वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों का प्रतिशत	
	1	2	3	2024-25	2023-24
1 राजस्व प्राप्ति	3087960	2508953	2209782	81.2	81.9
1.1 कर राजस्व (निवल)	2556960	2015634	1849452	78.8	79.6
1.2 करेतर राजस्व	531000	493319	360330	92.9	95.9
2 गैर कर्ज पूंजीगत प्राप्ति	59000	37364	36140	63.3	64.5
2.1 ऋण की वसूली	26000	21655	23480	83.3	90.3
2.2 अन्य प्राप्ति	33000	15709	12660	47.6	42.2
3 कुल प्राप्ति (लिए गए उधार को छोड़कर) (1+2)	3146960	2546317	2245922	80.9	81.5
4 राजस्व व्यय जिसमें से :	3698058	3081282	2941674	83.3	83.1
4.1 ब्याज भुगतान	1137940	952844	880788	83.7	83.5
5 पूंजी व्यय	1018429	811887	805613	79.7	84.8
6 कुल व्यय (4+5)	4716487	3893169	3747287	82.5	83.4
7 राजस्व घाटा (4-1)	610098	572329	731892	93.8	87.1
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	1569527	1346852	1501365	85.8	86.5
9 सकल प्राथमिक घाटा [8-4.1]	431587	394008	620577	91.3	91.3

स्रोत: महालेखानियंत्रक (सीजीए), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार और अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25।

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2024	2025					
		मार्च 1	जन. 24	जन. 31	फर. 7	फर. 14	फर. 21	फर. 28
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	18054	9315	6520	7728	5632	7326	7071	7786
1.2 प्राथमिक व्यापारी	22676	18037	14311	13506	17806	15967	14883	14025
1.3 राज्य सरकारें	5701	16384	78012	78400	82800	82315	78315	73415
1.4 अन्य	88670	90048	100968	107166	110763	115907	108845	116990
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	84913	74430	39047	36704	35399	38165	35549	37126
2.2 प्राथमिक व्यापारी	87779	76367	46104	51382	50792	53182	52538	54510
2.3 राज्य सरकारें	4070	5037	8268	8243	8243	7422	7422	7528
2.4 अन्य	102311	96207	86549	85014	88109	84953	81213	85164
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	91819	86887	72359	73685	74285	73520	69687	66240
3.2 प्राथमिक व्यापारी	159085	172500	108412	109263	106534	112772	110441	112173
3.3 राज्य सरकारें	41487	44491	34014	36794	36365	36583	36494	36713
3.4 अन्य	165095	176613	156229	153053	154181	147709	151871	151587
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	318736	317650	298216	271755	191566	266338	290903	291002
4.4 अन्य	442	296	838	694	410	485	2591	38
कुल खज़ाना बिल (14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल को छोड़कर)#	871662	866316	750794	760937	770908	775820	754331	763256

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं हैं। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है, क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।

सं. 25: खज़ाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां			स्वीकृत बोलियाँ			कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य (₹)	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य				
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
91-दिवसीय खज़ाना बिल										
2024-25										
जन. 29	12000	138	39833	2879	44	11959	2879	14838	98.39	6.5625
फर. 5	12000	149	41861	6534	42	11966	6534	18500	98.41	6.4681
फर. 12	12000	117	32652	1424	63	11964	1424	13389	98.42	6.4445
फर. 20	14000	131	27118	5452	0	0	0	0	-	-
फर. 27	14000	136	34624	6168	74	13932	6168	20100	98.42	6.4490
182-दिवसीय खज़ाना बिल										
2024-25										
जन. 29	8000	84	25022	1019	41	7981	1019	9000	96.78	6.6691
फर. 5	8000	96	22886	715	55	7985	715	8700	96.82	6.5801
फर. 12	8000	70	16516	194	42	7984	194	8179	96.83	6.5700
फर. 20	12000	74	20772	1016	0	0	0	0	-	-
फर. 27	12000	96	23642	1775	66	11976	1775	13751	96.81	6.5989
364-दिवसीय खज़ाना बिल										
2024-25										
जन. 29	8000	138	41006	2931	27	7990	2931	10921	93.79	6.6345
फर. 5	8000	124	32756	174	31	7987	174	8160	93.87	6.5440
फर. 12	8000	88	26315	318	44	7968	318	8287	93.87	6.5500
फर. 20	7000	72	19287	46	32	6990	46	7036	93.86	6.5638
फर. 27	7000	104	27673	239	33	6988	239	7228	93.88	6.5409

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा	भारित औसत दरें
	उधार लेना / उधार देना	उधार लेना / उधार देना
	1	2
फरवरी 01 ,2025	5.50-6.65	6.23
फरवरी 03 ,2025	5.10-6.65	6.55
फरवरी 04 ,2025	5.10-6.65	6.49
फरवरी 05 ,2025	5.15-6.60	6.46
फरवरी 06 ,2025	5.15-6.60	6.45
फरवरी 07 ,2025	5.15-6.55	6.25
फरवरी 10 ,2025	5.15-6.45	6.29
फरवरी 11 ,2025	5.15-6.42	6.32
फरवरी 12 ,2025	5.15-6.40	6.29
फरवरी 13 ,2025	5.15-6.50	6.34
फरवरी 14 ,2025	5.15-6.50	6.35
फरवरी 15 ,2025	5.25-6.50	5.89
फरवरी 17 ,2025	5.15-6.65	6.34
फरवरी 18 ,2025	5.25-6.50	6.35
फरवरी 20 ,2025	5.15-6.45	6.35
फरवरी 21 ,2025	5.15-6.60	6.29
फरवरी 24 ,2025	5.15-6.45	6.32
फरवरी 25 ,2025	5.15-6.65	6.31
फरवरी 27 ,2025	5.15-6.45	6.31
फरवरी 28 ,2025	5.15-6.65	6.36
मार्च 01 ,2025	5.70-6.45	5.91
मार्च 03 ,2025	5.15-6.45	6.32
मार्च 04 ,2025	5.15-6.40	6.27
मार्च 05 ,2025	5.25-6.40	6.23
मार्च 06 ,2025	5.15-6.35	6.21
मार्च 07 ,2025	5.15-6.40	6.25
मार्च 10 ,2025	5.15-6.40	6.26
मार्च 11 ,2025	5.15-6.45	6.30
मार्च 12 ,2025	5.15-6.40	6.27
मार्च 13 ,2025	5.15-6.45	6.33
मार्च 15 ,2025	5.25-6.40	6.05

टिप्पणी: इसमें नोटिस मनी भी शामिल है।

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2024	2025				2025	
	फर. 23	जन. 10	जन. 24	फर. 7	फर. 21	मार्च. 7	मार्च. 21
	1	2	3	4	5	6	7
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	381444.86	493930.59	499396.94	519276.82	513816.40	511207.89	532971.66
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (₹ करोड़)	63348.26	33890.42	30080.60	71093.96	30077.77	70936.37	117053.02
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	7.17-8.22	7.05-7.48	7.07-7.88	7.03-7.83	7.02-7.93	7.02-8.02	6.98-8.05

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2024	2025				2025	
	फर. 29	जन. 15	जन. 31	फर. 15	फर. 28	मार्च. 15	मार्च. 31
	1	2	3	4	5	6	7
1 बकाया राशि (₹ करोड़)	408048.25	450242.05	456483.15	479257.25	465926.95	457051.30	442892.70
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (₹ करोड़)	82067.80	39647.30	69001.15	80693.35	64880.85	107624.20	77133.85
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	7.05-11.91	7.06-12.12	7.12-13.77	6.97-12.40	6.78-12.24	6.67-11.78	7.00-14.46

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक कारोबार

(₹ करोड़)

मद	2023-24	2024	2025					
		मार्च. 1	जन. 24	जन. 31	फर. 7	फर. 14	फर. 21	फर. 28
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	17761	18315	20631	23225	23493	22880	23232	25329
2 नोटिस मुद्रा	2550	4361	598	4419	269	5854	472	8886
3 मीयादी मुद्रा	871	1311	798	976	699	1109	532	1425
4 त्रिपक्षीय रेपो	601363	712802	649147	744181	645390	788692	648196	802167
5 बाजार रेपो	574534	652752	525850	606457	568944	658189	521248	627685
6 कॉरपोरेट बॉण्ड में रेपो	1817	2620	6711	7411	8450	7343	7841	7237
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	95115	122015	133491	137918	143060	147352	129410	155172
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	90992	59429	127533	126216	124531	99396	77969	86173
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	6102	10427	7675	10831	9153	6885	10974	16088
10 खज़ाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	5378	3740	6107	5708	5072	5368	3585	5438
10.2 182-दिवसीय	6079	5309	2691	2525	3052	3390	2016	4596
10.3 364-दिवसीय	4307	3685	1893	3326	3273	5458	3548	4148
10.4 नकदी प्रबंधन बिल		0	0	0	0	0	0	0
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	112858	82589	145899	148605	145081	120496	98091	116444
11.1 भारतीय रिज़र्व बैंक	492	760	4307	5572	249	8342	10385	704

सं. 30: गैर-सरकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि ₹ करोड़ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2023-24		2023-24 (Apr.-Feb.)		2024-25 (Apr.-Feb.) *		Feb. 2024		Feb. 2025 *	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	339	80942	303	76666	443	208151	35	15643	31	15513
1.1 पब्लिक	272	65832	246	61976	310	189947	29	7684	21	14745
1.2 राइट्स	67	15110	57	14690	133	18204	6	7959	10	768
2 बॉण्ड और डिबेंचर	44	16342	41	15639	52	7694	4	517	14	297
3 कुल (1+2+3)	383	97284	344	92305	495	215845	39	16160	45	15810
3.1 पब्लिक	316	82174	287	77615	362	197641	33	8201	35	15042
3.2 राइट्स	67	15110	57	14690	133	18204	6	7959	10	768

टिप्पणी: 1. अप्रैल 2020 से इक्विटी निर्गमों का मासिक डेटा उनकी लिस्टिंग की तारीख के आधार पर संकलित किया गया है।
2. संख्याओं के पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़े कुल में न जुड़ पाने की संभावना है।
3. सारणी में केवल इक्विटी और ऋण के सार्वजनिक और अधिकार निर्गम शामिल हैं। इसमें ऋण के निजी प्लेसमेंट, योग्य संस्थागत प्लेसमेंट और अधिमान्य आवंटन के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

स्रोत: भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31 : विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2023-24	2024				2025	
			फर.	अक्तू.	नव.	दिसं.	जन.	फर.
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	₹ करोड़	3618952	343516	327466	269603	321264	313936	321343
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	437072	41406	38970	31957	37802	36392	36913
1.1 तेल	₹ करोड़	696850	68163	37000	29821	39998	30311	50620
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	84157	8216	4403	3535	4706	3514	5815
1.2 तेल से इतर	₹ करोड़	2922102	275353	290466	239782	281265	283625	270724
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	352915	33190	34567	28422	33095	32878	31098
2 आयात	₹ करोड़	5616042	505408	546768	539310	496988	512696	443664
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	678215	60919	65069	63926	58479	59432	50964
2.1 तेल	₹ करोड़	1480232	140134	158683	134206	115546	115942	103530
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	178733	16891	18884	15908	13596	13440	11893
2.2 तेल से इतर	₹ करोड़	4135810	365274	388085	405103	381442	396754	340133
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	499482	44028	46184	48018	44883	45992	39071
3 व्यापार शेष	₹ करोड़	-1997090	-161892	-219301	-269707	-175724	-198760	-122321
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-241143	-19514	-26098	-31969	-20677	-23040	-14051
3.1 तेल	₹ करोड़	-783382	-71972	-121683	-104386	-75547	-85631	-52911
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-94576	-8675	-14481	-12373	-8889	-9926	-6078
3.2 तेल से इतर	₹ करोड़	-1213708	-89921	-97619	-165321	-100177	-113129	-69410
	मिलियन अमेरिकी डॉलर	-146567	-10839	-11617	-19596	-11787	-13114	-7973

टिप्पणी: सारणी में डेटा अनंतिम हैं।
स्रोत : वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियां

मद	इकाई	2024	2025					
		अप्रै. 05	फर. 21	फर. 28	मार्च 07	मार्च 14	मार्च 21	मार्च 28
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल आरक्षित निधियां	₹ करोड़	5401575	5553750	5589313	5682099	5692791	5662867	5687095
	यूएस \$ मिलियन	648562	640479	638698	653966	654271	658800	665396
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	₹ करोड़	4756930	4715811	4754944	4841987	4848035	4803678	4829095
	यूएस \$ मिलियन	571166	543843	543350	557282	557186	558856	565014
1.2 स्वर्ण	₹ करोड़	454381	646668	641218	645780	647273	664219	664889
	यूएस \$ मिलियन	54558	74576	73272	74325	74391	77275	77793
	मात्रा (मीट्रिक टन)	822.09	879.01	879.01	879.01	879.01	879.01	879.58
1.3 एसडीआर	एसडीआर मिलियन	13694	13706	13706	13706	13706	13706	13706
	₹ करोड़	151325	155830	157504	158222	158894	156784	155344
	यूएस \$ मिलियन	18170	17971	17998	18210	18262	18240	18176
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	₹ करोड़	38939	35441	35646	36110	38588	38186	37768
	यूएस \$ मिलियन	4669	4090	4078	4148	4431	4429	4413

* अंतर यदि कोई हो, तो पूर्णांकन की वजह से है।
टिप्पणी : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वेप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा को आस्तियों में रिजर्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास के लिए शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियाँ

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2023-24	2024	2025		2023-24	2024-25
		फर.	जन.	फर.(अ)	अप्रै.-फर.	अप्रै.-फर.(अ)
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियाँ	151879	149724	161212	160339	11808	14558
1.1 एफसीएनआर (बी)	25733	24902	32754	32492	5538	6759
1.2 एनआर (ई) आरए	98624	97682	98495	97938	2636	4010
1.3 एनआरओ	27522	27140	29963	29908	3633	3790

अ: अनंतिम।

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2023-24	2023-24	2024-25 (अ)	2024 (अ)	2025 (अ)	
		अप्रै.-फर.	अप्रै.-फर.	फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	10129	11495	1460	-28	1150	-1247
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	26807	24511	26231	1203	3996	2673
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह / सकल निवेश	71279	65179	75105	5006	6061	5471
1.1.1.1.1 इक्विटी	45817	41949	47753	2774	3451	2919
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	585	521	1901	47	16	37
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	31826	28718	32246	2136	2588	2291
1.1.1.1.1.3 शेयरों का अधिग्रहण	12013	11442	12719	466	759	502
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की इक्विटी पूंजी	1394	1269	887	125	88	88
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	19768	17990	21414	1777	2130	2130
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	5694	5239	5938	454	479	421
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	44472	40668	48873	3804	2065	2797
1.1.1.2.1 इक्विटी	41334	37690	47003	3645	2009	2669
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	3137	2978	1870	159	56	129
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	16678	13016	24771	1231	2846	3920
1.1.2.1 इक्विटी पूंजी	9111	7001	14706	684	1929	2698
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	5786	5303	6009	482	546	546
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5406	4101	7323	300	561	1143
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन / विनिवेश	3624	3389	3267	235	191	467
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	44081	36296	-1210	3746	-6591	-4041
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	44626	36778	-1398	3808	-6683	-3992
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	544	482	-188	62	-91	49
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	54210	47791	250	3718	-5441	-5288

अ: अन्तिमा

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	2023-24	2024		2025	
		फर.	दिसं.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	31735.74	2013.28	2315.96	2768.89	1964.21
1.1 जमाराशियाँ	916.45	36.70	48.10	58.20	51.62
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	242.51	15.38	30.14	34.19	28.76
1.3 इक्विटी / कर्ज में निवेश	1510.89	135.40	179.34	104.98	173.84
1.4 उपहार	3580.27	233.91	229.47	232.76	190.82
1.5 दान	11.31	0.84	0.63	0.63	0.59
1.6 यात्रा	17006.27	1053.64	1323.64	1646.74	1090.61
1.7 निकट संबंधियों से संबंधित खर्चे	4611.53	266.39	279.02	308.76	234.99
1.8 चिकित्सा उपचार	79.62	7.25	5.13	4.47	3.43
1.9 विदेश में शिक्षा	3478.65	246.82	210.20	368.21	182.17
1.10 अन्य	298.23	16.96	10.31	9.96	7.38

सं. 36: भारतीय रुपये का सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) और
वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) सूचकांक

मद	2023-24	2024-25	2024	2025	
			मार्च	फर.	मार्च
	1	2	3	4	5
40- मुद्रा समूह (आधार: 2015-16 = 100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	90.75	91.06	92.07	89.37	89.07
1.2 रीर	103.71	105.28	104.53	102.51	101.49
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	93.13	93.54	94.51	91.99	91.74
2.2 रीर	101.22	102.35	101.64	99.75	98.72
6- मुद्रा समूह (व्यापार-भारित)					
1 आधार : 2015-16 =100					
1.1 नीर	83.62	82.39	83.57	80.93	80.25
1.2 रीर	101.66	102.76	101.52	100.26	99.15
2 आधार : 2022-23 = 100					
2.1 नीर	97.31	95.89	97.25	94.18	93.39
2.2 रीर	99.86	100.93	99.72	98.48	97.39

टिप्पणी: 2023-24 और 2024-25 के लिए अब तक का डेटा अनंतिम है।

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) - पंजीकरण

(राशि मिलियन यूएस\$ में)

मद	2024-25	2024	2025	
		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1188	104	108	107
1.2 राशि	29461	2021	1978	2627
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	33	3	5	1
2.2 राशि	19748	275	2020	197
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1221	107	113	108
3.2 राशि	49209	2296	3998	2824
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	5.60	5.80	5.80	5.40
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 अस्थिर दर के ऋणों@ के लिए वैकल्पिक संदर्भ दर पर भारत औसत मार्जिन	1.66	1.77	1.53	1.87
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-27.00	0.00-10.00	0.00-11.00	0.00-11.00

उधारकर्ता श्रेणियाँ

I. कॉरपोरेट विनिर्माण	15836	591	242	1389
II. कॉरपोरेट - बुनियादी संरचना	15916	341	831	527
ए) परिवहन	1505	75	0	371
बी) ऊर्जा	3513	152	398	49
सी) पानी और सफाई व्यवस्था	33	0	0	0
डी) संचार	6309	0	13	0
ई) सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी संरचना	115	0	0	0
एफ) अन्वेषण, खनन और रिफाइनरी	2480	10	207	100
जी) अन्य उप-क्षेत्र	1961	104	213	7
III. कॉरपोरेट सेवा क्षेत्र	1526	330	115	211
IV. अन्य संस्थाएं	1728	127	1000	0
ए) एसईजेड में इकाई	1	0	0	0
बी) सिडबी	0	0	0	0
सी) एक्विजिशन बैंक	1727	127	1000	0
V. बैंक	0	0	0	0
VI. वित्तीय संस्थान (एनबीएफसी के अलावा)	20	0	0	0
VII. एनबीएफसी	13361	902	1792	623
ए) एनबीएफसी - आईएफसी / एएफसी	7734	398	1370	472
बी) एनबीएफसी - एमएफआई	531	11	56	0
सी) एनबीएफसी - अन्य	5096	493	366	151
VIII. गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ)	0	0	0	0
IX. सूक्ष्म वित्त संस्था (एमएफआई)	0	0	0	0
X. अन्य	822	5	18	74

टिप्पणी: ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्ड (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों के आधार पर जिन्हें निर्धारित अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या आबंटित की गई है।

@ 01 जुलाई, 2023 से लागू, बेचमार्क दर को बदलकर वैकल्पिक संदर्भ दर कर दिया गया है।

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(₹ करोड़)

मद	अक्टू-दिसं. 2023			अक्टू-दिसं. 2024 (अ)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	452267	446269	5998	544591	582251	-37660
1 चालू खाता (1.1+1.2)	236020	246451	-10431	261653	273133	-11480
1.1 पण्य	106626	178267	-71641	109817	188970	-79153
1.2 अप्रत्यक्ष मदें (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	129394	68184	61210	151837	84164	67673
1.2.1 सेवाएं	87785	42778	45007	103487	52277	51210
1.2.1.1 यात्रा	9850	7487	2363	10068	8371	1698
1.2.1.2 परिवहन	6950	6457	493	8278	8847	-569
1.2.1.3 बीमा	811	856	-46	870	894	-24
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	182	280	-98	167	307	-139
1.2.1.5 विविध	69993	27699	42294	84104	33859	50245
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	41041	4774	36267	47619	6561	41057
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	22647	14067	8581	29603	18252	11352
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	2491	956	1535	2086	741	1346
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	701	397	303	580	616	-37
1.2.2 अंतरण	31539	2237	29302	36081	2898	33182
1.2.2.1 आधिकारिक	94	230	-135	89	334	-244
1.2.2.2 निजी	31445	2007	29438	35992	2565	33427
1.2.3 आय	10069	23168	-13099	12268	28988	-16720
1.2.3.1 निवेश आय	8058	22292	-14233	10088	27943	-17854
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	2010	876	1134	2180	1046	1135
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	216247	198955	17291	282367	309118	-26751
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	144352	128388	15964	192195	206344	-14148
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	18875	14923	3952	20783	23560	-2776
2.1.1.1 भारत में	18309	9947	8362	19870	16218	3653
2.1.1.1.1 इक्विटी	11912	8773	3140	11135	15637	-4501
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	5155		5155	6131		6131
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1242	1175	67	2604	581	2024
2.1.1.2 विदेश में	566	4976	-4410	913	7342	-6429
2.1.1.2.1 इक्विटी	566	2355	-1789	913	3211	-2297
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	1446	-1446	0	1639	-1639
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1174	-1174	0	2493	-2493
2.1.2 संविभाग निवेश	125477	113465	12012	171412	182784	-11372
2.1.2.1 भारत में	124485	112814	11671	170667	182102	-11435
2.1.2.1.1 एफआईआई	124485	112814	11671	170667	182102	-11435
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	108785	102117	6668	144811	156671	-11860
2.1.2.1.1.2 ऋण	15701	10697	5003	25856	25431	425
2.1.2.1.2 एडीआर / जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	991	651	341	745	682	63
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	25440	28191	-2751	42894	33992	8901
2.2.1 बाह्य सहायता	4605	1401	3204	2955	2289	666
2.2.1.1 भारत द्वारा	9	48	-40	6	26	-20
2.2.1.2 भारत को	4596	1353	3244	2949	2263	686
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	6600	11067	-4466	20838	16462	4375
2.2.2.1 भारत द्वारा	2712	4503	-1791	9621	9593	28
2.2.2.2 भारत को	3888	6564	-2676	11217	6869	4348
2.2.3 भारत को अल्पावधि	14235	15723	-1489	19101	15241	3860
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	12535	15723	-3188	14260	15241	-980
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	1700	0	1700	4840	0	4840
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	40849	24492	16358	39538	49311	-9774
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	40654	24492	16162	39530	49306	-9776
2.3.1.1 आस्तियां	16550	5276	11274	11853	25923	-14070
2.3.1.2 देयताएं	24103	19215	4888	27677	23383	4294
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियाँ	22381	18461	3921	25912	22771	3141
2.3.2 अन्य	196	0	196	8	5	2
2.4 रुपया कर्ज चुकौती	2	2	-2	0	0	0
2.5 अन्य पूंजी	5606	17884	-12278	7740	19471	-11730
3 भूल-चक	0	862	-862	571	0	571
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	5998	-5998	37660	0	37660
4.1 आई.एम.एफ.	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)		5998	-5998	37660		37660

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(₹ करोड़)

मद	अक्तू-दिसं. 2023			अक्तू-दिसं. 2024 (अ)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	3766056	3716109	49947	4599615	4917695	-318081
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1965353	2052216	-86862	2209923	2306886	-96963
1.1 पण्य	887883	1484446	-596562	927511	1596038	-668527
1.2 अदृश्य मर्चे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	1077470	567770	509700	1282412	710849	571564
1.2.1 सेवाएं	730995	356218	374778	874055	441534	432521
1.2.1.1 यात्रा	82022	62341	19681	85035	70697	14338
1.2.1.2 परिवहन	57875	53767	4108	69915	74723	-4807
1.2.1.3 बीमा	6749	7130	-381	7347	7553	-206
1.2.1.4 जी.एन.आई.ई.	1512	2328	-816	1413	2590	-1177
1.2.1.5 विविध	582837	230650	352187	710344	285971	424373
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	341751	39756	301995	402186	55417	346769
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	188585	117135	71450	250030	154153	95877
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	20739	7958	12781	17623	6256	11367
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	5834	3309	2524	4896	5207	-310
1.2.2 अंतरण	262631	18628	244002	304738	24479	280259
1.2.2.1 आधिकारिक	785	1913	-1127	753	2817	-2064
1.2.2.2 निजी	261845	16716	245130	303985	21662	282323
1.2.3 आय	83844	192924	-109080	103619	244836	-141216
1.2.3.1 निवेश आय	67103	185626	-118523	85206	236005	-150799
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	16741	7298	9443	18413	8831	9582
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	1800703	1656716	143987	2384871	2610809	-225938
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	1202027	1069092	132935	1623281	1742779	-119498
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	157173	124264	32909	175537	198987	-23449
2.1.1.1 भारत में	152460	82832	69628	167826	136974	30852
2.1.1.1.1 इक्विटी	99194	73050	26144	94049	132068	-38019
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	42926	0	42926	51780	0	51780
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	10340	9783	557	21996	4905	17091
2.1.1.2 विदेश में	4713	41432	-36718	7712	62013	-54301
2.1.1.2.1 इक्विटी	4713	19610	-14897	7712	27116	-19405
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	12044	-12044	0	13842	-13842
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	9777	-9777	0	21055	-21055
2.1.2 संविभाग निवेश	1044854	944828	100026	1447744	1543792	-96048
2.1.2.1 भारत में	1036599	939411	97188	1441453	1538030	-96577
2.1.2.1.1 एफआईआई	1036599	939411	97188	1441453	1538030	-96577
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	905860	850336	55523	1223076	1323243	-100167
2.1.2.1.1.2 ऋण	130739	89075	41664	218376	214787	3590
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	8255	5417	2838	6291	5762	529
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	211839	234747	-22908	362279	287097	75181
2.2.1 बाह्य सहायता	38345	11667	26679	24961	19334	5626
2.2.1.1 भारत द्वारा	72	404	-331	52	217	-166
2.2.1.2 भारत को	38273	11263	27010	24909	19117	5792
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	54961	92153	-37192	175994	139042	36953
2.2.2.1 भारत द्वारा	22583	37494	-14911	81258	81026	232
2.2.2.2 भारत को	32378	54659	-22281	94736	58016	36720
2.2.3 भारत को अल्पावधि	118532	130928	-12396	161324	128721	32602
2.2.3.1 खरीदार और आपूर्तिकर्ता का ऋण > 180 दिन	104379	130928	-26549	120442	128721	-8280
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	14154	0	14154	40882	0	40882
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	340156	203943	136212	333936	416483	-82547
2.3.1 वाणिज्यिक बैंक	338525	203943	134582	333872	416438	-82566
2.3.1.1 आस्तियां	137815	43936	93879	100112	218949	-118837
2.3.1.2 देयताएं	200710	160008	40702	233760	197489	36271
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियाँ	186372	153723	32648	218851	192322	26530
2.3.2 अन्य	1630	0	1630	64	45	19
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	13	-13	0	0	0
2.5 अन्य पूंजी	46682	148921	-102239	65376	164450	-99074
3 भूल-चूक	0	7177	-7177	4820	0	4820
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	0	49947	-49947	318081	0	318081
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0	0	0
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि - / कमी +)	0	49947	-49947	318081	0	318081

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन यूएस \$)

मद	अक्टू-दिसं. 2023			अक्टू-दिसं. 2024 (अ)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	236013	246429	-10416	261647	273103	-11457
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	194412	221046	-26634	213304	241247	-27943
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	106626	178267	-71641	109817	188970	-79153
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	106094	164567	-58473	109391	169503	-60112
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	532	0	532	426	0	426
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	13701	-13701	0	19467	-19467
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	87785	42778	45007	103487	52277	51210
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	330	20	310	244	31	213
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	49	297	-248	82	305	-223
1.अ.ख.3 परिवहन	6950	6457	493	8278	8847	-569
1.अ.ख.4 यात्रा	9850	7487	2363	10068	8371	1698
1.अ.ख.5 निर्माण	1097	624	473	1047	834	213
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	811	856	-46	870	894	-24
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	2491	956	1535	2086	741	1346
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	434	4633	-4199	621	4573	-3952
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	41837	5400	36437	48296	7416	40880
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	22647	14067	8581	29603	18252	11352
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	1006	1464	-459	1148	1242	-95
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी माल और सेवाएं	182	280	-98	167	307	-139
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	103	239	-136	977	465	513
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	10069	23168	-13099	12268	28988	-16720
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	2010	876	1134	2180	1046	1135
1.आ.2 निवेश आय	6557	21972	-15415	8021	27150	-19128
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	2104	13735	-11631	2558	17331	-14772
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	51	1911	-1860	95	2596	-2502
1.आ.2.3 अन्य निवेश	557	6102	-5545	690	7019	-6329
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	3845	224	3621	4678	204	4474
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	1501	320	1181	2067	793	1274
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	31532	2215	29317	36074	2868	33206
1.इ.1 वित्तीय निगम, वितेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएव	31445	2007	29438	35992	2565	33427
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	30589	1430	29160	35063	1871	33192
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	856	578	278	928	694	234
1.इ.2 सामान्य सरकार	87	208	-120	83	303	-221
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	191	280	-89	185	322	-137
2.1 अनुत्पादित वितेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तरण (जमा)	36	86	-50	16	151	-135
2.2 पूँजी अंतरण	155	194	-38	169	171	-2
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	216063	204696	11367	319849	308826	11023
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	18875	14923	3952	20783	23560	-2776
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	18309	9947	8362	19870	16218	3653
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	17067	8773	8295	17266	15637	1629
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	11912	8773	3140	11135	15637	-4501
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	5155	0	5155	6131		6131
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1242	1175	67	2604	581	2024
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1242	1175	67	2604	581	2024
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	566	4976	-4410	913	7342	-6429
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	566	3801	-3235	913	4849	-3936
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	566	2355	-1789	913	3211	-2297
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	1446	-1446		1639	-1639
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1174	-1174	0	2493	-2493
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	1174	-1174		2493	-2493
3.2 संविभाग निवेश	125477	113465	12012	171412	182784	-11372
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	124485	112814	11671	170667	182102	-11435
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	108785	102117	6668	144811	156671	-11860
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	15701	10697	5003	25856	25431	425
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	991	651	341	745	682	63
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	5776	7904	-2128	6569	12105	-5536
3.4 अन्य निवेश	65936	62407	3529	83424	90377	-6953
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	22577	18461	4117	25919	22776	3143
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी कर्ज मूवमेंट; एनआरजी)	196	0	196	8	5	2
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	22381	18461	3921	25912	22771	3141
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0			0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0			0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूँजी)	29477	18499	10979	37411	45287	-7876
3.4.3अ भारत को ऋण	26757	13948	12809	27784	35668	-7883
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	2721	4551	-1830	9627	9619	8
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	37	158	-121	52	59	-7
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	14235	15723	-1489	19101	15241	3860
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	-390	9566	-9957	941	7015	-6074
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0			0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	5998	-5998	37660	0	37660
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0			0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0			0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0			0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	5998	-5998	37660	0	37660
4. कुल आस्तियां / देयताएं	216063	204696	11367	319849	308826	11023
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	133222	123403	9819	170356	190003	-19647
4.2 ऋण लिखत	83231	65728	17503	110891	111808	-916
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	-390	15565	-15955	38601	7015	31586
5. निवल भूल-शुद्ध	0	862	-862	571	0	571

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(₹ करोड़)

मद	अक्टू-दिसं. 2023			अक्टू-दिसं. 2024 (अ)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1. चालू खाता (1.अ+1.आ+1.इ)	1965295	2052031	-86736	2209867	2306632	-96765
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1अ.ख.)	1618879	1840663	-221785	1801566	2037572	-236006
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1अ.क.3)	887883	1484446	-596562	927511	1596038	-668527
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	883452	1370357	-486905	923914	1431621	-507707
1.अ.क.2 वाणिज्यिक के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	4432	0	4432	3597	0	3597
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	114089	-114089	0	164417	-164417
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	730995	356218	374778	874055	441534	432521
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	2746	163	2583	2061	262	1798
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	407	2474	-2067	689	2574	-1886
1.अ.ख.3 परिवहन	57875	53767	4108	69915	74723	-4807
1.अ.ख.4 यात्रा	82022	62341	19681	85035	70697	14338
1.अ.ख.5 निर्माण	9139	5196	3942	8843	7044	1799
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	6749	7130	-381	7347	7553	-206
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	20739	7958	12781	17623	6256	11367
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	3611	38576	-34965	5245	38627	-33383
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	348376	44964	303412	407907	62636	345271
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	188585	117135	71450	250030	154153	95877
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	8373	12194	-3820	9693	10492	-799
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न किए गए सरकारी माल और सेवाएं	1512	2328	-816	1413	2590	-1177
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	861	1991	-1130	8255	3926	4329
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	83844	192924	-109080	103619	244836	-141216
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	16741	7298	9443	18413	8831	9582
1.आ.2 निवेश आय	54604	182963	-128359	67749	229307	-161558
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	17522	114371	-96848	21607	146374	-124767
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	425	15915	-15490	800	21930	-21130
1.आ.2.3 अन्य निवेश	4636	50812	-46176	5827	59279	-53452
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	32021	1866	30155	39515	1724	37791
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	12499	2663	9836	17457	6698	10760
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	262572	18444	244128	304682	24225	280457
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तोत्तर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	261845	16716	245130	303985	21662	282323
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	254718	11904	242814	296144	15800	280343
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	7127	4811	2316	7842	5862	1980
1.इ.2 सामान्य सरकार	727	1728	-1001	697	2563	-1866
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	1590	2328	-739	1564	2720	-1156
2.1 अनुत्पादित वित्तोत्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	296	715	-419	136	1275	-1139
2.2 पूँजी अंतरण	1293	1613	-320	1428	1445	-17
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	1799172	1704519	94652	2701444	2608343	93101
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	157173	124264	32909	175537	198987	-23449
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	152460	82832	69628	167826	136974	30852
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	142120	73050	69070	145829	132068	13761
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	99194	73050	26144	94049	132068	-38019
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	42926	0	42926	51780	0	51780
3.1.आ.2 ऋण लिखत	10340	9783	557	21996	4905	17091
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	10340	9783	557	21996	4905	17091
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	4713	41432	-36718	7712	62013	-54301
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	4713	31654	-26941	7712	40958	-33246
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	4713	19610	-14897	7712	27116	-19405
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	12044	0	0	13842	-13842
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	9777	-9777	0	21055	-21055
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	9777	-9777	0	21055	-21055
3.2 संविभाग निवेश	1044854	944828	100026	1447744	1543792	-96048
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	1036599	939411	97188	1441453	1538030	-96577
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	905860	850336	55523	1223076	1323243	-100167
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	130739	89075	41664	218376	214787	3590
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	8255	5417	2838	6291	5762	529
3.3 वित्तीय डेसिग्टिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	48093	65814	-17720	55483	102239	-46756
3.4 अन्य निवेश	549051	519667	29385	704599	763325	-58727
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	188002	153723	34279	218915	192367	26549
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी कर्ज मूवमेंट; एनआरजी)	1630	0	1630	64	45	19
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेनेवाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	186372	153723	32648	218851	192322	26530
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	245460	154040	91420	315976	382492	-66517
3.4.3अ भारत को ऋण	222804	116142	106662	234666	301249	-66583
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	22656	37898	-15242	81310	81243	67
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	306	1315	-1009	437	497	-59
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	118532	130928	-12396	161324	128721	32602
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	-3249	79661	-82910	7947	59249	-51302
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	0	49947	-49947	318081	0	318081
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	0	49947	-49947	318081	0	318081
4. कुल आस्तियां / देयताएं	1799172	1704519	94652	2701444	2608343	93101
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	1109347	1027586	81762	1438829	1604767	-165939
4.2 ऋण लिखत	693073	547325	145748	936587	944327	-7740
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	-3249	129608	-132857	326028	59249	266779
5. निवल भूल-वृक्क	0	7177	-7177	4820	0	4820

टिप्पणी: प्रा: प्रारंभिक

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष / समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2023-24		2023		2024			
			दिसं.		सितं.		दिसं.	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	242271	542950	236506	536935	253846	555666	260275	547588
1.1 इक्विटी पूंजी*	153343	511142	149394	505572	161794	523146	165730	513545
1.2 अन्य पूंजी	88927	31808	87112	31363	92053	32520	94545	34043
2. संविभाग निवेश	12469	276739	11744	268727	12503	293843	12173	276024
2.1 इक्विटी	10942	162061	9523	161206	11241	170934	9356	155573
2.2 ऋण	1527	114678	2220	107521	1262	122909	2817	120451
3. अन्य निवेश	132654	575284	128316	561466	146714	622795	170554	619611
3.1 व्यापार ऋण	33450	123723	31689	123290	32953	130938	33280	135136
3.2 ऋण	17547	221894	18510	214954	22147	239779	22523	240977
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	53519	154787	44339	149326	56105	164076	68630	165713
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	28138	74880	33777	73895	35510	88002	46121	77784
4. आरक्षित निधियाँ	646419		622452		705782		635701	
5. कुल आस्तियां/देयताएं	1033812	1394973	999018	1367128	1118845	1472304	1078704	1443223
6. निवल आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)	-361161		-368110		-353459		-364519	

टिप्पणी: * इक्विटी पूंजी में निवेश निधि और पुनर्निवेशित अर्जन का शेयर शामिल है।

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक

भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक – भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2023-24	2024	2025		FY 2023-24	2024	2025	
		फर.	जन.	फर.		फर.	जन.	फर.
	1	-2	-1	0	5	2	3	4
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)	43.04	3.60	4.88	3.72	259206893	21907760	30296790	25171733
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.10.1 से 1.1.3)	16.80	1.46	1.77	1.16	170464587	14722762	17807347	14137926
1.1.1 आउटराइट	9.51	0.87	1.10	0.63	13463848	1273135	1627265	1088598
1.1.2 रेपो	4.94	0.39	0.41	0.33	76718788	6575139	7288494	5916603
1.1.3 त्रि-पक्षीय रेपो	2.35	0.20	0.25	0.20	80281951	6874488	8891588	7132725
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन	24.92	2.04	2.94	2.45	80984671	6537554	11164125	9957432
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @	1.31	0.09	0.17	0.12	7757636	647444	1325318	1076374
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)	-	-	-	-	-	-	-	-
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)	2700.16	238.26	268.15	244.20	170886670	14614297	17499363	16099371
1.1 ग्राहक लेनदेन	2686.04	237.09	266.89	243.05	152406168	13083464	15571748	14226027
1.2 अलबैंक लेनदेन	14.12	1.17	1.26	1.16	18480503	1530833	1927615	1873344
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.6)	1486106.89	137733.21	186538.41	177394.61	67542859	6039675	7000487	6497660
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @	3.92	0.32	0.31	0.28	261	21	18	16
2.2 एपीबीएस \$	25888.17	2965.77	2263.21	3103.12	390743	48312	52280	57097
2.3 आईएमपीएस	60053.35	5346.35	4442.23	4048.29	6495652	568092	606420	563082
2.4 एनएसीएच जमा \$	16227.27	1504.81	1304.72	1533.06	1525104	123887	145699	140881
2.5 एनईएफटी	72639.50	6889.23	8567.93	7647.93	39136014	3471495	3848033	3540103
2.6 यूपीआई @	1311294.68	121026.73	169960.01	161061.93	19995086	1827869	2348037	2196482
2.6.1 जिसमें से यूएसएसडी@	26.19	1.66	1.38	1.15	352	19	16	13
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.3)	18249.53	1611.25	1878.45	1862.80	1687658	153734	199535	193068
3.1 भीम आधार पे @	193.59	15.43	15.79	15.67	6112	376	486	494
3.2 एनएसीएच नामे \$	16426.49	1464.78	1715.83	1701.10	1678769	153173	198857	192387
3.3 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @	1629.45	131.04	146.83	146.03	2777	184	193	186
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)	58469.79	4634.92	5522.42	5052.09	2423563	190658	223090	201522
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)	35610.15	3112.44	4305.72	3969.59	1831134	149206	184126	167208
4.1.1 पीओएस आधारित \$	18614.08	1618.50	2177.43	1999.96	651911	54431	69429	62125
4.1.2 अन्य \$	16996.08	1493.94	2128.29	1969.63	1179223	94775	114697	105083
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)	22859.64	1522.47	1216.69	1082.50	592429	41452	38963	34314
4.2.1 पीओएस आधारित \$	16477.95	1108.96	910.91	803.42	393589	27918	25999	23216
4.2.2 अन्य \$	6381.69	413.51	305.78	279.07	198840	13534	12965	11098
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)	78775.40	6470.84	6547.10	6398.44	283048	22674	19496	19236
5.1 वॉलेट	63256.69	5211.85	4875.14	4850.75	234353	18434	14700	14404
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)	15518.71	1259.00	1671.97	1547.69	48695	4240	4796	4833
5.2.1 पीओएस आधारित \$	8429.87	702.41	701.18	641.84	11247	919	1000	969
5.2.2 अन्य \$	7088.84	556.58	970.79	905.86	37447	3321	3796	3863
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)	6632.10	541.88	516.61	462.02	7212333	602630	606756	540834
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)	6632.10	541.88	516.61	462.02	7212333	602630	606756	540834
6.2 अन्य	0.00	-	-	-	-	-	-	-
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1648233.71	150992.11	201003.00	191169.95	79149461	7009371	8049363	7452321
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)	1650933.88	151230.37	201271.14	191414.16	250036131	21623668	25548726	23551692
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)	1644301.78	150688.49	200754.53	190952.14	242823799	21021038	24941970	23010857

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	वि.व. 2023-24	2024	2025		वि.व. 2023-24	2024	2025	
		फर.	जन.	फर.		फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)	1252599.21	117275.04	158794.78	150031.46	30687088	2828120	3451865	3215517
1.1 अंतर्बैंक \$	83000.56	7774.97	9234.72	8703.42	5676805	530845	607541	558355
1.2 अंतर-बैंक \$	1169598.65	109500.07	149560.06	141328.04	25010283	2297275	2844325	2657162
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)	45034.98	3800.36	4167.05	3648.03	102117736	8867591	11639721	10409819
2.1 अंतर्बैंक @	12033.28	1008.05	1212.87	1003.88	53247042	4540083	6130804	5354635
2.2 अंतर-बैंक @	33001.71	2792.31	2954.18	2644.15	48870694	4327508	5508917	5055184
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी \$ (3.1 से 3.3)	66440.72	5172.34	4910.07	4497.97	3259388	257238	251938	235618
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$	95.80	7.91	7.79	6.84	4648	395	412	370
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	66001.01	5139.17	4883.53	4473.77	3241538	255809	250646	234408
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	343.90	25.26	18.75	17.36	13202	1034	879	840
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)	15.18	0.55	0.27	0.22	148	5	3	2
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$	15.06	0.53	0.24	0.19	147	5	3	2
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$	0.12	0.01	0.03	0.03	1	0	0	0
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @	11754.95	812.15	915.09	921.64	314003	21543	23246	23605
5.1 ईपीएस @	11754.95	812.15	915.09	921.64	314003	21543	23246	23605

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	मार्च 2024	2024	2025	
	तक	फर.	जन.	फर.
	1	2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)	10667.22	10612.71	10909.12	10949.92
1.1 क्रेडिट कार्ड	1018.03	1006.00	1088.73	1093.15
1.2 डेबिट कार्ड	9649.19	9606.71	9820.39	9856.77
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)	16743.63	17118.53	13463.21	13614.38
2.1 वालेट @	13381.80	13795.76	8954.73	9001.61
2.2 कार्ड @	3361.82	3322.78	4508.48	4612.77
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)	2.58	2.57	2.57	2.58
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$	2.23	2.23	2.21	2.22
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$	0.35	0.34	0.36	0.36
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @	17.55	17.01	14.74	14.68
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या	89.03	87.73	103.53	107.18
6 भारत क्यूआर @	62.50	61.50	64.43	65.48
7 यूपीआई क्यूआर *	3434.93	3371.80	6401.65	6496.91

@: नवंबर 2019 से नया समावेश
#: सहकारी बैंकों, एलायबी और आरआरबी द्वारा रिपोर्ट किया गया डेटा शामिल किया गया जो दिसंबर 2021 से प्रभावी है।
\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा।
* सितंबर 2020 से नया समावेश; केवल स्थिर यूपीआई क्यूआर कोड शामिल है।
टिप्पणियाँ: 1. डेटा अंतिम है।
2. 31 जनवरी 2020 से ईसीएस (डेबिट और क्रेडिट) एनएसीएस के साथ मिला दिया गया है।
3. कार्ड फेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड फेमेंट इस्ट्रुमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तलुना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा की परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
4. केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि शामिल हैं। इसके अलावा, असफल लेनदेन, बाजबैंक, स्थिरल, एसएसपायर्ड कार्ड / वालेट को शामिल नहीं किया गया है।
भाग I-ए. निपटान प्रणाली
1.1.3: प्रतिभूति खंड के तहत त्रि-पक्षीय रेपो 05 नवंबर 2018 से चालू हो गया है।
भाग I-बी. भुगतान प्रणाली
4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड ट्रांसफर और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।
5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध।
5.1: वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और वालेट के माध्यम से फंड ट्रांसफर शामिल हैं।
5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।
6.1: तीन ब्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।
6.2: 'अन्य' में गैर-एनआईसीआर लेनदेन शामिल हैं जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृहों से संबंधित हैं।
भाग II-ए. अन्य भुगतान चैनल
1: मोबाइल भुगतान -
बैंकों के मोबाइल ऐप्स और यूपीआई ऐप्स के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल।
जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू किए गए, संसाधित और अधिकृत कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं किए गए हैं, उन्हें बाहर रखा गया है।
2: इंटरनेट भुगतान - इसमें 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट का उपयोग करके वित्तीय लेनदेन शामिल हैं।
भाग II-बी. एटीएम
3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई का उपयोग करके लेनदेन से संबंधित है।
भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना
3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) द्वारा तैनात एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

आवसरिक शृंखला

सं. 44 लघु बचत

(₹ करोड़)

प्रणाली		2023-24	2023	2024		
			दिसं.	अक्तू.	नव.	दिसं.
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	232460	16670	10981	9805	11133
	बकाया	1865029	1789946	1962367	1971752	1982465
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	161344	12386	8792	7469	8734
	बकाया	1298795	1247555	1379283	1386750	1395484
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	17229	2279	1062	20	1090
	बकाया	191692	213964	200889	200909	201999
1.1.2 सुकन्या समृद्धि योजना	प्राप्तियां	35174	2171	1787	1944	2244
	बकाया	157611	104859	172819	174763	177007
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	26696	1713	1033	900	827
	बकाया	269007	263383	280416	281316	282142
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	38167	2197	1699	1609	1531
	बकाया	175472	169033	191465	193074	194605
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	25341	2429	2121	2109	2125
	बकाया	305776	297989	326679	328786	330912
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	140423	135196	155580	157349	159174
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	11967	11265	13910	14093	14299
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	8932	8472	10033	10166	10308
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	144454	143056	147156	147178	147131
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	18713	1616	1238	1023	1025
	बकाया	197134	196491	205221	206244	207269
1.1.9 डाक घर संचयी मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	8	-19	-149	-137	-108
	बकाया	1754	1488	1440	1303	1195
1.1.11 पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन	प्राप्तियां	16	0	1	1	0
	बकाया	349	348	354	355	355
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	56069	3957	2080	2184	2226
	बकाया	418021	407244	434502	436268	438074
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	16853	1213	637	524	430
	बकाया	183905	177154	191667	192191	192621
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	20939	1568	783	932	1113
	बकाया	220560	216509	226662	227594	228707
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	0	0	0	0	0
1.2.7 एम.एस. प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	18277	1176	660	728	683
	बकाया	18277	15064	23891	24620	25303
1.2.8 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	-4721	-1483	-7718	-8137	-8557
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	15047	327	109	152	173
	बकाया	148213	135147	148582	148734	148907

टिप्पणी : अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डाटा निवल प्राप्तियाँ हैं, अर्थात सकल प्राप्तियों से सकल भुगतान को घटाने पर प्राप्त।

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

सं. 45 केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2023	2024			
	दिसं	मार्च	जून	सितं	दिसं
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	10538792	10740389	10946860	11271589	11422728
1. वाणिज्यिक बैंक	37.55	37.66	37.52	37.55	37.98
2. सहकारी बैंक	1.49	1.47	1.42	1.35	1.36
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.67	0.66	0.70	0.77	0.65
4. बीमाकृत कंपनियां	26.16	25.98	26.11	25.95	26.14
5. म्यूच्युअल फंड	3.03	2.90	2.87	3.14	3.11
6. भविष्य निधियां	4.57	4.47	4.41	4.25	4.25
7. पेंशन निधि	4.44	4.52	4.74	4.86	5.05
8. वित्तीय संस्थाएं	0.55	0.55	0.57	0.63	0.64
9. कॉरपोरेट	1.33	1.35	1.44	1.60	1.45
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	1.92	2.34	2.34	2.80	2.81
11. भारतीय रिजर्व बैंक	12.54	12.31	11.92	11.16	10.55
12. अन्य	5.74	5.79	5.97	5.92	6.01
12.1 राज्य सरकार	2.07	2.04	2.13	2.19	2.21

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2023	2024			
	दिसं	मार्च	जून	सितं	दिसं
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	5338587	5646219	5727482	5909490	6055711
1. वाणिज्यिक बैंक	33.90	34.14	33.85	34.39	35.11
2. सहकारी बैंक	3.53	3.39	3.38	3.29	3.22
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	0.63	0.60	0.59	0.60	0.53
4. बीमाकृत कंपनियां	26.64	26.14	25.85	25.56	25.16
5. म्यूच्युअल फंड	2.00	2.09	2.08	1.93	1.89
6. भविष्य निधियां	22.00	22.35	22.94	23.02	22.90
7. पेंशन निधि	4.56	4.76	4.87	4.87	4.82
8. वित्तीय संस्थाएं	1.63	1.59	1.58	1.57	1.58
9. कॉरपोरेट	2.03	2.02	2.03	1.95	1.97
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.03	0.07	0.05	0.04	0.03
11. भारतीय रिजर्व बैंक	0.66	0.63	0.62	0.60	0.58
12. अन्य	2.37	2.20	2.17	2.18	2.19
12.1 राज्य सरकार	0.27	0.25	0.26	0.26	0.26

खज़ाना बिल					
श्रेणी	2023	2024			
	दिसं	मार्च	जून	सितं	दिसं
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	849151	871662	858193	747242	760045
1. वाणिज्यिक बैंक	57.18	58.53	47.79	44.74	40.45
2. सहकारी बैंक	1.28	1.67	1.49	1.58	1.22
3. गैर-बैंक प्राथमिक व्यापारी	1.70	1.66	2.69	2.28	1.41
4. बीमाकृत कंपनियां	5.50	5.06	5.78	5.26	4.73
5. म्यूच्युअल फंड	11.21	11.89	14.50	15.06	15.41
6. भविष्य निधियां	0.08	0.15	0.60	0.26	0.04
7. पेंशन निधि	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
8. वित्तीय संस्थाएं	5.34	7.16	6.56	6.36	6.77
9. कॉरपोरेट	4.58	4.50	4.79	4.66	4.56
10. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	0.07	0.01	0.20	0.15	0.12
11. भारतीय रिजर्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12. अन्य	13.06	9.36	15.59	19.65	25.29
12.1 राज्य सरकार	9.26	5.88	11.55	14.95	20.11

टिप्पणी: (-) शून्य या नगण्य को दर्शाता है
बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फार्मेट संशोधित किया है।
केंद्र सरकार दिनांकित प्रतिभूतियों में विशेष प्रतिभूतियां और सॉवरैन गोल्ड बांड शामिल हैं।
राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।
वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इनका हिस्सा बहुत कम है।
अन्य श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।
सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक का एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(₹ करोड़)

मद	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24 (सं.अ.)	2024-25 (ब.अ.)
	1	2	3	4	5	6
1. कुल वितरण	5410887	6353359	7098451	7880522	9110725	9800798
1.1 विकास संबंधी	3074492	3823423	4189146	4701611	5514584	5862996
1.1.1 राजस्व	2446605	3150221	3255207	3574503	3965270	4195108
1.1.2 पूंजी	588233	550358	861777	1042159	1453849	1526993
1.1.3 ऋण	39654	122844	72163	84949	95464	140895
1.2 गैर-विकास संबंधी	2253027	2442941	2810388	3069896	3467270	3800321
1.2.1 राजस्व	2109629	2271637	2602750	2895864	3266628	3537378
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	955801	1060602	1226672	1377807	1562660	1711972
1.2.2 पूंजी	141457	169155	175519	171131	196073	259346
1.2.3 ऋण	1941	2148	32119	2902	4569	3597
1.3 अन्य	83368	86995	98916	109015	128871	137481
2. कुल प्राप्तियां	5734166	6397162	7156342	7855370	9054999	9650488
2.1 राजस्व प्राप्तियां	3851563	3688030	4823821	5447913	6379349	7209647
2.1.1 कर प्राप्तियां	3231582	3193390	4160414	4809044	5456913	6142276
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	2012578	2076013	2626553	2865550	3248450	3631569
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	1216203	1114805	1530636	1939550	2204462	2506181
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	2800	2572	3225	3943	4001	4526
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	619981	494640	663407	638870	922436	1067371
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	31137	33448	35250	42975	49552	57273
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	110094	64994	44077	62716	86733	118239
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	59515	16951	27665	15970	55895	45125
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	50578	48044	16412	46746	30839	73114
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	1449230	2600335	2230553	2369892	2644642	2472912
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	1440548	2530155	2194406	2332768	2619811	2456959
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	571872	890012	627255	687904	346483	...
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	190241	107493	350911	529	-257913	...
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	868676	1640143	1567151	1644864	2273328	...
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	8682	70180	36147	37124	24832	15952
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	1440548	2530155	2194406	2332768	2619811	2456959
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	971378	1696012	1213169	1651076	1962969	1983757
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	209232	458801	526693	358764	434151	447511
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	38280	41273	28100	13880	21386	19857
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	10411	4545	42153	68803	52385	-33653
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	-14227	25682	42203	51989	35819	-10138
3ख.1.6 नकद शेष	-323279	-43802	-57891	25152	55726	150310
3ख.1.7 अन्य	548753	347643	399980	163104	57374	-100684
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	8682	70180	36147	37124	24832	15952
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल वितरण	26.9	32.0	30.1	29.2	30.8	30.0
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कुल प्राप्तियां	28.5	32.2	30.3	29.1	30.7	29.6
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्राप्तियां	19.2	18.6	20.4	20.2	21.6	22.1
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर प्राप्तियां	16.1	16.1	17.6	17.8	18.5	18.8
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सकल वित्तीय घाटा	7.2	13.1	9.5	8.8	9.0	7.6

... : उपलब्ध नहीं। सं.अ. संशोधित अनुमान, ब.अ. बजट अनुमान।

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज।

टिप्पणी : जीडीपी डेटा 2011-12 के आधार पर है। 2024-25 के लिए जीडीपी केन्द्रीय बजट 2024-25 से है।

डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।

1 और 2: डेटा केंद्र सरकार (एनएसएसएफ को पुनर्भुगतान सहित) और राज्य सरकारों के निवल पुनर्भुगतान का है।

1.3: राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को प्रतिकर और समनुदेशन का प्रतिनिधित्व करता है।

2: डेटा केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में निवल भिन्नता को दर्शाता है और इसमें केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियां शामिल हैं।

3ए.1.1: आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार डेटा।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधार।

3बी.1.2: राष्ट्रीय अल्प बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में निवल निवेश को दर्शाता है।

नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण यह डेटा पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को अर्थोपाय अग्रिम शामिल हैं।

3बी.1.7: ट्रेजरी बिल, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकद शेष निवेश खाता शामिल हैं।

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	फरवरी 2025 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
	1	2	3	4	5	6	7
1	आंध्र प्रदेश	6564.26	28	1905.35	25	2581.48	9
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	277.96	2	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	1092.28	6	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	464.42	11	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	500.58	24	264.77	8
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	18.56	4	386.34	4	-	-
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	1551.31	28	961.17	24	759.21	2
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	108.25	28	146.18	28	-	-
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	100.07	4	-	-	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	4553.66	28	991.24	24	201.58	3
23	राजस्थान	2655.84	25	1435.34	6	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	4966.69	28	2028.42	28	874.65	15
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	493.48	4	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणीयां: 1) राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेष तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।
2) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।
3) राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।
4) प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।
5) -: नगण्य

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 48: राज्य सरकारों द्वारा किए गये निवेश

(₹ करोड़)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	फरवरी 2025 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	नीलामी खजाना बिल (एटीबी)
1		2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	11642	1149	0	0
2	अरुणाचल प्रदेश	2765	7	0	3300
3	असम	8321	91	0	0
4	बिहार	12574	-	0	20000
5	छत्तीसगढ़	8281	495	0	8495
6	गोवा	1086	460	0	0
7	गुजरात	15424	672	0	2000
8	हरियाणा	2640	1716	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	0	0
10	जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश	19	18	0	0
11	झारखंड	2433	-	0	780
12	कर्नाटक	20400	754	0	29966
13	केरल	3132	-	0	0
14	मध्य प्रदेश	-	1283	0	0
15	महाराष्ट्र	72256	1756	0	0
16	मणिपुर	70	141	0	0
17	मेघालय	1283	109	0	0
18	मिज़ोरम	508	81	0	0
19	नगालैंड	1901	46	0	0
20	उड़ीसा	18398	2060	20802	13488
21	पुदुचेरी	583	-	0	1500
22	पंजाब	9205	0	0	0
23	राजस्थान	1803	-	0	7700
24	तमिलनाडु	3458	-	0	3627
25	तेलंगाना	7957	1746	0	0
26	त्रिपुरा	1232	27	0	0
27	उत्तरप्रदेश	5328	260	0	0
28	उत्तराखंड	10818	421	0	25000
29	पश्चिम बंगाल	13920	1039	0	1500
	कुल	237436	14331	20802	117356

- टिप्पणियां 1. सीएसएफ और जीआरएफ कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी गई आरक्षित निधियां हैं।
2. एटीबी में प्राथमिक बाजार में राज्य सरकारों द्वारा निवेश किए गए 91 दिनों, 182 दिनों और 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।
3. - : लागू नहीं (योजना का सदस्य नहीं)।

सं. 49: राज्य सरकारों की बाजार उधारियाँ

(₹ करोड़)

क्र.सं.	राज्य	2022-23		2023-24		2024-25						2024-25 में	
		ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	दिसं		जन		फर		सकल	निवल
						ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि	ली गई सकल राशि	ली गई निवल राशि		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	आंध्र प्रदेश	57478	45814	68400	55330	4237	3237	5000	4000	6820	5820	70057	49975
2	अरुणाचल प्रदेश	559	389	902	672	395	315	-	-	-	-	795	569
3	असम	17100	16105	18500	16000	1800	1100	1000	1000	3650	2650	15700	12050
4	बिहार	36800	27467	47612	29910	6000	3500	8000	5000	7546	6946	47546	31368
5	छत्तीसगढ़	2000	-2287	32000	26213	-	-	-	-700	4000	2000	10500	4300
6	गोवा	1350	500	2550	1560	-	-	-	-	-	-	1050	250
7	गुजरात	43000	28300	30500	11947	4500	2000	7000	2700	9700	5580	30200	11280
8	हरियाणा	45158	28638	47500	28364	2000	1150	6000	3400	4500	2750	37500	26020
9	हिमाचल प्रदेश	14000	11941	8072	5856	1000	900	-	-300	-	-384	6700	4066
10	जम्मू और कश्मीर	8473	5969	16337	13904	1600	1600	920	720	200	200	12870	11330
11	झारखंड	4000	-155	1000	-2505	-	-750	-	-2700	-	-	-	-3450
12	कर्नाटक	36000	26000	81000	63003	16000	13500	16025	13025	13000	10000	72025	52525
13	केरल	30839	15620	42438	26638	2755	2455	4000	2500	4920	3920	40922	26222
14	मध्य प्रदेश	40158	26849	38500	26264	5000	4250	5000	4000	6000	5000	41000	31900
15	महाराष्ट्र	72000	42815	110000	79738	-	-3100	18000	15600	14000	9617	99000	66917
16	मणिपुर	1422	1147	1426	1076	200	200	-	-100	250	147	1250	787
17	मेघालय	1753	1356	1364	912	635	535	-	-100	-	-125	1882	1069
18	मिजोरम	1315	1129	901	641	140	40	119	119	119	119	1049	819
19	नगालैंड	1854	1199	2551	2016	250	250	-	-	-	-100	550	100
20	उड़ीसा	0	-7500	0	-4658	-	-	1000	500	7000	7000	9000	7000
21	पुदुचेरी	1200	698	1100	475	350	350	-	-300	400	400	1300	600
22	पंजाब	45500	33660	42386	29517	2500	2200	3900	2500	2000	1250	38830	31926
23	राजस्थान	46057	30110	73624	49718	4800	3800	5000	3000	6000	4326	63565	43809
24	सिक्किम	1414	1320	1916	1701	-	-	-	-	488	388	1488	1258
25	तमिलनाडु	87000	65722	113001	75970	11000	10000	10000	7000	13000	9500	101025	69675
26	तेलंगाना	40150	30922	49618	39385	3500	2500	6209	4609	3000	2000	49709	38591
27	त्रिपुरा	0	-645	0	-550	-	-	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	55612	41797	97650	85335	12000	8422	5000	3000	9000	5000	35000	15713
29	उत्तराखंड	3200	1450	6300	3800	1000	-	1000	350	2000	2000	6400	4750
30	पश्चिम बंगाल	63000	42500	69910	48910	7000	5000	8500	5500	5000	2500	51500	30900
	कुल	758392	518829	1007058	717140	88662	63454	111673	74323	122593	88504	848413	572320

- : शून्य।

टिप्पणी: 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देयताएं जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देयताओं के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2021-22				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	3,42,813	3,30,490	4,85,203	5,54,816	17,13,322
जीडीपी का प्रतिशत	6.6	5.9	7.7	8.5	7.3
I. वित्तीय आस्तियां	3,63,395	5,25,419	8,16,484	9,07,366	26,12,664
जीडीपी का प्रतिशत	7.0	9.3	13.0	13.9	11.1
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	(81,064)	2,04,486	4,28,035	2,83,634	8,35,091
(ए) बैंक जमाराशि	(1,06,429)	1,97,105	4,22,393	2,70,025	7,83,094
i. वाणिज्यिक बैंक	(1,07,941)	1,95,442	4,18,267	2,62,326	7,68,094
ii. सहकारी बैंक	1,512	1,663	4,126	7,699	15,000
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	25,365	7,380	5,642	13,610	51,997
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	17,555	(435)	(2,178)	5,770	20,712
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	5,578	(1,371)	73	4,021	8,302
ii. आवास वित्त कंपनियां	11,977	936	(2,252)	1,748	12,410
2. जीवन बीमा निधियाँ	1,15,539	1,28,277	1,04,076	1,38,998	4,86,889
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ सहित)	1,24,971	1,12,810	95,493	2,18,719	5,51,993
4. मुद्रा	1,28,660	(68,631)	62,793	1,46,845	2,69,667
5. निवेश	24,884	82,260	69,715	50,926	2,27,785
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	14,573	63,151	37,912	44,964	1,60,600
(बी) इक्विटी	4,502	13,218	27,808	3,084	48,613
6. अल्प बचत (पीपीएफ छोड़ कर)	50,405	66,218	56,372	68,243	2,41,238
II. वित्तीय देयताएँ	20,583	1,94,929	3,31,281	3,52,550	8,99,343
जीडीपी का प्रतिशत	0.4	3.5	5.3	5.4	3.8
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	20,479	1,94,825	3,31,178	3,52,446	8,98,928
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	21,428	1,38,720	2,67,955	2,74,181	7,02,284
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	26,979	1,40,269	2,65,271	3,37,010	7,69,529
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	(949)	56,105	63,223	78,266	1,96,644
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	(8,708)	30,151	32,177	40,003	93,623
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	7,132	24,404	29,495	37,436	98,467
iii. बीमा कंपनियाँ	627	1,550	1,551	827	4,554
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	34	34	34	34	135
3. सामान्य सरकार	70	70	70	70	279

सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2022-23				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियां(I-II)	2,89,980	2,99,395	2,96,132	4,54,240	13,39,748
जीडीपी का प्रतिशत	4.5	4.6	4.3	6.4	5.0
I. वित्तीय आस्तियां	5,79,958	6,34,471	7,50,245	9,71,526	29,36,200
जीडीपी का प्रतिशत	8.9	9.8	10.9	13.6	10.9
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियां (ए+बी)	1,85,429	3,17,361	2,80,233	3,25,853	11,08,876
(ए) बैंक जमाराशि	1,63,172	2,99,533	2,56,400	3,07,867	10,26,971
i. वाणिज्यिक बैंक	1,58,613	3,00,565	2,48,460	2,84,968	9,92,606
ii. सहकारी बैंक	4,559	(1,032)	7,940	22,899	34,365
(बी) गैर-बैंक जमाराशियां	22,257	17,829	23,833	17,986	81,905
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	6,505	2,077	8,082	2,234	18,897
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां	4,231	3,267	3,247	3,946	14,690
ii. आवास वित्त कंपनियां	2,274	(1,191)	4,835	(1,712)	4,207
2. जीवन बीमा निधियाँ	73,298	1,51,677	1,67,522	1,56,613	5,49,109
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ सहित)	1,48,915	1,20,367	1,38,584	2,18,709	6,26,575
4. मुद्रा	66,439	(54,579)	76,760	1,48,990	2,37,610
5. निवेश	51,503	48,530	49,779	64,151	2,13,962
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	35,443	44,484	40,206	58,955	1,79,088
(बी) इक्विटी	13,561	1,378	6,434	1,665	23,038
6. अल्प बचत (पीपीएफ छोड़ कर)	54,375	51,115	37,368	57,211	2,00,068
II. वित्तीय देयताएँ	2,89,978	3,35,076	4,54,113	5,17,285	15,96,452
जीडीपी का प्रतिशत	4.5	5.2	6.6	7.3	5.9
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	2,89,781	3,34,880	4,53,917	5,17,089	15,95,667
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	2,34,235	2,63,450	3,70,783	3,83,845	12,52,313
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	2,30,284	2,61,265	3,68,305	3,31,293	11,91,146
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	55,546	71,429	83,134	1,33,244	3,43,354
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	30,532	36,650	55,792	94,565	2,17,539
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	22,337	33,031	24,903	36,746	1,17,017
iii. बीमा कंपनियाँ	2,678	1,748	2,439	1,933	8,798
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	34	34	34	34	135
3. सामान्य सरकार	163	163	163	163	650

सं.50 (ए): हाउसहोल्ड की वित्तीय आस्तियों और देयताओं का प्रवाह- लिखत-वार (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	2023-24				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियाँ(I-II)	3,53,093	2,89,675	2,98,111	6,11,366	15,52,245
जीडीपी का प्रतिशत	5.0	4.1	3.9	7.8	5.3
I. वित्तीय आस्तियाँ	6,74,763	8,15,842	8,08,779	11,32,130	34,31,514
जीडीपी का प्रतिशत	9.6	11.5	10.7	14.5	11.6
जिसमें:					
1. कुल जमाराशियाँ (ए+बी)	2,68,925	4,12,388	2,99,372	4,10,559	13,91,244
(ए) बैंक जमाराशि	2,55,249	5,06,208	2,79,872	3,94,573	14,35,902
i. वाणिज्यिक बैंक	2,46,079	5,06,700	2,82,537	3,87,313	14,22,629
ii. सहकारी बैंक	9,170	(492)	(2,665)	7,260	13,273
(बी) गैर-बैंक जमाराशियाँ	13,676	(93,820)	19,499	15,986	(44,658)
जिसमें से:					
अन्य वित्तीय संस्थान (i+ii)	(485)	(1,07,982)	5,338	1,825	(1,01,305)
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	6,119	4,782	4,896	1,943	17,740
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	(6,605)	(1,12,764)	442	(118)	(1,19,045)
2. जीवन बीमा निधियाँ	1,58,358	1,41,413	1,61,192	1,30,036	5,90,999
3. भविष्य और पेंशन निधि (पीपीएफ़ सहित)	1,63,508	1,48,178	1,53,255	2,53,719	7,18,661
4. मुद्रा	(48,636)	(36,701)	56,719	1,46,644	1,18,026
5. निवेश	41,409	73,060	79,633	1,08,732	3,02,834
जिसमें:					
(ए) म्यूचुअल फंड	32,086	55,769	60,135	90,973	2,38,962
(बी) इक्विटी	3,757	7,146	9,941	8,236	29,080
6. अल्प बचत (पीपीएफ़ छोड़ कर)	91,198	77,504	58,607	82,441	3,09,751
II. वित्तीय देयताएँ	3,21,670	5,26,167	5,10,667	5,20,764	18,79,269
जीडीपी का प्रतिशत	4.6	7.4	6.7	6.7	6.4
ऋण/ उधार					
1. वित्तीय निगम (ए+बी)	3,21,520	5,26,016	5,10,516	5,20,613	18,78,666
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	2,13,606	8,68,874	4,02,647	3,92,330	18,77,458
जिसमें:					
i. वाणिज्यिक बैंक	2,08,027	8,75,654	3,89,898	3,82,558	18,56,136
(बी) अन्य वित्तीय संस्थान	1,07,914	(3,42,858)	1,07,869	1,28,283	1,208
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	81,449	59,684	85,032	1,00,836	3,27,001
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	23,784	(4,04,294)	21,233	25,853	(3,33,424)
iii. बीमा कंपनियाँ	2,681	1,753	1,604	1,594	7,631
2. गैर-वित्तीय निगम (निजी कॉरपोरेट व्यापार)	34	35	35	35	138
3. सामान्य सरकार	116	116	116	116	465

टिप्पणियाँ: 1. हाउसहोल्ड की निवल वित्तीय बचत से तात्पर्य निवल वित्तीय परिसंपत्तियों से है, जिन्हें वित्तीय परिसंपत्ति और देयताओं के प्रवाह के बीच अंतर के रूप में मापा जाता है।
2. 2023-24 के लिए प्रारंभिक अनुमान और 2020-21 और 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान।
3. एनएसओ द्वारा राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण, 2023-24 के पहले संशोधित अनुमान जारी होने के साथ 2023-24 के प्रारंभिक अनुमानों में संशोधन किया जाएगा।
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ, सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं।
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2021	सितं-2021	दिसं-2021	मार्च-2022
वित्तीय आस्तियाँ (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	2,33,27,377	2,39,99,280	2,47,08,474	2,54,40,650
जीडीपी का प्रतिशत	110.4	108.9	108.2	107.8
(ए) बैंक जमाराशियाँ (i+ii)	1,07,90,832	1,09,87,937	1,14,10,330	1,16,80,355
i. वाणिज्यिक बैंक	99,53,044	1,01,48,486	1,05,66,753	1,08,29,079
ii. सहकारी बैंक	8,37,788	8,39,451	8,43,577	8,51,276
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	2,06,509	2,06,074	2,03,896	2,09,665
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	67,840	66,469	66,542	70,564
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	1,38,669	1,39,605	1,37,353	1,39,102
(सी) जीवन बीमा निधि	49,29,725	51,42,279	52,13,527	53,57,350
(डी) मुद्रा	27,42,897	26,74,266	27,37,059	28,83,904
(ई) म्यूचुअल फंड	18,55,000	20,64,364	21,26,112	21,52,141
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	7,57,398	7,62,264	7,67,287	8,34,148
(जी) पेंशन निधि	6,16,517	6,67,379	6,99,173	7,36,592
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	14,28,499	14,94,717	15,51,089	15,86,496
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	77,43,630	79,38,456	82,69,633	86,22,079
जीडीपी का प्रतिशत	36.6	36.0	36.2	36.5
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	61,80,377	63,19,097	65,87,052	68,61,233
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	56,47,239	57,87,508	60,52,779	63,89,789
ii. सहकारी बैंक	5,31,728	5,30,164	5,32,833	4,69,989
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	15,63,253	16,19,358	16,82,581	17,60,847
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	7,36,312	7,66,463	7,98,641	8,38,643
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	7,21,510	7,45,914	7,75,408	8,12,845
iii. बीमा निगम	1,05,431	1,06,981	1,08,532	1,09,359

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (जारी)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2022	सितं-2022	दिसं-2022	मार्च-2023
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	2,56,21,348	2,64,23,992	2,71,87,716	2,78,44,981
जीडीपी का प्रतिशत	102.8	102.6	103.2	103.3
(ए) बैंक जमा राशियाँ (i+ii)	1,18,43,527	1,21,43,060	1,23,99,459	1,27,07,326
i. वाणिज्यिक बैंक	1,09,87,692	1,12,88,257	1,15,36,717	1,18,21,685
ii. सहकारी बैंक	8,55,835	8,54,803	8,62,742	8,85,641
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	2,16,170	2,18,247	2,26,328	2,28,562
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	74,794	78,061	81,308	85,254
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	1,41,376	1,40,185	1,45,020	1,43,308
(सी) जीवन बीमा निधि	53,25,967	55,59,682	57,86,593	57,95,431
(डी) मुद्रा	29,50,343	28,95,764	29,72,524	31,21,514
(ई) म्यूचुअल फंड	20,48,097	22,60,210	23,55,316	23,67,793
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	8,51,913	8,58,591	8,64,731	9,39,449
(जी) पेंशन निधि	7,44,459	7,96,454	8,53,412	8,98,343
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	16,40,871	16,91,985	17,29,353	17,86,563
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	89,11,861	92,46,741	97,00,657	1,02,17,746
जीडीपी का प्रतिशत	35.8	35.9	36.8	37.9
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	70,95,468	73,58,918	77,29,701	81,13,546
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	66,20,073	68,81,338	72,49,643	75,80,936
ii. सहकारी बैंक	4,73,897	4,76,025	4,78,487	5,30,915
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	18,16,393	18,87,823	19,70,956	21,04,201
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	8,69,175	9,05,825	9,61,617	10,56,182
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	8,35,181	8,68,213	8,93,116	9,29,862
iii. बीमा निगम	1,12,037	1,13,785	1,16,223	1,18,157

50(बी): हाउसहोल्ड के वित्तीय आस्तियों और देयताओं का स्टॉक- चुनिंदा संकेतक (समाप्त)

(राशि ₹ करोड़ में)

मद	जून-2023	सितं-2023	दिसं-2023	मार्च-2024
वित्तीय आस्तियां (ए+बी+सी+डी+ई+एफ+जी+एच)	2,87,56,851	2,96,44,299	3,07,47,010	3,19,86,847
जीडीपी का प्रतिशत	104.6	105.4	106.6	108.3
(ए) बैंक जमा राशियाँ (i+ii)	1,29,62,575	1,34,68,783	1,37,48,656	1,41,43,228
i. वाणिज्यिक बैंक	1,20,67,764	1,25,74,464	1,28,57,001	1,32,44,314
ii. सहकारी बैंक	8,94,811	8,94,319	8,91,655	8,98,914
(बी) गैर-बैंक जमा				
जिसमें से:				
अन्य वित्तीय संस्थान	2,28,077	1,20,095	1,25,432	1,27,257
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	91,373	96,156	1,01,051	1,02,994
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	1,36,703	23,939	24,381	24,263
(सी) जीवन बीमा निधि	60,64,437	62,55,801	65,53,726	67,69,272
(डी) मुद्रा	30,72,878	30,36,177	30,92,896	32,39,540
(ई) म्यूचुअल फंड	26,26,046	28,29,859	31,56,299	33,87,208
(एफ) सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ)	9,55,061	9,60,344	9,64,852	10,51,376
(जी) पेंशन निधि	9,70,016	10,17,975	10,91,276	11,72,651
(ज) लघु बचत (पीपीएफ को छोड़कर)	18,77,761	19,55,265	20,13,873	20,96,314
वित्तीय देयताएँ (ए+बी)	1,05,39,266	1,10,65,282	1,15,75,799	1,20,96,412
जीडीपी का प्रतिशत	38.3	39.3	40.2	41.0
ऋण/ उधार				
(ए) बैंकिंग क्षेत्र	83,27,152	91,96,026	95,98,673	99,91,003
जिसमें:				
i. वाणिज्यिक बैंक	77,88,962	86,64,616	90,54,514	94,37,072
ii. सहकारी बैंक	5,36,409	5,29,528	5,42,241	5,51,852
(बी) अन्य वित्तीय संस्थाएँ	22,12,114	18,69,256	19,77,126	21,05,409
जिसमें:				
i. गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	11,37,631	11,97,315	12,82,347	13,83,183
ii. आवास वित्त कंपनियाँ	9,53,646	5,49,352	5,70,585	5,96,438
iii. बीमा निगम	1,20,837	1,22,590	1,24,194	1,25,788

टिप्पणियाँ: 1. जीडीपी के अनुपात के रूप में डेटा की गणना एनएसओ द्वारा 31 मई 2024 को जारी राष्ट्रीय आय 2023-24 के अनंतिम अनुमान के आधार पर की गई है।
2. पेंशन निधि में राष्ट्रीय पेंशन योजना की निधि शामिल है।
3. लघु बचत के साथ बकाया जमा राशि भारत सरकार के लेखा महानियंत्रक से प्राप्त की जाती है।
4. अन्य वित्तीय संस्थानों के अलावा गैर-बैंक जमा में राज्य ऊर्जा उपयोगिताएँ सहकारी गैर-ऋण समितियाँ आदि शामिल हैं। बकाया जमा के लिए आंकड़े केवल अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए उपलब्ध हैं।
5. संभव है कि पूर्णांकन के कारण कॉलम के आंकड़ों का जोड़ कुल के बराबर न हो।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6 : वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
- 3.5 और 3.7 : वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
- 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
- 4.5, 4.6 और 4.7 : माह / वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
- 4.10 से 4.12 : माह/ वित्त वर्ष के अंतिम नीलामी दिन से संबंधित है।
- 4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
- 7.1 और 7.2 : यूएस डॉलर में विदेशी व्यापार से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
- 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियाँ और अल्पावधि प्रतिभूतियाँ / बॉण्ड जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी, शामिल है।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टैम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉरवर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य अर्थात् एक्सिम बैंक को विशेष पुनर्वित्त सुविधा 31 मार्च 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

- अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े रिपोर्टिंग अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
- 2.2 : आईएमएफ खाता सं. 1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4 : आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्ड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

- एनएम₂ और एनएम₃ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
- 2.4 : चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
- 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय संस्थाओं में एकजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल₁ और एल₂ मासिक आधार पर और एल₃ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कॉलम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाये गए आंकड़े अंतिम और कॉलम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 14

कॉलम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़े अनंतिम हैं।

सारणी सं. 17

2.1.1 : राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4: आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं

1 : बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2 : संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बॉण्डों में निवेश, भारत सरकार द्वारा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया को अंतरित एसडीआर तथा सार्क और एसीयू करेंसी स्वैप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिज़र्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास के लिए शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रुपया - अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों पर रुपए में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

‘अन्य पूंजी’ एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी संस्थाओं / शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है। हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय अंतराल के कारण ये आंकड़े भुगतान संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : पत्र-पत्रिकाओं के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि और विपरीत क्रम का संकेतक है। 6- मुद्राओं वाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2021-22 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतित किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। नीर/रीर सूचकांकों के संकलन के लिए उपयोग की जाने वाली कार्यप्रणाली का ब्यौरा आरबीआई बुलेटिन के दिसंबर 2005, अप्रैल 2014 और जनवरी 2021 के अंक में उपलब्ध है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉण्डों (एफसीसीबी) के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43**भाग I-ए. भुगतान प्रणाली**

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर 2018 से किया गया है।

भाग II-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: 'अन्य' में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: वॉलेट के माध्यम से माल और सेवाओं की खरीद और निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रिडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: 'अन्य' में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन गृह से संबंधित है।

भाग II-ए अन्य भुगतान चैनल

1 : मोबाइल भुगतान -

- इसमें बैंकों के मोबाइल ऐप और यूपीआई ऐप के जरिए किए गए लेनदेन शामिल हैं।
- जुलाई 2017 के बाद के डेटा में मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत किए गए केवल व्यक्तिगत भुगतान और कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2 : इंटरनेट भुगतान - 'नेटबैंकिंग' के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी. एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): शून्य/ नगण्य को दर्शाता है।

बुलेटिन के जून 2023 के संस्करण से टेबल फॉर्मेट संशोधित किया है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉम एथोरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बॉण्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इनका हिस्सा बहुत कम है।

'अन्य' श्रेणी में राज्य सरकारें, डीआईसीजीसी, पीएसयू, ट्रस्ट, केंद्रीय विदेशी बैंक, हिंदू अविभक्त परिवार/व्यक्ति आदि शामिल हैं।

सितंबर 2023 के बाद के आंकड़ों में एक बैंक का एक गैर-बैंक के साथ विलय का प्रभाव शामिल है।

सारणी सं. 46

जीडीपी डेटा वर्ष 2011-12 के आधार पर आधारित है। वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी केंद्रीय बजट 2023-24 से ली गई है। डेटा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनः चुकौती सहित) और राज्य सरकार की निवल चुकौती से संबंधित हैं।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डेटा केंद्र और राज्य सरकारों की उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार हैं।

3बी. 1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) की ओर से केंद्र और राज्य सरकारों की विशेष प्रतिभूतियों में किए गए निवल निवेश को दर्शाते हैं।

यह डेटा नए डेटा की उपलब्धता के साथ घटकों में समायोजन के कारण पिछले प्रकाशनों से भिन्न हो सकता है।

3बी. 1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी. 1.7: खजाना बिल, वित्तीय संस्थानों से ऋण, बीमा और पेंशन निधि, विप्रेषण, नकदी शेष निवेश खाता सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और नीलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्पकालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ / डब्ल्यूएमए / ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

--: नगण्य।

सारणी सं. 48

समेकित ऋणशोधन निधि (सीएसएफ) और गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों के खजाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी के लिए अवधारणाएं और कार्यप्रणाली आरबीआई मासिक बुलेटिन की वर्तमान सांख्यिकी के लिए व्यापक मार्गदर्शिका में उपलब्ध हैं (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>)

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का समय श्रृंखला डेटा <https://data.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत व्याख्यात्मक नोट आरबीआई द्वारा जारी प्रासंगिक प्रेस प्रकाशनियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों/विज्ञप्तियों जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2025	₹350 एक प्रति ₹250 एक प्रति (रियायती दर*) ₹4,000 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,000 (एक वर्ष रियायती दर*)	15 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति 150 अमेरिकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकी पुस्तिका 2023-24	₹550 (सामान्य) ₹600 (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका 2023-24	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमेरिकी डॉलर (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2024-25 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. मुद्रा और वित्त संबंधी रिपोर्ट 2023-24	₹575 एक प्रति (काउंटर पर) ₹625 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	22 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 45, सं. 1, 2024	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
7. पंचायती राज संस्थाओं का वित्त	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
8. भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति संबंधी रिपोर्ट 2023-24	आरबीआई बुलेटिन जनवरी, 2025 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
9. वार्षिक रिपोर्ट 2023-24	आरबीआई बुलेटिन जून, 2024 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
10. वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट-दिसंबर 2024	आरबीआई बुलेटिन जनवरी, 2025 के पूरक के रूप में जारी किया गया।	
11. मौद्रिक नीति रिपोर्ट - अक्तूबर 2024	आरबीआई बुलेटिन अक्तूबर 2024 में शामिल है।	
12. नगर निगम वित्त पर रिपोर्ट - नवंबर 2024	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	16 अमेरिकी डॉलर, एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
13. बैंकिंग शब्दावली (अंग्रेजी-हिन्दी)	₹100 एक प्रति (काउंटर पर) ₹150 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	

टिप्पणियां:

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
 - टाइम सीरीज़ डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<https://data.rbi.org.in>)।
 - भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-2008 (5 खंड), भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक / शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

हाल के प्रकाशन

सामान्य अनुदेश

1. सभी संचार निम्न को संबोधित किए जाएँ:
निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग,
आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीआरकेडी, डीईपीआर),
भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर भवन, तल मंजिल,
सर पी. एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स सं. 1036. मुंबई- 400 001
टेलीफोन: 022-2260 3000 विस्तार: 4002, ईमेल: spsdepr@rbi.org.in
2. बिक्री के लिए प्रकाशन प्रातः 10:30 बजे से अपराह्न 3:00 बजे तक (सोमवार से शुक्रवार) उपलब्ध हैं।
3. प्रकाशनों को कैश ऑन डिलीवरी के आधार पर नहीं दिया जाएगा।
4. एक बार बेचे गए प्रकाशनों को वापस नहीं लिया जाएगा।
5. प्रकाशन के पिछले अंक आम तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं।
6. जहां रियायती मूल्य का संकेत नहीं दिया गया है, भारत में छात्रों, शिक्षकों, शैक्षिक/ अकादमिक संस्थानों, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं के लिए 25 प्रतिशत की छूट उपलब्ध है, बशर्ते पात्रता का प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।
7. सदस्यता शुल्क के भुगतान के लिए एनईएफटी को प्राथमिकता दी जाए और भुगतानकर्ता के नाम, सदस्यता संख्या (यदि कोई हो), खाता संख्या, तारीख और राशि सहित लेनदेन विवरण spsdepr@rbi.org.in पर ईमेल किया जाए या डाक द्वारा भेजा जाए।

ए. एनईएफटी ट्रांसफर के लिए अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है:

लाभार्थी का नाम	आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, आरबीआई
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा और पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBISOMBPA04
खाता प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19

बी. गैर- डिजिटल मोड के माध्यम से सदस्यता के मामले में, कृपया भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के नाम पर मुंबई में देय डिमांड ड्राफ्ट/ चेक भेजें।

8. 'प्रकाशन प्राप्त न होने' संबंधी शिकायतें दो माह की अवधि के अंदर भेजी जाएं।